

**DUE DATE SLIP****GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj )

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER S No	DUE DTATE	SIGNATURE

# भारत का रक्षा-संगठन

DEFENCE ORGANISATION IN INDIA

---

---

NDIA by

Publication Division, Govt of India, Delhi-6. The  
/ the Commission for Scientific and Technical  
ght out under the Scheme of Production of  
sponsored by Government of India,  
ducation and Social Welfare

# भारत का रक्षा-संगठन

( स्वाधीनता के बाद से संगठन और प्रशासन में हुए प्रमुख विकासों का अध्ययन )

71892

लेखक

ए० एल० वैकटेश्वरन्

सचिव, राष्ट्रीय रक्षा कालेज,

नई दिल्ली

अनुवादक

राजेन्द्र नारायण



मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी

भारत का रक्षा-संगठन  
( DEFENCE ORGANISATION IN INDIA )

प्रकाशक  
मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी  
भोपाल

•

प्रथम संस्करण १९७३

•

मूल्य  
पुस्तकालय संस्करण १८ रुपये  
साधारण संस्करण १५ रुपये

•

मुद्रक  
इसाहाबाद प्रेस  
३७०, रानी मण्डी,  
इसाहाबाद-३



## प्रस्तावना

इस शताब्दी के प्रारम्भ में भारत की सीमाएँ अभेद नानी जाती थी। उस समय का विचारों भारत में की व दना करते हुए बड़े गर्व से कहता था कि उत्तर और बाधे पश्चिम में हिमालय भारत का प्रहरी है—और दोब सीमाओं का रक्षण सागर करता है। गंवर और बोलत ही वो ऐसे दर्रे थे जिनसे होकर शत्रुओं ने अतीत में भारत पर आक्रमण किये थे। सामान्य विचार था कि यदि इन रास्तों को सुरक्षित बना लिया जाय तो देश आक्रमणों से सुरक्षित रहेगा। स्वतन्त्रता से पूर्व वो भी जन-सामान्य को भारत की सुरक्षा की चिन्ता नहीं थी। ब्रिटिश सरकार पर देश की सुरक्षा का दायित्व था और उसके पास विश्व का सबसे बड़ा जहाजी बेड़ा था। उत्तर या पूर्व से आक्रमण की आशंका नहीं थी, क्योंकि चीन और भारत के बीच तिब्बत मध्यवर्ती राज्य (Buffer State) के रूप में अवस्थित था। पूर्व में ब्रह्मदेश अंग्रेजों के ही अधीन था। इसके अतिरिक्त चीन अपनी घरेलू समस्याओं में तथा पड़ोसी देशों के साथ इस बुरी तरह उलझा हुआ था कि उसकी ओर से किसी आक्रमण की कल्पना नहीं की जा सकती थी।

सन् १९४७ के बाद भारत की सुरक्षा का प्रश्न पहली बार भारतीयों के सम्मुख उपस्थित हुआ। हिमालय के कारण सुरक्षित एक बड़े भू-भाग में पाकिस्तान नाम से एक नये राष्ट्र का निर्माण हुआ, जिसने जन्म के पहले साल ही काश्मीर पर, जो कि भारत में मिल गया था, हमला बोल दिया। उसके बाद चीन के अचानक आक्रमण और पाकिस्तान के दो-दो आक्रमणों का आयात भारत को घेरे हुए था। इन आक्रमणों ने स्पष्ट करा दिया कि कार्यता का वक्त और है, किन्तु वस्तुतः अब भारत की सीमा का कोई भी भाग अवशेष नहीं रहा। भारत की सीमाओं पर जो खतरे हैं उनके निकट भविष्य में समाप्त होने की कोई आशा नहीं है। ये खतरे स्पष्ट मार्ग, पहाड़ों और समुद्र, तीनों ओर से हैं। जिस प्रकार की लड़ाई की कल्पना भारत कर सकता था, उत्तरी अंचल की लड़ाई उसने भिन्न है। हिमालय की ऊँची-ऊँची चोटियों पर सड़ने की कल्पना भारतीय सैनिकों को नहीं थी। हिमालय के इन प्रदेशों में यातायात और परिवहन की व्यवस्था, भयंकर शीत में रहकर लड़ने का प्रशिक्षण, ऊँचे-प्रदेशों में युद्ध सामग्री और रसद पहुँचाने के साधन, इन सबने सुरक्षा तैयारी के लिए नया आह्वान दिया। यह भी अनुभव हुआ कि भारत को न केवल पहाड़ी इलाकों की सुरक्षा के लिए नये ढंग में तैयारी

करना है, अपितु उसे अपनी सामुद्रिक सीमाओं की रक्षा के लिए भी विघ्नित तैयारी करनी है। पानी में सुरंगें बिछाना और उन्हें हटाना, पनडुब्बियों और सड़ाऊ पोतों की संख्या बढ़ाना, उसके लिए नौसैनिकों को प्रशिक्षित करना आदि अनेकों चीजें ऐसी हैं, जिन पर गम्भीरता के साथ भारत ने पहली बार ध्यान दिया। बंगला देश के मुक्ति संग्राम के समय जब कि अमेरिका का जर्गी-ब्रेडा हिन्द महासागर में हमारे करीब जा-पहुँचा, तब हमने अपनी दुर्बलताओं का ठीक ठीक अहसास हुआ।

विज्ञान के विकास के साथ-साथ युद्धकला एवं युद्धास्त्रों में भी तेजी से प्रगति हो रही है। आज का नया हथियार कल पुराना पड़ जाता है। विकसित देशों के पास एकत्रित युद्ध-सामग्री और आणविक-युद्ध के लिए प्रशिक्षित सैनिकों का तो कहना ही क्या है। ऐसी स्थिति में भारत जैसे देश के सामने, जिसकी दो लम्बी सीमाओं पर भयंकर ईर्ष्यानु क्षत्रु हों, सगं सावधान और सतर्क रहने के अतिरिक्त अन्य उपाय ही क्या है।

सेना के नियमित सैनिकों के अनिश्चित द्वितीय रक्षा-पक्ति का भी देश की सुरक्षा में कम महत्व नहीं होता। जनता का मोर्चेबल और नागरिकों की रक्षा पक्ति, सुरक्षा के अत्यंत महत्त्वपूर्ण साधन है। विकसित देशों के नागरिक अपने देश के रक्षा संगठन में भली-भाँति परिचित होते हैं और वे जीवन में कम से कम एक बार सैनिक के रूप में सुरक्षा पक्ति में गढ़े भी होते हैं। प्रबुद्ध नागरिक देश की सुरक्षा व्यवस्था से ध्यानभारित रूप में परिचित हो, इनकी व्यवस्था अब प्रायः सभी सुरक्षित, अमुरक्षित देशों में की जा रही है। अतः यह आवश्यक है कि हमारे देश के तत्क्षण विद्यार्थी भारत के रक्षा-संगठन से भली-भाँति परिचित हों। इसी उद्देश्य में नेशनल डिफेंस बालेज के सचिव श्री ए० एल० वेङ्कटेश्वरन् के अंग्रेजी ग्रन्थ 'Defence Organisation in India' का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें पाठकों को भारतीय रक्षा संगठन ने सभी वर्गों की लक्ष्य-महान् जानकारी प्राप्त हो सकेगी। मूल-अंग्रेजी की पुस्तक के समान अनुवाद की भाषा भी सरल और प्रवाहपूर्ण है। आशा है, इस हिन्दी संस्करण का भी मूल-ग्रन्थ के समान स्वागत होगा।

प्रमुदमानु अग्निहोत्री

(डॉ० प्रमुदमानु अग्निहोत्री)

सचिव

मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी

## आमुख

भारत के स्वाधीन हो जाने के बाद के कुछ वर्षों में यह देखा गया कि भारत के रक्षा-प्रसाधन के संगठन में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं। यह अनुभव किया गया कि इन परिवर्तनों का, रक्षा के बारे में स्वाधीन भारत के सामने आने वाले विभिन्न समस्याओं का और उनको किम तरह निपटाया गया, यदि हा अभिनेष रखना बड़ा उपयोगी होगा। तदनुसार एक ऐसी पुस्तक प्रकाशित करने का निश्चय किया गया, जो न केवल सामान्य पाठक के लिए सूचनाप्रद हो, बल्कि रक्षा-संगठन के तदस्थों के लिए भी सन्दर्भ सामग्री प्रस्तुत करे। यह काम १९५७ में पूरा हुआ और उसमें स्वाधीनता के बाद के दशक के विकासों को लिया गया। बीच की अवधि के प्रमुख विकासों को भी अवशामित कर लिया गया है, पर स्वाधीनता प्राप्ति के बाद के पहले दशक की जो निर्माणक अवधि थी, उस की घटनाओं को ज्यादा ध्यौरे के साथ लिया गया है।

इस पुस्तक को प्रकाशित करने की याज्ञा देने के लिए लेखक सरकार का आभारी है। इसकी विषय-वस्तु के लिए सारा उत्तरदायित्व लेखक का ही है। मुझे रक्षा-मुख्यालय के उन अनेक लोगों को धन्यवाद देना है, जिन्होंने पाण्डुलिपि टाइप करने में मदद दी, लेकिन विशेष उल्लेख श्री बी० के० सान्यो, श्री टी० आर० शर्मा और श्री के० बालकृष्णन का करना है (जिन्होंने अधिकांश काम किया)। सेना मुख्यालय के लेफ्टी० कर्नल आर० के० चड्ढा और लेफ्टी० कर्नल कुमार सिंह, नौसेना-मुख्यालय के कैप्टन के० के० सनजवा और वायुसेना-मुख्यालय के विंग कमांडर एच० एल० कपूर सम्बन्धित सेनाओं के बारे में रंगीन रेखाचित्र प्रदान करने के लिए हमारे धन्यवाद के पात्र हैं और फोटोग्राफ देने के लिए लोक सम्पर्क-निदेशालय के मेजर जी० एस० पात्रले और तमगां या पदको (मैरुलो) की रंगीन ट्रासपेरेंसियाँ तैयार करा देने के लिए फोटो-इन्जीन के श्री टी० काशीनाथ को भी मैं धन्यवाद देता हूँ।

अतः इस पुस्तक को अस्तित्व में लाने का सबसे अधिक ध्येय श्री० बी० घोष (संयुक्त-सचिव, रक्षा मन्त्रालय, १९४३-२६) को है, जिन्होंने १९१३ में रक्षा-सचिव के रूप में इस पुस्तक की रचना का विचार दिया और श्री पी० बी० आर राव आई० सी० एस० (रक्षा-सचिव, १९६२-६६) को भी, जिनकी अतिरिचि और प्रोत्साहन के बिना यह पुस्तक प्रकाशित न हो पाती।

/

मुधार के लिए जो भी सुभाव आये, उनका सहर्ष स्वागत किया जायगा।

राष्ट्रीय रक्षा कालेज,  
नई दिल्ली।

लेखक

## विषय-सूची

### प्रस्तावना

### आमुख

अध्याय	पृष्ठ
१—१९४७ तक रक्षा-संगठन का विकास	१
२—रक्षा-सेनाओं का विभाजन	३४
३—विभाजन के पश्चात्	६२
४—रक्षा-नीति का निर्माण	८६
५—रक्षा-मन्त्रालय का उच्चिवालय	११२
६—फल सेना, नौसेना और वायुसेना मुख्यालय और निम्नतर रक्षा-विरचनाएँ	१३३
७—रक्षा-सेनाओं का राष्ट्रीयकरण और रियासती सेनाओं का एकीकरण	१५१
८—भरतों और प्रशिक्षण	१८०
९—नए संविधान से सम्बन्धित परिवर्तन	२१८
१०—सेवा की शर्तें	२३८
११—रक्षा-मन्त्रालय, वैज्ञानिक अनुसन्धान और रक्षा-उद्योग	२६३
१२—अन्त-सेना-संगठन	३०२
१३—नागरिकता में प्रशिक्षण	३३५
१४—रक्षा-व्यय और रक्षा-आयोजना	३५०

### परिशिष्ट

१—रक्षामन्त्रालय के अन्तर्गत आने वाले विषय	३२६
२—रक्षा-मन्त्रालय सम्बन्धी चालू केन्द्रीय अधिनियमों की सूची	३६१
३—तीनों सेनाओं के सापेक्ष पद	३६३
४—तीनों सेनाओं में प्रयुक्त राब्दावली	३६३

### अनुसूचिका

## चित्र-सूची

### अध्याय—१

पृष्ठ

जवाहरलाल नेहरू					
सरदार बलदेव सिंह					
एच० एम० पटेल	...	...	...		३२—३३

### अध्याय—६

भा० नौ० पो० विक्रान्त					
वायुसेना के विमानों के प्रकार		...	...		१४८—१४९

### अध्याय—७

जनरल कै० एम० करिखप्पा					
फाइस एडमिरल आर० डी० कटारी					
एयर मार्शल एस० मुकर्जी	...	...			१६८—१६९

### अध्याय—८

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़गवासला का प्रशासनिक-भवन					
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़गवासला का विशान-भवन					
भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून का प्रशासनिक-भवन	...				१८४—१८५

### अध्याय—९

देहरादून में सम्राट के रंगध्वज के ताप मार्च-पास्ट ।					
भारतीय सैन्य अकादमी के कमांडर,					
सुरक्षित रहने के लिए सम्राट के रंगध्वज ग्रहण करते हुए ।					
डॉ० राजेन्द्र प्रसाद भारतीय नौसेना की राष्ट्रपति के					
रंगध्वज भेंट करते हुए	...				२१८—२१९

### अध्याय—११

विजयन्त टैंक					
	...	...	...		२८८—२८९

## रंगोन चित्रफत्तक

अध्याय—६

पृष्ठ

नए पदक अलङ्करण

परम वीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र

सामान्य सेवा पदक

भारतीय स्वाधीनता पदक

अशोक चक्र, वीरि चक्र, शौर्य चक्र

प्रादेशिक सेना पदक अलङ्करण

दीर्घ सेवा और सदाचरण पदक

सुयोग्य सेवा पदक

सेना, नौसेना, वायुसेना पदक

परम विशिष्ट, अतिविशिष्ट और विशिष्ट सेवा पदक

...

२६२—२६३

अन्त में—

सेना, नौसेना और वायुसेना के पदों के शिक्षरक,

बिल्ले, रणध्वज, पताकाएँ आदि ।

## पहला अध्याय

### १९४७ तक रक्षा-संगठन का विकास

१५ अगस्त, १९४७ के बाद भारत के सैन्य प्रशासन-संगठन में अनेक परिवर्तन जरूरी हो गये। सत्ता के हस्तान्तरण तक रक्षा एक आरक्षित विषय था और रक्षा-व्यय के लिए विधान-मण्डल में मतदान जरूरी न था। वस्तुतः भारत की रक्षा समुचे ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा-योजना का एक अंग ही थी। इसलिए भारत के लिए कोई अलग भारतीय रक्षा-नीति तैयार करने की कोई गुंजाइश ही न थी। भारत के कमाण्डर-इन-चीफ सशस्त्र सेनाओं के प्रशासन के भारमायक थे और वे गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव कौंसिल के सुरक्षा-सदस्य भी थे। देश के रक्षा प्रशासन में किसी भारतीय का कोई योगदान न था। रक्षा नीति इंग्लैंड के राजप्रासाद में तैयार की जाती थी और उसकी कार्यान्विति के लिए भी १९४६ तक भारत-स्थित सैन्य-प्रशासन भी प्रायः ब्रिटिश अधिकारियों के ही हाथ में था। अमेरिकी प्रशासन की हालत इतनी बुरी न थी, जिसमें काफी पहले से ही भारतीयों को लिया गया था। भारतवासी इंडियन सिविल सर्विस में भरती हो सकते थे और उनमें से कुछ लोग उन्नीसवीं सदी के सातवें दशक से ही मेवा में जाने लगे थे। भारतीय सेना में कमीशन-प्राप्त अधिकारी बनने का अवसर भारतीयों का प्रथम महायुद्ध के अन्त की ही ओर दिया गया।

सितम्बर, १९४६ में जब अन्तरिम सरकार बनी, तब पहली बार एक भारतीय, गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव कौंसिल में, रक्षा-सदस्य बनाया गया, पर रक्षा-नीति का निर्माण करने की कार्यविधि में इससे कोई अन्तर न आया। १२ अगस्त, १९४७ को ही पहले-पहल रक्षा-नीति के निर्माण पर सारा नियन्त्रण और भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रशासन एक भारतीय रक्षा-मन्त्री को सौंपा गया जो एक निर्वाचित विधानमण्डल के प्रति जिम्मेदार थे। इस महत्वपूर्ण सांविधानिक परिवर्तन के अलावा स्वाधीनता की प्राप्ति ने भी भारतीय सशस्त्र सेनाओं की भूमिका और दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन ला दिया। बदली परिस्थितियों की दृष्टि में सैन्य प्रशासन-तन्त्र में भी परिवर्तन किये गये। आधुनिक सशस्त्र सेनाओं की आव-

क्षमताओं को पूरा करने के लिए या भारत में तब तक अप्रान्य सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए नये-नये संगठन भी बनाये गये ।

जो बड़े-बड़े परिवर्तन करने पड़े, उनको व्याख्या उस प्रशासनिक ढाँचे के प्रकाश में ही की जा सकती है और उसी ढाँचे के परिप्रेक्ष्य में उनको समझा जा सकता है, जिसका विकास ब्रिटिश काल में हुआ था और जो सत्ता-हस्तान्तरण के समय विरासत में मिला था । इसलिए ब्रिटिश काल में सैन्य-संगठन और प्रशासन के विकास का सक्षिप्त विवरण देना लाभप्रद होगा । इस विस्तरेण से ही स्वाधीन तन्त्र में आवश्यक प्रतीत हुए परिवर्तनों के स्वरूप का संकेत मिल जाएगा और पाठकों का ध्यान कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर आकषित किया जा सकेगा, जिनकी स्वाधीनता के बाद के दशक में समेकन के लिए किये गये प्रयासों का निर्धारण करते समय समझ लेना जरूरी है ।

### मेना का उदय ईस्ट इंडिया कम्पनी का काल

भारतीय सेना का आरम्भ ईस्ट इंडिया कम्पनी के आरम्भिक दिनों में खोजा जा सकता है और इसका विकास भारत में कम्पनी के कार्यकलाप के साथ जुड़ा हुआ है । शुरु-शुरु में अपने अनेक कारखानों की सुरक्षा के लिए कम्पनी ने भारतीय गारद भरती किये । सत्रहवीं सदी के अन्त तक कम्पनी ने तीन किलेबन्द जगहें, बम्बई, मद्रास ( फोर्ट सेंट जार्ज ) और कलकत्ता ( फोर्ट विलियम ) में बना ली थी । इन तीन किलेबन्दियों के चारों ओर एन-डूबरे से स्वतन्त्र तीन प्रेसीडेंसियाँ खड़ी हुईं, और प्रत्येक की अपनी-अपनी मेना थी । प्रत्येक का प्रेसीडेंट ही प्रेसीडेंसी की मेना का कमाण्डर-इन-चीफ भी था । वह इगर्लैंड में कम्पनी के डाइरेक्टरो के प्रति ही उत्तरदायी था । फलस्वरूप प्रेसीडेंसी की मेनायें अलग इकाइयों के रूप में काम करती रही । प्रेसीडेंसी सेनाओं में इगर्लैंड में भरती हुए या यहाँ ही लिये गये यूरोपवासी थे और भारतीय सिपाही भी थे, जो देशी बर्दियाँ पहनते थे और भारतीय नॉन-कमीसाड-अधिकारियों की कमान में थे । १७४८ में कम्पनी की भारत-स्थित सभी सेनाओं का एक कमाण्डर-इन-चीफ नियुक्त किया गया । कहा जाता है कि इससे प्रेसीडेंसी सेनाओं के संगठन में सुधार हुआ, हालाँकि सभी बातों में वे अलग-अलग बनी रही । इगर्लैंड से ब्रिटिश सेनाओं की पहली टुकड़ी १७५४ में भारत आयी और इसके आने के बाद भारत में सेनाओं की तीन धेनियाँ हो गईं, अर्थात् सम्राट की मेना, कम्पनी की यूरोपीय सेना और कम्पनी की भारतीय सेना । १७५७ में भारतीय मेना की नियमित बटातियनों में पुनर्गठित करने की कोशिश की गयी और थोड़े-थोड़े ब्रिटिश अधिकारी प्रत्येक में रखे गये । यह एन महत्वपूर्ण परिवर्तन था, क्योंकि पहली बार भारतीय यूनिटों में ब्रिटिश नॉन-कमीसाड अधिकारी रख गये, जबकि वे अब तक अपने ही भारतीय अधिकारियों की कमान में अधीन चलो आ रही थी । थोड़े में ब्रिटिश अधिकारियों की नियुक्तियों में रहने वाली इन बटातियनों की यथासमय ब्रिटिश कमांडरो वाली बटातियनों में बदल दिया गया । भारतीय सैनिकों को भी बहुत कुछ यूरोपीय सैनिकों के समान वस्त्रों और हथियार दिये गये ।



१७७३ के 'रेगुलेंटिंग एक्ट' के अनुसार, चार सदस्यों की कौंसिल की सहायता में काम करने वाले, गवर्नर जनरल का पद बनाया गया, जिसको कम्पनी के प्रदेश में मुख्यतया और असेनिक शासन के नियम, अध्यादेश और विनियम बनाना सौंपा गया। कौंसिल के पहले चार सदस्यों का नामोल्लेख अधिनियम में ही कर दिया गया। उनमें से एक कमांडर-इन-चीफ था। १७८४ के अधिनियम ने गवर्नर जनरल की परिषद् के सदस्यों की संख्या चार से घटाकर तीन कर दी और इनमें से एक कमांडर-इन-चीफ बना रहा। १७९३ के अधिनियम ने यह व्यवस्था की कि कमांडर-इन-चीफ अब परिषद् का पदेन नियमित सदस्य न रहेगा, पर डाइरेक्टर उसे एक असाधारण सदस्य से रूप में नामित कर सकते हैं।

१७८६ में भारत में सरकार के मुख्यालय में एक सैन्य-विभाग खोला गया। यह उच्चतम सरकार के आदेश सेनाओं के कार्यपालक प्रमुखों तक भेजने की शृंखला बना।

१७९६ में अतिरिक्त पुनर्गठन किया गया, जिसके अनुसार पुनिटो में भारतीय सैनिकों की संख्या कम की गयी और ब्रिटिश अधिकारियों की संख्या काफी बढ़ायी गयी। उस समय बंगाल, मद्रास और बम्बई की तीन प्रेसीडेंसियों में भारत-स्वतः यूरोपीय सैनिकों की संख्या १३,००० थी, जब कि भारतीय सैनिकों की संख्या २७,००० थी। १७९७ से १८५७ तक प्रेसीडेंसी सेनाओं की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही, जो प्रदेशों को हड़पने की विस्तृत नीति के अनुकूल ही था। इम्पीरियल सेना और कम्पनी की ब्रिटिश और भारतीय पुनिटों वाली तीन प्रेसीडेंसी सेनाओं के अलावा विशेष स्थानों में सैनिक सेवाएँ प्राप्त करने के लिए स्थानीय सैन्य टुकड़ियाँ भी खड़ी की गयी थी। इनमें से उल्लेखनीय हैं: हैदराबाद कांस्टिबल और पंजाब अनियमित सेना, जो बाद में पंजाब फॉर्टिफर सेना बन गयी।

### गवर्नर जनरल की परिषद् में सेना-सदस्य

१८३३ के चार्टर अधिनियम ने गवर्नर जनरल की परिषद् में सेना सदस्य और विधि-सदस्यों के पद बनाये। अधिनियम में यह भी व्यवस्था की गयी थी "समूचे असेनिक और सैन्य-भरदार का अधीक्षण, निदेश और नियन्त्रण सपरिषद् गवर्नर जनरल के अधीन रहेगा और रखा जाता है।" इस अधिनियम के अधीन परिषद् का पहला सेना-सदस्य १८३४ में नियुक्त किया गया। इस नयी नियुक्ति का प्रयोगन सपरिषद् गवर्नर जनरल को एक विशेषज्ञ के परामर्श का लाभ देना था, गवर्नर जनरल को बहुत से सैन्य-कार्य से मुक्त करना था और गवर्नर जनरल का कार्यक्षेत्र कार्यपालक-कर्तव्यों तक ही सीमित करना था। सेना-सदस्य का पदधारी अपनी पदावधि में किसी सैन्य-कमान को न संभाल सकता था और न किसी वास्तविक सेना-कर्तव्य में हो नियुक्त हो सकता था। व्यवहार में कमांडर-इन-चीफ परिषद् का एक असाधारण सदस्य बना रहा।

१७८५ से १८३३ तक एक सैन्य-जोड़ भी चलता रहा, जिसमें कमांडर-इन-चीफ, एड्रूटेंट जनरल, क्वार्टर मास्टर जनरल और सेना-मुख्यालय के अन्य अधिकारी थे। यह केवल

मन्दन और निरीक्षण का बोर्ड था, जो त्रुटियों और दुरुपयोगों की रिपोर्टें सुपरिगढ़ गवर्नर जनरल के पास भेज देता था।

१८६१ तक देश का कोई भी सैनिक और असेनिक कार्य परिपड़ के सदस्य-विशेष को न सौंपा गया था, बल्कि पूरी परिपड़ ही उसे निपटाती थी। विभाग बाँटने की प्रणाली भारत में पहली बार १८६१ में शुरू की गयी। इस तरह १८६१ में गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव कौंसिल के दो सदस्यों का विशेष सम्बन्ध सैन्य-मामलों से था, अर्थात् कमांडर-इन-चीफ जो सेना की कमान और कार्यपालक काम के लिए जिम्मेदार था और मेना का प्रमुख था, पर परिपड़ में उसे कोई विभाग न मिला हुआ था, और एक अन्य सदस्य भी था, जो मेना-सदस्य के रूप में प्रसिद्ध था और वह भी एक सैनिक होता था, जो सेना के प्रशासनिक कार्य के लिए जिम्मेदार था और सरकार के आदेशों की अधिष्ठा करने वाले सभी प्रस्ताव कमांडर-इन-चीफ को उसके पास भेजने पड़ते थे।

१८५७ के विद्रोह के बाद में भारत के बारे में मुसगठित सैन्य-नीति तैयार की गयी। तब से सत्ता-हस्तान्तरण के समय तक रक्षा और विदेश-कार्य-विभाग, जो परस्पर निकट सम्बद्ध हैं, सदैव आरक्षित-विषय बने रहे। विदेश-विभाग परिपड़ के एक सदस्य को न सौंप कर सीधा वायसराय के अंतर्गत ही रखा गया। १८५८ में जब सम्राज्ञी ने भारत-सरकार की बागडोर सीधे अपने हाथ में ले ली और ईस्ट इंडिया कम्पनी बन्द कर दी गयी, तब कम्पनी की यूरोपीय सेना को इंग्लैण्डन ब्रिटिश सेना के साथ मिला दिया गया। भारतीय सेना को भी पुनर्गठित किया गया। कुछ घुससवार और पैदल यूनिटें छोड़ दी गयीं और कुछ आपम में मिला दी गयीं। पूरे देश से सेना में भरती करने की पुरानी नीति बदली गयी और धीरे-धीरे सेना में प्रवेश पंजाब और पश्चिमोत्तर सोमान्ध की तबाकयिन सैन्य जातियों तक ही सीमित कर दिया गया। इसके बाद ब्रिटिश मेना की बड़ी-बड़ी यूनिटों को अपना कर्तव्य करने के लिये भारत के दोरे पर भेजा गया। यह उसी तरह था जिस तरह ब्रिटिश मेनाओं को अन्य निर्भर-राज्यों और उपनिवेशों को अध्यायी प्रवास के लिये भेजा जाता था।

१८६१ में तीन जगम प्रेसीडेंसी-स्टाफ-‘कोरें’ शुरू की गयीं। इससे पहले ब्रिटिश अधिकारी रेजीमेंटी ‘काडरो’ में होते थे और ये काडर हालांकि काफी बड़े-बड़े थे, पर असेनिक पदों पर काम करने वाले या मेनाओं के मातहत होने वाले अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण जो दबाव पड़ता था, उसको बरदाश्त करने के लिए अर्थात् सहन कर लेते थे। साथ ही एक रेजीमेंट के अधिकारियों और दूसरे रेजीमेंट के अधिकारियों के बीच पदोन्नति की समानता जैसा कोई दावा न था और विभिन्न रेजीमेंटों में पदोन्नति की गति में काफी अक्षमता थी। काफी सभ्यता में अधिकारियों के साथ प्रेसीडेंसी स्ट्राफ की स्थापना हो जाने पर ये दोनों दोष दूर हो गये और प्रेसीडेंसी मेनाओं के अधिकारियों को समूची सभ्यता अब एक केन्द्रित समूहन में आ गयी।

### प्रेसीडेंसी मेनाओं की मर्यादा

इन बीच कुछ और भी परिवर्तन किए गये, जिन्होंने नीतियों प्रेसीडेंसी मेनाओं के केन्द्रित

सम्मिलन का पथ प्रशस्त कर दिया। १८६४ में तीनो प्रेसीडेंसियों के सैन्य-लेखा-विभाग भारत सरकार के सैन्य-विभाग के अधीन समेकित किये गये। १८७६ में लार्ड लिटन ने एक सेना-संगठन-आयोग सैन्य-व्यय कम करने का उपाय सुझाने और युद्ध के लिए सेना की प्रकायगत दक्षता सुधारने के तरीकों की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया। इस आयोग की एक प्रमुख सिफारिश यह थी कि प्रेसीडेंसी सेनायें समाप्त कर दी जायें, पर सोलह साल बाद तक इसको अवल में न लाया गया। पहले कदम के रूप में तीनो प्रेसीडेंसी स्टाफ कोरों एक भारतीय स्टाफ कोर में एकत्र कर दी गयी, जिसका अर्थ यह हुआ कि ब्रिटिश अधिकारियों का एक अखिल भारतीय कांडर अस्तित्व में आ गया। आगे चल कर, प्रेसीडेंसी सेनायें १ अप्रैल, १८९१ से समाप्त कर दी गयी और इस तरह पहली बार एकीकृत भारतीय सेना अस्तित्व में आयी, जिसे प्रशासन के प्रयोजन से नौबे सिखी चार कमानों में बांट दिया गया। प्रत्येक कमान कुछ प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करने वाले एक लेफ्टिनेन्ट जनरल के अधीन थी और ये सीधे कमांडर-इन-चीफ के अधीन थे —

पंजाब कमान ( पश्चिमोत्तर-सोमात सहित )

बंगाल कमान

मद्रास कमान ( बर्मा सहित )

बम्बई कमान ( सिंध, कचेडा और अवन सहित )

कमानों की यह पद्धति बाद में ढोढी बदल दी गयी, किन्तु १९२१ में चार कमानों की पद्धति पुन स्थापित की गयी।

इस तरह यह पता चलता है कि भारतीय सेना का इस रूप में जन्म उन्नीसवीं सदी के अन्त की ओर ही हुआ। वस्तुतः 'भारतीय सेना' शब्द का प्रयोग १ जनवरी, १९०२ को ही पहले-बहुल किया गया, जब भारतीय स्टाफ कोर समाप्त की गयी और इस कोर के अधिकारियों को 'भारतीय सेना' के अधिकारी कहा गया।

### सैन्य-प्रशासन का संगठन

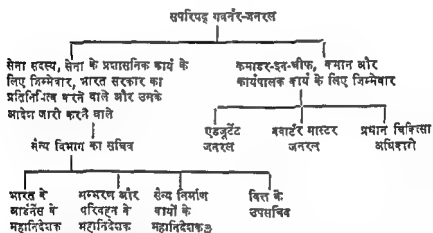
अब सरकार के मुख्य केन्द्र में भारत के सैन्य-प्रशासन का संगठन वस्तुतः महत्व की चीज बन गया था। भारत की ( अर्सेनिक और सैनिक दोनों ही प्रशासनों की ) शासित करने का उत्तरदायित्व सपरिपद् गवर्नर जनरल का था, जो भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्रति और उसके जरिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। जैसा कि बताया जा चुका है गवर्नर की परिपद् में सैन्य मामलों से सम्बन्धित दो सदस्य थे। एक तो कमांडर-इन-चीफ था, जो सेना का ( नौ बड़े समेत ) कार्यपालक-प्रमुख था और उसके संगठन और दक्षता के लिए उत्तरदायी था। उसके कार्यालय को सेना-मुख्यालय कहने थे, जिसमें दो प्रमुख स्टाफ अधिकारी थे, अर्थात् एडजुटेंट जनरल और क्वार्टर मास्टर जनरल और साथ ही प्रमुख चिकित्सा अधिकारी भी था। दूसरे एक सेना-सदस्य भी था, जो सेना के प्रशासनिक कार्य के लिए उत्तरदायी था और वह सरकार के आदेश कमांडर-इन-चीफ तक पहुँचाता था। माप ही उम

पर पुर्ति, परिवहन, आयुषसामग्री ( आर्डेन्स ), और सैन्य निर्माण-कार्य की जिम्मेदारी थी । वह सैन्य-वित्त बनाने के लिए भी उत्तरदायी था ।

### सैन्य-विभाग की भूमिका

उग समय का सैन्य-विभाग अपने अधिकार-क्षेत्र में मौलिक काम तो करता ही था, साथ ही सेना-मुख्यालय या चारो मेना-कमानो से सीधे ही आने वाले सभी प्रस्तावों की स्वतन्त्र जाँच भी करता था । फलतः अपने समक्ष आने वाले और उसके द्वारा मूकपात किये जाने वाले सभी प्रस्तावों के लिए वह अपने कानूज-पत्र रखता था, जिसमें विभाग में अंग्रेजित मात्रा में मातृत्व बना रहे । विभाग में तीन प्रभाग थे, अर्थात् सैन्य, प्रशासन और वित्त । वित्त-प्रभाग महानताकार, सैन्य-विभाग के अधीन था, जो सभी सैन्य और नौसैनिक मामलों में भारत सरकार का वित्तीय सलाहकार था । दूसरे शब्दों में वित्त-प्रभाग सैन्य-विभाग का ही एक भग था । नीचे लिखे आरेख में सारा ढोचा स्पष्ट हो जाता है ।

#### आरेख—१



उग समय अपनायी जाने वाली कार्यविधि यह थी कि मेना-कमानो या मेना-मुख्यालय में चलने वाले महत्वपूर्ण सैन्य-मुद्दारा या व्यय को अन्तर्ग्रस्त करने वाले सभी प्रस्ताव सैन्य-लेखा-निपन्त्र के जरिए सैन्य-विभाग को भेज दिये जाते थे । फिर सैन्य-विभाग में हुनकी विनीय और प्रशासनिक, दोनों ही दृष्टियों में जाँच की जाती थी । जो प्रस्ताव सेना-सदस्य द्वारा अनु-मोदित हो जाता था, उसे वित्त विभाग को भेज दिया जाता था और अगर वित्त-विभाग भी मान लेता था तो उग मामले को अनुमोदन के लिए गवर्नर जनरल के पास भेज दिया जाता

■ उग पद की बाद ( १९२१ ) में इन्वीनियर-इन-चीफ नाम दिया गया ।

था। कोई मतभेद होने पर उसे एग्जीक्यूटिव कोसिल में पेश कर दिया जाता था। जब कोसिल प्रस्ताव मान लेती थी या जब दोनों विभागों से अनुमोदित प्रस्ताव गवर्नर जनरल मान लेता था, तो एक डिप्टी द्वारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भी सूचित कर दिया जाता था। यदि सेक्रेटरी आफ स्टेट ठीक समझता था तो युद्ध-कार्यालय से परामर्श करते हुए या यथावश्यक ब्रिटिश-मन्त्रिमण्डल से अनुमोदन लेकर, मंजूरी दे देता था। इस तरह सभी महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अन्तिम निर्णय सेक्रेटरी आफ स्टेट और सम्राट की सरकार का ही होता था।

### कर्जन-किचनर-विवाद

एग्जीक्यूटिव कोसिल में दो सदस्यों का होना, जिनमें एक सशस्त्र सेना का कार्यपालक प्रमुख था और दूसरा कमांडर-इन-चीफ के प्रस्तावों की छानबीन करता था और उनके बारे में सरकार के आदेश जारी करता था, काफी उत्तुपजनक व्यवस्था न थी। खानकर जब कि सेना-सदस्य भी एक सेना अधिकारी हो या जो पद में कमांडर-इन-चीफ से कनिष्ठ होता था। कुछ लोग कमांडर-इन-चीफ को परिपक्व का सदस्य बनाया जाना ही असंगत मानते थे, जब कि कुछ लोग स्वयम् कमांडर-इन-चीफ, सैन्य-विभाग और सेना-सदस्य को निरर्थक और आहम्बर मानते थे। स्पष्ट ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इस सचर्चे के अस्तित्व से परिचित थे, जिसके बारे में पहले के वायसराय और कमांडर-इन-चीफ मुद्दे विचार व्यक्त करते रहे थे, और सभी सम्बन्धित लोग युक्ति और समझबूझ द्वारा ही जिसे स्पष्टन नियन्त्रण में रखते चले आ रहे थे। इसलिए भारत सम्बन्धी सेक्रेटरी आफ स्टेट ने औपचारिक रूप से भारत-सरकार से कहा कि वह भारत की सैन्य-प्रशासन-पद्धति की पूरी छानबीन करे और सुधार के लिए उपयुक्त प्रस्ताव भेजे। १९०५ के आरम्भ में इस सम्बन्ध में तत्कालीन कमांडर-इन-चीफ लार्ड किचनर ने दृढ़ रवैया अपनाते हुए उस व्यवस्था में सैन्य-प्रशासन में पैदा हुए इस द्वैध नियन्त्रण की घोर आलोचना की। उनका दृढ़ अभिमत था कि यह व्यवस्था सदोष है, अकार्यक्षम है और एक महापुद्ग के लिए अपेक्षित विस्तार के प्रयोजन में अवरोध है। वह इसके घोर विरोध में थे, हालाँकि उन्होंने यह स्वीकारा कि इसके कारण वे ससदीय नियन्त्रण को कठिनाई में मुक्त रहते हैं। उनके अनुसार इस पद्धति का एक प्रमुख दोष यह था कि इसमें अन्तर् चर्चा और अपार देर अन्तर्ग्रस्त रहती थी। सैन्य-विभाग के योगदान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, 'तब तक आवश्यक सुधारों का सूत्रपात नहीं किया जा सका और उपयोगी उपाय नहीं अपनाए जा सके, जब तक कि तर्ज करने वाली और अधिकशक्त, अनावश्यक जालोचना का शिकार न बना जाय और यह आलोचना न केवल प्रस्ताव के वित्तीय प्रभाव को लेकर होती है, बल्कि विशुद्ध सैन्य-दृष्टिकोण से उसकी वाञ्छनीयता या आवश्यकता के प्रश्न को लेकर भी की जाती है।' इस लिए उन्होंने सुझाव दिया कि सेना-सदस्य के बद को समाप्त करके यह पद्धति खत्म कर दी जाय। इस तरह लार्ड किचनर ने सुझाया कि युद्ध-विभाग के प्रमुख का सरकारी नाम कमांडर-इन-चीफ और परिपक्व में युद्ध-सदस्य हो।

सैन्य-विभाग के विरुद्ध लगाये गये आरोपों का मुद्दा प्रतिवाद तत्कालीन सेना सदस्य

मेजर जनरल सर ई० आर० एलेस द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि तग करने वाला और विलम्बकारी न होकर सैन्य-विभाग सेना की कार्यक्षमता के लिए अनेक महत्वपूर्ण उपायों का सूत्रपात करने के लिए उत्तरदायी रहा है, जैसे सामबन्दी योजना, मैदानी सेना का बनाया जाना, प्रेसीडेंसी सेनाओं और विभागों का मिलाया जाना, परिवहन-सेवा का पुनर्गठन आदि। इसके अलावा कमांडर-इन-चीफ के सुभाव ने एक बड़ा महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक प्रश्न छेड़ दिया। भारत की सेना का प्रमुख एक ही है—सपरिपडू गवर्नर जनरल और परिपडू का सेना-सदस्य सभी ऐसे मामलों में जो पूरी परिपडू के सामने नहीं आने, सपरिपडू गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि ही है। दूसरी ओर कमांडर इन-चीफ नियम और चलन के अनुसार सेना की कमान संभालता है। इस स्थिति को स्वर्गीय सर जार्ज वेसनी ने नीचे बिले शब्दों में बड़ी अच्छी तरह निरूपित किया है

‘कमांडर-इन-चीफ’ स्वभावतः अपना प्रस्ताव सैन्य-दृष्टिकोण से भेजते हैं, जो उचित ही है, क्योंकि यदि सेना की ओर से उसके लिए वह जोर नहीं देंगे तो और कोई जोर डाले, यह सम्भव नहीं है। दूसरी ओर परिपडू के सेना-सदस्य को सरकार के पूरे कार्य-कलाप का ध्यान रखना होता है और सेना के ध्येय पर सरकार की वित्तीय स्थिति को देखते हुए ध्यान देना होता है और सपरिपडू गवर्नर जनरल द्वारा तय की गयी नीति का भी ध्यान रखना होता है। यह सब उसके निर्णय पर बैसे प्रभाव डालते हैं, यह एकाधिक विविध उदाहरण से जाना जा सकता है। मैगडाला के लार्ड नेपियर जब परिपडू के सेना-सदस्य थे, तो अपने कमांडर-इन-चीफ के काल की तुलना में वह चीजों को भिन्न दृष्टिकोण से देखते थे।

‘इससे यह बात स्पष्ट है कि कमांडर-इन-चीफ को जो नियंत्रण और हस्तक्षेप पसन्द नहीं है, वह सेना-सदस्य का नहीं, बल्कि सरकार का है।

‘मेरा कहना है कि न केवल वित्तीय दृष्टिकोण से बल्कि राज्य के दूसरे विभागों को प्रभावित करने वाले अन्य पहलुओं की दृष्टि से भी प्रभावी आलोचना न केवल तग न करने वाली है, बल्कि जरूरी भी है। प्रभावी आलोचना में कुछ देर तो हो ही जाती है।

‘हालांकि लार्ड ईंचर की समिति ने यह बात बिलकुल स्पष्ट कर दी थी कि सेना परिपडू (इंग्लैंड में) का काम सेना की प्रशासित करना है, उसकी कमान सम्भालना नहीं, पर लार्ड रिचमर की योजना के अधीन कमांडर-इन-चीफ और युद्ध-सदस्य में सभी प्रशासनिक और कार्यपालक कर्तव्य एकीभूत हो जाते हैं, जो बात किसी भी बड़ी शक्ति की सेना में देखने को नहीं मिलनी। साथ ही सेना-परिपडू गठित करने वाले ‘लेटमें पेटेंट’ के अधीन मेजेटरी ऑफ स्टेट और सदस्य सभी एक समान हैं और सभी के मत बराबर होते हैं, केवल मेजेटरी ऑफ स्टेट अध्यक्ष होता है, पर लार्ड रिचमर के प्रस्ताव के अधीन वे सभी उगते अधीनस्थ होंगे और न उनका मताधिकार होगा और न विमताधिकार ही।’

एवम् १८७० में १८७६ तक कमांडर-इन-चीफ रहे।

१९०३ में लार्ड किचनर ने सेना-मुख्यालय में एक परामर्श-परिषद् बनायी थी, जिसमें उनके अपने ही मातहतों में सम्मुख-कार्य के दोष दूर किए जा सकें और सेना-मुख्यालय के घटक-विभागों को एक दूसरे से ज्यादा निकट लाया जा सके। कमांडर-इन-चीफ को इसके अध्यक्ष में होना, साथ ही परिषद् में एडजुटेंट जनरल, क्वार्टर मास्टर जनरल, सेना-मुख्यालय के कुछ अन्य अधिकारी भी इसमें होते थे। उन्होंने सुझाव दिया था कि पुनर्गठन का उनका प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने पर परामर्श-परिषद् में वे मौजूद रहें जाएँ। कमांडर-इन-चीफ (अध्यक्ष), चीफ आफ जनरल स्टाफ (एक नयी सामान्य मातहत-शाखा बननी थी), एडजुटेंट जनरल, क्वार्टर मास्टर जनरल, आइर्नेस के महानिदेशक और वित्त-सचिव सदस्य रहेंगे और युद्ध-विभाग के सचिव परिषद् के पदेन सचिव होंगे।

उन्होंने सेना-सङ्गठन-समिति, १८७६, के प्रतिवेदन को ओर भी ध्यान आकर्षित किया। उक्त प्रतिवेदन का 'उच्चतम सरकार के एक सदस्य के रूप में कमांडर-इन-चीफ की स्थिति' में सम्मिलित एक उद्धरण नीचे दिया जा रहा है

‘१४१—बहुमन रूप में हमारे विचार में कार्यपालक कमांडर-इन-चीफ की स्थिति परिषद् के एक सदस्य के रूप में ऐसी चीज है, जिसका पूर्व दृष्टान्त किसी भी यूरोपीय सरकार या सेना के सङ्गठन में देखने को नहीं मिलता। यह ठोस प्रशासन के एक बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण सिद्धान्त के विरुद्ध जाता है और सभी प्रशासकों ने, चाहे वे प्रतिनिधायी हों या निरंकुश, सहजबुद्धि और अनुभवों की प्रेरणा ने इसे अस्वीकार कर दिया है।

‘१४२—यह कमांडर-इन-चीफ का सतत कर्तव्य है कि वह सेना के मुखार के लिए ओर अधिक धन के व्यय के लिए सरकार पर जोर देता रहे। सेना के अधिकारी और सैनिक अपने धर्मों पर जोर देने और उनकी ज़रूरतें बनाने के लिए उद्योग की ओर देखते हैं। दूसरी ओर यह भारत सरकार का सतत कर्तव्य है कि भारत के कर्दावाशों के हित में ऐंम खर्च की माँग अस्वीकार कर दे, जिसे वह अनावश्यक या अयुक्ति-सङ्गत या देश की महनशक्ति से परे मानती है। सेना के कार्यपालक प्रमुख के रूप में या भारत-सरकार के अधीनस्थ के रूप में अपने दृष्टि-कोण के समर्थन में यथोचित रूप में पूरा आग्रह कर लेने के बाद उनका अधिकार का कर्तव्य-पूरा हो जाता है, और फिर देश की सरकार के लिए उत्तरदायी लोगों का ही यह दायित्व रह जाता है कि अपनी कर्तव्य-भावना के अनुरूप वे किस सीमा तक उसका अनुरोध मान सकते हैं ...’

सेना-सदस्य के विचारों से सहमत होते हुए भी बाबुराय लार्ड कर्जन ने साथ-साथ यह बात भी कही

पैराग्राफ २७ में ३० में (लार्ड किचनर ने) प्रशासन की अपनी नयी योजना की रूप-रेखा दी है। मुख्य-विभाग अब विस्तृत समर्थ हो जायेगा और उसकी जगह पर आने वाले संगठन के उच्चतम प्रमुख के रूप में कमांडर-इन-चीफ और परिषद् के युद्ध-सदस्य होंगे। सेना की हर शाखा और सरकार का हर सेना-विभाग उसके अधीनस्थ होगा, हर अधिकारी आदेश के लिए, अपने भविष्य और पदोन्नति के लिए उसी ही ओर देखेगा। परामर्श-परिषद् जो उसके सहयोग के लिए होगी, वह सार्वभौम या गणतन्त्र लोगों को न होकर अधीनस्थ लोगों की होगी।

कमांडर-इन-चीफ सभी उपक्रमों का खेत होगा और कार्यपालन का भी एवमात्र साधन होगा। उनके अधिकार पर कोई भी अड़स न होगा, केवल वित्त-विभाग द्वारा वित्तीय मामलों का नियन्त्रण उन रोक संभेगा या भारत-सरकार की मजबूरी की अपेक्षा करने वाले मामलों में वह अनिम प्रतिकार। ये प्रकट मुरदाएँ निष्फल होंगी, क्योंकि सरकार विरोध की महायत्ना और सलाह में दक्षिण रह जाएंगी, जो उनकी प्रभावी बनाने के लिए अत्यावश्यक है।

जमा कि लाईं डफरिंग ने पहले ही समझ दिया था—ऐसी किसी भी व्यवस्था के अर्धीन बायमराय का सेना के प्रतिनिधि को छोड़ कोई और सलाहकार न रह जायेगा और वह भी व्यव या संगठन में परिवर्तन के प्रस्तावों पर आग्रह करने में ही ज्यादा भविष्य लेगा। इस तरह देश का राजन्य कमांडर-इन-चीफ की दया का आविर्भाव हो जायेगा।

मैंने मेना-मुख्यालय द्वारा पेश किये गये ऐसे प्रस्ताव देने हैं, जो सरकार की नीति के मौलिक सिद्धान्तों या स्थिति के वास्तविक तथ्यों में ही अमंगल थे। सरकार के अभिनेत्रों और परम्पराओं से अभिरक्षा के लिए प्रभारी विभाग ही ऐसी किसी युक्ति के विरुद्ध चेतावनी जारी कर सकता है। कमांडर-इन-चीफ ने अर्धीनस्थ प्राविशारियों की जो माता प्रस्तावित की है, वह ऐसी कोई सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती, क्योंकि उल्लिखित मामलों में वर्तमान पद्धति के तत्समाधी अधिकारी ऐसी कोई सुरक्षा नहीं द सकते हैं।

परिपट्ट में सभी अन्य सदस्यों ने साईं किचनर के प्रस्ताव का विरोध किया। एक सदस्य ने तो यहाँ तक कहा 'एक अमैनिश सरकार के नियन्त्रण के प्रति अर्धीरता आक्षेपण का रूप है। सर चार्ल्स नैपियर जब कमांडर-इन-चीफ थे, सब उन्होंने भारत सरकार में सिना पूरे भारतीय सेना का केतन बढ़ाने वाला एक आदेश जारी कर दिया था, और जब उनके कार्य को चुनौती दी गयी, तो उन्होंने तैयारी से यह कहा कि ऐसा करने वह अपने वित्तीय-अधिकार के अधीन ही रहे हैं। सेना-विभाग खत्म हो जाने में सैन्य-व्यय पर कुछ नियन्त्रण रखने में वित्त-विभाग की दिव्यता बड़ जायेगी। तकनीकी जानकारी के बिना व्योरो की हमारी आलोचना सदैव युक्ति-विहीन और अज्ञानपूर्ण होगी।'।

देखने ही यह कहा जा सकता है कि यद्यपि इस चर्चा ने उस समय काफी मनसुनी पैदा कर दी होगी—बस्तुतः ऐसा हुआ भी—पर आज की वास्तविकता में उसका विशेष उपयोग नहीं है और दोनों ओर के तर्कों का आज केवल छात्तीय महत्व ही रह गया है। पतन उपर उद्भूत अवतरण कुछ ज्यादा लम्बे लग सकते हैं। पर मचाई यह है कि यह विवाद बढ़े हो महत्व का था और इसका प्रभाव दीर्घकालीन था, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप जो विभाग बना, वह व्यवहार में १९६९ तक सिना बरने हुए चलता रहा। फिर, उस समय व्यक्त किये गये विचार आज भी रोचक हैं, क्योंकि इनमें कुछ मौलिक तत्व आ जाते हैं। यह ध्यान में रखना होगा कि उस समय भी यह चर्चा बड़ी ओजस्वी बन गयी थी, जब देश की सरकार का काम बानूत और व्यवस्था बनाने रखने के अलावा और कुछ न था। निर्वाचित विधान मण्डलों के (मने ही उनका प्रतिनिधायी स्वयं विस्तृत सीमित हो) दिन अभी बहुत दूर थे, जो कम-से-कम से-य-मामलों की चर्चा हो कर सकते, भने ही उनको प्रभावित न कर पाते। ऐसी स्थिति में लोक-तन्त्रीय ढाँचे में जब सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, इन तर्कों का महत्व बहुत ही



ज्यादा बड़ जाता है, सशस्त्र सेनाओं के कमांडर तो हमेशा ही अपने प्रस्तावों पर शीघ्र और अनुकूल निर्णय के लिए जोर डालते रहेंगे। साथ ही सरकार को राज्य के प्रति अपना कर्तव्य निभाना होगा और किसी निर्णय पर पहुँचने के पहले सैन्य आवश्यकताओं की ध्यानवोन विभिन्न दृष्टिकोणों से कराने होंगे, जैसे देश की सुरक्षा के खतरे का स्वरूप और उसकी सीमा क्या है, सरकार की विदेश नीति क्या है, साधनों की उपलब्धता कैसी है, निर्वाचन-मण्डलों को दिये गये वोटों के प्रमाण में सरकार के सभ्य आदि की पूर्ति कहीं तक होती है यदि लोकतन्त्र में वृत्त और अद्वैत सभी अनुरोधों को जिम्मेवारी मन्त्री की होती है, भले ही सैन्य सलाहकारों ने कुछ भी सलाह दी हो। बिस्मन् चर्चिल ने १९५० में हाउस ऑफ कामन्स में ठीक ही कहा था, 'मन्त्री इस बात का सहारा नहीं ले सकते कि उन्होंने अपने विरोधकों की बात मान ली थी, दूसरी ओर यह बात भी नहीं कही जा सकती कि वे उनकी सलाह नहीं मानते।'।

१९०५ के विचार के अन्त में परिपक्व के विचारों को बताने वाला एक डिस्चैज २३ मार्च १९०५ को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास भेजा गया, जिसके साथ कमांडर-इन-चीफ की एक अनहमति की टिप्पणी भी थी। साबं विचर के प्रस्ताव पर जो मुख्य निष्कर्ष दिये गये, वे इस प्रकार थे

'१५... हम ऐसे संगठन' के बनाये जाने में सहमत नहीं हैं, जिसका समकक्ष, जहाँ तक हम जानते हैं, विश्व की किसी सेना या प्रशासन में नहीं है। यह ऐसे परिवेश में सैन्य-निरंकुशता पैदा कर देगा, जहाँ किसी मसद्दीय या लोक नियन्त्रण की व्यवस्था नहीं है। इसमें बहुत बड़ा खतरा है हमारे विचार से जैसे ही इसे व्यवहार में लाया जायेगा, यह तुरन्त ही एक भयंकर गतिरोप पैदा कर देगा।'

### सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का निर्णय

कमांडर-इन-चीफ, सेना-मन्त्रालय और वायसराय की टिप्पणियों के साथ-साथ भारत-सरकार के डिस्चैज के मिलने पर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने भारत के सैन्य प्रशासन का धारा प्रदत्त इंडिया आफिस की एक उच्चस्तरीय समिति को सौंप दिया और अन्त में अपना निर्णय डिस्चैज सत्या ६६, तारीख ३१ मई, १९०५ द्वारा भेज दिया। उनका विचार था कि वायसराय की परिपक्व में सेना के प्रश्नों पर विशेष राय देने के प्रयोजन में दो अधिकारों रहना अवाञ्छनीय है और उन्होंने निर्णय दिया कि विमुक्त सैन्य सेवायें कमांडर-इन-चीफ के नियन्त्रण में होनी चाहिये, जिसका माता कमांडर-इन-चीफ के साथ नूतनपूर्व सेना-मन्त्रालय की अपेक्षा भिन्न होगी। इस तरह कमांडर-इन-चीफ को बर्मान, माउहूतो और रेजीमेंट की नियुक्तियाँ, पदोन्नति, अनुशासन, प्रशिक्षण, सङ्गठन, सेना-वितरण, गुप्तचर्या, सामग्र्य, आक्रमण और रक्षा की योजनायें, युद्ध लंगारी (सामग्री की पूर्ति को छोड़) और युद्ध-संचालन के लिए सपरिपक्व पवनर जनरल के प्रति सीधे उत्तरदायी बना दिया गया। परिपक्व के दूसरे सदस्य के वृत्त्य, जो एक नये विभाग का भारसाधक होगा, सेना के टेको का नियन्त्रण, भण्डार, आर्बिनेंस और नये घोड़ों की सरीद, सैन्य निर्माण-कार्यों का प्रबन्ध, कपड़ा और निर्माण-विभाग, भारतीय चिकित्सा सेवाएं और भारतीय नौ सेना तक ही सीमित रहे गये। दस्तुतः सैन्य-विभाग का कार्य दो

विभागों के बीच बाँट दिया गया, एक सेना-विभाग था, जो परिपक्व के सैन्य के रूप में कमांडर-इन-चीफ के सीधे अधीन था, और दूसरा था सैन्य-पूर्ति-विभाग। सैन्य-पूर्ति के भार-माध्यक का काम सपरिपक्व गवर्नर जनरल को विमुक्त सैन्य प्रदनों में भिन्न सामान्य नीति के प्रदनों पर मलाह देना था। यह सदस्य भी एक सैन्य-अभिवारी ही होता था, जिसे भारत का बाकी अनुभव हो और जिसमें प्रशासनिक क्षमता हो और जो भारतीय सेना के गुणों से निरुद्ध से परिचित हो। उमके कृत्य सैन्य-ज्ञान और अनुभव वाले एक अमेरिकी अधिकारी जैसे ही थे। प्रत्येक विभाग का अलग सचिवालय भारत-मरकार के एक सचिव के अधीन बनाया गया।

### सामान्य अमला-शाखा की रचना (१९०६)

कमांडर इन-चीफ को निरन्तर घड़ते हुए कार्यों को करने में समर्थ बनाने के लिए एहायता देने की दृष्टि में सेनेटरी ऑफ स्टेट ने उच्च हैमियल के एक अनिरिक्त सेना-अधिकारी को नियुक्त करने का भी निर्णय लिया, जो कमांडर-इन-चीफ के चीफ ऑफ स्टॉफ के रूप में था। उसे सत्रियागत आयोजन, गृहचर्या और प्रशिक्षण आदि का काम सौंपा गया। इस तरह सामान्य अमला-शाखा ने जन्म लिया। सेनेटरी ऑफ स्टेट के निर्णय में यह भी कहा गया कि स्थान रिक्त होने पर अगर कमांडर-इन-चीफ प्रिटिंग सेना का अधिकारी हो, तो उसके नीचे के तीन प्रमुख अधिकारियों में से अर्थात् चीफ ऑफ स्टॉफ, एडजुटेंट जनरल और क्वार्टर मास्टर जनरल में से दो भारतीय सेना में से चुन कर भरे जाने चाहिये, इसके विपरीत यदि कमांडर-इन-चीफ भारतीय सेना का एक अधिकारी हो, तो इन तीन अधिकारियों में से दो प्रिटिंग सेना में से लिने जायें। इस तरह सैन्य मामलों में कमांडर-इन-चीफ भारत सरकार का एवमान-सलाहकार बन गया।

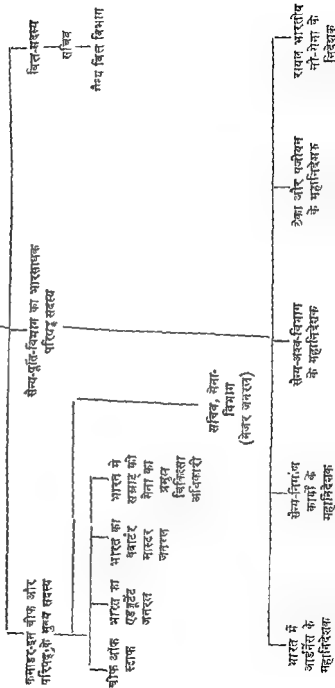
### सैन्य-वित्त-विभाग की रचना

जब पुराना सैन्य-विभाग अपने कटे-कटे रूप में कमांडर-इन-चीफ के अधीन आ गया, तो सैन्य ध्यय के ऊपर समुचित वित्तीय नियन्त्रण के लिए अब यह उपयुक्त न रहा कि सैन्य-सेवा-विभाग के भारमाध्यक नियन्त्रण के रूप में सैन्य महासलाहकार नये सेनाविभाग के अधीन बना रहे। इसलिए एक तीसरा विभाग सैन्य-वित्त-विभाग नाम से बनाया गया (१९०६), जो समुक्त वित्तीय मन्त्र के अधीन था (जिसे बाद में वित्तीय सलाहकार नाम दिया गया)। वह वरिष्ठ वित्त मन्त्र और वित्त के प्रभावी परिपक्व-मदस्य के नियन्त्रण में था। इस तरह सैन्य-वित्त-विभाग का जन्म हुआ। उसके निर्णय के फलस्वरूप १९ मार्च १९०६ में जो संगठन-दोष बना, वह एक आरेख में बताया जा रहा है।

आ रे ख-२

परिषद् के रोना-सदस्य के पद की समाप्ति के बाद का  
सन्दर्भ डीचा (१९०६)

सपरिषद् गवर्नर जनरल



उपयुक्त निर्णयों को विषयनिष्ठ दृष्टि से देखा जाय, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से वे ठोस और उभयुक्त ही थे। कमांडर-इन-चीफ ने यह आपत्ति की थी कि उसके प्रस्तावों की जाँच परिषद् के एक अन्य सदस्य से द्वारा नहीं होनी चाहिये, जो सेन्य-मद के हिसाब से उसने कनिष्ठ होना था, और इसीलिए अनुमति में भी। आपत्ति को और जानदार बनाने वाली एक बात यह भी थी कि सेन्य-विभाग का सचिव, जिसके कर्तव्य और दायित्व भारत-सरकार के दूसरे सचिवों जैसे ही थे, वायसराय के पास सीधे ही पहुँच सकता था। सचिवालय की नियुक्तियों बात दूसरे भी सेन्य अधिकारी सेन्य विभाग में थे, जो सेना मुख्यालय में आने वाले सभी प्रस्तावों पर टीका-टिप्पणी कर सकते थे। (ये अधिकारी सेन्य-विभाग में तीन साल की अपनी पदावधि पूरा करने के बाद कमांडर-इन-चीफ के अधीन ब्रह्मण या स्टाफ नियुक्तियों पर भेजे जा सकते थे)। इस तरह आशा के विपरीत सेन्य-विभाग में अमेनिक अधिकारी न थे। बहुत समय तक सेन्य विभाग के अधिकारी भारतीय सेना में सीमित पदावधि (अर्थात् तीन साल) की नियुक्तियों पर सेना मुख्यालय के अधिकारियों की तरह आने रहे। दूसरी ओर परिषद् के दूसरे सदस्यों ने यह जल्दी समझा कि सरकार के सामने आने वाली सभी समस्याओं के बारे में स्वतन्त्र सेन्य सलाह प्राप्त करें। यद्यपि सेन्य विभाग के अधिकारियों में यह आशा की जाती थी कि वे प्रस्तावों को विपुल सैनिक दृष्टि से न देख कर व्यापक दृष्टि से देखेंगे, फिर भी यह तो तथ्य ही था कि सेन्य अधिकारी के रूप में वे कमांडर-इन-चीफ के अधीनस्थ बड़े ही कनिष्ठ अधिकारी होते थे। यह बात भी नगण्य हो जाती है, जब हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण मामलों पर अन्तिम निर्णय लेने के लिए भारत-सरकार भी सन्नम नहीं थी। सेन्य (और अमेनिक) समस्याओं पर भारत-सरकार का यत्न निश्चिन्त करने के लिए तन्त्र या कार्यविधि कैसी भी क्यों न हो, इन सभी प्रस्तावों पर अन्त में मेजेटरी ऑफ स्टेट की मंजूरी प्राप्त करनी होती थी। इसलिए इस बात की सम्भावना न थी कि परिषद् के किसी एक सदस्य के हाथ में सत्ता केन्द्रित हो जायेगी (उसकी प्राप्ति और कीर्ति कुछ भी क्यों न हो) भारत-सरकार के इशारे पर अपना आदेश भेजते हुए मेजेटरी ऑफ स्टेट ने स्वयं यह स्पष्ट किया कि कमांडर-इन-चीफ के प्रस्तावों पर किसी भी हाल में परिषद् के वित्त-सदस्य और रित्त की आलोचना तो आयेगी ही। राजनीतिक रूप से उन सभी प्रस्तावों की समीक्षा परिषद् के पाँच-छह दूसरे सदस्य भी करेंगे और महान् चर्चा करने वाले गवर्नर जनरल ही सबसे ऊपर उठें देखेंगे। यह बात भी लिया जाये कि सभी वाद्यों दूर हो गये, तब भी महत्व वाले किसी भी आदेश का सपरिषद् मेजेटरी ऑफ स्टेट के पास भेजना होगा। भारतीय सेन्य मामलों के बारे में अपने प्रमुख महासूत्र के रूप में मेजेटरी ऑफ स्टेट के पास भारतीय सेना का एक उच्च पद वाला अधिकारी होता है, जो सामान्यतः लेफ्टिनेंट-जनरल होता है और उसका भारत का अनुमति प्राप्त होता है तथा वह इंडिया आर्म्स के सैन्य विभाग का सचिव होता है और भारत सम्बन्धी सभी सैन्य मामलों की परीक्षा करता है। फिर ये मामले भारत की परिषद् की एक या अधिक समितियों को भी जाते हैं, जिनमें भी अनुमति दीय अधिकारी होते हैं। (याच हो इंडिया आर्म्स का मार्ग-

दर्शन सम्राट् का युद्ध-कार्यालय और नौ-सेना कार्यालय करता है, जो साम्राज्य के दृष्टिकोण से खानेजी की वृहत्तर बातों को ध्यान में रखने है) । फिर इन प्रस्तावों पर सपरिपद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट निर्णय लेते हैं । कहना न होगा, दूरगामी महत्व के मामले ब्रिटिश मन्त्रि-मण्डल तक जाते हैं ।

नये सैन्य-पूति-सदस्य के कार्यक्षेत्र और पहले व्यक्ति का चुनाव करने के लिए जो पत्र-व्यवहार चला, उसकी चर्चा आवश्यक नहीं है । इसके जन्त में वायसराय लार्ड कर्जन ने अनुभव किया कि—

सैन्य पूति-विभाग वित्तकुल असमर्थ बनकर रह जायेगा और सैन्य-पूति सदस्य के पद की रचना सार्वजनिक धन के अक्षम्य अपव्यय का कारण होगी और यह ज्यादा अच्छा होगा कि विभाग और सदस्य दोनों को ही न रखा जाय ।

इस मामले में लार्ड कर्जन की भावनाएँ उन्ची सिद्ध हुईं । यह व्यवस्था न तो प्रशासन और न बजट की दृष्टि से ही ठीक सिद्ध हुई (जैसा कि भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लार्ड मारले ने बाद में बताया) और सैन्य-पूति-विभाग १९०६ में समाप्त कर दिया गया । इस विभाग की समाप्ति के बाद आइर्नसे के महानिदेशक भी, जिनको बाद में आइर्नसे का मास्टर-जनरल कहा गया, एक प्रमुख स्टाफ अधिकारी बन गये । तब स सेना के प्रशासन, भारत-सरकार को सैन्य नीति के निर्माण और कार्यान्वयन, भारत पर आधारित सैन्य-सक्रिया का निर्देशन आदि को केवल एक ही अधिकारी अर्थात् कमांडर-इन-चीफ और सेना-सदस्य को ही सौंप दिया गया । यह स्थिति यथार्थतः सितम्बर, १९४६ में अन्तरिम लोकप्रिय सरकार बनने तक चलती रही ।

### सैन्य-वित्त-विभाग की जिम्मेदारियाँ

अब हम सैन्य वित्त-विभाग की रचना की बात को फिर सेते हैं । वित्तीय सत्ताहकार सेना-विभाग में वित्त-विभाग का प्रतिनिधि था । वह महामहिम कमांडर-इन-चीफ और सेना-सदस्य का सैन्य-व्यय सम्बन्धी सभी मामलों में विरोध सत्ताहकार भी था । उसे सेना-विभाग से न केवल व्यय की अनियमितताएँ रोकने के लिए संलग्न किया गया था, बल्कि उसको सिप्रता और बचत के साथ सैन्य-कार्य का निपटारा करने में उस विभाग की मदद देने के लिए भी रखा गया था । यह उसका कर्तव्य था कि व्यय वाले सभी प्रस्तावों की विलीय सिद्धान्तों और कोर-बजट की दृष्टि में दायरवीर नये, यह सत्ताह दे कि क्या उसके स्वीकार किया जा सज्जा है और यह देखे कि नियमों के अधीन सरकार या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की मजूरी जरूरी होने पर प्राप्त की गयी है या नहीं ।

संक्षेप में १९१४ में प्रथम विश्व-युद्ध गुरु होने से ठीक पहले सपरिपद गवर्नर जनरल भारत में सेना का सर्वप्रमुख था । सेना का प्रशासनिक नियन्त्रण महामहिम सेना-सदस्य (और कमांडर-इन-चीफ) के अधीन सेना-विभाग के हाथ में था । सेना-सदस्य गवर्नर जनरल की परिपद का सहायक सदस्य था । भारत सरकार के आदेश संवूचित करने वाले सभी पत्रादि भारत-सरकार के सेना विभाग के सचिव या उसके नाम से जारी किये जाने पे । वह विभाग को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, स्थानीय सरकारों और प्रशासनों तथा ईस्ट इंडीज स्वेडिन के नौसेना

कमांडर-इन-चीफ (जो भारत सरकार के नीतिना महाह्वार थे) के साथ सारा पत्राचार करता था। सरकार के दूसरे विभागों के साथ भी पत्राचार मेला विभाग के द्वारा ही किया जाता था। जेवन मेला मुन्शायन की शाखाओं को यह छूट थी कि अन्य विभागों में ऐसी दैनन्दिन पूछताछ योग्य-योग्य कर लें, जिनके बारे में सरकारी आदेशों की अपेक्षा नहीं होती थी।

गना-विभाग का काम मेला-मुन्शायन की शाखाओं के प्रमुखों के रूप में नीचे लिखे अधिकारियों के अंगीत बाटा गया था

चीफ आफ दि जनरल स्टाफ

एडजुटेंट जनरल

क्वाटर मास्टर जनरल

चिक्किमा-पेशा-निदेशक

मेन्स सचिव

आदम के महानिदेशक (बाद में नामकरण जाईनेम के मास्टर जनरल किया गया)  
मन्स-निर्माण-शाखों के महानिदेशक (बाद में नामकरण इजीनियर इन चीफ किया गया)।

### प्रस्ताव भेजने की समोधिग कार्यविधि-मेला-विभाग की स्थिति

नये ढांचे में कार्य निरटाने की समोधिग कार्यविधि पर ध्यान दे लेना जरूरी है। पुराने मेन्स विभाग की भूमिका समान हो चुकी है। मेला विभाग में अब यह प्रत्याना नहीं की जाती कि उसके पास जाने वाले प्रस्तावों की वह स्वतन्त्र छानबीन करे और न वह इस स्थिति में ही था कि काम की गुण्जात वह स्वयं करे। पुराने मेन्स विभाग में नये विचारों का सूत्रात किया जाता था और मण्डल के बाहर में जाने वाले प्रस्तावों की जांच पहले विभाग में ही की जाती थी और उसके बाद ही संपादक्यक मेला-मुन्शायन की सम्बन्धित शाखा या कमांडर इन चीफ के टिप्पणी समोधिग जाती थी।

जब मन्स विभाग अस्तित्व में था, तब मेला मुन्शायन में जाने वाले सभी प्रस्ताव पहले उस विभाग में भेज जाते थे। नयी व्यवस्था के अंगीत जिन जाने ऐसे सभी प्रस्ताव जब पहले मन्स-विभाग के पास भेज जाते हैं, वो उस पर टिप्पणी करके सम्बन्धित शाखा को लौटा देता है। यदि विभाग न विचार सम्बन्धित निदेशक की स्वीकार हो, या जब मामला प्रमुख स्टाफ अधिकारियों के ध्यान में लाने लायक पर्याप्त महत्व का हो, तो फाइन मेन्स-विभाग के पास आकर उस समोधिग, आदेश या उत्तर प्रस्तुत करने के लिये लौटा दी जाती थी। इन समोधिग के मान मेन्स विभाग फाइलों से या तो सम्बन्धित शाखा के पास भेज देता था, या मेला विभाग के सचिव के पास, जहाँ से सरकार के आदेश जारी होते थे। इस तरह नयी प्रणाली में मेला विभाग के पास मेला सम्बन्धी किसी मामले में कुछ सूत्रात करने की गुंजायत न रही थी। सभी मामलों को विलीय जांच मेन्स-विभाग करता था, ऐसे मामलों की भी नही गना-विभाग द्वारा जारी किये जाते वाले सरकारी आदेशों के समोधिग भी बनाने होते थे। इस अनुकूल ही मेला-विभाग में बाहरी समोधिग में प्राप्त सभी पत्र प्राप्त बिना छुट्टे ही गना-मुन्शायन की सम्बन्धित शाखा के पास भेज दिये गते थे। जेवन रॉयल इंडियन मेरीन,

चर्चसम्बन्धी विषय, भारतीय चिकित्सा-सेवा, (मृत अविहारियों की) सम्मदायें, और पदको वाली फाइलें पहले-पहल सेना विभाग में खोली जानी थीं। इन मामलों में आदेश कार्य-नियमावली प्रीर सचिवालय अनुदेशों के अनुसार निकाले जाने थे, क्योंकि ये नियम और अनुदेश समान रूप में सेना-विभाग पर भी लागू थे। सेना-विभाग के जरिए पत्र प्राप्त होने पर सम्बन्धित शाखा एक नयी फाइल खोल लेती थी या उस विषय की पहचान से विद्यमान किसी फाइल के होने पर, उस पत्र को उस फाइल में रखकर, सारी जरूरी कार्रवाई करती थी और सैन्य-वित्त विभाग के साथ पर्यावश्यक सीधे परामर्श कर लेती थी। सेना-मुख्यालय की शाखाओं में यह प्रथाया की जाती थी कि पूरे फाइल सरकारी आदेशों के मसौदों सहित प्रस्तुत करें, वासरर वर उनसे मामलों के निरटारने में सुविधा होने की सम्भावना हो। फिर भी उनकी मेजेटरी ऑफ स्टेट या स्थानीय सरकार और प्रशासनो के साथ पत्राचार करने की अनुमति न थी, न वे सेना-सदस्य की हैसियत में कमांडर-इन-चीफ में हो किसी प्रस्ताव का अनुमोदन प्राप्त कर सकती थी। लेकिन ऐसे तकनीकी या दैनन्दिन मामलों में वे इंग्लैंड में नोवेना या युड-गर्पा-लय से पत्राचार कर सकती थी, जिन पर मेजेटरी ऑफ स्टेट या भारत-सरकार के आदेशों की जरूरत न थी। मेजेटरी ऑफ स्टेट आदि से पत्राचार की अपेक्षा करने वाले सभी मामले आवश्यक कार्रवाई के लिए सेना विभाग के पास भेजने होते थे, पर वह विभाग एक प्रतिष्ठित डाकघर मात्र था।

विभाग के सचिव के पास भी दूसरे सचिवों जैसी शक्तियां थी और वह ठीक समझे तो किसी भी समय कोई मामला सीधे गवर्नर जनरल के पास भेज सकता था। सीधे पहुँच की यह व्यवस्था सितम्बर, १९४६ तक बनी रही।

भारत-सरकार सचिवालय के अन्य भागों के साहस्य पर, इस विभाग और इसके मनन और अधीनस्थ कार्यालयों का काम, सेना मुख्यालय की शाखाओं में प्राप्त संयुक्त हो जाता था। सेना-मुख्यालय के शाखा-प्रमुखों के दृश्य दुहरे थे। वे कमांडर-इन-चीफ के स्टाफ अधिकारों में और उनके निर्णयों की कार्यनिधि के लिए जिम्मेवार थे। साथ ही वे कमांडर-इन-चीफ के निर्देश से सेना सम्बन्धी उन मामलों का सूत्रपात भी करने थे, जिन पर भारत-सरकार या मेजेटरी ऑफ स्टेट के आदेशों की जरूरत होती थी। विद्वने प्रकार के मामले पहले सीधे वित्त-विभाग ले जाये जाने थे और वे सेना-विभाग तक अन्तिम रूप में ही पहुँचने थे। सरकार के आदेश निवानने के लिए जिम्मेवार भारत-सरकार का यह विभाग यन्त्रवा हो रह जाता था। इस तरह सैन्य-वित्त-विभाग पर जो जिम्मेवारी आ जाती थी, वह प्रत्यक्ष है। प्रशासनिक विभाग कमांडर-इन-चीफ के अवान आ जाने में सैन्य-व्यय की कोई स्वतन्त्र आँच केवल सैन्य-वित्त-विभाग द्वारा ही की जा सकती थी। रक्षा-नेताओं का आय-व्यय तैयार करने का काम, व्यय की प्रगति पर ध्यान रखना (यह सब काम पहले सैन्य-विभाग करता था), वस्तुतः सैन्य व्यय सम्बन्धी सारी जिम्मेवारी अब इस विभाग पर आ गयी। स्वभावतः इस प्रक्रिया में सैन्य-वित्त-विभाग के अधिकारियों को सैन्य मामलों में काफी गहरा ज्ञान हो जाता था और आगे के वर्षों में सैन्य-व्यय की प्रभावी द्दानबोध करने में बड़ी समर्थ रहे। यह अनि-वार्य हो गया कि उस भीमा तक सेना-विभाग के अधिकारों (और उनके उत्तरवर्ती विभाग

के ) वमश ज्ञान और प्रभावना में पीछे पड़ गये, क्योंकि कोई उपजम उनके हाथ में न रह जाने से गम्भीर रूप में कुछ काम करने के लिए उनके पास कोई प्रोत्साहन न रह गया था । सेना-विभाग की यह घटने वाली और सुन्ध भूमिका सत्ता-हस्तान्तरण तक और उसके कुछ समय बाद तक बनी रही । सौजन्यी टांके में नयी और अदृष्टपूर्ण जिम्मेवारियाँ सम्भालने के मामले में भी इसका प्रभाव बना रहा ।

### सलाहकार परिपद्

सेना-मुख्यालय सेना-विभाग और सैन्य-वित्त-विभाग के बीच समुचित सहयोग और समन्वय की दृष्टि से एक सलाहकार परिपद् बनायी गयी थी ( जिसका सचिवान सेनेटरी ऑफ स्टेट ने १९०६ में मजूर किया था ), जो सेना में सुधार करना, युद्ध की तैयारी करना आदि घटे-घटे प्रश्नों पर चर्चा करती थी । परिपद् का गठन इस तरह था —

महामहिम सेना-मदस्य	अध्यक्ष
चीफ ऑफ जनरल स्टाफ	सदस्य
सचिव, सेना-विभाग	
वित्तीय सलाहकार, सैन्य-वित्त	
एडजुटेंट जनरल	
क्वार्टर मास्टर जनरल	जब विचाराधीन विषय का सम्बन्ध मुख्यतः उनकी शाखा से हो
महानिदेशक, सैन्य-निर्माण-कार्य	
आर्टिलरी महानिदेशक	
चिबिल्टा-मेवा-निदेशक	
सैन्य-भूमिया-निदेशक	पदेन सचिव
भारतीय चिबिल्टा-मेवा-महानिदेशक	सह-सदस्य

जसा कि नाम से ही स्पष्ट है, परिपद् ब्रितिश सलाहकारों का नाम था और उसमें कोई सामूहिक उत्तरदायित्व न था ।

### प्रथम विश्व-युद्ध और भारत-भरकार-अधिनियम, १९१९

यही हीना प्रथम विश्व-युद्ध के दौरान चलता रहा । विश्व-युद्ध छिड़ जाने पर भी, जिसमें भारतीय सैनिकों को सक्रिय सैन्यचर्चा के लिए विदेश भेजा गया, सेना में १९१८ तक किंग कमीशन प्राप्त कोई भी भारतीय न था ।

भारत-भरकार-अधिनियम, १९१९ ने भारत को कुछ सीमा तक स्वायत्तता की व्यवस्था के साथ एक नया सचिवान दिया, पर सेना-प्रशासन के मामले में उसके अधीन कोई परिवर्तन न हुआ । कमांडर-इन-चीफ पदों की तरह गवर्नर-जनरल की परिपद् के सदस्य बने रहे, लेकिन अधिनियम में यह व्यवस्था की गयी कि परिपद् में उनकी हैगियन और प्राथमिकता गवर्नर



जनरल के बाद हो होंगी। केन्द्रीय विधान-मण्डल को विनष्ट नया रूप दिया गया। अब दो सदस्य रहे गये; विधान-सभा जिसमें सदस्यों का निर्वाचित बहुमत था और राज्य-परिषद् (कौन्सिल ऑफ स्टेट), जो बड़े हो सकीं मताधिकार से चुनी जानी थी। केवल अमेरिकी आध्यक्षक ही विधान-सभा के सदस्य रखा जाया था, पर मगर जनरल को शक्ति थी कि वह आध्यक्षक या उसके, विधान-सभा के द्वारा मनोद्विज, किनी भी सद को प्रस्तावित कर दे। कनाडा-इन-चीफ को राज्य-परिषद् का एक सदस्य नामित किया गया और नेना-सचिव को विधान-सभा का। रक्षा और चर्च सम्बन्धी मामलों का व्यय विधान-मन्त्र के समक्ष मजबूत के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाया था और अन्य चीजों के साथ-साथ इन विषयों पर भी अब एक मगर जनरल जनरल अध्यक्ष निवेश न दे, विधान-मन्त्र या राज्य-परिषद् में चर्चा नहीं की जा सकती थी। भारतीय विधान-मन्त्र को कोई शक्ति न दो गयी थी कि मन्त्र नेनाओं के विहित सदस्यों पर लागू होने वाले कानून बना सके, बने हों वे स्थानों रूप में भारत में निवृत्त हो।

### एगार समिति १९१९-२०

प्रथम विश्व-युद्ध की समाप्ति पर भारत की सैन्य-प्रशासन-पद्धति की जांच भारत-नेना-समिति द्वारा, जिने एगारातर एगार समिति के नाम से जाना जाता है, १९१९-२० में की गयी। इन समिति ने यह बहुत ध्यानपूर्वक समझा कि उसी स्थिति के कनाडा-इन-चीफ और नेना-विभाग का भारताधिक सदस्य होने में जो कृत्य-क्षेत्रता या जाड़ी है, उसे समझ कर दिया जाय। उनका मुख्य तर्क यह था कि विद्यमान व्यवस्था में कनाडा-इन-चीफ के ऊपर काम का बहुत भारी बोझ आ पड़ता है, क्योंकि उसे परिषद् के सामने आने वाले सभी कारक-मन्त्र देखना और उन पर टिप्पणी करना पड़ती है और परिषद् की बैठकों में जाना पड़ता है। इनके अलावा वह नेना-विभाग का भारताधिक भी होता है और मन्त्र नेनाओं का कारक-मन्त्र-प्रमुख भी। समिति के बहुमत ने यह सिद्धांत की कि बारसराय की एगारातर-कौन्सिल में एक अमेरिकी-मन्त्र-सदस्य निवृत्त किया जाय, जो सैन्य-मूर्ति के उत्साह और व्यवस्था के लिए उत्तरदायी हो। अन्यथा का विचार था कि उत्साह और व्यवस्था करना कनाडा-इन-चीफ को नयन-सावि सैन्य-परिषद् की सीट दिया जाय। अन्त में समिति द्वारा इस बारे में की गयी सिद्धांत का कुछ भी फल न हुआ।

जैसा पहले बताया जा चुका है, नेना-विभाग के सचिव के भी वही फर्जन और जनरल-सचिव थे, जैसे कि भारत सरकार के अमेरिकी विभागों के दूसरे सचिवों के। फिर भी जाने अन्य सहयोगियों से विभिन्न वह एक सैन्य अधिकारी था—जेनरल जनरल सी हेन्ड्रिक्स का। एगार समिति ने पद्धति के इस रूप पर दोर आलोचन की। फलस्वरूप १९२१ में नेना-विभाग

१. भारत सरकार में सचिव, संयुक्त सचिव और उपसचिव के दर आर्द २०० एगार के लिए आरक्षित रहें थे, पर ये पर मेनर, नौ-नेना, शिक्षा, विदेश, उद्योग-विकास और नौ-विभाग-विभाग में इस तरह आरक्षित न रहें थे (भारत-सरकार-समिति-मन्त्र, १९१९ की तीसरी अनुसूची देखिए)। इनमें नेना-विभाग में वरिष्ठ पदों पर काठो समय में सैन्य अधिकारी रहें जाने थे।

के सचिव का पद एक अमेरिकी को मिलने लगा। यही बात विम्वय की है यह परिवर्तन करने में टुनी देर लगी।

एयर समिति की सिफारिशों के पत्रम्बन्ध सेन्य-विन-विभाग को, सेना मुख्यालय की जगह मन्त्रालय शाखाओं के साथ एक ठो विनीय सलाहकार नियुक्त करके, सेना-मुख्यालय के जगह निवृत्त न आया गया। विनीय सलाहकार और उसके जिरादी प्रभाव बनान में अनौपचारिक सहायता देने के लिए सेना-मुख्यालय के अधिकारियों के लिए मुनम बने रहे। उपविनीय सलाहकार का कर्तव्य था कि विन-विन निदेशान्तों के साथ के संगत थे, उनमें उपरान्त होने का न विनीय प्रदनों के बारे में, प्रभावित की सहायता करें और उंग सलाह देने रहे और साथ ही प्रमुख स्टार अधिकारियों को उनके बापिक अनुमान-पत्र बनान में मदद देने रहे।

यह देखा जायेगा कि कमांडर-इन-चीफ को पूर्वोन्तिवित्त परिपद उस समय तक सक्रिय रूप में अग्नित्व में न जाने पाये थी, जब एयर समिति ने संगठन के बारे में प्रतिवेदन दिया क्योंकि, समिति ने उच्च स्टार अधिकारियों तथा अन्य लोगों में बनी एक परिपद को म्यामता की सिफारिश की थी, जो कमांडर-इन-चीफ को उसके प्रभावितिक कृत्यों के पान में मदद दे सके। समिति ने काफी जोर दिया कि विनीय सलाहकार भी परिपद में रहे और इस तरह शाखाओं के सेन्य-प्रमुखों का एक साथी रहे, जो आलोचक नहो। इस तरह परिवर्तित रूप में अग्नित्व में आने का न सेन्य परिपद की रचना इस प्रकार से की गयी थी—

कमांडर इन चीफ (अध्यक्ष)

चीफ जनरल स्टार

एड्यूटेंट जनरल

क्वार्टर मास्टर जनरल

सचिव, सेना-विभाग

विनीय सलाहकार, सेन्य-विन

इस परिपद के अग्नित्व में आ जाने में सेना-सदस्य द्वारा विनी ऐसी सिफारिश नामजूर कर देने की सम्भावना न रही, जिसे वह कमांडर-इन-चीफ के रूप में अनुमानित कर चुका था। परिपद का रूप मुख्यतः सलाहकार का था। उससे कोई सामूहिक जिम्मेदारी न थी। उसकी बैठकों के पत्रम्बन्ध जिसे गये निर्णय कमांडर-इन-चीफ के थे, परिपद के नहो। पर इस परिपद के जरिए वह आका फैला करने में पहले नीति के किसी प्रश्न पर सेन्य, प्रभावित और विनीय दृष्टि में, इसके सदस्यों के मुनिवित्त विचार जान सजता था। यह परिपद इस विश्व-युद्ध के आरम्भ तक चली रही, भले ही इसकी सदस्यता में उपरुक्त परिवर्तन किसे आते रहे।

### गो-सेना

जब नौ-सेना और संगठन नया सेना वायु-सेना के विभाग की कहानी का वर्णन किया जा सजता है। भारत में नौ-सेना का जन्म मई १९१२ में हुआ जा सजता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहाजों का एक छाट-सा बड़ा संग्रह भरा था, जो कमानों और उसके वेद

का मुख्यालय बना रहा। १८६१ में भारतीय नौ-सेना का मुख्यालय सूरत में बम्बई आ गया। १८३० तक इसे बम्बई मेरीन कहा जाता था, १८३० से १८६२ तक इसे भारतीय नौसेना कहा गया, पर १८६३ में पुराना नाम फिर चल पड़ा। १८७७ में एक पुनर्गठन के बाद इसे इंडियन मेरीन कहा गया। जिन उद्देश्यों के लिए इसे खड़ा किया गया था, उन्हें भारतीय मेरीन-सेवा-अधिनियम, १८८४ में बता दिया गया था, अर्थात् सैनिकों को ले जाना, अपराधियों की बातों की रखवाली, जन-दस्सुता रोकना, समुद्र-तटों और बन्दरगाहों का संरक्षण, प्रकाशगृहों की देखभाल, सकटग्रस्त और भ्रम पोतों की सहायता पहुँचाना और अन्य स्थानीय उद्देश्य। पर जलदस्सुता रोकना कभी भी निश्चित कर्तव्य के रूप में इसे न सौंपा गया। उपर्युक्त प्रयोजन १९२८ तक मेरीन के मूल उद्देश्य बने रहे। १८९२ में रॉयल नाम जोड़ दिया गया और यह सेवा रॉयल इंडियन मेरीन कही जाने लगी। १९२८ में इस सेवा को लड़ाकू रूप में पुनर्गठित कर दिया गया और छ साल बाद, भारतीय नौसेना (धनुसासन) अधिनियम के पास हो जाने के बाद, यह = मितम्बर, १९३४ से रॉयल इंडियन नेवी बन गयी। रॉयल इंडियन मेरीन में भी १९३२ तक कोई भी भारतीय कमीशन-प्राप्त अधिकारी न था।

रॉयल इंडियन मेरीन पहले सैन्य-विभाग के अधीन थी, पर १९०६ में उसे नवगठित सैन्य-मूर्ति-विभाग के अधीन कर दिया गया, और फिर, १९०९ के बाद उस विभाग के खतम हो जाने पर, यह सीधे-सीधे कमांडर-इन-चीफ के अधीन आ गयी। उस समय यह सेना एक निदेशक के अधीन थी, जिसका कार्यालय बम्बई में था। १९३४ में इसके रॉयल इंडियन नेवी बन जाने पर इसने कमान अधिकारों को पतेग अफ़्तर कमांडिंग, रॉयल इंडियन नेवी कहते थे। इसका मुख्यालय अब भी बम्बई में ही था। १९४० में मुख्यालय जमला भेज दिया गया, ताकि रक्षा-मुख्यालय के निकट रहे और अब इसे नौसेना-मुख्यालय कहा जाने लगा। रॉयल नेवी के ईस्ट इंडीज स्क्वेड्रन के महामहिम, नौसेना कमांडर-इन-चीफ, पूरे ब्रिटिश काल में भारत सरकार के नौसेना सहायकार बने रहे।

## वायु-सेना

भारतीय वायुसेना तीनों सेनाओं में न सेवने लगी है। केन्द्रीय विधान-मण्डल द्वारा पास किये गये भारतीय वायुसेना अधिनियम के ८ अक्टूबर १९३२ में प्रभाव हो जाने के बाद, १ अप्रैल १९३३ में इसने जन्म लिया।

पहले विश्वयुद्ध के दौरान ही बहुत से भारतीय रॉयल फ्लाइट कोर में अधिकारियों के रूप में लिये गये थे। (रायल फ्लाइट कोर १९१९ में रॉयल एयर फोर्स बनने तक इंग्लैण्ड की सेना का एक अंग था)। ऐसे दो अधिकारियों लड़ाई में काम आये थे और एक को सुविशिष्ट उड़ान क्रॉस प्रदान किया गया था। रॉयल फ्लाइट कोर की पहली टुकड़ी दिसम्बर, १९१५ में भारत पहुँची और व्रमदा १९१९ में उसकी संख्या कुछ बढ़ गयी। जब उस साल इंग्लैंड में रायल एयर फोर्स एक अलग सेवा विभाग बन गया, तब भारत में इस सेवा को भारतीय रॉयल एयर फोर्स कहा जाने लगा। १९३३ में, एक अलग भारतीय वायु-सेना बनने तक,

इसका आयन्त्रयक सेना के वजेट में शामिल किया जाता था। वायुसेना के प्रमुख को भारत का एयर अफसर कमांडिंग कहा जाता था, जिसकी हैसियत पहले एयर वाइस मार्शल की थी, जो बाद में एयर मार्शल की हो गयी। रॉयल इंडियन नेवी के फ्लेग जफमर कमांडिंग की तरह एयर अफसर कमांडिंग भी भारत के कमांडर-इन-चीफ के नियन्त्रण में था। वायुसेना का मुख्यालय सेना-मुख्यालय के निकट सम्पर्क में काम करता था।

भारतीय वायुसेना बनाने के लिए छ छात्र सैनिकों की एक टुकड़ी रॉयल एयर फोर्स कालेज, ट्रेनवेल को मिनस्वर १९३० में आने वाले पाठ्यक्रम के लिए भेजी गयी। भारतीय वायुसेना की पहली एलाइट में चार 'वापीती' विमान थे, जो माइल कि पहले ही पुराना पड़ चुका था। उनमें छ ट्रेनवेल में शिक्षित अधिकारी और १६ वायु सैनिक (एयरमैन) थे। वायु सैनिक उन प्रशिक्षणों में से भरती किये जाते थे, जो रेल कारखाने में कुछ सालों का प्रशिक्षण पूरा कर चुके होते थे। उनको आगे प्रशिक्षण विमान ड्रिपों, कराची में दिया जाता था। भारतीय वायुसेना की एक खास बात यह थी कि, सेना या नौ सेना से भिन्न, इसमें केवल भारतीयों की ही कमीशन दिया जाता था। इसलिए स्वाधीनता के समय भारतीय वायुसेना में कोई जर्नल भारतीय कमीशन-धारी न थे। फिर भी भारतीय अधिकारियों की संख्या बहुत कम थी और ५ दहक पतिष्ठ भी थे। अपेक्षित संख्या में बरिष्ठ अधिकारी और तत्कालीन रायल एयर फोर्स में सम्मिलित करने के लिये जाते थे। दूसरे विश्व युद्ध में पहले भारतीय वायुसेना का काम पश्चिमोत्तर सीमान्त में सेना की मदद करने तक ही सीमित था। वस्तुतः भारत में शान्ति काल में मजबूत सेना का सन्ने बड़ा काम हम इसके में शान्ति रखना था। फिर भी, सरकार केवल सेना का ही प्रयोग न करती थी, बल्कि उनमें वार्षिक ८५ करोड़ रुपये तक की रकम भिन्न-भिन्न तरह की राशियों में बांट कर उन जनजातियों में व्यवस्था रखती थी।

### सेना में कमीशन

जमा पहले ही बताया जा चुका है, यद्यपि प्रथम विश्व-युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों का सक्रिय सेवा के लिए विदेश भेजा गया था, फिर भी उस समय एक भी ऐसा भारतीय न था जिसने कमीशन मिला हुआ हो। १९१८ में ही भारतीयों की रिंग कमीशन का पात्र घोषित किया गया और पहला नियमित रिंग कमीशन जुलाई, १९२० में दिया गया। उस समय तक भारतीय अ-कमीशन पदों से बढ़कर वायसरॉय के कमीशन-अधिकारी के पद तक जा गये थे। इस तरह के निम्नलिखित प्राइवेट के रूप में ही सेना में प्रवेश पा सकते थे। १८४७ के बाद अपनायी गयी यह नीति कि पञ्जाब और पश्चिमोत्तर के कुछ वर्गों अर्थात् सामन्तों की जातियों में से ही भरती की जाय, धातु रही।

१. दुम २ में जो छ भारतीय अधिकारी भारतीय वायुसेना के जन्म के समय कमीशनधारी थे, उनमें से पञ्च एक ही १९४७ में पदोन्नत था। आगे चलकर वही पहला भारतीय चीफ ऑफ एयर स्टाफ बना। दोष ने सेना में स्वीका दे दिया, दुपेयना में मारे गये, आदि।

२३ फरवरी, १९२३ को कमांडर-इन-चीफ ने केन्द्रीय विधान-सभा में घोषणा की कि सरकार ने यह निश्चय किया है कि घुड़सवार और पैदल सेना की, मुख्यतः पैदल सेना की, आठ चुनौतियाँ युनिटों में आगे से केवल भारतीय ही अधिकारों होंगी। पर अब भी भारतीय सेना की तकनीकी शाखाओं में कमीशन प्राप्त कर सकने के पात्र न थे।

मदा से यह भारतीय जनमत व्याप्त था कि भारतीयों को भारत की सेना, नौसेना और वायुसेना की सभी शाखाओं में अवकाश रूप में प्रवेश मिलना चाहिये। फलस्वरूप भारत-सरकार ने १९२५ में एक समिति बनायी, जिसे भारतीय सैंडहर्स्ट-समिति या स्कीन समिति भी कहा गया। उसे अन्य बातों के साथ-साथ ये काम भी जांच के लिए सौंपे गये। (१) मख्या और गुण दोनों दृष्टियों में किंग कमीशन में भारतीय उम्मीदवारों के आने में सुधार के उपाय सुझाना और (२) भारत में एक सैन्य कॉलेज की स्थापना करने की वाञ्छनीयता पर विचार करना, जिसमें भारतीयों को सेना के कमीशन-पदों के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। समिति ने निष्कारिता की कि भारतीयों को वायुसेना समेत सेना की सभी तकनीकी-शाखाओं में किंग कमीशन के लिए पात्र बनाया जाना चाहिये।

बाद में सरकार सहमत हो गयी कि छह भारतीय छात्र सैनिकों को तैयार करने में प्रशिक्षण के लिए ब्रिटेन स्थित रॉयल मिलिटरी अकादमी में भेजा जाय। सैंडहर्स्ट स्थित रॉयल मिलिटरी कालेज को भेजे जाने वाले छात्र सैनिकों की संख्या भी बड़ा कर बीस कर दी गयी।

देहरादून में इंडियन मिलिटरी अकादमी दिसम्बर १९३२ में स्थापित की गयी। वहाँ शिक्षित छात्र सैनिकों की पहली टुकड़ी को १९३५ में भारतीय कमीशन-प्राप्त अधिकारियों के रूप में कमीशन दिये गये। इसके बाद किसी भी भारतीय अधिकारी को किंग कमीशन नहीं दिया गया। इंडियन मिलिटरी अकादमी में होकर आने वाले भारतीय कमीशन-प्राप्त अधिकारियों को भारत स्थित ब्रिटिश सैनिकों के समान अधिकार प्राप्त न थे। पर वे भारतीय किंग कमीशन-प्राप्त अधिकारियों को प्राप्त थे। लेकिन जब १९४२ में युद्ध भारत की सीमा के निकट आ गया, तो उनकी कमान की बड़ी शक्ति दी गयी, जो किंग कमीशन-प्राप्त अधिकारियों को मिली हुई थी। रक्षा-मेतबो में अधिकारी-पदवी वाले भारतीयों की स्थिति का अधिक विस्तृत विवरण एक बार के अन्वय में दिया गया है (रक्षा-मेतबो का राष्ट्रीयकरण)।

### भारत-सरकार-अधिनियम, १९३५

भारत-सरकार-अधिनियम, १९३५, जिसे ब्रिटिश संसद ने पास किया था, भारत के सांविधानिक इतिहास में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विधान है। इस विधान ने प्रांतों को कुछ स्वायत्तता प्रदान की और इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने की बात कही गयी, जिसमें देशी रियासतों भी शामिल होने की थी, पर उसमें सैन्य-प्रशासन के नियन्त्रण के विषय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इस अधिनियम के अधीन सशस्त्र सेनाओं का संचालन एकाग्र केन्द्रीय विषय था और उसकी धारा ११ (१) में यह व्यवस्था की गयी थी कि रक्षा और चर्च सम्बन्धी मामलों में गवर्नर जनरल के दृष्ट्या का प्रयोग उनके द्वारा अपने स्वविवेक से किया जाएगा। धारा ३४ (१) के अनुसार रक्षा और चर्च सम्बन्धी व्यय को विधान-संघटन

के मनाधिकार में नहीं रखा गया था। यह व्यवस्था थी कि भारत में महामहिम सम्राट की सेनाओं का एक कमांडर-इन-चीफ होगा, जिसकी नियुक्ति राजकीय अभिषेक द्वारा की जायेगी। धारा ६ (१) में एक मन्त्रि-परिषद् की व्यवस्था की गयी, जिसमें १० से ज्यादा लोग न होंगे और जो गवर्नर जनरल को उसके कृत्यों के पालन के बारे में सलाह देगी, उन मामलों को छोड़ कर जिनमें उसमें स्पष्टिकरण में काम करने की अपेक्षा की गयी थी। उसके पिछले प्रकार के कृत्यों में (जिसमें रक्षा, चर्च सम्बन्धी मामले, विदेश कार्य और जनजाति क्षेत्र शामिल थे) उसे मदद देने के लिए गवर्नर जनरल अधिक से अधिक तीन परामर्शदाता नियुक्त कर सकता था। अधिनियम में कहा भी यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि कमांडर-इन-चीफ की स्थिति रक्षा-परामर्शदाता की नियुक्ति के बाद में क्या होगी। चायद यह धारणा रही होगी कि प्रस्तावित महामण की गवर्नर जनरल की मन्त्रि-परिषद् में कमांडर-इन-चीफ अब एक सदस्य के रूप में न रहेगा। महासम्र बनने तक भारत-सरकार-अधिनियम, १९१६, के कुछ उपबन्ध अधिनियम की नवी अनुसूची में किए गये और कुछ मशीनों के साथ प्रभावी बने रहे। चूंकि महामण की सरकार वास्तविक रूप में ले सकी, ये सत्रमणकालीन उपबन्ध, अर्थात् रक्षा और कमांडर-इन-चीफ के मामले में १९१६ का अधिनियम ही वस्तुतः सत्ता के हस्तान्तरण तक प्रभावी बना रहा। नवी अनुसूची की धारा ३७ में यह व्यवस्था थी कि यदि कमांडर-इन-चीफ एग्जीक्यूटिव कौमिल का सदस्य हो तो कौंसिल में उसकी हैसियत और बरिष्ठता स्वयं गवर्नर जनरल के बाद की होगी। गवर्नर-जनरल और परिषद् के अन्य सदस्यों के प्रमग में कमांडर इन-चीफ की यह स्थिति नवी अनुसूची की धारा ८ (१) में विहित नीचे लिखे अधिकतम-वार्षिक वेतन के मामले में भी भलकती थी

गवर्नर जनरल	₹ २,५६,०००
कमांडर-इन-चीफ	₹ १,००,०००
एग्जीक्यूटिव कौंसिल के	
अन्य सदस्य	₹ ८०,०००

बरिष्ठता-अभिषेक में कमांडर-इन-चीफ का स्थान गवर्नर जनरल के बाद था। अपने प्रभार क्षेत्र में अथ प्रांतों के गवर्नर और मद्रास, बम्बई, और बंगाल के गवर्नर बरिष्ठ थे। कमांडर इन-चीफ को एग्जीक्यूटिव कौमिल के अन्य सदस्यों में कुछ ऊपर रखा गया था।

नवी अनुसूची के अनुसार अन्य व्ययों के साथ-साथ रक्षा और चर्च सम्बन्धी व्यय को विधान मण में मनदान के लिए नहीं पेन किया जाना था। ये व्यय दोनों में से किसी भी मदद के अधिकार में नहीं थे।

इस तरह भारत-सरकार अधिनियम, १९३५ के अधीन भारत में सैन्य प्रशासन के पुर्गठन के मामले में कोई भारी परिवर्तन नहीं हुआ। फिर भी समग्र सेनाओं के भारतीय अभिधारियों को महामहिम सम्राट के नाम में समीक्षण जारी करने की धनि गवर्नर जनरल को प्रत्ययोपेक्षित कर दी गई।

मशी पर रक्षा-सेनाओं के वित्तीय प्रशासन के सम्बन्ध में गवर्नर जनरल के कार्यभारक प्राधिकार की सीमाओं की गतिम चर्चा करना उचित होगा, जो १ अप्रैल, १९३७ को भारत-

सरकार-अधिनियम, १९३५ (भाग ३) के प्रभावो होने के बाद भी बनी रहो। अधिनियम की धारा २३५ में व्यवस्था की गयी थी कि सेन्टेरी ऑफ स्टेट समय-समय पर स्पष्ट कर सर्वेये कि कौन-कौन से ऐसे नियम, विनियम या आदेश उनकी पूर्वानुमति में बनाये जा सकेंगे, जो भारत में सम्राट की सभी या किन्हीं सेनाओं की सेवा-शर्तों पर प्रभाव डालने हों। इसके अनुसरण में सेन्टेरी ऑफ स्टेट ने निर्णय किया कि १ अप्रैल, १९३७ से कोई ऐसे नये नियम या विद्यमान नियमों में ऐसे कोई संशोधन उनकी पूर्वानुमति में ही बनाये जा हिये जायें, जो स्पल सेनाओं में किंग कमीशन-प्राप्त अधिकारियों, रॉयल एयर कोर्स के अधिकारियों, रॉयल इन्डियन नेवी के अधिकारियों और सेना, नौ-सेना और वायुसेना के दोष सभी ब्रिटिश सदस्यों के वेतन, भत्ते, भविष्य निधि, छुट्टी, भारतीय स्थापनों में निवृत्ति और तैनाती, पदोन्नति, सेवा-निवृत्ति और सेवा-मुक्ति, आवास-मान, वस्त्र, उपस्कार, राशन आदि को शामिल करते हुए उनकी सेवा शर्तों पर प्रभाव डालने हों। साथ ही विदेश में सेन्य भण्डारों की खरीद उसके द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार ही की जा सकेगी। इसका अर्थ था कि भारत-सरकार, सेन्टेरी आफ स्टेट से बिना पूछे, सेना के केवल भारतीय कमीशन-प्राप्त अधिकारियों (जिनको पहली बार १९३५ में ही कमीशन मिला), वायुसेना कमीशन-प्राप्त अधिकारियों और अन्य पदधारियों के बारे में और नौ-सेना के भारतीय 'रेटिरो' के बारे में तथा वायुसेना के भारतीय एयरमेनो के बारे में ही आदेश जारी कर सकती थी। भारत-सरकार को प्रत्यायोजित बहुत सीमित शक्तियों के बारे में भी यथासम्भव इंग्लैंड में प्रचलित नियम-विनियमों के पालन का ही चलन चलता था, जब तक ये स्पष्ट ही भारतीय स्थिति में लागू करने योग्य न हों। इस तरह भारत में सेन्टेरी ऑफ स्टेट के अनुमोदन के बिना रक्षा-सेवाओं के सम्बन्ध में किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव का सूत्रपात या उसकी जाँच करने की बहुत थोड़ी ही गुंजाइश थी। सेना-मुख्यालय स्वतः इंग्लैंड के अपने सहायी विभागों की ओर से ही मार्ग दर्शन प्राप्त करता था।

सेना-विभाग का नाम १९३६ में बदल कर रक्षा-विभाग कर दिया गया, जो उपयुक्त ही था, क्योंकि अब उसमें नौ-सेना और वायुसेना भी आती थी। उस समय यह विलुप्त छोट्टा-सा विभाग था, जिसमें एक सचिव, दो उपसचिव, एक सेना-भूमि तथा छावनी-निदेशक, दो अनुसचिव और दो सहायक सचिव थे। विभाग केवल तीनों सेनाओं के मुख्यालयों के साथ ही पञ्चाबाद करता था, उनकी छोटी किरकतारों के साथ नहीं। पर पूर्ण रॉयल इन्डियन नेवी का फ्लैग अफसर कमांडिंग इन्चार्ज में था, इसलिए नौ-सेना के मामलों में भी सेना या वायुसेना मुख्यालयों या सरकार के अन्य विभागों से परामर्श करने का दायित्व भी रक्षा-विभाग का ही था। (जैसा बताया जा चुका है, १९४० में युद्ध शुरू हो चुकने के बाद नौ-सेना का मुख्यालय ताम्रता ले आया गया, ताकि रक्षा-विभाग के निकट रह सके और उसे नौ-सेना मुख्यालय के रूप में गठित किया गया)। इस विभाग में आरम्भत निपटायें जाने वाले विषय ये थे गना भूमि-छावनी प्रशासन, चर्च-सम्बन्धी मामले, मुद्रण, लेखन-सामग्री, मृत-अधिकारियों की सम्पदाएँ, भारतीय सैनिक बोर्ड, भारतीय सेना-सूची और पदक दिया जाना। रक्षा-सचिव रिपान-सभा का एक सदस्य था और कमांडर-इन-चीफ राज्य-परिषद् का।

१९३८ की स्थिति को संक्षेप में लें जो दूसरा विश्व-युद्ध छिड़ने में पहले शान्ति का आखिरी माल था भारत। वी असेनिक सरकार और रक्षा भारत के सेक्रेटरी आफ स्टेट के निदेश और नियन्त्रण के अधीन सपरिपट्ट गवर्नर-जनरल में निहित थी। भारत की रक्षा-सेनाओं की उच्चतम ब्रह्मन् ब्रमाडर-इन-चीफ के हाथ में थी, जो रक्षा का भारसाधक परिपट्ट का सदस्य भी था। कमांडर-इन-चीफ न केवल यत-सेना का प्रशासनिक और कार्यपालक प्रमुख था, बल्कि नौसेना और वायुसेना का भी। सेना-मुख्यालय में चार प्रमुख स्टाफ अधिकारी थे, नामतः चीफ आफ जनरल स्टाफ, भारत का एडजुटेंट जनरल, भारत का क्वार्टर मास्टर जनरल, भारतीय आर्टिलरी का मास्टर जनरल। इनका प्रमुख कर्तव्य कमांडर-इन-चीफ को उसके प्रशासनिक कार्य के कार्यपालक पक्ष में मदद करना था। दो अन्य शाखा-प्रमुख भी थे (जिन को प्रमुख स्टाफ अधिकारी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था, नामतः सैन्य-अभिन्न और इंजीनियर-इन-चीफ। वायुसेना के प्रमुख का पदनाम था एयर अफसर कमांडिंग रॉयल एयर फोर्स इन इंडिया। यदि वायुसेना सम्बन्धी किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर उनके और कमांडर-इन-चीफ के बीच मतभेद हो, और वह चाहे तो गवर्नर जनरल के सामने अपना मत उपस्थित करने की अनुमति प्राप्त कर सकता था। उसे यह भी अधिकार था कि भारत के रॉयल एयर फोर्स पर प्रभाव डालने वाले किसी मामले के बारे में अपने विचारों भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास भेज सकता था, (अगर उन विचारों को कमांडर-इन-चीफ और गवर्नर-जनरल दोनों ने नामजूर कर दिया हो)। नौसेना का प्रमुख (अर्थात् पहले अफसर कमांडिंग रॉयल इंडियन नेवी) रॉयल इंडियन नेवी के प्रशासन और दक्षता के लिए कमांडर-इन-चीफ के प्रति उत्तरदायी था। अपने और कमांडर-इन-चीफ के बीच मतभेद होने पर यदि वह चाहता, तो उसे भी रॉयल इंडियन नेवी सम्बन्धी किसी महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में अपना दृष्टिकोण गवर्नर जनरल के सामने प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता था। फिर भी नौसेना के स्वातंत्र्य सम्बन्धी महत्व के सभी मामलों में केन्द्रीय सरकार का नौसेना सलाहकार ब्रिटिश नौसेना कमांडर-इन-चीफ, ईस्ट इंडीज खण्ड ही था।

ऊपर उल्लिखित सैन्य-परिपट्ट अब भी चल रही थी, पर उसकी रचना बदल कर इस तरह हो चुकी थी —

कमांडर-इन-चीफ और रक्षा-सदस्य

—अध्यक्ष

चीफ आफ जनरल स्टाफ

—उपाध्यक्ष

एडजुटेंट जनरल

क्वार्टर मास्टर जनरल

आर्टिलरी के मास्टर जनरल

रॉयल एयर फोर्स के एयर अफसर कमांडिंग

सचिव, रक्षा-विभाग

वितीय सलाहकार, सैन्य-वित्त

भारत मंत्रि, रक्षा-विभाग

—सदस्य

—सचिव



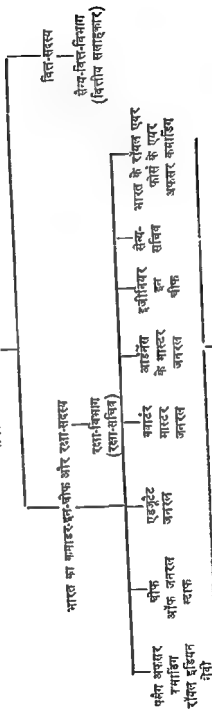
आरेख-१

१९३८ में संगठन-रीया

महामहिम सम्राट्

ब्रिटिश गवर्नर-जनरल—महामहिम सम्राट्—भारत का गेनेरल ऑफ स्टेट

भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल



परिपट्ट एक सलाहकार निकाय बनी रहती, जिसकी कोई सामूहिक जिम्मेवारी न थी। सैन्य परिपट्ट के अलावा दो अन्य महत्वपूर्ण समितियाँ थी, नामन रक्षा-समिति और स्टाफ प्रमुखों की समिति। रक्षा-समिति का कोई निश्चित सचिवान न था और यह सभी दैत्यों की जब बायमराय इसे बुलाने थे। इसके अध्यक्ष बायमराय थे और इसके सदस्य बायसराय अपने सह-योगियों और तन्त्रीकी सहायकों में से चुनते थे जो ऐसे व्यक्ति होते थे, जिनकी सलाह के समिति के समस्त आये किसी प्रश्न पर लेना चाहते थे। बायसराय का निजी सचिव इस समिति का सचिव था। यह विशुद्ध सलाहकार समिति थी और उसका कोई कार्यपालक या प्रशासनिक दायर न था, न वह कोई नीति विहित कर सकती थी या निर्देश ही दे सकती थी। इस समिति द्वारा दी गयी किसी सलाह पर सपरिपट्ट गवर्नर जनरल की पुष्टि जरूरी थी।

स्टाफ-प्रमुख-समिति में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ अध्यक्ष थे, एयर अफसर कमांडिङ्ग और पैरामाउन्टर कमांडिङ्ग सदस्य थे और रक्षा-विभाग का एक उपसचिव इस समिति का सचिव था। यह समिति ऐसे महत्वपूर्ण मामलों पर विचार करती थी, जिसमें एकाधिक सैन्य सेवा की दिलचस्पी होती थी और यह अपनी सिफारिशें कमांडर इन चीफ के पास भेजती थी। किसी माम सैन्य-सेवा में सम्बन्धित कोई खास तौर पर महत्वपूर्ण मामला ही इस समिति के विचारार्थ भेजा जा सकता था। अनेक अन्य गौण समितियाँ भी थी, जो विभिन्न समस्याओं को निपटानी थी।

सैन्य परिपट्ट और स्टाफ-प्रमुख-समिति बहुत सीमा तक इस प्रकार के विचार-समर्पण की सम्भावना को कम कर देती थी (एक) तीनों सेना-मुख्यालयों के बीच, (दो) एक ओर सेना-मुख्यालय और रक्षा-विभाग तथा दूसरी ओर सैन्य-वित्त-विभाग के बीच और (तीन) रक्षा-विभाग और सैन्य-वित्त-विभाग के बीच। फिर भी महत्वपूर्ण मामलों को से कर मतभेद हो जाते थे। यदि सेना-मुख्यालयों की साक्षात् सहमति न हो पाती थी, तो प्रमुख सम्बन्धित साक्षा-प्रमुख वह मामला निर्णय के लिए कमांडर-इन-चीफ के पास भेज देता था कि क्या इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाय या उसमें हेरफेर किया जाय। यदि साक्षा-प्रमुख और उपवितीय सलाहकार के बीच मतभेद होता था, तो पहला या ती पिछने की सलाह मजूर कर लेता था या मामले को तृतीय सलाहकार के पास भेज देता था या उसे स्वयं रक्षा-सचिव के पास भेज देता था। यदि रक्षा-सचिव साक्षा-प्रमुख के विचार में सहमत न होता था, तो वह रक्षा-मदस्य के आदेश प्राप्त कर लेता था। सचिव और तृतीय सलाहकार के बीच सहमति न होने पर, मामला रक्षा-मदस्य के पास तक आता था और वह उसे वित्त-मदस्य के पास भेज देता था। सदस्यों के बीच के मतभेद के मामले निर्णय के लिए गवर्नर जनरल या एग्जीक्यूटिव कौन्सिल तक आते थे।

भारतीय सेना के आधुनिकन और उद्योगे लिए यान्त्रिक उपस्कर और उनको चलाने के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों की व्यवस्था करने की जरूरत समझी गयी थी और दूसरे विश्व युद्ध के शुरू होने के कुछ पहले उस पर गम्भीरता के साथ विचार भी किया गया था। सार्ट चैटवीथ के अधीन बनी एन समिति द्वारा ब्योरेवार योजनायें भी तैयार की गयी थी, जिनको बाद में

कुछ परिवर्तनों के साथ मंजूर भी किया गया। ब्रिटिश सरकार ने भी कुछ शर्तों के साथ सहायता देने का वचन दिया था, लेकिन आवश्यक परिवर्तन पूरे हो, इसके पहले ही मुद्र छिड़ गया था।

जब मुद्र के बादल छा गए तो तत्कालीन समस्याओं के अनुसार स्थितियों पर कदम उठाये जाने लगे। जनवरी, १९३६ के आरम्भ में मुद्र सन्वन्धी विभागों के लिए एक अलग रक्षा-संगठन-विभाग बना दिया गया।

### युद्ध-काल में विस्तार

युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर भरतों का कार्यक्रम शुरु करना पड़ा और जब भारत को पूर्व में हमने का खतरा हो गया, तो इस काम में बहुत तेजी आ गयी। घटनाओं के दबाव में मेना में भारती केवल तथाकथित बीर जातियों तक हो सीमित करने की नीति छोड़ देनी पड़ी और मेना में सभी प्रदेशों और समुदायों को भरती के लिए छूट देनी पड़ी। १९४४ में दिये गये एक वक्तव्य के अनुसार उस समय तक अधिकारियों के पदों पर भारतीय अधिकारियों की संख्या पैंतीस प्रतिशत तक पहुँच गयी थी, जब कि १९३८ में सेना में भारतीय अधिकारियों की संख्या दस प्रतिशत भी न थी। १९३८ में भारतीय और ब्रिटिश दोनों अधिकारियों की कुल संख्या लगभग ४५०० थी, पर युद्ध की तेजी के नाते में जल्दी संख्या ५०००० तक पहुँच गयी। सडाबू मेनाओं की संख्या में भी भार वृद्धि हुई और यह संख्या १९४३ तक बीस लाख से ऊपर निकल गयी (अर्थात् युद्ध-पूर्व की संख्या से दस गुनी में ज्यादा)। रक्षा-विभाग युद्ध से पहले तुलना में एक छोटा सा विभाग था, अब बहुत बड़ा हो गया। युद्ध से पहले कतकों समेत इस विभाग में कुल ६६ व्यक्ति थे, १९४७ में विभाजन से ठीक पहले विभाग में कुल संख्या ३१६ थी। युद्ध के वर्ष में अनेक ब्रिटिश मेबरों की भी पोरे समय के लिए विभाग में अनु-पचिवों के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया गया था।

### युद्ध-विभाग

१९४२ में रक्षा-विभाग को हिस्सों में बाँट दिया गया, नामतः युद्ध-विभाग, जो कमांडर-इन-चीफ के अधीन था और रक्षा-विभाग के सभी महत्वपूर्ण कर्तव्य पूरे करता था। रक्षा-विभाग नामक एक नया विभाग बनाया गया, जिसमें उस विभाग की पहले की कुछ कम महत्व की चीजें थीं, जैसे छावनिदार और सेन्य भूमि, पैट्रोनियम, मुद्रण, लेखनसामग्री और फार्म, पदक, मेना-भूषण, युद्धबन्दी, सैनिकों की सुविधाएँ और कन्साप और १९४५ में सेन्य-विनष्टन और मुद्रोत्तर पुनर्निर्माण के लिए बनाया गया एक नया संगठन। यह नया विभाग २० जुलाई, १९४८ ने एम्बोक्सुटिव कौंसिल के एक भारतीय सदस्य के अधीन कर दिया गया था, जो सन्तकउ. भारतीय जनमत के सन्तोष के लिए किया गया था। युद्ध के बाद यह विभाग बन्द कर दिया गया और १९४६ के आरम्भ में इसे युद्ध-विभाग में ही शामिल कर दिया गया।

## पूर्ति-विभाग

पूर्ति-विभाग नामक एक नया महत्वपूर्ण विभाग इस उद्देश्य हेतु बनाया गया कि देश की समय समायोजित उत्पादन सामग्री का भंडार में उचित वितरण हो सके। एम्बोक्लूटिज कॉमिशन का एक भारतीय सदस्य इनका आरंभकर्ता था और युद्ध-विभाग के वित्तीय सलाहकार को इन विभाग का भी वित्तीय सलाहकार बना दिया गया था, ताकि युद्ध की अच्छी तरह से चराने के लिए इन दोनों विभागों के बीच प्रभावी सहयोग बना रहे। उसे फिर युद्ध और पूर्ति का वित्तीय सलाहकार नाम दे दिया गया।

फिर भी भारतीय कमान ने न तो कोई आक्रामक युद्ध देखा था और न कोई मरिया ही बताया थी। १९८३ में एक उच्चतम कमांडर के अधीन दक्षिण-पूर्व-एशिया कमान जापानिया के विवाद पूरा-पूरा आक्रामक युद्ध चलाने के लिए खोली गयी। इसमें भारत की रक्षा के लिए भारत के कमांडर-इन-चीफ की प्राथमिक जिम्मेवारी पीछे पड़ गयी। उसका समय महत्वपूर्ण तथ्य यही रह गया कि दक्षिण-पूर्व-एशिया कमान द्वारा बताया जाने वाली युद्ध सुविधाओं के आधार के रूप में और इस प्रयोजन में आवण्टित सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए भारत को तैयार करने के लिए प्रभावी कदम उठाए। दक्षिण-पूर्व-एशिया कमान के उच्चतम कमांडर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कमांडर-इन-चीफ की दृष्टि के चीफ ऑफ स्टॉफ में निर्देश प्राप्त होते थे।

दक्षिण-पूर्व-एशिया कमान की स्थापना के साथ-साथ कमांडर-इन-चीफ की युद्ध समिति भी स्थापित की गयी। इस समिति की बैठक प्रायः रोज ही होती थी और कमांडर-इन-चीफ इसके अध्यक्ष थे। मेता-मुख्यालयों के प्रमुख स्टाफ अधिकारी, नौसेना और वायुसेना के प्रमुख, युद्ध और पूर्ति के वित्तीय सलाहकार और युद्ध-विभाग के सचिव इसके सदस्य थे। उस समय युद्ध-विभाग का मुख्य वर्तमान युद्ध-समिति के निर्णयों का पालन करने के लिए आदेश निकालना और सैन्य-वित्त-विभाग में परामर्श करते हुए किशिष्ट प्रयोजन के लिए व्यय की अनुमति देना ही था। मेता-मुख्यालयों में यह रिवाज था कि निकाले जाने वाले सरकारी आदेशों के समुदाय तैयार कर द और फिर उन्हें सीधे सैन्य-वित्त-विभाग के पास भेज दे। यदि उस विभाग ने समीक्षा अनुमोदित कर दिया तो वे युद्ध-विभाग के पास अन्तिम रूप से सरप्राइज गवर्नर जनरल को और न जारी होने के लिए सशस्त्र अधिकारी के हस्ताक्षर के ही लिए आते थे।

युद्ध में भारतीय मनाओं के योगदान का वर्णन इस पुस्तक के क्षेत्र में नहीं आता और युद्ध-तान न मनी स्तरों पर प्रशासनिक स्तर में निम्ने कये विभिन्न परिवर्तनों का पूरा-पूरा व्योम देना भी हमारा अभिष्ट नहीं है।

## सैन्य-विघटन

यह प्रकट था कि युद्ध समाप्त होने पर अतिरिक्त व्यक्तियों का बड़ा पैमाने पर विघटन करना होगा। पर इनकी भारी संख्या में सैन्य सेवा में मोचन का काम जल्दी में नहीं किया जा सकता था। इसलिए सैन्य-विघटन के कार्यक्रम को आवश्यक रूप में चलाया

जहरी था। साथ ही सेवाओं में और युद्ध के बाद जिन इलाकों में भोग लौट कर जा रहे हैं, वहाँ अग्रस्था बचाने की दृष्टि में निकाले गये व्यक्तियों के लिए, असेनिक रोजगारों में उद्युक्त पदों को आरंभित करके उनके नियुक्त किए जाने के बारे में बड़ी सावधानीपूर्वक एक कार्यक्रम बनाना भी जरूरी था। यह ठीक है कि निकाले गये व्यक्तियों को रोजगार देने की जिम्मेवारी में भारत-सरकार वचनबद्ध न थी। पर असेनिक जीवन में उनके पुनर्वास के लिए प्रवासी कदम न उठाये गये, तो बड़ा अमन्तोष और क्षोभ फैल जायेगा, एक विदेशी सरकार इस सम्भावना को आसानी से बिमार न सकती थी। निश्चय ही इसमें सशस्त्र सेनाओं की प्रतिष्ठा कम हो जायेगी और भविष्य में भरती पर इसका बुरा असर पड़ेगा। नये रक्षा-विभाग का 'सैन्य-विघटन और युद्धोत्तर-पुनर्निर्माण-संगठन' अतिरिक्त सैनिकों के विघटन और नागरिक जीवन में उनके पुनर्वास के लिए सावधानीपूर्वक एक क्रमबद्ध योजना तैयार कर रहा था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत युद्ध की समाप्ति के बाद के तीन सालों में काम पूरा होना था। मूल योजना के अनुसार जून, १९८८ तक मेना की संख्या कम होकर २,३०,००० रह जायेगी। पर जब यह समझा गया कि भारत के सम्भावित विभाजन का एक प्रतिफल यह भी होगा कि सशस्त्र सेनाओं का भी विभाजन करना पड़ेगा, तो सैन्य-विघटन का काम रोक दिया गया। इस तरह सत्ता-हस्तान्तरण के समय सेना की संख्या लगभग ४,००,००० थी। युद्ध के बाद कमांडर-इन-चीफ की युद्ध-समिति का नाम बदल कर कमांडर-इन-चीफ की समिति कर दिया गया था, पर इसकी रचना अब भी वैसी ही थी। स्टाफ प्रमुखों की समिति, जैसी पहले थी, वैसे ही काम करती चली आ रही थी।

### भारतीय रक्षा-मदस्य

जब दिसम्बर, १९४६ को अन्तरिम सरकार बनी तो पहली बार गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव कौंसिल का रक्षा-सदस्य एक भारतीय की बनाया गया। मरदार बन्धेव सिंह ने १६ नवम्बर १९४६ को रक्षा-सदस्य का काम संभाला और कमांडर-इन-चीफ एग्जीक्यूटिव कौंसिल के अगुआरण सदस्य न रहे, जिस पद पर वह मसूचे ब्रिटिश मासन-कान में आरुढ़ चले आ रहे थे। वे तीनों रक्षा-मेनाओं के कार्यापातक प्रमुख बने रहे और रक्षा-सदस्य के सलाहकार बन गये।

उस समय रक्षा-सदस्य की एक समिति बनायी गयी जिसके अध्यक्ष रक्षा-सदस्य थे और कमांडर-इन-चीफ, रक्षा-सचिव और वित्तीय सलाहकार इसके सदस्य थे तथा कमांडर-इन-चीफ की समिति के सचिव इस समिति के भी सचिव थे। कमांडर-इन-चीफ की समिति अब भी काम करती रही और इन बदली हुई परिस्थितियों में वह तीनों ही मेनाओं सम्बन्धी मामलों (जिन को जन्तु-सेना-विषय कहते थे) और उच्च रक्षा नीति के मामलों का विवेचन करती रही। इन विषयों के कमांडर-इन-चीफ की समिति के सामने आने में पहले इन पर स्टाफ प्रमुखों की समिति में विचार कर लिया जाता था।

महामहिम सम्राट्-मरहम की ३ जून, १९८७ को इस घोषणा के बाद कि सत्ता-हस्तान्तरण भारत और पाकिस्तान के दो डॉमिनियनों के बीच किया जायेगा, सशस्त्र सेनाओं

और उनकी परिसम्पत्तियों के विभाजन का काम अन्तरिम सरकार ने अपने हाथ में लिया और यह भी निर्णय किया गया कि भारत के कमांडर-इन-चीफ १५ अगस्त, १९४७ में भारत और पाकिस्तान के मुरोम कमांडर होंगे और भारत और पाकिस्तान के डोमिनियनों की सशस्त्र सेनाओं के पुनर्गठन का उत्तरदायित्व उनका होगा ।

१५ अगस्त, १९४७ को अर्द्ध रात्रि में एक प्रभावी समारोह में सत्ता का भारतीय हाथों में औपचारिक रूप से हस्तान्तरण कर दिया गया । १५ अगस्त, १९४७ को भारतीय रक्षा-मन्त्री रक्षा-सेनाओं के प्रशासन, रक्षा-आयन्त्रयक और भारत की रक्षा-नीति के निर्माण के लिए पहली बार एक निर्वाचित विधान-मण्डल के उत्तरदायी बने, और रक्षा-सेनाओं के कमांडर-इन-चीफ की जगह तीन रक्षा-सेनाओं, चल-सेना, नौ-सेना और वायुसेना के तीन स्वतन्त्र प्रमुख नियुक्त किये गये ।



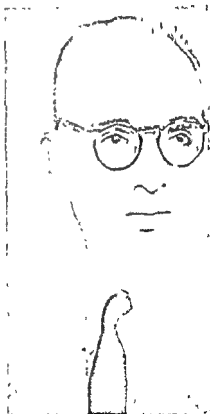
जवाहरलाल नेहरू

प्रधानमंत्री तथा मन्त्रिमण्डल की रक्षा समिति के अध्यक्ष, १९४७—१९६४



सरदार वल्लेभ सिंह  
रक्षा-सदस्य, सितम्बर १९४६—  
अगस्त १९४७, रक्षा-मन्त्री,  
अगस्त १९४७—मई १९५२

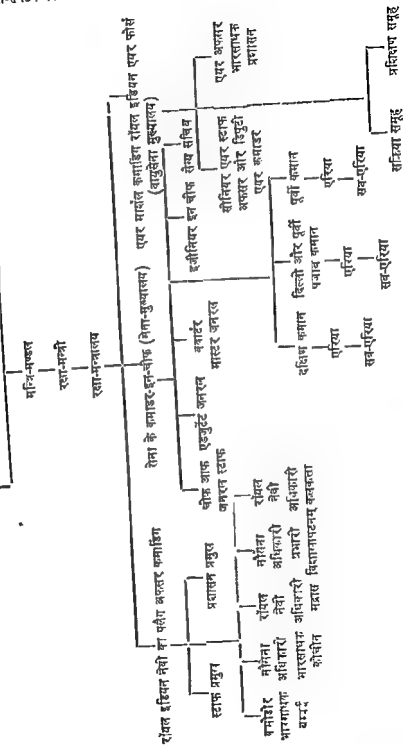
एच० एम० पटेल  
रक्षा सचिव, १९४७-१९५३





१९४७ तक रक्षा-संगठन का विकास

आरेख-४  
१५ अगस्त, १९४७ को सगुन-डोंचा  
मविधान सभा (विधायी)



## सशस्त्र सेनाओं का विभाजन

२० फरवरी, १९४७ को ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि उनका जून, १९४८ तक सत्ता को भारतीयों के हाथ में सौंप देने का इरादा है। घटनाचक्र तेजी में चला और ३ जून १९४७ को महामहिम सम्राट की सरकार ने घोषणा की कि सत्ता दो उत्तरवर्ती राज्यों भारत और पाकिस्तान को हस्तान्तरित कर दी जायेगी। १५ अगस्त में दो स्वतन्त्र होमीनियनों की स्थापना की व्यवस्था करने वाला भारतीय-स्वाधीनता-विधेयक ब्रिटिश हाउस ऑफ़ कामन्स में ४ जुलाई, १९४७ को पेश किया गया। यह विधेयक उस सदन में १५ जुलाई को और १६ जुलाई को लार्ड-मैमो में पार होने के बाद १८ जुलाई, १९४७ को सम्राट की स्वीकृति पर कानून बन गया। यह समझा गया कि भारत के विभाजन के प्रसामनिक नतीजे बड़े ही कष्ट-साध्य होंगे। इसका अर्थ था कि दोनों होमीनियनों की अनेक और रक्षा-मेवाओं का पुनर्गठन किया जाय, परिसम्पत्तियों और देयताओं का बँटवारा किया जाय और भण्डार को एक होमीनियन में दूसरे में ले जाया जाय। यह बड़ा भारी काम १५ अगस्त, १९४७ तक उपलब्ध बहुत थोड़े में समय में पूरा होना था।

सशस्त्र सेनाओं का विभाजन होना था, इसलिए दूसरे विश्वयुद्ध के समय में रक्षा मैग्निफिण्डन और रोक दिया गया। मूल योजना के अधीन सेना की संख्या जून, १९४८ तक घट कर २,३०,००० रह जानी थी। सैन्य-विपटन रोक देने में यह संख्या ८,००,००० रह जानी थी। मैग्निफिण्डन रोक देने में यह संख्या ८,००,००० हो बनी रही।

सशस्त्र सेनाओं का विभाजन देना के विभाजन की सामान्य योजना का ही एक अंग था, पर इसमें कुछ बात अनोखी और भावनामय भी थी।

भारतीय सशस्त्र सेनाओं में मोर्च, नौसेनिक और वायुसेनिक विभिन्न समुदायों और प्रदेशों से आये थे और यह एक सम्बद्ध संगठन था। इसके सदस्य अपनी-अपनी सेना के प्रति अनुशासन और निष्ठा में बंधे थे। रेजीमेंट या ब्रिगेड विभाग के अधिकारियों-मैजिस्ट्रो के बीच सम्बन्ध की भावना थी। धर्म, जाति, विश्वास या प्रान्त ने कभी भी समूची सेना के प्रति उनकी अविनाशित निष्ठा पर प्रभाव नहीं डाला। इन परम्पराओं के अनुकूल ही भारतीय

महान्व मेना राजनीतिक प्रभाव में भी मुख्य था और विभिन्न विध्वंसों और रीतिरिवाजों वाले इस महादेश में तान्त्रिक एकता की साधना जिसने उन्होंने की थी, शायद ही किसी और ने की हो। सारी दुनिया में पिछले विद्व-युद्ध के विभिन्न युद्ध-क्षेत्रों में भारतीय मूलियों के मुख्य योगदान ने इस भावना को और भी बढ़ाया था। विभाजन के बाद भारतीय महान्व मेनाओं में ये भाव्य परम्पराएँ फिर दृढ़ रूप में आरोपित कर दी गयीं हैं और हमेशा की तरह फिर वह विविधता में एकता की प्रतीक बन गयी है।

### विभाजन-परिपद

अब हम फिर देश के विभाजन की ओर आते हैं। मन्त्रिमण्डल ने ९ जून, १९४७ को फैसला किया कि बाबरामास की अद्यतना में एक मन्त्रिमण्डल-समिति विभाजन को कार्यान्वित करने के लक्ष्य की योजना बनाने के लिए गठित की जाय। १७ जून, १९४७ को यह घोषणा की गयी कि बाबरामास के अलावा इस समिति में दो कांग्रेस सदस्य होंगे, सरदार पटेल और डा० राजेन्द्र प्रसाद, और दो लोम के सदस्य, लियारज अली खान और सरदार अंगुर रव निहल। ये लोम दो अधिकारियों की विषय-निर्वाचन-समिति के जरिये विशेषज्ञ स्तर पर देश के विभाजन में पैदा होने वाली विविध समस्याओं की ब्यौरेवार जाँच और समन्वय करेंगे। इस विशेषज्ञ समितियाँ इन चीजों के लिए बनायीं गयीं—संगठन, अभिवेक और कामिक, परिसम्पत्ति और देणायें, केन्द्रीय राजस्व, सविदायें, चनायें, शिक्षा और विनियम (आयुष्यक और लेहे), आर्थिक सम्बन्ध (नियन्त्रण), आर्थिक सम्बन्ध (व्यापार), अधिकागिता, विदेश सम्बन्ध, और महान्व मेनाओं का पुनर्गठन इसमें सरकार के सभी विभाग आ जाते थे। हर विभाग की विशेषज्ञ समिति के जयोन उप समितियाँ थीं। ~~स~~ तरह तरह से महान्व मेनाओं के विभाजन की समस्याओं का निपटारा इसकी विशेषज्ञ समिति ने किया, जिसे महान्व-मेना-पुनर्गठन-समिति कहा गया। इस समिति की भी तीन उपसमितियाँ थीं। एक-एक प्रत्येक मेना के लिए। सभी विशेषज्ञ समितियों में भारत सरकार के वरिष्ठ भारतीय अधिकारी थे। मुसलमान भी थे और अन्य भी, लेकिन महान्व मेनाओं में काफी संख्या में भारतीय अधिकारियों के उपलब्ध न होने से, मेनाओं ने भारतीय अधिकारियों को महान्व मेनाओं की उपसमितियों में, विविध अधिकारियों के साथ काम करना पड़ा। जिस विषय-निर्वाचन-समिति की सीपेंस विशेष समिति और विशेष समितियों के बीच संपर्क कार्य करना था, उसमें ये लोग थे।

एच० एम० पटेल, मन्त्रिमण्डल सचिव, और मुहम्मद अली, वित्तीय सलाहकार, रक्षा और पूर्ण विभाग। विषय-निर्वाचन समिति विशेषज्ञ-समितियों के प्रतिवेदनों का समन्वय तो करना ही था, साथ ही वह उनको विभाजन परिपद के समझ निर्णय के लिए पेश भी करती थी और निर्णय का उचित समय पर पालन भी सुनिश्चित करती थी। वह विभिन्न विशेषज्ञ समितियों को उनकी मित्रारियों के नेपार करने में मार्गदर्शन भी करती थी।

महान्व मेना पुनर्गठन समिति और उसकी उपसमितियों के ब्यौरे के लिए देखिए इस अध्याय के अन्त में अनुबन्ध—१।

मन्त्रिमण्डल की विशेष समिति ने निदेश दिया कि विभाजन-कार्य मैत्री-भावना और मद्भाव से हाथ में लिया जाय और इच्छा यह रहे कि दोनों पक्षों को उचित हिस्सा दिया जाय। वगान के बाद पञ्जाब और सिन्ध की विधान-सभाओं ने विभाजन के पक्ष में मतदान किया। २६ जून १९४७ को विशेष समिति को अग्रह विभाजन-परिपद् ने ३ लो : परिपद् में तीन सदस्य वाप्रेस के रने गये थे और तीन मुसलिम लोग के, पर किसी भी बैठक में हर दल के केवल दो-दो सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक था। मन्त्रिमण्डल की विशेष समिति की तरह, इसके भी अध्यक्ष वायसराय ही थे। सरदार बल्लभ भाई पटेल, डा० राजेन्द्र प्रसाद और चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को कांग्रेस की ओर से नामित किया गया और मुहम्मद अली जिन्ना, सिद्दाकत अली खाँ और सरदार अब्दुर रब निस्तर की लीग की ओर से। उड़ीसा के तत्कालीन गवर्नर चन्दापाल त्रिवेदी, जो उच्च स्तर पर रक्षा-संगठन के कुछ अनुभव वाले एकमात्र भारतीय अमेरिक अधिकारी थे, परामर्शदाता के रूप में दोनों पक्षों को उपलब्ध रहे और सरस्व मेनाओं के पुनर्गठन सम्बन्धी वागज-पत्र उनके पास भेजे गये।

### सशस्त्र मेनाओं के पुनर्गठन सम्बन्धी सिद्धान्त

३० जून १९४७ को हुई बैठक में विभाजन-परिपद् ने यह निर्णय किया कि नीचे लिखे सिद्धान्त सशस्त्र मेनाओं के पुनर्गठन के आधार होने चाहिये -

(१) भारत और पाकिस्तान, प्रत्येक के अपने-अपने सीमा-क्षेत्र में, वे सेनायें रहें, जो (क) १४ अगस्त को उनके अपने-अपने सन्निव्यागत नियन्त्रण में हैं, (ख) १५ अगस्त को मुख्य तौर से जिनमें प्रमत्त गैर-मुसलमान हैं या मुसलमान हैं और (ग) जो १५ अगस्त के बाद यथानीय मुख्यतया प्रादेशिक आधार पर पुनर्गठित कर दी जायें।

(२) प्रत्येक होमोनियम की गीली मेनाओं के प्रमुखों का चुनाव करके उनको अपने-अपने मुख्यालय स्थापित करने का काम शुरू करने का प्राधिकार दे दिया जाय, ताकि १५ अगस्त तक कमान संभालने के लिए वे तैयार हो जायें। सेना-प्रमुख अपने-अपने रक्षा-महसूयों के जरिए अपने-अपने मन्त्रालयों के प्रति सीधे ही उत्तरदायी होंगे और अपने-अपने सीमा क्षेत्र की मेनाओं पर उनका कार्यपालन नियन्त्रण रहेगा।

(३) अविभाजित भारत की विद्यमान सशस्त्र सेनायें तब तक भारत के तत्कालीन कमांडर-इन-चीफ के प्रशासनिक नियन्त्रण में रहेगी, जब तक उनको दो स्पष्ट सेनाओं में जनम-जनम अलग छूट न दिया जाय और उनको प्रशासित करने के लिए दो जनम-अलग सरदारों न चुन जायें। फिर कमांडर-इन-चीफ भी गठित की जाने वाली उस संयुक्त रक्षा-परिपद् के नियन्त्रण में होगा, जिसमें सरदार जनरल या दोनों होमोनियमों के गवर्नर जनरल, दोनों रक्षा-मन्त्री और स्वयं कमांडर-इन-चीफ रहेंगे।

१५ अगस्त, १९४७ को गड़बड़ी न हो, इस दृष्टि से भारत के कमांडर-इन-चीफ को तब तक व लिए पदनाम गुपीत कमांडर दे दिया गया, जब तक मसल मेनाओं का विभाजन पूरा न हो जाय। दोनों में से किसी भी होमोनियम में विधि-व्यवस्था के लिए उनकी कोई जिम्मेवारी न थी और न किसी भी यूनिट के ऊपर उनका सन्निव्यागत नियन्त्रण हो था, एक

डोमोनियन ने दूसरे की ओर संक्षेप को छोड़कर। सशस्त्र सेनाओं के पुनर्गठन के बारे में, संयुक्त रक्षा-परिषद् के निर्णयों के पालन के लिए, उच्चतम कमांडर का एक मुख्यालय बना दिया गया। चोक्त ऑफ जनरल स्टाफ सेना मुख्यालयों के परिष्कृत प्रमुख स्टाफ अधिकारी थे। उनको उप-उच्चतम कमांडर (सेना) बना दिया गया। इन तरह उच्चतम कमांडर के मुख्यालय में अविभाजित सशस्त्र सेनाओं के कमांडर-इन-चीफ, रायल इंडियन नेवी और एयर फोर्स कमांडिंग रायल इंडियन एयर फोर्स को, क्रमशः उप-उच्चतम कमांडर (नौ सेना) और उप-उच्चतम कमांडर (वायुसेना) पदनाम दे दिये गये। जैसा कि स्वयं उच्चतम कमांडर के मामले में था, इन अधिकारियों को फ्ल-सेना, नौ सेना और वायुसेना की कमान संभालने का अधिकार नहीं दिया गया। उनको तीनों सेनाओं के पुनर्गठन का ही खास काम, उच्चतम कमांडर के नियन्त्रण में, सौंपा गया।

सशस्त्र सेना पुनर्गठन-समिति का कृष, विभाजन परिषद् के आदेश में काम करने वाली विषय-निर्वाचन-समिति के निकट परामर्श में, भारत की तीनों विद्यमान सशस्त्र सेनाओं, नामतः रॉयल इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और रॉयल इंडियन एयर फोर्स (जिन में भारत सरकार के रक्षा-विभाग के स्वामित्व वाले विभिन्न संस्थापन, स्थापनाएँ और मण्डार शामिल थे) के विभाजन के लिए प्रस्ताव तैयार करना था। जैसे-जैसे उपसमितियों और सशस्त्र सेना पुनर्गठन-समिति का काम बढ़ता गया, वेमे-वेमे विभाजन-परिषद् ने विषय-निर्वाचन-समिति को प्राधिकृत किया कि वह अपने विवेक से, सशस्त्र सेना पुनर्गठन-समिति के पास, प्रतिवेदित करने के लिए विषय चुन लिया करे और अन्य निर्णयों पर जो कार्रवाई हुई हो उस सूचित कर दिया करे।

विभाजन-परिषद् के सदस्यों ने युक्ति सगठन रूप में यह प्रत्याशा न की जा सकती थी कि वे सैन्य-संगठन के व्योरो से सुपरिचित हों। यह निर्णय किया गया कि जैसे ही सशस्त्र सेना पुनर्गठन-समिति अपने सिफारिशों की अन्तिम रूप दे दे, वेमे ही तीनों सेनाओं की उप-समितियों को सम्प्रदागत उप-अभिपक्षों के अभ्यस्त, अपने-अपने पक्ष के नेताओं को सलाह देने और चीजों का विवादोकरण करने के लिए, उपजम्न होने चाहिये।

सरकार ने सभी विभागों में विभाजन के कार्य को दोष सभी कामों से ज्यादा परिष्ठा दी गयी। सभी विशेषज्ञ समितियों से भी कहा गया कि वे २२ जुलाई, १९४७ तक अपना काम पूरा कर दें। केवल परिणामति और देवता-समिति के मामले में, अपवादस्वरूप, प्रतिवेदन ३१ जुलाई, १९४७ तक दे देने की अनुमति दे दी गयी।

### व्यक्तियों को विकल्प

भारत के विभाजन के अनुपालन का तन्त्र तय करने के लिए नियुक्त मन्त्रिमण्डल की विशेष समिति ने यह निर्णय लिया था कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, भारतीय या यूरोपीय, को यह विकल्प दिया जाय कि वह दोनों में से जिस किसी डॉमोनियन सरकार के अधीन नौकरी करना चाहे, चुनाव कर सकता है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को यह बताने के लिए कहा गया था कि क्या वह सत्ता-हस्तान्तरण की तारीख से छ महीने के भीतर अपने चुनाव

पर पुनर्विचार का अवसर चाहता है। जो अनन्तिम विचार १७ फरवरी, १९८८ तक बंद नही दिये जायेंगे, अन्तिम मान दिये जायेंगे।

साम्प्रदायिकता का विनाश करने के लिए भारत में किया गया। मेनाओं को छोड़ कर और पाकिस्तानी क्षेत्र में उस समय बाह्य नैदान, सुसज्जित दलबद्ध बारी सुसज्जित मुनिट्री को पाकिस्तान भेजा जाय और उन्हीं पर पाकिस्तानी क्षेत्र में स्थित सुसज्जित, एकमात्र गैर-मुस्लिम और गैर-मुस्लिम दल, मुनिट्री भारत भेज दी जायें। इनके कारण में सुसज्जित के गैर-मुस्लिम स्थापत्य के अन्तर्गत पर मुनिट्री में छेदों की गयी। इसमें एक ही अवसर था, नानव सृष्टि पाकिस्तानी क्षेत्र वाले किसी सुसज्जित को, जो उस समय सुसज्जित मेनाओं में जान कर रहा था, भारतीय क्षेत्र की सुसज्जित मेनाओं में शामिल होने का विचार न दिया गया था। पर पाकिस्तानी क्षेत्र के गैर-मुस्लिमों और क्षेत्र भारतीय क्षेत्र के सुसज्जितों को यह विचार दिया गया था कि दोनों में वे किसी होमोनियन की सुसज्जित मेनाओं में नौकरी करने का चुनाव कर दें।<sup>१</sup> चुनाव की स्थापना पर यह प्रतिबन्धन इस दृष्टि से लगाया गया कि एक होमोनियन के मैनिफेस्ट बुरे उद्देश्य में दूसरे होमोनियन में नौकरी का चुनाव न कर दें।

इस समय सुसज्जित मेनाओं में भरती के छेदों के भी नैदान व्यक्तियों की ही तरह विचार दिया गया। साथ ही नैदान व्यक्तियों की स्वीकृति देने का विचार भी दिया गया। यदि वे दोनों में वे किसी भी होमोनियन को मेना में नाम न करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में वे अच्छी प्रतिक्रिया को प्राप्त करने के अवसरों में, जो सन्तुष्ट स्थापत्य के सम्बन्ध उनको मेना का अन्त कर दिये जाने में मिलते।

### समीक्षण-प्राप्त अधिकारियों की प्रतिक्रिया

जमा कि मेनेटरी बाय स्टेट की स्थिति मेनाओं (आई० सी० एम०, आई० पी० एम० आई०) के बारे में किया गया था, स्थिति सरकार के राज्य दलित नैवी, भारतीय मेना और विचार मेना के ऐसे नियमित अधिकारियों के लिए उपयुक्त प्रतिक्रियाएं मजूर कर दिन, विचार निष्कर्षों सुना-दस्तावेज के सम्बन्ध सुधार कर दी गयी थी। बाद-

१. तदनुसार पाकिस्तानी क्षेत्र के गैर-मुसलमानों ने पाकिस्तान की सुसज्जित मेनाओं में नौकरी करने का चुनाव किया और भारत के सुसज्जितों ने भारत की सुसज्जित मेनाओं में। पर बाद में साम्प्रदायिक दलों के दलबद्ध बारी सुसज्जित में जन-स्थानांतरण जारी रहा। साथ ही इस समय में बहुत से लोगों ने अपना अन्तिम विचार बंद करने को अनुमति मांगी। इस समय की अग्रगण्य हस्त को देखते हुए, संयुक्त-रक्षा-परिषद् ने १६ अक्टूबर, १९८७ को निम्न किया कि पूर्वी पत्राव, पश्चिमी पत्राव, और पश्चिमोत्तर सीमांत प्रदेश के सुसज्जितों और गैर-मुसलमानों को अपना विचार बदलने की अनुमति दी जाय। इस निर्णय में दोनों में से किसी भी होमोनियन द्वारा इन नये विचार चुनने वालों को रोकथाम की गारंटी न दी जा सकती थी। इस मामले पर उनके सुन-दस्तावेज पेशा किया गया।

राय की ३० अंश, १६६३ की योजना में जिस प्रतिस्तर-राशि की व्यवस्था की गयी थी, वह आयु के आधार पर एक क्रमबद्ध मान में थी। यह १६ मान की उम्र पर २७-१० पाँड में लेकर ३६ मान की उम्र तक, बढ़ कर, अधिकतम ६००० पाँड तक हो जाता था (मेट्रोरो आफ स्टेट की मेनाओ के बारे में ३६ मान की उम्र अधिकतम प्रतिस्तर के निर्धारण की गयी थी)। फिर वह उम्र कम में कम होने-होते १५ मान की उम्र में शून्य रह जाता था। ऐसे अधिकारियों को तो अपनी पूर्ण पेंशन मिलने/ले जाने की थी। जो अधिकारी रिटायर नौकरियों में स्वतन्त्र रह कर दिये गये, उनको इन विहित दरों का चौथाई दिया गया।

डोमोनियनों के पड़ित हो जाने के बाद संयुक्त-रक्षा-परिषद् ने २० अगस्त, १९६३ को यह निर्णय लिया कि भारतीय मगन मेनाओ के सभी भारतीय पदधारियों को आम्नयित वेतन दिया जाय, यदि वे पूरी तरह सुरक्षित हों और उनको मेनामुक्ति इसी कारण हुई हो कि उन्होंने दाताओं में से किसी भी डोमोनियन को नौकरगी करने के लिए नहीं चुना। उस समय, प्रभु मेना-नियमों के अनुसार, संचालित मैनिफेस्ट को, मेना पर, कमान-आधिकारी के विवेका-नुसार आम्नयित वेतन दिया जा सकता था, पर यदि चार साल की सेवा पूरी होने के पहले उन व्यक्ति की डग के हों अनुरोध पर मेनामुक्त किया जाय तो आम्नयित वेतन उन्हें तभी मिल सकता था, जब त्रिमेड कमांडर को मन्तोष हो कि उस व्यक्ति की मेनामुक्ति जरूरी थी।

एग्जिक्यूटिव कौंसिल के (संयमन-कालीन उपबंध) आदेश, १९६३ (अधिमूचना संख्या जी जी जी० १ तारीख १६ जुलाई, १९४३) के अग्रीन भारत सरकार के प्रत्येक विभाग के पुराने नाम के जगह कोठक में भारत लगा कर उसे नया नाम दिया गया, जिससे वह एकमात्र या मुख्यतः भावी भारत डोमोनियन ने सम्बन्धित मामलों को निपटाये। साथ ही प्रत्येक विद्यमान विभाग के संबन्धों एक नये विभाग को दिखाने नाम के आगे कोठक में पाकिस्तान नाम जोड़ कर बनाया गया और इस विभाग को एकमात्र या मुख्यतः भावी पाकिस्तान डोमोनियन ने सम्बन्धित काम सीका गया। भावी डोमोनियनों ने सम्बन्धित मामले भारत और पाकिस्तान के उपरान्त विभागों में परामर्श करते निपटाए गये। भारत और पाकिस्तान संबंधी विभाग गवर्नर जनरल द्वारा नामित कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के अग्रीन रखे गये। एग्जी-क्यूटिव कौंसिल के सदस्य कौंसिल की उन बैठकों में भाग न ले सकते थे, जिनमें अन्य भावी डोमोनियन सम्बन्धी मामले एकमात्र रूप में या मुख्यतः विवेक जाने हों। यह फैसला गवर्नर जनरल करने थे कि यह मानता एकमात्र या मुख्यतः किन डोमोनियन का है या यदि वह समान रूप में दोनों का है, तो दोनों भावी डोमोनियनों के प्रतिनिधि भाग में। इस तरह व्यवहारतः २१ जुलाई, १९६३ की दो एग्जिक्यूटिव कौंसिल बैठक में आ गयी और रक्षा-विभाग (भारत), रक्षा-विभाग (पाकिस्तान) और ऐसे ही अन्य भावी विभाग भी दुहरे हो गये। पाकिस्तान के कार्या-लय कराची में स्थानित होने तक भारत और पाकिस्तान दोनों ही के विभाग दिल्ली में काम करते रहे।

### संयुक्त रक्षा-परिषद्

२० जुलाई, १९६३ को निर्णय लिया गया कि विनाशन-परिषद् जम्हायी रूप में १५

अगस्त, १९४७ तक संयुक्त रक्षा-परिषद् की तरह काम करेगी\* पंद्रह अगस्त, १९४७ को संयुक्त रक्षा-परिषद् कार्यरत हो जायगी।

संयुक्त रक्षा-परिषद् की स्थापना संयुक्त रक्षा-परिषद्-आदेश, ‡ १९४७ (अधिमूचना सभ्या

६ बालरम की दृष्टि से संयुक्त रक्षा-परिषद् की स्थापना का उत्तरेख वाद में किया जाना चाहिए। पर यह ज्यादा मार्के की बात नहीं है। सशस्त्र सेनाओं सम्बन्धी सभी फैसले विभाजन-परिषद्, या अन्तिम संयुक्त रक्षा-परिषद् के रूप में काम कर रही विभाजन-परिषद्, या १५ अगस्त के बाद संयुक्त रक्षा-परिषद् ने किए। उनके काम करने के सिद्धान्त सदैव एक हो रहे।

‡ आदेश के पैरा ८ में परिषद के ये कृत्य बताये गये थे

‘८—केवल संयुक्त रक्षा-परिषद् ही निम्नलिखित बातों का नियन्त्रण करेगी—

- (क) भारतीय सेनाओं का डोमीनियन के बीच विभाजन और उनका दो अलग डोमीनियन सेनाओं में पुनर्गठन।
- (ख) ऐसे पुनर्गठन के लिये भारतीय सेनाओं के सैनिकों और अधिकारियों का स्थानान्तरण और गमन।
- (ग) ऐसे पुनर्गठन के लिए भारतीय सेनाओं के उन सयन्त्रों, मशीनों, उपकरणों और भण्डारों का विभाजन, स्थानान्तरण और भेजा जाना, जो १५-८-४७ तक सर्वरर जनरल के अधीन थे।
- (घ) जो संयुक्त रक्षा-परिषद् बताये और उतने अस्थायी काल के लिए जितना वह परिषद जरूरी या इष्टकर समझे, नौसेना, धलसेना और वायुसेना की स्थापना।
- (ङ) नौ सेना, धलसेना और वायुसेना के कानूनों का सामान्य प्रशासन और दोनों में से प्रत्येक डोमीनियन की सशस्त्र सेनाओं में अनुशासन बनाये रखना।
- (च) दोनों में से प्रत्येक डोमीनियन की सशस्त्र सेनाओं के भुगतान, लाघ, बख्श, चिकित्सा और उपकरण की सामान्य व्यवस्था करना।
- (छ) दोनों डोमीनियनों के बीच की सीमाओं के पार के उस क्षेत्र में, जिसे कुछ समय के लिए प्रांतीय कानून के द्वारा उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया जाय, सन्धिकार या याद के लिए भेजी जाने वाली सशस्त्र सेनाओं का नियन्त्रण।
- (ज) ऐसी भारतीय सेनाएँ, जो इस समय विदेश में है

इस शर्त पर कि संयुक्त रक्षा-परिषद् का नियन्त्रण इन पर न होगा—

(एक) दोनों में किसी डोमीनियन की सशस्त्र सेनाओं के डोमीनियनों के भीतर विन्यास और स्थानीय प्रशासन पर, सेक्रेटरी इन अनुच्छेद के पैरा (छ) और (ज) में वर्णित सेनाओं से सम्बन्धित मामलों को छोड़ कर, या

(दो) दोनों में से किसी डोमीनियन की सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों और सैनिकों के भुगतान और भरोसी तथा उनके प्रशिक्षण पर, जब कि ऐसा प्रशिक्षण इन अनुच्छेद के



जी० जी० ओ० २, तारीख ११ अगस्त, १९४७ जी १ अर्बित १९४८ तक वैध था) के अजीब की गयी। आदेश के मसौदे पर चर्चा के समय पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बिल्लो ने सुझाव दिया कि यदि यह व्यवस्था की गयी कि भारत के गवर्नर जनरल परिषद के स्वतन्त्र अध्क्ष होगे, तो वह राखी हो जायेंगे कि उनका नाम सदस्य-मन्त्री में न रहे, क्योंकि बैठकों में भाग लेने के लिये पाकिस्तान में अनुपस्थित रहने में उन्हें दिक्कत होगी। संयुक्त परिषद में भारत के गवर्नर जनरल स्वतन्त्र अध्क्ष के रूप में रहे और भारत और पाकिस्तान के रक्षा-मन्त्री और उच्चतम कमांडर उसके सदस्य थे।

यदि रक्षा-मन्त्री कारणावली संयुक्त रक्षा-परिषद की किसी बैठक में न आ सकें, तो दूसरे मन्त्री या अपने डोमीनिनियन के उच्चायुक्त का भेज सकते थे। बैठक में रक्षा-मन्त्री के साथ एक अन्य मन्त्री भी आ सकता था।

परिषद को पूरी शक्ति थी कि संयुक्त सेनाओं सम्बन्धी सभी मामलों पर निर्णय ले ले, किन्तु कोई भी सदस्य किसी भी खास विवादग्रस्त मद को विभाजन-परिषद के पास भेज सकता था।

### संयुक्त सुरक्षा-परिषद् का सचिवालय

यह जरूरी था कि संयुक्त रक्षा-परिषद् का एक अर्धनैतिक संघटन हो, जो उसके सचिवालयीन स्तम्भ निभा सके और दोनों डोमीनिनियनों के सरकारी विभागों तक परिषद् के निर्णय पहुँचा सके। यह संगठन निरन्तर ही ऐसा हो जो दोनों डोमीनिनियनों का विस्मयनायक हो और यह आश्वासन करने में समर्थ हो कि परिषद् के आदेशों का बिना विलम्ब और सहज ही पालन किया जायगा। संयुक्त संयुक्त रक्षा-परिषद् का सचिवालय बनाया गया और दोनों डोमीनिनियनों के रक्षा-सचिव परिषद् के संयुक्त सचिवों के रूप में इसके प्रमुख रहे गए।

### उच्चतम कमांडर के मुख्यालय को वित्तीय सलाह

दोनों डोमीनिनियनों की स्थापना हो जाने पर अल्प-अल्प डोमीनिनियनों के सशस्त्र-सेना-मुख्यालय बन गये और डोमीनिनियनों की सेनाओं का संक्रियता निरन्तर उनके हाथ में आ गया और भरती, प्रशिक्षण आदि कुछ सहायक मामलों की जिम्मेवारी भी उनकी ही हो गयी। जैन-जैन सेनाओं के पुनर्गठन का काम आगे बढ़ा गया, क्रमशः डोमीनिनियन मुख्यालयों के हृत्कों में विस्तार होता गया और उच्चतम कमांडर के कृत वेम-वेम कम होते गये। उच्चतम कमांडर

पैरा (५) के अर्धनैतिक संयुक्त रक्षा-परिषद द्वारा बताया गयी प्रशिक्षण स्थापना से अन्यत्र ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता है।

यह एवं और भी कि संयुक्त रक्षा-परिषद ऐसे उपाय कर सकेगी, जिनसे क्रमशः इस अनुच्छेद के पैरा (५), (६) और (७) में वर्णित किसी या सभी के बारे में वह अपना निश्चयन हटा सके। उसका निश्चयन द्वायुक्तनीय और किसी भी दशा में १ अर्बित, १९४८ से पहले समाप्त हो जाने।

का मुख्यालय सशस्त्र सेनाओं के सामान्य प्रशासन और सन्धारण के लिए जिम्मेवार था, अर्थात् वेतन, वस्त्र, उपस्कर, खाद्य और चिकित्सा के लिए। इसलिए हमने सम्बन्धित वित्तीय कार्य की व्यवस्था करना भी जरूरी हो गया। यह निर्णय लिया गया कि उच्चतम कमांडर के मुख्यालय के लिए यह कार्य उस समय वर्तमान सैन्य-वित्त-विभाग करेगा (जिसमें वे अर्द्धतः कम हो जायेंगे जो दोनों डोमीनियनों ने डोमीनियन सशस्त्र-सेना-मुख्यालयों से सलाना अपने नये सैन्य-वित्त-विभागों के लिए ले लिए हों), भले ही इसमें वे व्यक्ति हों जो भारत के लिए चुनाव कर चुके हैं या वे जो पाकिस्तान के लिए। यह उच्चतम कमांडर के संगठन की तरह एकीकृत संगठन ही था। दोनों डोमीनियनों के वित्त-विभागों के समान पद वाले एक-एक करके दो अधिकारी समुक्त संगठन के प्रमुख थे। दोनों वित्तीय सहायकार उच्चतम कमांडर की समिति के सदस्य इस सादृश्य पर थे कि अतीत में युद्ध और पूर्ति का वित्तीय सहायकार कमांडर-इन-चीफ की समिति का सदस्य था। समुक्त-रक्षा-परिषद् के निर्णय की अपेक्षा करने वाले और वित्तीय आलेखों वाले मामले दोनों वित्तीय सहायकारों के परामर्श से तैयार किये जाते थे। सितम्बर, १९४७ के अन्त तक भारत और पाकिस्तान के लिए दो अलग-अलग सैन्य-सेवा-कार्यालय बनाने के लिए कदम उठाये गये। भारत में विद्यमान सैन्य-सेवा-कार्यालय भारत डोमीनियन का कार्यालय १ अक्टूबर, १९४७ से बन गया। पाकिस्तान के लिए विकल्प देने वाले कर्मचारियों को शामिल करके पाकिस्तान के लिए अलग कार्यालय खोला गया।

### सैन्य-सेवा-विभाग

जो सैन्य-सेवा-विभाग राज्य-क्षेत्र के आधार पर बने हुये थे, उनको सम्बन्धित डोमीनियनों ने संभाल लिया। इस तरह पूर्वी कमान और दक्षिणी कमान के सैन्य-सेवा-नियन्त्रक भारतीय सैन्य-महालेखाकार के अधीन काम करने रहे, जबकि उत्तरी कमान के सैन्य-सेवा-नियन्त्रक का कर्तव्य पाकिस्तान के सैन्य महालेखाकार ने संभाल लिया। अन्य सैन्य-सेवा-कार्यालय, जैसे सैन्य-सेवा-क्षेत्र-नियन्त्रक (अन्य पद), सैन्य-सेवा-क्षेत्र-नियन्त्रक (अधिकारी और घोषनगृह) सैन्य-सेवा-नियन्त्रक (वेल्थ) और बारखाना-सेवा-महानियन्त्रक, तब तक दोनों डोमीनियनों की सभी कमानों का काम करने रहे, जब तक पुनर्गठन पूरा न हो गया। इसलिए उनको सीधे उच्चतम कमांडर-मुख्यालय का काम करने वाले समुक्त-सैन्य-वित्त-संगठन के प्रशासनिक नियन्त्रण में बने रहने दिया गया। नौ-सेवा-सेवा-नियन्त्रक और सेवा-नियन्त्रक (वायुसेना) भी कुछ समय तक समुक्त-सैन्य-वित्त-संगठन के अधीन बने रहे, पर जंगे ही इन सेनाओं की मूर्तियों का विभाजन पूरा हुआ, इन कार्यालयों को बांट दिया गया और उनका काम सम्बन्धित डोमीनियनों को सौंप दिया गया। उपर उल्लिखित समुक्त-रक्षा-परिषद्-आदेश में समुक्त-रक्षा-परिषद्-उपचालक और समुक्त-वित्त-सेवा-संगठन दोनों के बनाने की व्यवस्था की गयी थी।

१५ अगस्त, १९४७ के बाद विभाजन-नन्तर औपचारिक रूप से स्थापित कर दिया गया। समुक्त-रक्षा-परिषद् की औपचारिक रचना का उल्लेख किया जा चुका है। भारत और पाकिस्तान की विभाजन-परिषद् का पुनर्गठन भारतीय स्वाधीनता (विभाजन परिषद्) आदेश १९४७ (अधि-चना मन्थी जी० जी० ए०, तारीख १२ अगस्त, १९४७) द्वारा किया

गया। विभाजन-परिपङ्क्ति में सदस्य रूप में भारत सरकार के दो मन्त्री और पाकिस्तान सरकार के दो प्रतिनिधि थे, जिनमें से एक पाकिस्तान सरकार का मन्त्री और दूसरा या तो मन्त्री या पाकिस्तान सरकार का भारत स्थित उच्चायुक्त हो सकता था। पर यदि पाकिस्तान के दोनों प्रतिनिधि मन्त्री हों, तो पाकिस्तान का उच्चायुक्त प्रेक्षक के रूप में बैठक में जा सकता था। यह व्यवस्था की गयी थी कि विभाजन-परिपङ्क्ति की बैठकों के अध्यक्ष, एक-एक बैठक के हिमायत में बदल कर, भारत के प्रतिनिधियों में से एक और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों में से एक रहेंगे।

भारत और पाकिस्तान की विभाजन-परिपङ्क्ति का प्रमुख कर्तव्य सारिपङ्क्ति गवर्नर जनरल की परिमार्शितियों और देवताओं के दोनों डोमोनियनों के बीच विभाजन में सम्मिलित था। यह भी व्यवस्था की गयी थी कि यदि परिपङ्क्ति एक सहमत निष्पत्ति न कर सके, तो वह बात मन्त्रिमण्डल अधिकरण को सौंप दी जाय, जो साथ-साथ ही मध्यस्थ अधिकरण आदेश (अभिपूचना सरना जो जी ओ ६, तारीख १० अगस्त, १९४७) के अधीन बनाया जा रहा था। इस अधिकरण में गवर्नर जनरल द्वारा नामित अध्यक्ष और दोनों भावी डोमोनियनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उसके ही द्वारा नामित दो सदस्य होने थे। यह व्यवस्था की गयी थी कि यदि अध्यक्ष का पद खाली हो जाय तो उसे ऐसे व्यक्ति में भरा जायेगा, जो भारत के गवर्नर जनरल और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल का एक सहमत नामित-व्यक्ति होगा और यदि किसी सदस्य का पद खाली हो जाय, तो सम्बन्धित डोमोनियन का गवर्नर जनरल उस खाली पद की पूर्ति के लिए एक सदस्य नामित कर देगा।

सदनुसार गवर्नर जनरल ने सर पेट्रिक स्टेंसर (भारत के फेडरल कोर्ट के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश) को अध्यक्ष, न्यायमूर्ति हरिलाल जे० कानिया को भारत के भावी डोमोनियन का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य और न्यायमूर्ति एम० इस्माइल को पाकिस्तान डोमोनियन का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य नामित कर दिया।

### पुनर्गठन के दौरान महाम्म मेनाओं का नियन्त्रण

पुनर्गठन के दौरान सशस्त्र मेनाओं के नियन्त्रण का स्वल्प आगे दिये जाने वाले आरेख-५ में बताया गया है। नौसेना और वायुसेना का नियन्त्रण भी सामान्यतः इसी आधार पर था।

मूलतः महाम्म मेनाओं का पुनर्गठन पूरा करने के लिए १ अप्रैल, १९४८ की तारीख तय की गयी थी, जिस तारीख को केन्द्रीय प्रशासन-नियन्त्रण समाप्त होना था। इसी कारण मनुक्त-रक्षा-परिपङ्क्ति का बाल भी इसी तारीख तक सीमित रखा गया था।

महाम्म मेनाओं के पुनर्गठन को तीन मुख्य चीजों के अन्तर्गत रखा जा सकता है—

( १ ) व्यक्ति।

( २ ) शस्त्र-भण्डार और उपकरण, जैसे गाड़ियाँ, तोपें, टैंक, आदि।

( ३ ) स्थिर संस्थान।

पूर्वोक्त रूप में व्यक्तियों के विभाजन के मिश्रण तब हो चुके थे। यह भी तय हो

गया कि दोनों होमीनियनो की अपनी-अपनी सैन्य-मह्यता के अनुपात में स्थूल रूप में यूनिटों के उपस्कर और वैयक्तिक उपस्कर भी बाँट दिये जायें। पर यह निद्वन्द्व भारी आरक्षित भण्डारों और युद्ध अस्त्रियों के बारे में लागू करना कठिन था, जो कुछ मामलों में कई सालों की सामान्य ज़रूरतों के बराबर था। काफी विचार-विमर्श के बाद ही इन भण्डारों के बारे में सहमति हो सकी। मेना में मुसलमानों और गैर-मुसलमानों का समग्रीण-अनुपात ३० ७० था। पर इस अनुपात में मेना की व्यक्तिगत विरचनाओं में अन्तर था। इसे ध्यान में रखते हुए पैदल रेजीमेंटों, तोपखाना रेजीमेंटों और आर्मर्ड कोरों का विभाजन इस तरह से किया गया कि दोनों होमीनियनो के बीच व्यक्तियों का कम से कम आदान-प्रदान हो। विभाजन करने में रेजीमेंट-केंद्रों का स्थल भी ध्यान में रखा गया था।

### तीनों उप-समितियों की कार्य-प्रणाली

सशस्त्र मेनाओं के विभाजन के लिए वस्तुतः अपनाये गये तरीके के बारे में भी यहाँ कुछ कह देना उचित होगा। मेनाओं सम्बन्धी तीनों उपसमितियों को पहले अपने-अपने प्रति-वेदन सम्बन्धित मेनाओं के धुत्तरांकन के लिए सशस्त्र-मेना-मुत्तरांकन-समिति के पास भेजने थे। यह अभिलिखित बात है कि उपसमितियों ने अपना काम सहयोग के वातावरण में किया। पहले सभी समस्याओं पर किसी उपसमिति के मुसलमान और गैर-मुसलमान सदस्यों द्वारा अलग-अलग विचार किया जाता था। बाद में वे समुक्त रूप से आपस में बात कर लेते थे और फिर उनकी मिफारिशों पर अध्यक्ष और उपसमिति के ब्रिटिश अधिकारियों के सामने खर्चा हो जाती थी। सभी मामलों में उपसमिति की सिफारिशें एकमत रही।

### सेना की यूनिटों का विभाजन

पैदल रेजीमेंटों की भारत और पाकिस्तान के बीच १५ ८ के अनुपात में बाँटा गया, जिसमें गोरखा यूनिटें शामिल न थीं। एक रेजीमेंट में तीन से छ बटालियनों तक हो सकती हैं। इसलिए इस अनुपात में सक्रिय बटालियनों की वास्तविक संख्या थी ६४ भारत और ४५ पाकिस्तान। पर पाकिस्तान की सभी बटालियनों में कुछ अनुपात में हिन्दू और सिख थे। वास्तविक संख्या थी भारत ६४ और पाकिस्तान ३३। जब सिख और हिन्दू अथवा पाकिस्तान बटालियनों में वस्तुतः बाहर आ गये, तो भारत संघ की बटालियनों की अंतिम उपस्कर सामर्थ्य ७९ थी और इसमें १२ गोरखा बटालियनों को जोड़ कर यह अंतिम अनुपात भारत ८८ और पाकिस्तान ३३ रहा। जो कमनियॉ एक होमीनियन से दूसरे को स्थानांतरित की गयी थीं, उनको अपने व्यक्तिगत हथियार और यूनिट के उपस्कर का यथोचित अनुपात अपने साथ ले जाने की अनुमति दे दी गयी थी।

यहाँ पर गोरखों का कुछ उल्लेख कर देना भी ज़रूरी है। बहुत समय से वे आत्र की तरह भारतीय मेना के एक महत्वपूर्ण तत्व रहे हैं। अविभाजित भारतीय मेना में जब गोरखों की इच्छा भांगी गयी तो उनमें से बहुमध्यक भारत में रहना चाहते थे। यह स्थानीय भारत और नेपाल के बीच पुरू से ही चले आते हुए सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्धों का प्रमाण है कि नेपाल

सरकार नेपाली गोरखाओं को स्वतन्त्र भारत की सेनाओं में रहने देने के लिए तैयार हो गयो। नवम्बर, १९४७ में भारत, नेपाल और इंग्लैंड की सरकारों के बीच एक त्रिपक्षीय करार पर काठमांडू में हस्ताक्षर किये गये, जिसके अनुसार नेपाल सहमत हो गया कि १२ गोरखा बटालियन भारतीय सेना में और ८ बटालियन ब्रिटिश सेना में रह सकती हैं। यह ध्यान रखना होगा कि यह व्यवस्था नेपाल के गोरखों के ही बारे में थी। उन गोरखों के बारे में नहीं, जो भारत में बग गये थे और इस तरह भारतीय अधिवास के गोरखा थे।

आमंडं कोर रेजीमेंटों को भारत १२ और पाकिस्तान ६ के अनुपात में बांटा गया। तोपखाना और इंजीनियरी यूनिटें, विमानन में कुछ रहते ही होते थले आ रहे पुनर्गठन के फलस्वरूप, बहुत-कुछ साम्प्रदायिक आधार पर बंठित की जा चुकी थी। तोपखाना-यूनिटें भारत १८३ के और पाकिस्तान ८३ के अनुपात में बांटी गयी और इंजीनियरी यूनिटें ६१ और ३४ के अनुपात में।

विभाजन के समय भारतीय सेना की कुछ यूनिटें बर्मा और मलाया में काम कर रही थीं। ब्रिटिश सरकार और बर्मा सरकार के अनुरोध पर विमानन परिपट्ट १५ अगस्त, १९४७ के बाद ३१ मार्च, १९४८ तक इन यूनिटों के वहाँ बने रहने के लिए सहमत हो गयी पर इन यूनिटों के विदेश में बने रहने ने भारतीय सेना के पुनर्गठन में कोई बाधा न डाली।

### रॉयल इंडियन नेवी के जहाजों का बँटवारा

रॉयल इंडियन नेवी का बँटवारा दोनों डोमीनियनों की वास्तविक जरूरत के आधार पर किया गया। मुसलमानों और गैर-मुसलमानों की सत्ता के अनुपात पर नहीं, जो ४० : ६० था। इस सिद्धान्त के मान लिए जाने के फलस्वरूप भारत के व्यापार, वाणिज्य बेड़े और तट-रेखा के, पाकिस्तान की तुलना में बहुत विस्तार होने की दृष्टि से, भारत को चार स्लूप दिये गये, जब कि पाकिस्तान को दो। जहाजों के वास्तविक विभाजन में भारत को दो सबसे नये और दो सबसे पुराने स्लूप मिले। पाकिस्तान को उनी वर्ग के दो अच्छे स्लूप दिये गये। चार फ्रिगेटों में से दो भारत को मिले और दो पाकिस्तान को। सर्वोत्तम पाकिस्तान को दिये गये। बेड़े के सुरंग स्वच्छकों के बारे में भारत की जरूरत पाकिस्तान से ज्यादा थी। इसलिए भारत को तीन और पाकिस्तान को एक, इस तरह बँटवारा हुआ। एवमात्र उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ पोत भारत को ३००० मील की तट-रेखा की दृष्टि से भारत को दिया गया, क्योंकि इसमें बहुत कुछ पुनः सर्वेक्षण जरूरी था। पतन-रक्षा मोटर लॉच बराबर-बराबर बाँटी गयीं, क्योंकि पाकिस्तान की तट-रेखा में डेल्टा क्षेत्र ज्यादा था।

### रॉयल इंडियन एयर फोर्स के स्क्वेड्रनों का बँटवारा

रॉयल इंडियन एयर फोर्स में २०% मुसलमान और ८०% गैर-मुसलमान व्यक्ति थे। बँटवारे के लिए एक इजिन वाले लड़ाकू-विमानों (तूफानी) के आठ स्क्वेड्रन और दो इजिन वाले बीच के परिवहन विमानों (ड्राफ्ट) के दो स्क्वेड्रन उपलब्ध थे। साम्प्रदायिक अनुपात के आधार पर पाकिस्तान को दो ही स्क्वेड्रन मिलने चाहिये थे और दोष आठ भारत को। फिर

भी सशस्त्र सेना पुनर्गठन-समिति की वायुसेना-उपसमिति इस बारे में एकमत थी कि पाकिस्तान को दो परिवहन स्क्वेड्रनों में से एक मिलना चाहिये। इसका मतलब था कि अगर बंटवारा विस्तृत साम्प्रदायिक आधार पर किया जाय तो पाकिस्तान के हिस्से में एक ही लड़ाकू स्क्वेड्रन आता था। किन्तु सशस्त्र सेना-पुनर्गठन-समिति के सदस्यों के बहुमत ने सुझाया कि पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रदेश में पाकिस्तान की जिम्मेवारी को देखते हुये वायुसेना के स्क्वेड्रनों का बंटवारा इस तरह किया जाये।

	पाकिस्तान	भारत
लड़ाकू स्क्वेड्रन	२	६
परिवहन स्क्वेड्रन	१	१

जब यह मामला विभाजन-परिपक्व के सामने आया, तो भारत एक अतिरिक्त स्क्वेड्रन पाकिस्तान के दिये जाने के पक्ष में न था। आपत्ति इस आधार पर थी कि वायुसेना सीमान्त प्रदेश की जनता के विरुद्ध इस्तेमाल की जावेगी। वायुसेना बाहरी आक्रमण के विरुद्ध उपयोग के लिए होती है। वह यह तर्क मानने के लिए तैयार नहीं है कि पश्चिमोत्तर सीमान्त में उसकी जिम्मेवारी के आधार पर ८०-२० का अनुपात बटल दिया जाय, जो कि सेना में मुसलमानों और गैर मुसलमानों की संख्या पर आधारित है। यह सही है कि नौसेना में जहाजों का बंटवारा ७०-३० के आधार पर किया गया है, यद्यपि अभिलिखित साम्प्रदायिक संख्या ६०-४० थी और गुप्तता भारतीय नौसेना द्वारा निभाये जाने वाले दायित्वों को ध्यान में रखकर दी गयी थी। यह सम्मानना नहीं थी कि भारतीय नौसेना भारतीय जनता के विरुद्ध इस्तेमाल की जावेगी। भारत एक अतिरिक्त स्क्वेड्रन उधार या बंटवारे में भाग देने को तैयार है यदि पाकिस्तान यह गारंटी दे कि इसका इस्तेमाल अविभाजित भारत की मूल सीमा के भीतर जनजातियों पर हमला करने के लिए न किया जावेगा। पर विभाजन-परिपक्व ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने इस पर आग्रह किया कि सशस्त्र-सेना-पुनर्गठन-समिति द्वारा सिफारिश किये गये अनुसार ही बंटवारा हो। अनिरोध पार करने के लिए लार्ड माउण्टबेटन ने, जो परिपक्व के अध्यक्ष थे, एक नया तरीका सुझाया कि अगर स्थितान अतिरिक्त उपकरण काफी मात्रा में हों, तो एक नया लड़ाकू स्क्वेड्रन खड़ा कर लिया जाय और तब पाकिस्तान को दो लड़ाकू स्क्वेड्रन दे दिये जायें। यह दोनों पक्षों को स्वीकार था और जाँच पर पड़ा जाता कि नवें स्क्वेड्रन के लिए काफी सामग्री उपलब्ध है। इसलिए बंटवारे में दो लड़ाकू स्क्वेड्रन और एक परिवहन स्क्वेड्रन पाकिस्तान को और गान लड़ाकू स्क्वेड्रन और एक परिवहन स्क्वेड्रन भारत को मिले। शेष, आरक्षण और पुराने आदि भी दोनों अनुपात में बाँटे गये।\*

### रेजीमेंट की निर्धियाँ

यह निर्णय किया गया था कि पुनर्गठन पर जब सेनिक एक यूनिट में दूसरी में जायेंगे तो रेजीमेंटों की निजी निर्धियों के जमा शेष का जो पूरा-पूरा या अंशतः वापसराय बर्तमान-

एदोनों रेजीमेंटों की बीच सशस्त्र सेनाओं की विभिन्न यूनिटों के बंटवारे की पूरी मात्रा इस अध्याय के अन्त में अनुबन्ध दो में मिल सकती है।

प्रान्त अधिकारियों या भारतीय अन्य मनों में प्राप्त चन्दे से बना है, एक अंश स्थानान्तरित होने जाने मेंनिको को सत्य के अनुग्रह में स्थानान्तरित कर दिया जाय । जविकारियों के मैमो की नियियां या सम्पत्ति अधिकारियों की निजी सम्पत्ति मानो गयी और वह सम्बन्धित रेजिमेंट के पास बनी रही ।

### स्थिर मस्यापन

कारखाना, प्रशिक्षण संस्थान, आईनिस, गोलाबारूद और गाड़ी दिरो, प्रयोगशालायें आदि जेने स्थिर संस्थापन सामान्यतः उन्हीं डोमीनियनों को दिये गये, जहाँ वे स्थित थे । कुछ मामलों में इन संस्थापनों के वस्तु उपकरणों का उपयुक्त अनुपात दूसरे डोमीनियन में ले जाये जाने के भी आदेश दे दिये गये ।

### प्रशिक्षण संस्थान

तीनों सेनाओं के प्रशिक्षण संस्थान पूरे देश में स्थित थे । सेना के अधिकार विद्यालय भारत में थे, जबकि ज्यादा महत्वपूर्ण नौसेना प्रशिक्षण स्थापनायें पाकिस्तान में थी । पाकिस्तान में स्थित ज्यादा महत्वपूर्ण प्रशिक्षण संस्थान, जिनके समान संस्थान विदेश होकर भारत में भी बनाने पड़ने, वे थे . स्टाफ कातेज, रॉयल इंडियन आर्मी सर्विस कौर स्कूल, इक्विटेशन स्कूल, एंटी एयरनाइट स्कूल, नेवन बायज ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट और पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल । दुहरे संस्थान बनाने, संयुक्त उपयोग और सेनाओं की प्रशिक्षण स्थापनाओं के नियन्त्रण की जिम्मेदारी पर साम्प्रजना-पुनर्गठन-समिति ने विचार किया । ऐसे भी स्कूल थे, जिनको अंशतः ही और विभिन्न खरणों में बांटा जा सकता था, पुनर्गठन काल में दोनों ही डोमिनियनों के काम आने वाले स्कूलों के बारे में समिति के बहुसंख्यक सदस्यों का विचार था कि ऐसी प्रशिक्षण स्थापनायें १ जून, १९४८ तक उच्चतम कमांडर ने नियन्त्रण में रहे, या जब तक दूसरे डोमिनियन में वैसी दूसरी स्थापना न बन जाय, अर्थात् दोनों में जो तारीख पहले पड़े । पर भारत का विचार था कि अपने क्षेत्र के प्रशिक्षण संस्थानों के ऊपर उसका नियन्त्रण सुरक्षित हो जाना चाहिये । यह माना गया कि उन सनो की एकदम नियन्त्रण में ले लेने में खतरा है, पर यदि हम अपने पेटों पर सजा होना है, तो ऐसा करना ही होगा । इस पर अनन्तिम-संयुक्त-रक्षा-परिषद् ने ६ अगस्त, १९४७ को फैसला किया कि १५ अगस्त, १९४७ के बाद दोनों डोमिनियन यथाशीघ्र परिषद् की बजा दें कि दोनों डोमिनियनों के काम आने वाली विभिन्न प्रशिक्षण स्थापनाओं का नियन्त्रण ने किस तारीख में अपने हाथ में लेना चाहते हैं । इस बीच विद्यमान संस्थाओं दोनों डोमिनियनों की जम्हरी को पूरा करती रहेंगी । प्रशिक्षण स्थापनाओं के संयुक्त उपयोग आने भी चालू रहने के प्रश्न पर सितम्बर, १९४७ ने मध्य में फिर चर्चा हुई । यह बताया गया कि यद्यपि कुछ प्रशिक्षण स्थापनाओं में, जैसे इंडियन मिनिस्ट्री एग्जेंटेमो में, विभिन्न देशों के प्रशिक्षणों साथ रहकर समन्वित में काम करना रहे है, कुछ अन्य स्थापनाओं में साम्प्रदायिक भावनाएं उभर चुकी हैं और बढ़ रही हैं । कुछ स्थापनाओं में प्रशिक्षणियों के बीच गुने संघर्ष का भी खतरा है । ऐसी स्थिति टावर के लिए अनुत्तर-रक्षा-

भी मसाला मेला पुनर्गठन-समिति की वायुसेना-उपसमिति इस बारे में एकमत थी कि पाकिस्तान को दो परिवहन स्क्वेड्रनों में से एक मिलना चाहिये। इसका मतलब था कि अगर बंटवारा विन्दु साम्प्रदायिक आधार पर किया जाय तो पाकिस्तान के हिस्से में एक ही लड़ाकू स्क्वेड्रन आना था। किन्तु मसाला मेला-पुनर्गठन-समिति के सदस्यों के बहुमत ने सुझाया कि पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रदेश में पाकिस्तान की जिम्मेवारी को देखते हुये वायुसेना के स्क्वेड्रनों का बंटवारा इस तरह किया जाये।

	पाकिस्तान	भारत
लड़ाकू स्क्वेड्रन	२	६
परिवहन स्क्वेड्रन	१	१

जब यह मामला विभाजन-परिषद् के सामने आया, तो भारत एक अतिरिक्त स्क्वेड्रन पाकिस्तान के दिये जाने के पक्ष में न था। आपत्ति इस आधार पर थी कि वायुसेना सीमान्त प्रदेश की जनता के विरुद्ध इस्तेमाल की जायेगी। वायुसेना बाहरी आक्रमण के विरुद्ध उपयोग के लिए होती है। वह यह ठक मानने के लिए तैयार नहीं है कि पश्चिमोत्तर सीमान्त में उनकी जिम्मेवारी के आधार पर ८० २० का अनुपात बदल दिया जाय, जो कि मेला में मुसलमानों और गैर मुसलमानों की सख्या पर आधारित है। यह सही है कि नौसेना में जहाजों का बंटवारा ७० ३० के आधार पर किया गया है, यद्यपि अभिलिखित साम्प्रदायिक सख्या ६० ४० थी और गुलना भारतीय नौसेना द्वारा निभाये जाने वाले दायित्वों को ध्यान में रखकर दी गयी थी। यह सम्मानना नहीं थी कि भारतीय नौसेना भारतीय जनता के विरुद्ध इस्तेमाल की जायेगी। भारत एक अतिरिक्त स्क्वेड्रन उधार या बंटवारे में भी देने को तैयार है यदि पाकिस्तान यह गारंटी दे कि इसका इस्तेमाल अधिभाजित भारत की मूल सीमा के भीतर जनजातियों पर हमला करने के लिए न किया जायेगा। पर विभाजन-परिषद् में पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने इस पर आपत्ति जिया कि मसाला-मेला-पुनर्गठन-समिति द्वारा सिफारिश किये गये अनुसार ही बंटवारा हो। अनिरोध पार करने के लिए लार्ड माउंटबेटन ने, जो परिषद् के अध्यक्ष थे, एक नया तरीका सुझाया कि अगर शिद्यमान आर्क्षित उपस्कर काफी मात्रा में हो, तो एक नया लड़ाकू स्क्वेड्रन खड़ा कर लिया जाय और नव पाकिस्तान का दो लड़ाकू स्क्वेड्रन दे दिये जायें। यह दोनों पक्षों को स्वीकार था और जाँच पर पता चला कि नव स्क्वेड्रन के लिए काफी समर्थन उपलब्ध है। इसलिए बंटवारे में दो लड़ाकू स्क्वेड्रन और एक परिवहन स्क्वेड्रन पाकिस्तान को और गान लड़ाकू स्क्वेड्रन और एक परिवहन स्क्वेड्रन भारत को मिले। दोष, आर्क्षित और पुराने आदि भी इसी अनुपात में बाँटे गये।\*

### रेजीमेन्ट की निर्धियाँ

यह निर्णय किया गया था कि पुनर्गठन पर जब सैनिक एक यूनिट से दूसरी में जायेंगे तो रेजीमेन्टों की निजी निर्धियों के जमा सैप का जो पूरा-पूरा या अंशतः वापसराय क्षमीकरण-

८०००० डीमीनियनों के बीच मसाला मेलाओं की विभिन्न यूनिटों के बंटवारे की पूरी माँगों पर ध्यान्य के अन्त में अनुगुण्य दो में मिल भक्ती है।



प्रान्त अधिकारियों या भारतीय अन्य भद्रों से प्राप्त चन्दे से बना है, एक अश स्थानान्तरित होने वाले सैनिकों को सस्या के अनुपात में स्थानान्तरित कर दिया जाय। अधिकारियों के मैसों की निधियाँ या सम्पत्ति अधिकारियों की निजी सम्पत्ति मानो गयी और वह सम्बन्धित रेजीमेंट के पास बनो रही।

### स्थिर स्थापन

कारखाना, प्रशिक्षण सस्यान, आर्डनेंस, गोलाबारूद और गाड़ी डिपो, प्रयोगशालायें आदि जैस स्थिर संस्थापन सामान्यतः उन्हीं डोमिनियनों को दिये गये, जहाँ वे स्थित थे। कुछ मामलों में इन संस्थापनों के बल उपकरणों का उपयुक्त अनुपात दूसरे डोमिनियन में ले जाये जाने के भी आदेश दे दिये गये।

### प्रशिक्षण संस्थान

तीनों सेनाओं के प्रशिक्षण संस्थान पूरे देश में स्थित थे। सेना के अधिकांश विद्यालय भारत में थे, जबकि ज्यादा महत्वपूर्ण नोसेना प्रशिक्षण स्थापनायें पाकिस्तान में थी। पाकिस्तान में स्थित ज्यादा महत्वपूर्ण प्रशिक्षण संस्थान, जिनके समान स्थापन विवाद होकर भारत में भी बनाने पड़ते, वे थे. स्टाफ कालेज, रॉयल इंडियन आर्मी सर्विस कोर स्कूल, इन्विटेशन स्कूल, एटो एयरक्राफ्ट स्कूल, नेवल वायज ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट और पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल। दुसरे संस्थान बनाने, समुचित उपयोग और सेनाओं की प्रशिक्षण स्थापनाओं के नियन्त्रण की जिम्मेदारी पर सशस्त्र-सेना-पुनर्गठन-समिति ने विचार किया। ऐसे भी स्कूल थे, जिनको भंडार. ही और विभिन्न चरणों में बाँटा जा सकता था, पुनर्गठन काल में दोनों ही डोमिनियनों के काम आने वाले स्कूलों के बारे में समिति के बहुसंख्यक सदस्यों का विचार था कि ऐसी प्रशिक्षण स्थापनायें १ अप्रैल, १९४८ तक उच्चतम कमांडर के नियन्त्रण में रहे, या जब तक दूसरे डोमिनियन में वैसी दूसरी स्थापना न बन जाय, अर्थात् दोनों में जो तारीख पहले पड़े। पर भारत का विचार था कि अपने क्षेत्र के प्रशिक्षण संस्थानों के ऊपर उसका नियन्त्रण सुरक्षित हो जाना चाहिये। यह माना गया कि उन सभी को एकदम नियन्त्रण में ले लेने में खतरा है, पर यदि जमे अपने पैरों पर खड़ा होना है तो ऐसा करना ही होगा। इस पर अन्तिम-संयुक्त-रक्षा-परिषद् ने ९ अगस्त, १९४७ को फैसला किया कि १५ अगस्त, १९४७ के बाद दोनों डोमिनियन दयाशील परिषद् को बता दें कि दोनों डोमिनियनों के काम आने वाली विभिन्न प्रशिक्षण स्थापनाओं का नियन्त्रण वे किस तारीख से अपने हाथ में लेना चाहते हैं। इस बीच विद्यमान संस्थाएँ दोनों डोमिनियनों की जरूरतों को पूरा करती रहेंगी। प्रशिक्षण स्थापनाओं के संयुक्त उपयोग आगे भी चालू रहने के प्रश्न पर सितम्बर, १९४७ के मध्य में फिर चर्चा हुई। यह बताया गया कि यद्यपि कुछ प्रशिक्षण स्थापनाओं में, जैसे इंडियन मिलिट्री एकेडेमी में, विभिन्न देशों के प्रशिक्षार्थी साथ रहकर समन्वित से काम चला रहे हैं, कुछ अन्य स्थापनाओं में साम्प्रदायिक भावनाएँ उभर चुकी हैं और बढ़ रही हैं। कुछ स्थापनाओं में प्रशिक्षार्थियों के बीच खुले संघर्ष का भी खतरा है। ऐसी स्थिति टालने के लिए संयुक्त-रक्षा-

परिपक्व ने निर्णय किया कि दुहरी स्थापना खटी करने में, दूसरे डोमीनियन के योग्य हो जाने की प्रतीक्षा बिना किए, एवं डोमीनियन के सभी प्रशिक्षार्थियों और कर्मचारियों को दूसरे डोमीनियन में स्थित सभी सयुक्त प्रशिक्षण स्थापनाओं में हटा लिया जाय। इस सिद्धांत के किसी खाम म्यापना पर लागू किये जाने की बात तय करना भारत और पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं के कमांडरो के परामर्श से उत्तम कमांडर के विवेक पर छोड़ दिया गया। यह भी तय किया गया कि जहाँ सम्भव हो सयुक्त प्रशिक्षण उस समय चातू पाठ्यक्रम के अन्त तक चलना रहे। सितम्बर तक नौसेना और वायुसेना के लिए कोई भी सयुक्त प्रशिक्षण स्थापना चातू न रही हो। अक्टूबर, १९४७ के अन्त तक एक डोमीनियन के प्रशिक्षार्थियों और कर्मचारियों को दूसरे डोमीनियन में स्थित चल-सेना प्रशिक्षण स्थापनाओं में भी हटा लिया गया।

### उपसमिति की सदस्य-सख्या में कमी

उपसमितियों का मुख्य काम १५ अगस्त, १९४७ तक पूरा हो गया था। उसके बाद उपसमितियों की सदस्य-सख्या घटा कर दो कर दी गयी। अर्थात्, एक भारतीय अधिकारी, एक पाकिस्तानी अधिकारी, एक ब्रिटिश अधिकारी, दो वित्तीय सदस्य और एक सचिव। १ सितम्बर, १९४७ तक यह सख्या और भी कम करके एक ब्रिटिश, एक भारतीय और एक पाकिस्तानी अधिकारी कर दी गयी। आगे चलकर उपसमितियों का काम स्वीकृत निर्णयों का निर्वचन करना, कामपालन कृत्य के लिए जिम्मेवार सयुक्त सशस्त्र सेना मुख्यालयों को सलाह देना और सयुक्त सशस्त्र सेना मुख्यालयों और दोनों डोमीनियनों के मुख्यालयों के बीच सम्पर्क रखना ही रह गया।

### सीमा दल

यद्यपि हमारा सम्बन्ध सीधे सशस्त्र सेनाओं के पुनर्गठन से नहीं है, फिर भी ये अभिनेता उन कदमों का उद्देश्य निये बिना पूरे न होंगे, जो १५ अगस्त, १९४७ के पहले और बाद में दोनों सीमाओं के पास हुए उपद्रवों में निपटने के लिए उठाये गये। ३० जून, १९४७ को कमांडर इन-चीफ से कहा गया कि वे ऐसी आकस्मिकता से निपटने के सर्वोत्तम उपाय बनाने वाले सुविचारित प्रस्ताव प्रस्तुत करें। अनेकित व्यवस्था पर विभाजन-परिपक्व में १७ जुलाई, १९४७ की चर्चा हुई। यह निर्णय किया गया कि पंजाब के सम्भाव्य उपद्रव-क्षेत्रों में कार्य करने के लिए एक सीमा दल पहले में ही पंजाब में स्थित चौथे भारतीय डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल रोस को अध्यक्षता में बनाया जाय, जो दोनों डोमिनियनों की ओर में सयुक्त कमांडर हों। मेजर जनरल रोस ने पंजाब के परिभाषित क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी सेनिकों का नियन्त्रण संभाला और वह उत्तम कमांडर के जरिए सयुक्त-रक्षा-परिपक्व के प्रति उत्तरदायी था। (यह पूर्वाना नहीं की गयी थी कि बंगाल में कोई ज्यादा गम्भीर उपद्रव होना, नाकि वहाँ भी ऐसा दम रचना जरूरी हो जाये। अगर जरूरत पड़े तो वही सिद्धान्त बंगाल पर भी लागू निये

जावें। जैसा सुविदित है, अकेले गान्धी जी बंगाल में एक सोमादल के समान प्रभावी हुए। सोमादल के सभी जैनिक भारतीयों के और दल में जिने-श्रुते लोगों की धूमिल थी, ताकि पञ्च-पात्रिता के बिना ऐसे सम्भव आरोपों से बचा जा सके, जो तब लगाये जा सकने थे, जब केवल एक ही दल के सैनिकों से बनी वटाविलियन का प्रयोग किया जाता। अनेक ब्रिटिश अधिकारी सैनिकों के कमान-धारी थे और सयुक्त कमांडर के स्टाफ में उपयुक्त बरिष्ठता वाले एक मुसलमान और एक निख अधिकारी की सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। १५ अगस्त, १९४७ के बाद दोनों डोमोनियनों के सैनिकों के ऊपर, केवल इस मान में, सक्रियतागत नियन्त्रण उच्चतम कमांडर के हाथ में बना रहा।

यह निर्णय किया गया कि १५ अगस्त के बाद उपद्रवों को दशाने में असैनिक सत्ता की मदद के लिए जितने समय तक सैनिकों को लगाया जाय, उनके उपयोग को शामिल करने वाले कानून में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन सोमा-दल का इस तरह उपयोग करने से पहले एक विपक्षी कठिनाई को पार करना था। जनसंख्या बनाये रखना एकमात्र प्रादेशिक विषय था और सयुक्त-रक्षा-परिषद् के पास ऐसी कोई शक्ति न थी कि किसी प्रभावित जिले को उपद्रवग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दे। ऐसी घोषणा एक प्रदेश-सरकार ही कर सकती थी और जब तक ऐसा न हो, सशस्त्र सेना के सदस्य उस क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों और मजिस्ट्रेटों की शक्ति का उपयोग न कर सकते थे। फलस्वरूप भारत सरकार अधिनियम १९३५ की धारा १२६ (५) में उपयुक्त अनुकूलन किया गया ताकि डोमोनियन सरकारें प्रान्तों को भारत या उसके किसी भाग में, शान्ति और प्रशान्ति के लिए घोर संकट की स्थिति को रोकने के प्रयोजन से, प्रदेशों को उपयुक्त निर्देश दे सके। तदनुसार पंजाब सरकार से कहा गया कि संगठित प्रान्तीय अधिनियम के अन्तर्गत १ अगस्त, १९४७ से प्रान्त के कुछ जिलों को 'उपद्रवग्रस्त क्षेत्र' घोषित कर दे। इस बारे में भी बहस उठाये गये कि पूर्वी पंजाब तथा पश्चिमी पंजाब को सरकारों को, भारत तथा पाकिस्तान की केन्द्रीय सरकार की सहमति के बिना, घोषणा को रद्द करने से रोक जा सके। जुलाई के तीसरे सप्ताह में पंजाब के गवर्नर, उत्तरी कमान के जनरल अफमर कमांडिंग और पंजाब-विभाजन-समिति के साथ परामर्श करके, ऐसे १२ जिलों की सूची बनायी गयी, जो गम्भीर रूप से उपद्रवग्रस्त होने की सम्भावना वाले थे और जहाँ सोमादल को सुरक्षा करनी थी। १ अगस्त, १९४७ तक सोमा दल ने अपनी जगह संभाल ली।

जैसा भय था, विभाजन के फलस्वरूप पंजाब के सोमा जिलों में बस्तुन भयंकर स्थिति पैदा हो गयी। सोमा दल के सैनिकों की उपस्थिति ने ही पूर्ण हत्याकाण्ड और जागृनी को रोके रखा। सैनिकों को बड़ी संख्या में दंगाइयों को मारना पड़ा, लेकिन शोष हो साट हो गया कि स्थिति प्रत्याशा से नहीं ज्यादा गम्भीर है। आरम्भ में तो सैनिक अपने कर्तव्य का पालन करने में पूरी तरह निष्पक्ष रहे, यद्यपि इसके विपरीत सेना के कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाये गये। शोष ही शरणाथियों की उपस्थिति ने सोमा दल का काम बहुत मुश्किल कर दिया। शरणाथी अपने प्रति हुए दुर्व्यवहार की करुण-कथाएँ कहने थे और जहाँ वे पहुँचने थे, उनको बचाओ में जाग भड़कना अनिवार्य हो जाता था और फलस्वरूप और अधिक प्रतिशोध लिए जाते थे। शरणाथी भी सैनिकों की अनुरक्षा में ले जाये जाने पर और शिथिलों में उनको

मरधा में रहने पर अपने को काफी सुरक्षित समझने थे। २५ अगस्त, १९६७ को समुक्त-रक्षा-परिषद् ने निर्णय किया कि यथासम्भव शरणार्थी जिविरो को रक्षा, को जाव और शरणार्थी काफिलों की अनुरक्षा के लिए उनके ही सम्प्रदाय के सैनिक भेजे जायें।

बठिन परिस्थिति के बावजूद सीमादल के मैनिंक पहले दो-तीन हफ्ते प्रगमनीय रूप में निष्पक्ष बने रहे। पर धीरे-धीरे मैनिंको पर भी दबाव बढ़ रहा था, भारतीय अधिकारियों पर (यूरोपीय अधिकारियों को तुलना में) सैनिकों की अपेक्षा कहीं ज्यादा। क्षान्ति भंग करने वाले लोगों के खिलाफ सैनिकों ने जो कार्रवाई की, वह बड़ी बठोर रही—सामान्य परिस्थितियों में जितना उपयुक्त समझा जाता उसके अनुपात में कहीं ज्यादा उग्र। काफी लोग मारे गये। फिर ऐसी घटनाएँ भी होने लगी, जिनमें अपने ही सम्प्रदाय के लोगों के विरुद्ध आक्रामक कार्रवाई करने का आदेश मिलने पर, उनका कार्य बिला रहा और एकाध उदाहरण ऐसे भी मिले कि जहाँ सैनिकों को हस्तक्षेप करना चाहिये था, वे चुपचाप खड़े रहे। कमांडर ने अनुभव किया कि सीमादल के मैनिंको की निष्पक्षता इतनी प्रभावित हो सकती है कि विधि-व्यवस्था बनाये रखने की उनकी योग्यता को भी मन्द कर दे। दोनों डोमीनियनों की सेनाओं के बीच सभावित भगटे बचाने के लिए यह निश्चय किया गया कि पञ्जाब सीमा दल के सैनिकों को पुनर्बिगत किया जाय जिसमें भारतीय सेना को दो गयी घुनटें पूर्वी पञ्जाब में रहे और पाकिस्तान सेना को दो गयी घुनटें पश्चिमी पञ्जाब में। इसके बाद किसी डोमीनियन की सेनाएँ सत्रिया-गत रूप से आवश्यक होने पर ही सीमा पार करेंगी, जैसे कि जिन उग्र जत्थों को उन्होंने घेर रखा है, वे सीमा पार कर जायें।

अगस्त के अन्त तक उपद्रव पञ्जाब सीमा दल के क्षेत्र के बाहर के इलाकों में फैल चुके थे, जिनको रोकने के कोई साधन दल कमांडर के पास न थे। उन्होंने कहा कि जिन असाधारण परिस्थितियों में वे पड़ गये हैं, उनके कारण, और जिन परिस्थितियों में उन्हे असैनिक सत्ता की सहायता करने की माँग की जा रही है, उसके दबाव के कारण, भारतीय (ब्रिटिशों से पूर्व) अधिकारी और सैनिक भी अनिवार्यतः साम्प्रदायिक चिप के शिकार हो गये हैं। उनको भय था कि हालत और बिगड़ती जायेगी। इसलिए उन्होंने यह निवेदन किया कि अपने कमान की सेनाओं की विद्वसनीयता की अब और आगे, और ज्यादा में ज्यादा सितम्बर के मध्य के बाद, गारंटी देना उनके लिए सम्भव नहीं है। विधि-व्यवस्था बनाये रखने के काम की जो बल्लना सीमादल के गठन के समय की गयी थी, तबसे स्थिति बहुत ही अधिक उग्र हो चुकी है और अब पैदा हुई स्थिति उसकी क्षमता और नियन्त्रण में परे है। यद्यपि सैन्य-दृष्टिकोण में पञ्जाब सीमादल सुरक्षा बनाये रखने के लिए सर्वोत्तम साधन है, तथापि राजनयिक बातों की ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया कि ३१ अगस्त/१ सितम्बर की रात में सीमादल को सत्तम कर दिया जाय और विधि-व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेवारी सम्बन्धित सरकारों की गोप दी जाय। यह भी तय किया गया कि दोनों में से प्रत्येक डोमीनियन, अब तक पञ्जाब सीमादल के अधीन आने वाले क्षेत्र के नियन्त्रण के लिए, अलग-अलग नये सैन्य मुख्यालय गठित कर और हम प्रयोजन में साहौर एरिया का मुख्यालय और चौथे भारतीय डिमोजन का मुख्यालय दोनों ही साहौर में रहे जायें, ताकि निवट मगरा रखा जा सके। योत्र हो यह भी

उत्पन्न माना गया कि शरणार्थी शिविरो की रक्षा उसी समुदाय के सैनिक करे, पर यह व्यवस्था सेनाओं के पुनर्गठन के लिए सैनिकों के आने-जाने में बाधक न बने। शरणार्थी शिविर जिस डोमीनियन में है, उसकी रक्षा की जिम्मेवारी उसी की है, लेकिन एक डोमीनियन की सेनायें शरणार्थियों को पहुँचाने और शरणार्थी-शिविरो की रक्षा के लिए अगर दूसरे डोमीनियन में सीमा पार कर जायें, तो कोई आपत्ति नहीं है।

### समुक्त-रक्षा-परिषद् की बैठकें

अब हम मूल बात की ओर आते हैं। समुक्त-रक्षा-परिषद् की बैठकें दिल्ली में सितम्बर के अन्त तक चलती रही, पर समुक्त-रक्षा-परिषद् सचिवालय के मुसलमान कर्मचारियों को होने वाली कठिनाइयों की दृष्टि में रक्तकर १ अक्टूबर, १९४७ को यह निर्णय लिया गया कि आगे से समुक्त-रक्षा-परिषद् की बैठकें पाक्षिक और वैकल्पिक रूप से दिल्ली और लाहौर में बुलाई जायें और भारत के गवर्नर जनरल लाहौर और दिल्ली दोनों जगह बैठकों की अध्यक्षता करें। इस निर्णय के फलस्वरूप समुक्त-रक्षा-परिषद् की बैठकों की समिति का कार्य भारत के गवर्नर जनरल के सम्मेलन सचिव, ले० कर्नल बी० एफ० एरस्किन क्रम ने अपने हाथ में ले लिया।

### पुनर्गठन की प्रगति

सितम्बर के पहले हफ्ते तक नौसेना और वायुसेना के सदस्यों के, सम्बन्धित डोमीनियन को जाने के प्रसंग में, पुनर्गठन काफी पूरा हो चुका था। अक्टूबर के मध्य तक नौसेना और वायुसेना का बँटवारा अधिकारियों-सैनिकों और पोतों तथा विमानों के मामले में प्रायः पूरा हो चुका था। यद्यपि सस्या की दृष्टि से ये दोनों सेनायें छोटी थी, पर फिर भी वे अखिल भारतीय आधार पर ज्यादा निकट रूप से सम्बद्ध थी और उनके बँटवारे की समस्या सरल नहीं। सेना के पुनर्गठन के सिलसिले में दो अलग-अलग और बड़े जटिल कार्यक्रम चलाने पड़े। बड़ी इकाइयों और उप-यूनिटों के, एक डोमीनियन में दूसरे में ले जाने के लिए, विस्तृत और व्योरेवार कार्यक्रम बनाना पड़ा और ११० विशेष रेल गाड़ियाँ चलानी पड़ी। इस आवागमन में ही सेना को उपलब्ध पूरी-पूरी रेल-क्षमता खर्च हो गयी। बड़ी-बड़ी इकाइयों-रेजीमेन्टों बटालियनों और कम्पनियों—का आवागमन शरणार्थियों की रक्षा के लिए, दूसरे डोमीनियन में छोड़ी गयी यूनिटों के अनावा, प्रायः ३१ अक्टूबर तक पूरा हो गया। बड़ी-बड़ी इकाइयों का स्थानान्तरण पूरा हो जाने के बाद व्यक्तियों का भेजा जाना शुरू किया गया। योजना यह बनी थी कि बड़ी-बड़ी इकाइयों और व्यक्तियों का आवागमन १ दिसम्बर तक पूरा हो जाएगा, मूल योजना को कार्यान्वित करने में कुछ देर हो गयी, जिसका कारण यातायात का अव्यवस्थित हो जाना और शरणार्थियों का आवागमन था।

उच्चतम कमांडर ने तारीख ३३ अक्टूबर, १९४७ की एक लिपणी में, जो समुक्त-रक्षा-परिषद् के पास प्रस्तुत की गयी थी, यह सिफारिश की थी कि उच्चतम कमांडर और उसके मुख्यालय का काम ३० नवम्बर से खत्म कर दिया जाय। उन्होंने बताया कि रेल और सड़क-यातायात के अव्यवस्थित होने से, और पंजाब के उपद्रवों और बड़े पैमाने पर शरणार्थियों के

आवागमन द्वारा खड़ी हुई बाधा के बावजूद, और हाल की भारी वाद द्वारा स्थिति और भी खराब होने के बावजूद, मंगल सेनाओं के पुनर्गठन में उन्नेखनीय प्रगति की जा चुकी है।

सेना के पुनर्गठन का अन्तिम हिस्सा, जो रोप था, वह चल परिसम्पत्तियों का बंटवारा था, जिसमें स्टाक का सन्धारण और कार्यकरण और युद्ध और सामग्री रक्षितियाँ आती थीं। भारी मात्रा में भण्डार का प्रदन होने से इन रक्षितियों और स्टाक के भौतिक बंटवारे में कई महीने लगने की सम्भावना थी। इस विभाजन का उत्तरदायित्व उच्चतम कमांडर के मुख्यालय का था। भले ही मुख्यालय अप्रैल, १९४८ तक बना रहूँ, जैसी कि सयुक्त-रक्षा-परिपद् धष्टि करने वाले आदेश में मूलतः प्रत्याज्ञा की गयी थी, पर उसके द्वारा काम पूरा हो सने की सम्भावना न थी। चन-भण्डार को छोड़कर उच्चतम कमांडर के मुख्यालय का बहुत कुछ काम पूरा हो चुका था।

### उच्चतम कमांडर के मुख्यालय का समेटा जाना

उच्चतम कमांडर का मुख्यालय, भारत और पाकिस्तान से ब्रिटिश सेना और रॉयल एयर फोर्स की यूनिटों के प्रत्यावर्तन, और भारत और पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं के साथ काम कर रहे ब्रिटिश अधिकारियों तथा अन्य पदवारियों के कल्याण और सुरक्षण के लिए भी, उत्तरदायी था। लेकिन कमांडर का विचार था कि केवल ब्रिटिश अधिकारियों और अन्य पदवारियों की देखभाल के ही लिए उच्चतम कमांडर और उसने मुख्यालय को बनाये रखना उपयुक्त नहीं है। उच्चतम कमांडर ने बताया कि चालू स्थिति में सशस्त्र सेनाओं के पुनर्गठन के बारे में अपने दायित्व को निभाता उनके लिए कठिन हो रहा है। उनका विचार था कि वर्तमान वित्तविवरण में उनके और उनके अफसरों के लिए व्यवहारतः उस सारोस (अर्थात् ३० नवम्बर) के बाद काम करना असम्भव हो गया है। वह एक असम्भव स्थिति में अपने अधिकारियों को रखने के लिए तैयार नहीं है। उनके मुख्यालय के विरुद्ध लगातार आक्षेप और आरोप लगाये जा रहे हैं और यह स्पष्ट है कि ऐसी परिस्थिति में और उनके अधिकारी ऐसा काम आगे चलाते हैं असमर्थ हैं, जिसके लिए सहयोग बहुत जरूरी है। इसलिए उच्चतम कमांडर ने सिफारिश की कि उनका मुख्यालय ३० नवम्बर, १९४७ को समाप्त कर दिया जाय। जब यह प्रस्ताव सयुक्त-रक्षा-परिपद् के सामने १६ अक्टूबर, १९४७ को लाहौर में आया, तब इस आधार पर पाकिस्तान हमने वगैरे में था कि उच्चतम कमांडर के मुख्यालय को मौफा दिया काम पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। भारत उच्चतम कमांडर द्वारा किये गये स्थिति-मुख्यालय से तो सहमत न था, पर उसने इस प्रस्ताव का समर्थन दिया। उसने समझा कि उच्चतम कमांडर का सही गये अधिकाधिक कार्य के पूरे हो जाने पर, न तो यह जरूरी हो था और न वादनीय ही कि सामान्य प्रक्रिया को छोड़कर, जिसके अनुसार दोनों सरकारों के बीच आने वाली कठिनाइयों पर दोनों सरकारों के प्रतिनिधि हो चर्चा करके उसे निपटा लेते हैं, उसी जगह उच्चतम कमांडर के मुख्यालय जंग विशेष ढाँचे को रखा जाये। पाकिस्तान का विचार अब भी यही था कि चन-भण्डार का बंटवारा उच्चतम कमांडर के अधीन हो हो जाय और जब तब यह काम न हो, उसका मुख्यालय बना देने दिया जाय।

उच्चतम कमांडर के प्रस्ताव के अनुसार, उच्चतम कमांडर के मुख्यालय के विघटन के बाद, भण्डार उस डोमीनियन की सशस्त्र सेना की देखभाल में छोड़ दिये जायेंगे, जहाँ वे रियल हैं। भारत के रक्षा-मन्त्री ने अपनी सरकार की ओर से यह वचन दिया कि वे इस मामले में हुए निर्णयों के अनुसार, पाकिस्तान के हिस्से के भण्डार उसे सौंपने की पूरी जिम्मेवारी लेते हैं। इसके बावजूद बैठक में कोई निर्णय न लिया जा सका और भारत तथा पाकिस्तान की सरकारों से अनुरोध किया गया कि उच्चतम कमांडर के मुख्यालय के भविष्य के बारे में वे अपने-अपने मन्त्रिमण्डलों में विचार करें।

ब्रिटिश अधिकारियों के दृष्टिकोण में इसका सम्बन्ध ब्रिटिश सरकार में भी था, इसमिए लन्दन में भी पूछा गया। संयुक्त-रक्षा-परिपद् की इस बैठक के सिलसिले में उसके अध्यक्ष लार्ड माउंटबेटन ने बोनों डोमीनियनों के बीच उस समय की भावनाओं का एक संकेत दे दिया था। उन्होंने कहा था कि उनके विचार से पाकिस्तान के गवर्नर जनरल और भारत के प्रधान मन्त्री दोनों ही इस बात से अवगत होंगे कि अगर दोनों डोमीनियनों के बीच युद्ध छिड़ जाने जैसी निम्ननीय घटना घटी तो दोनों में से प्रत्येक डोमीनियन में काम करने वाले ब्रिटिश अधिकारी किसी भी परिस्थिति में परस्पर न लड़ेंगे।

अपने-अपने मन्त्रिमण्डलों में विचार करने के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों की ही सरकारों ने अपनी-अपनी पहली वाली बात का ही समर्थन किया। महामहिम सम्राट की सरकार के विचार भी तार से ७ नवम्बर, १९४७ को प्राप्त हो गये, जिसमें बताया गया था कि पैदा हुई परिस्थिति में और उच्चतम कमांडर के अभ्यावेदन की दृष्टि में महामहिम सम्राट् की सरकार अनिच्छापूर्वक इस निकर्ष पर पहुँची कि उसके पास इसके सिवाय अब और कोई विकल्प शेष नहीं है कि स्वयं उच्चतम कमांडर समेत सभी ब्रिटिश अधिकारियों और अन्य पदधारियों को वापस बुला ले। तदनुसार उच्चतम कमांडर का मुख्यालय ३० नवम्बर १९४७ को खत्म कर दिया गया। संयुक्त-रक्षा-परिपद् की ७ मार्शल आर्म्सलेफ को पूरे वेतन पर चार महीने की छुट्टी १ दिसम्बर १९४७ से देना चाहनी थी, पर इसमें कुछ विधि सम्बन्धी कठिनाइयाँ थी। १५ अगस्त १९४७ से पहले ही, जब भारत सरकार अधिनियम १९३१ की नवी अनुसूची में, जो प्रभावी थी, उनके भारत के कमांडर-इन-चीफ का पद खाली कर देने के बाद, उनको पूरे वेतन की छुट्टी देना अनुमत न था। संयुक्त-रक्षा-परिपद् के आदेशों में भी उनकी सेवा की शर्तें और निदयन स्पष्ट न किये गये थे। इन कठिनाइयों की दृष्टि से संयुक्त-रक्षा-परिपद् ने फील्ड मार्शल आर्म्सलेफ को चार महीने के आधे वेतन और पूरे वेतन का अन्तर अनुग्रह-अनुदान के रूप में मंजूर कर दिया।

अब संयुक्त-रक्षा-परिपद् की रचना में परिवर्तन करना पड़ा। ३

७ संयुक्त-रक्षा-परिपद् की संशोधित रचना संयुक्त-रक्षा-परिपद् (संशोधन) आदेश, १९४७ (अधिसूचना संख्या जी. जी. ओ. ३०, तारीख २ दिसम्बर, १९४७ में दी गयी है।)

### ३० नवम्बर, १९४७ के बाद संयुक्त रक्षा परिषद् की रचना

अब परिषद् में भारत के गवर्नर जनरल स्वतन्त्र अध्यक्ष के रूप में थे और भारत के रक्षा-मन्त्री तथा एक और मन्त्री तथा पाकिस्तान के रक्षा-मन्त्री तथा एक और मन्त्री उसके सदस्य थे। यह भी व्यवस्था की गयी कि परिषद् की प्रत्येक बैठक में प्रत्येक डोमिनियन के तीन मेनाध्यक्षों में से एक सलाहकार की हैसियत में उपस्थित रहेगा।

मशौघित आदेश के अधीन संयुक्त-रक्षा-परिषद् अब भी इन कार्यों की नियंत्रक बनी रही। सशस्त्र सेनाओं के विभाजन और उनके दो अलग डोमिनियनों की सेनाओं के रूप में पुनर्गठन, ऐसे पुनर्गठन के लिए अधिकारियों और सैनिकों के वण्टन, परिवहन और आवागमन और सशस्त्र सेनाओं के पुनर्गठन के लिए अविभाजित भारत की सशस्त्र सेनाओं के संयन्त्र, मशीनरी, उपकरण और भण्डार के वण्टन, स्थानान्तरण और आवागमन अब वह 'आइर्नस' कारखानों में मैग्नेट-भण्डार और उपकरण के उत्पादन (जिसमें इस उत्पादन के लिए किसी आइर्नस कारखाने की पूरी या एकाग्र क्षमता का वण्टन शामिल था) की नीति निर्धारित करती थी और आइर्नस कारखानों में उत्पादित सभी मैग्नेट-भण्डार और उपकरण का निपटारा करती थी।'

उच्चतम कमांडर के मुख्यालय की समाप्ति के बाद संयुक्त-रक्षा-परिषद् अब शेष रह गए प्रश्नों की निपटाती रही। उसके निर्णयों का अनुपालन दोनों डोमिनियन करते थे।

उच्चतम कमांडर के मुख्यालय के विघटन के बाद उच्चतम कमांडर की अध्यक्षता वाली सशस्त्र-सेना-पुनर्गठन-समिति और उसकी तीनों सेनाओं वाली उपसमितियाँ ३० नवम्बर, १९४७ में समाप्त हो गयीं।

फिर भी कुछ अन्य डोमिनियन समितियाँ थी, जैसे आइर्नस-भण्डार-उपसमिति (पुनर्गठन), जो आइर्नस-भण्डारों के बँटवारे के प्रस्ताव तैयार करती थी और संयुक्त-इंजीनियर-भण्डार और भण्डार-आवागमन-समिति तथा इतिहास अनुभाग (जिसमें दूसरे विश्वयुद्ध का अधिवृत्त इतिहास, खासकर अविभाजित भारत की सशस्त्र सेनाओं ने जिन सक्रियताओं में भाग लिया था, उनके प्रमाण में संकलित करने के लिए गठित किया गया था) जैसे कुछ संयुक्त संगठन अब भी काम कर रहे थे। इसलिए यह जरूरी समझ गया कि इन सभी तकनीकी समितियों के लिए एक समन्वय प्राधिकार हो, जो यदि सम्भव हो तो उनके मतभेद निपटा सके और उनकी प्रगति संयुक्त-रक्षा परिषद् की बढावा दे। तदनुसार सशस्त्र-सेना-पुनर्गठन-समिति के उत्तरवर्ती के रूप में संयुक्त-रक्षा-परिषद् की एक कार्यपालक समिति बनायी गयी। इसमें दोनों रक्षा-सचिव थे, (मना के) दोनों कमांडर-इन-चीफ सदस्य थे और एक ब्रिटिश अधिकारी भी उसका सदस्य था। बाद में दोनों रक्षा-मन्त्रालयों के वित्तीय सलाहकारों को भी सदस्यों के रूप में शामिल करने हेतु विन्युक्त कर दिया गया। संयुक्त-रक्षा-परिषद् कार्यपालक-समिति की पहली बैठक २६ नवम्बर, १९४७ का हुई और आखिरी बैठक १८ मार्च, १९४८ की। इस दौरान इसकी पाँच बैठकें दिन्नी, कराची और लाहौर में हुईं।

शेष काम में सहाय्य करने के लिए उच्चतम कमांडर के सचिवालय को बटे-भट्टे रूप में पुनर्गठन-सचिवालय के रूप में बनाये रखा गया। ज्ञान और अनुभव के आधार पर उच्चतम



कमांडर के सचिवालय के सचिव को पुनर्गठन-सचिवालय का सचिव नियुक्त किया गया। वे सशुक्र-रक्षा-परिषद् की कार्यपालक-समिति के भी सचिव थे।

### ब्रिटिश सैनिकों का निष्क्रमण

उच्चतम कमांडर के मुख्यालय की समाप्ति के फलस्वरूप भारत और पाकिस्तान में ब्रिटिश सैनिकों के निष्क्रमण की व्यवस्था करना जरूरी हो गया। ३० नवम्बर, १९४७ को शरिवारों समेत लगभग ३०,००० ब्रिटिश नागरिक प्रत्यावर्तन के लिए शेष रह गये थे, जबकि सितम्बर में यह संख्या ४२,००० थी।

उच्चतम कमांडर के मुख्यालय के वन्द हो जाने के बाद ब्रिटिश सैनिकों के निष्क्रमण का काम जारी रखने के लिए लेफ्टीनेंट जनरल के पद के एक अधिकारी को भारत और पाकिस्तान में ब्रिटिश सेना के कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया, और भारत और पाकिस्तान में ब्रिटिश सेना-मददों के बारे में जो जिम्मेदारियाँ पहले उच्चतम कमांडर को मिली हुई थी, उसको सौंपी गयी। नये कमांडर की कोई जिम्मेवारी दोनों डोमिनियनों को सहाय्य मेनाओ के पुनर्गठन के बारे में न थी और उनमें काम कर रहे ब्रिटिश व्यक्तियों को छोड़कर उनसे उसका कोई नाता न था। उसका एक छोटा-सा मुख्यालय दिल्ली में था, जिसमें उतने ही मेना, गौमेना और वायु-सेना अधिकारी रहे गये थे, जो उसके दायित्व के निर्वहन के लिए जरूरी थे। ३१ दिसम्बर, १९४७ को, जब भारत और पाकिस्तान की सहाय्य सेनाओं में काम कर रहे ब्रिटिश अधिकारियों और अन्य पदधारियों की मूल संविदायें समाप्त हो गयी, तब ब्रिटिश मेना के कमांडर और उसका मुख्यालय भी समाप्त हो गये। उसके बाद भारत और पाकिस्तान ने सीधे ही महामहिम सम्राट की सरकार के साथ ब्रिटिश अधिकारियों की सेवायें जारी रखने के लिए व्यक्तिगत बात-चीत चलायी। फरवरी, १९४८ से पहले, ब्रिटिश सैन्यजनों का प्रत्यावर्तन पूरा होने की सम्भावना न होने के कारण, उनका नियन्त्रण करने के लिए और उनके निष्क्रमण की व्यवस्था के लिए कुछ-न-कुछ संगठन जरूरी था। यह नियन्त्रण दो छोटे-छोटे स्वतन्त्र ब्रिटिश मुख्यालय बना कर रखा गया, जिनमें से एक मेजर जनरल के अधीन देवलाही (बम्बई) में था और दूसरा कराची में एयर कमांडर के अधीन था। इन दो मुख्यालयों का एकमात्र काम प्रत्यावर्तन की प्रतीक्षा करने वाली मूनिटों और व्यक्तियों को प्रेषित करना था, जो भारत में देवलाही और कन्यात में और पाकिस्तान में कराची में मन्त्रण-विधियों में एकत्र होते थे। दोनों मुख्यालय भारतीय उप-महाद्वीप में किसी एक सशुक्र केन्द्रीय नियन्त्रण के अधीन न थे और वे यथास्थिति इंग्लैंड की सरकार और भारत और पाकिस्तान के रक्षा-मन्त्रालयों के साथ सीधे-सीधे सभी ब्रिटिश अधिकारियों या पदधारियों के कल्याण या निष्क्रमण के बारे में पत्राचार करते थे।

इंग्लैंड से ब्रिटिश सैनिकों की पहली टुकड़ी १७५४ में भारत पहुँची थी। भारत छोड़ कर जाने वाली ब्रिटिश सैन्य-बल को पहली टुकड़ी १७ अगस्त, १९४७ को बम्बई से गयी। उसके बाद, देश के भीतर आवागमन की स्थिति बिगड़ने न देने की जरूरत का ध्यान रखते हुए, जो (सैन्य और असैनिक) व्यक्तियों के स्थानान्तरण और विस्थापित व्यक्तियों के आवागमन के कारण काफी कठिन हो गयी थी, और इंग्लैंड के परिवहन-मन्त्रालय द्वारा उपलब्ध किये गये

जहाजों की मात्रा का ध्यान रमते हुए, इन सेनाओं की तेजो से भेजा जाता रहा। पहले यह आशा थी कि पृथक्करण का सारा कार्यक्रम १९४७ तक पूरा हो जायेगा। पर जहाजों की कमी के कारण इस कार्यक्रम के अनुपालन में कुछ विलम्ब हुआ और अन्तिम दुकड़ी भारत का तट छोड़ कर २८ फरवरी १९४८ को गयी। १५ अगस्त के बाद से अपने प्रत्यावर्तन के समय तक, भारत में रही इन सेनाओं का, कोई भी सक्रियगत काम न था और इसलिए वे आन्तरिक सुरक्षा या किसी ऐसे अन्य प्रयोजन के लिए उपलब्ध न थी।

मत्ता-हस्तान्तरण से पहले भारत म्यिन ब्रिटिश सेना सम्बन्धी सभी वित्तीय दायित्व भारतीय राजकोष का हो था। (१५ अगस्त, १९४७ से) ये सेनायें भारत और पाकिस्तान की सेवार्य न रही थी और अब वे सैन्य-कार्यों के लिए उपलब्ध न थी। दोनों डोमिनियन सरकारों ने यह अनुभव किया कि उनका सन्धारण-व्यय अब उनको देयता न रहे जाना चाहिए। फिर भी दोनों डोमिनियनों ने यह दायित्व स्वीकार किया, जो उनके इंग्लैंड या किसी अन्य स्थल तक परिवहन से सम्बन्धित था। तैबिन ब्रिटिश सरकार से भी १५ अगस्त, १९४७ के बाद से उनका पूरा दायित्व संभालने की बात कहना भी मुक्तिवृत्त न था। यह माना गया कि इस सेना के प्रत्यावर्तन में सम्बन्धित एक छोटी अवधि सम्बन्धी देयता दोनों डोमिनियनों को संभालनी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए अनुमति अवधि के धारे में कुछ घर्चा के बाद एक ओर ब्रिटिश सरकार और दूसरी ओर भारत और पाकिस्तान सरकारों के बीच, भद्रगा-समझन की भावना के अनुसार, यह सहमति हो गयी कि केवल ३० नवम्बर, १९४७ तक ब्रिटिश सेनाओं पर होने वाला खर्च भारत और पाकिस्तान को वहन करना होगा। इस तारीख को उच्चतम कमांडर का संगठन समाप्त हो गया। इन सेना के लिए दोनों सरकारों ने इस तारीख के बाद जो भुगतान किये वे पांड का चालू उपाजैन माने गए।

### भारत और पाकिस्तान के बीच व्यय का मावण्टन

महामहिम नम्राट् की सरकार के साथ समझौता हो जाने के बाद यह तय किया गया कि प्रत्यावर्तन की प्रतीक्षा करने वाले ब्रिटिश सैनिकों के वेतन-भत्तों सम्बन्धी, और इस मिल-सिने में लड़े किये गए सज्जन निधिरो और नि शुल्क जहाज-टिकटों सम्बन्धी, सारा खर्च भारत और पाकिस्तान के बीच उसी अनुपात में आवण्टित कर दिया जायेगा, जितनी नि विभाजन के बाद दोनों देशों की सैन्य-संख्या थी।

७१७ अगस्त, १९४७ से ३० नवम्बर, १९४७ तक भारत और पाकिस्तान के बीच रक्षा-व्यय का आवण्टन इस प्रकार था—

- (१) मत्ता सेनाओं के वेतन और भत्ते, उच्चतम कमांडर की स्थापना का कुछ व्यय और व्यक्तियों के आवागमन (वास्तवीर और जूनाषड की छोड़ कर) सम्बन्धी व्यय का अन्त भाजन दोनों डोमिनियनों की पुनर्गठित सैन्य-संख्या के अनुपात में किया जायेगा।
- (२) प्रत्येक डोमिनियन में हुए निर्माण-व्यय तथा दोनों डोमिनियनों में भण्डार-अवस्थिति के लिए किये गये खर्च उसी डोमिनियन की देयता होंगे। विदेशों में अवस्थित किये गये भण्डार का खर्च उस डोमिनियन के हाते में जाना था, जिन वह भण्डार मिला।

सन्नेप में कहे तो ३० सितम्बर, १९४७ के बाद सशस्त्र सेनाओं के पुनर्गठन को निपटाने के लिए कोई केन्द्रीय संयुक्त मुख्यालय न था। संयुक्त-रक्षा-परिषद् दोष प्रश्नों का समाधान करती रही और उसके निर्णयों का अनुपालन सम्बन्धित सरकारें करती थीं। संयुक्त-रक्षा-परिषद् के नीचे उसकी कार्यपालक-समिति थी, जो सशस्त्र-सेना-पुनर्गठन-समिति की जगह पर बनायी गयी थी। कार्यपालक-समिति भण्डार आदि सम्बन्धी उन अन्त-डोमोनियन समितियों के काम को देखभाल करती थी, जो अब भी काम कर रही थी और वह इतिहास अनुभाग के समान संयुक्त सप्टरों का पर्यवेक्षण भी करती थी। इसके अलावा समिति भारत और पाकिस्तान के रक्षा-मन्त्रालयों द्वारा सौंपे गये पुनर्गठन सम्बन्धी किसी भी अन्य मामले पर भी विचार करती थी। फिर समिति की सिकारियों पर संयुक्त-रक्षा-परिषद् विचार करती थी।

संयुक्त-रक्षा-परिषद् को आतिरी बैठक नई दिल्ली में १९ मार्च, १९४८ को सम्पन्न हुई। भण्डारों के ले जाये जाने को छोड़ कर, बाकी सभी काम उस समय तक पूरे किये जा चुके थे। इसलिए समिति ने निर्णय किया कि संयुक्त-रक्षा-परिषद्-आदेश, १९४७ की वैधता का समय बढ़ाना अनावश्यक है, जो भारत के गवर्नर जनरल और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल द्वारा संयुक्त रूप से बढ़ाया न जाय, तो अपने-आप १ अप्रैल, १९४८ को व्यंगत हो जायेगा। परिषद् ने यह भी निर्णय किया कि इसकी कार्यपालक-समिति का नाम बदल कर अब अन्त-डोमोनियन-रक्षा-सचिवों की समिति रखा जाय और वह संयुक्त-रक्षा-परिषद् के दोष कृत्यों का निपटान करती रहे, खासकर भारत और पाकिस्तान के बीच भण्डारों के अज्ञान-प्रदान का। अन्त-डोमोनियन-रक्षा-सचिवों की समिति की बैठकें अप्रैल से नवम्बर, १९४८ तक सात बार हुईं। बैठकें विकल्पतः कराची और नई दिल्ली में हुईं।

अब केवल उन दो विषयों की चर्चा करना शेष रह जाता है, जिनको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच काफी विवाद छिड़ा। एक का सम्बन्ध आर्डनेंस कारखानों के स्थिर संस्थापनों में है और दूसरे का चल-भण्डारों के बंटवारे से, अर्थात् किसी खास रेजीमेन्ट या यूनिट से सम्बन्ध न रखने वाले और समग्र सशस्त्र सेनाओं के उपयोग के लिए स्टाकपारी जिनो में रखे गये चल-भण्डार और उपकरणों के बंटवारे से है।

### आर्डनेंस कारखाने

यद्यपि अविभाजित भारत के स्थिर संस्थापन सारे देश में फैले हुए थे, पूरे सोलह आर्डनेंस कारखाने भारत डोमोनियन में ही स्थित थे, ये कारखाने यद्यपि सन्तुलित और वक्षतपूर्ण

(ग) भण्डार के गोदाम में रखने और अभिरक्षा का सर्वे दोनों डोमोनियनों के बीच बांटे गये भण्डार के अनुपात से होना था।

(घ) आर्डनेंस कारखानों सम्बन्धी व्यय इंडिया (अविभाजित) की देयता था, पर ३० नवम्बर के बाद उत्पादित भण्डार विभाज्य समूहों का अंग न थे।

३० नवम्बर के बाद हुआ कोई सामान्य व्यय दोनों डोमोनियनों की अन्तिम सैन्य-सन्दा के अनुपात में बाँटा जाना था।

समूह के रूप में थे, पर आधुनिक युद्ध में अपेक्षित गोनाबालद के सामने भे देश की जहरतो को पूरा करने में अपर्याप्त थे ।

कारखाने के काम करने के लिए उनमें पास इमारत, मशीनरी, विजली, कच्चे माल का मिलना, कुशल मजदूर और समुचित निदेशन होना चाहिए । जो लोग अपना विकल्प देकर एक से दूसरे डोमोनियन में घने गये थे, उनको छोड़ कर न तो एक डोमोनियन से प्रवीण मजदूरों को दूसरे में ले आया जा सकता था, न निदेशन को ही ।

मशीनों के विभाजन पर सभी विचार किया जा सकता था, अब प्रत्येक कारखाने में एनार्गिक स्वतः पूर्ण उत्पादन यूनिट हो । सेन्य स्थापनाओं में भिन्न रूप में आर्डनेंस कारखानों में अमेरिकी लोग काम करते थे । उनके लिए अत्यन्त कुशल मजदूरों की जरूरत थी और वे स्थानीय आबादी में भरती लिये जाते थे । फिर निर्माण तकनीक और ज्ञान वर्षा तक निदेशक कर्मचारी और मजदूर साथ-साथ काम करके विकसित करते थे । आर्डनेंस कारखानों के विभाजन के प्रश्न पर विचार करने समय इसलिए इस बात पर ध्यान देना आवश्यक था कि इस बंटवारे में इन परिसम्पत्तियों का काम करना ही नष्ट न हो जाय । यह स्पष्ट था कि आर्डनेंस कारखानों की मशीनें और सप्लाय, उनकी उत्पादन क्षमता को हानि पहुँचावे बिना, बाँट कर पाकिस्तान को नहीं दिये जा सकते थे । इसलिए भारत ने सुझाव दिया कि विद्यमान कारखानों यथापूर्व भारत में चालू रहने दिये जायें और पाकिस्तान का हिस्सा पैमें में दे दिया जाय । पर पाकिस्तान द्वितीय मजदूर के लिए राजी न था और वह अपना हिस्सा मशीनों और उपकरणों के रूप में चाहता था । भारत सिद्धान्त आर्डनेंस कारखानों को बाँट कर पाकिस्तान से दिये जाने के लिए सहमत न हो सता, क्योंकि उनका भौतिक विभाजन सम्भव न था ।

यद्यपि कारखानों का उत्पादन भारत की सामान्य जरूरतें भी पूरी न कर पाता था, भारत न केवल पाकिस्तान को कारखानों के उनके हिस्से के लिए द्वितीय क्षतिपूर्ति देने को तैयार था, बल्कि इसके लिए भी तैयार था कि जब तक पाकिस्तान अपने कारखाने स्थापित न कर स, वह वार्षिक रूप से दत्त कारखानों के उत्पादन का एक सहमत अनुपात पाकिस्तान को दता रहेगा । इस मतभेद के कारण समुक्त-रक्षा-परिषद् में कोई फैसला न हो सका और यह मामला निर्णय के लिए विभाजन-परिषद् के पास भेजा गया । यह मामला मध्यस्थ अधिकरण को सौंपा ही जाने वाला था कि विभाजन-परिषद् ने १ दिसम्बर, १९८७ को एक निर्णय दे दिया । इस निर्णय के अनुसार भारत पाकिस्तान में आर्डनेंस कारखाने लगाने के पक्ष के लिए और कुछ विशिष्ट अमेरिकी सस्त्राय, जेमे कृषि-अनुसंधान-मस्थान स्थापित करने के लिए ॥ करोड़ रुपये की रकम पाकिस्तान को देने के लिए राजी हो जाय । यह रकम पाकिस्तान को यथावश्यक रूप में दे जानी थी । यह व्यवस्था भारत डोमोनियन में स्थित आर्डनेंस कारखानों और कुछ विशिष्ट संस्थानों के सम्बन्ध में अन्तिम निपटान के रूप में की गयी ।

### चल परिसम्पत्तियाँ

जैसा कि बताया जा चुका है, यूनिटों के उपकरण और व्यक्तियों के उपकरण, दोनों डोमोनियनो के बीच यूनिटों और व्यक्तियों के आगमन के समय, उनमें पास बने रहे । ऐसे उपकरणों

का बँटवारा इस प्रकार स्वयं दोनों मेनाजो की अन्तिम सरया के अनुपात में हो गया। पर उत्पत्तिको और भण्डारो का एक दृष्ट सप्ताह समय मेना के उपयोग के लिए भी मञ्जूर था। कुछ मामलों में ये भण्डार कई सानो की अन्तरतो के लिए पर्याप्त थे। इसलिए उनका विभाजन दोनों समग्र सेनाजो की संख्या के अनुपात में नहीं किया जा सकता था। उनको पुरानी भारत सरकार की विभाजन परिस्थितियों के रूप में माना जाना चाहिये। इसलिए भारत ने कहा कि उनको उसी अनुपात में बाँटा जाय, जिस अनुपात में पुरानी भारत सरकार की सामान्य परिस्थितियों और अपूरित श्रृणों बाँटे गये हैं। अपूरित श्रृणों के लिए सद्मन अनुपात था, भारत ८२.३% और पाकिस्तान १७.३% लेकिन पाकिस्तान इस बात के लिये तैयार न था और विभाजन-परिपत्र ने यह मामला पहले मध्यस्थ अधिकरण के पास भेजने का निर्णय लिया।

इस बारे में कोई निर्णय न होने से, उच्चतम कमांडर का मुख्यालय भण्डार के विभाजन का काम अपने हाथ में न ले सका। भण्डारो की भारी मात्रा को जो लगभग ४,२०,००० टन हो आर्डेनस भण्डार ही थे और ५ लाख टन से ज्यादा इजीनियरी भण्डार छोट्टा और दोनों डोमीनियो के बीच लापना, भेजना और प्राप्त करना एक बहुत ही बड़ा काम था। सेना के विभाजन का प्रश्न पैदा होने से पहले ही ये भण्डार खड़े किये गये थे। उनमें काग में आने वाली चीजें, सन्धारण के लिए जरूरी चीजें और सामग्रियों के समय जरूरी भण्डार शामिल थे। असली झगडा उस भण्डार को लेकर था, जो न तो व्यक्तिगत उपकरण थे और न सामान्य सन्धारण के लिये आवश्यक उपकरण ही थे, बल्कि जिनको अतिरिक्त भण्डार कहा जा सकता था। भण्डार के विभाजन में और देर न होने देने के लिए, संयुक्त रक्षा परिषद् ने १६ अक्टूबर, १९४७ को जब उच्चतम कमांडर के मुख्यालय को बन्द कर देने के बारे में उसके टिप्पण पर विचार हो रहा था, यह निर्णय किया कि उसके मुख्यालय को चाहिये कि भण्डार के उस अंश का भौतिक बँटवारा करना सीधे घुट कर दे, जिसे दोनों सेनाजो की, अपनी-अपनी संख्या के अनुसार, उनकी सामान्य सन्धारण आवश्यकता माना जा सकता है।

उस समय सामान्य सन्धारण आवश्यकता की परिभाषायें यो की गयीं।

(क) उचित पिनाब के कारण भण्डार के दैनिक रूप से नष्ट होने की पूर्ति के लिए सन्धारण स्टाफ, तथा

(ख) इनकी पूर्ति के लिए रुंद गये मञ्जूरि-स्टाक (एक) युद्ध के आरम्भिक काल में यूनिटों को दी जाने वाली अतिरिक्त प्रत्याशित चीजें (दो) यूनिटों द्वारा अपेक्षित चीजें, जो युद्ध के आरम्भ के कुछ गहरीनों में अक्सर दी जाती चाहिये और (तीन) अपूर्वाशित अपेक्षायें।

इस रीति में बाँटे जाने वाले भण्डार वे थे, जो अविभाजित मेना की संख्या के लिए बहती समझे गये थे, जैसी कि विभाजन ने पहले कल्पना थी। पर यह निर्णय उस शेष भण्डार पर लागू न था, जो इस प्रसंग में अतिरिक्त भण्डार बताया गया था और जिसे मध्यस्थ अवि-करण द्वारा निर्णय अनुपात में बाँटा जाना था, जिसे कि उचित अधिकरण को सौंप दिया गया था।

मध्यस्थ अधिकरण को सौंपा गया मामला इसी बात के निर्णय तक सीमित होना था कि अतिरिक्त भण्डार को किस अनुपात में बाँटा जाय और बाँटे गये भण्डार का आगिरी

समञ्जन किस रीति में किया जाय। पाकिस्तान अपनी जम्हूरियों के लिए अपने हिस्से में ज्यादा अतिरिक्त भण्डार भी ले सक्ता था, यदि भारत सरकार राजी हो और वित्तीय समञ्जन हो जाए।

सयुक्त-रक्षा-परिषद् ने जो आर्जनेंस भण्डार (पुनर्गठन) उपसमिति बनायी थी, जिसका अध्यक्ष ब्रिगेडियर के पद का एक ब्रिटिश अधिकारी था और जिसमें भारतीय सेना आर्जनेंस कोर और पो० ए० ओ० कोर (P A O C) से लेफ्टीनेंट कर्नल के पद का एक-एक सदस्य था, यह आवश्यक करने के लिए जिम्मेदार थी कि आर्जनेंस भण्डार का (अतिरिक्त भण्डार को छोड़ कर) विभाजन सयुक्त रक्षा परिषद् के निर्णय के अनुसार कर दिया जाय।

सयुक्त-रक्षा-परिषद् के उक्त निर्णय के अनुसार सन्धारण स्टाफ का आदान-प्रदान अभी चल ही रहा था कि चारों ओर से आरोप-प्राप्त लगाये जाने लगे। उच्चतम कमान्डर ने शिकायत की कि सयुक्त-रक्षा-परिषद् के निर्णयानुसार उसका मुख्यालय, रक्षा सेनाओं की परि-सम्पत्तियों का उचित और व्यापक बंटवारा करने का जो भी प्रयास करना है, उसमें दोनों होमीनियनों के ब्रिटिश सैनिक और अमेरिकन अधिकारियों द्वारा बाधा बाली जाती है, जो कि लगता है उसका काम अमम्भव बना देने के लिए कटिबद्ध हो चुके हैं। दूसरी ओर ये भी आरोप थे कि उच्चतम कमान्डर का मुख्यालय भी इस बारे में अपना उत्तरदायित्व निभाने में पर्याप्त निष्पक्ष न था। २६ नवम्बर, १९४७ को सयुक्त-रक्षा-परिषद् ने यह निर्णय किया कि प्रत्येक होमीनियन की आर्जनेंस कोर के एक-एक कमीशन-प्राप्त अधिकारी और दो-दो वायसराय कमीशन-प्राप्त अधिकारियों की टीमों पर्यवेक्षण के काम के लिए नियुक्त की जायें और अपने-अपने होमीनियनों के लिए भण्डार के चुनाव, मुहूर्तवन्दी और प्रेषण के काम का पर्यवेक्षण करने के लिए उनको दूसरे होमीनियन के केन्द्रीय आर्जनेंस डिग्रे में नैनात कर दिया जाय। ऐसी ही टीमों गोलाबालू और मोटरगाड़ी डिग्रे में भी बनायी गयी। इन सभी टीमों को आर्जनेंस भण्डार (पुनर्गठन) उपसमिति के सामान्य निदेशन और पर्यवेक्षण में काम करना था।

परिवहन की दिक्कतों के अलावा भण्डार के आवागमन में देर का एक कारण, भारत से महाहिम सम्राट सरकार के स्वामित्व के उस भारी भण्डार को हटा कर ले जाने का भारी काम भी था, जिसके बारे में इंग्लैण्ड के युद्ध-कार्यालय ने तय कर दिया था कि इसे भारत से वहाँ-कहाँ भेजना है। भारत ने अपनी ओर से कड़े निदेश जारी कर दिये थे कि उन अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासन की सख्त कार्रवाई की जायेगी, जो भारत में पाकिस्तान को भण्डारों के ले जाये जाने में देर लगाने का प्रयास करेंगे। दुर्भाग्य से या शायद किसी गलतफहमी से पाकिस्तान ने अधिकृत आदेश निकाय कर उन इन्जिनियरों और विकास भण्डारों का आवागमन रोक दिया था, जो पाकिस्तान से भारत जाने को थे। लेकिन भारत ने वास्तविक मिलने पर पाकिस्तान भारत को भण्डारों का जाना रोकने के बारे में लगाये गये अपने आदेश वापस लेने लिए राजी हो गया।

सयुक्त-रक्षा-परिषद् ने यह भी निदेश दिया कि दोनों में से किसी भी सरकार को एक-पक्षीय आदेश, एक होमीनियन के दूसरे तक सैन्य-भण्डार के आवागमन पर रोक लगाने वाले आदेश, नहीं निवास्त चाहिये। यह भी निर्णय किया गया कि भारत में पाकिस्तान ले जाये

जाने जाने भन्डारों को भी वही पूर्वादा दी जायेगी, जो युद्ध-कार्यालय के भन्डार को दी जाती है। अब तक सिद्दने को ज्यादा पूर्वादा दी जाती थी। हड़ताल के समय जहाजों में भन्डार के लाने जाने पर, पाकिस्तान को भन्डार भेजने के लिए, इंग्लैंड के युद्ध-कार्यालय जाने भन्डारों में अधिक पूर्वादा दी गयी।

दाद में भन्डार के आवागमन की देखभाल के लिये संयुक्त रक्षा परिषद् ने भारत और पाकिस्तान के रक्षा मन्त्रालयों से कहा कि एक विहित प्रश्न में भन्डार के जाने-आने के बारे में विचार भेजते रहें।

चय भन्डारों के विभाजन सम्बन्धी विवाद मध्यस्थ-अधिकरण को सौंपे गये, पर इसके पहले कि अधिकरण इस प्रश्न को ले, यह मामला वापस ले लिया गया, क्योंकि १ दिसम्बर, १९४७ को हुई बैठक में विभाजन-परिषद् इस बारे में एक समझौते पर पहुँच गयी। इस समझौते के अनुसार १४ अगस्त १९४७ को डिपो में दृढ़ और गहनतर गनरल में निहित अन्य भन्डार दोनों डेपॉनियन्तो के बीच इस सूत्र के आधार पर बाँटे जाने चाहिये कि पाकिस्तान का हिस्सा वास्तविक स्टाफ का एक तिहाई होगा, जिसका अधिकतम  $\frac{1}{3}$  का (स +  $\frac{1}{3}$  स) में ज्यादा न होगा। 'स' की परिभाषा पहले ही कर दी गई थी - 'सामान्य सप्लाय आडमिनिस्ट्रेशन'। शेष भन्डार भारत के हिस्से में जायेगा। इस निर्णय के अनुपालन के लिए हर धीपी के भन्डार के बारे में, इस सामान्य सूत्र का विचार करने हुए, औरतार सूत्र बनाने पड़े। ये सूत्र संयुक्त-रक्षा-परिषद् की कार्यपालक समिति ने १ फरवरी, १९४८ को मंजूर किये व संयुक्त-रक्षा-परिषद् ने अपनी १६ मार्च १९४८ को हुई आखिरी बैठक में मंजूर किये।

आइनेस भन्डारों की हालत सामान्यतः पहले से ही समीपवर्तन न थी। दूसरे विश्व-युद्ध के उत्तरार्द्ध में भारी आनंद और छाया वाली जगह काटी न होने के कारण, ताबहार होकर, भन्डारों को सुने में रहना पड़ा। इसके उनकी हालत सामान्यतः बिगड़ गयी। साथ ही स्टाफ की मौजिक जाँच करने से यह भी स्पष्ट हो गया कि ताब में बर्ब दकाना और गरती पर वास्तविक स्टाफ के बीच काफी अन्तर है। फलतः आपस पर दिने गये बाँझों के साथ वास्तविक स्टाफ का निदान करना कठिन हो गया।

यहाँ विनाश स्टाफ के स्वरूप के बारे में भी कुछ झोंरे के बेता ठीक रहेगा। युद्ध के दौरान महानहिम सम्राट की सरकार के पास भारत में काटी बड़ी मात्रा में भन्डार सञ्चित हो गये थे। भारत मुद्र पूर्व में संविदाओं का आस्थान (बैठ) था। युद्ध की समाप्ति पर बड़ी मात्रा में भन्डार बच गये, जिनमें से कुछ ही मरों की सम्राट-सरकार को अपने लिए अंगरत थी। भारत में जो शेष भन्डार १ अप्रैल, १९४७ को बचे थे, उनकी भारत सरकार ने संभावित चिन्ता था। सम्राट-सरकार से चिने गये इन भन्डारों के अन्धा कुच और अन्य भन्डार थे, जिनका स्वामित्व (अविभाजित) भारत का था। यद्यपि सम्राट-सरकार का भारत सरकार के स्वामित्व वाले भन्डारों के जतन-अलग हो न थे।

१ अप्रैल, १९४७ को पुनरुद्भव पर ने चिने गये सम्राट-सरकार के भन्डारों के बारे में भारत और पाकिस्तान के बीच यह सहनति हो गयी थी कि इन भन्डारों के लिए प्रारम्भिक कुतान भारत कर देगा। पाकिस्तान में जो भन्डार ११ अगस्त, १९४७ को स्थिति थे, या उन्हें

३० जून, १९४८ तक प्राप्त होने, उनका मूल्य पाकिस्तान को भारतीय रुपये में भारत को नगद चुकाना था। ये वे भण्डार थे जो अविभाजित भारत द्वारा १९४७-४८ में दिये गये आदेशों के अनुसरण में पाकिस्तान पहुँचे। ३० जून, १९४८ के बाद पाकिस्तान को दिये जाने वाले भण्डारों के लिए पाकिस्तान को अपने पौड खाना सत्या २ में से भारत को भुगतान करना था। १५ अगस्त, १९४७ को पाकिस्तान-स्थित भण्डारों और बाद में उमे स्थानान्तरित भण्डारों का मूल्य उम्मीदवादी आधार पर होना था, जबकि १ अप्रैल, १९४७ को सम्राट-सरकार ने भण्डार मंगाने पर किया जाता। पाकिस्तान को इन भण्डारों के लिए जो नगद भुगतान करना था, उसका पुस्तक-मूल्य के साथ बड़ी अनुपात होना था, जो सम्राट-सरकार में दिये गये भण्डार के लिये उमको किये गये वार्षिक भुगतान का उसके पुस्तक-मूल्य के साथ था।

लेकिन जब भण्डारों के लिए भुगतान का प्रश्न उठा, तो पाकिस्तान ने कहा कि विभाजन के फलस्वरूप भारत में प्राप्त सभी भण्डारों को पहले भारत के स्वामित्व वाले भण्डार में पाकिस्तान के हिस्से के रूप में जोड़ा जाना चाहिये और जब इन भण्डार में उसका हिस्सा प्राप्त हो जाय, तभी भारत में प्राप्त भण्डारों को सम्राट-सरकार के स्वामित्व वाले भण्डार का अंश माना जाना चाहिये। फिर भी, जैसा पहले ही बताया जा चुका है, सम्राट-सरकार और भारत-सरकार के स्वामित्व वाले भण्डारों के ढेरों का अलग-अलग हिसाब नहीं रखा गया था। पाकिस्तान ने यह भी सुझाव दिया कि विभाजन के फलस्वरूप प्राप्त भण्डारों का वित्तीय समन्वयन यथा-प्राप्त भण्डारों की दशा और माता के आधार पर किया जाना चाहिये। यह असम्भव था, क्योंकि दोनों देशों को, सशस्त्र सेनाओं के पुनर्गठन की योजना के अन्तर्गत, जो कुछ भी प्राप्त होता, वही मिलना था। सम्राट-सरकार से लिये गये भण्डार के बारे में वित्तीय समन्वयन के लिये जो भी वागचीत हुई थी, पाकिस्तान का भी उसमें हाथ था। फिर, अविभाजित भारत में भण्डारों की कुल मात्रा सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकता से ज्यादा थी, और अनिश्चित अंश दोनों ही डोमीनियनों द्वारा सामान्य रीति में निपटाये जा रहे थे। पाकिस्तान के साथ हुये समझौते के अनुसार, पाकिस्तान को उसके द्वारा बेचे गये सभी अतिरिक्त भण्डार का वित्तिय करने प्राप्त सारी रकम, चालू रूप में भारत को चुकानी थी। लेकिन ऐसे विनोद में प्राप्त कुछ भी रकम भारत के नाम जमा न की गयी थी, न पाकिस्तान द्वारा बेचे गये अतिरिक्त भण्डारों की सूची तक ही पाकिस्तान द्वारा भारत को दी गयी थी। पाकिस्तान इस बात पर भी सहमत हुआ था कि सम्राट-सरकार से प्राप्त सम्पत्ति के लिए वह भारत को सम्राट-सरकार के साथ समझौते के तीस दिन के भीतर ही उम्मीद भुगतान कर देगा।

भारत ने भण्डार के भेजने के बारे में जो भी वचन दिये थे, उनका पूरा पालन किया गया और भारत में पाकिस्तान तक जनवरी और अगस्त, १९४८ के बीच यथा-सम्भव अतिशय टन-भारों के भण्डार भेजे गये (यह ध्यान रखा जाय, कि इनके वावजूद, कि इस बीच वादमीर पर आक्रमण हो चुका था)। भारत के अनुसार उमे पाकिस्तान ने ऐसा ही परस्पर या व्यवहार न मिला था, न केवल भण्डार के भेजने के बारे में बल्कि उनके द्वारा वचन दिये



गये अनुसार भुगतान के बारे में भी । ३

भण्डार के विभाजन का विषय अन्त डोमीनियन-रक्षा सचिव-समिति के सामने कई बार चर्चा के लिए आया, पर पाकिस्तान के रवैये के फलस्वरूप, सैन्य भण्डार सम्बन्धी मद रक्षा मेनाओ के सम्बन्ध में, भारत और पाकिस्तान के बीच, बाकी बचे एक महत्वपूर्ण मद के रूप में बनी हो रही । पाकिस्तान का विचार अपने को प्राप्त भण्डार के लिये भुगतान करने का विलकुल नहीं था । इसलिए विभाजन के लिए स्वीकृत धुब के अनुसार भारत में और अधिक सैन्य भण्डार का पाकिस्तान भेजा जाना संदपूर्वक बन्द करना पड़ा ।

सशस्त्र सेनाओं के विभाजन का यह लेखा-जोखा नि सन्देह काफ़ी अपूर्ण है, क्योंकि विभाजन के केवल स्थूल पहलुओं को ही लिया गया है । वस्तुतः सशस्त्र सेनाओं के विभाजन सम्बन्धी विद्यमान दम्पात्र-हजारों पृष्ठों में है और उनमें आज भी अन्तर्ग्रस्त कार्य के विस्तार और जटिलता की भाँकी मिल जाती है । तनाव के उन दिनों में काम की गति को इस बात में आँका जा सकता है कि ३० जून, १९४७ से ६ अगस्त, १९४७ तक विभाजन-परिपट्ट (और २१ जुलाई से ६ अगस्त तक अन्तिम-संयुक्त-रक्षा-परिपट्ट के रूप में काम करने वाली विभाजन-

३ नीचे लिखे विवरण में पता चलता है कि पाकिस्तान ने सैन्य भण्डार के बारे में नवम्बर १९४८ में ये रकमें प्राप्त कीं । इनमें से पाकिस्तान ने १९४६ के आरम्भ में रु० २ ३५ करोड़ की ही रकम चुकायी थी ।

नीचे लिखी चीजों के लिए पाकिस्तान ने प्राप्त रकम -

	(करोड़ रुपये में)
१. भण्डार (यूनिट उपकरणों समेत), जो इंग्लैंड में विद्यमान थे और १५ अगस्त, १९४७ को पाकिस्तान में स्थित थे	११.३८
२. इंग्लैंड से की गई स्थिर परिसम्पत्तियाँ, जो अगस्त, १९४७ को पाकिस्तान में स्थित थीं	२.३५
३. भारत से ११-८-१९४७ से ३१-८-४८ के बीच पाकिस्तान भेजे गये भण्डार	४.२१
४. पाकिस्तान भेजे गये भण्डार का परिवहन व्यय	०.१८
५. पाकिस्तान में स्थित इंग्लैंड के स्वामित्व वाले अतिरिक्त भण्डारों की विक्री में प्राप्त शुद्ध अनुमानित रकम, जो पाकिस्तान द्वारा चुकायी जानी थी	२.२१
६. ईशिया-माल में जाने गये संयुक्त व्यय में पाकिस्तान का हिस्सा—	
(क) पाकिस्तान को पहले ही बनाये जा चुके नामे व्यय जो १५-८-४७ से ३०-११-४७ के बीच जोड़े गये	८.२०
(ख) संयुक्त रूप में किया गया और नामे डाला गया भण्डार अन्तर्गत में और व्यय (ज्यादातर १५-८-४७ से ३०-११-४७ तक की अवधि का बचाया खर्च)	२.१०

परिपक्व) को १८ बैठकें हुई, जिनमें मुख्य मसौ पर चर्चा हुई (मोटे तौर पर प्रति सप्ताह तीन बैठकें)। सयुक्त-रक्षा-परिपक्व को १६ अगस्त, १९८७ से १६ मार्च १९४८ तक १६ बैठकें हुई—जो इस बात पर ध्यान देने से काफी बड़ी सख्या मानूम पड़ती है कि १५ अगस्त के बाद दोनों देशों के सदस्यों की सुविधा के अनुसार ही बैठकें बुलाई जा सकती थीं। फिर विभाजन सम्बन्धी कार्य के साथ-साथ मन्त्री और अधिकारी नये राज्यो की प्रशासनिक समस्याओं में भी बहुत व्युत्थित रह गये थे। अब समय ही दो दशकों बाद यह समझ पाना आसान नहीं है कि मन्त्रियों और अधिकारियों को त्रिज दशकों में काम करना पड़ा और उन पर दोनों होमीनिषनों के बीच सन्तान्तर बढ़ते हुये तनावों के कारण कितना बोझ रहा होगा, जबकि एक बार सयुक्त-रक्षा-परिपक्व के स्वतन्त्र अध्ययन को भी भारत और पाकिस्तान के बीच मुट्ठ टिड्ड जाने की सम्भावना का उल्लेख करना पड़ा था।

### अनुबन्ध—१

सशस्त्र सेना पुनर्गठन-समिति और उसकी उपसमितियों की रचना इस प्रकार थी—

#### सशस्त्र सेना पुनर्गठन-समिति

१—महामहिम फौजदारी मांसल सर बजौड आकिदलेक—

भारत के कमांडर-इन-चीफ

अध्यक्ष

२—शरिफ एडमिरल सर ज्योकरों मादन्स, कमांडर-इन-चीफ

रॉयल इंडियन नेवी ( यह पदनाम पत्रेण अफसर कमांडिंग

रायल इंडियन नेवी के स्थान पर १ मार्च, १९४७ से गुरु

किया गया )।

३—एयर मार्शल एच. एस. पी. बामसने, एयर अफसर कमांडिंग इन चीफ  
इन इंडिया

४—ले० जनरल सर आर्बर एफ० स्मिथ, चीफ आफ दि जनरल स्टाफ

५—मुहम्मद अली, वित्तीय सलाहकार, रक्षा और पूर्ति, सैन्य वित्त विभाग  
पाकिस्तान जाने पर उनका स्थान १२ अगस्त को ए० डी० एफ०  
दुबस ने लिया ( दुबान जनवरी, १९४६ में चन्द्रलाल त्रिवेदी के  
बाद अविभाजित भारत सरकार के मुट्ठ-सचिव बने थे। वे पाकिस्तान  
के पहले रक्षा सचिव नियुक्त हुए )।

६—जी. एम. भालाजी, अतिरिक्त सचिव, रक्षा-विभाग

७—नरेंद्र एच० बी० एस० मुलर, आई० ए०, कमांडर-इन-चीफ के सचिवालय  
के सचिव

सचिव

#### (क) नौसेना उपसमिति

१—कमांडर जे० डबल्यू० जेकर्स, आर० आई० एन०

२—कमांडर ए० बी० गूड, स्टाफ अफसर, योजना, आर० आई० एन०

३—कमांडर जे० सी० मानमेल, आर० आई० एन०, कमांडर, प्रशासन, नौसेना मुख्यालय

४—कमांडर एच० एम० एम० चौधरी, आर० आई० एन० स्टाफ अफसर, नौसेना नियुक्ति, नौसेना मुख्यालय

५—कमांडर वो० एस० सोमन, आर० आई० एन०

६—ले० कमांडर ( ई० ) डी० शंकर, आर० आई० एन०

७—ले० कमांडर ( ई० ) आई० के० मुसनाज, उपनिदेशक, इंजीनियरी, नौसेना मुख्यालय ।

८—एस० जयशंकर, उप-वित्त सलाहकार, सैन्य वित्त

९—मुसताज मिर्जा, उप-वित्त सलाहकार, सैन्य वित्त

१०—ले० कमांडर ( एस० ) ए० आर० एन० हुसैन }

११—लेफ्टीनेंट ( एस० ) सी० जे० मुसिफ }

सचिव

### (ख) सेना उपसमिति

१—मेजर जनरल एस० ई० इरविन, डिप्टी चीफ ऑफ दि जनरल स्टाफ अध्यक्ष

२—ब्रिगेडियर जी० बी० एल० कोलमेन, सज्जटन उपनिदेशक, एडजुटेंट जनरल की शाखा

३—ब्रिगेडियर के० एम० करिअप्पा

४—ब्रिगेडियर एस० बी० एस० चिम्मो

५—ब्रिगेडियर के० एम० धिमय्या, डी० एस० ओ०, कमांडर, १ पैदल ब्रिगेड

६—ब्रिगेडियर ए० एम० रजा, कामिक चयन निदेशक, एडजुटेंट जनरल शाखा

७—कनॅल टी० एच० एगुस, डी० एम० ओ०, निदेशक, जनरल स्टाफ शाखा

८—कनॅल मुहम्मद गेर खान, एम० सी०, सैन्य प्रशिक्षण उपनिदेशक, जनरल स्टाफ शाखा

९—ले० कनॅल एच० डबल्यू नेवेल, १६ पब्लिक रोजीमेंट, क्वार्टर मास्टर

१०—ले० कनॅल अकबर खान, डी० एस० ओ०, फटियर फोर्म राइफल्स, बटालियन कमांडर, भारतीय सैन्य अकादेमी, देहरादून

११—मुसाम अह्मद, उप वित्त सलाहकार, सैन्य वित्त

१२—बी० बी० घोष, उप-वित्त सलाहकार, सैन्य वित्त

१३—ले० कनॅल एम० ए० लतीफ खान, एडजुटेंट जनरल शाखा }

१४—ले० कनॅल जी० जी० वेक्कूर, बलूच रेजीमेंट }

सचिव

### (ग) वायुसेना उपसमिति

१—एयर वाइस मार्शल ए० एल० ए० पैरी कीन, एयर अफसर, भारमाध्यक वायु सेना मुख्यालय ( भारत )

अध्यक्ष

- २—एयर कम्पोडोर, जी० डब्ल्यू० विरजिनजा, वरिष्ठ तकनीकी स्टाफ अफसर,  
वायुसेना मुख्यालय ( भारत )
- ३—एयर कम्पोडोर एस० मुन्शी, ३६—एयर अफसर, भारसाक्षक प्रबन्धन,  
वायुसेना मुख्यालय ( भारत )
- ४—ग्रुप कैप्टेन डी० एच० एफ० बारनेट, ग्रुप कैप्टेन एयर स्टाफ योजना,  
वायुसेना मुख्यालय ( भारत )
- ५—ग्रुप कैप्टेन ए० एम० इजीनियर, ग्रुप कैप्टेन धार्मिक सेवाएँ, वायुसेना  
मुख्यालय ( भारत )
- ६—विंग कमांडर एम० के० जगजुजा, विंग कमांडर, जन, वायुसेना मुख्यालय  
( भारत )
- ७—स्ववैद्वन सीडर एम० ए० खान, मुख्य उड्डयन प्रशिक्षक, रायल इंडियन  
एयर फोर्स स्टेशन, अम्बाला
- ८—एम० जयगकर, उपबिक्त सलाहकार, मैन्स ब्रिक्त
- ९—मुमताज मिर्जा, उपबिक्त सलाहकार, सैन्य ब्रिक्त
- १०—विंग कमांडर अर्जुन सिंह, अफसर कमांडिंग, रायल इंडियन एयर  
फोर्स स्टेशन, रिसालपुर
- ११—कमांडर लेफ्टीनेंट, एच० भट्टी, जन, भारतीय वायुसेना मुख्यालय

मन्त्रि

### घ) वित्तीय मामलों की विशेष उपसमिति

- १—गुलाम अब्बास  
२—एम० जयगकर  
३—बी० बी० घोष  
४—मुमताज मिर्जा

गुलाम अब्बास और बी० बी० घोष मेला उपसमिति के सदस्य थे और एम० जयगकर और मुमताज मिर्जा मौमेला और वायुसेना दोनों उपसमितियों के। उपसमिति की सिफारिशें सलाह मेला पुनर्गठन समिति के जरिये परिमल्यति और देपना सम्बन्धी मुख्य विशेषज्ञ समिति के पास भेजी जाती थी।

### अनुबन्ध—दो

मेला	भारत	पाकिस्तान	कैपिटल
पैदा रेजीमेंट	१५	८	
आर्मड कौर	१७	६	
ताइवाना रेजीमेंट	१८३	८३	
इजीनियरी यूनिटें	६१	३४	

मिगनल कौर  
पूनि यूनिटें ( मार० आई० ए० ए० सी० ) } तात्कालिक स्थिति विन्यास प्रत्येक डोपानिपन  
में अपरिवर्तित रहा

सेना	भारत	पाकिस्तान	कैफियत
विजली और यान्त्रिक इंजीनियरी यूनिटें	१०	४	
भारतीय पायोनियर कोर समूह मुख्यालय	और ६ कम्पनियां	२ कम्पनियां	
पशु परिवहन रेजिमेंट	८	३	पाकिस्तान की इस तरह की यूनिटों की ज्यादा जरूरत थी ;
यान्त्रिक परिवहन यूनिटें (थार, आई, ए एस. सी)	३४	१७	
एम्बुलेंस वाहन	१२	७	
भारतीय सेना चिकित्सा कोर अस्पताल	८२ ११,७१३	३४ ४०३७	कुल ११६ में से १२ ब्रिटिश सैन्य अस्पताल थे। और फार्म जिस डोमोनियन में स्थित थे उसी को शय्याएँ शय्याएँ
सैन्य फार्म	७२	२६	डोमोनियन में स्थित थे उसी को स्टॉक या फार्म साधियों के माध्यम से संपि गये।
पहाड़ रेजिमेंट	२	१	अब-माघन ज्यादातर पाकिस्तान में केन्द्रित थे। भाटगुमरी और लायलपुर में दो प्रजनन-क्षेत्र थे, लेकिन भारतीय डोमोनियन में कुछ भी नियन्त्रित घोड़ा या खन्वर प्रजनन की व्यवस्था न थी और स्वामीय बाजार में उपलब्ध पशुओं के मात्रक मैन्य मानकों में कहीं कम थे।
मौसैना (रोमल इन्विजन नेवी)			
स्कूप	८	२	
फ्रिगेट	२	०	
वेब-मुररुङ्ग स्क्वैड्रन	१२	४	
कोर बोट	१	—	
मर्वेशन जहाज	१	—	
ड्रगनर	४	२	
मोंटर मुरंग स्क्वैड्रन	४	२	
मोटर लॉच	१	—	

सेना	भारत	पाकिस्तान	कैफियत
बन्दरगाह रक्षा	४	४	
मोटर लैंच			
अवतरण नौकायें	सभी विद्यमान	—	
	बड़ी-छोटी		
	अवतरण नौकायें		
वायु-सेना (रॉयल इण्डियन एयरफोर्स )			
लडाकू स्क्वेड्रन	७	२	
परिवहन स्क्वेड्रन	१	१	

## तीसरा अध्याय

### विभाजन के पश्चात्

सत्ता-हस्तान्तरण के तुरन्त बाद और परिणामी प्रचामनिक पुनः समजन पूरे होने में पहले भारत को भारी पैमाने पर अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा।

सद्भाव और सहयोग की कमी के कारण सशस्त्र सेनाओं का पुनर्गठन आवश्यक रूप से दुस्तर काम हो गया। पाकिस्तान और भारत में हुए साम्प्रदायिक दंगों में इतिहास में पहली बार विस्थापितों का अत्यधिक आवागमन शुरू हो गया। इसने पुनर्वासि और जातिगत सुरक्षा की बड़ी-बड़ी समस्याएँ खड़ी कर दी। जूनागढ़ और हैदराबाद के शासकों ने शत्रुता-पूर्ण और बेडंगा रवैया अपनाया था, जिसने उनके राज्यों में और पड़ोसी राज्यों में भारी अव्यवस्था पैदा हो गयी। एक तीसरे राज्य काश्मीर पर भारत में उसके सम्मिलित होने के बाद, शस्त्र-मुक्त-जित्त हमलावरों ने सोना पार में आक्रमण कर दिया और पाकिस्तान और भारत के, जटिल-मनीय रूप से अत्य सूचना पर, सीमाप्राय से सेना भेजनी पड़ी। भारतीय सशस्त्र सेना को इन अदृष्टपूर्व कठिनाइयों का सामना, कानून-व्यवस्था बनाए रखने में अनैतिक अधिकारियों को मदद देने के अलावा, करना पड़ा। लेकिन १९४८ के अन्त तक इन समस्याओं का जम कर सामना कर लिया गया और भारतीय प्रचामन मुहृद रूप में स्थापित हो गया।

अगस्त, १९४७ में सशस्त्र सेनाओं का जलज-गत डोमीनियन सेनाओं के रूप में पुनर्गठन उच्चतम कमांडर के मुख्यालय के तत्वावधान में चल रहा था। सेना की जो कई यूनिटें भारत की मिली थी, जब भी पश्चिमोत्तर सीमान्त और पश्चिमी पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों की गैरिसनों में स्थित थी। सत्ता-हस्तान्तरण ने पहले कमान और स्टाफ के सभी उच्च पदों पर ब्रिटिश अधिकारी ही नियुक्त थे। अब इन पदों पर, और जो कार्यनिवृत्त होने या पाकिस्तान में नौकरी करने का चुनाव कर चुके थे, उनकी जगह, भारतीय अधिकारियों को नियुक्त किया जाना था। कमान और स्टाफ के उच्चतर पदों पर अनेक भारतीयों को पदोन्नति दी गयी और उनकी तैनातियों के फलस्वरूप नीचे के स्तरों पर भी शृङ्खला-पदोन्नतियों और स्थानान्तरण करने पड़े। पुनर्गठन के फलस्वरूप रेजीमेंटों के स्थानान्तरण ने, बहुत-सी वाली और अमलुलित यूनिटें रह गयी थी और सभी जगह अव्यवस्था-मयी थी। भारतीय डोमीनियन

के कई अधिकारी, पाकिस्तान के स्थानों में या स्वयं भारत के कमान अधिकारियों में से अधिकार प्राप्त मये थे। आवश्यक संगठनों में सतत पर भारी आघात पड़ा था। भारतीय सेना-मुख्यालयों की दिक्कतें, अनेक अत्यावश्यक अभियानों के उपलब्ध न रहने से, बढ़ गयी थी, जिनमें से बहुत से ब्रिटिश अधिकारियों ने नष्ट कर दिये थे। इसके अलावा उच्चतम कमांडर से मुख्यालय और साथ ही अविभाजित सशस्त्र सेना-मुख्यालयों में, जो भी हो सके, क्षीनाभपटी करने की पाकिस्तानी नागरिकों की कोशिशों के कारण और भी गड़बड़ी पैदा हो गयी थी। माय ही दिल्ली शहर पर भी साम्प्रदायिक दंगों का असर पड़ा था। अनेक अमेरिक कर्मचारी दफ्तर न आ पाते थे और जो थोड़े से, मुद्रा जनसमूह के दृष्टियों से बच कर, आ भी जाते थे, उनको काफी समय तक काम करना पड़ता था। दानि स्थापना में अमेरिक अधिकारियों की मदद देने के लिए रेजीमेंटों को भेजना पड़ा था, पर वे भी विभाजन के कारण काफी असंगठित हो चुकी थी। कई स्थानों में उनके पुराने ब्रिटिश अधिकारी आ चुके थे और उनकी जगह पर दूसरी यूनिटों में नये ब्रिटिश अधिकारी आ गये थे। पाकिस्तानी नागरिकों की पूरी की पूरी कम्पनियाँ आ चुकी थी और उनकी जगह भारतीय सैनिकों की कम्पनियाँ आ गयी थी, जो मूलतः पाकिस्तान के बाँट में आयी रेजीमेंटों से सम्बद्ध थी। इस तरह रेजीमेंटें विघटित हो गयी थी और वे समस्त और एकवद्ध यूनिटें न रह गयी थी। ऐसी परिस्थिति में, अभी सेना को जमाने और साँस लेने का भी मौका न मिला था कि उनको इन कठिन स्थितियों का सामना करने के लिए बुला लिया गया।

### मैन्य निष्क्रामण संगठन

इस भारी उपल-मुपल के बीच ही लाखों विस्थापित व्यक्तियों का पाकिस्तान में आना शुरू हुआ और विस्थापित व्यक्तियों के अनुरक्षण, संरक्षण और उनकी जरूरतों की पूर्ति में सेनाओं की एक बड़ी भूमिका निभानी पड़ी। पंजाब सीमा-दल का पहला उद्देश्य क्या था चुका है, जिनमें चौथा पदल डिबीजन था। इसे ३१ अगस्त, १९४७ की आधी रात में विघटित कर दिया गया। इस सेना में आने वाले क्षेत्र सम्बन्धी जिम्मेवारी अब सम्पन्नित डोमीनियमों की रह गयी। भारतीय सैनिकों की पश्चिमी पंजाब में गैर मुसलमानों को लाने में मदद देने के लिए लगाया गया और पूर्वी पंजाब से मुसलमानों को ले जाने में पाकिस्तानी सैनिकों की। सीमा की भारतीय ओर वाला जो इलाका पहले पंजाब सीमा दल के क्षेत्र-क्षेत्र में था, उसे अब पूर्वी पंजाब सीमा नाम दिया गया और उसे मेजर जनरल बे० एम० विमर्या डी० एम० ओ० के अधीन कर दिया गया। ये पहले पंजाब सीमा-दल के कमानधारी मेजर जनरल रीत के एक सम्पूर्ण अधिकारी रह चुके थे। जब सेनाओं का पुनर्वितरण, पुनर्निर्माण और जनरल में मेजर जनरल विमर्या के मुख्यालय का पुनर्गठन चल हो रहा था, उन्ही समय हजारों हिन्दू-मिश्र पश्चिमी पंजाब में पूर्वी पंजाब में आ रहे थे और अपने गाय पाकिस्तानियों द्वारा किये गये अविश्वसनीय अत्याचारों और सम्पूर्ण हत्याओं की कहानियाँ ला रहे थे।

पाकिस्तान में दारणाधियों का निष्क्रामण तेजी में व्यवस्थित करने के लिए १ गिग्वर,



१९४७ को एक सैन्य निष्क्रामण समूह, व्यवहारतः बिना पूर्व सूचना के, खड़ा किया गया और उसका मुख्यालय अमृतसर में रखा गया। ऐसा ही सैन्य निष्क्रामण समूह पाकिस्तान में एक ब्रिटिश सेना अधिकारी की भारसाधकता में लाहौर में स्थापित किया गया। सैन्य निष्क्रामण समूह को अनेक अडचनों के बीच काम करना पड़ा। पूर्वी पंजाब एरिया, विविध-व्यवस्था बनाये रखने और शरणार्थी शिविरो और मुसलमानों के काफिलों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार था। भारतीय सैन्य निष्क्रामण समूह प्रशामनिक दृष्टि से पूर्वी पंजाब एरिया के अधीन था और वह गैर-मुसलमानों में पश्चिमी पंजाब में निष्क्रान्त करने के लिए था। गैर मुसलमानों के पश्चिमी से पूर्वी पंजाब आने और मुसलमानों को उल्टी दिशा में से जाने के लिए भारतीय सेना की यूनिटें पाकिस्तान में नैनात की गयीं और पाकिस्तान की यूनिटें पूर्वी पंजाब के क्षेत्र में।

भारतीय सैन्य निष्क्रामण समूहों ने निष्क्रामण का कार्य बड़ी सक्षमतापूर्वक चलाया। पंदल काफिलों के रूप में निष्क्रामण की औसत हर तीन दिनों में १००,००० व्यक्ति थी। अक्टूबर, १९४७ तक १६ लाख व्यक्तियों को लाया गया। अब और पंदल आने वाले व्यक्ति न रहे। हर रोज १५,००० व्यक्ति रेल गाड़ियों से आते थे। और पूर्वी और पश्चिमी पंजाब के बीच दोनों दिशाओं में छह गाड़ियाँ रोज चलती थीं। कुल मिलाकर १०६२,५०० व्यक्ति रेल से लाये गये। लगभग ४५०० व्यक्ति रोज मोटर गाड़ियों से आए और इस तरह कुल ३२०,००० व्यक्ति लाये गये। ३०,००० व्यक्ति हवाई जहाज से आये। निष्क्रान्त किये गये व्यक्तियों का कुल योग ३०,३२,५०० था।

हवाई जहाज में निष्क्रामण के बारे में यह बात अब प्रकट हो जा सकती है कि रॉयल इंडियन एयर फ़ोर्स के पाइलटों ने इन व्यक्तियों को उठाकर लाने में बड़ा भारी उत्तरा उठाया, जबकि जहाज के कार्य-क्षेत्र में शरणार्थी भरे रहते थे। हर जहाज में व्यक्तियों की संख्या अनुसूचित अधिकतम संख्या से कहीं ज्यादा रहती थी। पाइलट जहाज में ठसाठस भरे लोगों के बीच से होकर मुश्किल में कॉन्क्रेट तक पहुँचते थे। वापुसेना विनियमों के अधीन विहित सुरक्षा सीमा का उल्लंघन करने के लिए पाइलटों के खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई की जा सकती थी, लेकिन स्वयं भारी सतरा उठाकर वे इस आपात में दयासम्भव अधिकाधिक लोगों को ले आना ज्यादा पसन्द करते थे। हवाई रास्ते में उठाकर लाने में कोई दुर्घटना नहीं हुई। इन धीरे पाइलटों की उद्गम-प्रवीणता की जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी होगी।

भारत के विभिन्न भागों से मुसलमान प्रवासार्थियों की अनुरक्षित करके पूर्वी पंजाब लाने का काम न केवल असुखकर था, बल्कि कठिन भी था और सतराक भी। इस काम के लिए ब्रिटिश सैनिकों को जल्दी-जल्दी इकट्ठा कर लिया गया था और अधिकांश मामलों में उनको ऐसे नमीरान प्रांत और नान-नमीरान अफसरों के अधीन रख दिया गया, जिनको वे जानते भी न थे। इस काम के लिए लगाये गये सैनिकों के लिए सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था न की जा सकती थी और न अनुरक्षा-कार्य में उनको कितना समय लग जायेगा, इसका ही पूर्वानुमान लगाया जा सकता था, इनमें से अनेक सैनिक विदेश के इलाकों से हाल ही में लौटे थे और उनके दस्तावेज और दूसरे व्योरो की जाँच तक न हो पायी थी। उनमें से कई को छुट्टी पर जाना था, कुछ का अमेरिकी जीवन के लिए मेवासोचन होना था और कुछ मिलाकर अपने खराब

हालत उनकी थी, जो स्वयं विस्थापित थे और जो अपने परिवार के साथ सम्पर्क स्थापित न कर पाते थे, न उनके बारे में विश्वस्त जानकारी ही प्राप्त कर सकते थे। रेतगाड़ियों की अनुरक्षा का काम दम कारण और भी कठिन हो गया था कि सैनिक नये थे और ऐम भारी आन्दोलन से भोचके रह जाते थे तथा उनका मार्गदर्शन और नेतृत्व करने के लिए उनके अफसर भी उनके पास न होते थे। फिर भी सारा काम बड़े प्रशसनीय ढंग से पूरा किया गया।

सरकार ने यह आश्वस्त करने के लिए सख्त कदम उठाये कि सवारी गाड़ियों का संरक्षण करने समय सशस्त्र सेना के लोग अपना वतव्य न भूल जायें। रेतवे (सशस्त्र सेनाओं द्वारा संरक्षण) अध्यादेश, १९४७ (१९४७ का सोलहवाँ) १० सितम्बर, १९४७ को लागू किया गया जिसके अन्तर्गत यदि भारतीय सेना अधिनियम १९११ या भारतीय वायुसेना अधिनियम १९३२ के द्वारा प्राप्ति कोई व्यक्ति रेत द्वारा ले जाये जा रहे यात्रियों या माल का संरक्षण करने के अपने कर्तव्य के पालन में त्रुटि करता है तो सक्षिप्त सामान्य कोर्ट मार्शल या फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा सिद्धोप होने पर उसे दंडित किया जा सकेगा, और १० वर्ष तक की सख्त सजा और अपराध के समय किसी आदमी को मृत्यु हो जाने पर मृत्यु दण्ड तक दिया जा सकता था।

१५ दिसम्बर, १९४७ तक अधिकांश गैर-मुसलमानों को पश्चिमी पंजाब से निकाल लिया गया। उससे बाद सैन्य निष्क्रामण संगठन की सख्ता क्रमशः कम कर दी गयी जो छोटा-सा सैन्य निष्क्रामण संगठन बना रहा वह अनेक छोटे-छोटे बेन्द्रो से लोगों को निकालने का काम या अपहृत स्त्रियों-बच्चों या जबरदस्ती मुसलमान बना लिये गये लोगों के निकालने का काम करता रहा। लेकिन शीघ्र ही भारत से शत्रुता बढने पर पाकिस्तान के अधिकारियों ने छोटे-छोटे बेन्द्रो से लोगों के निकालने का काम बन्द कर दिया और इस तरह २३ अगस्त, १९४८ को भारतीय सैन्य निष्क्रामण संगठन बन्द हो गया।

इस बीच सेना से कहा गया कि गुरुक्षेत्र के सबसे बड़े शरणार्थी शिविर को संगठित कर और बसाये, जिसमें दो लाख शरणार्थी थे। इस काम के लिए सैन्य संगठन २७ अक्टूबर, १९४७ को बनाया गया और वह १५ फरवरी, १९४८ तक शिविर के प्रशासन का काम संभालता रहा।

पूर्वी पंजाब और दिल्ली में कानून और व्यवस्था को उग्र समस्या का सामना करने के लिए पूर्वी पंजाब और दिल्ली उपद्रवग्रस्त क्षेत्र (सशस्त्र सेना की विशेष शक्तियाँ) अध्यादेश, १९४७ (१९४७ का सत्रहवाँ) के अधीन जो १ सितम्बर, १९४७ को लागू किया गया था, उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में काम कर रहे सशस्त्र सेना के अधिकारियों की विशेष शक्तियाँ प्रदान की गयीं। इस अध्यादेश द्वारा उपद्रवग्रस्त या खतरनाक घोषित किये गये किसी क्षेत्र में सशस्त्र सेना के बमोदहन-प्राप्त अधिकारी, वारंट अधिकारी या नॉन-बमोदहन अफसर को यह शक्ति दी गयी कि वह कानून तोड़ने वालों के खिलाफ बल-प्रयोग कर सकेगा, मने ही किसी को मृत्यु तक हो जाय, बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा या बिना वारंट के किसी घर में घुसकर तलाशी ले सकेगा। जिस तेजी और निष्पक्षता के साथ सशस्त्र सेनाओं ने दिल्ली और पंजाब के उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों की स्थिति को संभाला, उससे एक बार फिर सारे

देश की जनता उसकी आगारी हो गयी ।

अभी जमाने के लिए तैयार हो रही एक विभाजित मेवा के लिए इतने सारे काम ही बहुत काफी थे, कि टने इतने भी ज्यादा कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा ।

देशी रियासतें ( जूनागढ़, हैदराबाद और काश्मीर को छोड़कर ) देशभक्ति को भावना से प्रेरित हो और बदलते भारत की वस्तुस्थिति के प्रति जागृकता से उत्साहित हो और साथ ही भारत सरकार द्वारा कुशलतापूर्वक चलायी गयी बातचीत के कारण, १५ अगस्त, १९४७ तक, भारत में सम्मिलित हो गये थी ।

सत्कालीन एग्जीक्यूटिव कौंसिल के उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने यह स्पष्ट कर दिया था कि 'हम भारत के भीतर किसी भी रियासत की आजादी को मान्यता नहीं देंगे । किसी विदेशी सत्ता द्वारा ऐसी किसी रियासत को दी गयी मान्यता अनुनापूर्ण कार्रवाई मानी जायेगी ।' फिर रियासतों के शासकों और प्रतिनिधियों की बैठक में २५ जुलाई, १९४७ को भाषण देते हुए वायसराय लार्ड माउंटबेटन ने भी कहा कि रियासतें इस बात में स्वतन्त्र थी कि वे दोनों में से किसी भी डोमोनियन में सम्मिलित हो जायें, पर कुछ भौगोलिक विवरणों हैं, जिनमें इनकार नहीं किया जा सकता । १६५ रियासतों में से अफ़्गान भौगोलिक दृष्टि से निश्चय ही भारत के डोमोनियन में जुड़ी है । आप अपनी पड़ोसी डोमोनियन सरकार से मुक्त नहीं मोट सफ़ते । देशी रियासतों के सम्मिलन सम्बन्धी राजनीति के पहलू और अन्य बातें इस पुस्तक के लिए संगन नहीं हैं और तीन रियासतों का जो उल्लेख किया जा रहा है, वह भी हम बात तक ही सीमित है कि सपास्य सेना का इसमें कितना नाता था ।

### जूनागढ़

काठियावाड़ की रियासतों में जूनागढ़ रियासत का विशेष स्थान था । दक्षिण में अरब सागर को छोड़ कर, बाकी दिशाओं में यह भारतीय रियासतों से ही घिरी थी । वह पल के रास्ते पाकिस्तान में जुड़ी हुई नहीं थी । जूनागढ़ के राज्य क्षेत्र के दुकाने पाकिस्तान की दूसरी देशी रियासतों के बीच पड़ते थे, और पहले ही भारत में सम्मिलित हो चुकी इन रियासतों के कुछ हिस्से जूनागढ़ के राज्य क्षेत्र के बीच पड़ते थे । शासक एक मुसलमान नवाब था, पर आबादी ८० प्रतिशत हिन्दू और जैन थी । इन सभी बातों के बावजूद और आरम्भ में भारत में सम्मिलन का संकेत देने के बाद भी, १५ अगस्त, १९४७ को नवाब ने घोषणा कर दी कि रियासत पाकिस्तान के साथ सम्मिलित हो रही है । स्थिति स्पष्ट करने के लिए बार-बार अनुरोध किये जाने के बाद, पाकिस्तान ने लगभग एक महीने बाद बताया कि उसने जूनागढ़ का पाकिस्तान में सम्मिलन स्वीकार कर लिया है और बाद में यह मत व्यक्त किया कि जूनागढ़ की भौगोलिक स्थिति की परवाह किये बिना जूनागढ़ के नवाब को पाकिस्तान से सम्मिलन का पूरा-पूरा अधिकार है । यह स्पष्ट था कि पाकिस्तान भारत को कुछ कार्रवाई शीघ्र कर गुजरने के लिए उत्तेजित कर रहा था । इस बात पर ध्यान देना बड़ा दिलचस्प है कि पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने यह भी तर्क दिया कि 'सम्मिलन के नैतिक या जातिगत पहलुओं का ध्यान बिना ही, जूनागढ़ के नवाब को पाकिस्तान के साथ सम्मिलन का पूरा-

पूरा अधिभार है।' जूनागढ़ बाबरीवाड और मगलौर को अपनी सामन्त रियासतें मानता था, पर वे स्वयं भारत में सम्मिलन कर चुकी थी। अपने सम्मिलन के आधार पर जूनागढ़ ने पहले बाबरीवाड और फिर मगलौर को सेना भेजी। जिन परिस्थितियों में जूनागढ़ पाकिस्तान में सम्मिलित हुआ था, उनमें भारत सरकार स्वभावतः इस सम्मिलन को नहीं मान सकती थी। फलस्वरूप उसने बाबरीवाड और मगलौर से जूनागढ़ की सेना वापस लिए जाने की मांग की। सितम्बर के तीसरे हफ्ते में स्थिति गम्भीर हो गयी। सारा देश ही कठिनाई के एक दौर से गुजर रहा था और परिस्थिति का दृढ़ता, धीमेपन और सावधानी के साथ सामना करना जरूरी था। अगर भारत थोड़ी भी डोल दिखाता, तो दूसरी देशी रियासतों को भी गंभीर शक हो जाते, जिसके स्पष्ट ही गम्भीर प्रतिफल होते।

काठियावाड़ की रियासतों के अनुरोध पर भारतीय थल, वायु और नौसेनाओं को यूनिटें अक्टूबर, १९४७ के आरम्भ में पोखण्डर पहुँच गयी और उनको जूनागढ़ के चारों ओर उपयुक्त रूप से तैनात कर दिया गया। शीघ्र ही जूनागढ़ के नवाब द्वारा शुरू किये गये अत्याचारों की कहानी दिल्ली पहुँची। १ नवम्बर, १९४७ को भारत सरकार द्वारा भेजे गये एक असेनिक प्रशासक ने सेना की एक छोटी टुकड़ी के साथ जा कर बाबरीवाड और मगलौर का प्रशासन संभाल लिया। बाद में जूनागढ़ के दीवान के इस अत्यावेदन पर कि रियासत में हालत गम्भीर हो गयी है, भारत सरकार ने १ नवम्बर, १९४७ को जूनागढ़ का प्रशासन संभाल लिया और इस तरह जूनागढ़ की समस्या का समाधान हो गया।

फरवरी, १९४७ में जूनागढ़ और उसके उपाय सौराष्ट्र सच के भाग बन गये, जो अब गुजरात राज्य में शामिल है। यद्यपि इन स्थितियों में सैन्य सत्रिया की जरूरत नहीं पड़ी, तथापि उस समय उपलब्ध बहुत सीमित सेना के एक छोटे-से अंश का नियोजन भी सशस्त्र सेनाओं के तत्कालीन कार्यकरण के प्रसंग में बहुत महत्वपूर्ण है।

### हैदराबाद

निजाम की रियासत हैदराबाद की सीमा पर उत्तर में मध्यप्रदेश पश्चिम में बम्बई प्रेसीडेन्सी और पूर्व और दक्षिण में मद्रास प्रेसीडेन्सी थी। १२ जून, १९४७ को निजाम ने यह फरमान निकाला कि हैदराबाद न तो पाकिस्तान में सम्मिलित होगा और न भारत में ही। उसने यह भी घोषित किया कि १५ अगस्त, १९४७ को निजाम स्वतन्त्र सम्राट् को हैसियत के हक्दार होगा और राष्ट्रमण्डल के सदस्य के रूप में डोमोनियन स्टेटस प्राप्त कर सकेगा। हैदराबाद ने बाद में सम्मिलन के बारे में जो टालमटोल दिखायी वह पहले ही एक बिकट समस्या बन चुकी थी। भारत सरकार और निजाम सरकार के बीच अनन्त बातचीत अब भी लगातार चल रही थी। भारत डोमोनियन ने बीचोबीच स्थान एक देशी रियासत का यह पक्षतावादी खेया बढ़ी भारी चिन्ता का विषय बन रहा था। भूगोल के व्यावहारिक आधार और आन्तरिक सुरक्षा की अनिवार्य जरूरतों को देखते हुए वस्तुतः यह विचारणीय था कि क्या भारत की राज्यसीमा के भीतर स्वतन्त्रता का दावा करने वाली कोई रियासत रह सकती है?

२२ अक्टूबर, १९४७ को पाकिस्तान की सीमा की ओर गे भेजे सशस्त्र लोगों के

काश्मीर-आक्रमण के बाद, भारतीय सेना के वहाँ व्यस्त हो जाने पर, हैदराबाद का खेया और भी मस्त हो गया। २६ नवम्बर, १९४७ को पर्याप्त बातचीत के बाद भारत सरकार ने निजाम के साथ एक यथास्थिति समझौता कर लिया, जिसमें उस राज्य का भारत में सम्मिलित होना शामिल न था। समझौते में व्यवस्था थी कि रक्षा, विदेशकार्य और संचार भवित समान अभि-सम्बन्धों वाले सभी मामलों में १५ अगस्त, १९४७ से पहले हैदराबाद और भारत के बीच जो भी प्रशासनिक व्यवस्थाएँ चल रही थी, वे सभी एक वर्ष तक चालू रहेगी। रक्षा के पहलु की ओर दृष्टि में इस समझौते में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था यह थी कि भारत सरकार फरवरी, १९४८ तक हैदराबाद में अपनी सेनाएँ वापस बुला लेगी और गोला-बारूद और सन्नाख के बारे में रियासत को न्याय-संगत माँग पूरी करेगी। इस करार का यथावत् पालन करते हुए भारत सरकार ने मिरान्दराबाद में स्थित भारतीय सेना की यूनिटों के वापस आने का आदेश दे दिया। यह ध्यान रखना होगा कि भारत सरकार की सेनाएँ १५० साल में ज्यादा समय में मिरान्दरा-बाद की छावनी में रहती थी और रियासत में उनकी स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण थी। फिर भी राष्ट्रभाव के सन्नेत के रूप में और पान्तिपूर्ण निपटारा करने की दृष्टि में भारत सरकार ने वापस बुलाने के लिए सहमत हो गयी।

सेना वापस बुलाने में सम्बन्ध मुघरने की तो बात असल, उससे बाद में ऐसी चीजें पैदा हो गयी, जो भारतीय प्राधिकारियों के लिए गन्धीर चिन्ता का कारण बनीं। निजाम सरकार ने देशी-रियासत-सेना-योजना, १९३६ के अधीन अपने दायित्वों का सन्दर सख्त कर दिया और कार्यत उल्लंघन किया। यह एक बुनियादी करार था, जो यथास्थिति करार के अनुसार यथावत् रहा था। इस योजना के अधीन सम्राट—और अब यथास्थिति करार के अनुसार भारत सरकार—को अधिकार था कि रियासती सेनाओं की यूनिटों की संख्या और वर्गीकरण को विनियमित करे। निजाम सरकार ने सेना की संख्या में अनधिकृत वृद्धि करना शुरू कर दिया और सन्नाखों और गोला-बारूद का निर्माण शुरू कर दिया। यह भी खबर मिली कि युद्ध सामग्री खरीदी जा रही है और तत्कालीन रूप से रियासत में लायी जा रही है और सन्नाख, गोला-बारूद और सैन्य-उपकरण भारतीय प्रान्तों में रियासत में लाने के लिए पूरे देश में एजेंडों का जाल बिछा दिया गया है। वस्तुतः सन्नाख संपर्क के लिए बड़ी तेजी से तैयारियाँ की जा रही थीं। पाकिस्तान की भी भारत की दिक्कतें बढ़ाने का पूरा-पूरा मौका मिल रहा था। साथ ही रजिस्ट्रारों के (मुतलकाल सल्लयदायिख संयन्त्र) कारनामों ने हैदराबाद में आतंक पैदा कर दिया था और सामान्य प्रशासनी से किसी भी राज्य में ऐसी स्थिति में विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए सेना का बुलाया जाना जरूरी हो जाता। तदनुसार भारतीय सेना के प्राधि-कारियों को ऐसी आवश्यकता का पूरा स्थान करना पड़ा और तदनुसार तैयार होना पड़ा। इस तरह हैदराबाद भारत के लिए पेट का फोड़ा बन रहा था और इसी बीच अप्रत्याशित घट-नाओं के कारण भारतीय सेनाओं को काश्मीर में जाना पड़ गया था।

### काश्मीर

२५ अक्टूबर, १९४७ को भारत सरकार ने बहुत कुछ विस्तार की तरह अवस्थान

भारतीय सैन्य अधिकारियों को आदेश दिया कि जम्मू और काश्मीर में तुरन्त सेना भेजने की योजना बनायें ताकि राज्य को पाकिस्तान के सोमान्त इलाके में जाने वाले कबाइलियों के झुंडों से बचाया जा सके, जो काश्मीर में पहले ही काफी आगे बढ़ चुके हैं। सैन्य इतिहास में यह वस्तुतः अनूतपूर्व स्थिति थी।

१५ अगस्त, १९४७ को ब्रिटिश सम्राट की परम-प्रभुता के समाप्त होने की आशंका ने दूसरी देशों रियासतों के लिए, भौगोलिक निकटता की दृष्टि में, जोकि निश्चय ही सबसे महत्वपूर्ण बात थी, भारत या पाकिस्तान के साथ सम्मिलित हो जाने का फैसला करना आसान कर दिया था। इस बारे में जम्मू और काश्मीर रियासत ने अपने को कठिन परिस्थिति में पाया, क्योंकि वह पाकिस्तान और भारत दोनों के निकट या वस्तुतः दोनों से घिरी थी। भारत सरकार ने महाराजा के भारत में सम्मिलन का आग्रह न किया, बल्कि सार्ज माउंटबेटन के जरिए यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह चाहे तो पाकिस्तान के साथ सम्मिलित हो सकते हैं। अन्तिम निर्णय करने में पहले, समय चाहते हुए, राज्य ने पाकिस्तान और भारत दोनों से यथा-स्थिति करार करके पूर्ण स्थिति बनाये रखने की इच्छा प्रकट की। ऐसा करार वस्तुतः पाकिस्तान के ही साथ हस्ताक्षरित हुआ, पर भारत के साथ बर्बाद हुए सवे, इससे पहले ही रियासत में गंभीर आपात स्थिति आ गयी। यथा स्थिति करार का उल्लंघन करके पाकिस्तान ने पेट्रोल, नमक, चीनी, फेफड़ा और अन्य उपभोग-द्रव्यों की महत्वपूर्ण पूर्ति में कटौती करते हुये, राज्य पर आर्थिक दबाव डालना शुरू कर दिया। आर्थिक घेराबन्दी सख्त कर दी गयी और ३ सितम्बर १९४७ से ४५० मील लम्बी सीमा रेखा के अनेक स्थलों पर पाकिस्तान की ओर से रोज कई कई हमले होने लगे। बिना किसी कारण के पाकिस्तान ने श्यालकोट से जम्मू आने वाली रेलगाड़ी-सेवा बन्द कर दी। सीमा-हमले तेजी से बढ़ते गये।

२० अक्तूबर, १९४७ को पाकिस्तान ने काश्मीर पर पूरे पैमाने पर आक्रमण कर दिया। मुख्य हमलावर २००-३०० के झुंडों में आये और उनकी कुल संख्या, कबाइली और "छुट्टी" वाले पाकिस्तानी सैनिकों को मिलाकर, ५००० थी। उनका नेतृत्व कुछ नियमित अधिकारी कर रहे थे, जो भूप्रदेश में सुपरिचित थे। सीमित रियासती सेना काफी विस्तृत मोर्चे पर नियोजित की गयी थी, इसलिए वे कहीं पर भी सैनिक दृष्टि से बलवान न थे। फलतः पूरी सीमा रेखा पर राज्य की रक्षा व्यवस्था में दरार पड़ चुकी थी। हमलावर धीनगर के रास्ते पर बारामुला की ओर बढ़ रहे थे।

ये घटनायें यद्यपि एक सीमा पर की रियासत में घटित होने के कारण काफी गंभीर थी, पर हमने भारतीय सैन्य अधिकारियों को कोई चिन्ता न हुई थी। वस्तुतः इनको इन बातों में परिचित भी न किया गया था और उनसे पास जो जानकारी थी, वह समाचार-पत्रों की सवरो पर आधारित थी। साथ ही वे विमानन की समस्याओं और नानूत-व्यवस्था बनाये रखने के काम में इतने व्यस्त थे कि उनको इस उत्तरी रियासत के बारे में सोचने का कुछ भी मौका न मिल पाया था। वस्तुतः यदि वह रियासत १५ अगस्त, १९४७ को भारत में सम्मिलित भी हो गयी होती, तब भी यह बड़ा गन्देहास्पद है कि गणराज्य आक्रमण के मुकाबिले सामान्य रूप से उसके सरक्षण की उपयुक्त व्यवस्था करना भी सुभव हो पाता या नहीं। २४

अक्टूबर, १९४७ को भारतीय सेना के कमांडर-इन-चीफ (जनरल लोकहार्ट) को यह सूचना मिली कि ५००० क्वाड्रिलियो ने मुजफ्फराबाद और डोमेल पर २२ अक्टूबर १९४७ को कब्जा कर लिया है (जो पाकिस्तान और काश्मीर की सीमा के बिल्कुल पास है)। इस समाचार की ओर भी गम्भीरता से ध्यान नहीं दिया गया था, हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से पठान के एक राज्य की ऐसी लूट-पाट भारत के लिये व्यापक चिन्ता का कारण थी। सेन्य दृष्टि में स्थिति को धौंकने में काश्मीर समस्या के राजनीतिक पहलू आटे नहीं आते। फिर भी पूर्वोक्त तथ्यों में यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि २५ अक्टूबर, १९४७ को तारीख तक भारतीय सेन्य अधिकारियों के दिमाग में यह बात रज्जधान भी न आयी थी कि भारतीय सेना से यह माँग की जायेगी कि वह काश्मीर की सहायता के लिए आगे बढ़े। इसलिए काश्मीर को रक्षा करने का आदेश जितना आन्तरिक था, उतना ही अप्रत्याशित भी। आगे तीनों सेनाओं के तत्कालीन प्रमुखों द्वारा (जो तीनों ही ब्रिटिश अधिकारी थे) हम्बाराहित, एक मयुक्त टिप्पण की, एक फोटोस्टेट अंग्रेजी नज़र का अविकल अनुवाद दिया जा रहा है, जिसने उस बात की पुष्टि हो जानी है और जिसमें घटनाक्रम भी दिया जा रहा है।

### परम प्रवृत्ता

#### भारत के स्टाफ प्रमुखों का वक्तव्य

१—यह आरोप लगाया गया है कि भारतीय सेनामें काश्मीर भेजने की आयोजनायें, २२ अक्टूबर में जिस तारीख को एकादश की ओर से दियासब पर हमला शुरू हुआ, उसने पहले ही दिनों तारीख को बना ली गई थी।

२—तीनों घटनाओं की एक समय-भारणी दी जा रही है कि इन बारे में कब निर्णय लिया गया, आयोजना बनायी गयी, आदेश दिये गये और संचालन शुरू हुआ —

- (१) २४ अक्टूबर को भारतीय सेना के कमांडर-इन-चीफ को सूचना मिली कि क्वाड्रिलियो ने मुजफ्फराबाद पर कब्जा कर लिया है। यह हमले का पहला संकेत था।
- (२) इस तारीख से पहले भारतीय सेनाओं को काश्मीर में भेजने के लिए कोई भी आयोजना न तो बनायी हो गयी थी और न उस पर विचार ही किया गया था।
- (३) २५ अक्टूबर को प्रातः हमें निर्देश दिया गया कि क्वाड्रिलियो का आक्रमण रोकने के लिए यदि जरूरी हो जाय तो वायुमार्ग और सड़क से काश्मीर में सेना भेजने के लिए आयोजना की जाँच की जाय और तैयारी की जाय। इस विषय में हमें मिलने वाला यह पहला निर्देश था। इस बैठक से पहले ऐसी आयोजना की जाँच और तैयारी के लिए कोई धारंवाई न की गयी थी।
- (४) २५ अक्टूबर को दोपहर-बाद हमने भारतीय सेना और रॉयल भारतीय वायु-सेना का एक-एक स्टाफ अधिकारी विमान से श्रीनगर भेजा। वहाँ पर उन्होंने

काश्मीर की राज्य मेना के अधिकारियों से बात की। यह हमारे मुख्यालय के अधिकारियों और काश्मीर राज्य-मेना के अधिकारियों के बीच काश्मीर में भारतीय सेनाओं भेजने के विषय में पहला सम्पर्क था।

- (५) २५ अक्टूबर को ही दोपहर-वाद हमने यह आदेश जारी किये कि भारत सरकार द्वारा काश्मीर का सम्मिलन स्वीकार कर लिये जाने और मदद भेजने का निर्णय करने पर अन्य सूचना पर विमानों से श्रीनगर को जाने के लिये एक पैदल बटालियन अपनी तैयारी करे।
- (६) उपर्युक्त उप पैरा (४) में बताये गये स्टाफ अधिकारी २६ अक्टूबर को प्रातः श्रीनगर में लौट आये और उन्होंने काश्मीर राज्य-मेना के अधिकारियों के माध्यम से अपनी भेंट की रिपोर्टें दी।
- (७) २६ अक्टूबर को दोपहर-वाद हमने सैनिकों के वायु मार्ग द्वारा भेजे जाने के लिये अपनी आयोजना को अन्तिम रूप दिया।
- (८) काश्मीर के द्वारा सम्मिलन लिखन पर हस्ताक्षर कर देने के बाद २७ अक्टूबर को तबके भारतीय मेना का वायु मार्ग से काश्मीर भेजा जाना शुरू हुआ।

३—२५ अक्टूबर से, जो बचाव-कार्रवायों का हमला शुरू होने के तीस दिनों बाद था, पहले सेना भेजने की कोई आयोजना नहीं तैयार की गयी थी और न ऐसी किसी आयोजना पर विचार ही किया गया था।

ह० आर० एन० एन० लोकहाउट  
जनरल, कमांडर इन-चीफ  
भारतीय मेना

ह० एयरमार्शल कमांडिंग  
रायन इंडियन एयर फोर्स

ह० रियर एडमिरल  
फ्रेड अफसर कमांडिंग,  
रायन इंडियन नेवी

३१ अक्टूबर, १९४७

दूसरी ओर, जैसा कि बाद की घटनाओं में सिद्ध हो गया, काश्मीर के आक्रमण की पूरी-पूरी तैयारी पाकिस्तान में सावधानी से पहले में आयोजित की गयी थी और वह मुश्किल थी।

काश्मीर में भारतीय मेना और भारतीय वायुसेना की सफलता का निर्धारण इसी पृष्ठ-भूमि में किया जाना चाहिए।

जम्मू और काश्मीर के महाराजा ने २६ अक्टूबर को, परिस्थितियों में अभिभूत हो चुकने के बाद, भारत में सम्मिलन के लिए लिखन पर हस्ताक्षर कर दिये और तदनुसार राज्य के सीमान्त की सुरक्षा करना भारत सरकार का मावधानित और नैतिक उत्तरदायित्व हो



गया। दूसरे ही दिन बिना कुछ आयोजना बनाये भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना को काश्मीर में सक्रियता शुरू करनी पड़ गयी।

परिस्थिति सब तरह से गम्भीर थी और अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए भारतीय सेना को तुरन्त धीनगर पहुँचना था। धीनगर के लिए यथोचित सुदक की व्यवस्था भी न थी। सम्भारिको (लोजिस्टिक्स) की बात सोचने के लिए भी कोई समय न था। हाज़त इतनी तेज़ी से बिगड़ रही थी कि काश्मीर की सुरक्षा के लिए एक-एक मिनट महत्वपूर्ण हो रहा था। सत्रिया का एक मात्र साधन था कि सेना को वायुमार्ग से भेजा जाय। ऐसा कदम निःसंदेह सफ़ाकौर्ण और भारी ख़तरो से भरा था। पहले से व्यौरेवार आयोजना बनायी भी जाती, तब भी वायुमार्ग से सैनिकों को भेजना और वायुमार्ग से ही अत्यावश्यक पूर्ति भेजना एक अव्यवहारिक बात मानी जाती। राज्य की रक्षा के लिए भारत की सांविधानिक जिम्मेदारी थी और ख़तरे और व्यय या हानि की परवाह किये बिना यह तो करना ही था। ऐसी परिस्थिति में यह निश्चय ही समझ में आने योग्य बात है कि सत्रिया के दृष्टिकोण से सरकार के सैन्य सलाहकारों ने अन्तःक्षेत्र ख़तरो के बारे में भारी शका व्यक्त की थी। पर जब राजनीतिक और सवैधानिक जिम्मेदारियों में बना न जा सकता था, तो सक्रियतायुक्त प्रयत्नों के कारण सेना भेजने का निर्णय नहीं पलटा जा सकता था।

दिल्ली और पूर्वी कमान के मुख्यालय को सेना भेजने का आदेश २६ अक्टूबर को १ बजे दोनहर मित्तल और २७ को प्रातः भयंकर ख़तरो और अडचनों के बावजूद सिल रेजीमेंट की पहली बटालियन के ३२६ सैनिकों को, जो उस समय गुडगाँवा में आन्तरिक रक्षा के काम पर लगे हुए थे, उड़ा कर धीनगर ले जाया गया। इस अनोखी सक्रियतायुक्त हवाई उड़ान के लिए सभी उपलब्ध राँयल इन्डियन एयर फ़ोर्स का असेनिक विमानों को काम में लगा दिया गया। सेना के इतिहास के पृष्ठों में पहले कभी भी सैनिकों से यह अपेक्षा न की गयी थी कि इतने आकस्मिक रूप में राष्ट्र के आह्वान पर संश्रम में मूढ़ पड़ें और मोर्चा सँभाल लें। इस मामले में सिल रेजीमेंट को २४ घंटे से भी कम समय की पूर्व सूचना मिली थी और हमारे सैनिकों को इस बात का घोंडा-सा भी भान न था कि शत्रु की आकाशार्थ और विन्यास क्या हैं, उसकी रणनीति और संख्या क्या है और इसी तरह सैन्य आसूचना की दूसरी बातों का भी उसे ज्ञान न था। उस समय भारत सरकार और भारतीय सेना के सामने जो विकट परिस्थिति थी, उसकी गम्भीरता का वर्णन सम्भव नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच सशस्त्र सेना का पुनर्गठन अभी चल ही रहा था। इसके साथ ही लाखों व्यक्तियों को पाकिस्तान से भारत लाने में सराया और अनुरक्षण देने का काम भी था और आन्तरिक सुरक्षा को बनाये रखने का सवाल अवगत था। तीनों सेनाओं के मुख्यालय अभी मुश्किल से स्थापित ही हो पाये थे। वस्तुतः सारा रक्षा-संगठन गड़बड़ी की स्थिति में था। भारतीय सशस्त्र सेनाओं किसी सैन्य सत्रिया के लिए अभी उपयुक्त हाज़त में न थी। इस तरह परिस्थिति अमम्भावित परिणामों को दृष्टि से संदिग्ध थी और संश्लेष में कश्मीर को सेना भेजने का निर्णय बड़ा ही साहसपूर्ण और ऐतिहासिक था। जैसा कि बाद में पता चला हमलावरों का २६ अक्टूबर को धीनगर पहुँचने का इरादा था। वस्तुतः उन्होंने घोषणा कर रखी थी कि जिन्ना साहौर में प्रतीक्षा कर रहे थे और वे २६

अबूवर को धीनगर को मस्जिद में विजयोन्लासपूर्वक ईद का समारोह मनाना चाहने थे ।

२७ अक्टूबर, १९४७ को मेना भेजने समय भारतीय सेना के अधिकारियों को यह भी भरोसा न था कि सेना भुरखापूर्वक धीनगर के हवाई अड्डे पर उतर भी पायगी या नहीं । इसलिए मेना की पहली टुकड़ी उड़ा कर धीनगर से जाने वाले वायु मेना के पाइलटों को हिदायत दी गयी थी कि पहले यह देख लें कि हवाई जहाज दुश्मनों के हाथ में तो नहीं पहुँच गया है, तभी विमान उतारें । इसलिए दिल्ली में विमानों पर चढ़ने वाले सैनिकों को यह भी ज्ञान न था कि वे कहाँ पर उतरेंगे ।

सौभाग्य से धीनगर के हवाई अड्डे पर अभी दुश्मनों का कब्जा न हो पाया था और हमारे विमान हवाई अड्डे पर उतर सके । सेना की इस वीर टुकड़ी के कमांडर ले० कर्नल डॉ० आर० राय ने काफी सूक्ष्म-सूक्ष्म से काम लेते हुए सैनिकों की एक कम्पनी को हवाई अड्डे की सुरक्षा का भार सौंप दिया और दूसरी को हमलावरों का सामना करने के लिए आगे बढ़ाया, भले ही बढ़ने वाले हमलावरों की संख्या ज्यादा थी—३००० से ५००० के बीच । इस लड़ाई का फल यह हुआ कि हमलावरों का आगे बढ़ना रक गया और दस कोष और अपेक्षित कुमुद आ गयी । कमांडर ने कश्मीर और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर देश के लिए एक आदर्श प्रस्तुत कर दिया । बाद में उनको मरणोत्तर, नवस्थापित महावीर ध्वज, प्रदान किया गया ।

सैन्य-सत्रिया के लिए अपेक्षित आयोजना के या पहले की बात सैन्य हलकों के बाहर सामान्यतः नहीं समझी जाती है । हर ध्यौरे की बात का पूर्वानुमान करके उसकी व्यवस्था की जाती है, सत्रिया चलाने की स्थूल आवेजी, मैदान में उतारे जाने वाले सैनिकों की संस्था और उनका स्वरूप, युद्ध के लिए प्रमुख समर्थक बल, संचार पथ का बनाये रखना, हताहतों का निष्चामण, रक्षितियाँ बनाये रखना आदि । ये सब चीजें यथासम्भव काफी पहले से तैयार करके रखी जाती हैं । ऐसी स्थिति में जब भारतीय मेना को कुछ पदों में ही जा कर कश्मीर में लड़ने का आदेश दिया गया तो कितना खतरा उठाया गया, इसका कुछ अन्दाजा लगाया जा सकता है । आयोजना की कमी और सत्रिया की आतंस्मिकता ने अपनाया सञ्चार और पूर्ति आदवस्त रखने की कठिनार्द भी कम न थी ।

आरम्भ से ही यह विसृत स्पष्ट था कि तत्कालीन कबाइली अपने भाग कश्मीर में नहीं बंढ रहे हैं । हमलावर मोटर-मारियों में आ रहे थे और अद्यतन सम्पन्न—ब्रेन गन, स्टेन गन, ग्रेनेड, भारी मोर्टार, टैंकमार रायफल्स, घन्टी की सुरंगें और असीमित संस्था में गोला-बारूद में सज्जित थे । उन्होंने जो वृत्तचाल और खानेजी दिखायी, उमने विशेषज्ञों द्वारा बनायी गयी मैथ-आयोजना का आभास मिलना था । जैसा कि बाद की घटनाओं में स्पष्ट हो गया, वस्तुतः यह सड़ार्द पाकिस्तानी मेना द्वारा लड़ी जा रही थी । आक्रमण के प्रवर्तकों ने स्पष्ट ही यह हिमाय लगाया था कि भारतवासी कानून-व्यवस्था बनाये रखने और हैदराबाद और जूनागढ़ की पट्टेलियों में उलझे हुए हैं और ऐसी हालत में भारत अपने को कश्मीर की लड़ाई में शामिल न करना चाहेंगा । फिर भारत और कश्मीर में बीच सञ्चार का कोई उपयुक्त साधन बन द्वारा है ही नहीं । सम्भारिणी का प्रश्न ही इतना विचट होगा कि भारत कश्मीर

में हस्तक्षेप करने की कोशिश न करेगा। वायुमार्ग से भी दिल्ली और श्रीनगर की दूरी ५०० मील है। यत्नमार्ग से भारत और श्रीनगर के बीच ३०० मील की पतली-सी सड़क है, जो अच्छे मौसम में ही चलती है। २०० मील लम्बी जम्मू-श्रीनगर सड़क भी बड़ी ऊबड़-खाबड़ है, और पीरपंजाल की पहाड़ी पर वह ६२०० फीट की ऊँचाई में बलनिहाल दर्रे में होकर गुजरती है, जिस पर काफी वर्ष पड़ती रहती है। ऐसी हासत में इतनी दूरी से कश्मीर में हस्तक्षेप एक बड़ी सक्क वायुसेना के लिए भी बड़ा मुश्किल काम था। फिर कश्मीर में कड़के की बर्फीली सड़ों को, पहाड़ी भूमि को और अनेक भारतीय सैनिकों को ठंढ और पाला सहन करने कोई अनुभव न था। सरमे मुश्किल बात यह थी देश के उस हिस्से का ज्ञान लोगों को बहुत कम था, क्योंकि उस क्षेत्र का ध्योरेवार सर्वेक्षण अभी तक हुआ ही न था। बहुत थोड़े से नक्शे उपलब्ध थे और वे भी पुराने पड़ गये थे।

यह सौभाग्य हो था कि भारतीय सेना कश्मीर में एक-दो दिन और बाढ़ नहीं पहुँची, क्योंकि पूरी सम्भावना थी कि उस समय तक श्रीनगर हवाई अड्डा हमलावरों के हाथों में पहुँच जाता और इस तरह किसी भी सेना के लिए वहाँ उतरना असम्भव हो जाता। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में राज्य का भाग्य निश्चिन हो था। सौभाग्य से रियासत की वीर परलु कम पड़ गयी मेना की एक छोटी टुकड़ी ने, जिसमें मुश्किल से १५० सैनिक थे, हमलावरों को दो दिनों तक उरी में रोक रखा और इस तरह उनका चढ़ना दो बहुमूल्य दिनों के लिए रोक दिया, हालाँकि उनमें से प्रायः सभी खेत रहे। जब भारतीय सेना की पट्टी टुकड़ी कश्मीर में उतरी, तब हमलावर केवल ३५ मील दूर बारामूला तक पहुँच चुके थे और उनका श्रीनगर पहुँचना कोई भी न रोक सकता था।

इस सिलसिले में यह भी ध्यान में रखने की बात है कि जैसे ही जिन्ना ने मुना कि भारत ने कश्मीर का सम्मिलन स्वीकार कर लिया है और भारतीय सेना हवाई जहाजों से श्रीनगर जा रही है तो उनमें तुरन्त पाकिस्तान सेना के कमांडर-इन-चीफ जनरल ग्रेसी को आदेश दे दिया कि वह श्रीनगर में सेना भेज दें। पर उन्चतम कमांडर के अनुमोदन के बिना अनुदेश जारी करने में जनरल ने अपनी अहमियत प्रकट की। फील्ड मार्शल आकिनलेक २८ अक्टूबर को प्रातः हवाई जहाज से लाहौर पहुँचे और उन्होंने पाकिस्तान के गवर्नर जनरल के सामने स्पष्ट कर दिया कि कश्मीर अब कानूनी तौर से भारत का क्षेत्र है और अगर अब पाकिस्तानी सेना कश्मीर में जाती है, तो जैसा कि पहले ही समझा जा चुका है, पाकिस्तानी सेना में काम करने वाले ब्रिटिश जफ्तारों को वापस बुलाना पड़ जायेगा। इस बात पर जिन्ना ने पाकिस्तानी सेना कश्मीर भेजने का आदेश रद्द कर दिया। फिर भी हालाँकि पाकिस्तानी सेना गुने आम आगे नहीं बढ़ी, पर सेना के साधन वक्तों तरह से कश्मीर के आक्रमणकारियों के साथ रहे।

जम्मू और कश्मीर की लड़ाई का मित्रशिप वर्णित करना इस पुस्तक का विषय नहीं है। इतना कहना ही काफी होगा कि पूर्ववर्णित अनुसार आयोजना की कमी और सब तरह की अड़चनों के बावजूद सेना और वायुसेना ने मिलकर श्रीनगर को बचा लिया, बल्कि हमलावरों को उनके राज्य के प्रायः सभी क्षेत्रों में निशान देने में भी सफलता प्राप्त की। वस्तुतः

१९४८ के अन्त तक पाकिस्तान की सेना प्रायः सभी मोर्चा पर पीछे हट रही थी। पर सभी १ जनवरी, १९४९ को भारत-याक सयुक्त-राष्ट्र-आयोग द्वारा स्थापित शम्भू-विराम लागू हो गया।

जम्मू और कश्मीर में भारतीय सेना को जो सड़ाई सटनी पड़ी, वह एक नियमित युद्ध से कुछ भी कम न थी। स्वतन्त्र भारत में भारतीय सेना की यूनिटों द्वारा पहली बार इस सत्रिया में हिस्सा लिया गया था। यत्नेना और वायुसेना के सभी व्यक्ति सहज देशभक्ति को भावना में ओत-प्रोत थे। पूरे मग़ास में हमारी सेनाओं ने अपनी सहन-शक्ति के बहुते उच्च स्तर का परिचय दिया। भारी सैन्य मोटर गाड़ियों के लिए अपाय बनायी गयी सड़को और घरों से होकर हमारी सेना टैंकों को ले गयी और उनको मोर्चों पर लगा दिया। भारतीय वायुसेना ने भी कश्मीर सत्रिया में ऐतिहासिक कार्य किया। यह आम विश्वास था कि स्पिट-फायर विमान धीनगर से सत्रियारत नहीं हो सकें, पर भारतीय वायुसेना के दो युवा पाइलटों ने लड़ाई के पहले तीन दिनों में सफलता और साहसपूर्वक धीनगर के हवाई अड्डे पर उतर कर और वहाँ से उड़ान भर कर इम सिद्धान्त को यत्न सिद्ध कर दिया। अपने मार्च की बात पूँछ की पतली-सी हवाई पट्टी पर उतरना था, जिसके चारों ओर ऊँची-ऊँची पहाड़ियाँ हैं। ऐसी पट्टी में सत्रिया करना बड़ी प्रवीणता और साहस का काम था। वस्तुतः उतरने के पहले जहाज को कई-कई-बार चक्कर बाटने पड़ते थे। इन सबमें भी ज्यादा साहस का करतब ग्रुप कैप्टन ( बाद में ) एयर कम्मोडोर मेहर सिंह, बी० एस० बी० ( भारतीय वायुसेना ) ने दिखाया, जिन्होंने दुनिया के सबसे ऊँचे पहाड़ों से होकर २३००० फीट की ऊँचाई पर में एक अमापित पहाड़ी वायुमार्ग से, आसानीन के बिना हो, अपने जहाज को ले जाकर, ११,५५८ फीट की ऊँचाई पर, तेह में एक सूखी नदी की तलहटी में उतार दिया, जहाँ पर हवाई पट्टी जैसी चीज भी न थी। तेह के ऊपर में होकर पहले न कोई विमान उड़ा था, न वहाँ उतरा ही था। हमारी सेना ने जम्मू और कश्मीर में जो साहस और वीरता के कार्य किये, उनमें ये छोटे से नमूने ही उदाहरण स्वल्प दिखे गये हैं।

मनोबल के दृष्टिकोण से यह बड़ा महत्वपूर्ण था कि वीरता के इन कार्यों को मान्यता देने के हेतु उपयुक्त वीरता-पुरस्कार घोषित किये जायें। लेकिन २६ जनवरी, १९५० तक सांविधानिक कठिनाइयों के कारण इन पुरस्कारों की घोषणा न की जा सकी। स्वतन्त्र भारत में बाद में जो पुरस्कार चालू किये गये, उनका उल्लेख आगे किया गया है।

जम्मू और कश्मीर में हमारी सेना की सफलता के दूरगामी प्रतिकूलों के वर्णन को अतिरिञ्चित नहीं कहा जा सकता। यदि देर में पहुँचने पर या अन्य विपरीत परिस्थितियों में भारतीय सेना धीनगर को पहली बार में हा न बचा पाती, तो उसका प्रतिकूल बड़ा ही कष्ट-कर हो जाता। भारत में सम्मिलित स्वीकार कर कश्मीर एक राज्य है रूप में देश के राज्य क्षेत्र का एक अनन्य अंग ही बन गया था। अगर दुर्भाग्य में राज्य पराजित हो जाता, तो सभी यही कहेंगे कि भारत अपने राज्यक्षेत्र के एक अंग को सख्त न कर सका। भारत में सम्मिलित ही सभी अनेक देशों रियासतों का विश्वास डग जाता और इसके पनस्वल्प विषयों की गिनियाँ बतानी हो जाती। स्वयं भारतीय सेना का मनोबल टूट जाता। यदि पाकिस्तान

आने मुचक में सफल हो जाता, तो पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तानी मेना की विजय के रूप में, इस पूरे संक्रिया के लिए दानदार जशन मनाये जाते । उस समय पाकिस्तान जोर-शोर से कहता कि यह पाकिस्तानी मेना का काम है । तब यह बात भारत-पाक संयुक्त-राष्ट्र-आयोग के सामने स्वीकारने के लिए न छोड़ दी जानी । शायद इसने पाकिस्तान को और भी बड़े दु साहस करने के लिए बल मिलता ।

भारतीय राज्यों पर पड़ने वाले सम्भाव्य प्रभाव के उदाहरण के रूप में हैदराबाद की ही बात को लिया जा सकता है । निजाम और उसके सलाहकार कश्मीर, के प्रतिफलो पर बारीक निगाह रख रहे थे और भारत के लिए दुर्भाग्य की किसी घटना का इतबार ही कर रहे थे । बहुत भारतीय मेना द्वारा कश्मीर में सक्रिया शुरू कर दिये जाने के बाद ही निजाम सरकार जान-बूझकर कुछ टडो पड़ी और भारत के साथ कुछ करार करने-को तैयार हुई । पाकिस्तान भी भारत को साथ-साथ चार मसलों में उलमाना चाहता था । अर्धान साम्प्रदायिक समस्या, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर । साम्प्रदायिकता के नाब का फल अच्छी तरह कुचल दिया गया और उसे भारत में काबू में कर लिया गया । जूनागढ़ की समस्या का समाधान हो गया और कश्मीर को बचा लिया गया किन्तु हैदराबाद का प्रश्न अब भी निपटाना शेष रह गया था ।

### हैदराबाद में सैनिक कार्रवाई

जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, हालांकि भारतीय सेना अब भी कश्मीर सक्रिया में सक्रिय रूप से उलझी हुई थी, फिर भी अगर भारत सरकार कहती तो उसे साथ ही हैदराबाद में कानून-व्यवस्था स्थापित करने के लिए भी तैयार रहना था । हैदराबाद की समस्या में भी कई पैस थे । उस राज्य के साथ २६ नवम्बर, १९४७ को गया स्थिति करार हो जाने के बावजूद, दो साल से ऊपर सरा में सशस्त्र और बाकायक रजाकारों ने पूरे राज्य में आतक पैदा कर रखा था । उन्होंने कई बार सीमा पर भी हमले करके जनता को आतंकित किया । कानून-व्यवस्था इस सीमा तक बिगड़ चुकी थी कि आस-पास के राज्यों के पुलिस और अर्सेनिक अधिकारी हैदराबाद के भीतर से होने वाले हमलों का मुकाबला करने में अपने को असमर्थ पा रहे थे । भारतीय सेना कश्मीर में काफी उलझी हुई थी और यह समझ जाता था कि भारत अब अपने को हैदराबाद में गंभीर रूप से नहीं उलझायेगा । यह भी सुभाव दिया जाता था कि हैदराबाद में हस्ताने के फलस्वरूप, सारे देश में साम्प्रदायिक दंगे हो जाएंगे जो पूरे प्रशासन-तन्त्र को पूरे सीमा तक उलमन्न देने के लिए काफी होंगे ।

हैदराबाद अपने को उस रूप से शस्त्र-सज्जित कर रहा था । तत्कालीन से शस्त्रास्त्र लाये जा रहे थे । इस सबके अलावा पाकिस्तान के खैरे के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता था । सब मिलाकर यह बड़ी सकलमय स्थिति थी । बाद में यह इतनी गंभीर हो गयी कि एक दिन भी और ज्यादा बरदाश्त करना मुश्किल हो गया ।

भारत सरकार के द्वारा बार-बार अनुरोध किये जाने के बावजूद, हैदराबाद सरकार न तो रजाकारों को बिपटित करने के लिए तैयार हुई और न कानून-व्यवस्था स्थापित करने

के लिए भारतीय सैनिकों को वापस सिन्धु-राज्य आने के लिए मुविजा देने को हो तैयार हुई। स्थिति सहिष्णुता में अगर जा चुकी थी, इसलिए भारतीय सेना ने कानून-व्यवस्था स्थापित करने को कहा गया और तदनुसार भारतीय सेना ने १३ सितम्बर, १९४८ को ४ बजे प्रांत राज्य की सीमा को पार करके बूच कर दिया। पुलिस कार्रवाई १३ दिनों में पूरी हो गयी और हैदराबाद की सेना ने १ सितम्बर, १९४८ को आत्म-समर्पण कर दिया।

पुलिस कार्रवाई के सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाने पर उप-प्रधान-मन्त्री और गृहकार्य तथा राज्य-मन्त्री सरदार पटेल ने कहा, 'जिस सेना और कुशलता के साथ ये मन्त्रियाँ चलायी गयीं, उसकी सराहना हमारे उत्तम मानोचक भी करेंगे। मुझे मन्द्हेह नहीं कि इतिहास में इन मन्त्रियों को कार्यक्षमता, संगठन और सार्वजनिक सहयोग के अनूठे प्रमाण के रूप में अंकित किया जायेगा। भारतीय सेना ने अपनी वस्तु-सफलताओं की कहानी में एक और अध्याय जोड़ा है।' उस समय भारतीय सेना के सामने जो तरह-तरह की समस्याएँ थी, अगर हम उनको ध्यान में रखें तो यह माना जायेगा कि इस सराहना में कोई अतिरजना न थी। भारतीय वायुसेना ने भी टोह का काम करने और राज्य के हवाई अड्डों को अलग बना कर, इस मन्त्रियों में महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि सभी जानते थे कि ये हवाई अड्डे वायुमार्ग में ब्लॉक लाइने के लिए इस्तेमाल किये जा चुके हैं।

मेजर जनरल जे० एन० चौबरो को, जो उस प्रथम आनंद द्वीप के जनरल अफसर कमांडिंग थे (जिसने हैदराबाद में बूच किया था), सैन्य-राज्यपाल नियुक्त किया गया और उनका पहला काम कानून-व्यवस्था स्थापित करना था। थोड़े में ही समय में राज्य में शान्ति-व्यवस्था और सामान्य जन-जीवन स्थापित करने, सैन्य-राज्यपाल के प्रशासन ने बड़ा ही सराहनीय काम किया। हैदराबाद के भारत में सम्मिलन के बाद भारत बोमीनियन पहली बार एकीकृत देश बन गया। इस तरह १९४७ और १९४८ के वर्षों में देश की एकता और स्वाधीनता को समेकित और सुदृढ़ बनाया गया।

पुलिस कार्रवाई खानू करते समय भारतीय सैन्य अधिकारियों को सभी स्थलों पर सम्भावित परिस्थितियों का ध्यान रखना पड़ा और हर तरह की घटनाओं का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना पड़ा। उस समय हैदराबाद में जो हावत थी, उसे देखते हुए कुछ लोगों ने बड़-बड़ कर अन्दाजे लगाये थे कि राज्य-सेना जमकर प्रतिरोध करेगी और कुछ काफी समय चलेगा। भारतीय सेना ने लिए पर्याप्त जनशक्ति आसन्न करने की दृष्टि में गवर्नर जनरल ने राष्ट्रीय सेवा (अध्यायी और मेसामुक्त व्यक्ति) अध्यादेश, १९४८ (१९४८ का २३वाँ) ११ सितम्बर, १९४८ को प्रवर्तित किया।

द्वय अध्यादेश के अन्तर्गत भारतीय सेवा में अस्थायी तौर पर काम करने वाले हर व्यक्ति को राष्ट्रीय सेवा के लिए रोक लिये जाने का दायी बनाया गया था, अर्थात् उसको सेवा करने वृद्ध भी हो। साथ ही ४५ वर्ष की आयु तक के प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जिसे भारतीय सेना में १ जनवरी, १९४६ को या उसके बाद सेवा-मुक्त किया गया हो, तब तक राष्ट्रीय सेवा के लिए बुला लिये जाने का दायी बनाया गया था, जब तक कि वह बुलाये जाने के समय सरकार के किसी विभाग में अवैयक्तिक हेमियत में काम न कर रहा हो। अवैयक्तिक बैंक

नौकरियों में काम कर रहे सेवामुक्त व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से अध्यादेश ने अत्यैतिक नियोक्ता के लिए यह बाध्यकर बना दिया कि वह ऐसे सेवामुक्त व्यक्तियों को उनको राष्ट्रीय सेवा समाप्त होने पर अन्याय अनुकूल वैसी ही शर्तों के अधीन पुन नौकरी देगा, जो उनके लिए नौकरी में यह बाधा न पड़ने की दशा में उनके ऊपर लागू रहती। १५ सितम्बर, १९४८ को गवर्नर जनरल ने लोक-भुरसा अध्यादेश भी लागू किया, जिसने केन्द्रीय और राज्य सरकारों को अपने-अपने क्षेत्रों में सामान्यतः भारत-रक्षा नियमों जैसे नियम बनाने के लिए प्राधिकृत कर दिया। ये दोनों अध्यादेश छ महीने बाद खत्म हो गये। जिन परेशानियों का सामना करने के लिए उनको लागू किया गया था, वे उस समय तक दूर हो चुकी थीं।

## चौथा अध्याय

# रक्षानीति का निर्माण

## खण्ड—१ भारत का तन्त्र

सत्ता-हस्तान्तरण से पहले भारत को रक्षा-नीति ब्रिटिश साम्राज्य की नीति का अंग थी और भारत की सशस्त्र सेनाओं की सख्या साम्राज्य की रक्षा की योजना में उसकी भूमिका के सन्दर्भ में तय की जाती थी। स्वतन्त्र होने पर भारत को अपनी नयी रक्षा-नीति तैयार करनी पड़ी और अपनी परिस्थितियों और साधनों के अनुसार अपनी रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं का निर्धारण करना पड़ा। इस प्रयोजन से पहला काम रक्षा-मेनाओं का आकार-रचना और संगठन तय करना था। ऐसा करने में नये स्वतन्त्र राज्य के सामाजिक उद्देश्यों और उसकी रक्षा सत्तद्धता के बीच एक सन्तुलन अवश्य तय करना था।

नियी राज्य के राजस्व पर कुछ प्रभार अनम्य तरीके के होते हैं। पहले राष्ट्रीय ऋण का ब्याज चुकाने के लिए पैमे की व्यवस्था करनी होती है, फिर पेंशन सम्बन्धी खर्च और फिर देश के अमैतिक प्रशासन पर अत्यावश्यक व्यय। समाज-सेवाओं के लिए भी कुछ रकम अलग रखनी होती है। इसलिए रक्षा-व्यय के लिए उपलब्ध शेष रकम सामान्य हालातों में हम तरह से सीमित रहती है। लेकिन जब देश की सुरक्षा को बाहरी आक्रमण का खतरा हो जाता है, तो रक्षा व्यय के साथ निश्चय ही बरीयता का व्यवहार किया जाता है।

निश्चय ही यह तय करना कोई आसान बात नहीं है कि किम चीज को सुपर्याप्त सशस्त्र शक्ति कहा जा सकता है। सुपर्याप्तता केवल एक सापेक्ष चीज हो सकती है, जो देश की सुरक्षा के खतरे के स्वरूप और शक्ति पर निर्भर है। लेकिन मने ही देश की सुरक्षा को बाहरी आक्रमण का कोई तत्काल खतरा न हो, सामान्य बुद्धिमानों का तकाबा है कि देश में थल सेना उसके सीमान्त की रक्षा करने के लिए काफी सख्या में होनी चाहिए। नौसेना यूनिटें उसकी तटरेखा की रक्षा के लिए और वायुसेना वायु-पट्टी की रक्षा के लिए सुपर्याप्त होनी चाहिये। सेना, नौसेना और वायुसेना की सख्या का अनुमान एकीकृत आधार पर लगाना होगा और उसके बाद हम प्रकार की रक्षा-मेनाओं को खड़ा करने और उनका सम्भरण करने के लिए पैमे की व्यवस्था करनी होगी। राज्य के उद्देश्यों की ओर विभिन्न बन्ध्याण योजनाओं के लिए पैमा जुटाने की सामान्य योजना में चाही नयी धनराशि को अत्यधिक समझा जा



सहना है। पर रक्षा के प्रयोजन में जरूरी रकम में इतनी कटौती करना बुद्धिमानीपूर्ण न होगा कि उसमें देश की बाह्य सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाय। इसलिए यह फैसला करना मन्त्रिमण्डल का काम है कि रक्षा के लिए कितना पैसा दिया जा सकता है।

एक बार यह तय हो जाने के बाद पैसों की तीनों सेनाओं के बीच उपयुक्त रूप में बांटना होगा। ऐसा करने में भी, सेनाओं के संगठन के बारे में विभिन्न सामान्य सिद्धान्तों को भी तय करना होगा। सेना छोटी-सी सख्या में कम पर काफी मजबूत-सन्नद्ध हो सकती है, जिसमें रक्षित्व की सख्या काफी हो, अथवा वह एक काफी बड़ी सेना हो सकती है, जिसमें व्यापक क्षमताओं से सुज्जित किया जाय। यह तय करना होगा कि उसकी कवचित गाड़ियों में भारी टैंक, बिजने टैंक या छोटे आकार के टैंक होंगे या सब तरह के, और ऐसी स्थिति में उनका अनुपात क्या होगा। नौसेना में केवल व्यापारिक बेड़े के संरक्षण के लिए उपयोगी पोत हो सकते हैं या वह बड़े-बड़े जहाजों में सुज्जित हो सकता है, जो तट में काफी दूर रह कर भी रक्षात्मक और आक्रामक दोनों ही प्रकार को कार्यवाही कर सकते हैं। वायुसेना की भूमिका भी विभिन्न प्रकार की हो सकती है, जिसमें सेना को निकट से सहायता देना भी शामिल है। इसकी रचना को भी फाइटरों, बममारों, टोह वाला और परिवहन वाले विमानों की सख्या के रूप में तय करना होगा। यह प्रश्न भी उठेगा कि कितनी सख्या में दोप्यास्त्र (मिसाइलें) फाइटरों का स्थान ले लेंगी। ये उच्चस्तरीय सत्रातेजी का निदर्शन करने वाले कुछ उदाहरण हैं, जिन पर सैन्य विशेषज्ञों के परामर्श से ध्यानपूर्वक विचार करना होता है। इनमें से कुछ निर्णयों के दूरगामी द्वितीय आलेपन भी होंगे, जो उतने सात तन रहेंगे, जितने सालों में उनकी आपान्ति करनी हो।

सैन्य विशेषज्ञ हमेशा यह मांग करेंगे कि रक्षा-सेनाओं को पर्याप्त कार्यक्षमता के लिए कुछ न्यूनतम आवश्यकताओं का समाधान तो करना ही होगा। लेकिन एक बार सैन्य-सत्रातेजी का विरलेपन हो जाने के बाद अन्तिम फैसला व्यापक राजनीतिक समस्याओं के आधार पर ही अनिवार्यतः किया जायेगा।

सारी दुनिया में होने वाले विभिन्न विकासों, पड़ोस के देशों पर उनके प्रभाव और फिर अन्ततः स्वयं अपने देश पर उनके प्रभाव के आलेपनों को भी ध्यान में रखना होगा। इन ज्ञान और उपलब्ध सैन्य-आमूचना के आधार पर सरकार देश की सुरक्षा के लिए सम्भव खतरों का निर्धारण कर सकेगी और यह कि किस तरह यह साकार रूप ग्रहण करेगा, कब करेगा और उसकी क्या सम्भाव्यताएँ होंगी, आदि। इन बातों की पृष्ठभूमि में ही यह निर्णय करना होगा कि सशस्त्र सेना की कितनी संख्या बनाये रखी जाय, उसे किस तरह गठित किया जाय, उसका क्रियास किंश तरह किया जाय और दोनों सेनाओं की अलग-अलग भूमिका क्या हो। अन्य गौण प्रश्नों पर भी ध्यान से विचार करना होगा। यह ठीक है कि हमेशा दोष-भालोन्-जायोजना बनाया जाना चाहिये, लेकिन रक्षा-सन्नद्धता एक स्थिर चीज नहीं हो सकती। बदली परिस्थितियों में लगातार समीक्षा करते रहना जरूरी होगा।

परन्तु के सैन्य सलाहकारों को विदेश-मामलों के विशेषज्ञों से सलाह लेनी चाहिये। किसी देश की विदेशनीति भी अन्तर बहुत सीमा तक उसकी रक्षा-सम्भाव्यताओं पर निर्भर

रहती है। नैतिक या सैन्य शक्ति के बिना किसी देश की बात विश्व-समस्याओं पर प्रभावी रूप से नहीं सुनी जा सकती। किसी देश को विदेश नीति को भी इस तरह समझित करना होगा कि वह देश को समय से पूर्व युद्ध में न फँसा दे। मने ही सपर्यन्त अन्ततः अनिवार्य मालूम पड़ने लगे, पर भुपर्याप्त सदाकू शक्ति पहले विकसित कर लेनी चाहिये। वाइकाउट टेम्पुलवुड ने अपनी पुस्तक 'नाइन ट्वून्ड ईयर्स' में १९३८ में जर्मनी के प्रति इंग्लैण्ड के रवैये की चर्चा करते हुए एक बड़ी ही रोचक बात कही है कि उस समय इंग्लैण्ड जर्मनी की सशस्त्र शक्ति के साथ खुला सघर्ष करने के लिए तैयार न था। स्टाफ-प्रमुखों का विचार था कि ब्रिटेन युद्ध के लिए तैयार नहीं है और वह समय मित्र राष्ट्रों की मदद के बिना तीन मोर्चा पर ( जर्मनी, इटली और जापान से ) नहीं लड़ सकता, और न वह शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों से घिरे और पूर्ण-रक्षा से अलग-थलग चैकोस्लोवाकिया की २५०० मील लम्बी सीमा का ही संरक्षण कर सकता है। इसलिए ब्रिटेन के सैन्य कार्यक्रम के पूरा होने तक समय टाल देने के की जरूरत सबसे बड़ी थी। इसलिए म्यूनिल में शान्ति की जाननीत चलाते हुए तथा आष्ट्रिया और चैकोस्लोवाकिया में जर्मनी का बूख बरदास्त करते हुए, ब्रिटेन ने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए तेजी से कदम उठाये और जब सैन्य विशेषज्ञ उसकी युद्ध-सज्जदता के बारे में मुक्तिसमय रूप से सन्तुष्ट हो गये, तभी जर्मनी को यह अन्टीमेम दिया गया कि पोलेण्ड की राख्य-सीमा की अलम्बता के उल्लंघन का अर्थ ब्रिटेन से युद्ध होगा।

सैन्य दृष्टि से जो सम्भव है, वह राजनीतिक दृष्टि से इष्टकर नहीं भी हो सकता। सैन्य उपायों से एक दुबल देश को दबाने का प्रयास करने वाली एक बड़ी शक्ति अन्तर्राष्ट्रीय भावना अपने प्रतिवृत्त कर सकती है और अपने खिलाफ विरोध तक खड़ा कर सकती है। १९४६ में ब्रिटेन और फ्रान्स द्वारा स्वेज नहर वाले भग्ने का उदाहरण दिया जा सकता है।

सरकार के निर्णय को रूप देने में जनमत का भी काफी योगदान होता है। कभी-कभी सैन्य-न्यातेजी के भी ऊपर राजनीतिक बातों को ज्यादा महत्व देना पड़ जाता है। उदाहरण के लिए अबूधर, १९४७ में एक बार कश्मीर के भारत में सम्मिलित हो जाने के बाद, फिर भारी सैन्य खतरे के बावजूद, भारत का जनमत कश्मीर में सेना भेजे बिना और किसी बात से घान्त न होया। साथ ही कोई भी उत्तरदायी सरकार केवल जनमत की बाध में नहीं बह जाना चाहेगी, जो हमें सा पूरी तरह से घटनाओं की पृष्ठभूमि और उनके आवेपनों के बारे में उतना जानकार नहीं हो सकता जितनी कि सरकार हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में स्वयं राज्य के हित में जनमत को ही अधिभावो तत्व नहीं माना जा सकता। ये सब बातें केवल यहो सिद्ध करती है कि विदेश-नीति और रक्षा-नीति का चौली-सामन का साथ होता है। रक्षा और विदेश मन्त्रालयों को, मन्त्रिमण्डल के सर्वोपरि उत्तरदायित्व के अधीन रहने हुए, पूरे-पूरे सहयोग और सहकार के साथ काम करना चाहिये।

उपर का विस्लेषण शान्तिवालीन हालत के सन्दर्भ में है, जब कि दीर्घकालीन नीति शान्तिपूर्वक बनायी जा सकती है। आपानकाल में तो कोई भारी महत्व के निर्णय तभी प्रभावी होंगे, जब पूरी तेजी के साथ ही निर्णय लिये जायेंगे। कहने का तात्पर्य यह नहीं कि विभिन्न दृष्टियों में स्थिति की समीक्षा लिये बिना जन्दराजी में निर्णय कर लिये जायें। एक बात तो

स्पष्ट है ही कि ज्यादा संख्या में सहाय्य भेजने वाली करने का मतलब होगा कि करदाता में ज्यादा पैसा इकट्ठा किया जाय। यह चिन्तन-मन्त्री की जिम्मेवारी है। मित्र व्यवस्था बनाये रखना और बाह्य धातुमण की आसक्ति के समय राष्ट्र के मनोबल को परिरक्षित रखने का भी बड़ा महत्व है और यह गृह-मन्त्री का काम है। आपात में बड़े पैमाने पर सेनाओं का गमनागमन जरूरी हो जाने पर परिचर्य और रेलवे के भारमाधक मन्त्री को भी तैयार करना होगा। इसके अलावा रक्षा-भेनाओं के क्रियाकलाप का कई अन्य दोनो जंमे लाद्य-भूति, वस्त्र आदि पर भी असर पड़ता है। जब युद्ध वस्तुतः छिड़ जाता है, तो देश के सारे साधनों को संगठित करना होता है। ऐसे आपात में निर्णय लेने वाले अन्तिम प्राधिकार में जितने कम लोग होंगे ( निश्चय ही ससद के प्रति अन्तिम रूप में उत्तरदायी होने हुए ) उतना ही ज्यादा तेजी से ये निर्णय लिये जा सकेंगे। जब घटनाएं तेजी से चलने लगती हैं, तो दिनन्दिन विकासो और तत्काल करणीय कारंवाई पर विचार करने के लिए पूरे मन्त्रिमण्डल की बैठकें बुलाना सम्भव नहीं भी हो सकता। पाय हो प्रतिकूल चलने दूरगामी होते हैं कि उन पर अकेले रक्षा-मन्त्री को, अपने साधियों से परामर्श लिये बिना, फैसला करना उसकी क्षमता में परे होगा।

### मन्त्रिमण्डल की रक्षा-समिति

अगस्त-सितम्बर, १९४७ में भारत को ऐसी ही आपात-स्थिति का सामना करना पड़ा। उस समय एक उच्चतर रक्षा-निगमन-तन्त्र की आवश्यकता समझी गयी जो सरकार की ओर से निर्णय करने के लिए सज्ज हो। ३० सितम्बर, १९४७ को यह निर्णय किया गया कि मन्त्रिमण्डल की एक रक्षा-समिति बनायी जायेगी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमन्त्री होंगे ( जो विदेश मंत्री भी थे ) और उपाध्यक्ष उप-प्रधान-मन्त्री ( जो गृह-मन्त्री, राज्य-विपयक-मन्त्री और सूचना-प्रसारण-मन्त्री भी थे ) होंगे, वित्त-मन्त्री और रक्षा-मन्त्री उनके सदस्य होंगे। दूसरे मन्त्रियों को भी जरूरत पड़ने पर सहयोगित कर लिया जाता था। यह समिति एक आपात में बनाया गयी थी, पर इसका मतलब यह नहीं कि ऐसी समिति केवल संकट-काल में ही जरूरी है। निर्णयो में क्षिप्रता और उच्चस्तर पर समन्वय की दृष्टि से ऐन प्राधिकार की जरूरत हर समय बनी रहेगी।

वस्तुतः जब १९४६ में अन्तरिम मन्त्रिमण्डल बना था, तो उसी समय मन्त्रिमण्डल की रक्षा-समिति बनाने का प्रस्ताव उठा था, पर मुखतिम सींग के प्रतिनिधियों द्वारा केनाये गये इस विभ्रम के फलस्वरूप कि अन्तरिम सरकार में संयुक्त उत्तरदायित्व जैसी कोई चीज नहीं है, प्रस्ताव को अगे न बढ़ाया गया। ताई माउटबेटन ने सितम्बर, १९४७ में यह गुभाव फिर से दिया और इसके थ्योर साई इसमें ने तैयार किये जो उस समय मन्त्र-जनरल के स्टाफ प्रमुख थे। साई इंगने को इंगनेण्ड के मन्त्रिमण्डल की रक्षा-समिति के सचिव के रूप में युद्धकाल का काफ़ी अनुभव था और बसा सुविदित है इस समिति ने बड़ी सक्षमता से काम किया था। लेकिन भारत की मन्त्रिमण्डल-रक्षा-समिति इंगनेण्ड की समिति का अनुकरण मात्र न थी। एने भारत की समिति ने अनुगार अनुकूलित किया गया था ( दूसरे देशों में उच्चतर रक्षा

नियन्त्रण के लिए जो तन्त्र है, उसका मशिन लेना-डोना हम जय्याय के जन्त में दिया गया है ।

मन्त्रि-मण्डल की रक्षा-समिति मन्त्रि-मण्डल की जार में दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों ही प्रकार की रक्षा-नीतियों का निर्माण करती है और बड़ा बावश्यक समझती है, प्रति-वेदन मन्त्रि-मण्डल को भेज देती है । व्यवहार में मन्त्रि-मण्डल की रक्षा-समिति सभी प्रयोजनों में रक्षा के सम्बन्ध में सरकार का काम निभाती है । तीनों मंत्राओं के प्रमुख समिति की सभी बैठकों में उपस्थित रहते हैं, ताकि चर्चा के समय उठते वाली विभिन्न बातों के बारे में ठोकाव देकर सत्य दृष्टि में परिचय और स्पष्टीकरण दे सकें । साथ ही रक्षा-मन्त्रालय के मुख्य और विनीय सहायकार ( रक्षा ) भी उपस्थित रहते हैं, ताकि प्रशासनिक या वित्तीय दृष्टिकोण में किसी भी बात का स्पष्टीकरण दे सकें ।

रक्षा-समिति की रचना में समय-समय पर कुछ परिवर्तन होते रहे हैं ।

चलते-चलते यह भी बता दिया जान कि यहाँ एकमात्र मन्त्रि-मण्डलीय उपसमिति नहीं है । कुछ और उपसमितियाँ काय को ज्यादा नुबिसा में निपटाने के लिए बनायी गयी हैं, जैसे आर्थिक समिति, विदेश समिति, आदि ।

### रक्षा-मन्त्री की समिति

अन्तरिम सरकार बनते समय रक्षा मन्त्रालय की जो समिति बनायी गयी थी, वह सत्ता-हत्यान्तरा के बाद रक्षा-मन्त्री की समिति बन गयी । रचना में थोड़े से परिवर्तन के बाद इसे मन्त्रि-मण्डल की रक्षा-समिति की योजना के साथ जोड़ दिया गया । पहले केवल वमाहर-दल-चीफ ही रक्षा-मन्त्री की समिति के सदस्य थे, अब तीनों ही मंत्राओं के प्रमुख रक्षा-मन्त्री की समिति के सदस्य बन गये हैं । इस तरह समिति की रचना जब इस तरह है ( रक्षा-मन्त्री ( अध्यक्ष ), तीनों मंत्राओं के प्रमुख, रक्षा-सचिव और विनीय सहायकार । समिति मन्त्रिमण्डल की रक्षा समिति के समस्त रक्षा सम्बन्धी मामलों में ऐसी आयोजनार्थ और कागज पत्र भेजती रहती है, जिन पर मन्त्रि-मण्डल का अनुमोदन अपेक्षित होता है । समिति साथ ही या तीनों मंत्राओं में सुपुन रूप से सम्बद्ध उन सभी महत्वपूर्ण मामलों का निर्णय करती रहती है, जो इनमें महत्व के नहीं होते कि मन्त्रि-मण्डल की रक्षा-समिति के पास भजना जरूरी हों ।

१९४८ में रक्षा-सचिव की अवयव-वर्ग समितियों नीतिना, चरनेना और वायुसेना के के लिए बनायी गयी । इन सभी समितियों का अध्यक्ष रक्षा-सचिव है और सम्बन्धित मन्त्रा-प्रमुख, विनीय सहायकार और मन्त्रालय के सम्बन्धित मन्त्र-सचिव इनके सदस्य होते हैं । ये समितियाँ सम्बन्धित सत्ता विषयक प्रशासनिक और नीति व प्रश्नों पर विचार करती हैं । फिर जुलाई, १९४९ में यह तय किया गया कि इन समितियों की नेता, नीतिना और वायुसेना सम्बन्धी रक्षा-मन्त्री की समितियों में वदन दिया जाय और रक्षा-मन्त्री इसके अध्यक्ष हों और सम्बन्धित मन्त्रा के प्रमुख, रक्षा-सचिव और विनीय सहायकार उनके सदस्य ।

नये शीघ्र में दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण समिति स्टार प्रमुखों की समिति थी, जिसमें तीनों मंत्राओं के प्रमुख हैं । स्टार-प्रमुख प्रासूटिक रूप में सरकार के ध्यायमायित सैन्य सहायकार

है। वे मैन्य आयोजनायें तैयार करने और सामान्य सरकार की रक्षा सम्बन्धी समस्याओं पर सलाह देने के लिए उत्तरदायी हैं। मुद्रास्वयं में वे सरकार के नियन्त्रण के अर्थात् संयन्त्र-समिति के निदेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। रक्षा-मन्त्र में इस समिति का महत्व निर्विवाद है। तीनो मेनाओं के बीच समन्वय के एक महत्वपूर्ण सूत्र की श्रुति का निभाने के अलावा, संयन्त्र समस्याओं के बारे में स्टाफ प्रमुख मार्माहिक रूप में उच्चतम व्यावसायिक सलाह देने हैं और ऐसा करने में अन्त-संस्था-महकार की समस्याओं का पूरा ध्यान रखने हैं। वही सरकार के आदेश सन्निध कमांडरो तक पहुँचाने के माध्यम भी होते हैं। स्टाफ प्रमुख समिति को हैसियत में तीनो मेनाओं के प्रमुख मैन्य आयोजन बनाने और फिर सरकार द्वारा अनुमोदित रूप में उसे कार्यान्वित करने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। प्रत्येक मेना का प्रमुख मन्त्रानय को अपनी मेना के बारे में व्यावसायिक सलाह देने के लिए और फिर सरकार के आदेशानुसार उसे प्रेषित करने के लिए व्यक्ति जिम्मेदार होता है। भारत में स्टाफ प्रमुख समिति का कोई अनग अघ्यश नहीं होता। जो सदस्य समिति में सत्रने पुराना होता है, वही अघ्यश होता है।

रक्षा-मन्त्री की समिति और स्टाफ-प्रमुख-समिति के अर्थात् नीचे लिखी विशेष समितियाँ भी दिसम्बर, १९४७ में गठित की गयी थी —

संयुक्त आयोजना-समिति

संयुक्त प्रशासनिक-आयोजना-समिति

संयुक्त जामूचना-समिति

मेना-मन्त्र-समिति ( बाद में १९५७ में इसकी जगह पर संयुक्त मन्त्र-मन्त्र-समिति बनाई गयी )

प्रमुख कार्मिक-अधिकारी-समिति

प्रमुख पूँति-अधिकारी-समिति

नये शास्त्रात्मक और नये उपकरण के उत्पादन और पूँति सम्बन्धी समिति ।

बाद में ऐसी ही और भी समितियाँ बनायी गयीं, नामां विविध-मेना-मन्त्र-मन्त्र-समिति ( अगस्त, १९४८ ), संयुक्त पशुपालन-समिति ( सितम्बर, १९४८ ) संयुक्त समुद्र वायुयुद्ध-समिति ( जनवरी, १९४९ ) और अन्त-मेना-उत्पन्न-नीति-समिति ( जून, १९६० )। इन समितियों के नामों द्वारा स्पष्ट रूप में उनके कृत्यों की भी भाँकी मिल जाती है। वे सभी अपने स्वयं में अन्त-मेना हैं, नानि उनकी विचारियों के पीछे तीनो मेनाओं के दृष्टिकोण का बल रहे।

इन सभी समितियों के सचिवालय कार्य की व्यवस्था ( संयुक्त मन्त्र-मन्त्र-मन्त्र-समिति, विविध-मेना-मन्त्र-मन्त्र-समिति और १९६२ में संयुक्त जामूचना-समिति को छोड़कर ) मन्त्रि-मन्त्र-सचिवालय द्वारा की जाती है, जिसमें इस उद्देश्य में अक्टूबर, १९४७ में एक अनग मैन्य स्थापित बनाया गया था। इस स्थापना का भारतीय मन्त्रि-मन्त्र का उन्मूलन ( मेन्य ) है और वह मिनेटियर के पद ( या समरज, क्योंकि इस पद पर तीनो मेनाओं के लोग ब्रम में रहते हैं ) का होता है और वह मन्त्रि-मन्त्र सचिव के प्रशासनिक नियन्त्रण में

रहता है। इस व्यवस्था में समन्वय ज्यादा अच्छा रहता है। फिर सैन्य स्तम्भ में सेना के अधिकारियों के रहने से आवश्यक सैन्य-मृच्छ-भूमि की भी व्यवस्था हो सकती है।

रक्षा-विज्ञान नीति बोर्ड और रक्षा-विज्ञान सलाहकार समिति का, जो अगस्त, १९४८ में बने, उत्तरेख वैज्ञानिक अनुसंधान वाले अध्याय में किया गया है।

### अन्त-सेना-निर्माण-अग्रता-समिति

अन्त-सेना-निर्माण-अग्रता-समिति की स्थापना भी जनवरी, १९४७ में की गयी थी, जिसके अध्यक्ष रक्षा-सचिव हैं और तीनो मेनाओं के प्रमुख, वित्तीय सलाहकार और इंजीनियर-इन-चीफ इसके सदस्य हैं। इस समिति का कार्य है कि पंजी व्यव के लिए उपलब्ध रकम तीनों सेनाओं के बीच बाँट देना और तीनों सेनाओं की विभिन्न निर्माण प्रयोजनाओं के सापेक्ष महत्व और अविलम्बनीयता पर विचार करना और इस क्रम में अग्रताएँ निर्धारित कर देना कि सीमित इंजीनियरी ससाधन पूर्णतः लाभप्रद रूप में प्रयुक्त किये जा सकें।

इन विभिन्न समितियों की स्थापना से एक समन्वयकारी अभिकरण के रूप में रक्षा-मन्त्रालय की जिम्मेवारी समाप्त नहीं हो जाती। अन्तः मन्त्रालय ही रक्षा-मन्त्रालय सभी नीति के प्रश्नों पर सरकार के निर्णय प्राप्त करने, उनको तीनों सेनाओं के मुख्यालयों तक पहुँचाने और उनको द्वारा उनकी कार्यविधि की जाँच रखने के लिए जिम्मेवार है। उपयुक्त मामले में यह सन्दर्भों को स्टाफ प्रमुखों की समिति या सम्बन्धित मन्त्रालय अन्त-सेना समिति के पास भेज देता है, जब कि कभी तीनों सेनाओं की समन्वित राय अपेक्षित होती है। मन्त्रालय में रक्षा-मन्त्री की समिति या मन्त्रि-मण्डल की रक्षा-समिति सम्बन्धी कागज-पत्र हर मामले के स्वरूप के अनुसार तैयार कराये जाते हैं। सेना-मुख्यालय अपने कागज-पत्र सीधे रक्षा-मन्त्री की समिति के पास नहीं भेजते। फिर रक्षा-मन्त्रालय ही मन्त्री के अनुमोदन पर मन्त्रि-मण्डल की रक्षा-समिति के विचारार्थ प्रस्ताव भेज सकता है। सेना मुख्यालय अन्त-सेना प्रकार के अपने आन्तरिक-प्रस्ताव आदेश स्टाफ-प्रमुखों के पास भेजते हैं। जहाँ आवश्यक होता है, स्टाफ प्रमुख अपने प्रस्ताव मन्त्रालय के पास भेज देते हैं।

हालांकि इस बारे में कोई पक्के अनुदेश विद्यमान नहीं है, पर यह माना जाता है कि स्टाफ-प्रमुख मन्त्रि-मण्डल की रक्षा-समिति तक पहुँच सकते हैं। बीच-बीच में प्रधान मन्त्री उनको बुलाते रहते हैं, जब उस सेना के सामान्य हित के मामले पर चर्चा की जानी है।

रक्षा-मुख्यालय में विभिन्न समितियों की स्थापना ने कार्य को ज्यादा तेजी से निपटाने में काफी सहायता दी है। उनकी उपयोगिता स्वभावतः इस बात पर निर्भर है कि इस बात को सही-भरोसे तरह से समझ लिया जाय कि किस प्रकार के मामले और किस प्रक्रम में उसके पास भेजे जायें। समितियों का धमिदाय यह नहीं कि वे फाइलों पर चर्चा का स्थान ले लें, बल्कि वे इसलिये सही की गयी हैं कि अनावश्यक रूप से इस तरह समय बरबाद न किया जाय, वे इसलिये हैं कि लालफीताशाही कम-से-कम रहे और काम का निपटान तेजी में और सन्तोदमकर रूप में किया जाय। साथ ही रक्षा-मन्त्रालय, वित्त-मन्त्रालय (रक्षा) और तीनों सेना-मुख्यालयों के अधिकारियों के बीच विभिन्न स्तरों पर जो सम्पर्क इस तरह स्थापित हो जाते हैं, उन्होंने एक

दूमरे की भूमिका और सम्स्याओं को ज्यादा अच्छी तरह से समझने और परस्पर गुनाहना की भावना से विभिन्न दृष्टिकोणों को देखने में बहुत मदद दी है। सिंहावलोकन के रूप में यह कहा जा सकता है कि समिति प्रणाली के सन्तोषप्रद कार्यकरण के अभाव में इस बहुत सारे काम का मुकाबला करना सम्भव न होता, जो सत्ता-हस्तांतरण के बाद सभी सम्बन्धित लोगों के ऊपर आकर पड़ गया। १९४७ में उच्चतर-रक्षा नियन्त्रण-मन्त्र का गठन समूह रूप में जारुख-६ में किया गया है।

मिनम्बर, १९५६ में रक्षा-मन्त्री की समिति को दो हिस्सों में बांट दिया गया। रक्षा-मन्त्री की अन्त-मेना-समिति (क) और (जन्त-मेना) समिति (ख)। रक्षा-मन्त्री की समिति (ग) की स्थापना मिनम्बर, १९६० में की गयी। रक्षा-मन्त्री इन समितियों के अध्यक्ष हैं और इनके अलावा इनमें से प्रत्येक में रक्षा-उत्पादन-मन्त्री, रक्षा-उप-मन्त्री, रक्षा-सचिव, तीनों सेना प्रमुख और वित्तीय सलाहकार (रक्षा) होते हैं। रक्षा-मन्त्री की अन्त-मेना-समिति (क) रक्षा विषयों सम्बन्धी आयोजनाओं और कार्यक्रमों को निपटानी है (कल्याण, छावनी और निर्माण विषयों को छोड़ कर), समिति उन सभी विषयों पर निर्णय देती है, जो इनके ज्यादा महत्व के नहीं होते कि उनको मन्त्रि-मण्डल की रक्षा-समिति के पास भेजा जाए और जिन के बारे में कार्य-सम्बन्धी नियमों के द्वारा ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती। अन्त-मेना-समिति (ख) सेना कार्यक्रमों की कल्याण समस्याओं, भूमि और छावनियाँ, और विभिन्न कल्याण निधियों के नियन्त्रण और प्रबन्ध सम्बन्धी सभी नीति के प्रश्नों का निर्णय करती है। अन्त-मेना-समिति (घ) तीनों सेनाओं सम्बन्धी निर्माण-कार्यों और निर्माण सम्बन्धी मामलों को निपटाती है। वैज्ञानिक सलाहकार को १९६३ में इन समितियों का सदस्य बनाया गया।

रक्षा-मन्त्री की मेना-समिति, नौसेना-समिति और वायुसेना-समिति सेना-विशेष सम्बन्धी प्रमुख नीति के ऐसे प्रश्नों पर विचार करती रहती है, जिनका दूसरी सेनाओं से सम्बन्ध नहीं होता। रक्षा-मन्त्री के अलावा रक्षा-उत्पादन-मन्त्री, रक्षा-उप-मन्त्री, रक्षा-सचिव, सम्बन्धित सेना प्रमुख और वित्तीय सलाहकार इन समितियों के सदस्य होते हैं।

उच्चतर-रक्षा-नियन्त्रण-मन्त्र में एक नयी समिति और बनायी गयी है। रक्षा-मन्त्री की उत्पादन-समिति, जिसका सचिवालय कार्य मन्त्रि-मण्डल का सचिवालय (मेन्स क्लक) सहायता है। सितम्बर, १९५५ में एक रक्षा-उत्पादन-बोर्ड भी बनाया गया था, जिनके अलावा रक्षा-उत्पादन-मन्त्री हैं। मार्च, १९५६ में बोर्ड का नाम रक्षा-मन्त्री की (उत्पादन) समिति कर दिया गया। रक्षा-मेनाओं के अनुसन्धान और विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों का समन्वय करने के लिए अक्टूबर, १९६२ में रक्षा-मन्त्री के सभासदत्व में एक अनुसन्धान और विकास परिषद् की स्थापना की गयी। इस समिति और परिषद् की रचना और कार्य रक्षा-उद्योग और वैज्ञानिक अनुसन्धान बाने अध्याय में दिये गये हैं।

अप्रैल, १९६२ में अन्त-मेना-समिति की धोरणा के बाद रक्षा समेत जागतिक सम्बन्धित सभी मामलों पर निर्णय मन्त्रि-मण्डल की जागतिक-समिति करती है, जिसकी रचना में समन्वय पर परिचर्चा होते रहे हैं। लेकिन हमेशा ही इस समिति में प्रधान मन्त्री, रक्षा-मन्त्री,

आर्येण-६

**सुच्यते-रथा-नियन्त्रण**

मन्त्रि-मण्डल को रक्षा-मिति

रक्षा-मन्त्री

रक्षा-मन्त्रो को समिति

रसा-मन्त्री को यलसेना/  
नौसेना/वायुसेना समिति

रक्षा-मन्त्रालय

स्टाफ-प्रमुखों को समिति

अन्त-सेना-निर्मण-अप्रत्या-सन्निधि

```

graph TD
    A[विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग] --> B[उच्च शिक्षण]
    A --> C[स्कूल शिक्षण]
    A --> D[तकनीकी शिक्षण]
    B --> B1[यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन]
    B --> B2[एल आई सी टी ई]
    B --> B3[सेण्ट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन]
    C --> C1[नॅशनल काउन्सिल एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग]
    C --> C2[सेण्ट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन]
    C --> C3[नॅशनल इंस्टीट्यूट एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन]
    D --> D1[एल आई सी टी ई]
    D --> D2[सेण्ट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन]
    D --> D3[नॅशनल इंस्टीट्यूट एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन]
  
```

विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग

- उच्च शिक्षण
  - यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन
  - एल आई सी टी ई
  - सेण्ट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन
- स्कूल शिक्षण
  - नॅशनल काउन्सिल एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग
  - सेण्ट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन
  - नॅशनल इंस्टीट्यूट एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन
- तकनीकी शिक्षण
  - एल आई सी टी ई
  - सेण्ट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन
  - नॅशनल इंस्टीट्यूट एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन

नये शस्त्रान्त्र  
और नये  
उपकरणों के  
उत्पादन और  
पूर्ति सम्बन्धी  
समिति

चिकित्सा  
सेवा  
समिति

प्रधान  
कार्यकारी  
अधिकारी  
समिति

प्रधान  
पूति-  
अधिकारी  
समिति

सेना-पुण्यालय  
(सेना-प्रमुख)

नौसेना-  
मुरयालय

वायुसेना-  
मुद्र्यालय  
(वायुसेना-प्रमुख)

—सना  
गठन

समुक्त आयोजना-  
समिति

आयोजना-समिति

संयुक्त आभूषणा-  
समिति

—  
सयुक्त-  
प्रशिक्षण-  
समिति

इस बारे में वैद्यन ज्यादा महत्वपूर्ण समितियाँ शामिल की गई है ।



गृह-मन्त्री, वित्त-मन्त्री और विदेश-मन्त्री (इस विभाग में अलग मन्त्री नियुक्त होने के बाद में) रहे हैं। सचिवों की भी एक आपात-समिति बनायी गयी है, जिसके अध्यक्ष मन्त्रि-मण्डल-सचिव हैं, तथा अन्य लोगों के माय-माय रक्षा-सचिव, गृह-सचिव, विदेश-सचिव और वित्त-सचिव इसके सदस्य हैं। यह समिति या तो अन्तिम निर्णय करती है अथवा नीति के ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अपनी सिफारिशें मन्त्रि-मण्डल की आपात-समिति के पास भेज देती है।

स्वयं रक्षा-मन्त्रालय में रक्षा-मन्त्री रोज-रोज के महत्वपूर्ण विकासों की चर्चा करने के लिए हर रोज (जिन दिनों वह बाहर होते हैं, उनको छोड़ कर) दोनों मेन्स-प्रमुखों, मन्त्रि-मण्डल-सचिव, रक्षा-सचिव, रक्षा-उत्पादन-विभाग के सचिव और रक्षा-अतिरिक्त-सचिव की बैठक बुलाते हैं।

नवम्बर, १९६२ में (प्रधान मन्त्री की अध्यक्षता में) राष्ट्रीय रक्षा-परिषद् बनायी गयी है और मेम्बर-कार्य समिति भी बनायी गयी है (जिसके अध्यक्ष हैं रक्षा-मन्त्री)। ये समय-समय पर बैठती रहती हैं। परिषद् रक्षा सम्बन्धी मामलों की समीक्षा सामान्यतः करती रहती है और समिति में रक्षा के सैन्य पहलुओं पर चर्चा होती है। परिषद् और समिति की बैठकों का मयोजन मन्त्रि-मण्डल सचिवालय करता है।

वहाँ भी होने वाली ऐसी सैन्य घटनाओं और आर्थिक राजनीतिक विकासों का, जिनका देश की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है, निर्धारण समुक्त आसूचना-समिति द्वारा किया जाता है। समिति का अध्यक्ष विदेश-मन्त्रालय का एक समुक्त सचिव होता है और उसमें रक्षा और गृह-मन्त्रालयों के प्रतिनिधि तथा मेन्स, नौसेना और वायुसेना मुख्यालयों के आसूचना-निदेशक होते हैं। यह स्टाफ-प्रमुखों की समिति की एक सहायक समिति थी। १९६५ में इस समिति का पुनर्गठन करके इसे मन्त्रि-मण्डल-सचिवालय के अधीन रखा गया, जहाँ का एक अतिरिक्त सचिव अब इसका अध्यक्ष है। पूर्वकालिक सचिव के अलावा रक्षा और गृह मन्त्रालयों के प्रतिनिधियों का स्तर भी ऊँचा कर दिया गया है। अब समिति आवश्यकता पड़ने पर बैठती है और संकट काल में रोजाना भी इसकी बैठकें होती हैं, ताकि बदलती परिस्थितियों और सम्भाव्य विकासों का परिबोध रखा जा सके।

वर्तमान उच्चतर-रक्षा-नियन्त्रण-तन्त्र की रूपरेखा आरेख-७ में दी गयी है।

## खण्ड—२ अन्य देशों में उच्चतर रक्षा नियन्त्रण

रक्षा-नीति के निर्माण के लिए कुछ दूसरे देशों में विद्यमान तन्त्र की सशिव रूपरेखा जागे दी जा रही है। यह रूपरेखा प्रकाशित अभिलेखों से यथासम्भव एकत्र करके दी जा रही है।

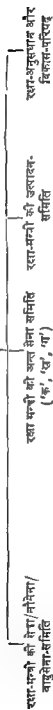
### डगलैंड

इंग्लैंड में अप्रैल, १९६४ से रक्षा के केन्द्रीय संगठन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये। पहले तीनो मेन्सों के लिए एक-एक भार-साधक-मन्त्री होते थे, जिनमें क्रमशः एडमिरल्टी के प्रथम लाई (नौ सेना के लिए), युद्ध के राज्य-सचिव (सैन्य सेना के लिए) तथा वायु के राज्य-

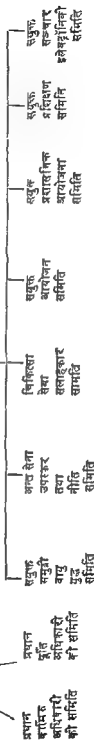
उच्चतर-रक्षा-नियन्त्रण (१९६६)

मन्त्रि-मण्डल

मन्त्रि-मण्डल की रक्षा-समिति



रक्षा प्रमुखों की समिति



सचिव (वायुसेना के लिए) । वे मन्त्रि-मण्डल के सदस्य न थे । नीमेना, यलमेना और वायुसेना के ऊपर कार्यपालक प्राधिकार का प्रयोग एक सेना-प्रमुख द्वारा न किया जाता था, बल्कि सामूहिक रूप में ग्रमस एडमिरल्टी बोर्ड, यलमेना-परिपट्ट और वायुसेना-परिपट्ट द्वारा एडमिरल्टी, युद्ध कार्यालय और वायु मन्त्रालय के जरिये काम करने हुए अवसर किया जाता था । बोर्ड या परिपट्टों का जन्म इंग्लैण्ड में कुछ ऐतिहासिक और राजनीतिक कारणोंसे हुआ था । एडमिरल्टी बोर्ड की रचना १६६० के एडमिरल्टी अधिनियम द्वारा की गयी थी और यलसेना-परिपट्ट की रचना फरवरी, १६०४ में की गयी थी, वायुसेना की स्थापना एक अलग सेना के रूप में होने के समय, इन दोनों निकायों के सादृश्य पर, इसका प्रशासन १६१७ के वायुसेना (गठन) अधिनियम के अधीन, एक वायु-परिपट्ट की स्थापना की गयी । बोर्ड और परिपट्टों की रचना एक जैसी ही थी ।

एडमिरल्टी के प्रथम लार्ड या यलसेना या वायुसेना के सम्बन्धित राज्य सचिव (सेक्रेटरी आफ स्टेट) बोर्ड या परिपट्ट के अध्यक्ष थे, जेप सदस्य थे । ससदीय अवर सचिव (ससद सदस्य), प्रत्येक सेना का प्रधान स्टाफ अधिकारी और प्रत्येक सेना का स्थायी अवर सचिव (एक असेनिक अधिकारी) छ । बोर्ड या परिपट्ट के सभी सदस्य सद्-समान थे, भन्ने ही उनका सैन्य पद या असेनिक हैसियत कुछ भी हो । बोर्ड के भीतर भय पर नियन्त्रण स्थायी अवर सचिव द्वारा किया जाता था, जो राजकोष (वित्त मन्त्रालय) और लोक-सेवा-समिति के प्रति उत्तरदायी था । एडमिरल्टी के प्रथम लार्ड और युद्ध तथा वायु के राज्य-सचिव संसद के प्रति और सम्राट के प्रति अपने-अपने बोर्ड या परिपट्ट के समग्र कार्य-जात के लिए उत्तरदायी थे । वे बोर्ड या परिपट्ट की सलाह की मानने या न मानने के लिए स्वतन्त्र थे ।

तीनों सेनाओं का तीन स्वतंत्र निकायों द्वारा प्रशासन करने के कारण स्वभावतः समन्वय की समस्या उठ खड़ी हुई । अतएव १६४६ में एक रक्षा-मन्त्रालय बनाया गया, जिसके भार-साधक एक रक्षा-मन्त्री थे । उनका काम 'सम्राट की सशस्त्र सेनाओं के सम्बन्ध में समग्र रूप से एक एकीकृत नीति बनाना और उसका सामान्य अनुपालन और सेनाओं की आवश्यकताओं को देखना था ।' राष्ट्रीय रक्षा की उच्चतम जिम्मेवारी प्रधान मन्त्री और मन्त्रि-मण्डल के ऊपर थी । इनके अधीन रहते हुए रक्षा-समस्याओं का निपटान मन्त्रि-मण्डल की ओर से रक्षा-समिति करती थी, जो प्रधान मन्त्री के समामन्त्रित्व में बैठती है । जुलाई, १६५८ में संसद के समक्ष प्रस्तुत किये गये एक पत्र के अनुसार समिति में ये लोग थे : गृह-सचिव, विदेश-मन्त्रि, चांसलर आफ एक्साचेकर, राष्ट्रमण्डल-सचिव, उपनिवेश-सचिव, रक्षा मन्त्री, धर्म और राष्ट्रीय सेवा-मन्त्री एडमिरल्टी के प्रथम लार्ड, युद्ध राज्य-सचिव, वायु राज्य-सचिव और पूर्ति मन्त्री । प्रधान मन्त्री निर्णय करते थे कि इनमें से कौन-कौन से सदस्य समिति की किसी खास बैठक में भाग लें । मन्त्रि-मण्डल और रक्षा समिति के उत्तरदायित्वों के अधीन रहते हुए, रक्षा-मन्त्री को इन बातों के निर्णय का अधिकार था : 'सशस्त्र सेनाओं के आकार, रूप, संगठन और विन्यास और उनके शस्त्रागार, युद्ध सम्बन्धी उपकरण और पूर्ति (रक्षा अनुसन्धान और विकास को शामिल करने हुए) पर प्रभाव डालने वाले रक्षा-नीति सम्बन्धी सभी मामलों ।' नीति के प्रमुख प्रश्नों का निर्णय

जिनसे एडमिरल्टी में एडमिरल्टी सचिव कहते थे ।

करने के लिए और अन्त-सेना-समस्याओं पर चर्चा करने के लिए जुलाई, १७५८ में एक रक्षा-बोर्ड की स्थापना की गयी थी, जिसके अध्यक्ष रक्षा-मन्त्री थे और एडमिरल्टी के प्रथम लाई, युद्ध राज्य-सचिव, वायु राज्य-सचिव, पूर्ति मन्त्री और रक्षा स्टाफ के प्रमुख (एक नया पद), नौसेना स्टाफ प्रमुख, इम्पीरियल जेनरल स्टाफ के प्रमुख, वायु सेना स्टाफ के प्रमुख, रक्षा-मन्त्रालय के स्थायी सचिव, नौ-रक्षा-मन्त्रालय के प्रमुख वैज्ञानिक इसके सदस्य थे। रक्षा-स्टाफ के प्रमुख रक्षा-मन्त्री के प्रति उत्तरदायी थे और वह उनके प्रमुख सैन्य सलाहकार बन गये। स्टाफ प्रमुखों की समिति ने अध्यक्ष और रक्षा-मन्त्री के स्टाफ-प्रमुख के संयुक्त पद समाप्त कर दिये गये।

रक्षा के केन्द्रीय संगठन को सुदृढ़ बनाने के हेतु लिये गये अन्य निर्णय जून, १९६३ में ब्रिटिश संसद में पस्तुत किये गये एक पत्र में दिये गये थे। इनको १, अप्रैल १९६४ में प्रभावी बनाया गया।

अब एक एकीकृत रक्षा-मन्त्रालय है, जिसमें पुराने रक्षा-मन्त्रालय, एडमिरल्टी, युद्ध-कार्यालय और वायु-मन्त्रालय को एक ही रक्षा-राज्य-सचिव के अधीन आत्मसात कर दिया गया है। यह मन्त्रालय सेनाओं की वधन-वद्धताओं, समाधानों और भूमिकाओं के बीच समुचित संतुलन रखा। हालाँकि तीनों सेनायें अलग-अलग हैं, मन्त्रालय के भीतर कार्य का गठन यथा-सम्भव समग्र रक्षा के आधार पर किया जाता है, एक-एक सेना के आधार पर नहीं।

प्रधान मन्त्री और मन्त्रि-मण्डल के उच्चतम प्राधिकार के अधीन रहने लिये रक्षा-नीति के प्रमुख प्रश्नों का निपटारा रक्षा और समुद्रपार नीति सम्बन्धी समिति द्वारा किया जाता है, जिसके अध्यक्ष प्रधान मन्त्री हैं और सामान्यतः ये सदस्य हैं प्रथम राज्य-सचिव, विदेश-सचिव, चांसलर आफ एक्सचेंजर राजकोष का प्रमुख सचिव, गृह-सचिव, राष्ट्र-मण्डल सम्बन्धी और उपनिवेशों के राज्य-सचिव और रक्षा के राज्य-सचिव। अन्य मन्त्री यथावश्यक अवसरों पर आमन्त्रित कर लिये जाते हैं। रक्षा-स्टाफ-प्रमुख और स्टाफों के प्रमुख कार्य के स्वरूप के अनुसार उपस्थित रहते हैं। अन्य अधिकारी जैसे स्थायी राज्य अवर सचिव, या रक्षा के राज्य-सचिव के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार यथापेक्षित उपस्थित रहते हैं। रक्षा-स्टाफ-प्रमुख, और स्टाफों के प्रमुखों की प्रधान मन्त्री के पास तक पहुँचने का अधिकार मिला रहता है। उपयुक्त अवसरों पर उनको पूरे मन्त्रि-मण्डल की बैठकों में भी बुलाया जाता है।

एडमिरल्टी के प्रथम लाई और युद्ध तथा वायु के राज्य-सचिवों के दफ्तर और साथ ही एडमिरल्टी बोर्ड, वल सेना परिषद् और वायु सेना परिषद् को खत्म कर दिया गया। इनके स्थान पर रक्षा के तीन मन्त्री हैं। जिनकी मदद के लिए तीन सहायक अवर सचिव हैं और उनका मूल कृत्य राज्य सचिव की ओर से अतिरिक्त सेना के सम्बन्ध में रक्षा (संयुक्त सेवा) दल सेना और राज्य एयर फोर्स, के मन्त्रियों के रूप में नीति का पालन कराना है, हालाँकि उनको रक्षा के पूरे क्षेत्र में उत्तरदायित्वों का प्रत्यायोजन किया जा सकता है।

पहले जो वमान की क्षक्तियाँ और प्रशासनिक नियन्त्रण कार्य एडमिरल्टी बोर्ड और वल सेना और वायु-परिषदों द्वारा किया जाता था, वह अब (१९५८ में बने रक्षा-बोर्ड के स्थान पर बनी) एक रक्षा-परिषद् द्वारा किया जाता है। रक्षा राज्य-सचिव इसमें अध्यक्ष हैं और उनके अलावा ये सदस्य हैं तीनों रक्षा-मन्त्री, रक्षा-स्टाफ के प्रमुख, नौसेना स्टाफ-प्रमुख,

वायु, मेना स्टाफ-प्रमुख, सामान्य रक्षा राज्य-सचिव के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार और स्थायी राज्य-अवर सचिव । उद्घरण-मन्त्री और मोरु-भवन तथा निर्माण-कार्य-मन्त्री उपयुक्त कार्य सामने होने पर चर्चायें उपस्थित होते हैं । परिषद् मुख्यतः रक्षा-नीति का निपटान करती है और प्रवन्ध-कार्य रक्षा-परिषद् के नौसेना, मेना और वायुसेना बोर्डों को प्रत्याबोधित कर दिया जाता है और हर मामले में राज्य-सचिव अध्यक्ष रहते हैं । पहले एडमिरल्टी बोर्ड सेना-परिषद् और वायु-परिषद् के नाम पर जारी किये जाने वाले सभी आदेश अब रक्षा-परिषद् के नाम से जारी किये जाते हैं ।

रक्षा के राज्य-सचिव सामान्यतः उपयुक्त मन्त्री ने कह देते हैं कि उनकी ओर से प्रत्येक बोर्ड की अध्यक्षता करें । बोर्ड के अन्य सदस्य ये हैं—उपयुक्त ससदीय राज्य-अवर-सचिव, स्टाफ-प्रमुख, सम्बन्धित मेना के प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी वरिष्ठ सैन्य और अनैतिक स्टाफ तथा उपयुक्त मुख्य व्यावसायिक या वैज्ञानिक सलाहकार ।

रक्षा-स्टाफ-प्रमुख, नौसेना-स्टाफ-प्रमुख, सामान्य-स्टाफ-प्रमुख और वायुसेना-स्टाफ-प्रमुख की सदस्यता से स्टाफ-प्रमुखों की समिति बनती है । स्थायी जवर-सचिव और मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी समिति को बैठकों में उपस्थित रहते हैं । स्टाफ-प्रमुखों की समिति सामूहिक रूप से नौसेना और रक्षा-सचिवों के बारे में और रक्षा-नीति के सैन्य-आलेखों के बारे में व्यावसायिक सलाह देने के लिए सरकार के प्रति उत्तरदायी हैं । नौसेना, सामान्य और वायुसेना स्टाफों के प्रमुख आनी-आनी सेनाओं के व्यावसायिक प्रमुख बने रहते हैं । जब स्टाफ-प्रमुखों में मतभेद होता है, तो रक्षा-स्टाफ-प्रमुख विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में अपनी सलाह के साथ सरकार के निर्णय के लिए राज्य-सचिव के पास भेज देता है । स्टाफ-प्रमुख रक्षा-स्टाफ-प्रमुख के जरिए सैन्य सत्रियाओं के संचालन के लिए राज्य-सचिव के प्रति जिम्मेवार होते हैं । सत्रिया-आदेश रक्षा-स्टाफ-प्रमुख के नाम से जारी किये जाते हैं, जबकि परिणामी या एफ मेना सम्बन्धी आदेश व्यक्तिगत स्टाफ-प्रमुख के प्राधिकार में जारी किये जाते हैं ।

स्थायी राज्य-अवर-सचिव रक्षा-मन्त्रालय के कार्य में सम्मन्वय के लिए उत्तरदायी हैं ।

रक्षा-मन्त्रालय के प्रत्येक मन्त्री को जमिराब का क्षेत्र-विशेष उसके एक-मेना सम्बन्धी उत्तरदायित्वों के अलावा सौंप दिया जाता है—राज्य उप-सचिव न केवल मेना का मन्त्री होता है, पर साथ ही उसका रक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय नीति के मामलों में विशेष सम्बन्ध भी होता है । रॉयल नेवी के मन्त्री का विशेष सम्बन्ध तीनों सेनाओं के यामिरों और सम्भारिकों में होता है और रॉयल एयर फोर्स मन्त्री का विशेष सम्बन्ध तीनों सेनाओं के अनुचरान, विरास और उत्साहन और सन्तुष्ट रक्षा-वर्ग में होता है । उत्तरदायित्वों का एक अन्तरिम विभाजन है ।

यह पुनर्गठन इंग्लैंड के जाने को भारत के निष्कर्ष सा देता है, जहाँ आजादी के बाद ने मंडेर एफ एकीकृत रक्षा-मन्त्रालय हमें पता चला है, जिसकी जिम्मेवारी में तीनों सेनाओं रही है ।

इंग्लैंड में दानि कात में मन्द की सम्मति के बिना कोई स्थायी मेना नहीं रखी जा सकती । इसका उद्देश्य १९५८ के अधिहार विधेयक में देखा जा सकता है और तब ने सरकार एक वारिष्ठ प्रतिनिधिम हर सात मन्त्र-मेना (और स्थापना के बाद ने वायु सेना) के संचारण

के लिए समद में पास करानी रही है। नौसेना के लिए ऐसी मजूरी की जरूरत नहीं है। साथ ही दोनों सेनाओं के सदस्यों की अनुशासन-संहिता, जैसे सेना अधिनियम और वायुसेना अधिनियम, को भी हर साल नवीकृत कराना होता है। इस प्रयोजना में संसद द्वारा हर साल एक सेना और नौसेना (वापिक) अधिनियम पास किया जाता है। यह वापिक अधिनियम यह भी स्पष्ट करता है कि सलसेना और वायुसेना में कितनी सख्या का संग्धारण किया जाना है। फिर भी ये ऐसी परम्पराएँ हैं, जो इंग्लैण्ड की विशेष परिस्थितियों के कारण विकसित हुई हैं। इंग्लैण्ड में वर्तमान संगठन-ढाँचा बताने वाला एक आरेख भी दिया जा रहा है।

### संयुक्त राज्य अमेरिका

संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अनुसार 'अमेरिका के राष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना और नौसेना के कमांडर-इन-चीफ होंगे और अनेक राज्यों की चमू के भी, जब उसे स० रा० अमेरिका की वास्तविक सेवा के लिए लगाया जायेगा।' वायु शक्ति के जन्म के बाद एक व्यवस्था यह भी कर दी गयी है कि सेना और नौसेना दोनों ही आवश्यक विमानों की किसी युद्ध जैसी सज्जिया में काम आने योग्य सज्जाम की तरह रखयी और इस प्रकार स० रा० सेना, वायु, बल और नौसेना का जन्म हुआ। राष्ट्रपति का मन्त्रिमण्डल विभुद्धत एक सलाहकार निकाय होता है और विधान-मण्डल से मुक्त होता है। मन्त्रिमण्डल के सदस्य राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और वे उनके ही प्रति उत्तरदायी होते हैं। सभी कार्यपालक कामों की आपसी जिम्मेवारी राष्ट्रपति की होती है और उसे उसके किसी सलाहकार में ऊपर नहीं डाला जा सकता।

१९४७ के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, १९४७ ने राष्ट्रीय सेन्य स्थापना को जन्म दिया। तत्कालीन युद्ध-विभाग का नया नाम सेना-विभाग रखा गया, जो सेना के सचिव के अधीन था। प्रमदा वायुसेना विभाग और स० रा० वायुसेना की स्थापना, असंग विभाग और सशस्त्र सेना के रूप में, सेना के कुछ कृत्य अलग करके, की गयी। अधिनियम में समन्वित और असेनिक नियन्त्रण में एकीकृत निदेश की व्यवस्था की गयी, जो सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों के लिए थी। उनके स्वातंत्र्य, निदेश और सज्जिया को भी एकीकृत कमान के अधीन लाया गया। इस तरह उनका एकीकरण थल, वायु और नौसेनाओं की एक सक्षम टीम के रूप में किया गया, पर इसके लिए न तो वस्तुतः उनका विलय किया गया और न उनको एक ही रटाफ प्रमुख के अधीन लाया गया। १९४९ के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम ने रक्षा-विभाग की स्थापना की (जो राष्ट्रीय सेन्य स्थापना की जगह बना) और रक्षा-सचिव इसके प्रमुख बनाये गये। सेना, नौसेना और वायुसेना के तीन विभाग प्रत्येक एक-एक सचिव के अधीन, रक्षा-विभाग के सेन्य विभाग बन गये। १९४७ के अधिनियम ने राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सुरक्षा मन्त्रियों धरेलू, विदेशी और सैन्य नीतियों के एकीकरण के बारे में सलाह देने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा-परिषद् बनायी। परिषद् के स्थायी सदस्य हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य-मन्त्रि, रक्षा-सचिव, और आपात आयोजना कार्यालय के निदेशक। राष्ट्रपति अन्य कार्यपालक या सेन्य विभागों के सचिवों और अवर-सचिवों को भी सहयोजित कर सकते हैं, जो उसकी इच्छानुसार रखे या हटाये जा सकते

है। समुक्त स्टाफ-प्रमुखों के अध्यक्ष और केन्द्रीय आभूचना अधिकरण (सी० आई० ए०) के निदेशक परिपद के गतिविधि सहायकार होते हैं। सदस्यता सविहित होती है और मेनेट की मजूरी के बिना उसमें कोई परिवर्तन नहीं किये जा सकते। परिपद का एक असेनिका कार्य-यानक सचिव होता है, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अपनी रचना द्वारा परिपद यह आश्वस्त करती है कि रक्षा और निदेश विभागों के बीच समुचित समन्वय बना रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा-परिपद को तुलना भारतीय मन्त्रि-मण्डल की रक्षा-समिति से की जा सकती है।

रक्षा-सचिव की, जो भारत के रक्षा-मन्त्री का सहायी होता है, नियुक्ति पहले पहल १९४७ में की गयी। वह सेना, नौसेना और वायुसेना के तीनों विभागों का सर्वोपरि भार-मायक होता है। वह रक्षा विभाग सम्बन्धी सभी मामलों में राष्ट्रपति का प्रधान सहायक होता है। रक्षा-मन्त्रि की नियुक्ति राष्ट्रपति असेनिका क्षेत्र में से चुन कर करते हैं। चुना गया व्यक्ति ऐसा गृही होना चाहिये जिसने पिछले दस साल के भीतर सशस्त्र सेनाओं में सेवा की हो। रक्षा-मन्त्रि के कृत्य सामान्य नीतियों और राज्य-स्वचित्त करना, रक्षा-विभाग के ऊपर सामान्य प्रारिभार और नियन्त्रण रखना, तीनों सेनाओं के बीच समन्वय आश्वस्त करना, बजट तैयार करना आदि होते हैं। एक-एक सचिव के अधीन तीन सेवा-विभाग भी होते हैं, नामतः सेना-विभाग, नौसेना-विभाग और वायुसेना-विभाग। सचिव उपयुक्त स्टाफ-प्रमुख के साथ सीधे काम करता है, जो सम्बन्धित सेना के प्रमुख होते हैं। सेना, नौसेना और वायुसेना के सचिव सीधे राष्ट्रपति तक पहुँच सकते हैं।

रक्षा-मन्त्रि की सहायता, उसके बहुविध कर्तव्यों के पालन में, साध-साध इनके द्वारा भी की जाती है (एक) समुक्त स्टाफ प्रमुख, (दो) सशस्त्र सेना नीति-परिपद, (तीन) उच्च अनुसन्धान प्रयोजना अभिकरण, (चार) सशस्त्र पद्धति मूल्यांकन समूह और (पाँच) तीनों सेना-विभाग। रक्षा-विभाग में आठ सहायक सचिव हैं। इनमें से सात राष्ट्रपति द्वारा असेनिका क्षेत्र में से नियुक्त किये जाते हैं। केवल रक्षा-सहायक-सचिव (नियन्त्रक), जो बजट और वित्तीय नियन्त्रण के लिए जिम्मेदार है, एक स्थायी असेनिका कर्मचारी होता है।

समुक्त स्टाफ-प्रमुख में से शामिल होते हैं अध्यक्ष और सेना स्टाफ-प्रमुख नौ-मरिया प्रमुख और वायुसेना स्टाफ प्रमुख। पिछले तीन तीनों सेनाओं के व्यावसायिक प्रमुख होते हैं। समुक्त स्टाफ-प्रमुख के अध्यक्ष की नियुक्ति सीनेट की सलाह और राष्ट्रपति से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और दस पद पर आखीर रहते हुए उसे सशस्त्र सेनाओं के सभी अधिकारियों से अधिक गरिष्ठता प्राप्त होती है। भारत में इसका सहायी कोई पद नहीं है। संयुक्त-स्टाफ-प्रमुख राष्ट्रपति, राष्ट्रीय सुरक्षा-परिपद और रक्षा-सचिव के प्रधान सैन्य सलाहकार होते हैं। वे स्थानिक-आयोजना बनाने हैं और सैन्य बलों के स्थानिक निदेश की व्यवस्था करने हैं।

सशस्त्र सेना-नीति-परिपद का काम सशस्त्र सेनाओं सम्बन्धी स्थूल नीतियों के बारे में रक्षा-मन्त्रि की सलाह देना है। इसमें से होते हैं रक्षा-सचिव (अध्यक्ष), रक्षा-उप-सचिव, सेना, नौसेना और वायुसेना के सचिव, रक्षा अनुसन्धान और इंजीनियरी के निदेशक (जो भारत में रक्षा-मन्त्रालय वैज्ञानिक सलाहकार का सहायी होता है), संयुक्त-स्टाफ प्रमुखों के

के सामान्य स्टाफ-प्रमुख के साथ सामूहिक-रूप से स्टाफ-प्रमुखों की समिति बनाते हैं, जिसके अध्यक्ष सेनाओं के मन्त्री हैं। इन समितियों की रचना और कृत्य आज्ञासि द्वारा स्थापित किये जाते हैं।

- (ग) बलसेना, नौसेना और वायुसेना में प्रत्येक के लिए सामान्य निरोधनायक।
- (घ) सचिव, सामान्य प्रशासन, जो प्रशासनिक और वित्तीय मामलों के प्रभारी है, यथा
- (ङ) सेनाओं के स्टाफ-प्रमुख, जो सेनाओं के सामान्य संगठन और विकास की आयोजनाएँ बनाने, संस्कारण और सम्मार्जिकी समर्थन कार्यक्रम तैयार करने, अन्त-सेना उच्चतर सैन्य-शिक्षण का नियन्त्रण, अन्त-सेना पदों पर नामनों सम्बन्धी सिफारिशें करने के लिए उत्तरदायी है।

इसके अलावा तीनों सेनाओं की बरिष्ठ परिपदे हैं। ये सेनाओं के मन्त्रियों को प्रत्येक सेना के ऊपर व्यक्तिगत प्रभाव डालने वाले सामान्य विषयों पर सलाह देती हैं। इसके अलावा 'उच्च रक्षा-शिक्षण सम्बन्धी अनुस्थापन और परिपूर्णकरण की समिति' भी है, जो सेनाओं के मन्त्रियों को राष्ट्रीय रक्षा, उच्च अध्ययन-संस्थान के कार्यक्रमों और रीतियों के सम्बन्ध में सलाह देती है। इस समिति में सेनाओं के स्टाफ-प्रमुखों के प्रतिनिधि, उच्च अध्ययन-संस्थान के निदेशक, वैज्ञानिक कार्य सम्बन्धी समिति के अध्यक्ष, विदेश, गृह, वित्त और आर्थिक कार्य, राष्ट्रीय शिक्षा, लोक निर्माण और परिवहन और उद्योग मन्त्रालय (रक्षा के पहलुओं के सम्बन्ध में), बरिष्ठ सैन्य-शिक्षा के निदेशक, सेनाओं के मन्त्रियों द्वारा चुने गये तीन जनरल और उपरकर उत्पादिता आयोजना के जनरल कमिसरो होते हैं। फ्रांस में उच्चतर रक्षा-नियन्त्रण का ढाँचा साथ के आरेख में दिया जा रहा है।

### कनाडा

दूसरे संघीय सचिवालयों की तरह राज्य के प्रमुख अर्थात् गवर्नर जनरल संसद सेनाओं के उच्चतम कमानधारी है। राष्ट्रीय रक्षा-अधिनियम, १९२२ में एक रक्षा-मन्त्री की नियुक्ति की व्यवस्था है, जिसे रक्षा सम्बन्धी सभी मामलों का पूरा-पूरा उत्तरदायित्व सौंपा गया है। तीनों सेनाओं के भारसायक तीन अलग मन्त्रियों की कोई व्यवस्था नहीं है, हालाँकि सपरिपद गवर्नर जनरल द्वारा एक उप मन्त्री और एक राष्ट्रीय रक्षा-सह मन्त्री नियुक्त किया जा सकता है। तीनों सेनाओं का समन्वय रक्षा-मन्त्री के अधीन राष्ट्रीय रक्षा-विभाग में किया जाता है। रक्षा-मन्त्री की निदेशकता में सेनाओं की कमान तीन सम्बन्धित सेना प्रमुखों के हाथ में रहती है। तीनों सेनाओं के लिए एक कमांडर-इन-चीफ भी है। प्रत्येक सेना का स्टाफ-प्रमुख उस सेना का प्रधान माना जाता है।

मन्त्रिमण्डल के सर्वोपरि प्राधिकार के अधीन रहने हुये, जिसे नीति के प्रमुख प्रश्न सौंपे जाते हैं, रक्षा सम्बन्धी छेप मद्दतपूर्ण प्रश्नों पर एक मन्त्रिमण्डल रक्षा-समिति द्वारा नियन्त्रण किया जाता है, जिसके अध्यक्ष प्रधान मन्त्री होते हैं, राष्ट्रीय रक्षा-मन्त्री उपाध्यक्ष और ये सदस्य होते हैं विदेश राज्य-सचिव, वित्त-मन्त्री, रक्षा-उत्पादन-मन्त्री, न्याय-मन्त्री,



राष्ट्रीय स्वास्थ्य और वन्याप-मन्त्री और राष्ट्रीय रक्षा के महामन्त्री। स्टाफ-प्रमुखा की समिति के अध्यक्ष, नौसेना स्टाफ-प्रमुख, सामान्य स्टाफ प्रमुख, वायुसेना स्टाफ-प्रमुख और अध्यक्ष, रक्षा-अनुसन्धान-बोर्ड भी उपस्थित रहते हैं।

स्टाफ-प्रमुखा की समिति राष्ट्रीय रक्षा-अधिनियम, १९५० के अनुसार सविहित रूप में बनायी गयी है। समिति में स्टाफ-प्रमुखों के अध्यक्ष, तीनों सेना-प्रमुख और रक्षा-अनुसन्धान-बोर्ड के अध्यक्ष रहते हैं। राष्ट्रीय रक्षा-उपमन्त्री भी मामान्यतः उपस्थित रहते हैं। वनाडा-मन्त्रि मण्डल के मन्त्रि, डिफेंस-राउंड-अवर-मन्त्रि और अन्य अवैयक्तिक अधिकारी भी नियमन पर उपस्थित रहते हैं। समिति के कृत्य यथासामान्य प्रकार के होते हैं।

समन्वय करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा-विभाग ने कुछ और अन्य-सेना-समितियाँ बनायी हैं, जैसे वार्षिक सदस्य-समिति, प्रधान प्रति-अधिकारी-समिति आदि जिनके नाम स्पून-रूप से उनके कृत्यों का संकेत करते हैं। साथ ही एक रक्षा-अनुसन्धान-बोर्ड भी है, जिसका कार्य राष्ट्रीय रक्षा को प्रभावित करने वाले वैज्ञानिक अनुसन्धान सम्बन्धी सभी मामलों में मन्त्री को सलाह देना है। यह एक उच्चाधिकार प्राप्त विभाग है, जिसमें भारत की तरह अन्य लोगों के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख भी होते हैं।

इस तरह भारत की भाँति वनाडा में भी तीनों सेनाओं को यथासम्भव अधिकतम सीमा तक एकत्र कर दिया गया है। तीन अलग-अलग सेना मुख्यालय भी हैं और रक्षा-मन्त्रालय तीनों सेनाओं के कार्य का समन्वय करता है। फिर मन्त्रालय में काम सेना-वार विभिन्न अनुभागों द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि कृत्य-आधार पर किया जाता है। इस तरह कार्मिक मामलों का निपटारा करने वाला एक अधिकारी तीनों सेनाओं पर पड़ने वाले उसके प्रभाव की दृष्टि से उन निपटावेगा, केवल एक सेना के नहीं।

भारत में भी तीनों सेनाओं के लिए अलग-अलग मन्त्री नहीं हैं। मन्त्री और उन-मन्त्री पूरी रक्षा-सेनाओं के प्रयोग में काम करते हैं। फिर भारत के रक्षा-मन्त्रालय में ऐसे अनेक अनुभाग हैं, जो अलग-सेना-आधार पर समस्याओं को निपटारते हैं।

## आस्ट्रेलिया

भारत की तरह आस्ट्रेलिया में भी मशहूर सेनाओं का उच्चतम कमान राज्य के प्रमुख में निहित है। दूसरे शिबबुद्ध में पहले रक्षा-नियन्त्रण एकात्मक प्रकार का था, अर्थात् एक ही रक्षा-विभाग तीनों सेनाओं को प्रशासित करता था। १९३६ में, रक्षा-सेनाओं में काफी विस्तार के बाद, तीनों सेनाओं के लिए तीन अलग-अलग विभाग स्वतन्त्र मन्त्रियों के अधीन बनाये गये। पुनर्गठित रक्षा-विभाग ने हाल में रक्षा-मन्त्री के अधीन सर्वोपयोग रक्षा नीति सम्बन्धी उत्तर-दायित्व बना रखा। यह तीनों सेनाओं और सेना मन्त्रालयों के बीच समन्वय भी करता रहा और साथ ही रक्षा-परिषद् का सचिवालय-कार्य भी इनके पास रहा। आस्ट्रेलिया में भी तीनों सेनाओं के लिए एक ही कमांडर-इन-चीफ नहीं है।

अब रक्षा-समूह में पाँच विभाग हैं, अर्थात् रक्षा-विभाग, सेना विभाग, नौसेना-विभाग,

वायुसेना-विभाग और पूर्ति-विभाग मुख्यतः रक्षा-उत्पादन और अक्षाति का काम अपने एक अलग मन्त्री के अधीन करता है और उसकी स्थिति भी तीन मेना-विभागों जैसी ही है।

मन्त्रि-मण्डल रक्षा-नीति के निर्धारण के लिए जिम्मेवार है। पहले इसकी स्थापना के लिए एक रक्षा-परिषद् थी। रक्षा-परिषद् दृढ़ विश्वयुद्ध के दौरान युद्ध-मन्त्रि-मण्डल के रूप में काम करती रही। परिषद् अब भी विद्यमान मानो जाती है, हालाँकि हाल-हाल के सालों में उसकी कोई बैठक नहीं हुई है। प्रधान मन्त्री परिषद् के अध्यक्ष हैं और इसके सदस्य हैं राज-कोष-मन्त्रि, रक्षा-मन्त्री, विदेश-मन्त्री, तीनों मेनाओं के मन्त्री, पूर्ति-मन्त्री, राष्ट्रीय-विकास-मन्त्री, सीनेट में सरकार के नेता, तीनों मेना-प्रमुख और रक्षा-विभाग के मन्त्रि।

१९६३ में रक्षा-परिषद् का नाम नवम्बर्गिन रक्षा और विदेश मन्त्रिमण्डल समिति में सम्मिलित किया। यह समिति पूरे मन्त्रि-मण्डल के निर्णय की अपेक्षा करने वाले मामलों का निर्धारण करती है और क्यापेक्षित सेनाओं के प्रमुखों या अन्य लोगों को बुला लेती है। प्रधान मन्त्री इस समिति के अध्यक्ष हैं और अन्य सदस्य हैं व्यापार और उद्योग-मन्त्री, विदेश-मन्त्री, रक्षा-मन्त्री, निर्माण-मन्त्री और पोस्ट मास्टर जनरल।

रक्षा-मन्त्री के अधीन रक्षा-विभाग इन चीजों के लिए जिम्मेवार है रक्षा-नीति, मेना सम्बन्धी मामलों का समन्वय और उपलब्ध निधि का बँटवारा, रक्षा-नीति का पूर्तिपक्ष, जिनमें उत्पादन कार्यक्रमों और क्षमता की समीक्षा शामिल है, मेनाओं में उच्चतर नियुक्तियों, शस्त्रास्त्र और उपस्तर और रक्षा-अनुसन्धान और विकास। मेनाओं में समन्वय का महत्वपूर्ण कार्य विभिन्न समितियों की मदद में पूरा किया जाता है, जिनमें में ज्यादा महत्व की समितियाँ ये हैं रक्षा-समिति, स्टाफ-प्रमुखों की समिति, रक्षा-प्रशासन-समिति और सयुक्त युद्ध-उत्पादन-समिति।

रक्षा-समिति एक मुखरित निकाय है, जिसमें ये हैं रक्षा-विभाग-मन्त्रि (अध्यक्ष), स्टाफ-प्रमुखों की समिति के अध्यक्ष, तीनों सेना-प्रमुख, राजकोष-मन्त्रि, प्रधान मन्त्री के विभाग के मन्त्रि और विदेश-विभाग के मन्त्रि। (रक्षा वैज्ञानिक-मलाहवार और अन्य विशेषज्ञों को सहयोजित कर लिया जाता है।) समिति रक्षा-मन्त्रों का इन मामलों में सलाह देती है (क) समग्र रक्षा-नीति, (ख) रक्षा-नीति के श्रेष्ठ, आर्थिक, आर्थिक, वित्तीय और वैदेशिक पहलुओं का समन्वय, (ग) मुख्य मेना या अन्तर्विभागीय रक्षा पहलुओं वाले सिद्धान्त और महत्वपूर्ण प्रश्न या नीति सम्बन्धी मामलों और (घ) रक्षा-पहलू वाले ऐसे ही अन्य मामलों, जो मन्त्री द्वारा या मन्त्रों की ओर से समिति की सौंप जायें।

दूसरे देशों की तरह स्टाफ-प्रमुखों की समिति मुख्य-परिचोष और आयोजनाओं को तैयार करने और युद्ध की मन्त्रियाओं का नियन्त्रण करने के लिए जिम्मेवार है (यदि एक अलग कमाण्ड-इन-चीफ न नियुक्त किया जाय)। पिछले पाँच सालों में मेनाओं में में प्रत्येक का एक अध्यक्ष चुन लिया गया है और उसे रक्षा-विभाग में पूर्णवर्तिन नियुक्ति दी गयी है। किसी भी मेना के कमान की सौंपी जिम्मेवारी उस पर नहीं है, पर वह रक्षा-मन्त्रों का मलाहवार है और सीधे प्रधान मन्त्री तक पहुँच रखता है। साथ ही वह आर्जुम (आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, मंगलन अमेरिका मन्त्रि) और सीएटी (६० यू० एनिय मन्त्रि मंगलन) का आस्ट्रेलियाई मुख्य

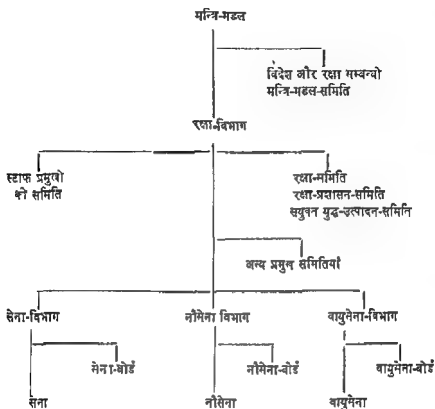
मनाह्वार है। इस तरह समिति में एक पूर्णजातिवृद्ध व्यक्ती होता है और उसके सामान्य स्थापनप्रमुख, नौसेना स्थापनप्रमुख और वायुसेना एक प्रमुख मरत्य होते हैं।

रक्षा-प्रशासन-मिति में ये होते हैं रक्षा-विभाग-सचिव ( अध्यक्ष ), सचिव, मेता-विभाग, सचिव, नौसेना-विभाग, सचिव, वायुसेना-विभाग, सचिव, पूर्वी-विभाग, सहायक सचिव, राजकोष-विभाग ( रक्षा-प्रभाग ), मामान्य स्टाफ के उप-प्रमुख, नौसेना स्टाफ के उप-प्रमुख, और वायुसेना स्टाफ के उप-प्रमुख । ( अन्य प्रतिनिधि और विशेष सलाहकार सहभाजित कर लिये जाते हैं ) । मिति के मुख्य ये हैं (क) रक्षा-कार्यक्रम की नियमित समीक्षा करना और कार्यक्रम के निष्पादन में अनिरोध या विमर्श के कारणों से पड़ाना करना (ख) जब कभी यह समझा जाय कि ऐसा करने में बचप हो सकेगी और कार्यसमता बढ़ जायेगी, तब विभाग या सेना के लिए प्रमुख प्रयोजना के निष्ठापर धनराशें निर्धारित करना या कृषो का बँटवारा करना (ग) विभागों के रक्षा सम्बन्धी समूह के प्रबन्ध-व्यवहारों को चर्चा करना ताकि उपादा मन्त्र नेतिपों और गुप्त समूहों का मूदपात्र किया जा सके और (घ) सामान्यतः समान हित के प्रशासनिक प्रश्नों पर समग्र विचार और चर्चा करना ।

समुपन रक्षा उत्पादन-समिति के अध्यक्ष सामान्यतः एक गुप्तनिष्ठ अधिकारी या उद्योग-पति होते हैं और इसके सदस्य ये होते हैं - यलमेना-विभाग-सचिव, नौमेना-विभाग-सचिव, वायुसेना-विभाग-सचिव, आर्डेन्स के मास्टर जनरल ( यलमेना ), चौथा नौमेना-सदस्य ( नौमेना ), पूर्ति और उपकरण सम्बन्धी वायुसेना-सदस्य ( वायुसेना ), पूर्ति-विभाग-सचिव, महानियन्त्रक ( उत्पादन ), पूर्ति-विभाग, राजकोष विभाग के सहायक सचिव ( रक्षा-प्रभाग ), और रक्षा-विभाग के सहायक सचिव ( सम्भारिकी ) । ( धर्म और राष्ट्रीय सेवा-विभाग और अन्य विभागों के प्रतिनिधि सह्योजित कर लिये जाते हैं ) । समिति के कृत्य ये हैं (क) मेनाओं की सामग्री सम्बन्धी खाली जगहों का सहसम्बन्धन और परिवर्तनीय उत्पादन कार्यक्रम (ख) औद्योगिक मुद्र सम्मान्यताओं के प्रश्न का सभी पहलुओं में अध्ययन, व्यावहारिक वर्तमान क्षमता को बनाये रखने की निवारण करना और दान्ति क्षमता में मुद्र सम्मान्यता के रूप में नशी क्षमता धारणा और (ग) औद्योगिक उत्पादन की आयोजना में साधारणतः सम्मिलित लाना तारिक मुद्र क्षमता की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके । अनेक अपेक्षित समितियाँ भी हैं, जिनके नाम नीचे तौर पर उनके कृत्यों का संक्षेप दिये हैं । वे हैं प्रधान प्रशासनिक अधिकारियों की समिति ( प्रशासन और सामग्री ), प्रधान प्रशासनिक अधिकारियों की समिति ( वाणिज्य ) - रक्षा-अनुसन्धान और विभाग-नौति-समिति, समुपन आयोजना-समिति, समुपन आगुपना-समिति, समुपन प्रशासनिक-आयोजना-समिति और रक्षा-वारवार-बोर्ड ।

आन्दोलन में मेना का प्रयोग अभी मरु एक रीत्य-बोर्ड द्वारा बताया जाता है, जो कि ईशान्य में पहले मेना परिषद् बनाने थी। इसी तरह नौमेना और वायुमेना का प्रयोग भी प्रमत्त एव नौमेना-बोर्ड और एव वायुमेना-बोर्ड बनाते हैं। प्रत्येक मेना का मन्त्री अपनी-अपनी मेना के बोर्ड का प्रेमीडेंट होता है, पर हर मामले में बोर्ड का विचारदेन सम्बन्धित मेना का प्रमुख ही होता है। बोर्ड बैठक में प्रेमीडेंट के न होने पर वाम बर बनने दे—राने भी है।

इस ढाँचे को मोटे तौर पर इस प्रकार बनाया जा सकता है —



### सोवियत रुम

सोवियत रूस और चीन जैसे देशों के रक्षा-तंत्र की निवट तुलना किसी ऐसे सत्तरीय पद्धति की सरकार वाले दूसरे देशों के साथ नहीं की जा सकती, जहाँ सत्ताधारो दल की विहित सावधानिक रीति से बदला जा सकता है। सोवियत संविधान में यह व्यवस्था है कि 'सैन्य सेवा में सेवा करने वाले नागरिकों को राज्य के सभी नागरिकों की तरह समान रीति से चुनने और चुने जाने का अधिकार होगा।' ऐसी व्यवस्था नहीं सम्भव होगी, जबकि प्रशासन सभी स्तरों पर शासी दल से पूर्णतः तादात्म्य प्राप्त कर चुका हो। दूसरा नतीजा यह होता है कि दल और सैन्य सेनाओं अन्तर्गत पर्याप्तवाची बन जाते हैं। सत्तरीय प्रजातन्त्रों में सैन्य सेनाओं के सदस्यों को किसी सदस्य दल का सदस्य बनने और उसने नियंत्रण में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाती। फिर भी उनकी अपना वोट अपनी इच्छा के उम्मीदवार को देने की आजादी होती है (और उनका वोट गुरु रहना है), पर यदि कोई सदस्य किसी विधान-मण्डल या किसी अन्य चुने जाने वाले सोवियतवाय की सदस्यता के लिए खड़ा होता पाट्टा है,

तो उसे गगन्य मेना की नौबरी में स्तोषा देना होता है। लेकिन सोविपत रूम में गगन्य अधि-  
कारी मन्त्रि-परिषद् के सदस्य बन सकते हैं। इस समय दोनों सेनाओं के कमांडर-इन-चीफ पदेन  
उप-मन्त्री हैं और रक्षा-मन्त्री भी सेनाओं में से ही नियुक्त किया जाता है।

रक्षा-मन्त्री के अधान में मुख्य सेनाएँ हैं, नामतः परमेना, वायुसेना, नौसेना, वायु-रक्षा  
और क्राउजिक रॉकेट-बल। इसके अलावा परच मेनाएँ भी हैं और गल्ल निर्देशालय भी है।  
रक्षा-मन्त्री के प्रमोद पन्द्रह उप-मन्त्री होते हैं, जो उपर्युक्त एक-एक सेना और कुछ अन्य कार्यों  
को देखते हैं। सामान्य स्टाफ-प्रमुख और नौसेना-प्रमुख प्रथम डिप्टी होते हैं। सामान्य स्टाफ-  
प्रमुख घरेलूता को प्रभावित करता है। वायुसेना हालाँकि एक अलग सेवा है, पर उसे घनमेना  
का अतिरिक्त भोग माना जाता है।

सोविपत रूम में मुख्य सोविपत उच्चतम विधायी निवास है। इसमें दो सदन होते  
हैं। सदन की सोविपत और नेचनलिटीज (राज्यों) की सोविपत। सदन सोविपत का चुनाव सारे  
सदन के नागरिक करते हैं, जो भारत की लोकसभा को सदासी होती है। नेचनलिटीज की  
सोविपत हमारी राज्य सभा की तरह उच्च सदन है। मुख्य सोविपत की बैठक कभी-कभी ही  
होती है और अधिवेशन के बीच इनका प्रतिनिधित्व एक स्थायी समिति करती है, जिसे प्रेसी-  
डियम कहते हैं और जो मुख्य सोविपत की समुक्त बैठक में चुनी जाती है। मुख्य सोविपत  
या इसकी-प्रेसीडियम साविधानिर रूप में सोविपत सदन की समस्त सेनाओं के उच्चतर कमान  
को नियुक्त करने या हटाने के लिए और सामान्य नियन्त्रण रखने के लिए उत्तरदायी है। व्यव-  
हारतः नियन्त्रण मन्त्रि-परिषद् रखती है।

राज्य का उच्चतम कार्यपालक प्राधिकार मन्त्रि-परिषद् है (जिसे १९४६ तक जन-  
कमिषनरी की परिषद् कहा जाता था), जिसकी नियुक्ति मुख्य सोविपत करती है, और उसका  
अधिवेशन न होने समय वह प्रेसीडियम के प्रति उत्तरदायी होता है।

सदनने योग्य दल वाले प्रचार के दलों में रक्षा-मन्त्री सीधे निम्न विरचनाओं के पाम  
आदेश नहीं भेजता। ये आदेश स्टाफ-प्रमुख या सम्बन्धित कमांडर-इन-चीफ के जरिये भेजे जाते  
हैं। पर सोविपत रूम में रक्षा-मन्त्री द्वारा विरचनाओं के कमांडरों के पाम सीधे आदेश भेजे जा  
सकते हैं।

## चीन

चीन में भी मन्त्रालय सेनाओं के सदस्यों की विधान-समिति या कार्यपालक निकायों में  
गले जाने की आशा होती है। जन गणराज्य का केयरमेन राज्य का प्रमुख होता है। राज्य-  
परिषद् में प्रीमियर, १५ उप-प्रमियर और मन्त्री होते हैं। यह भारत के मन्त्रि-समिति की  
गमनाह है। सारे सरकारी समिति पर, जिसमें मन्त्रालय, वायुसेना और विदेश अतिरिक्त होते  
हैं, नियन्त्रण राज्य-परिषद् द्वारा रखा जाता है।

रक्षा सम्बन्धी निर्णय लेने के लिए सिटान्तन चीन में उच्चतम प्राधिकार हार्ड-कमल  
है, जिसमें ये होते हैं। राष्ट्रीय जन-कमिषनरी की स्थायी समिति, साम्यवादी दल की केन्द्रीय समिति  
और राज्य-परिषद्। हार्ड कमल रक्षा समिति देना की नीति समिति बनाना है। रक्षा मन्त्री हार्ड

क्रमानुसार बनायी गयी रक्षा नीति के अनुपालन के लिए जिम्मेवार होना है और उसे आवश्यक वस्तु के ऊपर पूरी-पूरी शक्ति दी जाती है। रक्षा-सम्बन्धी मामलों में हार्ड कमान को राष्ट्रीय-रक्षा-परिषद् सलाह देनी है। गणराज्य का चेयरमेन साथ ही राष्ट्रीय-रक्षा-परिषद् का भी चेयरमेन होता है, जिसमें १३ वाइस चेयरमेन और १०७ अन्य सदस्य होते हैं। रक्षा-मन्त्री राष्ट्रीय-रक्षा-परिषद् का एक वाइस चेयरमेन होता है और जन स्वतन्त्रता (लिबरेटन) मेना का सामान्य स्टाफ-प्रमुख उसका एक सदस्य होता है। हार्डकमान और राष्ट्रीय-रक्षा-परिषद् दोनों ही बटे-बटे निकाय हैं और वे जरूरी-जल्दी नहीं बैठ सकते इसलिए चीन के साम्यवादी दल के पोलित ब्यूरो की गतिशीलता मैन्स-कार्य-समिति ही रक्षा-मन्त्रिणी मंत्री महत्वपूर्ण निर्णय करती है। मैन्स-कार्य-समिति के चेयरमेन का नाम कभी बनाया नहीं जाता, पर विद्वत्ता दिया जाता है कि वह माओ से कुछ स्वयं है। वह लिन प्याओ भी हो सकते हैं, जिनसे सामान्यतः वाइस चेयरमेन के रूप में जाना जाता है। जन-स्वतन्त्रता-मेना के सामान्य स्टाफ-प्रमुख ही इस समिति के महामन्त्रि होते हैं।

राष्ट्रीय-रक्षा-परिषद् के महत्वपूर्ण सदस्य केन्द्रीय प्रादेशिक समिति के पोलित ब्यूरो के भी सदस्य होते हैं और मैन्स-कार्य-समिति में भी प्रतिनिधि रहते हैं, इसलिए राज्य परिषद् और पोलित ब्यूरो के बीच मध्य की सम्भावना नहीं रहती चीन के अधिकांश शिवरम्य नेता हर दशा में जन-स्वतन्त्रता मेना में उच्च पदों पर रह चुके हैं और वे सामान्य मैन्स समस्याओं से परिचित होते हैं।

चीन में नौसेना और वायुसेना जन-स्वतन्त्रता-मेना के अंग हैं और उनका नियन्त्रण रक्षा-मन्त्री द्वारा जन-स्वतन्त्रता-मेना के कमाण्डर-इन-चीफ की हैसियत से किया जाता है।

सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में चीनी मेना के योगदान के बारे में और साथ समस्या के निपटान के बारे में बहुत कुछ सुना गया है। पर इसमें कुछ ऐतिहासिक परिस्थितियों का योगदान है, जो अन्य देशों में सामू नहीं होती। वर्तमान सरकार के चीन में सत्तास्थ होने से पहले स्वतन्त्रता-मेना एक सुसंगठित सेना थी जिसे भारी लोकप्रियता मिली हुई थी। मेना को न केवल मुद्रा करना पड़ता था, बरिन् सेनिकों के लिए मोर्चे पर अनाज पैदा करना होता था और उपकरण और अन्य जरूरतों की चीजों का उत्पादन भी करना होता था। इसलिए गृहयुद्ध के दिनों में मेना, जो पहले ही ऐसे कामों के लिए शिक्षण मिल चुका था और यह राष्ट्रीय आन्ध्र-वादी मण्डन था। मरण ममास होने पर स्वतन्त्रता-मेना के सभी सदस्यों को सरकार ने जमोन दी और उन पर यह सामान्य नियम भी नहीं लगाया गया कि भूमि केवल जोतने वाले मालिक के पास हो रह सक्ती है।

### निकर्ष

दूरे देशों में उच्चतर रक्षा-नियन्त्रण की योजना के इस विन्नेषण से प्रकट है कि भारत की तरह प्रत्येक देश में बाँचा अपनी-अपनी जरूरतों के अनुसार गढ़ लिया गया है। रक्षा-

मगधन की आधुनिक प्रवृत्ति यही है कि तीनों सेनाओं को समानम्भव अलग रखा जाय, पर उनके व्ययिन्त्र का क्रिय न कर दिया जाय । इस दृष्टि में प्रत्येक सेना के लिए एक मन्त्री नियुक्त करना एक परवर्गामी कार्य होगा और साथ ही समन्वय का पूर्ण प्रदान सड़ा कर देगा । भारत में रक्षा-मन्त्री की समिति एक अद्वितीय सत्त्वा है, जो बहुत उच्चस्तर पर समन्वय की भूमिका का ठीक तरह निर्वहण कर देती है । सेनाओं के प्रमुख न केवल अपनी-अपनी सेना का दृष्टिकोण उपस्थित करते हैं, बल्कि तीनों सेनाओं की समग्र जख्मों का व्यापक दृष्टि में भी देखते हैं ।

## पाँचवाँ अध्याय

# रक्षा-सचिवालय का मन्त्रालय

## मण्ड—१ मन्त्रालय की नयी भूमिका

पूरे ब्रिटिश शासन काल में न केवल जनता और विधान-मण्डल के सदस्यों के लिए ही, बल्कि सिविल सेवा के भारतीय सदस्यों के लिए भी रक्षा सम्बन्धी मामले वस्तुतः एक बन्द पोथी की तरह रहे। रक्षा संगठन और प्रशासन के बारे में जो भारतीय अमेरिकी जनो की सीधा-सीधा ज्ञान और अनुभव था, क्योंकि शायद ही कोई भारतीय अधिकारी रक्षा-विभाग के सचिवालय में दूसरा महामुख शुरू होने के बाद तक नियुक्त हुआ रहा हो। रक्षा-व्यय के अमत्र देय होने में रक्षा-विभाग विधान-मण्डल की छान-बीन से बचा रहता था और इसके सामने रक्षा-व्यय की विभिन्न मदों को न्यायोचित ठहराना जरूरी न था। इस व्यय में कोई कटौती विधानमण्डल में पेश नहीं की जा सकती थी, लेकिन सदस्य एग्जीक्यूटिव कौंसिल के अनुमानों में कटौती सुझाकर रक्षा-प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर धर्चा छेड़ देते थे। हालाँकि १९२१ से विभाग-सचिव एक अमेरिकी व्यक्ति होने लगा था और पहले की तरह एक नैप्य अधिकारी न था, और सचिवालय के अग्र बरिष्ठ पदों पर भी आई. सी. एस. के सदस्य रहते थे, पर वे सभी ब्रिटिश अधिकारी ही होते थे। पहली बार १९३८ में ही एक भारतीय अमेरिकी अधिकारी को विभाग का एक अनुसन्धित नियुक्त किया गया। मुद्र शुरू होने के बाद १९४१ में थोड़े से समय के लिए एक भारतीय आई. सी. एस. अधिकारी अपर सचिव बनाया गया। जुलाई १९४२ में एक भारतीय आई. सी. एस. अधिकारी (चन्द्र साल एम० त्रिवेदी) को विभाग का सचिव नियुक्त किया गया और जनवरी, १९४६ तक उस पद पर रहे। १९४८ में एक अन्य भारतीय आई. सी. एस. अधिकारी को अपर सचिव नियुक्त किया गया। लेकिन १९४६ से सत्ता-हस्तान्तरण तक एक ब्रिटिश आई. सी. एस. अधिकारी (ए. डी. एक डैटस) विभाग के सचिव रहे और उन्होंने पाकिस्तान जाना का विकल्प चुना। विभाग के मुसलमान सदस्यों ने भी पाकिस्तान जाने का विचार चुना।

विभाग के पूर्व-अनुभव वाले बहुत थोड़े में ही अमेरिकी व्यक्ति नये रक्षा-सचिवालय में नियुक्त करने के लिए उत्तम थे।



किर भी मैन्स वित्त-विभाग में भारतीय अधिकारी काफी समय में उत्तरदायी पदों पर चने आ रहे थे। १९१६ में एक भारतीय अधिकारी मैन्स वित्त-विभाग का प्रमुख बन गया, जब कि उसे मैन्स महालेखाकार और रक्षा-वित्त-विभाग का अतिरिक्त वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया गया। १९२५ में भारतीय अधिकारी उप-वित्त-सलाहकार और सहायक-वित्त-सलाहकार के पदों पर रहने आये थे। वस्तुतः सत्ता हस्तान्तरण के समय मैन्स वित्त-विभाग के बहुगंभीर अधिकारी भारतीय थे। यह पहले बताया जा चुका है कि रक्षा-सदस्य के अधीन भूतलों सेन्स-विभाग के समान्त कर देने के बाद संयंत्रित वित्त-विभाग, जिसके पास रक्षा-व्यय की ध्यानवीन करने का माय और पर एक मात्र उत्तरदायित्व था, धीरे धीरे कहीं ज्यादा जानकारी और महत्व प्राप्त करता जा रहा था, जबकि सेना (बाद में रक्षा) विभाग की उत्तम क्षमता खत्म होती जा रही थी। इस तरह सेन्स वित्त-विभाग के अधिकारी सेनाओं के मुख्यालयों और रक्षा-मन्त्रालय दोनों को ही आजादी के बाद के बारम्बार वर्षों में मार्गदर्शन दे सकते थे। दो-तीन दूसरे भारतीय अधिकारी भी थे, जो रक्षा-संगठन और उसके समस्याओं के बारे में, सत्ता सेनाओं के विभाजन के नियमों में, अपने कर्तव्य के दौरान, काफी जानकारी प्राप्त कर चुके थे। उनमें से एक (एच. एम. पटेल) को सत्ता-हस्तान्तरण के बाद सीन ही रक्षा-सचिव नियुक्त किया गया और दूसरे (बी. बी. पोप) को मयुक्त सचिव। रक्षा-मन्त्रालय को उसकी नयी जिम्मेदारियों के अनुरूप धवन देने में इन दोनों अधिकारियों ने एक बड़ी भूमिका निभायी।

आजादी से पहले भारत को रक्षा-नीति का निर्माण करने की अन्तिम जिम्मेवारी भारत सरकार के ऊपर न रहने से, रक्षा-विभाग को इस रूप में रखा गया था कि नीति और संगठन सम्बन्धी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न निर्णयार्थ सन्धन भेजने की उसे आदत पड़ गयी थी। निर्णय आने पर वह उसे अमल में लाने के लिए सेना-मुख्यालयों के पास भिजवा देता था। इन प्रस्तावों को प्रयासनिष्ठ और वित्तीय दृष्टिकोण से अन्य विभागों की तरह स्वतन्त्र रूप में प्रस्तावों की जाँच करने की कोई जिम्मेवारी इस विभाग के ऊपर न थी। सभी वित्तीय आवेदन यावे प्रस्ताव इस विभाग के पास मैन्स वित्त-विभाग की जाँच के बाद आते थे और अवसर उनके साथ विभाग द्वारा सरकारों आदेश के रूप में जारी करने के लिए आदेश का मसौदा भी रहता था। इस प्रस्ताव का अनुमोदन समाहर इन धीक की हैसियत में रक्षा-सदस्य पढ़ने ही पर चुकते थे। इनलिए विभाग में उसकी आलोचनापूर्ण जाँच की प्रवृत्ति कोई अपेक्षा न रहती थी। बाहर या दूसरे विभागों में प्राप्त पत्र प्रायः स्वतः ही सेना मुख्यालयों के पास जरूरी कार्रवाई करने या दिये जाने वाले उत्तर का रूप मुमाने के लिए भेज दिये जाते थे। विभाग एक प्रकार का प्रतिष्ठित डाकघर बन गया था। इस तरह विभाग के अधिकारियों को रक्षा-संगठन की समस्याओं के बारे में बन्धनासीनता के साथ अपना मन लगाने के लिए कोई जरूरत या गुन्ना-इस तक न रही थी। इसका असर यह हुआ था कि उनकी उत्तम क्षमता ही निरूप हो गयी थी। १५ अगस्त, १९४७ से विभाग की भूमिका और उत्तरदायित्व स्वभावतः वित्तुल बदल गये। अब वह नीति की तरह रक्षा सदस्य के भी रूप में काम कर रहे बनावट इन-धीक द्वारा पहले से ही अन्तिम रूप दिये गये सरकारों आदेशों को जारी करने का एक कार्यालय मात्र न

रह सकता था। अब विभाग को स्वतन्त्र रूप से निर्णय तैयार करने पड़ते थे, जिसके लिए कोई बाह्य मार्गदर्शन न मिलता था और रक्षा-मन्त्री और मन्त्रिमण्डल से उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में सलाह देनी पड़नी थी, जिनके लिए मन्त्रिमण्डल का निर्णय अपेक्षित था। रक्षा-नीति सम्बन्धी प्रमुख प्रश्नों पर विमुक्त सैन्य शब्दों में केवल चर्चा हो नहीं की जा सकती थी बल्कि उनकी देश की विदेशनीति और अर्थनीति के प्रसंग में भी जांच करनी होती थी।

आजादी के पहले कुछ वर्षों में दूरगामी प्रतिफल वाले विषयों को निपटाना पड़ा और नये और अत्रत्याक्षिप्त प्रश्न उठ खड़े हुए, जो अतीत में रक्षा-संगठन और रक्षा-सचिवालय से पूरी तरह परिचित थले आये अधिकारियों के लिए भी कठिन थे। नये रक्षा-विभाग-सचिवालय के अधिकारों हालांकि अपने काम में नये थे, पर उनको अपने विशाल उत्तरदायित्व से प्रेरणा मिली। अङ्ग्रेजों के बाजबूद सत्ता हस्तान्तरण के बाद पहले कुछ वर्षों में एक सक्षम रक्षा-सचिवालय की मोब अच्ची और पक्की तरह से जमा हो गयी।

२६ अगस्त, १९४७ से भारत-सरकार के सभी विभाग मन्त्रालय कहें जाने लगे। हम तरह रक्षा-विभाग रक्षा-मन्त्रालय बन गया और नैसर्गिक-विभाग वित्त-मन्त्रालय (रक्षा)। नये रक्षा-मन्त्रालय के प्रसंग में यह केवल नाम का ही परिवर्तन न था, बल्कि अब उसकी भूमिका पूरी तरह बदल गयी थी। उसे निर्वाचित संसद के प्रति उत्तरदायी एक सौतन्त्र्यीय सरकार के निर्णयों का निर्माण करने और कार्यान्वित करने में मदद देने के एक प्रभावी साधन के रूप में परिवर्तित करना था।

ब्रिटिश काल में, जब कमांडर-इन-चीफ तीनों सेनाओं का सर्वप्रमुख था, वही तीनों सेनाओं की ज़रूरतों से सम्बन्धित सभी प्रमुख कार्यों का समन्वय करना था। सामान्यतः जो प्रस्ताव उसे स्वीकार न थे, रक्षा-विभाग के सामने न आ सकते थे।

जब १५ अगस्त, १९४७ को कमांडर-इन-चीफ तीनों सेनाओं के सर्वप्रमुख न रहे, और बदले में उनकी जगह तीन सेना प्रमुख नियुक्त किये गये, तो तीनों सेनाओं को समन्वित और एकबद्ध रखने का महत्वपूर्ण कार्य रक्षा मन्त्रालय के ऊपर आ पड़ा। समन्वय का अर्थ यह नहीं कि तीनों सेनाओं के विचारों को नरबी कर दिया जाय। अक्सर ये विचार भिन्न-भिन्न भी होते थे, क्योंकि उनकी आवश्यकताओं में अन्तर था। एक का काम जमीन पर था, दूसरी का समुद्र पर और तीसरी का वायु में। इसलिए अब यह मन्त्रालय का काम था कि सेनाओं की समस्याओं को क्या सापेक्ष बल दिया जाय और अधिराशिक सीमा तक, जितना संभव हो, समरस और एकबद्ध नीति बनाने के लिए ज़रूरी समझनों के बारे में सलाह दे।

रक्षा-सेनाओं सम्बन्धी नियम और विनियम, जो रक्षा-सेनाओं के सदस्यों को प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में बुनियादी मार्ग दर्शन देते हैं, पिछली बार १९३५ के भारत सरकार अधिनियम के प्रवृत्त होने के बाद संशोधित किये गये थे। १९३६ में युद्ध शुरू हो जाने के बाद, युद्ध-आपात का सामना करने के लिए, नये अनुदेश और आदेश जारी करने पड़े। सत्ता-हस्तान्तरण के बाद स्थायी विनियम व्यवहारन पुराने पड़ गये, क्या कि वे ब्रिटिश प्राधिकार के सुन्दर में बनाये गये थे। रक्षा-संगठन के सदस्यों के लिए यह एक बड़ी बाधा सिद्ध हुई।

स्वभावतः जब विनियम कोई भी मार्ग दर्शन न दें, तो आदेश के लिए सरकार को सन्दर्भ भेजना ही होता था और मन्त्रालय के पास आजादी के बाद के पहले कुछ वर्षों में आने वाले इन सन्दर्भों की संख्या स्वभावतः काफी ज्यादा थी।

फिर युद्ध के दौरान आग्रह इस बात पर था कि रक्षा सम्बन्धी ज़रूरतों को बड़ी तेज़ी के साथ पूरा किया जाय। सभी मामलों में यह सम्भव नहीं रहता था कि विवाद नियम-विनियमों का पालन किया ही जाय। फलस्वरूप बहुत काफी संख्या में अनियमितताएँ (इन शब्द का अर्थ हर मामले में किये गये व्यय की मद या अपनावी गयी प्रक्रिया का वह रूप था, जो प्रवृत्त विनियमों या आदेशों के अनुसार न थी) युद्ध काल में और उसके बाद इकट्ठी हो गयी थी। १५ अगस्त, १९४७ के तुरन्त बाद भारत की रक्षा-सेवाओं ने अपने आपको इन अनियमितताओं के भारी सभ्य से घिरा पाया, जो सेवा-परीक्षा की आपत्तियाँ बन चुकी थी। हालांकि जुलाई, १९४७ में निम्नतर सैन्य विवरणों को ज्यादा शक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए विशेष कर्म उठाये गये थे, इन आपत्तियों को साफ करना एक ऐसा बड़ा काम था, जो आजादी के बाद के कुछ वर्षों में कर्मचारियों के सभ्य और शक्ति का काफी अंश लें लेता था। इन आपत्तियों का निपटारा खासकर इस कारण मुश्किल हो गया कि उन अधिका-रियों के बिना, जो कि या तो सेवा-निवृत्त या सेवा-मुक्त हो गये थे या जिन्होंने पाकिस्तान जाने का विकल्प चुना था, समुचित जाँच न हो सकती थी। ये कारण अपने-आप में बड़े महत्व के भले ही न हों, पर उन सब ने मिल कर नये रक्षा-गण्डन के कार्यकरण में आरम्भ के दिनों में सचिव प्रभाव डाला था।

युद्ध के तुरन्त बाद रक्षा-सेवाओं के वेतन-मान में सुधार के प्रश्न पर विचार करना ज़रूरी हो गया। आजादी के बाद, कन्याणकारी राज्य के उद्देश्यों के अनुकूल करने की दृष्टि से, वेतन-सहिताओं में सुधार किया गया और पेन्शन-सहिताओं को भी बिलकुल नया रूप दिया गया।

सरासरी सेवाओं की अनुशासन-महिता में भी पूरा-पूरा सुधार करना ज़रूरी था, ताकि प्रत्यक्ष भुटियाँ दूर हो जायँ और एक राष्ट्रीय रक्षा-सेवा की ज़रूरतों की पूर्ति की जा सके।

मन्त्रालय की रक्षा-सेवाओं के अर्थनिक व्यक्तियों की समस्याओं का भी समाधान करना पड़ा, जो युद्ध के बाद, और खासकर आजादी के बाद काफी महत्व की बन गयी थी। युद्ध के खतम होने के बाद तक चलनेवाला मुख्यालय, नौसेना मुख्यालय और वायुसेना मुख्यालय की यथा सम्बन्धित शाखाएँ उनके अपने काम करने वाले अर्थनिक सम्बन्धी प्रश्नों का निपटारा करती थी और यथावश्यक रक्षा या युद्ध-विभाग के आदेश प्राप्त कर लेती थी पर शीघ्र यह समझ में आ गया कि सरकार द्वारा, अर्थनिक विभागों के कर्मचारियों के बारे में लिये गये निर्णयों के प्रकाश में, रक्षा-सेवाओं में काम कर रहे सभी अर्थनिक कर्मचारियों के लिए भी एक समान नीति होनी चाहिये।

सेवा की शर्तों वाले अध्याय में उन उपायों का विवरण दिया गया है, जो इन बारे में अपनाये गये।

ब्रिटिश शासन काल में, जब रक्षा-व्यय अमतदेय था और रक्षा प्रशासन के सम्बन्ध में चर्चा अप्रत्यक्ष रूप से ही उठायी जा सकती थी, विधान-मण्डलों के अधिवेशन का अर्थ रक्षा-विभाग के लिए कोई अनिश्चित काम बढ जाना नहीं होता था। रक्षा-विभाग में प्राप्त सभी प्रश्न उत्तरों के मसौदों के लिए सेना मुख्यालयों के पास भिजवा दिये जाते थे।

१५ अगस्त, १९४७ से रक्षा-व्यय विधान-मण्डल की छानबीन के अधीन आ गया। वित्तीय प्रशासन की ध्येरेवार जाँच लोक-सेवा-समिति करती है और संगठन ढाँचे की प्रभाविता की जाँच नवनिर्मित प्राक्कल्पन समिति करती है।

विधान-मण्डल रक्षा के मामलों के बारे में स्वभावतः अधिकाधिक रुचि ले रहा है, जो बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए १९४८ में रक्षा-मन्त्री ने भारत की संविधान-सभा (विधायी) में २०७ प्रश्नों के उत्तर दिये। १९६१ में संसद के दोनों सदनों में १५८४ प्रश्न भेजे गये, जिनमें से ७८२ के उत्तर दिये गये, १९६२ में ये आँकड़े १९०५ और ६२२ थे। १९६२ में सदस्यों द्वारा संसद-सचिवालय में दिये गये प्रश्नों की मन्त्रालयों के पास भेजने की कार्यविधि में प्रत्यक्षत कुछ परिवर्तन किया गया। १९६५ में रक्षा-मन्त्रालय के पास ११७६ प्रश्न आये, जिनमें से दोनों सभाओं में ८३२ के उत्तर दिये गये। प्राप्त हुए सभी प्रश्नों के बारे में तथ्य इकट्ठे करने होते थे। ये प्रश्न काफी संख्या में प्राप्त रक्षण प्रस्ताव, ध्याना-कर्षण प्रस्ताव आदि की सूचनाओं के असावा होते थे। अनेक मामलों में पूरे देश में पैनी यूनिटें और विवरणाओं से जानकारी इकट्ठी करनी होती थी।

नये टाचे में संसदीय प्रश्नों की प्राप्ति उत्तर तैयार करने के लिए सेना-मुख्यालयों के पास ही नहीं भेजा जा सकता था। उन सभी की पहले रक्षा-मन्त्रालय में जांच करनी होती थी और सेना मुख्यालयों में उतनी ही जानकारी मँगानी होती थी, जो मन्त्रालय में तत्काल उपलब्ध न हो। कुछ मामलों में, जैसे नीति के प्रश्नों में, उत्तर स्वतः सचिवालय में ही तैयार करने होते थे। दूसरे मामलों में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अपेक्षित सामग्री इकट्ठी करनी होती थी। कभी-कभी यह भी जरूरी होता था कि दूसरे मन्त्रालयों से भी सलाह की जाय, ताकि यह आश्वासित किया जा सके कि पूरी जानकारी देने के साथ ही उत्तरों में पूरी भारत सरकार की सामान्य नीति का भी सहो-सहो प्रतिक्रिया हो।

इन सभी अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए एक पूर्णकालिक संसद-अनुभाग मन्त्रालय में १९४८ में खोला गया। यह भी व्यवस्था की गयी कि संसद की कार्यवाही के सिलसिले में सेना मुख्यालयों द्वारा भेजी गयी सामग्री का अनुमोदन कम से कम सम्बन्धित प्रधान स्टाफ-अधिकारी द्वारा किया जाय।

पहले जब रक्षा-व्यय विधान-मण्डल द्वारा मतदेय न था, संसद में सभाओं के बारे में ध्येरेवार जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई भी अवसर न था। इंग्लैंड और दूसरे पश्चिमी लोकतान्त्रिक देशों में, जहाँ अनिवार्य सैन्य-सेवा की पद्धति है, वहाँ विधान मण्डलों के सदस्यों को रक्षा-सेनाओं के बारे में, युद्धकाल में सेना में सेवा करने के कारण या शान्ति काल में अनिवार्य सैन्य सेवा के कारण, रक्षा-सेनाओं के बारे में प्राथमिक जानकारी प्राप्त करने का

मौका मिल चुका होना था । भारत के संसद्-मदस्यों को ऐसा कुछ अनुभव न था । अगस्त, १९४७ में भारत की मन्त्रिमण्डल सभा (विधायी) में विभिन्न विभागों के लिए स्थायी मन्त्रियों की नियुक्ति की गयी । पहली संसद् के चुनाव के बाद इनको नियुक्ति कर दिया गया और अक्टूबर, १९४८ में दोनों सदनों के लगभग ३५ सदस्यों की अनौपचारिक परामर्श-समितियाँ बना दी गयी । ये मन्त्रियाँ सर्वोच्च या विमुक्त संसदीय समितियाँ नहीं हैं, लेकिन उनका उद्देश्य है कि सदस्यों को मन्त्रालयों के कार्यक्रम से निकट से परिचित रखा जाय । रक्षा मन्त्रालय विभिन्न रक्षा-सहायकों में संसदीय सदस्यों के दौड़ों की भी व्यवस्था करता रहा है । इस प्रकार के कार्यों से संसद्-मदस्य रक्षा-विषयों के बारे में जानकारी पूर्ण अभिमान बना सकने में समर्थ हो जाते हैं ।

यह पहले ही बताया जा चुका है कि सत्ता-हस्तान्तरण से पहले सभी प्रस्तावों पर आरम्भ में ही तीन सेना-मुख्यालयों और सैन्य वित्त विभाग के बीच चर्चा की जानी थी और फाइनल रक्षा-मन्त्रालय में उन्हीं समय पहुँचती थी, जब सरकार को यारें निकालने की हो बात रह जाती थी । पर आजादी के बाद में सभी प्रस्तावों पर अनेक दृष्टियों से विचार करना होता है, जो पहले विचारणीय न थे । पुनर्गठित रक्षा-विभाग को उसके नये उत्तरदायित्वों के अनुकूल तैयार करना निश्चय ही एक बड़ा काम था । परिवर्तन क्रमशः ही हो सकता था । वस्तुतः ३० नवम्बर, १९४७ को, सुप्रीम कमांडर का मुख्यालय बन्द करने तक, भारत के रक्षा-मुख्यालयों के विभिन्न अनुभाग अपनी काम पर जम भी न पाये थे ।

१५ अगस्त, १९४७ के बाद भी सेना-मुख्यालयों द्वारा अपने प्रस्ताव पहले विन्-मन्त्रालय ( रक्षा ) के पास भेजने की पुरानी कार्यविधि कुछ समय तक चलती रही । इससे एक बड़ी हानि थी । रक्षा-सेनाओं के प्रशासन के लिए मन्त्रिमण्डल और संसद् के प्रति उत्तरदायी रक्षा-मन्त्री, इन समस्याओं से और सेनाओं की जटिलता से, तब तक अनभिज्ञ रहते थे, जब तक वे प्रस्ताव बहुत कुछ निष्पक्ष रूप में रक्षा मन्त्रालय न पहुँच जाते थे । कभी-कभी सेनाओं के ऐसे प्रस्ताव रक्षा-मन्त्रालय के पास आते तक न थे, क्योंकि विन्-मन्त्रालय ( रक्षा ) द्वारा किये गये विरोध के कारण वे सेना मुख्यालयों द्वारा स्वतः ही वापस करके रख लिये जाते थे ।

यह प्रत्यक्ष है कि सैन्य आवश्यकताओं के प्रश्नों को केवल वित्तीय आधार पर नहीं साँका जा सकता । यह भी कल्पनीय है कि कोई प्रस्ताव विन्-मन्त्रालय को स्वीकार हो और उसे कार्यान्वित करने के लिए बजट में पैसे की भी व्यवस्था हो सकती है, पर वह प्रामाणिक दृष्टि में वाञ्छनीय न हो, अथवा इसकी कार्यान्विधि से अन्यत्र दुष्प्रभाव पड़े या परेशानी लक्ष्मी हो जाय । इसलिए यह जरूरी है कि रक्षा-मन्त्रालय और उसके जरिए रक्षा-मन्त्री को सेनाओं के सामान्य कार्य संचालन के लिए और नीति के प्रश्नों के लिए सबसे आरम्भ के चरण में ही इन प्रस्तावों के साथ ज्यादा सीधे-सीधे सम्बन्धित होना चाहिए । पर साथ ही यह भी बड़ी घातक घुटि होती यदि विमुक्त नेमी मामलों में सेना-मुख्यालयों द्वारा रक्षा-मन्त्रालय के पास भेजना जरूरी बना दिया जाता । फिर भी यह बताना बहुत मुश्किल है कि कौन-सा प्रस्ताव

यथायं में महत्वपूर्ण है और कौन-सा नहीं। यह अन्ततः ऐसी बात है, जो निर्णय के लिए अधिकारियों के ऊपर ही छोड़ दी जानी चाहिए। फिर भी, महत्वपूर्ण मामलों को एक निदर्शनात्मक सूची तैयार की गयी और १९४६ के आरम्भ में यह निर्णय लिया गया कि ऐसे मामलों के बारे में मेना-मुख्यालयों को अपने प्रस्ताव पहले रक्षा-मन्त्रालय के पास भेजने चाहिये। पहले की तरह सबसे प्रथम वित्त-मन्त्रालय ( रक्षा ) के पास नहीं। इसके बाद, प्रत्येक प्रस्ताव को सभी प्रकार से जाँच करना रक्षा-मन्त्रालय का काम होगा और जब प्रस्ताव पर प्रशासनिक अनुमोदन दिया जा सके, तभी वह सम्बद्ध खर्च की मजूरी देने के लिए रक्षा-मन्त्रालय ( वित्त ) के पास भेजा जा सकेगा। मन्त्रालय में इस आरम्भिक जाँच का अर्थ है कि वहाँ पर मेनाओं की समस्याओं, उनकी प्रयाजा-भरपराओं, नियमो-विनियमों आदि के बारे में काफी जानकारी उपलब्ध हो। यह राष्ट्रीय सरकार की नयी समग्रोण नीति को समझने की भी माँग करता है। अब रक्षा-मन्त्रालय के अधिकारियों को, मेना की जिस हाला में वे सम्बद्ध थे, उनके काम में भारी रुचि लेनी होगी और सामान्यतः समग्र रक्षा-संगठन में होने वाले विकासों में अपने को परिचित रखना होगा। इससे मन्त्रालय में परीक्षणार्थ आने वाली समस्याओं के प्रति निपटणिका और स्वरूप दृष्टिकोण बनाने के लिए भी प्रोत्साहन मिला। यह नयी पद्धति इसलिए चाहू की गयी थी कि मन्त्री या मन्त्रि-मण्डल को सलाह देने के अपने नये विभिन्न सम्मेलन कर्तव्य का विवेक निवाह कर सके और इसके लिए वित्त-मन्त्रालय ( रक्षा ) के विभिन्न सम्मेलन कृत्यों के किसी भी प्रकार बाड़े न आये, जो सभी प्रस्तावों की वित्तीय दृष्टि में जाँच करने के लिए प्रथमतः सम्बन्धित बना रहा था।

समय-बाल में यह प्रत्याशित ही था कि आरम्भिक जाँच की प्रक्रिया में मन्त्रालय के अनुभाग कभी-कभी मेना मुख्यालयों में कुछ ऐसी बिस्तृत जानकारी माँगें, जो तब जरूरी न होती, जब मन्त्रालय के वरमवारी पिछले निर्णयों और चालू व्यवहारों से अच्छी तरह परिचित होते। लेकिन वित्त मन्त्रालय ( रक्षा ) अपने पिछले अनुभव के आधार पर उतने ही गहरा प्रश्न पूछना और उन भी व्यौरों की यद्यपि अधिक नहीं तो कुछ जरूरत पड़ती है। आरम्भ में मेना-मुख्यालयों को दायद यह नयी पद्धति परेशान करने वाली लगी होगी। फिर भी मन्त्रालय या अभीष्ट, अनुचित बाधा और विलम्ब सड़ा करके, शाही का पाँचवाँ पहिया बनना बहाल न था। यह समझ लिया गया कि नयी पद्धति से मेनाओं का काम वही जवाबदास्त हो जाना चाहिये। एक बार जब मन्त्रालय मेनाओं के प्रस्ताव पर प्रशासनिक अनुमोदन दे देता है, तो फिर यह मन्त्रालय की जिम्मेवारी हो जाती है कि वह उपयुक्त अधिकारों के पास में आवश्यक वित्तीय मजूरी भी प्राप्त कर ले। लेकिन मेनाओं को मुविचारित प्रस्ताव ही भेजने चाहिये, कि जिनके ठोस होने का वह रक्षा-मन्त्रालय को पूरा विश्वास दिला सके। अपनी ओर से दाना कर देने के बाद, उसको यह मानने के लिए तैयार रहना चाहिये कि कुछ ऐसे प्रस्ताव हो सकते हैं, जिनके बारे में उनका अपना अभिमत भले ही छद्म हो पर वह कभी-कभी प्रशासनिक और वित्तीय कारणों से, सरकार की अन्य समग्र नीति के प्रकाश में, सरकार को मान्य न हो। ऐसी स्थिति में समग्र और जनता के प्रति उत्तरदायी सरकार को ऐसे निर्णय के प्रतिफल की मारो जिम्मेवारी भेलनी होगी और मेनाओं को अपनी ओर से इन निर्णयों का

निष्ठापूर्वक पालन करना होगा।

नयी कार्यविधि शुरू हो जाने के बाद भी सेना-मुख्यालय द्वारा रखी जाने वाली फाइलों में ही सरकार के निर्णय अभिलिखित होने रहे और ये फाइलें उनको लौटा दी जानी थी। सेना-मुख्यालयों को फाइलें लौटाने के इन चलन ने कुछ दिक्कतें पैदा कर दीं, क्योंकि नये प्रस्तावों को निपटाने में उन चर्चाओं का उल्लेख करना होता था, जो पहले सेना-मुख्यालयों को फाइलों पर अभिलिखित की जा चुकी थी, और फाइलें उनको लौटा दी गयीं। यह अनुभव किया गया कि उन सभी विषयों के निपटान के लिए मन्त्रालय की अपनी ही फाइलें होनी चाहिये, जो उसके सामने निपटान के लिए आये। पर यह जासान काम न था और यह ऐसी अनेक फाइलों को देखकर ही किया जा सकता था, जो कि सेना मुख्यालयों में ही उपलब्ध थी। इस संक्रमण में कुछ समय तो लगना ही था, पर आरम्भ करना भी जरूरी था। इसलिए मई, १९५२ में यह फैसला किया गया कि सभी महत्वपूर्ण मामलों में रक्षा-मन्त्रालय को अपनी अलग फाइलें रखनी चाहिये। उस समय अपनायी गयी कार्यविधि यह थी कि सेना-मुख्यालय अपने प्रस्ताव स्वतः पूर्ण टिप्पण के रूप में भेजते थे और उस विषय पर यदि उपलब्ध हुआ तो पहले का सन्दर्भ भी भेज देने थे। इस टिप्पण के प्राप्त होने पर मन्त्रालय का सम्बन्धित अनुभाग अपनी एक फाइल खोल कर जरूरी जाँच करता था। अगर मन्त्रालय को प्रस्तावित उपाय से सन्तोष होता था, और यदि मामला विद्रुत-प्रशासनिक रूप का ही होता था, तो सरकार के आदेश सीधे-सीधे सेना-मुख्यालयों के पास भेज दिये जाते थे, जो या तो एक स्वतः पूर्ण टिप्पण में, जयवा अगर मुख्यालय की कोई फाइल मन्त्रालय के पास आयी होती थी तो उस फाइल पर ही अभिलिखित करके भेजे जाते थे। अगर दूसरे मन्त्रालयों की सन्दर्भ भेजना जरूरी होता था, तो उनसे भी परामर्श किया जाता था, जो साधारणतः पृथक् मञ्चार द्वारा होता था और सभी अन्तिम निर्णय लिया जाता था। जब किस प्रस्ताव में वित्तीय आवेदन होते थे तो मन्त्रालय उस मामले की सहानुभूति के लिए वित्त-मन्त्रालय (रक्षा) के पास भिजवा देता था। दूसरी ओर अगर कोई स्वीकरण या और जानकारी अपेक्षित होती थी तो वह अलग टिप्पण भेज कर मुख्यालय ने भेगा ली जाती थी और सामान्यतः रक्षा मन्त्रालय की फाइल उनके पास न भेजी जाती थी। सेना-मुख्यालयों को मासिक में सरकार का अन्तिम निर्णय ही बताया जाता था और यह जरूरी न था कि उसके पूर्व रक्षा-मन्त्रालय और वित्त-मन्त्रालय (रक्षा) के बीच जो ब्यादेवार चर्चा चली थी, वह भी उनको बताया जाय। लेकिन किसी निर्णय पर पहुँचने के सब कारण सामान्यतः सेना-मुख्यालय को बता दिये जाते थे।

नयी कार्यविधि के प्रथम सेना-मुख्यालयों के सभी मामले रक्षा-मन्त्रालय के पास भेजे जाते थे, पर यदि मामला केवल वित्तीय होता था, जैसे कि निर्माण-कार्य के प्रावक्तकों की जाँच करना, भण्डार सँभालने के इंडेंट, बजट अनुमान आदि, जहाँ कोई नयी नीति निर्णय उत्पन्न न होती थी, तो सेना-मुख्यालय वह प्रस्ताव सीधे ही वित्त-मन्त्रालय (रक्षा) के पास भेज देने थे।

नयी पद्धति का अनिश्चय यह भी हुआ कि भारत सरकार के अन्य मन्त्रालयों, राज्य-

सरकारों आदि में प्राप्त सन्दर्भों के निपटान की रीति में भी अन्तर आ गया। पहले ऐसे सन्दर्भों या न्विक रूप में सम्बन्धित सेना-मुख्यालय के पास टिप्पणों या जर्नलों का रखाई तक के लिए भेज दिये जाते थे। नयी व्यवस्था में मन्त्रालय के अनुभाग का यह कर्तव्य हो गया कि जहाँ कहीं भी सम्भव या जरूरी हो, उस दिशा का संकेत दे दे, जिनके अनुसार वह प्रस्ताव विशेषज्ञों को जांच के लिये आगे बढ़ाये। इसके लिए उसे हर मामले में सरकार की जानी-मानी नीति को ध्यान में रखना पड़ता था या प्रयत्न उसकी प्रशासनिक-साध्यता पर विचार करना होता था।

वित्त और काम का दुहरापन मिटाने की दृष्टि से इस व्यवस्था का पुनर्विलोकन किया गया और अक्टूबर, १९५८ में कुछ और आदेश निकाले गये। इसके अनुसार किसी एक विषय पर सेना-मुख्यालय और मन्त्रालय के बीच केवल एक ही फाइल होनी चाहिये और उसमें सारे टिप्पण होने चाहिये तथा वह सर्वत पूर्ण होनी चाहिये। नीति में सम्बन्ध न रखने वाले विषयों की फाइलें सेना-मुख्यालय द्वारा पहली बार सीधे ही वित्त-मन्त्रालय (रक्षा) के पास भेज देनी चाहिये। सेना-मुख्यालयों को यह भी अधिकार दिया कि नेमी और तकनीकी स्वरूप वाले और नीति को अन्तर्गुह्य न करने वाले अनेक मामलों में वे अमेरिकी मन्त्रालयों के साथ सीधे ही पत्राचार कर सकते हैं। अप्रैल, १९५९ में सेना-मुख्यालयों और निम्नतर विरचनाओं को अतिरिक्त वित्तीय सक्तियों का भी प्रतिनिधित्व किया गया।

मन्त्रालय के अनुभागों के बीच काम के बँटवारे के बारे में भी एक महत्वपूर्ण नयी पद्धति शुरू की गयी। आरम्भ में हर अनुभाग को किसी खास शाखा या सेना सम्बन्धी काम सौंपा गया था और उन सभी मामलों में, जहाँ समग्र रक्षा-सेनाओं की ओर से दूसरे विभाग की या अन्यत्र सम्बन्धित जानकारी भ्रमणी होती थी, विशेष या प्रकीर्ण अनुभाग ही विभिन्न शाखाओं द्वारा भेजी गयी जानकारी को संकलित करना था। (अर्थात् में प्रमुख मामलों में तीनों सेनाओं के विचार या जरूरतों का समन्वय करने की कोई समस्या रक्षा-विभाग में न थी, क्योंकि सभी प्रयोजनों में व्यवहारतः यह काम करने की कोई समस्या रक्षा-विभाग में न थी। सभी प्रयोजनों से व्यवहारतः यह काम बमाडर-इन-चीफ स्वयं कर रहे थे। पर अब चूँकि तीन स्वतन्त्र सेनाओं के तीन अलग-अलग प्रमुख थे, यह मन्त्रालय का उत्तरदायित्व हो गया कि वह आदरपूर्वक करे कि यथामुम्भव सीमा तक एक समान नीति अपनायी जाय और एक सेना के बारे में लिये गये निर्णयों का प्रतिफलन अन्य सेनाओं पर न पड़े। इस उद्देश्य से मन्त्रालय के कुछ अनुभागों को कुछ ऐसे खास विषय सौंपे गये, जो सभी सेनाओं के व्यक्तियों के लिए एक समान थे। रक्षा-संगठन में नियुक्त अमेरिकी व्यक्तियों सम्बन्धी सभी मामलों में मन्त्रालय के कुछ अनुभागों को सौंपे गए।

रक्षा, उद्योग और सशस्त्र सेना सूचना-कार्यालय जैसे संगठन सीधे मन्त्रालय के ही अधीन से आये गये, नये संगठन सृष्टे किये गये, और जो संगठन पिछले रक्षा-विभाग के अधीन थे, जैसे मैरि नौम और छावनी निदेशालय, भारतीय सैनिक, नौसैनिक और वायु सैनिकों का बंड और सैन्य विनियमों और फार्मों का निदेशालय—उनको नये ढाँचे के अनुरूप नयी दिशा दी गयी। इनमें से कुछ का वर्णन या संक्षिप्त व्योरा आगे के अध्यायों में दिया गया है।



पेन्शन शाखा के काम का एक व्यौरा इसी अध्याय में आगे चलकर दे दिया गया है। युद्ध के फलस्वरूप और घर्षवर्षा-विभाग के बन्द कर देने के फलस्वरूप, जो रक्षा-विभाग के अधीन था, इस शाखा में काफी विस्तार हुआ है।

इस बात को भी ज़रूरत समझी गयी कि मन्त्रालय के अनुभागों के बीच काम का वितरण अब ज्यादा सरलता से बोधगम्य बना दिया जाय। पहले रक्षा-विभाग के अनुभागों के नाम थे—रक्षा-१, रक्षा-२ (डी-१, डी-२) आदि और युद्ध-विभाग के अनुभागों के नाम थे—युद्ध-१, युद्ध-२ (इन्फ्यू-१, इन्फ्यू-२) आदि। रक्षा-मुख्यालयों के नवागती को तत्काल यह याद रखने में कुछ समय लगता था कि प्रत्येक अनुभाग को क्या काम पिला हुआ है और किसी कार्य विशेष के लिए किस अधिकारी विशेष में सम्पर्क स्थापित किया जाय। इसलिए फरवरी, १९५१ में यह तय किया गया कि अनुभागों के नामों में स्थूल रूप में उनके द्वारा किये जाने वाले काम का संकेत मिलना चाहिये। इसलिए डी-१ अब डी (जी एस) बन गया अर्थात् यह सामान्य अमला शाखा का काम निपटाता है और डी-२ डी (नेवी) बन गया और इसी तरह अनुभागों को भी नये नाम दिये गये।

भारतीय सशस्त्र सेनायें अविभाजित भारत के आधार पर खड़ी की गयी थीं। विभाजन के कारण कार्मिकों, सामग्री, मस्यापन, प्रशिक्षण आदि में कुछ अभाव आ गये। इन सभी को अविलम्ब सुधारना था। इन पहलुओं को आगे के अध्यायों में लिया गया है।

## खण्ड-२ : वित्त-मन्त्रालय (रक्षा)

अब वित्तीय और लेखा-समठन का विवरण देना अभीष्ट है। वित्त-मन्त्रालय (रक्षा) का प्रमुख, वित्तीय सलाहकार है, जो रक्षा-व्यय की छानबीन के लिए वित्त-मन्त्री के प्रति उत्तरदायी है। यह याद रखना होगा कि १९१९-२० में बनी 'एक्स्ट-समिति' की सिफारिश के अनुसार सेना-मुख्यालय की प्रत्येक प्रमुख शाखा के साथ-साथ एक-एक उप वित्तीय सलाहकार संलग्न किया गया था। यह अब भी चल रहा है। अब भी सेना-मुख्यालय की प्रत्येक शाखा के साथ (सैन्य सचिव की शाखा को छोड़कर) नौसेना-मुख्यालय, वायुसेना-मुख्यालय, रक्षा-उत्पादन, पेन्शन और व्रत के साथ एक एक उप वित्तीय सलाहकार संलग्न है। इन वृत्तों में इन अधिकारियों की संख्या बढ़ी है। प्रमुख व्यक्तिगत-अधिकारी-समिति से भी एक उप वित्तीय सलाहकार जुड़ा है और दूसरा प्रमुख प्रति-अधिकारी-समिति से। उप वित्तीय सलाहकारों के अलावा ऊपरी स्तर पर अपर वित्तीय सलाहकार भी हैं। वित्तीय सलाहकार सरकार के अपर सचिव की हैसियत के हैं, अपर वित्तीय सलाहकार सयुक्त सचिव की हैसियत के, उप वित्तीय सलाहकार उप सचिव के, और सहायक वित्तीय सलाहकार अवर सचिव के।

सैन्य-व्यय अन्तर्ग्रस्त करने वाले सभी प्रस्तावों की जाँच करने में वित्तीय सलाहकार काफी निकट रूप से सम्बद्ध है। वह रक्षा-मन्त्रालय के साथ, प्रत्येक प्रथम में निकट का सहकार रखते हुए रक्षा-आकलनों के तैयार करने लिए उत्तरदायी है। अगस्त, १९४७ से पहले और १९५१ तक सेना-मुख्यालयों और शाखाओं द्वारा दिये गये आँकड़ों के आधार पर

वज्रट-अनुमान उप वित्तीय सलाहकार (वज्रट) द्वारा तैयार किये जाने थे : इन अनुमानों को अन्तिम रूप देने के बाद उन पर वित्तीय सलाहकार और रक्षा-सचिव के बीच चर्चा होती थी। इस काम में मन्त्रालय के किसी अन्य अनुभाग या अधिकारी को शामिल न किया जाता था। पर अब रक्षा-मन्त्रालय के उप सचिव और आरम्भिक प्रक्रम में सेनाओं और शाखाओं के अनुमानों के साथ सम्बद्ध रहते हैं। वित्तीय सलाहकार अपनी पास की सभी जानकारी सेना-मुख्यालयों के शाखा-प्रमुखों के पास भेजता रहता है, ताकि वे प्रस्तावों के निर्माण और सामान्यतः वित्तीय कार्य के निपटान के बारे में अपनी वित्तीय विम्बेवारियाँ निम्ना सकें।

१ अक्टूबर, १९५१ से सैन्य-लेखा-विभाग को नया नाम रक्षा-लेखा-विभाग दिया गया, ताकि वह विस्तृत कार्यक्षेत्र का ज्यादा विवरण दे सकें। इनका काम अब सेना, नौसेना, वायुसेना और आर्मेन्स कारखानों तक व्याप्त हो गया है। सैन्य-महालेखाकार का नया नाम रक्षा-लेखा-महानियन्त्रक रखा गया और सैन्य-लेखा-नियन्त्रक अब रक्षा-लेखा-नियन्त्रक के नाम से जाने जाते हैं। मोटे तौर पर रक्षा-लेखा-विभाग के कर्तव्य भव्य हैं—कमीशन-प्राप्त अधिकारियों और अन्य पदधारियों के वेतन-नेचे बनाये रखना, रक्षा-व्यय की आन्तरिक लेखा-परीक्षा, सशस्त्र सेनाओं सम्बन्धी सभी व्ययों का मुपतान और लेखा रखना, जिसमें दी गयी पूर्तियों और की गयी सेवाओं और वेतन, भत्ते, पेन्शन और प्रकीर्ण व्यय के दायक (विन) भी शामिल हैं। यह विभिन्न यूनिटों और विरचनाओं द्वारा दिये जाने वाले भण्डार-लेखाओं की और आर्मेन्स कारखानों और नौसेना गोदी-प्रापण के भण्डार और निर्माण-लेखाओं की लेखा-परीक्षा के लिए भी उत्तरदायी है। रक्षा-लेखाओं के नियन्त्रक, कमानों के जनरल अफसर कमांडिंग-इन-चीफ और एरिया कमानों तथा अन्य के स्थानीय वित्तीय सलाहकार के रूप में भी काम करते हैं।

सेना में प्रत्येक कमान के लिए एक रक्षा-लेखा-नियन्त्रक भी होता है। साथ ही नीचे लिखे रक्षा-लेखा-नियन्त्रक भी होते हैं—

रक्षा-लेखा-नियन्त्रक (पेन्शन), इलाहाबाद। रक्षा-लेखा-नियन्त्रक (कारखाना) कलकत्ता। रक्षा-लेखा-नियन्त्रक (अधिकारी) पूना, जो सेना के कमीशन-प्राप्त अधिकारियों के वेतन का काम संभालते हैं और उसको लेखायें रखते हैं। रक्षा-लेखा-नियन्त्रक (अन्य पद) जो पहले सिकन्दरवाद में थे और अब मेमूर में हैं और सेना के अन्य पदधारियों के वेतन-भत्तों का काम संभालते हैं और उसको लेखायें रखते हैं। रक्षा-लेखा-नियन्त्रक (नौसेना) बम्बई। रक्षा-लेखा-नियन्त्रक (वायु सेना) देहली, और रक्षा-लेखा-नियन्त्रक (निर्माण) को केन्द्रित रूप से कमानों की प्रतियों और व्यय का अखिल भारतीय सफेकित सङ्ग्रह एक मध्य पद्धति पर रखते हैं। साथ ही पूरे देश में स्थानीय वेतन-नेचा-अधिकारी भी होते हैं, जो रेजीमेंट केन्द्रों और डिपो के निवट सहाकार से काम करते हैं।

## खण्ड-३ रक्षा-मन्त्रालय की पेन्शन-शाखा (१९४५-४६)

दूसरे विश्वयुद्ध के अन्त को और रक्षा-संगठन के सामने आने वाली प्रमुख समस्याओं में से एक समस्या सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों और उनके आश्रितों के क्रमशः निर्भोग्यता और परिवार-पेन्शन के दावों का निपटान करना था, जो युद्ध काल में निर्भोग्यता या मृत्यु के कारण पैदा हुए थे। इन दावों का निपटान करने के लिए युद्ध-विभाग में एक विशेष शाखा खोलनी पड़ी, जो जगते चल कर काफी बड़ गयी। यह शाखा और रक्षा-सेवाओं के असेनिक कर्मचारियों के अमाधारण बोट और परिवार-पेन्शन के दावों को भी निपटाती थी। सत्ता-हस्तांतरण के बाद कुछ वर्ष तक इस काम को काफी प्राथमिकता दी गयी, क्योंकि मुपात्र दावेशारों को वित्तीय सहायता देने में वित्त-मन्त्र का मतलब या वित्तीय सहायता देने से इनकार कर देना। दावों का निपटान हो जाने पर पेन्शन-शाखा का आकार कम होता गया, जब तक कि अन्त में बचे हुए धोड़े से अनुभाग रक्षा-मन्त्रालय के साथ विलीन न कर दिये गये।

निर्भोग्यता पेन्शन का दावा तभी पेश किया जा सकता था, जब सशस्त्र सेनाओं के किसी सदस्य को सैन्य-सेवा के कारण ऐसी कुछ निर्भोग्यता सहनी पड़ी हो। परिवार-पेन्शन का दावा सब उठना है, जब सशस्त्र सेनाओं के किसी सेवारत सदस्य की मृत्यु का सीधा कारण उसकी सैन्य-सेवा रही हो। सामान्य शान्ति काल में ऐसे दावे बहुत ही कम होते हैं, दूसरे महायुद्ध से पहले वायसराय कमीशन-प्राप्त अधिकारियों और भारतीय अन्य पदों (और अन्य दो सेनाओं के समकक्ष पदों) के सभी पेन्शन-दावों का निपटान सैन्य-सेवा-विभाग की प्राथमिक जिम्मेवारी थी। सेना के लिए यह काम सैन्य-सेवा-नियन्त्रक (पेन्शन), साहौर करते थे। इस अधिकारी को पूरी शक्ति थी कि इन मामलों को स्वीकार कर दे या अस्वीकार, और वह केवल सन्दिग्ध और कठिन मामलों को ही सरकार के आदेश प्राप्त करने के लिए सेना-मुख्यालय की एडमिनिस्ट्रेशनल जनरल की शाखा में भेजता था। नौसेना और वायुसेना में तत्समाचारी अधिकारी नौसेना-सेवा-नियन्त्रक, बम्बई और वायुसेना-सेवा-नियन्त्रक, देहरादून थे। तीनों सेनाओं के कमीशन-प्राप्त अधिकारियों के सभी मामलों पर भारत सरकार के आदेश जरूरी होने थे, पर पेन्शनो का वितरण वस्तुतः सम्प्रति नियन्त्रको द्वारा ही किया जाता था। तब तक कोई निर्भोग्यता या परिवार-पेन्शन नहीं दी जाती थी, जब तक कि नि सन्दिग्ध रूप से यह निश्चय न कर दिया जाय कि निर्भोग्यता या मृत्यु का कारण निश्चय ही उस व्यक्ति की सैन्य-सेवा ही थी। इसलिये अधिकतर मामले अस्वीकृत हो सकते थे।

विश्वयुद्ध छिड़ जाने के बाद भारत सरकार ने १९४१ में यह फैसला किया कि नियन्त्रक किसी भी मामले को स्वयं अस्वीकार न कर दें। अगर उनकी सन्तोष हो जाय तो वे दावा स्वीकार कर सकते हैं या उनको निपटान के लिए सेना-मुख्यालय के पास भेज सकते हैं। १९४६ में इंग्लैन्ड के पेन्शन-मन्त्रालय द्वारा अपनाये गये चलन के अनुसार भारत सरकार ने एक और भी उदार रवैया सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों के हत्या होने के कारण निर्भोग्यता और परिवार-पेन्शन के दावों के बारे में अपनाया। सरकार ने यह स्थिति मानी कि व्यक्ति की सेवा के कारण उसके स्वास्थ्य के गिरने के लिए उसको (और उसकी मृत्यु की स्थिति में

उसके परिवार को) तब तक क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिये, जब तक युक्तिसंगत सन्देह के बिना यह सिद्ध न हो जाय कि इस दुर्भाग्यपूर्ण दशा के नाने में उस व्यक्ति को युद्ध-मेवा का कोई भी हाथ नहीं है। इस प्रकार यह सिद्ध करने का भार भी सरकार पर आ पड़ा कि मृत्यु सैन्य-सेवा के कारण नहीं हुई अथवा नियोग्यता इसके कारण नहीं पैदा हुई या नहीं बढ़ी। किसी भी युक्तिसंगत सन्देह का लाभ दावेदार व्यक्ति को दिया जाता था। यह निर्णय और इस बात से कि युद्ध काल में भारतीय सशस्त्र सेनाओं की संख्या २० लाख से ऊपर हो गयी थी और हताहतों की संख्या में भी वृद्धि हुई थी, स्वभावतः नियोग्यता और परिवार-पेंशनो के दावे कई लाख तक पहुँच गये।

नये नियमों के गुरु हो जाने के बाद पेंशन के मामलों के निपटान में एक प्रकार की अर्ध-न्यायिक रीति अपनायी पड़ी। अब नियन्त्रक केवल वस्तुतः सीधे-साफ मामलों को ही मंजूर करते थे और बाकी निर्णय के लिए उच्च अधिकारियों के पास भिजवा देने थे। नयी प्रक्रिया के फलस्वरूप एडजुटेंट जनरल की शाखा में भारी मात्रा में शेष काम इकट्ठा हो गया, उनको युद्ध-विभाग से सलाह लेनी पड़ती थी। दावों की बाढ़ के निपटान में लिए युद्धपूर्व का संगठन बिल्कुल असमर्थ था और यह स्पष्ट हो गया था कि सैन्य-लेखा-नियन्त्रक (पेंशन) के कर्मचारियों में वृद्धि करने के अलावा, युद्ध-विभाग में एक बिल्कुल नयी शाखा सभी शेष दावों का इस रीति से निपटान करने के लिए खोनी जानी चाहिये कि निपटान राज्य और दावेदारों दोनों के लिए ही सन्तोषप्रद हो। तदनुसार अप्रैल, १९४५ में युद्ध-विभाग की पेंशन-शाखा की स्थापना की गयी।

पेंशनो के दावों के निपटान के लिए एक ब्यौरेवार कार्यविधि तय की गयी, जो बहुत कुछ इंग्लैंड के पेंशन-मन्त्रालय के चलन पर आधारित थी और जिसमें भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन कर लिया गया था। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में नियोग्यता और परिवार-पेंशनो के सभी दावे पेंशन-मन्त्रालय के पास भेज दिये जाया करते थे। इधर भारत में कमीशन-पद से नीचे वाले सभी सैनिक व्यक्तियों के ऐसी पेंशनो के दावे हमेशा से सैन्य-लेखा-नियन्त्रक (पेंशन) और अन्य दोनों सेनाओं में उनके समस्त नियन्त्रक निपटाने वाले आ रहे थे। इन दावों का निर्णय करने के लिए नये नियम शुरू होने के बाद भी, अनुभव में यह पाया गया कि सरल मामले निर्णयार्थ नियन्त्रक के ही ऊपर छोड़ दिये जाने चाहिये। सम्झनी मामलों में, जो कि ऐसे दावों के निपटान में हमेशा खड़े होते हैं—अपने कार्यालय में तैनात कुछ विशेषज्ञ डाक्टरों में सहायता ले सकते हैं। इसलिए रक्षा-मन्त्रालय की पेंशन शाखा कुछ ज्यादा जटिल मामलों को निपटाती रही, जो नियन्त्रक द्वारा सरकार के स्तर पर निर्णयार्थ भेजे जाते थे, और शेष दावों का निपटान स्वयं करते रहे। अपनी स्थापना के समय इस शाखा ने नियोग्यता और परिवार-पेंशनो के लगभग ३७,००० से ऊपर दावे हाथ में सम्भाले, जो कि एडजुटेंट जनरल की शाखा में इकट्ठे हो गये थे। पेंशन-शाखा को ये काम करने थे (क) नये नियमों के अधीन उन बहुत सारे मामलों का पुनर्विलोकन करना जहाँ नियन्त्रक ने पिछले नियमों के अधीन दावे अस्वीकार कर दिये थे (ख) उन सभी कठिन और सन्दिग्ध मामलों का निपटान करना, जो नियन्त्रक स्वयं नहीं कर सके थे, और (ग) नियन्त्रक के और सरकार के निर्णयों के विरुद्ध

असतुष्ट दावेदारों को सभी अपीलों की जाँच करना ।

यह शाखा सचिवालय की पद्धति से गठित की गयी, जिसमें सम्युक्त सचिव के प्रभार के अग्रीन उस सचिव और अवसर या सहायक सचिव रहते गये । जब दावे संगत-सेवा और चिकित्सा दस्तावेजों के साथ पेन्शन शाखा में पहुँचते थे, तो पहला कार्य कागजों की पड़ताल करना होता था और अनेक मामलों में यह पाया गया कि और अधिक तथ्य या कागज माँगना जरूरी है । दावों का निपटान इस कारण और भी हो गया कि अनेक मामलों में सेवा और चिकित्सा के दस्तावेज अपर्याप्त थे, जो युद्ध-कालीन कठिनाई के बीच तैयार स्थिते गये थे । निर्णायक प्रश्न यह था कि जिस आधार पर दावा पेश किया गया है, वह नियोज्यता या मृत्यु का कारण उस व्यक्ति की युद्ध सेवा के कारण घटित हुआ है या बड़ा है । यह किसी भी तरह साधारण मामला न था । पेन्शन-शाखा के अधिकारियों को किमी निर्णय पर पहुँचने में मदद देने के लिये, अनेक सैन्य चिकित्सा-अधिकारी भी थे, जिनकी सलाह दावे के विशुद्ध चिकित्सकीय पक्ष के बारे में ली जाती थी । पेन्शन के भुगतान को अन्तर्प्रभु करने वाले मामले वित्त-मन्त्रालय (रक्षा) से परामर्श करके निर्णय लिये जाते थे ।

भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को नियोज्यता और परिवार पेन्शनों के दावों पर, सरकारी निर्णय के विरुद्ध, एक स्वतन्त्र निकाय के पास अपील करने का भी अवसर दिया जाता था । इसके लिए दो भिन्न प्रकार के न्यायाधिकरण बनाये गये, अर्थात् अधिकार अपील न्यायाधिकरण और निर्धारण अपील न्यायाधिकरण । एक केन्द्रीय अपील न्यायाधिकरण भी था, जो अन्तिम अपीलीय प्राधिकार था । प्रत्येक अधिकार अपील-न्यायाधिकरण का समारति एक सुप्रसिद्ध वकील होता था और उसमें एक वारिष्ठ चिकित्सा अधिकारी और एक सेना अधिकारी भी रहते थे । इसका कार्य था कि इस प्रश्न का निपटान करे कि किमी व्यक्ति की नियोज्यता या मृत्यु का कारण क्या उसकी युद्ध-सेवा थी और साथ ही ऐसे गौण मामले भी निपटारते कि क्या उस व्यक्ति को पेन्शन उसकी सापरबाही, रुदाधार आदि के कारण ठीक ही कम की गयी है ।

निर्धारण अपील न्यायाधिकार का सम्बन्ध इस प्रश्न से था कि क्या किमी व्यक्ति की नियोज्यता की सीमा (जो प्रतिशत में व्यक्त की जाती थी) के बारे में सरकार का निर्णय सही था । अपने काम के स्वरूप के अनुसार ही ऐसे प्रत्येक न्यायाधिकरण में दो चिकित्सा अधिकारी होते थे, जिनमें से एक अध्यक्ष होता था और दूसरा सेना-सदस्य । अधिकार अपील-न्यायाधिकरण का निर्णय हमेशा के लिए उसके समक्ष आये सभी वादों का समाधान कर देता था । किन्तु निर्धारण अपील न्यायाधिकरण के मामले में ऐसी बातें न थी, क्योंकि व्यक्ति की नियोज्यता की मात्रा समय-समय पर कमोबेश होती रहती है और तदनुसार नियोज्यता के निर्धारण सम्बन्धी निर्णय तब तक बार-बार देने पड़ सकते हैं, जब तक कि नियोज्यता अन्तिम स्थिति को पार न कर जाय ।

आरम्भ में तो मामलों के भारी ढेर को यथासम्भव तेजी के साथ निपटाना पड़ा, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्य पेन्शन कम से कम विलम्ब करके दी जा सके । अपने प्रथम निर्णय के

विवाद अपील प्राप्त होने पर, पेन्शन-शाखा पूरे मामले की पुन जांच करती थी और जहाँ जरूरी होता था, निर्णय को बदल देती थी और दावेदार को नये निर्णय की सूचना दे देती थी। पर अगर मामले के सभी पक्षों की जांच के बाद, सरकार का अब भी यही निर्णय होता था कि मूल निर्णय ठीक था, तो वह अपील पेन्शन अरील न्यायाधिकरण के पास अन्तिम निर्णय के लिए भेज दी जाती थी और साथ ही दावे से सम्बन्धित सग्त तथ्य भी, जिनमें सरकार के बिजिलिया सनाहकारों को सलाह और सरकार का दृष्टिकोण भी शामिल होता था। इसके बाद न्यायाधिकरण उस अपील का अद्वैत-न्यायिक आचार पर निपटाती थी। दावेदार सरकारी खर्च पर स्वयं न्यायाधिकरण के सामने पेज हो सकता था या अपनी ओर से तर्क देने के लिए किसी को नामित कर सकता था। सरकार के प्रतिनिधि भी सरकार की ओर से मामले के तर्क देने के लिए न्यायाधिकरण के सामने उपस्थित रहते थे। सरकार उन मामलों को छोड़कर न्यायाधिकरण का निर्णय मान लेती थी, जिनमें यह समझा जाता था कि निर्णय नियमानुसूल नहीं है। ऐसे मामलों में केन्द्रीय अपील न्यायाधिकरण के सामने दूसरी अपील की जाती थी, जिसमें बिधि-मन्त्रालय द्वारा नियुक्त एक ही सदस्य होता था। दावेदार को भी विकल्प मिला हुआ था कि पेन्शन अपील न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध चाहे वो केन्द्रीय अपील-न्यायाधिकरण के सामने अपील कर सकता था। यह बता दिया जाय कि अधिकार को जो कुल अपीलें आती थीं, उनमें से २५ प्रतिशत सरकार द्वारा मन्त्रालय में पुनर्विचार के समय मान ली जाती थी और शेष में से कुल ६ प्रतिशत ही न्यायाधिकरणों द्वारा मानी जाती थी।

विभाजन से पहले पेन्शन-शाखा अविभाजित सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों के बारे में पेन्शन-दावों का निपटान करती थी। विभाजन के समय भारत सरकार ने ऐसे सभी मामलों में पेन्शन के खर्च का प्रथम उत्तरदायित्व मान लिया, जिनमें फ़ैसला १५ अगस्त, १९४७ से पहले हो चुका था, भले ही दावेदार भारत का नागरिक हो या पाकिस्तान का। तदनुसार पेन्शन शाखा ऐसे सभी विभाजन-पूर्व के दावों का निपटान करती रही। इसके फलस्वरूप पेन्शन अपील न्यायाधिकरणों में से दो का, भारत सरकार के निर्णयों के विरुद्ध, पाकिस्तान के नागरिकों के दावों की मुनवाई करने का काम सौंपा गया। इनमें से एक न्यायाधिकरण प्रायः एक वर्ष तक लाहौर में काम करता रहा, पर चूंकि पाकिस्तान इन न्यायाधिकरणों के लिए आवास को व्यवस्था न कर सका, इसलिए फिर इनको अपना काम भारत से खतावा पड़ा। फिर भी, इन्होंने पाकिस्तान के नागरिकों के दावों के समुचित निपटान पर किसी तरह से कोई प्रभाव न डाला।

विस्तार की परम सीमा के समय (१९४८) पेन्शन-शाखा के कर्मचारियों की संख्या मुख्य मन्त्रालय के कर्मचारियों से भी ज्यादा हो गयी थी। १९४९ से इस शाखा के कर्मचारियों में धीरे-धीरे कमी होती गयी और १ अप्रैल, १९५१ को छेप रहे केवल चार अनुभागों को मुख्य मन्त्रालय में विलीन कर दिया गया और पेन्शन-शाखा का अलग अस्तित्व न रहा। बाद में इन चार में से भी दो अनुभाग और खत्म कर दिये गये और इस तरह हुनादवों के पेन्शन का काम निपटान करने के लिए केवल दो ही अनुभाग छेप रहे गये।

युद्ध-पेंशन दावों सम्बन्धी काम १९७३ तक प्रायः पूरा हो गया था। अब पेंशन अनुभाग त्रिन दावों पर विचार कर रहे थे, उनका सम्बन्ध मुख्यतः युद्धोत्तर इनाहनों में था। यह काम कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि हज़ाहत कभी भी हो सकते हैं और नये दावे आ सकते हैं। पेंशन-शाखा द्वारा पूरे किये गये काम की भारी मात्रा का अन्दाज़ इस तथ्य से किया जा सकता है कि १ जनवरी, १९५७ तक इसने १,१६,५१६ दावों का निपटारा किया था। शेष केवल १८४ दावे ही रहे थे। उक्त तारीख तक ४७,२११ अधिकार अपीलों और २४०६१ निर्धारण अपीलों को भी निपटाया गया था। शेष क्रमशः १८१ और ५४ ही रही थी। पेंशन अपील न्यायाधिकरणों में २०,१५८ अधिकार अपीलों पर और १३,७६८ निर्धारण अपीलों पर न्याय-निर्णय दिये। केन्द्रीय अपील-न्यायाधिकरण में पेंशन अपील न्यायाधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध की गयी १८८४ अपीलों पर न्यायनिर्णय दिये।

जनवरी, १९४७ में सितम्बर, १९५४ तक समय-समय पर एक केन्द्रीय न्यायाधिकरण (नयी दिल्ली में), ५ अधिकार अपील न्यायाधिकरण (दो सलनऊ में और एक-एक मद्रास, दिल्ली और जालन्धर में), और २ निर्धारण-न्यायाधिकरण (दिल्ली और पुना में) काम करते रहे।

१९५१ में नियोग्यता-निर्धारण के विरुद्ध अपील करने का अधिकार १ मई १९५० को या उसके बाद दिये गये निर्णयों के बारे में वापस ले लिया गया। इसी तरह नियोग्यता या परिवार-पेंशन के अधिकार के विरुद्ध अधिकार न्यायाधिकरण में अपील करने का अधिकार भी ३१ सितम्बर १९५३ के बाद किये गये निर्णयों के बारे में वापस ले लिया। इन निर्णयों और न्यायाधिकरणों को खत्म कर देने का कारण यह था कि समय बीतते-बीतते अपीलों की संख्या बहुत कम हो गयी थी और अब थोड़े से खालू मामलों के बारे में सेना के किसी सदस्य की नियोग्यता या मृत्यु १९३९ से १९४६ के बीच की गयी युद्ध-सेवा से सम्बन्धित न थी, इसलिए पार्ष्वी अपील-स्थवस्था बनाये रखना उपयुक्त न रह गया था। १५ जनवरी, १९५४ को या इसके बाद (जिस तारीख तक की अपीलों न्यायाधिकरणों द्वारा निपटायी जा चुकी थी) सशस्त्र सेनाओं के भूतपूर्व सदस्यों या उनके आश्रितों द्वारा पेंशन मजूर करने वाले अधिकारियों के निर्णय के विरुद्ध, युद्ध या युद्धोत्तर सेवा के सम्बन्ध में जो भी अपीलों दायर की गयी, उसके बाद उन पर भारत सरकार द्वारा ही उनके गुण दोषानुसार विचार किया जाता था। जब कभी भी मामले के पुनर्विलोकन से यह उचित ठहरता था तो जिस निर्णय के विरुद्ध अपील की जाती थी, उसे बदल दिया जाता था। यह पेंशन अपील न्यायाधिकरण बनाये जाने से पहले के चलन के अनुसार ही था। पर बाद में सरकार से यह अनुरोध किया गया कि न्यायाधिकरण खत्म कर देने के बाद जब मन्त्रालय में किये गये निर्णयों के पुनर्विलोकन के लिए कोई तन्त्र नहीं रह गया है। तदनुसार अक्टूबर, १९५८ में रक्षा-मन्त्री की पेंशन संबंधी अपीलवीय समिति बनायी गयी, जिसके अध्यक्ष रक्षा-मन्त्री थे और रक्षा-उत्पादन-मन्त्री, रक्षा-सचिव, तीनों सेना-प्रमुख, वित्तीय सलाहकार (रक्षा), सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के महा-निदेशक और अपील-कर्ता से सम्बन्धित सेना से भिन्न किसी सेना का एक जून एडमिरल जनरल

इसके सदस्य हैं। यह समिति सशस्त्र सेनाओं के व्यक्तियों के नियोग्यता और परिवार पेन्शनों से सम्बन्धित अमीतों पर विचार करती है। मन्त्रि-मण्डल सचिवालय (सैन्य स्कन्ध) इस समिति के लिए सचिवालय को व्यवस्था करता है।

#### खण्ड ४ चर्च सम्बन्धी कार्यकलाप का समेटा जाना

रक्षा के आसपास गवर्नर जनरल स्वयंसेवक से चर्च सम्बन्धी कार्यों को भी प्रशासित करते थे। यह काम रक्षा-विभाग को सौंपा गया था। १५ अगस्त, १९४७ के बाद चर्च-सम्बन्धी कार्य का प्रशासन समाप्त कर दिया गया।

शुरु में चर्च-कार्य सम्बन्धी खर्च भारतीय राजस्व से करना इस आधार पर पर उचित ठहराया गया था कि देश में काफी अग्रेज है, जो अपने देश से आकर राज्य की सेवा कर रहे हैं। उनके देश में प्रायः हर गांव में चर्च होते हैं और ईसाई-धर्म के पुरोधा भी—और भारत जैसे देश में धार्मिक, जहाँ ये चीजें पहले तो बिल्कुल ही न थी। ठीक दिया गया कि जब तक राज्य धार्मिक-सुविधायें न दे, भारत के यूरोपीय ईसाइयों को ये सुविधाएँ कहीं न मिल पायेंगी। इस तरह भारत सरकार का यह सविहित दायित्व बन गया कि राज्य के खर्च पर धर्म सम्बन्धी व्यवस्था यूरोपीयों को उस कोटि के लिए की जाय, जिन्हे 'पात्र व्यक्ति' माना गया। सरकारी क्षेत्र में इस शब्द का अर्थ था (क) ब्रिटेन में जन्मे यूरोपीय अधिकारी और सशस्त्र सेनाओं के जवान, ब्रिटिश और भारतीय दोनों ही यूनिटों में, (ख) ब्रिटेन में जन्मे वे यूरोपीय व्यक्ति जो भारत में सप्ताह की सेवा में हैं, (ग) यूरोपीय उद्भव के राज्य-नेतृत्व-कर्मचारी, और (घ) उक्त के परिवार। इस दायित्व का निर्वहन इस आधार पर किया जाता था कि जिस किसी भी जगह पर एक तबके के २५ 'पात्र' व्यक्ति हों, तो सरकार पूर्णतः या अथवा उस तबके के लिए सरकारी या सहायक-अनुदान पर एक 'चैपलेन' (पुरोधा) को व्यवस्था करेगी। भारत सरकार का यह भी दायित्व था कि इन 'पात्र व्यक्तियों' के लिए कत्रगाह भी बनाये और उनका सम्भारण करे।

जिस मूल अनुमान के आधार पर राज्य ने यह दायित्व उठाया था, अर्थात् सरकार की नौकरी में लगे यूरोपीयों के लिए भारत में ईसाई धर्म के पालन के लिए सुविधाओं का अभाव, उसका क्रमशः कोई स्थान नहीं रहा। लगभग सौ साल में भारतीय ईसाई और ईसाई-चर्च अपने निजी संगठन के साथ देश में काफी सख्या में फैल-गये। इसको मान्यता देते हुए कहा गया कि भारत सरकार की यह मान्यता हुई नीति है कि 'चर्च सम्बन्धी कार्य' शीर्ष के अग्रीन खर्च धीरे-धीरे कम किया जाय। भारत सरकार अधिनियम, १९३५ में यह व्यवस्था की गयी कि चर्च सम्बन्धी कार्यों का वार्षिक खर्च, पेन्शन-व्यय को छोड़कर ४२ लाख रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिये।

भारत सरकार में भी चर्च-कार्य सम्बन्धी काम कुछ समय तक एक के बाद दूसरे विभाग को सौंपा जाता रहा और अन्त में उसे सेवा (बाद में रक्षा) विभाग को सौंपा गया, जिसका प्रत्यक्ष कारण यह था कि 'पात्र व्यक्ति' अधिकतम सख्या में सशस्त्र सेनाओं में ही थे।



चर्च कार्य सम्बन्धी कुछ खर्च सिविल, रेलवे और रक्षा अनुमानों के बीच उन आवण्टन नियमों के अनुसार बाँट दिया गया, जो प्रत्येक वर्ष में पात्र-व्यक्तियों की संख्या के आधार पर बनाये गये थे। खर्च इन चीजों पर होता था (१) चैप्लेन (२) स्थापना (अर्थात् चैप्लेन के लिए और चर्च और कर्मग्राह के कर्मचारी) और आकस्मिकताएँ (३) विभिन्न चर्च अधिकारियों को सहायक अनुदान (४) चर्च और कर्मग्राहों को व्यवस्था और सम्भारण। १९४७-१९४८ में चर्चकार्यों पर कुल खर्च, पेन्शन-व्यय के अन्तर्गत, ३६.५८ लाख रुपये था। इसमें से उक्त चारों शीर्षों का खर्च क्रमशः इस प्रकार था १४.८१ लाख, ६.६८ लाख, ८.२० लाख और ६.१९ लाख।

सत्ता-हस्तान्तरण के बाद 'पात्र' व्यक्तियों को धर्म-मुक्तिदा देने का भारत सरकार का संविहित दायित्व समाप्त हो गया। भारत सरकार ने धर्म-कार्य समाप्त करने का निर्णय पाकिस्तान सरकार के साथ-साथ लिया।

(१) भारतीय चर्च-कार्य स्थापना एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट-सेवा थी। समेटने के समय इसके सेवा में १०७ चैप्लेन थे, जिनमें से ६६ भारत, बर्मा और श्रीलङ्का के चर्च के थे (जिनकी स्थापना भारतीय चर्च अभिनियम, १९२७ के अधिन को गयी थी) और ८ स्काट-लेण्ड के चर्च के थे। तर्कमग्न रूप से इन सभी की सेवाएँ १५ अगस्त, १९४७ को ही समाप्त हो जानी चाहिये थी। फिर भी यह दृष्टि अपनाई गई कि अने ही ब्रिटिश फौज की संख्या कम होती जाय, वे निष्क्रमण की प्रक्रिया में उक्त तारोक्ष के बाद भी बने रहेंगे। इसलिए यह तय किया कि कुछ चैप्लेन की सेवाएँ ३१ दिसम्बर, १९४७ तक रखी जाएँ। १५ अगस्त, १९४७ से ७५ प्रतिशत चैप्लेन की सेवाएँ समाप्त कर दी गयी और शेष की १ जनवरी, १९४८ में। भारतीय चर्च-कार्य-स्थापना सम्बन्धी खर्च १ जनवरी, १९४८ से खत्म हो गया, केवल इस स्थापना के चैप्लेन को दुग्धोत्पन्न और पशुधन के भुगतान का खर्च ही रह गया।

(२) चैप्लेन की संविहित सेवा बनाये रखने के अन्तर्गत भारत सरकार, कुछ तबकों के चर्च अधिकारियों को ऐसी जगहों पर वेपनेन की व्यवस्था के लिए, जहाँ पूजा-कार्य के लिए स्थापना के चैप्लेन उपस्थित न थे, और खर्च आदि के पर्यवेक्षण के कार्य के लिए भी, कुछ वार्षिक सहायक-अनुदान दिया करती थी। ऐसे अनुदान भारत, बर्मा और श्रीलङ्का के चर्च, स्काटलेण्ड के चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च, मैथडिस्ट चर्च और यूनाइटेड चर्च को दिये जाते थे। वस्तुतः चर्च-आधिकार वाल-निर्भर न थे और वास्तव में सरकारी सहायता के अन्तर्गत हो गये थे। वह बात बत आग्रह के साथ कही गयी कि १५ अगस्त, १९४७ को यह सहायता एकदम दण्ड कर देने से बड़ी मुश्किल में पड़ जायेंगे। चर्च-अधिकारियों को इस कठिनाई का सामना करने में समय बनाने के लिए ११-२७ लाख रुपये का अन्तिम एक मुश्त सहायक-अनुदान (जो वार्षिक भुगतान से कुछ ज्यादा ही था) उनको दिया गया। इस बारे में सरकार ने वस्तुतः अपने दायित्व का अधिक दृष्टिकोण न अपना कर उदार दृष्टिकोण अपनाया।

(३) चैप्लेन, चर्च और कर्मग्राहों से सतत कर्मचारी अधिकारियों अस्थापित और अस्थायिक थे। चर्च-कार्य विभाग १ अप्रैल, १९४८ में समाप्त होने पर उनकी सेवाएँ भी

समाप्त कर दी गयी। जो थोड़े से लोग स्थायी और पूर्णकालिक आधार पर थे, उनकी सेवायें भी इसी तारीख से आनुषांगिक पैनल देकर समाप्त कर दी गयी।

(८) १ अप्रैल, १९४८ को चर्च, सम्बन्धित चर्च-अधिकारियों को, हस्तान्तरित कर दिये गये। इसी तरह कश्गाह भी, सन्धारण के लिए, भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त को, हस्तान्तरित कर दिये गये। इस तरह भारत सरकार ने ३ अप्रैल, १९४८ से चर्चों और कश्गाहों के सन्धारण के सारे दायित्व का परित्याग कर दिया।

चर्च-कार्य-विभाग के समाप्त हो जाने पर भारत सरकार ने राज्य के चर्च पर धर्म-पूजा-कार्य को राज्य के एक कृत्य के रूप में मान्यता देना बन्द कर दिया और भारत निश्चय ही एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बन गया।

### खण्ड—५ सचिवालय में संगठन सम्बन्धी परिवर्तन

रक्षा सम्बन्धी जहरतो में आत्मनिर्भरता के प्रयास को बढ़ाने के लिए रक्षा-मन्त्रालय में मई, १९५७ में एक अवर सचिव की नियुक्ति की गयी। रक्षा-उत्पादन को दिये गये महत्व को मई, १९६२ में रक्षा-मन्त्री की मदद के लिए एक रक्षा-उत्पादन-मन्त्री की नियुक्ति करके और भी मान्यता दी गयी। विद्यमान रक्षा-यूनिटों में उत्पादन का काम बड़ाकर, नये कारखाने स्थापित करके ( उदारहणन मध्याकार टैंक, ३ टन और १ टन की गाड़ियाँ आदि बनाने के लिए ) और वर्कशॉप हाथ में लेकर, ओ मन्त्रालय के प्रशासन के अधीन लोक-उपक्रम बन गये, रक्षा-उत्पादन सम्बन्धी जिम्मेवारी बहुत उषादा बढ गयी। फिर नवम्बर, १९६२ में रक्षा-मन्त्रालय में एक अलग रक्षा-उत्पादन-विभाग बनाया गया, जिसके लिए एक अलग शासन-सचिव की नियुक्ति की गयी।

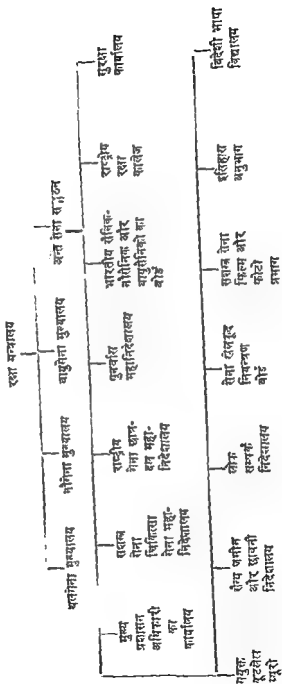
अक्तूबर, १९६२ के चीनी हमले, और फनस्वरूप देश की रक्षा सम्भाव्यताओं को बना कर रखने के निर्णय के कारण, रक्षा-मन्त्रालय सचिवालय और सशस्त्र सेना-मुख्यालयों में कुछ विस्तार अनिवार्य हो गया।

सितम्बर, १९६५ में पाकिस्तान से हुए युद्ध के समय, विदेश से पूर्ति बन्द हो जाने से, रक्षा-सामग्री के बारे में देश के आत्म-निर्भर हो जाने की अविनम्वनीय और अनिवार्य जरूरत स्पष्ट हो गयी। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए ज्यादा तेज कदम उठाने के लिए, और लोक और निजी क्षेत्रों के उद्योगों के साथ निकट सम्पर्क रखने के लिए, रक्षा-मन्त्रालय में नवम्बर, १९६५ में एक रक्षा-पूर्ति विभाग-की स्थापना की गयी, जिसका एक अलग शासन-सचिव बनाया गया। गृह-कार्य-मन्त्रालय में मन्त्री ने इस नवनिर्मित विभाग का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया। अधिक आयोजना और रक्षा आयोजना के बीच निकट सम्बन्ध रखने की दृष्टि से, नवम्बर, १९६५ में रक्षा-मन्त्रालय में एक अवर सचिव के अधीन आयोजना-कक्ष बनाया गया। रक्षा-उत्पादन-विभाग और रक्षा-पूर्ति-विभाग मध्ये रक्षा मन्त्रालय के संगठन की रूपरेखा सलग आरेखों में दी गयी है।

आरेख—१३

रक्षा मन्त्रालय के अधीन सेना मुख्यालय और अन्तर्गत सेना सत्राटन

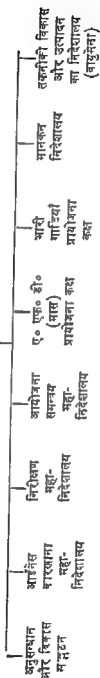
(रक्षा उत्पादन विभाग के अलावा)



## भारत— १५

## रक्षा उत्पादन विभाग के सत्वन्ध कार्यालय

## रक्षा उत्पादन विभाग



## थलसेना, नौसेना और वायुसेना-मुख्यालय और निम्न विरचनाये

मत्ता-हस्तान्तरण से पहले सशस्त्र सेनाओं के सभी वरिष्ठ पदों पर, मुख्यालयों और कमानों में भी, ब्रिटिश अधिकारी हो आये थे । १५ अगस्त, १९४७ में भारत के कमांडर-इन-चीफ सशस्त्र सेनाओं के पुनर्गठन के लिए भुप्रोम कमांडर बन गये और अविभाजित भारत के विद्यमान सामान्य-मुख्यालय, नौसेना-मुख्यालय और वायुसेना-मुख्यालय उनके कार्यालय हो गये । तीनों सेनाओं के कमांडर इन-चीफ का पद समाप्त कर दिया गया और प्रत्येक सेना के लिए एक स्वतन्त्र प्रमुख रखने का निर्णय किया गया । इसलिए तीनों सेनाओं के लिए नये प्रमुखों का चुनाव करना था । रक्षा-मुख्यालयों और कमानों में भी दूसरी वरिष्ठ नियुक्तियाँ होनी थी, क्योंकि अधिकांश सैनिक और अनेक ब्रिटिश अधिकारियों ने सेवा में निवृत्त होने का चुनाव किया था और कुछ ने पाकिस्तान में सेवा करने का भी विकल्प दिया था । इस तरह हालाँकि विभाजन सम्बन्धी काम को उच्चतम प्राथमिकता दी गयी, फिर भी साथ-साथ १५ अगस्त, १९४७ से नया टाका सारा करने की ओर भी ध्यान देना था ।

सेना मुख्यालयों की आदत पट चुकी थी कि सभी महत्वपूर्ण मामलों में, ब्रिटेन के अपने मन्त्रालयों से प्राप्त, मार्गदर्शन पर निर्भर करें । वे प्रशासनिक और संगठन के प्रश्नों पर सामान्यतः ब्रिटिश चलन और कार्यविधि का अनुसरण करते थे । अब नये सेना-मुख्यालयों को सभी रक्षा समस्याओं पर स्वतन्त्र रूप से विचार करने की, और सरकार के विचारार्थ प्रस्तावों का सूत्रपात करने और उनको बनाने की जिम्मेवारी आ पड़ी । मुख्यालयों में वरिष्ठ स्टाफ-पदों पर जिन भारतीय-अधिकारियों को नियुक्त किया गया, वे भारत के लिए एक स्वतन्त्र रक्षा-संगठन सदा करने के लिए, अपने ऊपर आ पड़ी भारी जिम्मेवारी के प्रति, पूर्णतः सजग थे । यह स्पष्ट है कि उनको स्टाफ कार्य करने के लिए पहले पर्याप्त अवसर न मिले थे । उन सभी ने मुद्र-कान में सक्रिय-श्रमा की थी । हमने उनको बहुमूल्य प्रशिक्षण और अनुभव प्रदान किया था । हमके साथ देशभक्ति की महान् भावना भी उनको प्रेरित कर रही थी । अतएव उन्होंने संरक्षा और जोर के साथ अपने आपको सामने आये काम में झोंक दिया । अक्टूबर, १९४७

में, मुश्किल से २४ घण्टे की पूर्व सूचना पर, कश्मीर को सैन्य-सहायता भेजना, और सितम्बर, १९४८ में हैदराबाद में पुर्तुगल कार्रवाई की ध्यानपूर्वक आयोजना बनाना, यह सिद्ध कर देंगे कि सेनाओं के मुख्यालय कितनी शोघ्रता और सज्जता के साथ अपने नये उत्तरदायित्व संभालने में समर्थ हो गये थे।

### तीनों सेनाओं के स्वतन्त्र प्रमुख

जैसा बताया जा चुका है, १९४७ तक यलसेना का प्रमुख, भारत का कमाण्डर-इन-चीफ था और नौसेना और वायुसेना के प्रमुख उसके अधीन थे। ब्रिटिश काल की उरुतो के लिए यह व्यवस्था बड़ी उपयुक्त थी। भारत की नौसैनिक रक्षा ब्रिटिश की नौसेना की जिम्मेवारी थी। नयी नयी वायुसेना का महत्त्व नाममान का हो था। इसलिए भारत की रक्षा में प्रमुख भूमिका यलसेना की ही थी। फलतः यह अनुपयुक्त न था कि यलसेना का प्रमुख तीनों सेनाओं का कमाण्डर-इन-चीफ बनाया जाय।

सत्ता-हस्तान्तरण के बाद स्थिति बिलकुल बदल गयी। भारत अब अपनी सुरक्षा के लिए मात्र यलसेना पर ही निर्भर नहीं रह सकना था। बिस्तुन तटरेखा की दृष्टि से उसे अपनी समुद्री रक्षा के लिए सुपर्याप्त नौसेना विकसित करनी थी। उसकी वायुसेना भी अपेक्षित सुदृढ़ और विस्तार होनी थी। यह स्पष्ट था कि तीनों सेनाओं के सन्तुलि बित्तर की दृष्टि से अब उनको यलसेना के प्रमुख के अधीन रखना उचित न था। यह समझ लिया गया कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी में हो रही तेज प्रगति की दृष्टि से, किसी एक सेना के अधिकारी से यह आशा नहीं की जा सकती थी कि वह तीनों सेनाओं की तकनीकी-बातों और जटिलता में सुपरिचित हो सके। फिर सभी आधुनिक सशस्त्र सेनाओं में, तीनों में से प्रत्येक सेना एक स्वतन्त्र प्रमुख के अधीन होनी है। इन सब बातों पर विचार करते हुए भारत सरकार ने तय किया कि दोनों नई सेनाओं के भी स्वतन्त्र प्रमुख होने चाहिये; अब तीनों सेनाओं को दिया गया समान महत्व भी इस निर्णय से प्रत्यक्ष था। तीनों सेना प्रमुख अपनी-अपनी सेनाओं के प्रशासन के लिए अब रक्षा-मन्त्री के प्रति सीधे उत्तरदायी हैं और सामूहिक रूप से वे सरकार के व्यावसायिक सैन्य सलाहकार भी हैं।

### चीफों के पदनामों में परिवर्तन

१५ अगस्त, १९४७ को तीनों सेनाओं के स्वतन्त्र प्रमुख नियुक्त करते समय उनके पदनाम में परिवर्तन नहीं किया गया, अर्थात् उनको क्रमशः कमाण्डर-इन-चीफ, भारतीय यल-सेना, प्रथम अफसर कमांडिंग, रॉयल इन्डियन नेवी, और एयर मार्शल कमांडिंग रॉयल इन्डियन एयर फोर्स कहा जाता रहा। लेकिन शीघ्र ही यह बात समझी गयी कि ये पदनाम उनके सक्रियागत-वृत्तियों का तो संकेत देने हैं, पर आयोजना और व्यावसायिक परामर्श के लिए उनके उत्तरदायित्व की बात को सुपर्याप्त रूप से व्यक्त नहीं कर पाते। इसलिए फरवरी १९४८ में यह निर्णय किया गया कि सेनाओं के प्रमुखों के पदनाम इस प्रकार होने चाहिये चीफ आर्माँ स्टाफ और कमाण्डर-इन-चीफ, भारतीय यलसेना चीफ ऑफ दि नेवल स्टाफ और

पद्म भन्सुर कमान्डिंग, रॉयल इन्डियन नेवी, और चीफ आफ दि एयर स्टाफ और एयर मार्शल कमान्डिंग, रॉयल इन्डियन एयर फोर्स। हालाँकि नौसेनाओं के प्रमुखों की प्रास्थिति और उत्तरदायित्व एक जैसे थे, उनके पदनाम अलग-अलग थे। कुछ लोग अब भी सोचते थे कि यलसेना के कमान्डर-इन-चीफ अलग की तरह अब भी भारत की सभी सैन्य सेनाओं के कमान्डर-आरी थे। नौसेना और वायुसेना के बड़े हुए महत्व पर जोर देने के लिए, इन प्रमुखों को भी जनता की दृष्टि में यलसेना के प्रमुख जैसी ही प्रास्थिति और महत्व देने के लिए और एकरूपता की दिशा में भी सेनाओं के प्रमुखों के पदनाम जून, १९४८ में बदल कर चीफ ऑफ दि आर्मी स्टाफ और कमान्डर-इन-चीफ भारतीय यलसेना, चीफ आफ दि नेवल स्टाफ और कमान्डर-इन-चीफ रॉयल इन्डियन नेवी तथा चीफ आफ दि एयर स्टाफ और कमान्डर-इन-चीफ रॉयल इन्डियन फोर्स कर दिये गये। इस तरह नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों के पदनाम यलसेना के प्रमुख के स्तर पर ही ला दिये गये।

लेकिन द्वि-नामों पदनाम लम्बे और अटपटे थे। दूसरे भारत के संविधान के मधीन राष्ट्रपति सेना-सेनाओं के मुख्य कमान्डर हो गये और यह उपयुक्त नहीं लगता था कि सशस्त्र सेनाओं के प्रमुखों को कमान्डर-इन-चीफ कह कर पुकारा जाय। पर नागरिकता अधिनियम पर भी ध्यान देना था। वाक्यो चर्चा के बाद अन्त में यह फैसला किया गया कि पदनामों में परिवर्तन करने की जरूरत है। १ अप्रैल, १९५५ से तीनों सेनाओं के प्रमुख को ये पदनाम दिये गये। चीफ आफ दि आर्मी स्टाफ, चीफ आफ दि नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ दि एयर स्टाफ। इनको कमान्डर-इन-चीफ (पदनाम परिवर्तन) अधिनियम, १९५५ (१९५५ का १६) के मधीन सांविधिक प्रभाव दे दिया गया।

२५ मार्च, १९५५ को सदन में पदनामों में परिवर्तन की यह घोषणा करते हुए प्रधान-मन्त्री ने स्पष्ट कर दिया कि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि इन प्रमुखों के प्राधिकार या प्रास्थिति में कोई बदोती की जा रही है। सन्निवागत प्राधिकार समेत उनका प्राधिकार पूर्ववत् हो बना रहेगा।

यलसेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुख क्रमशः जनरल, वाइस एडमिरल और एयर मार्शल के पद के थे। इन नियुक्तियों की पञ्चावधि में कोई एकरूपता न थी। यलसेना के प्रमुख की पञ्चावधि सामान्यतः चार साल तक थी, नौसेना के प्रमुख की ठीक साल (बड़ा कर चार साल तक) और वायुसेना के प्रमुख की चार साल। जनवरी, १९६६ में सरकार ने यह निर्णय किया कि दोनों प्रमुखों की पञ्चावधि तीन साल होनी चाहिये। कुछ सोचा कि पाञ्चदशीय एकरूपता लाने के अलावा इस निर्णय के पीछे एक और बात रही होगी। जब किसी अधिकारी को अपनी सेना का प्रमुख चुना जाता है, तो निम्नतर सेनाओं में भी परीक्षा की श्रद्धाता चल जाती है। जैसा कि बाद के एक अध्याय में व्यौरों के साथ बताया गया है, प्रत्येक पद के लिए पञ्चावधि और साथ ही अनिवार्य सेवानिवृत्ति की विधि आयु की पद्धति चम्कती है। इसलिए अगर सेना-प्रमुख की पञ्चावधि और अपने नीचे पद के अधिकारियों की (जो उनके बाद विचार-बोर्ड में आयेगे) पञ्चावधि एक ही रही, तो पिटने भी रहने के साथ-साथ सेवानिवृत्ति के लिए

पक्व हो जायेंगे। प्रमुख की पदावधि कुछ कम रहने में यह दिक्कत कम हो जायेगी।

वायुसेना के विस्तार को ध्यान में रखते हुए वायुसेना प्रमुख का पद १५ जनवरी, १९६६ से ऊपर बढ़ाकर एयर चीफ मार्शल कर दिया गया।

### नये सेना-मुख्यालयों को गठित करना

१५ अगस्त, १९४७ को तीनों प्रमुखों के अधीन तीन नये मुख्यालय पहले इन नामों के साथ गठित किये गये—थलसेना-मुख्यालय (भारत), नौसेना-मुख्यालय (भारत) और वायुसेना मुख्यालय (भारत)। बाद में 'भारत' शब्द अनावश्यक समझकर छोट दिया गया।

### थलसेना

थलसेना-मुख्यालय में पहले छह शाखाएँ थीं—चार लेफ्टिनेंट जनरल के पद वाले प्रमुख स्टाफ अधिकारियों के अधीन (नामत चीफ ऑफ दि जनरल स्टाफ, एडजुटेंट जनरल, क्वार्टर मास्टर जनरल और आर्डनेंस के मास्टर जनरल) और दो शाखाएँ मेजर जनरल के पद के अधिकारियों के अधीन (नामत सैन्य सचिव की शाखा और इञ्जीनियर-इन-चीफ की शाखा)।

पिछले महामुद्र के कुछ समय बाद सामान्य-मुख्यालय के पुनर्गठन की एक योजना बनायी गयी थी। फास्तरूप आर्डनेंस के मास्टर जनरल की अगभूत शाखाएँ क्रमशः सामान्य-मुख्यालय की अन्यशाखाओं को स्थानान्तरित कर दी गयीं। आर्डनेंस सेवा-निदेशालय को २४ फरवरी, १९४७ को क्वार्टर मास्टर जनरल की शाखा में स्थानान्तरित कर दिया गया और पाल्त्रिक इञ्जीनियरी और तत्वज्ञानी विभाग के निदेशालय १ अप्रैल, १९४७ को सामान्य स्टाफ शाखा में स्थानान्तरित कर दिये गये। इस तरह १ अप्रैल, १९४७ से आर्डनेंस के मास्टर जनरल की शाखा का अस्तित्व न रहा। उस समय यह सोचा गया था कि इन पुनर्गठन का यह फल होगा कि सैन्य सामग्रियों से सम्बन्धित लोगों के, अर्थात् उपयोगिता, तत्वज्ञानीविद, वैज्ञानिक, निर्माता, निरीक्षक और सन्धारक के काम में, समुचित समन्वय आ जायेगा।

आर्डनेंस कारखाना निदेशक, आर्डनेंस के मास्टर जनरल की दायरा के एक महत्वपूर्ण अधिकारी थे। वे आर्डनेंस कारखानों का नियंत्रण करते थे, जो रक्षा-मन्त्रालय के निदेश भण्डार का निमाण करते थे। युद्धकाल में कारखानों का प्रशासनिक निदन्त्रण पूर्ण विभाग को स्थानान्तरित कर दिया गया। व १ अप्रैल, १९४७ को रक्षा-विभाग में वापस स्थानान्तरित किये गये और उनको सामान्य-स्टाफ-शाखा के अधीन रखा दिया गया। १ अप्रैल, १९४७ से एक नया पद, डिप्टी चीफ ऑफ दि जनरल स्टाफ (शस्त्रास्त्र और उपस्तर) बनाया गया, जिसका काम उस समय सामान्य-स्टाफ-शाखा को सौंपे गये इस नये नाम का परीक्षण करना था। उस आर्डनेंस व मास्टर जनरल के वैज्ञानिक सलाहकार डिप्टी चीफ ऑफ दि जनरल स्टाफ (सामान्य और उपस्तर) के वैज्ञानिक सलाहकार बन गये, लेकिन १ फरवरी, १९४६ में यह निश्चिन्ता, मन्त्रालय के अधीन रक्षा-विज्ञान मण्डन में स्थानान्तरित कर दी गयी। रक्षा-मन्त्रालय में १ अप्रैल, १९४८ में सीनियर प्रशासन के लिए आर्डनेंस कारखानों को भी अपने हाथ में ले लिया था।



इस तरह १५ अगस्त, १९४७ को चलनेना मुख्यालय में सामान्य-स्टाफ शाखा, एडजुटेंट जनरल की शाखा और क्वार्टर मास्टर जनरल की शाखा के भारमापक तीन प्रमुख स्टाफ अधिकारी थे और दो अन्य शाखा-प्रमुख थे, नामतः सैन्य सचिव और इंजीनियर-इन-चीफ। इन सबका पद मेजर जनरल का था। उस समय सेना मुख्यालय में केवल १५० अधिकारी और ५६६ अन्य पदधारी, सैनिक और जैरेनिक दोनों थे।

बाद में यह पता चला कि आर्डनेंस के मास्टर जनरल की शाखा से कुछ निदेशालयों को स्थानान्तरित करने से, सामान्य-स्टाफ-शाखा और क्वार्टर-मास्टर-जनरल की शाखा के ऊपर काफी ज्यादा बोझ आ गया है। यह सोचा गया कि ज्यादा अच्छा समन्वय आवश्यक करने, और सेना में अनुसन्धान और विकास की ओर ज्यादा ध्यान दिये जाने की दृष्टि से, इस महत्वपूर्ण शाखा को फिर से गठित किया जाना चाहिये। तदनुसार, १५ जनवरी, १९४६ से आर्डनेंस के मास्टर जनरल की शाखा फिर से गठित की गयी।

१५ अगस्त, १९४७ में चलनेना-मुख्यालय में प्रमुख स्टाफ अधिकारियों के पदों पर मेजर जनरल के ओहदे के अधिकारी नियुक्त करने की बात तय की गयी थी। इसका कारण उष्णतर ओहदों में सहता रिक्रता आ जाना था और सेना की सख्या में कमी के फलस्वरूप जिम्मेवारी बढ जाना था। अगले दस सालों में सेना का ओहदा-ढाँचा काफी सुस्मर हो गया। शाखाओं की जिम्मेवारियाँ भी बहुत बढ गयी थी। अगस्त, १९५८ में प्रमुख स्टाफ अधिकारियों के पद ऊँचे करके, सेफ्टिनेट जनरल के ओहदे वाले बना दिये गये। साथ ही डिप्टी चीफ ऑफ दि जनरल स्टाफ, डिप्टी एडजुटेंट जनरल, डिप्टी क्वार्टर मास्टर जनरल और आर्डनेंस के डिप्टी मास्टर जनरल के पद मेजर जनरल के ओहदे वाले बनाये गये। सेना के प्रमुख की मदद के लिए डिप्टी चीफ ऑफ दि आर्मी स्टाफ का एक नया पद भी सेफ्टिनेट जनरल के ओहदे में बनाया गया।

१५ जनवरी, १९६५ से डिप्टी चीफ ऑफ दि आर्मी स्टाफ (चलनेना स्टाफ के उप-प्रमुख) और डिप्टी चीफ ऑफ दि आर्मी स्टाफ (चलनेना स्टाफ प्रति-प्रमुख) रखे गये। इन व्यक्तियों के अग्रेज उपप्रमुख को सामान्य स्टाफ शाखा के कुछ ऐसे निदेशालयों के काम का भारमापक बनाया गया, जो पूर्ववत् चला आ रहा है। डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ कर्तव्य-निदेशक का ओहदा ग्रेडेडियर से बढ़ाकर मेजर जनरल का कर दिया गया।

इस तरह चीफ ऑफ दि आर्मी स्टाफ की सहायता के लिए आर्मी स्टाफ के उप-प्रमुख और चार अन्य प्रमुख स्टाफ अधिकारी हैं (सेना स्टाफ के प्रति-प्रमुख, एडजुटेंट जनरल, क्वार्टर मास्टर जनरल, और आर्डनेंस के मास्टर जनरल) और दो शाखा-प्रमुख हैं (इंजीनियर-इन-चीफ और सैन्य-सचिव)। शाखाओं के कृत्यों की रूपरेखा नीचे दी जा रही है।

#### १—सामान्य-स्टाफ-शाखा

(क) सेना का संगठन और नियोजन, सैन्य-सक्रियता, सैन्य-आपूर्ति, सैन्य-प्रशिक्षण, सनायात-विकास, सैन्य-सर्वेक्षण नवशो के सन्धारण और पूर्ति समेत, और स्टाफ मामलों के इंजीनियर—जिनका निपटान सेना-स्टाफ के उप-प्रमुख द्वारा किया जाता है।

(ख) स्टाफ-कर्तव्य, साम्राज्य और उपस्कर का चुनाव और माप, प्रावधान करने सहित उपस्कर सम्बन्धी नीति का समन्वय, आर्मर्ड-कोर, आर्टिलरी, सिगनल्स, पैदल सेना, प्रादेशिक सेना और रक्षा-गुरखा दल—जिनका नियंटान सेना-स्टाफ के प्रति-प्रमुख द्वारा किया जाता है।

## २—एडजुटेंट जनरल की शाखा

जनसाधन, भरती, छुट्टी, वेतन और भत्ते और पेन्शन और सेवा की अन्य शर्तें, अनु-सामन। यह कल्याण और स्वास्थ्य और सैन्य-विधि का भी काम देखती है।

## ३—क्वार्टर मास्टर जनरल की शाखा

कामिज-संचयन, भण्डार और उपस्कर, ईंधन, स्वाच्छ-पदार्थ और चारे का प्रावधान, भण्डारण, निरोक्षण और वितरण, सैन्य-कामें, अस्त्र और पशुचिकित्सा-मेवायें, सेना की डाढ़, पायोनियर और बंटोन मेवायें, निर्माण-कार्य नीति, अग्निशामक-मेवायें और सैन्य-इंजीनियर-मेवाओं के निर्माण-कार्य बिलों की तकनीकी जाँच।

## ४—आइन्स के मास्टर जनरल की शाखा

सैन्य परिवहन, गाड़ियों, साम्राज्य और गोदा-बाब्द, सिगनल उपस्कर, सामान्य भण्डार और बत्ती की शामिल करते हुए आइन्स पूर्ति वाले सभी भण्डार और उपस्करों के बारे में अवान्ति-नीति, प्रावधान, भण्डारण, वसूली, भरण, सन्धारण और वितरण के सभी पक्ष और साथ ही नौसेना और वायुसेना को समान उपभोक्ता मदों की पूर्ति।

## ५—सैन्य-सचिव की शाखा

सेना में कमीशन दिये जाना, तैनाती, स्थानान्तरण, पदोन्नति, सेवा-मोचन, मेकानिब्रुति, त्यागपत्र, अग्रग होना, रतित्व में स्थानान्तरण और सेना के सभी चिकित्सेतर अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन और व्यक्तिगत अभिवेक्ष रखना, उन चुनाव बोर्डों के लिए सचिवानुप-व्यवस्था करना, जो अधिकारियों के सेलिफ्टेन्ट कर्नल और ऊपर के ओहदों में पदोन्नति के लिए सिफारिश करते हैं, सेना अधिकारियों के सम्मान और पुरस्कार और असेनिकों की सेना में आदरी कमीशन प्रदान करने के लिए सिफारिशें करना।

## ६—इंजीनियर-इन-चीफ की शाखा

इंजीनियर-यूनिट और इंजीनियर भण्डारों सम्बन्धी सभी मामले, इंजीनियर-कोर का प्रशासन और उसकी कामिक और सैन्य-इंजीनियरी-मेवायें, रक्षा-सेवाओं के लिए सभी आवासों और निर्माण-कार्यों के लिए डिजाइन बनाना, निर्माण करना और सन्धारण करना। ये सभी शाखायें विभिन्न विदेशालयों में बंटी हुई हैं।

१५ अगस्त, १९६७ को भारत की तीन सेना-कमानों में बाँटा गया—१. दक्षिणी,

२. पूर्वी और ३. दिक्की तथा पूर्वी पञ्जाब कमानें। दिल्ली और पूर्वी पञ्जाब कमान का किताबन के बाद निमाण हुआ था, तत्कालीन पूर्वी कमान भी अपने मूल आकार में कुछ संशुचित हो गयी थी। दक्षिणी कमान का क्षेत्राधिकार प्रायः अपरिवर्तित रहा। प्रत्येक कमान एक जनरल अन्वर कमांडिंग इन चीफ के अधीन थी और आज भी बनी हुई है, जिनका ओहदा सेलिफ्टेन्ट

जनरल का होना है। ये कमानें पहले की तरह एरिया कमांडरो के अधीन ( जिनको जनरल अफसर कमांडिंग, एरिया कहते हैं ) एरिया में बंटी रहती है, जो मेजर जनरल के ओहदे के होते हैं और उनके अधीन स्वतन्त्र सब-एरिया होते हैं, तथा ब्रिगेडियरो की कमान के अधीन सब-एरिया होते हैं। स्वतन्त्र सब-एरिया सीधे ही कमान के अधीन आते हैं। १९४७ में समय-समय पर बदलती जरूरतों को पूरा करने की दृष्टि से, एरिया और सब-एरिया की सीमा में परिवर्तन किये जाते रहे हैं।

१९४८ में दिल्ली और पूर्वी पंजाब कमान का नाम बदल कर पश्चिमी कमान कर दिया गया। १९५४ में इस कमान का मुख्यालय दिल्ली से, जहाँ इसे केवल अस्थायी आवास मिला हुआ था, हटाकर शिमला ले जाया गया, जहाँ रक्षा-सेनाओं में सम्बन्धित स्थायी भवन उपलब्ध थे। दिल्ली में स्थायी भवन बनाने के लिए काफी पूँजी व्यय करने की जरूरत पड़ती और फिर यह ऐसी जगह थी, जहाँ भवनों की भाँग पहले ही काफी सीमा थी। दूसरी ओर, शिमला में पंजाब सरकार का कार्यालय चंडीगढ़ चले जाने से गृह-समस्या काफी आसान हो गयी थी। तराकालीन पूर्वी कमान का मुख्यालय भी राँची से हटाकर लखनऊ ले आया गया। राँची रेल या सड़क-संचार की दृष्टि से सुविधाजनक जगह पर न था, साथ ही सरकार के पास वहाँ पर बहुत ज्यादा जमीन और भवन भी न थे। जमीन अवाप्त करने और नये भवन बनाने में भारी पूँजी व्यय करनी पड़ती। लखनऊ में अधिकार अहरी आवास-स्थान पू० पी० एरिया मुख्यालय लखनऊ ने बरेली से आकर प्राप्त कर लिया गया। संचार की दृष्टि से भी लखनऊ की स्थिति अच्छी है। यह स्थान-बदल फरवरी, १९५५ के अन्त तक पूरा कर लिया गया। इन तरह तीन सेना कमान थे—पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिण, जिनके मुख्यालय क्रमशः शिमला, बनकला और पूना में थे।

एरिया और सब-एरिया की स्थायी विरचना के रूप में उल्लिखित किया जाता है। चन या सज्जिगण विरचनार्थ होती है। ब्रिगेड, स्वतन्त्र ब्रिगेड या ब्रिगेड-समूह जो ब्रिगेडियर के ओहदे के ब्रिगेड कमांडर के अधीन रहती है, द्विवीजन, जो द्विवीजनल कमांडर ( मेजर जनरल ) के अधीन रहता है, ( जिसमें दो या अधिक दिशेजन रहते हैं या जो द्विवीजनो, ब्रिगेड समूहों और स्वतन्त्र ब्रिगेडों का मिश्रण होते हैं )। ये लेफ्टीनेंट जनरल के ओहदे के कोर-कमांडर के अधीन रहती हैं। कोर-कमांडर आर्मी कमांडर के अधीन काम करता है ( जो बर्मान वा जनरल अफसर कमांडिंग-इन-चीफ होता है )। कोर-कमांडर आर्मी कमांडर से कनिष्ठ होता है, हालाँकि उन दोनों का ही ओहदा लेफ्टीनेंट जनरल का होता है। यहाँ पर यह भी बताना दिया जाय कि सेना-स्टाफ उप-प्रमुख की प्राप्ति आर्मी कमांडर की होती है और प्रमुख स्टाफ-अधिकारियों की कोर कमांडर से आर्मी कमांडर की पदोन्नति अन्य वरिष्ठ पदों की तरह चुनाव द्वारा होती है, हालाँकि सेन्य ओहदा वही बना रहता है।

सत्ता-हस्तांतरण के बाद, जब वायसराय की नियुक्ति ही नहीं रही, तो वायसराय कमोशन-प्राप्त अधिकारी ( ची० सी० ओ० ) नाम अनुसूक्त हो गया। ची० सी० ओ० एक भारतीय सेना वा ही विशिष्ट व्योहता है और ब्रिटिशजनो ने ब्रिटिश अधिकारियों और भारतीय अधिकारियों के बीच एक कड़ी रखने के लिए ही इसकी मूर्ति की थी। वायसराय के कमोशन-

प्राप्त अधिकारी को नियुक्ति अन्य पदों से पदोन्नति द्वारा ही की जाती थी। मार्च, १९४८ में थो० सी० ओ० का नया पदनाम कनिष्ठ कमीशन-प्राप्त अधिकारी (जे० सी० ओ०) रखा दिया गया, हातांकि ओहदे वही बने रहे, अर्थात् जमादार, सूबेदार और सूबेदार मेजर। जमादार शब्द जन-समाज में क्रमशः एक व्यङ्ग्य-विशेष का वाचक बन गया है। इसलिए जे० सी० ओ० के इस ओहदे को क्रमशः बदलकर १९६५ में नायब सूबेदार कर दिया गया।

किंग कमीशन-प्राप्त भारतीय अधिकारी (के० सी० आई० ओ०) और भारतीय कमीशन प्राप्त अधिकारी के पदनाम भी क्रमशः अधिकारी और भारतीय अन्य पदधारी हो गये। पिछ्छना नाम मूलतः ब्रिटिश अन्य पदधारियों ने भेद करने के लिए रखा गया था, पर बाद में केवल अन्य पदधारी हो रह गये। इस तरह अब भारतीय सेना में अधिकारी, कनिष्ठ कमीशन-प्राप्त अधिकारी और अन्य पदधारी होते हैं।

यहाँ पर रक्षा-सुरक्षा-दल का संक्षिप्त उल्लेख कर देना भी उचित होगा, जो पूरे भारत में रक्षा-संस्थापनों के सरक्षण के लिए कार्मिक प्रदान करता है। पहले रक्षा और प्रतिपालन-काम के लिए अमेरिकी चौकीदार और तलाशगीन संस्थापनों द्वारा स्वयं ही लगा लिए जाते थे। पर बाद में यह अनुमति किया गया कि रक्षा-संस्थापनों की ज्यादा अच्छी सुरक्षा के लिए आक्रामक रूप से लगाये गये अमेरिकी की जगह ऐसे लोग लगाये जाने चाहिये, जो अनुशासन की कहीं ज्यादा कठोर संहिता के अधीन हों। इसलिए विभाजन से पहले ही आदेश निकाल दिये गये थे कि रक्षा विभाग की एक कास्टेबल-सेना गठित की जानी चाहिये। २६ अप्रैल, १९४७ को निहाली गयी एक अधिसूचना द्वारा कास्टेबल-सेना का नाम भारतीय सेना अधिनियम, १९११ के अधीन 'कोर' रखा गया और इस तरह इसके सदस्य स्वतः भारतीय सेना के अधीन आ गये। इस कास्टेबल सेना का नाम बाद में २३ अप्रैल, १९४८ को रक्षा-मन्त्रालय-सुरक्षा-दल रखा दिया गया। यह रक्षा-मन्त्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण में थी।

सुरक्षा-दल का उद्देश्य संस्थापनों को छोटी-मोटी तोड़फोड़ और सघु चोरियों से सुरक्षित रखना है, पर इसका अभिप्राय यह नहीं कि वह बाहर से भारी पैमाने के हमले या किसी बड़े आंतरिक उपद्रव के लिए भी है, जिसका सामना तो स्थायी मुख्यालय के आदेशों के अधीन नियमित सेना के व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिये। कोर की रचना सेना के प्रतिमान पर की गयी है और इसके भी ओहदे और उपाधि नियमित सेना जैसे ही हैं।

दल में तीनो सेनाओं के भूतपूर्व सैनिक भरती हो सकते हैं। रक्षा-सुरक्षा-दल के व्यक्तियों की सेवा शर्तें और निवृत्ति, यात्रा-रियायत, राशन, चिकित्सा-उपचार और आक्रामक और रोग-अवकाश के बारे में बनी है, जो नियमित सेना के व्यक्तियों पर लागू होते हैं। पर वेतन और भत्ते, पेन्शन, ग्रेज्युटी और वार्षिक छुट्टी की शर्तें कुछ भिन्न हैं।

नौसेना और वायुसेना के अधिकारियों को यथास्थिति नौसेना या वायुसेना की यूनिटों या संस्थापनों में कतव्य-लग्न सुरक्षा-व्यक्तियों के ऊपर कमान और दण्ड की शक्ति मिली हुई है। लेकिन ये व्यक्ति केवल सेना-अधिनियम के अधीन आते हैं, तत्पश्चात् नौसेना और वायुसेना के अधिनियमों के अधीन नहीं। सेना-नियमों के अधीन, नौसेना और वायुसेना अधिकारियों

को दी गयी शक्तियों के अधीन, वे छोटे-मोटे अपराधों के मामले में सशस्त्र कोर्ट मार्शल कार्य-विधि आना लेते हैं। लेकिन जब कोई गम्भीर अपराध का दोषी होता है, जिसके लिए कोर्ट मार्शल जांच जरूरी है, तो उसे उपयुक्त सेना-अधिकारियों के हवाले कर दिया जाता है। आइंमैंस कारखाने में काम करने वाले सुरक्षा-कार्यक अगर सेना-अधिनियम के अधीन किसी अपराध के दोषी होते हैं, तो उनको निकटतम सेना यूनिट में उपयुक्त कार्रवाई के लिए सौंप दिया जाता है।

कोर का प्रशासन एक निदेशक के हाथ में है। जैसा पहले बताया जा चुका है, पहले यह सीधे रक्षा-मन्त्रालय के अधीन था। रक्षा-मन्त्रालय सुरक्षा-दल को १६ अगस्त, १९५८ से चौक-ऑफ़ दि जनरल स्टाफ़ के प्रशासनिक नियन्त्रण में स्थानान्तरित कर दिया गया और उसका नाम रक्षा-सुरक्षा-दल रख दिया गया। इस तरह यह निदेशालय सामान्य-स्टाफ़-शाखा का एक अंग है।

सेना के अपसरो के ओहदे ये हैं : सेकिंड लेफ्टीनैंट, लेफ्टीनैंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टी-नैंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टीनैंट जनरल और जनरल। कनिष्ठ कमीशन प्राप्त अधिकारियों के ओहदे हैं : नायब सूबेदार, सूबेदार या रिसालदार और सूबेदार मेजर या रिसालदार मेजर। अन्य पद ये हैं : सिपाही, लास नायक, नायक, हवलदार और हवलदार मेजर।

सेना में अनेक टुकड़ियाँ और सेवार्थें हैं। पैदल सेना, आर्मी-कोर, आर्टिलरी की रेजी-मेंट, इंजीनियर-कोर, सिगनल्स-कोर, आर्मी-सर्विस-कोर, आर्मी-आइंमैंस-कोर, बिजली और पान्निनी इंजीनियरी की कोर, आर्मी-एक्वेडेशन-कोर, अड्डा, पशुचिकित्सा और फार्म-कोर, आर्मी-मेडिकल-कोर, आर्मी-डेंटल-कोर मिलिटरी-गुलिस-कोर, रक्षा-सुरक्षा-दल।

अक्टूबर, १९६२ के चीनी आक्रमण के बाद सेना में काफी विस्तार और पुनर्गठन हुआ। पूर्वी-सेना-कमान का काम चीन से लगी सीमा के मध्य और पूर्वी खण्डों की देखभाल करना भी हो गया। पूर्वी पाकिस्तान के सीमान्त की देखभाल करना तो जारी हो रहा आया। अनुभव ने बताया कि यह क्षेत्राधिकार एक आर्मी-कमांडर द्वारा देखभाल के लिए काफी बड़ा है। तदनुसार मई, १९६३ में पूर्वी कमान को दो हिस्सों में बाँट दिया गया। पूर्वी कमान का मुख्यालय लखनऊ से कलकत्ता ले आया गया। और एक नयी मध्य कमान लखनऊ में मुख्यालय के साथ बनायी गयी। मध्य कमान का क्षेत्राधिकार यू० पी०, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश था, जबकि पुनर्गठित पूर्वी कमान के अधीन पश्चिमी बंगाल, आसाम, 'नेफा' (उत्तर-पूर्वीय सीमा—'वूपो') नागालैण्ड, मणिपुर और त्रिपुरा आ गए।

मुद्रस्त यूनिटों के प्रश्न में, अक्टूबर-नवम्बर, १९६२ में उपसो में, चीनी सेना के साथ हुई सत्रिया के अनुभव-विशेष के आधार पर, पर्वत-इन्जीन नामक एक नयी विरचना बनायी गयी। यह संगठन ऊँचे पहाड़ी प्रदेशों में वृद्धित चलिणुता और अभि-वृत्ति के साथ सत्रिया के लिए सजा किया गया है। सैनिकों की चनिष्णुता बढ़ाने के लिए उनको पशु-परिवहन और हलकी गाड़ियाँ दी जाती हैं। उनको स्वतः उल्लाखों के सज्जित किया गया है, जिनको आदमी या

पशु ने जा सकते हैं और जोर इस बात पर दिया गया है कि जिस भूतल पर उनको काम करना है, उस पर उसी अग्नि-शक्ति बड़ा दी जाये। पर्वत-द्विबीजन के संगठन-दाँचे में यह आवश्यक करने के लिए यथोचित परिवर्तन किये गये हैं कि प्रत्येक सैन्य-विरचना यथासम्भव आत्मनिर्भर रहे। आपान के आरम्भ के बाद छ नये द्विबीजन बढ़ाने की मजूरी दी गयी थी, जिनमें से चार पर्वत द्विबीजन बनने थे। एक विद्यमान पैदल-पैना-द्विबीजन को भी पर्वत-द्विबीजन में पुनर्गठित किया गया और इस तरह पर्वत-द्विबीजनो की संख्या पाँच हो गयी। सेना के भावी रूप के बारे में एक और दूरगामी निर्णय की बात 'मरती और प्रशिक्षण' वाले अध्याय में बही गयी है।

### नौसेना

सत्ता हस्तान्तरण के बाद शुरू में नौसेना मुख्यालय को दो मुख्य विभागों में गठित किया गया। एक चीफ-ऑफ स्टाफ का विभाग था, जो आयोजना, सज्जिया, सन्चार, आसूचना और सुरक्षा, अर्थिक मामले, पोतों और तट-स्थापनाओं का समन्वय, प्रशिक्षण और शिक्षा, कन्याण और नौ सैनिक विधि के लिए उत्तरदायी था। दूसरा प्रशासन-प्रमुख का विभाग था, जो पूँव, साय-भरण, छाड़ीकरण, निर्माण-कार्य, इंजीनियरी आदि के लिए उत्तरदायी था। इन विभागों को विभिन्न शाखाओं और निदेशालयों में भी बाँट दिया गया, जो एक विषय-विशेष का काम करते थे।

कमान की गृहलक्ष्य में पनेग-अफसर कमांडिंग के बाद कमीडोर, भारसाधक, बम्बई थे, जिनका मुख्यालय भी बम्बई के बन्दरगाह में था। भारत के पश्चिमी समुद्रतट पर आधार वाले नौसेना के पोतों (जिनको उस समय द्विज मैजिस्ट्री के भारतीय पोत कहा जाता था) के लिए, उस क्षेत्र के रॉयल इंडियन नौवी सस्थापनों और व्यक्तियों और तटरेखा की नौवैनिक रक्षा के लिए, उत्तरदायी थे। अनेक उप-कमान भी थे। प्रत्येक, एक नौवैनिक-भारसाधक-अधिकारी या आवासी-नौसेना-अधिकारी के अधीन था। वे अपने-अपने बन्दरगाहों के आधार वाले पोतों के लिए और अपने-अपने क्षेत्र के नौसेना-सस्थापनों और व्यक्तियों के लिए उत्तरदायी थे। दो नौवैनिक-भारसाधक-अधिकारी थे। एक पश्चिमी तट में कोचिन में और दूसरा पूर्वी तट में किलावायटनम् में। दो आवासी-नौसेना-अधिकारी भी थे। एक मद्रास में और दूसरा बलरुता में।

१५ अगस्त, १९४७ को नौसेना ने पास एक क्रियेट स्वेड्डन था, जिसमें थे जहाज थे जमुना, नावेरी, सननज और कृष्णा, एक श्वायड-प्रशिक्षण-योन, 'तीर', एक गुरग गाक करने का स्वेड्डन, जिसमें थे जहाज थे बगाल, बम्बई, कोङ्ग, मद्रास, राजपूताना और म्हेलखण्ड और सर्व-अप-प्लेन-इन्वेस्टीगैटर। ये सभी बहुत पुराने जहाज थे। मूलतः यह प्रस्ताव था कि युद्धोत्तर नौसेना में तीन क्रूजर होने चाहिये, पर ब्रिटिश सरकार द्वारा सत्ता-हस्तान्तरण की घोषणा के बाद यह आयोजना बंद हो गयी। फ्रान्स्वल्फ मशमहिम सम्राट सरकार ने एक क्रूजर के लिए की गयी प्रार्थना को रद्द कर दिया गया। किमात्रन के तुरन्त बाद नवी भारत सरकार ने स्पष्टि पर पुनर्विचार किया और यह निर्णय किया कि भारतीय नौसेना के लिए

रॉयल नेवी में एक ब्रूजर मगाया जाय, भारत सरकार ने ५ अप्रैल, १९४८ को फिर से, उप-युक्त रूप से फिट करके, भूतपूर्व एच० एम० एस० एच० ( ७००० टन ) प्राप्त किया । इस जहाज का नाम एच० एम० एस० दिल्ली रखा गया और यह १६ नवम्बर, १९४८ को नौ-बंदे में शामिल हो गया । नौसेना के कमबद्ध विकास कार्यक्रम में अगला कदम रॉयल नेवी में 'आर' ध्रेणी के तीन डेस्ट्रॉयर प्राप्त करना था । आधुनिक और रक्षा-कटिबन्धीय-अनुकूलन के बाद ये जहाज जनवरी, १९५० में भारत पहुँचे । नौसेना में शामिल होने पर उनके नाम एच० एम० आई० एस० राजपूत, और राणा रखे गये ।

इस बीच १५ जनवरी, १९४९ को जल्दी समझते हुए नौसेना मुख्यालय का पुनर्गठन किया गया । इनमें पाँच प्रमुख विभाग, प्रत्येक एक-एक प्रमुख स्टाफ-अधिकारी के अधीन बनाये गये । उस समय प्रमुख-स्टाफ-अधिकारी डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और डिप्टी कमांडर-इन-चीफ थे जिनका ओहदा कमांडोर का था और टोप कैप्टेन के ओहदे के थे और ये आयोजना सत्रिया संचार, और आसूचना के लिए उत्तरदायी थे और स्टाफ के समशील समन्वय के लिए भी), कार्मिक-प्रमुख (जो नौसेना के व्यक्तियों की भरती, सेवा-सहा, प्रशिक्षण, कल्याण और अनुशासन, अधिकारियों की नियुक्ति और नौ-बंदे में सामान्यतः व्यक्ति-व्यवस्थापन के लिए उत्तरदायी थे), प्रशासन-प्रमुख (जो भूति और खाद्य-भरण, भण्डार, वेतन और भत्ते, परिवहन और निर्माण-प्रयोजनाओं के लिए उत्तरदायी थे), सामग्री-प्रमुख (जो सेवा के सामग्री-सहायन के लिए उत्तरदायी थे) और नौसेना-उद्बुधन के प्रमुख (जो नौसेना की वायुशाला के लिए उत्तरदायी थे) थे । सामग्री-प्रमुख और कार्मिक प्रमुख के ओहदे अक्टूबर, १९५६ में बढ़ाकर कमांडोर के कर दिये गये और प्रशासन-प्रमुख का पद खतम कर दिया गया ।

यहाँ पर नौसेना के नौमैनिक-उद्बुधन-विंग के बारे में कुछ बताना उचित ही होगा । पिछले महायुद्ध ने बता दिया था कि किसी भी सत्रिया को सफल रूप में चलाने के लिए पन-सेना, नौसेना और वायुसेना का मिला-जुला प्रयास अत्यावश्यक होता है । नौसेना-उद्बुधन आक्रमण और रक्षा दोनों ही प्रयोजनों से बड़ी भारी भूमिका निभा सकता है । यदि समुद्र पर का कोई निशाना भू-आधारित विमान की मार से बाहर है, तो विमान-बाहुरपोत नौसेना के विमान को समुद्र में काफी दूर तक ले जा सकते हैं, जहाँ से वे निशाने पर हमला कर सकें । रक्षा की भूमिका में, शत्रु के पोत हमारी स्थितियों पर हमला करने की कोशिश में पहुँचे ही, विमान-बाहक पोतों पर स्थित विमानों द्वारा रोके जा सकते हैं और वायु से उन पर हमला किया जा सकता है ।

कुछ उपलक्षण नौसेना के विमानों को सामान्य विमानों से पृथक् कर देते हैं । उनमें एक पादाक हुक लगा रहता है, जो अवतरण करते समय विमान-बाहक के डेक पर लगे एक पादाक-सार में फँस जाता है और २०० फीट की दूरी में हो विमान को रोक देता है । कुछ में मोटे जा सरने योग्य विंग होते हैं, जिससे एक विमान-बाहक पर ज्यादा संख्या में जहाज ले जाना सम्भव हो जाता है ।

नौसेना के एयरसेन को काफ़ी विशेषीकृत प्रशिक्षण लेना पड़ता है । रॉयल इंडियन

नेवी के १८ अधिकारियों के पहले बैच ने अपना आरम्भिक पाइलट-प्रशिक्षण, वायुसेना के साथ, प्रारम्भिक-उड़ान-प्रशिक्षण-विद्यालय, बोधपुर में १९४६ के मध्य में शुरू किया।

हट वर्ग के तीन डेस्ट्रॉयर, गोदावरी, गोमती और गंगा आरम्भ में रायल नेवी से उधार लिये गये और उनको १९५३ के मध्य में भारतीय नौसेना बेड़े में शामिल किया गया। १९५४-५५ में रायल नेवी से एक और क्रूजर प्राप्त करने की व्यवस्था पूरी कर ली गयी थी। यह क्रूजर, आई० एन० एम० मैमूर, २६ अगस्त, १९५७ को नौसेना में शामिल किया गया।

प्रथम क्रूजर, और अन्य पोतों को प्राप्त करने के बाद, नौसेना कमान में एक नयी नियुक्ति १५ अगस्त, १९४८ में की गयी, जिसका पदनाम फ्लैग-अफसर-कमांडिंग, रायल इंडियन स्क्वेड्रन रखा गया। इस नियुक्ति के नाम में समय-समय पर अन्तर पड़ता रहा और अब इसे फ्लैग-अफसर कमांडिंग इंडियन फ्लीट कहा जाता है और उसका ओहदा रीयर एडमिरल का है।

दो तटान्त सुरंग-भार्यक जेसीन और बिमलीपट्टम् भी १९५५ में प्राप्त किये गये। ब्रिटेन से प्राप्त किये गये चार तटीय सुरंग-भार्यक मई, १९५७ में बेड़े में शामिल हुए, जिनके नाम थे : आई-एन-शिप कारबाड, कन्नानूर, कड्डनूर और काकीनाडा। इंग्लैंड में आठ और नये फ्रिगेट बनवाने का कार्यक्रम १९५६-६१ में चल रहा। पनडुब्बी-रोधी फ्रिगेट छुफरी और बिमान-रोधी फ्रिगेट ब्रह्मपुत्र ७ नवम्बर, १९५८ को बेड़े में शामिल हुए और उनके बाद पनडुब्बी रोधी फ्रिगेट वृषाण और कुठार १० नवम्बर, १९५९ को आये। छेप चार फ्रिगेट सलवार, जिश्नू, व्यास और वेतवा १९६०-६१ में बेड़े में शामिल हुए—जिनमें से आखिरी मई, १९६१ में आया। फरवरी, १९५७ में भारत सरकार ने १९००० टन का एक विमान-वाहक प्राप्त किया, जिसका निर्माण जमी इंग्लैंड में पूरा होना था। उसके बाद पोत को पूरा किया गया और उसका आधुनिकन किया गया। यह वाहक, आई० एन० एम० विक्रान्त, औपचारिक रूप से बेलकास्ट में ४ मार्च, १९६१ को उतारा गया। फिर ब्रिटेन और भूमध्य सागर में उसे\* कार्यरत रहना पड़ा। रास्ते में भी कुछ अम्यासों में भाग लेता हुआ, यह वाहक भारत में नवम्बर, १९६१ में पहुँचा। उस पर ब्रिटेन से लिये गये सीहौक विमान हैं और फ्रान्स से लिये गये एलिज विमान। भारत में बना पहला सर्वेक्षण-पोत-द्वयक हिन्दुस्तान शिप-यार्ड लिमिटेड, किलासापटनम् में बना था और औपचारिक रूप से उसे, २८ दिसम्बर, १९६४ को उतार कर, बेड़े में शामिल किया गया। हाल में नौसेना में पनडुब्बी-शाला भी जोड़ दी गयी है।

पोर्ट ब्लेयर में १५ फरवरी, १९६४ को एक आवासीय-नौसेना-अधिकारी सगठन स्थापित किया गया और उसका नाम आई० एन० एम० जरवा (अदमान नौकोवार द्वीप समूह को एक पुरानी जनजाति के नाम पर) रखा गया। नौगना अड्डे (बेग) के रूप में विस्तृत करने के लिए मारमागाओ का नाम ७ मई, १९६४ को आई० एन० एम० गोमन्तक रखा गया।

\* साप्ताहिकी को एक टुकड़ी के रूप में पोत चलाने का प्रशिक्षण।



इस क्षेत्र में नौसेना का हवाई अड्डा सर्वोत्तम भी आता था, जहाँ पर जरूरी सुविधाओं में सुधार और विकास कर लिया गया।

बम्बई की नौसेनिक गोदी का विस्तार कई चरणों में किया जा रहा है। जून, १९६४ में नौसेना ने लंदीय चेटरियो का उत्तरदायित्व, सन्धारण और सफ़ाई के लिए, धनमेना से लेकर, सौंभाल लिया।

मजगांव गोदी में, ब्रिटेन के वाइकम-बारी के सहकार से तीन नये फ़्लोट बनने हैं। ब्रिटिश सरकार, ने फ़्लोट-प्रायोजना की बाह्य लागत को पहले चार साल में पूरा करने के लिए, और मजगांव गोदी के विस्तार के लिए, लगभग ६७ लाख पौण्ड का वित्तिय ऋण दिया। नये फ़्लोट नौसेना में १६७१ और १६७३ के बीच बनकर शर्मिने हो जाएंगे, ऐसी आशा की जाती है।

वेड़े में विस्तार के साथ-साथ, नौसेना की विभिन्न वरिष्ठ नियुक्तियों से सलगन जिम्मे-वारियाँ भी काफी बड़ गयीं। १९५८ में कमोडोर भारसाधक, बम्बई और नौसेनिक अधिकारी भारसाधक विद्यासायनम् के ओहदे बढ़ाकर कमच रोवर एडमिरल और कमोडोर कर दिये गये और उनके पदनाम पनेअ अफसर, बम्बई और कमोडोर पूर्वी तट, कर दिये गये। अगले साल डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ (नौसेना-स्टाफ-उप-प्रमुख) की नियुक्ति का ओहदा बढ़ाकर रोवर एडमिरल कर दिया गया। १९६५ में नॉर्मिक-प्रमुख और सामग्री-प्रमुख के पदों के ओहदे भी बढ़ाकर रोवर एडमिरल कर दिये गये।

अब नौसेना-मुख्यालय में प्रमुख स्टाफ-अधिकारी ये हैं नौसेना-स्टाफ-उप-प्रमुख, नॉर्मिक-प्रमुख, सामग्री-प्रमुख (नीना हो रोवर एडमिरल के ओहदे में) और नौसेना उद्बोधन-प्रमुख (कमोडोर के ओहदे में)। नौसेना-मुख्यालय के बाहर विभिन्न नौसेना-प्राधिकारी इस तरह हैं - पनेअ-अफसर-कमांडिंग, इडिफा फ़्लोट, पनेअ-अफसर, बम्बई, कमोडोर-भारसाधक कोचीन, नौसेना-अधिकारी-भारसाधक गोवा, कमोडोर पूर्वी तट, विद्यासायनम् आवासी-नौसेना-अधिकारी मद्रास, नौसेना-अधिकारी भारसाधक, कलकत्ता, और आवासी-नौसेना-अधिकारी, पोर्ट ब्लेयर।

नौसेना के अधिकारी-मजग में छः शाखाएँ हैं कार्यपालक, इंजीनियर, बिजली, पूर्ति और संचित्तय, अनुतिष्ठक तथा चित्रित्वा (चित्रित्वा अधिकारी सेना-चित्रित्वा-कोर के अधि-कारी होते हैं, जिनकी नौसेना के लिए अनुसमर्थन कर दिया जाता है।) नौसेना में अधि-कारियों के ओहदे इस तरह हैं मिडिंग मेन, सब लेफ्टीनेंट, लेफ्टीनेंट, लेफ्टीनेंट कमांडर, कमांडर, कैप्टन, कमोडोर, रोवर एडमिरल और वाइस एडमिरल (नौसेना में कमोडोर एक ओहदे की अपेक्षा एक नियुक्ति अधिक है)। नेना के कनिष्ठ कमीशन-प्राप्त अधिकारियों जैसे ओहदे नौसेना में नहीं हैं। नॉर्मिक के ओहदे हैं गार्डनरी सीमेन, एबुल सीमेन और सीडिंग सीमेन।

### वायुसेना

१५ अगस्त, १९४७ को नये वायुसेना मुख्यालय में दो मुख्य शाखाएँ थीं, नामतः

- (१) वायुनागा, जो आयोजना, गमिग, प्रशिक्षण, गिनतन और आयुचना के लिए उत्तरदायी रहे

धी और (२) प्रशासनिक साखा, जो उपस्कर, कार्मिक जनसाधन, सगठन और तकनीकी तथा उपस्कर सेवाओं के लिए उत्तरदायी थी।

उस समय वायुसेना-मुख्यालय के अधीन दो वायुसेना विरचनाएँ थी संस्था १—सक्रिया समूह, जो सभी उड़ान यूनितों का नियन्त्रण करता था (सड़ाकू, बममार, परिवहन, विमान आदि का) और भारत की वायु-रक्षा के लिए उत्तरदायी था और संस्था २—प्रशिक्षण समूह—जो वायुसेना के रंगरूटों के प्रशिक्षण और प्रशिक्षण-संस्थानों के लिए उत्तरदायी था।

पुनर्गठन के बाद २० अक्टूबर, १९४८ से वायुसेना मुख्यालय में तीन विभाग थे एक वायुसेना स्टाफ के उप-प्रमुख और डिप्टी एयर कमांडर के अधीन, जिनका ओहदा एयर साइम मार्शल का था (जो आयोजना और सक्रिया के लिए जिम्मेवार थे) और शेष दो का ओहदा एयर कमांडर का था वायुसेना अधिकारी भारसाधक कार्मिक और सगठन तथा वायुसेना-भारसाधक-अधिकारी, तकनीकी पूँति और सेवाएँ (जिसका नया नाम १६ मार्च, १९४९ में तकनीकी और उपस्कर-सेवाएँ रखा गया)।

सक्रिया-समूह और प्रशिक्षण समूह के पूरे महत्व और कृत्यों का, तथा उनकी कमान संभालने वाले वायु-अधिकारियों की प्राप्ति का, निरूपण करने के लिए (जो एयर कमांडर के ओहदे के थे), इन समूहों का नया नाम २२ जुलाई, १९४९ से सक्रिया कमान, भारतीय वायुसेना और प्रशिक्षण कमान, भारतीय वायुसेना रखा दिया गया। प्रशिक्षण कमान के अधीन पहले भारतीय प्रशिक्षण संस्थान ही थे, उड़ान-प्रशिक्षण-संस्थानों (वायुसेना अकादेमियों) का नियन्त्रण भी वायुसेना-मुख्यालय द्वारा ही किया जाता था। १५ दिसम्बर, १९५४ से इनको भी प्रशिक्षण-कमान के अधीन ले आया गया, जो अब अधिकारियों के उड़ान और भारतीय प्रशिक्षण दोनों के लिए उत्तरदायी है। भारतीय वायुसेना में भरती होने वाले एयरमैनो के पूरे प्रशिक्षण के लिए २६ जनवरी, १९५५ से एक सन्धारण कमान स्थापित की गयी। इसके सामान्य कृत्य हैं, विमानों और विमान इन्जनों का ओवरहाल, और विमानों, उपस्कर, विस्फोटक मोटर-परिवहन, गाड़ियाँ आदि की प्राप्ति, भण्डारण और वितरण।

१५ अगस्त, १९४७ से पहले सभी विमान-भरम्भन-डिपो पाकिस्तान में ही स्थित थे। १५ अगस्त, १९४७ को एक नया विमान-भरम्भन-डिपो कानपुर में स्थापित किया गया। बचन करने के लिए विमान-भरम्भन-डिपो और विमान-भण्डारण-यूनित को १५ अगस्त, १९४७ से एक एकीकृत मिले-जुले बेस-भरम्भन-डिपो में बदल दिया गया। यह डिपो अन्य चीजों के साथ-साथ नयी सन्धारण कमान का अंग बन गया।

१५ अगस्त, १९४८ से एक फोटोग्राफिक-टोह-उड़ान गठित की गयी। इसे १८ अप्रैल, १९५० से फोटोग्राफिक-टोह-स्क्वेड्रन नाम दे दिया गया। १९५१ के मध्य के करीब, भारत-के सर्वेक्षण के निचट सहकार से काम करने के लिए, एक सर्वेक्षण-उड़ान भी बनायी गयी। उस समय तक वायु-सर्वेक्षण-कार्य साध और कृषि-मन्त्रालय के साथ सविदा करने वाली एक विदेशी फर्म चलाने ली। इस फर्म की छात्राएँ भारत के बाहर भी थी। वायु-सर्वेक्षण कार्य अत्यन्त राष्ट्रीय महत्व का काम है। इसलिए इसे भारतीय वायुसेना में आने हाथ में ले लिया।

'वार निकोवार' (अन्दिमान और नीकोवार द्वीप-समूह में) का हवाई-क्षेत्र रॉयल एयर फोर्स के व्यक्तियों के औपचारिक नियन्त्रण में था। ३ जुलाई, १९५६ को यह भारतीय वायुसेना ने अपने हाथ में ले लिया।

१९५७-५८ में वायुसेना के नियमित स्क्वेड्रनों की मिस्टीयर, केनवरा, नेट, हंडर, मिग और ज्यादा हाल में एच एफ २४ जैसे नये प्रकार के विमानों से सज्जित किया गया। वायुसेना के इस विकास के साथ-साथ देश में विमान-उद्योग के उत्पादन का आधार भी विस्तृत हो गया है। १९५८ में सन्ध्यागत-कमान एक एयर वाइस मार्शल के प्रभार के अधीन कर दी गयी। सन्धारण-कमान के कमांडर का ओहदा भी ग्रुप कैप्टन ने बढ़ाकर एयर कर्गोडोर और बाद में १९५९ में एयर वाइस मार्शल कर दिया गया।

१९५९ में एक एयर वाइस मार्शल के अधीन एक नयी कमान बनायी गयी, जिसका मुख्यालय बलकत्ते में था। इस साल, भारी ऊंचाइयों पर सक्रिया कर सकने में समर्थ कुछ हेली-कोप्टर भी मंगाये गये। १९६० में विमान-निर्माण-डिपो, कानपुर में गुरु के. के. हाकर सिडनेयपूर के सहकार से, एव्रो-७४८ परिवहन विमान का निर्माण भी हाथ में लिया गया और कानपुर में बने विमान ने अपनी पहली सफल परीक्षण-उड़ान नवम्बर, १९६१ में भरी। उत्तरी सीमा के अपवर्ती इलाकों में सैनिकों के लिए, वायु में पूर्ति-व्यवस्था करने की बड़ी हुई बहनबद्धता के अनुसरण में १९६० में परिवहन-वेडे को बढ़ाने के लिए कदम उठाये गये। १९६१-६२ में सोवियत-संघ से भारी परिवहन विमान (ए एन १२) एम आई-१४ हेलीकॉप्टर और आई एल-१४ विमान मंगाये गये।

अक्टूबर, १९६२ के बाद वायुसेना के विस्तार में तेजी लानी पड़ी। परिवहन विमानों के वेडे में सोवियत संघ से ए०एन० १२, एन० आई० ४ हेलीकॉप्टर और आई एल १४ विमान मंगाकर (भास्पागित मुगलान की रातों पर खरीदकर), सैन्य सहायता कार्यक्रम के अधीन सं० रा० अमेरिका से सी-११९ विमान मंगाकर और कनाडा से कैरिबो मध्यम-भारी परिवहन विमान मंगाकर और वृद्धि की गयी। साथ ही कनाडा ने हमें आठ डकोटा विमान भेंट में दिये। आधुनिक और बढ़िया प्रकार के विमान आ जाने से प्रशिक्षण-मुविधाओं के लिए भी व्यवस्था की गयी। बंगलौर में विकसित बुनियादी-जेट प्रशिक्षक को जेट-प्रशिक्षण देने के काम में लाया जायेगा। एक हेलीकॉप्टर-वेडे की जरूरत भी समझी गयी और अनेक हेलीकॉप्टर मंगाये गये—स्वास्तिक एस्पूट और एम आई-४ प्रकार के। हेलीकॉप्टरों के लिए भी बंगलौर में एस्पूट हेलीकॉप्टरों का निर्माण-नाम हाथ में लेकर एक उत्पादन-आधार खड़ा करने के लिए कदम उठाये गये हैं।

विस्तार और बड़ी हुई जिम्मेदारियों के साथ, वायु स्टाफ के उपप्रमुख का एक पद वायुसेना-मुख्यालय में एयर वाइस मार्शल के ओहदे में बनाया गया। पहले वायुसेना के दो सैनिया बंगाल थे, जिनके मुख्यालय पालम और बलकत्ते में थे। जून, १९६३ में, वायु-रक्षा का ज्यादा अच्छा नियन्त्रण और पर्यवेक्षण वादस्त करने की दृष्टि में, एक तीसरा सैनिया कमान शिलांग (आसाम) के मुख्यालय के साथ बनाया गया। तीनों सैनिया कमान जो अब पालम,

इलाहाबाद (हाल में कलकत्ते से लाया गया) और शिलांग में है, वमरा पश्चिमी, मध्य और पूर्वी वायु-कमान कहे जाते हैं। वायुसेना में दो अन्य कमान ये हैं— बगलौर में मुख्यालय वाला प्रशिक्षण-कमान और सन्धारण-कमान, जिसका मुख्यालय १९६४ में बानपुर से नागपुर ले जाया गया था। पाँचों में से प्रत्येक कमान एक-एक एयर वाइंग मार्शल के अधीन है।

लडाकू डेढे में नेट जो बगलौर में निर्मित होने लगा है, एच एफ-४ (बगलौर में निर्मित करके), और मिग-२१ विमान बढ़ाकर वृद्धि की जायेगी, जिनके लिए हिन्दुस्तान एयरो-नौटिकल् लिमिटेड के प्रबन्ध के अधीन नासिर, कोरापुर और हैदराबाद में तीन नये कारखाने लगाये जायेंगे। इन्हें स्थापित किया जा रहा है। मध्यवर्ती काल की जरूरतें पूरी करने के लिए कुछ मिग-२१ विमान सोवियत-संघ से प्राप्त किये हैं।

रक्षा-आयोजना में ८५-स्वदेशीय वाली आधुनिक वायुसेना खड़ी करने की कल्पना की गयी है, जिसमें लडाकू, लडाकू-बममार, बममार, स्वातेजिक और समुद्री टोह-विमान और हेली-कॉप्टरों समेत परिवहन विमान शामिल होंगे। वायु-आक्रमण के विरुद्ध रक्षा में सुधार करने के अनिर्दिष्ट उपाय के रूप में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में परातल-प-वायु मार्गदर्शित एम्ब सनुच्चय में स्थापित किये गये हैं। वायु-रक्षा के समर्थन में ज्यादा विश्वस्त संचार पद्धति के साथ साथ रेडार की ज्यादा अच्छी व्याप्ति की व्यवस्था भी की जा रही है।

१५ जनवरी, १९६६ से वायु-स्टाफ-प्रमुख के पद का उत्थन करके उनका ओहदा एयर चीफ मार्शल का कर दिया गया और एयर मार्शल अब्रून सिंह इस ऊँचे ओहदे पर पहली बार नियुक्त किये गये। वायु-स्टाफ के उप-प्रमुख का पद भी बढ़ाकर उनका ओहदा एयर मार्शल का कर दिया गया। यह भी तय किया गया कि नौति और आयोजना-निदेशक तथा सिगनल्स-निदेशक पर भी एयर वाइंग मार्शल के ओहदे के अधिकारी रहेंगे।

वायु-स्टाफ-प्रमुख की सहायता करने वाले प्रधान स्टाफ अधिकारी अब ये लोग हैं—

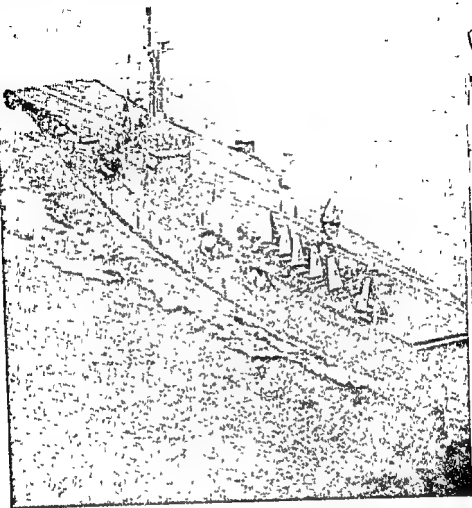
१—वायु-स्टाफ के उप-प्रमुख (एयर मार्शल) जो नीति और आयोजना, प्रशिक्षण, सिगनल्स, महायुद्ध वायु सेना और कर रक्षिति, शिक्षा और मार्ग निदेशक अन्विदेशालयों के लिए उत्तरदायी हैं।

२—वायु-स्टाफ के प्रति प्रमुख (एयर वाइंग मार्शल), जो सन्धिया (लडाकू, बममार, परिवहन और सम्भारिरी), उडान सुरक्षा, आनुषंगिक और ऋतुविज्ञान निदेशालयों के लिए उत्तरदायी हैं।

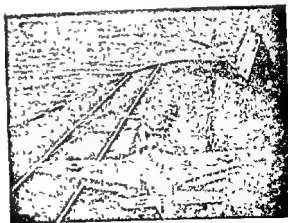
३—प्रशासन-भारक्षायक वायु अधिकारी (एयर वाइंग मार्शल), जो अधिकारियों और एयर-मैनो की सेवा शर्तों, अनुशासन, वायुसेना निर्माण शाय और विनित्ता सेवा (वायु) के लिए उत्तरदायी हैं।

४—वायु अधिकारी-भारक्षायक सन्धारण (एयर वाइंग मार्शल) जो तकनीकी और सामग्री सेवाओं, पान्थिक परिवहन, सम्मान और विनित्ता इकीनियरी के लिए उत्तरदायी हैं।

वायुसेना के अधिकारियों को दो ध्येयों में बाँटा जा सकता है, अर्थात् (क) सामान्य-कृत्य साम्रा के अधिकारी, जिनमें पाइलट और नेविगेटर आते हैं और (ख) प्रशिक्षण-कर्मच-



मार्ड एन एस विमान





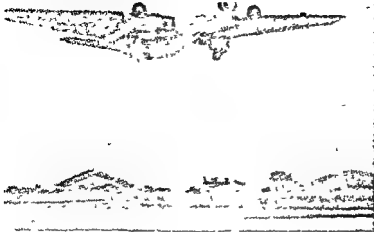
कोटा ११

वैष्णव ११

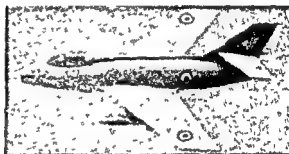
केट



वेनवरा



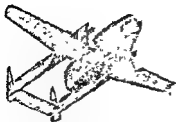
मिस्टोयर



हंटर



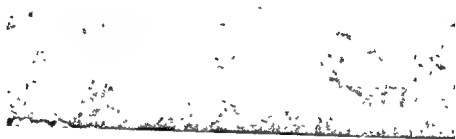




पेन्ट

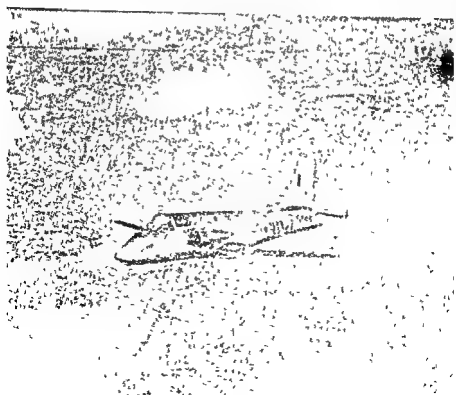
बाईकार्ड





एच एक २४

एच जे टी १६



शाखाओं के अधिकारी, जो वे हैं तबनीकी शाखा, प्रधानशाखा, सामग्री शाखा, सेवा शाखा, शत्रु विमान शाखा, शिक्षा शाखा और चिकित्सा और दन्त चिकित्सा शाखाएँ अन्तिम उल्लिखित धेनी में सेना-चिकित्सा तथा दन्तचिकित्सा-कोर में भेजे गये अधिकारी होते हैं) ।

भारतीय वायुसेना में अधिकारियों के ओहदे इस तरह हैं पाइलट अफसर, फ्लाइट अफसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वैड्रन लीडर, निग कमांडर, रुप कैप्टेन, एयर कमीडोर, एयर वाइम मार्शल, एयर मार्शल और एयर चीफ मार्शल । कनिष्ठ कमीशन प्राप्त अधिकारियों के तत्संबादी ओहदे मास्टर वारंट अफसर हैं और एयरसेना के ओहदे हैं, एयरक्राफ्ट्स मेन-नॉर्ग दो, एयर वाफ्ट्स मेन-नॉर्ग एक, सीडिंग एयर क्राफ्ट्समेन, कारपोरल और सार्जेंट ।

ठीक सेनाओं के सापेक्ष ओहदे पुस्तक के अन्त में दिये गये हैं ।

### वायुसेना आरक्षिति

आरक्षित और सहायक वायुसेनाएँ अधिनियम, १९५२ (१९५२ का ६२वा) इनके गठन की व्यवस्था करता है (एक) नियमित वायुसेना आरक्षिति भारतीय वायुसेना के सेवा-मुक्त और कार्यनिवृत्त व्यक्तियों से बना हुई, (दो) वायु-रक्षा आरक्षिति, जिसमें असेनिक पाइलट, असेनिक वायु-सापत्निक और विमान इंजीनियर और सिम्पल होते हैं, और (तीन) सहायक वायुसेना, जिसमें असेनिक स्वयंसेवकों की नामावली रखकर उसकी अद्यकालिक वायुसेना प्रशिक्षण दिया जाता है ।

भारत का ऐसा प्रत्येक नागरिक, जिसके पास उड़कपन सम्बन्धी कुछ विहित योग्यताएँ हों, अधिनियम के अधीन वायुसेना आरक्षिति के लिए पञ्चोद्योग होने के लिए दायी है अगर उसकी आयु कुछ धेणियों के लिए ३७ वर्ष और कुछ अन्य धेणियों के लिए ५० वर्ष से कम है, और फिर वायु-रक्षा आरक्षिति में नामांकित होने पर क्रमशः ४२ वर्ष और ५५ वर्ष की आयु तक सेवा के लिए दायी है ।

सहायक वायुसेना में नामांकित होने के लिए कोई भी ऐसा भारतीय नागरिक मुपात्र है, अगर वह ब्रिटिश धनों की पूरा करे । नामावली पर आने के बाद उसमें नियुक्ति या नामा-वन की धारोत में पाँच वर्ष तक सहायक वायुसेना में सेवा की अपेक्षा की जाती है । वह पाँच-पाँच वर्षों से अनधिक की प्रत्येक अवधि के लिए भी अपनी सेवाएँ अर्पित कर सकता है ।

वायुसेना आरक्षिति या सहायक वायुसेना का प्रत्येक सदस्य भारत या विदेश में प्रशिक्षण या सेवा के लिए बुलाये जा सकते का दायी है । इस अवधि के दौरान वह वायुसेना अधिनियम, १९५० के अधीन रहता है और वायुसेना के तत्संबादी ओहदों वाले वेतन और भत्तों का प्राप्त होता है । आवाहन से तत्काल पूर्व यदि ऐसा कोई व्यक्ति गैरसरकारी नौकरी में हो, तो उसके मातृक को उसके वेतन-भत्तों का वह अन्तर चुकाना पड़ता है, जो उसे प्रशिक्षण या सेवासाल के लिये बुलाये जाने पर मिलते हैं तथा जो उसे न बुलाये जाने पर अपने मातृक ने मिलता । अधिनियम के अधीन सेवा के लिए बुलाये गये किसी व्यक्ति के बारे में अधिनियम मातृक के लिए यह वाच्यकर कर देता है कि वह उसे जरूरी धुन दे दे और उसे इस तरह न बुलाये जाने पर जो भी हितनाम प्राप्त होते, उनसे साथ उसको पुनः मेवायोजित कर ले । अब मातृक ऐसा

सातवां अध्याय

## रक्षा-सेनाओं का राष्ट्रीयकरण और रियासती सेनाओं का एकीकरण

### खण्ड १ रक्षा-सेनाओं का राष्ट्रीयकरण

सत्तल मेनाओं के राष्ट्रीयकरण के निर्णय के बावजूद, आजादी के बाद कुछ वर्षों तक, ब्रिटिश अधिकारियों को नियोजन में रखना पड़ा। पहले क्या हो चुका है, यह बिना जाने ऐसे नवायोजन की जरूरत समझना सरल नहीं है। हमेशा से सभी मुख्य पदों पर ब्रिटिश अधिकारी रहे थे और इसलिए सत्ता-हस्तान्तरण के समय अपेक्षित वरिष्ठता, प्रशिक्षण और अनुभव वाले भारतीय अधिकारी सीधे-सीधे उन सभी के स्थान पर स्थान के लिए उपलब्ध न थे।

#### सेना में किंग कमीशन का दिया जाना

जैसा बताया जा चुका है, १९१५ तक भारतीय किंग कमीशन न पा सकते थे, बल्कि केवल एक निम्नतर कमीशन पा सकते थे जिसे वायसरॉय कमीशन कहा जाता था। वायसरॉय कमीशन भी सामान्यतः सीधे-सीधे नहीं दिया जाता था, बल्कि गैर कमीशन ओहदों से पदोन्नति पाने की राह दिखाया जा सकता था। इस तरह वस्तुतः भारतीय सेना में निम्नतम ओहदों पर ही भरती हो सक्ते थे। यह माँग बार-बार दुहरायी गयी थी कि भारतीय सेना में सेवा के लिए भारतीयों को वही अवसर मिलने चाहिये, जैसे कि ब्रिटिश प्रजा-जनों को मिलता है, पर ब्रिटिश अधिकारियों ने कभी इस माँग का पर्वाह उत्तर न दिया। १९०५ में हिंड मैजेस्टी की स्थानीय भारतीय थल सेना में उन भारतीयों के लिए एक विशेष प्रकार का कमीशन बनाया गया, जो तथारविन इम्पोरियल-कैडेट-कोर के पूरे पाठ्यक्रम में सफल हो जायें। लेकिन इस कमीशन में कमान-शक्ति केवल भारतीय सैनिकों के ही ऊपर थी और धारक एक रेजिमेंट-यूनिट में कप्तान-अपसर में ज्यादा उन्नति न कर सकता था। इस प्रतिबन्धित कमीशन ने स्वभावतः भारतीयों के लिए कोई प्रभावी सैन्य-जीवन के अवसर न प्रदान किये। १९१८ में प्रथम विश्वयुद्ध के अनेक रणक्षेत्रों में भारतीय सैनिकों के कुशल युद्ध के बाद ही, भारतीयों को हिंड मैजेस्टी की थल-सेना में किंग कमीशन का पात्र पहली बार घोषित किया गया और साथ

ही ब्रिटिश<sup>१</sup> और भारतीय सैनिकों के ऊपर उनको कमान-शक्ति दी गयी ।

युद्ध-काल में अधिकारियों की अविलम्बनीय जरूरत के कारण, अक्टूबर, १९१८ में अधिकारी बनने वाले कैडेटों को प्रशिक्षण देने के लिए, इन्दौर में एक कैडेट स्कूल खोला गया । पर यह एक न्यायो उपाय, युद्ध की विशेष जरूरतें पूरी करने के ही लिए, किया गया था । एक वर्ष बाद स्कूल बन्द कर दिया गया । प्रवेश दिये गये ४६ कैडेटों में से १॥ को किंग-आपात-कमीशन दिया गया । रॉयल मिलिटरी कालेज, सैंडहर्स्ट में भी रिक्त स्थान भारतीयों को आवंटित किये गये और तब से किंग कमीशन केवल उन्हीं भारतीय बालकों को दिये जाते थे, जो सैंडहर्स्ट में प्रशिक्षण पाते थे और वहाँ से उत्तीर्ण होकर जाते थे । सेना में भारतीयों को नियमित कमीशन जुलाई, १९२० से ही दिये गये, लेकिन तब भी भारतीय केवल पैदल और घुड़सवार सेना में ही कमीशन के पात्र थे, आर्टिलरी, इंजीनियर्स, सिग्नल्स या वायु-वाहक जैसी तकनीकी शाखाओं में नहीं ।

### सैंडहर्स्ट में प्रवेश के मार्ग में बाधाएँ

सैंडहर्स्ट में १० रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए भारतीय उम्मीदवारों के चुनाव के वास्ते एक सेना-प्रवेश-परीक्षा ली गयी । लेकिन यह एक मुश्की सर्चा-परीक्षा न थी । प्रवेश-परीक्षा के लिए पहले एक आरम्भिक चुनाव किया गया । आगामी परीक्षा के लिए निश्चित तिथि के बारे में घोषणा किये जाने पर, इच्छुक उम्मीदवारों को अपना आवेदन-पत्र अपने जिलाधीश के पास भेजना होता था, जो उम्मीदवार को उपयुक्त समझने पर, उसे अपने डिप्टी-जन के कमिश्नर के पास भिजवा देते थे । अगर कमिश्नर आवेदन को ठीक समझते थे, तो उसे प्रादेशिक सरकार के पास भिजवा देने थे । इन सभी अधिकारियों को स्पष्ट अनुदेश दिये गये थे कि सामान्य नियम के रूप में ऐसे ही समुदायों के उम्मीदवारों को भेजें, जिनके लोग सेना में भरती किये जाते हैं, हालांकि मध्य-वर्ग शिक्षित-वर्ग के उम्मीदवारों के दावों पर भी विचार किया जाय । जिन उम्मीदवारों के आवेदन प्रादेशिक सरकार तक पहुँच जाते थे, उन सब को राज्यपाल की अध्यक्षता वाले एक प्रादेशिक चुनाव-बोर्ड के समक्ष बुलाया जाता था । इस बोर्ड द्वारा चुने गये उम्मीदवारों को ही स्पर्धा-प्रवेश-परीक्षा में बैठने दिया जाता था । परीक्षा में एक लिखित प्रश्न-पत्र, विचित्र परीक्षा, और वायसरॉय द्वारा नामित दो बारिष्ट-तन्य अधिकारियों और एक शिक्षा अधिकारी द्वारा बने, एक बोर्ड द्वारा मौखिक परीक्षा शामिल थी । समुक्त परिणाम आ जाने पर अन्तिम चुनाव वायसरॉय द्वारा किया जाता था, जो सैंडहर्स्ट में प्रवेश के लिए चुने गये लोगों के बारे में अपनी सिफारिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास भेज देने थे । ये सब व्यौरे यहाँ पर केवल यह बताने के लिए दिये गये हैं कि एक भारतीय बालक को सैंडहर्स्ट तक पहुँचने में किननी बाधाएँ पार करनी होती थी ।

१ इस सूत्रपाठ के बाद भी सामान्य रूप से किसी भारतीय के लिए ब्रिटिश सैनिकों को कमान सम्भालने में कम से कम २५ साल और लग जाते (अर्थात् सेप्टिमेंट बर्नस का ओहदा पाने के लिए अपेक्षित सेवा-काल) ।

चुने गये भारतीय उम्मीदवार सैंडहर्स्ट में अपने को बिल्कुल नये परिवेश में पाने थे। भारम्भ में इसका नतीजा यह रहा कि उनमें से बहुत ज्यादा प्रतिशत अनुत्तीर्ण रहा। एक ओर भी बाधा थी। सैंडहर्स्ट में १८ महीने के पाठ्यक्रम का सबेरे भारतीय जनक को ११,००० रुपये देना पड़ता था, हालाँकि पिछा के सैन्य-अधिकारी होने पर भी उस कम करके लगभग ७००० रुपये मात्र रह जाती थी। इतना भारी खर्च एक औसत भारतीय मध्यमवर्गीय परिवार के जनक की क्षमता के परे होता था। फिर अगर उम्मीदवार सैंडहर्स्ट में अनुत्तीर्ण होकर कमीशन न पा सका, तो भारी खर्च करने पर भी उसे भारत प्रायः खाली हाथ ही लौटना पड़ता था। सैंडहर्स्ट जाने से पहले वह अपना उपाधि-पाठ्यक्रम पूरा न कर चुका होता था, न ही सम्भव था कि वह यू० के० में सामान्य शिक्षा के लिए फिर से स्वीकृत करे। यह बाधा सिविल सर्विस के लिए न थी, क्योंकि जो आई० सी० एस० में न आ पाते थे, वे कम से कम किसी विद्व-विद्यालय से एक उपाधि तो प्राप्त कर ही लेते थे, जो उनके स्वदेश लौटने पर एक अच्छा जीवन-धन स्रोत बनने में मदद देती थी।

### भारतीय कमीशन अधिकारियों को कमीशन दिया जाना

सैंडहर्स्ट के लिए चुने गये कैंडेडो की दीक्षित बाधाओं कम करने के लिए देहरादून में १३ मार्च १९२२ को ग्रिस ऑफ वेल्स रॉयल इन्डियन मिलिटरी कालेज खोला गया। निरन्तर चल रही भारतीय माँग के प्रति रियायत देते हुए जून, १९२५ में एक भारतीय सैंडहर्स्ट-समिति ( स्वीन समिति के नाम से भी विदित ) बनायी गयी, जिसका काम था कि किंग कमीशन के लिए सुझाव और गुण, दोनों दृष्टिकोण से, भारतीय उम्मीदवारों की प्रति में सुधार करने के और भारतीय सेना में कमीशन-वाले ओहदों के लिए, भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए तथा भारत में एक मिलिटरी कालेज स्थापित करने की बाध्यता पर विचार करने के लिए उठाये जाने वाले कदमों के बारे में जाँच करे और प्रतिवेदन दे। समिति ने सिफारिश की कि भारतीय सेना की तकनीकी शाखाओं में कमीशन पाने के लिए भारतीय पात्र होने चाहिये। समिति ने यह भी सिफारिश की कि सेना में कमीशन-ओहदों के लिए भारतीय कैंडेडो को योग्य बनाने के लिए एक भारतीय मिलिटरी कालेज भी स्थापित किया जाना चाहिये।

आगे चलकर भारतीय सैन्य-अकादेमी, देहरादून में १९३२ में स्थापित की गयी और उम्मीदवारों के पहले बैच को १९३५ में कमीशन दिये गये। इनको किंग कमीशन न देकर, भारतीय कमीशन, वायसराय द्वारा, हिड मेजेस्टी द्वारा प्रत्यक्षोक्ति प्रधिकार के अधीन, दिये गये। इसके बाद भारतीयों को भारतीय सेना में किंग कमीशन नहीं दिये गये। भारतीय सैन्य-अकादेमी में भारतीय कमीशन पाने वाले अधिकारियों को ब्रिटिश सेना के व्यक्तियों के ऊपर वह धमियाँ न मिली, जो उनको भारतीय व्यक्तियों के ऊपर मिली हुई थी। ब्रिटिश सेनिकों को दण्ड देने की कोई शक्ति उनको न मिली। उनके ऊपर कमान की शक्ति भी बड़ी सीमित थी, क्योंकि यह ऐसे ही अवसरों पर और ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन प्रयोग में लायी जा सकती थी, जो स्टेशन कमांडर या त्रिबेक कमांडर, ( जो हमेशा ब्रिटिश अधिकारी ही होते थे )

निश्चित कर दे। १९४२ में ही अब युद्ध भारत की सीमा पर पहुँच गया, तब भारतीय कमीशन-प्राप्त अधिकारियों को कमान की समान शक्ति प्रदान की गयी।

सैन्य-समिति ने अपने प्रतिवेदन में, एक वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारी के एक भाषण में से जो अंश उद्धृत किये हैं, वे बड़े रोचक हैं। यह भाषण वे, रायल मिलिटरी कातेज में भारतीय सेना में जाने वाले ब्रिटिश-जनो के आगे, भारतीयों के अधीन काम करने के भय को दूर करने के लिए, दे रहे थे। व्याख्याता ने कहा, आज (१९२५) भारतीय सेना में सात भारतीय कैप्टन हैं, जिनमें से दो तो जाने वाले ही हैं। शेष पाँच में से दो का सम्बन्ध भारतीय-यूनिटों से है, जिनमें ब्रिटिशजन सैनान नहीं किये जाते। इसलिए भारतीय सेना के कुल १५८३ कैप्टनों में से केवल तीन ही ऐसे भारतीय हैं, जिनके अधीन एक ब्रिटिश-जन को काम करने लिए कहा जा सकता है। इनमें से दो अपनी जायु के कारण मेजर के ओहदे से ज्यादा आगे नहीं जा सकते। १९२० से १९३४ तक के पन्द्रह सालों के दौरान केवल २१४ भारतीयों को किंग कमीशन प्रदान किया गया। १९३५ से १९३६ के दौरान केवल २७६ कनिष्ठ कमीशन-प्राप्त अधिकारियों को भारतीय सेना में कमीशन दिये गये। सेना के अधिकारियों की संख्या को देखते हुए भारतीयों के लिये जाने की यह सट्टा बड़ी नगण्य थी।

पर चिकित्सा-सेनाओं में भारतीयों की स्थिति ज्यादा सुन्तोपजनक थी। १९६० से ही भारतीयों को भारतीय चिकित्सा-सेवा में किंग कमीशन का पात्र माना गया था। १९२२ में दो यूरोपीय और एक भारतीय का अनुपात विहित किया गया था।

१९३८ वर्षात् दूसरा महायुद्ध होने से पहले के वर्षों में पूरी भारतीय सेना में, ४००० ब्रिटिश अधिकारियों की तुलना में, भारतीय अधिकारियों की कुल संख्या ४०६ ही थी। पल-सेना में, और अन्य दोनों सेनाओं में भी, मेजर और उसके समकक्ष पद तक पदोन्नति बेमनमान के अनुसार की जाती थी, वर्षात् अधिकारियों की न्यूनतम विहित सेवा-काल तरु सेवा करनी होती थी और विहित परीक्षा पास करनी होती थी, तभी अगले उच्च ओहदे में उनकी पदोन्नति हो सकती थी। इस सामान्य नियम को लागू करने से, १९३८ के आरम्भ तक, भारतीयों द्वारा प्राप्त किया गया उच्चतम ओहदा कैप्टन का था। जुलाई, १९३८ में एक भारतीय को मेजर के पद पर पदोन्नति दी गयी। १९३६ के आरम्भ में मेजर के ओहदे के ८ भारतीय अधिकारी से ज्यादा न थे, जब कि इस ओहदे की कुल स्थापना १०५६ थी। इस तरह यह स्पष्ट है कि अगर युद्ध न छिड़ा तो एक भारतीय के लेफ्टिनेंट कर्नल तक के ओहदे पर पहुँचने में कुछ वर्ष और लग जाते, और वह अगर पहले सेवा-निवृत्त न हो गया होता तो वह इस तरह के रेजिमेंट की कमान सम्भाल पाता। युद्ध चलने पर भी अप्रैल, १९४२ में ही एक भारतीय लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे में [ से० क० करिअपा ] कमान को सम्भाल पाया। इसी अधिकारी ने १९४६ में त्रिगेड को कमान सम्भाला। अधिकारियों की भारी कमी के बावजूद युद्ध की समाप्ति तक एक भारतीय जिस सञ्चलन पद तक पहुँचा, वह एक त्रिगेडियर का ही ओहदा था। अक्टूबर, १९४६ में सेना में त्रिगेडियर के अस्थायी या स्थापना ओहदे पर काम करने वाले केवल चार ही अधिकारी थे। कुल मिलाकर कर्नल और त्रिगेडियर के

स्थानाग्न ओहदे पर केवल एक दर्जन अधिकारी थे, हालांकि उनका मूल ओहदा मेजर का ही था।

साम ही, युद्ध गृह होने के बाद तक एक भी भारतीय सेना-मुख्यालय में स्टाफ अधिकारी के पद पर नहीं था। किसी अधिकारी के लिए आयोजना और इलाज की, और नीति-निर्माण की तकनीक को साधान् रण से समझने के लिए, स्टाफ नियुक्ति बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है। सारी समस्याओं को, एक यूनिट के नहीं बल्कि पूरे सेना के दृष्टिकोण से देखते हुए, उसमें एक व्यापक दृष्टि आती है और उसमें सरकारी नीति को अन्तर्दृष्टि पाने का भी अवसर मिलता है। इसलिए किसी अधिकारी का प्रशिक्षण केवल सैनिकी या इंजिनियरिंग की कमान सीमाने में ही पूरा नहीं हो जाता। इसीलिए चुने हुए सैन्य-अधिकारी एक सीमित अवधि तक मुख्यालय में काम करने के लिए चुने जाते हैं, जो सेवा सामान्यतः चार साल से ज्यादा नहीं होती। अद्यतनकाल में सामान्यतः केवल वे ही अधिकारी मुख्यालय के स्टाफ-पदों पर तैनात किये जाते थे, जो स्टाफ नातेज का पाठ्यक्रम पूरा कर चुके होते थे।

नौसेना की स्थिति और भी बुरी थी। रॉयल इंडियन नेवी में जो पहले दो भारतीय कमीशन देकर नियुक्त किये गये थे, वे १ सितम्बर, १९३३ को मिडशिप मैन बनाये गये थे (एच० एम० एस० चौधरी जो पाक नौ सेना में चले गये, १ सितम्बर १९३२ को मिडशिप मैन नियुक्त किये गये थे)। १९३८ के मध्य तक रॉयल इंडियन नेवी में बनाया गया उच्चतम ओहदा कैप्टन (बस-मेन में जनरल के समकक्ष) का था। कैप्टन ओहदे के छ. मंजूर पद और कमांडर ओहदे के २० पद सारे के सारे रॉयल इंडियन नेवी के ब्रिटिश अधिकारियों के हाथ में थे, सबसे बरिष्ठ भारतीय अधिकारी, दो वर्ष की बरिष्ठता वाले सेप्टिनेंट ही थे। कहना व्यर्थ है, द्वितीय विश्वयुद्ध के आरम्भ तक नौसेना मुख्यालय के स्टाफ में एक भी भारतीय अधिकारी न था। अगस्त, १९४४ में रीयर एडमिरल का पद रॉयल इंडियन नेवी में बनाया गया। जनवरी, १९४५ तक एग्जीक्यूटिव शाखा में भारतीय जिस उच्चतम मूल ओहदे तक पहुँचे थे, वह केवल सेप्टिनेंट का था और केवल छ. भारतीय रॉयल इंडियन नेवी में सेप्टिनेंट कमांडर के ओहदे पर थे। पर इजीनियरी शाखा में दो भारतीय, मूल परवारी सेप्टिनेंट कमांडर हो गये थे—उनमें से एक सितम्बर, १९४३ से कार्यवाहक कमांडर था। १ जनवरी, १९४६ को केवल तीन भारतीय अधिकारी एग्जीक्यूटिव शाखा में कमांडर के ओहदे पर थे। सत्ता-हस्तान्तरण के समय तक नौसेना के भारतीय अधिकारियों की बहुत थोड़ी ऐसी नियुक्तियाँ की गयी थी कि वे कमान या स्टाफ कार्यों का विविध अनुभव प्राप्त कर पाते।

वायुसेना की हालत भी बहुत कुछ नौसेना जैसी ही थी, पर एक बात अफसोस की कि इसमें आरम्भ से ही केवल भारतीयों की कमीशन दिये जाते थे। अतः भारतीय वायुसेना में अम्पायी कमीशन-प्राप्त कोई ब्रिटिश अधिकारी न था। लेकिन भारतीय वायुसेना संचारण और उपकरणों के लिए पूर्णतः रॉयल एयर फोर्स पर निर्भर थी, जिसके लिए अंग्रेज संस्था में रॉयल एयर फोर्स के अधिकारी भारतीय वायुसेना से संबन्ध रखते थे। १९३८ में किसी भारतीय द्वारा प्राप्त उच्चतम ओहदा पचाईंग अफसर (वेन में सेप्टिनेंट के समकक्ष) का था और भारतीय वायुसेना में केवल आधे दर्जन भारतीय पचाईंग अफसर थे। फरवरी, १९३६



में दो भारतीय फ्लाइट लेफ्टिनेंट ( थल सेना में कैप्टन और नौ सेना में लेफ्टिनेंट के समकक्ष ) के ओहदे पर आये । द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान ही भारतीय वायुसेना कुछ अवयवीय इकाई बन सकी और तब तक कोई भारतीय मुख्यालय में स्टाफ पद पर नहीं था ।

तुलना में, सिविल सर्विस की स्थिति कहीं अच्छी थी । १९३६ में १२९६ अधिकारियों की कुल संख्या में से आई० सी० एस० में १४० भारतीय थे । भारत सरकार सचिवालय में भी ४६ यूरोपीय अधिकारियों में से २१ भारतीय अधिकारी थे । वे उस समय तक भारतीय भारत सरकार के सचिव तक बन गये थे और १९४२ में भारतीय कुछ पान्ती में मुख्यसचिव तक बन चुके थे (जैसे मद्रास और मध्य प्रान्त में) । १ अगस्त, १९४७ को आई० सी० एस० अधिकारियों की कुल संख्या २२६ थी, जिनमें १२८ भारतीय थे । उस समय केवल १४ यूरोपीय आई० सी० एस० अधिकारी सचिव, सयुक्त-सचिव या भारत सरकार सचिवालय के समकक्ष पदों पर थे (अन्य १३ छुट्टी पर थे), लेकिन ४३ भारतीय आई० सी० एस० अधिकारी सचिव, सयुक्त-सचिव या समकक्ष पदों के ऊपर आरुढ़ थे । इन आँकड़ों में वे यूरोपीय और भारतीय अधिकारी शामिल नहीं हैं, जो भारतीय राजनीतिक सेवा में काम कर रहे थे । ये आँकड़े यह बताने के लिए दिये जा रहे हैं कि भारतीय सिविल सर्विस की तुलना में सशस्त्र सेनाओं का राष्ट्रीयकरण करने के लिए काफी बड़ा मैदान पार करना था ।

### राष्ट्रीयकरण समिति

सितम्बर, १९४६ के शुरू में अन्तरिम सरकार द्वारा पद-ग्रहण करते ही, सशस्त्र सेनाओं के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न बड़ी तेजी से हाथ में लिया गया । ३० नवम्बर, १९४६ के एक प्रस्ताव के अधीन सशस्त्र-सेना-राष्ट्रीयकरण-समिति एन० गोपाळस्वामी अग्रवाल के सभापतित्व में बनायी गयी\* । समिति ने १२ मई, १९४७ को अपनी रिपोर्ट पेश की, पर जब २ जून, १९४७ को सत्ता हस्तान्तरण की आयोजना घोषित कर दी गयी, तो इस समिति की सिफारिशों पीछे पड़ गयी । लेकिन इसके निष्कर्षों से उन दिक्कतों पर तो प्रकाश पड़ता ही है, जो १५ अगस्त, १९४७ को या उसके बाद पूरी तरह से राष्ट्रीयकृत बलसेना, नौसेना या वायुसेना बनाने के आगे आ रही थी ।

समिति ने बताया कि हालाँकि धक्केना में उस समय उपलब्ध अधिकारी संख्या में काफी थे, यह मान कर कि आपात बमोच्चन अधिकारियों को सेवायुक्त न किया जायेगा, पर तकनीकी शाखाओं और अतकनीकी शाखाओं में भी वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों की भारी कमी थी । हालाँकि अभिजाजित सेना में उपलब्ध भारतीय अधिकारियों की संख्या ६५४० हो

\* इसके सदस्य थे पंडित हृदय नारायण कुँजरू, मुहम्मद इस्माइल ख़ाँ, सरदार सम्पूर्ण सिंह, मेजर जनरल डी० ए० एल० वाडे, एम० सी०, त्रिनेश्वर बे० एस० तिममय्या डी० एस० ओ०, विंग कमांडर मेहर सिंह, डी० एस० ओ०, रॉयल इंडियन एयर फ़ोर्स और कमांडर एच० एम० एम० चौधरी, रॉयल इंडियन नैवी । इसके सचिव थे से० कर्नल बी० एम० कोन ।

जाती थी, उनमें से केवल ५०० ही युद्ध-पूर्व के नियमित अधिकारी थे, जो ३ सितम्बर, १९३९ से पहले सैंडहार्ट या भारतीय-मेन्स-अकादमी, देहरादून में प्रशिक्षण पा चुके थे। शेष युद्धकाल में या पदचाल कमीशन प्राप्त किये हुए अधिकारी थे। युद्धकाल में कमीशन प्रदत्त अधिकारियों को केवल संक्षिप्त प्रशिक्षण दिया गया था, ताकि वे युद्ध क्षेत्र में सीमित काम को संभालने के लिए तुरन्त समर्थ हो जायें। १० प्रतिशत से ज्यादा अधिकारियों का कुल सेवाकाल सात वर्ष से ज्यादा का न था और दान्तिकाय में सेना में मरती होने वाले अधिकारियों को दिया जाने वाला कुछ भी प्रशिक्षण उनको न मिला था।\*

भारतीय अधिकारियों के इस विवरण के समक्ष भारतीय सेना में जनवरी, १९४७ में २० साल से ज्यादा सेवाकाल वाले ८०० नियमित ब्रिटिश अधिकारी थे और १२०० नियमित ब्रिटिश अधिकारी (चिकित्सा, दन्तचिकित्सा और पशुचिकित्सा वाले अधिकारियों को छोड़ कर) २० साल से कम सेवाकाल वाले थे। २० साल से ज्यादा सेवा वालों में से अधिकांश १५ अगस्त, १९४७ तक पेंशन लेकर सेवा-निवृत्त हो गये और २० साल से कम सेवा वालों में से लगभग ७०० ब्रिटिश सेना में रख लिये गये। इनके अलावा ब्रिटिश सेना के लगभग ८००० ब्रिटिश अधिकारी थे। इनको पुनः ब्रिटिश यूनिटों में स्थानान्तरित कर दिया गया।

साथ ही लगभग ५०० धोबीबट्ट स्टाफ-नियुक्तियों में से स्टाफ-प्रशिक्षण-प्राप्त केवल २४२ भारतीय अधिकारी उपलब्ध थे। (इनमें से केवल १७ युद्ध-पूर्व प्रशिक्षित थे और शेष २२५ युद्धकाल में प्रशिक्षित थे)। बचे ही कुछ दाखानों या सेवानो के प्रतिरिक्त व्यक्तियों को,

\* उपर्युक्त पक्ष के अभाव इस सारणी में स्पष्ट हो जायेंगे -

ओहदा	सामान्य सेवाकाल	नियुक्तियों की संख्या	उपलब्ध भारतीय अधिकारी
जनरल जनरल	३०-४० साल	३८	किसी का भी सेवाकाल १७ साल से ज्यादा न था, इसलिए २० या १६ साल की सेवा वाले अधिकारी नियुक्त करने होंगे।
प्रिंसिपल और कर्नल	२० से ३५ साल	२२०	किसी का सेवाकाल १० साल से ज्यादा न था। इसलिए इस या ज्यादा साल की सेवा वाले अधिकारी नियुक्त करने होंगे।
सेनिटर्नट कर्नल	२० से ३० साल	४४०	किसी का सेवाकाल १० साल से ज्यादा न था। इसलिए १५ साल या ज्यादा सेवाकाल वाले और ३०० के लगभग युद्ध-नमीशन वाले अधिकारी नियुक्त होंगे।

और अन्यत्र के अभागों को, स्थानान्तरण या पुन प्रशिक्षण द्वारा घटाना पूरा भी कर लिया जाय, फिर भी उच्चतर कमान और वरिष्ठ स्टाफ नियुक्तियों के लिए, प्रशिक्षण और अनुभव के सामान्य मानकों के अनुसार, शीघ्र अधिकारियों की कमी बनी ही रहेगी। यह स्थिति प्रशिक्षित स्टाफ अपमरों, स्कूलों में शिक्षकों, आर्म्ड फोर, आर्टिलरी, इन्वीनियर्स, सिगनल्स और इंजनी और यान्त्रिक इन्वीनियर्स के अधिकारी-सवर्गों में नियुक्तियों में वारे में थी। इसलिए हम तथ्य का सामना करना था कि बहुत सख्या में कनिष्ठ अधिकारियों को उच्च ओहदों पर तरक्की देनी होगी, जो सामान्य स्थिति या शान्ति काल में प्रशिक्षण के सामान्य मानकों और सेवाकाल के अनुसार यथोचित न होता। १०० स्टाफ नियुक्तियों के आगे तो २४२ भारतीय अधिकारी उपलब्ध थे ही, साथ ही सशस्त्र-सेना-मुख्यालयों में अनेक दूसरी और तीसरी धेनी की स्टाफ नियुक्तियाँ थी, जिन पर सामान्यतः मेजर या कैप्टन या उनके समकक्ष ओहदे के अधिकारी रहते थे। युद्धकाल में अनुभवी सेना-अधिकारियों की कमी के कारण इन पदों पर अस्थैनिक अधिकारी थे और मई १९४७ में ऐसे १७४ अधिवारी काम कर रहे थे। सशस्त्र-सेना-मुख्यालयों में अनेक पदों के लिए विनियमों, पूर्व दृष्टान्तों और कार्यविधि का गहरा ज्ञान अपेक्षित था। इन पदों पर विशद आदेश तैयार करने और विद्यमान नियमों और आदेशों का निर्वहन करने का काम करना होता है। सशस्त्र-सेना-मुख्यालयों में, अपने प्रशिक्षण और निरन्तर सेवा के कारण, ये अस्थैनिक अधिवारी कुछ स्टाफ पद संभाल सकते थे, जिनके लिए वे उपयुक्त थे।

रॉयल इंडियन नेवी में मूलतः यह प्रस्ताव किया गया था कि बेड़े में तीन क्रूजर होने चाहिये, पर २० फरवरी, १९४७ को ब्रिटिश सरकार की घोषणा के बाद इस योजना को बदल दिया गया। रॉयल इंडियन नेवी के तत्कालीन कमांडर-इन-चीफ ने बेड़े में कम से कम एक क्रूजर रखना सबसे ज्यादा वाञ्छनीय समझा, मुख्यतः इसलिए कि वह भारतीय नौसेना के और आगे विस्तार में प्रशिक्षण मञ्च का काम दे सके और सेवा का अनुशासन सुधारा जा सके। फिर भी, वे भारतीय बेड़े में क्रूजर के न शामिल करने की सिफारिश करने के लिए विवश हो गये, क्योंकि (१) क्रूजर को कमान संभालने के लिए अपेक्षित सेवा-काल या समुद्र-गमन अनुभव वाला कोई भी भारतीय अधिकारी उपलब्ध न था, (२) कुछ तकनीकी पदों पर लगाने के लिए उपयुक्त भारतीय उपलब्ध न थे और (३) क्रूजर की फिर मरम्मत करने के लिए गोशीभाग सुविधाओं का अभाव था। वे तर्क सही थे, क्योंकि १९४७ में नौसेना में केवल सात ही ऐसे भारतीय अधिकारी थे, जिनकी वरिष्ठता कमीशन-ब्रास अधिकारी के रूप में १३-१४ साल की थी।

युद्धकाल के रॉयल इंडियन एयर फ़ोर्स एक स्क्वेड्रन से दस स्क्वेड्रन वाला होकर तेजी से बढ़ा था। इस तीव्र विस्तार के कारण प्रवीण-कर्मिकों के प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त ध्यान न दिया जा सका था। अधिकारी मर्यादा की दृष्टि से, दस साल से ज्यादा सेवाकाल वाले केवल आठ अधिकारी थे पर रॉयल इंडियन नेवी और भारतीय सशस्त्र-सेना के विपरीत इसमें किसी अन्तर्देशीय को कमीशन न दिया गया था।

राष्ट्रीयकरण के बाद पदोन्नतियों में त्वरा आ जाने में यह अनिवार्य हो गया कि ज्यादा

वरिष्ठ अधिकारी अक्षेत्रता कम आयु में उत्त्थर ओहदों पर आ जायेंगे। जब तक एक प्रकार की पदावधि-व्यवस्था जारी न की जाय, ये अधिकारी इन ओहदों पर अनुचित रूप से दीर्घकाल तक बने रहेंगे और इस तरह नौवे वालों की पदोन्नति के मार्ग में भारी बाधा सृष्टी कर देंगे।

समिति ने यह माना कि ऊपर के पदों को भरने के लिए पर्याप्त अनुभव वाले अधिकारियों की भारी कमी है। इस काम में इस बात भी भारी अड़चन थी कि अक्षेत्रता सीमित अनुभव वाले अधिकारियों द्वारा छोटी-सी हो जबकि मैं भारतीय सशस्त्र सेनाओं जैसे संगठन का कार्यभार धृष्ट किया जाना था। फिर भी समिति इस बात में प्रभावित हुई कि भारतीय अधिकारियों की अपनी योग्यता में पूरा आत्मविश्वास था और उनको जगने सक्षमों और सैनिकों का भी विश्वास प्राप्त था, जिससे वे यह काम जोर और कार्यकुशलता के साथ निभा सकते थे।

### पुनर्गठन और राष्ट्रीयकरण

जो समस्या समिति को सौंपी गयी थी, वह अविभाजित भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सम्बन्ध में थी। लेकिन स्थिति तब और भी गम्भीर हो गयी, जब यह फैसला किया गया कि १५ अगस्त, १९४७ को सशस्त्र सेनाओं का विभाजन कर दिया जाय। उपरान्त भारतीय अधिकारी दोनों डोमैनियनों के बीच बँट जाने में अधिकारियों की कमी, सावकर वरिष्ठ ओहदों और तकनीकी शाखाओं में, और भी ज्यादा उग्र हो गयी। यह स्पष्ट हो गया कि सशस्त्र सेनाओं का पुनर्गठन और उनका राष्ट्रीयकरण समय-समय नहीं चल सकता। प्रत्यक्ष ही पुनर्गठन पड़ने होना था और इसके लिए उस समय भारत में मेला कर रहे अनेक ब्रिटिश अधिकारियों की सेवाएँ प्राप्त करना अत्यावश्यक हो गया।

### ब्रिटिश अधिकारियों का नियोजन

भारत और पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं में १५ अगस्त, १९४७ के बाद काम करने के लिए उनमें स्वेच्छिक विन्यास माँगा गया। जिन अधिकारियों ने सेवा करने के लिए विन्यास दिया, उनको प्रथम एक विशेष ब्रिटिश मेला या ब्रिटिश नौमन्य सूची में रखा गया। प्रत्येक अधिकारी में पहले-पहल एक वर्ष काम करने के लिए कहा गया। उनको जो सतिखुति दी जानी थी, वह १५ अगस्त, १९४७ के अनुसार जोड़ी जानी थी और उस तारीख के बाद उनके आवेदन पर उनको देय था। रामल नेवी, ब्रिटिश सेना और रायल एयर फोर्स के नियमित अधिकारियों की भी एक मात्र नौकरी करनी थी, पर यह जगें थी कि सुप्रीम कमांडर तीन महीने की पूर्व सूचना देकर उनकी संविदा समाप्त कर सकते हैं। बाद में देखा गया कि काफी संख्या में अधिकारी और सैनिक एक मात्र एक काम करने का विन्यास नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वे अपने समय तक नौकरी के अन्त्य में नहीं खैलना चाहते। कुछ लोग छोटे से समय तक काम करना चाहते थे, जिन्होंने हाथ का काम पूरा हो जाय, जो तीन या छ महीनों में हो जाता।

इसलिए समुक्त-रक्षा-परिपद्, अबधि यथोपेक्ष, तीन, छ, नौ और बारह महीनों में बदल देने के लिए तैयार हो गयी ।

घोड़े से स्टाफ अफसरों को छोड़ कर, जो अधिकांश ब्रिटिश अधिकारी रहते थे, वे वैज्ञानिक और तकनीकी कोशों में थे अर्थात् आर्टिलरी, इंजीनियर्स, सिग्नल, बिजली और यान्त्रिक इंजीनियर्स, जिनके स्थान पर दूसरों का रखा जाना, प्रशिक्षित भारतीय अधिकारियों की भारी कमी के कारण, बिल्कुल असम्भव ही था । गैर-तकनीकी शाखाओं में भी स्थिति गहन थी । नियमित युद्ध-पूर्व प्रशिक्षण पाने वाले अधिकारियों की संख्या कम थी और ज्यादा महत्व की स्टाफ नियुक्तियों, और रेजीमेंट के ऊपर के कमान पदों को भरने के लिए उन सभी की जरूरत थी । ऐसा करने पर कैप्टन के मूलपद के ऊपर कोई भी भारतीय अधिकारी न रहता, जो किसी बड़ी यूनिट (बटालियन और रेजीमेंट) को समान सभाल सकता, (जिनकी कमान सामान्यतः कम से कम २० साल के सेवाकाल वाले लेफ्टिनेंट कर्नल द्वारा सम्भाली जाती है) । सुप्रीम कमांडर की गणना ने स्पष्ट किया कि विभाजन के बाद भारतीय सेना में ५२५० अफसरों की कमी पड़ेगी और पाक सेना में ३५५० अफसरों की । भारतीय-सैन्य-अकादमी और अधिकारी-प्रशिक्षण-विद्यालयों की प्रवेश संख्या घटाकर और वायसराय कमोडान अधिकारियों और अन्य पदधारियों को सीधे कमोडान देकर भी, जिनका जोड़ १०५० आता था, दोनों डोमीनियनों में ७७५० अधिकारियों की कुल कमी बतायी गयी । इस रिक्ति को भरने के लिए इसके अलावा और कोई चारा न था कि ब्रिटिश अधिकारियों को अस्थायी तौर पर लगाये रखा जाय ।

आगे सेवा के लिए स्वेच्छा से बने रहने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों से किये गये अनुरोध के फलस्वरूप, भारतीय सेना के ८००० ब्रिटिश अधिकारियों में से लगभग २७०० ने और रॉयल इन्डियन नेवी के २०० ब्रिटिश अधिकारियों में से लगभग १०० ने १५ अगस्त, १९४७ के बाद नौकरी में बने रहने का विकल्प दिया । बहुत से अधिकारों रॉयल नेवी, ब्रिटिश सेना और रॉयल एयर फोर्स के भी ऐसे थे, जो पुरानी भारतीय सशस्त्र सेनाओं में काम कर रहे थे और वे भी रुक जाने के लिए तैयार हो गये । १५ अगस्त १९४७ के बाद, भारत और पाकिस्तान में काम कर रहे सभी ब्रिटिश अधिकारी और अन्य पदधारी, सुप्रीम कमांडर के नियंत्रण-अधीन थे । इन लोगों को पहले एक साल के लिए रखा गया, क्योंकि यह अनुमान था कि सुप्रीम कमांडर का मुख्यालय उसमें पूर्व बन्द न होगा । पर जूँ बि सुप्रीम कमांडर के मुख्यालय का बन्द होना प्रत्याक्षित समय से पहले ही नज़र आने लगा, इसलिए १ अक्टूबर, १९४७ को सभी ब्रिटिश अधिकारियों को अपेक्षित तीन महीने की पूर्व सूचना दी गयी ( कुछ को यह पूर्व सूचना पहले ही दी जा चुकी थी ), ताकि उनकी सविज्ञा ३१ दिसम्बर, १९४७ से समाप्त की जा सके । इसके बाद यह बात भारत और पाकिस्तान के डोमीनियनों के ऊपर छोड़ दी गयी कि वे हिस्ट मैजेस्टी की सरकार में सीधे ही १ जनवरी, १९४८ के बाद ब्रिटिश अधिकारियों की अपनी जरूरत के बारे में बातचीत कर लें ।

## विभाजन के तुरन्त बाद भारत डोमोनियन की स्थिति

१५ अगस्त, १९४७ को भारत में घोड़े में ही ऐसे अधिकारी थे, जो मेना में २० साल से ज्यादा काम कर चुके थे। उस समय २१ जनरल अफसरों और ५१ रिजर्विस्टों की गणहों, पर उस समय उपलब्ध भारतीय अधिकारियों की संख्या थी—पाँच मूल पदगारों सेप्टिमेंट कर्नल और ८८ कार्यवाहक अस्थायी सेप्टिमेंट कर्नल, जो सभी किंग कमीशन-प्राप्त अधिकारी थे और १५ और २७ साल तक सेवा कर चुके थे। सेप्टिमेंट कर्नलों द्वारा धारणीय ५३० नियुक्तियों के आगे ५६० भारतीय कमीशन प्राप्त अधिकारियों और भारतीय आगल कमीशन प्राप्त अधिकारियों थे (पिछले सभी को बुद्धिमान में ही कमीशन मिला था)। इनमें से केवल ६० ही १० से १५ वर्ष तक सेवा कर चुके थे और वेप ने मेना में ५ से १० साल तक की ही सेवा की थी। सेप्टिमेंट कर्नल के ओहदे के ६३ अफसरों में से (मूल, अस्थायी या कार्यवाहक) छ मेजर जनरल बना दिये गए थे और १७ को रिजर्विस्ट के ओहदे में पदोन्नति दे दी गयी थी।

नौमेना में केवल दो ही ऐसे नियमित भारतीय अधिकारी थे, जिसका सेवाकाल रॉयल इंडियन नैवी में १० साल से ज्यादा था। ये जुलाई, १९४७ में कैप्टन के कार्यवाहक ओहदे तक आ गये थे। सेप्टिमेंट कमांडर और ऊपर के ओहदे के उपलब्ध भारतीय अधिकारियों की संख्या इस तरह थी—दो कैप्टन, तीन कमांडर और १५ सेप्टिमेंट कमांडर, एग्जीक्यूटिव गान्वा में, और १ कमांडर और चार सेप्टिमेंट कमांडर इंडीनिपर गान्वा में। विभाजन के समय रॉयल इंडियन नैवी में २११ ब्रिटिश कमीशन प्राप्त अधिकारी थे और १६ वारंट अफसर। १ अक्टूबर, १९४७ को कम कर के यह संख्या क्रमशः ४६ और ८ हो गयी थी। भारत के लिए एक अड़-चन यह भी थी कि पुर्काठन से पहले नौसेना के सभी वारंट अफसर मुसलमान थे। साथ ही उनकी भी शाखाओं में अधिकांश रेटिंग भी मुसलमान थे, जो पाकिस्तान जाने गये। उनकी कमी भी पूरी करनी थी।

वायुसेना में ११ साल से ज्यादा सेवाकाल के केवल चार ही अधिकारी थे और इनको मिलाकर कुल ३३ अधिकारी ही लगभग सात साल या ज्यादा सेवाकाल वाले थे। दो ब्रिटेनम अधिकारी १९४९ में ही घुस बैठे बने थे। ब्रिटेनम भारतीय अधिकारियों को १५ मई १९४७ को पदोन्नति देकर उसका ओहदा एयर कमींडर का बनाया गया। अक्टूबर, १९४७ में सात ब्रिटिश अधिकारी रॉयल इंडियन एयरफोर्स में नाम कर रहे थे।

इस तरह स्पष्ट है कि भारतीय अधिकारी, सामकर नौसेना और वायुसेना में, ओहदे और अनुभव में दोनों सेनाओं में, भीषे उच्चतम पदों पर, उनकी क्षमता पर प्रभाव डालते बिना, नियुक्ति के लिए बहुत ही कठिण थे। चलनेवा में भी जो सबसे बड़ी मेना है, सभी शीर्षस्थ पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में बरिष्ठ भारतीय अधिकारी उपलब्ध न थे। कुछ स्टिक पदों को भरने, और कठिण ओहदों पर भी तकनीकी शाखाओं में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए, इस कारण ब्रिटिश अधिकारियों की सेवाएँ बड़ी जरूरी थीं, ताकि तीनों सेनाओं की कार्यक्षमता कायम रहो जा सके।

## राष्ट्रीयकरण की नीति

सेनाओं का शीघ्र राष्ट्रीयकरण करने का मतलब यह होता कि कार्यदुरुस्तता में कुछ कमो आ जाती। इसका अर्थ यह भी होता कि कनिष्ठ अधिकारियों को शीघ्र पदोन्नतियाँ मिल जाती। इन खनरो के बावजूद, भारत सरकार ने नीति के रूप में यह फैसला किया कि सक्रिया कमान ब्रिटिश अधिकारियों के हाथों में न रहे और उनका उपयोग केवल अ-सक्रिया कमानों, तकनीकी शाखाओं, प्रशिक्षण संस्थापनों और बीच की स्टाफ नियुक्तियों में किया जाय। सेना-मुख्यालय में बरिष्ठ भारतीय अधिकारियों का विशेषज्ञ सलाह देने की दृष्टि से यह भी तय किया गया कि कुछ ब्रिटिश सलाहकार नियुक्त किये जायें। यह ध्यान रखना होगा कि आजादी के तुरन्त बाद सेना के बरिष्ठ अधिकारी पूरी तौर से आयोजना में हिस्सा बंटाने लगे थे, हालाँकि उनको पहले से इस काम का कोई अनुभव न था। तथापि नौसना में सक्रियामत नियुक्तियाँ तब तक ब्रिटिश अधिकारियों को देना जरूरी हो गया, जब तक भारतीयों को अपेक्षित अनुभव न हो जाय।

### भारत द्वारा नियोजित ब्रिटिश अधिकारियों के लिए शर्तें

१ जनवरी, १९४८ से ब्रिटिश अधिकारियों की सेवाएँ उधार लेने के बारे में ब्रिटिश सरकार के साथ एक समझौता किया गया, जिस के अनुसार पहले से भारतीय चलनेवा और रॉयल इन्डियन नेवो में काम करते चले आ रहे ब्रिटिश अधिकारी पूर्ववत् यू० के० की विशेष सूचियों पर बने रहे और और पहले की तरह सेवा-शर्तों और निवृत्तियों से शासित होने रहे, केवल छुट्टी और यात्रा-भाड़े के बारे में कुछ परिवर्तन किया गया। उस समय भारत या अन्यत्र काम कर रहे ब्रिटिश सेना अधिकारी ब्रिटिश-बेतन-सहिता और अन्य विनियमों से शासित होते थे और उन्हें समुद्रपार सेवा के लिए अलावा भत्ते मिलते थे। अनुशासन के मामले में भारतीय चलनेवा के कमांडर को एक अधिपत्र दिया जाना था, जिससे उसे यह अधिकार मिल जाता कि अपनी कमान में काम कर रहे ब्रिटिश सेना अधिनियम के अधीन आने वाले ब्रिटिशजनो पर मुकदमा चलाने के लिए कोर्ट मार्शल बना सकें। इस कोर्ट भागें द्वारा दिये गये कुछ दण्डों की पुष्टि सम्राट सरकार द्वारा होनी आवश्यक थी। हालाँकि इस योजना के अधीन काम कर रहे ब्रिटिशजन ब्रिटिश-सेना-अधिनियम या अन्य उपयुक्त अधिनियमों के अधीन आते थे, तथापि समझौते औसैनिक क्षेत्राधिकार बना रहा, जिसके अधीन ब्रिटिशजन भारतीय न्यायालयों में जाँच और कार्रवाई के लिए दाखी हो गये। यदि सेवाकाल में किसी समय सम्राट-सरकार ने यह फैसला किया कि ऐसी हालत पैदा हो गयी है, जिनके कारण उनका यू० के० में बुलाया जाना इष्टकर हो गया है, वे भारत सरकार को इस प्रकार सूचित करेंगे और वह तब उनके प्रत्या-वर्तन के लिए यथोचित कदम उठावेगी। भारत सरकार को भी अधिकार था कि जब भी ऐसा करना जरूरी या वाछनीय समझा जाय वह ब्रिटिश अधिकारियों के वापस आने के लिए कह सके।

चलनेवा में जरूरी समझे गये ब्रिटिश अधिकारी १ जनवरी, १९४८ से एक साल के

लिए रने गये थे, नौसेना में तीन साल के लिए और वायुसेना में दो साल के लिए, जो अवधि एक साल और बराबरी जा सकती थी। बलसेना की कुछ विविष्ट पदों की निश्चित संख्या पर अवधि २ या ३ साल या और भी ज्यादा होनी थी। सभी मामलों में दोनों में से किसी भी पक्ष द्वारा तीन महीने की सूचना देकर सेवा समाप्त की जा सकती थी।

### तीनों सेनाओं के लिए पदचरम समिति

युद्ध-पूर्व के वर्षों में जो चुनाव-बोर्ड विविष्ट नियुक्तियों के लिए बैठता था, उसे काफी संख्या में अधिकारी उस वर्ष में से चुनने होते थे, जो एक बटातिपन-कमान में पूरी पदावधि पूर्ण कर चुके होते थे। उस समय प्रश्न था कि अनेक उपलब्ध और उपयुक्त व्यक्तियों में से कुछ को चुना जाय। १५ अगस्त, १९८७ के बाद समस्या यह हो गयी कि उपलब्ध विविष्ट भारतीय अधिकारियों की सीमित संख्या को सेवाओं का पूरा-पूरा लाभ उठाया जाय।

उच्चतर ओहदों पर नियुक्तियों की संख्या निश्चय ही सीमित रहती है। अगर कोई युवा अधिकारी विविष्ट पद पर आ जाय और फिर जागे न बने, तो उसे सेवानिवृत्ति तक वहीं ठहरना होता है। उसे तो निराशा होती ही है, साथ ही यह निचले ओहदों के अनेक अफसरों का रास्ता रोक देता है। इन दोनों बातों का ही विरोध धनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। युद्ध-काल में कार्यवाहक, अस्थायी और युद्ध-मूलपद के ओहदों की पद्धति चलायी गयी थी, ताकि उच्चतर ओहदों में पदोन्नतियाँ हो जा सकें। प्रायः सभी अधिकारी इनमें से किसी एक धेनी में उच्चतर पदों पर काम कर रहे थे। यह पद्धति युद्धकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए चालू की गयी थी और स्वभावतः पुरानी पड़ चुकी थी। इसलिए अधिकारियों के ओहदों की पुनर्संरचना करना था। इस प्रयोजन से तीन पदचरम और स्थापना-समितियाँ एक-एक घनसेना, नौसेना और वायुसेना के लिए नियुक्त की गयी। उनमें कहा गया कि तीनों सेनाओं में विभिन्न पदों को दिये जाने वाले ओहदों और अपसरों के उच्चतर पदों पर पदोन्नति के लिए, अनेकित दोष्यताओं की मिकारियाँ करें। भारतीय सेना-अधिकारियों के ब्रिगेडियर, कर्नेल और लेफ्टेनैंट कर्नेल के रूप में, १ दिसम्बर, १९४७ को सेना की विभिन्न शाखाओं में सेवाकाल की तुलना, इन ओहदों में पदोन्नति के लिए विहित न्यूनतम औसत सेवाकाल से करने से, यह स्पष्ट हो गया कि कार्यकुशलता पर प्रभाव डालने बिना, सरकार भारतीय अधिकारियों को सभी ब्रिटिश अधिकारियों की जगह से सेने के लिए सीधे-सीधे पदोन्नति नहीं दे सकती।

नौसेना के कुल सभ्य ५०० अधिकारियों में से केवल एक ही भारतीय अधिकारी कमांडर का मूल ओहदा प्राप्त कर पाया था। १६ वर्ष के कुल सेवाकाल के साथ इंडोनिशिया सागर में कमांडर थे। केवल २७ अधिकारी लेफ्टीनैंट कमांडर के मूल ओहदे तक पहुँच पाये थे, जिनमें से दो विविष्टतम कार्यवाहक कैप्टेन थे। इन दोनों अधिकारियों का सेवाकाल केवल १३ साल ही था। रॉयल इंडियन नेवी के अधिकांश अधिकारी रतिवि में से स्थानांतरित होकर आये थे और उनका सेवा काल उन्ने ८ वर्षों तक का था।

वायुसेना में १ दिसम्बर, १९४७ को केवल ३६ अधिकारी बिग कमांडर या उससे



ऊपर के ओहदे के थे। इनमें से केवल ५ का ही कुल सेवाकाल १० साल से ज्यादा था,—वरिष्ठतम का सेवाकाल लगभग १५ साल था। भारतीय वायुसेना की युद्धपूर्व स्थापना में केवल एक ही स्क्वेड्रन था। फलस्वरूप सेना का वरिष्ठतम अधिकारी भी दिसम्बर, १९४७ में एकमात्र मूलपरचारी स्क्वेड्रन-लीडर था। अन्य अधिकारियों के मूल ओहदे फ्लाइट लेफ्टीनेंट या फ्लाईंग अफसर ही थे।

इन समितियों की सिफारिशों पर सरकार द्वारा सामान्य आदेश निकाल दिये जाने के बाद, तीनों सेनाओं के लिए व्यौरे तैयार करने, और इस बारे में शेष प्रश्नों को निपटाने के लिए, तीन पदक्रम और सर्वोच्च-समितियाँ बनायी गयीं। इन तीनों समितियों के सभापति रक्षा-सचिव थे और वित्तीय सलाहकार सदस्य थे। कमांडर-इन-चीफ, पसमेना, पतैंग अफसर कमांडिंग रॉयल इंडियन नेवी, और ए० एम० सी० रॉयल इंडियन एयर फोर्स सेवा विशेष से सम्बन्धित समिति के सदस्य थे।

### अन्तरिम पदोन्नति नियम और कुछ नियुक्तियों के ओहदे

अन्त में यह फैसला किया गया कि जब तक नये पदोन्नति नियम बनें, कार्यवाहक पदोन्नतियों के लिए सभी शाखाओं में सेनाओं में कई सेवाकाल की सीमाएँ काफी कम कर दी जायें। तदनुसार उपयुक्त रूप में कम की गयी सेवाएँ विहित की गयीं। उपयुक्त चुनाव बोर्डों को यह भी शक्ति दी गयी कि लेफ्टीनेंट कर्नल और ऊपर के पदों पर उन्नति के लिए अपवाद-भूत मामलों में सेवाकाल सीमाओं तक में ढील दे दें। कार्यवाहक पदोन्नति के लिए इन घटी हुई सीमाओं के शुरू होने से सवेतन कार्यवाहक और अस्थायी ओहदे और परिणामतः युद्ध-मूल ओहदा प्रदान करना २० फरवरी, १९४८ से समाप्त कर दिया गया, पर जो अधिकारी पहले ही अस्थायी ओहदे प्राप्त कर चुके थे, उनका ये ओहदे रखना अनुमत कर दिया गया। जो अधिकारी युद्ध मूल-ओहदा पा चुके थे, वे भी नये नियम बनने तक उन्हें रख सकते थे, पर जो अधिकारी अपने मूल ओहदे या उच्चतर ओहदे में किसी नियुक्ति पर न आ चुके हों, वे १९९ दिनों बाद उसका त्याग कर देंगे।

यह भी निर्णय किया गया कि सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों के ओहदे क्रमशः जनरल, वाइस एडमिरल और एयर मार्शल होने चाहए। सेना-कमांडरो का ओहदा लेफ्टीनेंट जनरल का बना रहा। मेना-मुख्यालय के प्रधान स्टाफ-अधिकारियों का ओहदा पहले लेफ्टीनेंट जनरल था, वह अब मेजर जनरल रखा गया। इसका कारण यह था कि विभाजन के बाद इन अधिकारियों की जिम्मेवारी कम रह गयी थी। सैन्य-संख्या अब कम हो गयी थी और प्रदेश-सीमा भी घट गयी थी और ब्रिटिश सैनिकों के लिए कोई भी जिम्मेवारी न रही थी। प्र० स्टा० अ० की जिम्मेवारी एरिया कमांडरो में (जो मेजर जनरल ही रहने थे) कुछ ही ज्यादा थी, पर मेना-कमांडरों (लेफ्टीनेंट जनरल) से कम थी। यह बात ओहदे में प्रकट नहीं हो सकती थी, क्योंकि कोई मध्यवर्ती ओहदा मेजर जनरल और लेफ्टीनेंट जनरल के बीच में न था। इस तरह यह तय किया गया कि प्र० स्टा० अ० के पदों पर काम कर रहे मेजर जनरलों का वेतन इस तरह तय किया जाय कि उनको एरिया कमांडरो की तुलना में कुछ ज्यादा मिले।

उनको प्राथमिकता-क्रम में एरिषा कमांडरों के ऊपर स्थान दिया गया।

यहाँ पर यह बता दिया जाय कि नौसेना और वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों को भी नये प्राथमिकता-क्रम में उनका स्थान निर्धारण करते समय मुत्त्व प्रदान किया गया। इन मेनाओं में रीमर एडमिरल या एयर वाइस मार्शल पदधारी एक-दो अधिकारी ही थे। अगर ओहदे के आधार का सस्ती से पालन किया जाता तो मेजर जनरल या उनके ऊपर के ओहदे वाले या समकक्ष अधिकारी ही जिन राज्य समारोहों में निमन्त्रित किये जाते हैं, इनमें वे दोनों सेनाओं कोई प्रतिनिधित्व न पा सकती थी। इसे दूर करने के ही कारण कमांडोर, एयर कमांडोर के ओहदे वाले प्र० स्टा० ज० को मेजर जनरलों के साथ प्राथमिकता-सारणी में शामिल किया गया। यह नौसेना और वायुसेना को महत्व देने की एक युक्ति मात्र थी। यह तीनों सेनाओं के अधिकारियों के ओहदे या हैमियत का समानोकरण नहीं है।

नौसेना में विभिन्न ओहदों के लिए सेवाकाल सम्बन्धी यह हील केवल राष्ट्रीयकरण में मदद देने के लिए दी गयी थी और यह ब्रिटिश अधिकारियों पर लागू न थी, क्योंकि उनमें से अधिकतर वरिष्ठतम भारतीय अधिकारियों में ज्यादा वरिष्ठ थे। साथ ही ब्रिटिश अधिकारियों को पदोन्नति में अलग भी न रखा गया था, पर एक ऊँची नियुक्ति को भरने में मुख्यतः विचारणीय बात यही थी कि क्या कोई भारतीय अधिकारी इस पद के लिए उपयुक्त था। यदि कोई भारतीय अधिकारी उपलब्ध न हो, तो एक ब्रिटिश अधिकारी का उस उच्चतर पद के लिए समर्पण किया जा सकता है।

भारतीय वायुसेना में भी विभिन्न ओहदों में पदोन्नति के लिए न्यूनित कुल सेवाकाल विहित किया गया।

## राष्ट्रीयकरण की प्रगति

हालांकि आरम्भ में ब्रिटिश अधिकारियों को सगाया जाना था, हर प्रक्रम में प्रत्येक उपाय किया गया कि उनकी जगह पर भारतीयों को रखा जाय। यथावश्यक चुने गये भारतीय अधिकारी प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे गये, ताकि वे उच्चतर या विशेष नियुक्तियों के लिए उपयुक्त हो जायें। वस्तुतः किसी उच्च पद पर किसी ब्रिटिश अधिकारी को लगाने, या उसने उनकी पदावधि-बढ़ाने के हर मामले में, यह बात ध्यान से देखी जाती थी कि क्या उस नियुक्ति पर रखने के लिए कोई उपयुक्त भारतीय अधिकारी मिल सकता है। इसके फलस्वरूप तीनों सेनाओं के राष्ट्रीयकरण में हुई प्रगति आगे सक्षेप में वर्णित की जा रही है।

फलसेवा—१५ अगस्त, १९४७ के पूर्व अविभाजित भारतीय सेना में १०,००० ब्रिटिश अधिकारी थे। १५ अगस्त को यह संख्या कम होकर भारत के लिए १२०० रह गयी। १ जनवरी, १९४८ के बाद भारत में नियुक्त ब्रिटिश अधिकारियों की संख्या लगभग ३०० रह गयी। १५ अगस्त, १९४४ की आर्मर्ड-फोर्स के मामले में बटाविलियो और रेजीमेंटों के कमांडरों के १० प्रतिशत से कम भारतीय थे। १ फरवरी, १९४८ को रिजर्व पलट गयी और लगभग ६५ प्रतिशत कमांडर भारतीय हो गये। जो ब्रिटिश अधिकारी रह गये, वे केवल रेजीमेंट-प्रशिक्षण-केन्द्रों के ही कमानधारी थे। अप्रैल, १९४८ तक सेफ्टीनेट कर्नल तक के सारे कमान भारतीयों के

हाथ में आ गये। फिर १५ अगस्त, १९४७ को केवल ५ प्रतिशत ब्रिगेड और सब एरिया कमांडर भारतीय रहे। १ जनवरी, १९४८ को सभी ब्रिगेडों को कमान भारतीयों के हाथ में थी और १३ सब एरिया कमांडरों में से केवल ३ ही ब्रिटिश अधिकारी थे। १५ अगस्त, १९४७ को ऐसा कोई भी भारतीय अधिकारी न था जो मेजर जनरल के ओहदे पर किसी डिवीजन या एरिया का कमानदार हो। १ जनवरी, १९४८ तक केवल दो एरिया कमांडर ही ब्रिटिश जन रह गये। बाकी सभी एरिया और डिवीजन कमानों पर भारतीय आ गये थे। तकनीकी शाखाओं, जैसे आर्टिलरी और सिग्नल्स में १५ अगस्त, १९४७ को किसी भी भारतीय को रिपोर्टिंग का ओहदा न मिला हुआ था। १ जनवरी, १९४८ तक ६० प्रतिशत पदों पर भारतीय थे और अगले अग्रेष तक यह प्रतिशत बढ़कर ८० हो गया था।

इस बीच सेना कमांडरों के प्रमुख पदों ( जिनका पदनाम जनरल अफसर कमांडिंग-इन-चीफ था ) का भी लेजी से भारतीयकरण कर दिया गया। एक भारतीय अधिकारी ने पूर्वी कमान २१ नवम्बर, १९४७ को संभाल ली। दिल्ली और पूर्वी पंजाब कमान ( जिसका नाम बाद में पश्चिमी कमान रखा गया ) २० जनवरी १९४८ को संभाल ली गयी और दक्षिणी कमान १ मई, १९४८ को। इस तरह मई १९४८ तक तीनों सेवा कमानों पर भारतीय अधिकारी आ गये।

सेना मुख्यालय में १४ अगस्त, १९४७ को एक भारतीय अधिकारी ने चीफ अफ जनरल स्टाफ का पद संभाला और दूसरे ने सैन्य-सचिव का। जनवरी, १९४८ के आरम्भ में एक भारतीय अधिकारी को एडजुटेंट जनरल बनाया गया और दूसरे को मार्च, १९४८ में क्वार्टर मास्टर जनरल। जब जनवरी, १९४६ में मास्टर जनरल आफ आर्मीनेस (एम जी. ओ.) शाखा को पुनः खोला गया तो पहला पदधारी एक ब्रिटिश अधिकारी था, जिसकी जगह एक भारतीय ने अगस्त, १९४६ में ले ली। इन्वीनियर-इन-चीफ के पद पर एक ब्रिटिश अधिकारी काफी बाद तक बना रहा। १५ अक्टूबर, १९४५ को एक भारतीय इन्वीनियर-इन-चीफ बनाया गया। अब सेना-मुख्यालय में किसी भी शाखा का प्रमुख अ-भारतीय न रहा।

सेना मुख्यालय में अब तक बरिष्ठ तकनीकी पदों पर ब्रिटिश अधिकारी अनिवार्यतः रहने पड़े, जब तक उपयुक्त भारतीय अधिकारियों ने अपेक्षित बरिष्ठता और अनुभव न प्राप्त कर लिया। तकनीकी विकास-निदेशक, छात्राध्यक्ष और उपकरण-निदेशक, सैन्य-प्रशिक्षण-निदेशक, निर्माण-कार्य-निदेशक, इन्वीनियर-इन-चीफ शाखा के अध्यक्ष, सिग्नल्स-निदेशक और सैनिक इन्वीनियरों के निदेशक के पदों पर अक्टूबर, १९४६ तक भारतीय आ गये।

१५ अगस्त, १९४७ को उस समय तक दक्षिणी कमान के जनरल अफसर कमांडिंग-इन-चीफ को भारतीय सेना का कमांडर-इन-चीफ बनाया गया, पर वे स्वास्थ्य के कारण १ जनवरी, १९४८ को पले गये और उनके स्थान पर जनरल एफ० आर० बूबर को रखा गया। १५ जनवरी, १९४६ को जनरल के० एम० करियप्पा पहले भारतीय कमांडर-इन-चीफ बने।

सेना के कुछ बरिष्ठ पदों पर निरन्तरता बनाये रखने के उद्देश्य से सरकार ने फैसला दिया कि इन पदों पर एक व्यक्ति को सामान्यतः चार साल में अधिक समय तक न रहना

चाहिए। लेकिन सेना में पदोन्नति और सेवा निवृत्ति साथ-साथ ही एक और नियम में शामिल होते हैं, जिसमें यह विहित किया गया है कि अगर कोई बरिष्ठ अधिकारी अपने निचले ओहदे पर अपनी मूल पदावधि में उच्चतर मूल पद पर पदोन्नति नहीं पा लेता, तो उसे अपने उस ओहदे की पदावधि पूरे होने पर सेना में सेवानिवृत्त होना पड़ेगा। युद्ध पश्चात् की विशेष स्थितियों में आयु और ओहदा वाला सेना का यह ढाँचा काफी असन्तुलित हो गया। यह असन्तुलन अनेक उपाय करके कम किया गया। कुछ मामलों में बरिष्ठ पदों पर काम कर रहे अधिकारियों की पदावधि बढ़ानी पड़ी, ताकि अपने निचले ओहदे पर काम कर रहे सैनिकों को बहुत जल्दी पदोन्नति न मिल जाय। कुछ मामलों में कुछ बहुत ज्यादा बरिष्ठ अधिकारियों को पदावधि चार साल में कम करना इनीशिए जरूरी हो गया। हालाँकि सरकार चार साल की पदावधि रखना चाहती थी, ताकि निरन्तरता बनी रहे, पर उस समय के विशेष कारणों को ध्यान में रखना होता। इसी कारण कुछ पदावधियाँ कम करनी पड़ी और कुछ बढ़ानी पड़ी।

नौसेना—नौसैनिक प्रशिक्षण एक सम्बन्धी प्रक्रिया है और इस समुद्रगामी सेवा में अनुभव का बहुत ही महत्व है। युद्ध-पूर्व-काल की रॉयल इंडियन नेवी एक बहुत ही छोटी सी सेना थी और हालाँकि युद्धकाल में कुछ विस्तार भी हुआ था, पर नियमित भरती की सच्चा कोई खास न बढ़ी थी। फल यह हुआ कि १९४७ तक हमारे अधिकांश नौसेना अधिकारियों का सेवा काल केवल ५ से ८ साल तक का था। ६२० कमीशन वाले अधिकारियों के सवर्ग में से केवल ६ का सेवाकाल दस साल से ज्यादा था।

१५ अगस्त, १९४७ को रॉयल इंडियन नेवी के कुल ८५० के सवर्ग में से २०० ब्रिटिश कमीशन-भ्राता और वारंट अधिकारी थे। १९४८ में अपेक्षित ब्रिटिश अधिकारियों की कुल संख्या लगभग ६० कमीशन-भ्राता और ७० वारंट अधिकारी थी। १९४७ के अन्त तक सभी रॉयल इंडियन नेवी पोतों की कमान पर भारतीय अधिकारी आ गये, जिनके पास अनेक तटीय नियुक्तियाँ भी थीं। नौसेना मुख्यालय के ७५ अधिकारियों के स्टाफ में ६ को छोड़ शेष सभी भारतीय थे।

रीयर एडमिरल जे० टी० एस० हाल को १५ अगस्त, १९४७ को रॉयल इंडियन नेवी का कमांडर-इन-चीफ बनाया गया। उनके स्थान पर अगस्त, १९४८ में वाइस एडमिरल सर एडवर्ड पैरी आये, जब आई० एन० एस० दिल्ली के अवतरण पर पहुँचे तो भारतीय नौसेना स्क्वेड्रन की कमान संभाल ली। वाइस एडमिरल सी० टी० एम० पिने ने १४ अक्टूबर, १९४९ को वाइस एडमिरल पैरी से कार्यभार संभाल लिया और फिर उनकी जगह पर २२ जुलाई, १९५५ को वाइस एडमिरल कार्लिल आये। वाइस एडमिरल आर० डी० कटारी ने २२ अप्रैल, १९५८ को पहुँचे भारतीय के हन में चीफ आफ नेवल स्टाफ का कार्यभार संभाला।

कमोडोर कर्माडिग आई० एन० स्क्वेड्रन के रूप में रीयर एडमिरल हाल के बाद उस स्थान पर कमोडोर एच० एन० एस० ब्राउन अप्रैल, १९४९ से मार्च, १९५० तक रहे। इस नियुक्ति का नाम बाद में रीयर एडमिरल कर्माडिग आइ एन० स्क्वेड्रन और फिर आगे चल-कर फर्गेस अक्सर, फ्लोटिला, भारतीय नौ बेड़ा रख दिया गया और इस पर एक-एक करके रॉयल नेवी के चार रीयर एडमिरल रहे। पहला भारतीय इस नियुक्ति पर २ अक्टूबर, १९५६

को रोयर एडमिरल के ओहदे में आया। दिसम्बर, १९५१ से दिसम्बर, १९५४ तक की अवधि में कैप्टन अधीक्षक, आई० एन० डोक्याड, नौसेना सचिव (नौसेना मुख्यालय), कमोडोर भार-सायक, कोचीन, नौसेना स्टाफ उच्च-प्रमुख, कमोडोर मारसायक, बम्बई, सामग्री-प्रमुख (नौसेना मुख्यालय) और नौसेना इंजीनियरिंग निदेशक के पदों पर भारतीय अधिकारी आ गये। एक भारतीय सिविलियन अधिकारी ने फरवरी, १९५५ में शस्त्रान्वृत्ति-निदेशक का पद सम्भाल लिया।

१९५७ के आरम्भ में नौसेना स्टाफ प्रमुख के अचावा जो बोटे स ब्रिटिश अधिकारी अब भी नौसेना में काम कर रहे थे वे अधिकारित शस्त्रान्वृत्ति-निदेशालय, शस्त्रान्व-निरीक्षण-निदेशालय में और नौसेना उड्डयन, नौसेना-निर्माण और नौसेना-संचार में तकनीकी अधिकारी थे। नौसेना के विस्तार और तकनीकी भारतीय अधिकारियों की कमी के कारण सेना की कार्य-कुशलता को क्षति न पहुँचे इसलिए कुछ और काल तक ब्रिटिश अधिकारियों का लगाया जाना आवश्यक हो गया था।

मुख्यालय में नौसेना-उड्डयन के प्रमुख के पद को, जिस पर अब तक रॉयल नेवी का एक अधिकारी था, अप्रैल १९६२ में एक भारतीय ने संभाल लिया और इस परिवर्तन के बाद नौसेना का पूरा-पूरा भारतीयकरण हो गया।

वायुसेना—पन्द्रह अगस्त, १९४७ से पहले रॉयल इंडियन एयर फोर्स की यूनिटों में १०० रॉयल एयर फोर्स अधिकारी और १०० रॉयल एयर फोर्स के एयरमैन काम कर रहे थे। १५ अगस्त, १९४७ के बाद तुरन्त सभी बरिष्ठ स्टाफ और सक्रियतापन पद भारतीयों ने संभाल लिये और केवल कुछ तकनीकी पदों पर ब्रिटिश अधिकारी रह गये। दिसम्बर, १९४७ के अन्त तक केवल छह ही रॉयल एयर फोर्स के अधिकारी रह गये थे। सरकार ने वायुसेना के विकास को बहुत अधिक महत्व दिया और इस नीति के अनुसार विशेषीकृत ज्ञान की अपेक्षा करने वाले पदों के लिए कुछ और रॉयल एयर फोर्स अधिकारियों की सेवाएँ प्राप्त करनी पड़ी। वही कारण था कि १९४७ से बाद के कुछ वर्षों में भारतीय वायुसेना में काम करने वाले ब्रिटिश अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हुई।

१५ अगस्त, १९४७ को रॉयल इंडियन एयर फोर्स के बरिष्ठतम भारतीय अधिकारी को रॉयल इंडियन एयर फोर्स का उप-वायु-कमांडर और वायु-मुख्यालय में बरिष्ठ-वायु-स्टाफ अधिकारी नियुक्त किया गया। उनको १५ नवम्बर, १९४७ को एयर वाइस मार्शल के ओहदे पर पदोन्नति दी गयी, जब उनको डिप्टी चीफ आफ एयर स्टाफ का पदनाम दिया गया।

१५ अगस्त, १९४७ को भारतीय वायुसेना के कमांडर-इन-चीफ का पद संभालने के लिए एयर मार्शल सर थामस वाकर एमहर्स्ट को चुना गया। उनके बाद एयर मार्शल सर रोल्फ माइक्ला चैम्पैन और एयर मार्शल जी० ई० गिब्स क्रमशः मार्च, १९५० और दिसम्बर, १९५१ में आये। पहले भारतीय अधिकारी एयर मार्शल एम० मुखर्जी ने १ अप्रैल, १९५४ को भारतीय वायुसेना के प्रमुख का पद सम्भाला और इस तरह अब इस सेना का पूर्ण राष्ट्रीय-करण हो गया। उसी दिन राष्ट्रपति ने रत्नचक्र प्रदान करने सेना का सम्मान दिया।

१५ अगस्त, १९४७ के बाद भारत में नियुक्त ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भी गयी



जनरल के० एम० करियप्पा  
मेना के प्रथम भारतीय चीफ

वाइस एडमिरल आर० डी० कटार  
नौसेना के प्रथम भारतीय चीफ



एयर मार्शल एस० मुजुमर्दी  
वायुसेना के प्रथम भारतीय चीफ

विशिष्ट सेना को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया जाना चाहिए। इस प्रसंग में २५ मार्च, १९५५ को लोक सभा में दिये गये प्रधान मंत्री के भाषण का एक उद्धरण नीचे दिया जा रहा है।

‘मैं कहना चाहूँगा कि पिछले कुछ वर्षों में जो ये ब्रिटिश अधिकारी हमारे यहाँ रहे हैं, उन्होंने रक्षा-सेनाओं में बड़ा ही उत्तम काम किया है और मैं उनके काम की बड़ी सराहना करना चाहूँगा कि उन्होंने तीनों सेनाओं के विकास में किन्ने मनोयोग से काम किया है खासकर नौसेना और वायुसेना में, जो अपेक्षतया अविकसित थी—सेना तो हमारे देश में काफी विकसित थी—और सब तरफ काफी सुधार हुआ है।

इसके प्रतीकस्वरूप हो एयर मार्शल एम्ब्रस्ट और एयर मार्शल गिम्स को भारतीय वायुसेना के चीफ एयर स्टाफ और कमांडर-इन-चीफ के पद से मुक्त होने पर एयर मार्शल का मानद ओहदा दिया गया। इसी तरह मुख्यालय में १९४८ से १९५५ तक इन्जीनियर-इन-चीफ के पदधारी मेजर जनरल विलियम्स को सेना में लेफ्टीनेंट जनरल का मानद ओहदा दिया गया।

### ब्रिटिश अधिकारी—अनुशासन

हालाँकि हम बात का अब केवल दैक्षिक महत्व है, फिर भी एक भारतीय अधिकारी द्वारा सेना के प्रमुख का पद संभाल लिये जाने के बाद, ब्रिटिश अधिकारियों के अनुशासनात्मक मामलों के बारे में की गयी व्यवस्था का, यहाँ चर्चेस किया जा सकता है। नवम्बर, १९४७ में सम्राट्-सरकार से हुए कटार के फनस्वरूप, जब जनरल करिष्पा जनरली, १९४९, में भारतीय सेना के कमांडर-इन-चीफ बने, तो ब्रिटिश सेना के अधीन एक रायल वारंट उनकी प्रदान किया गया, जो ब्रिटिश-सेना-अधिनिषेध के अन्तर्गत ब्रिटिश व्यक्तियों की जाँच के लिए कोर्ट मार्शल बनाने और कुछ मामलों में दण्ड की पुष्टि करने से सम्बन्धित था। जनरल करिष्पा सम्राट् की शन सेना में किय-कमीशन प्राप्त थे, इसलिए यह सम्भव था। २९ जनवरी, १९५० को जब भारत गणराज्य बन गया तो उन्होंने और किय-कमीशन-धारी अन्य लोगों ने उस कमीशन का त्याग कर दिया और तब कोर्ट मार्शल खरी करने की शक्ति उन्हें देने वाला रायल वारंट अप्रभावी हो गया।

जैसा बताया जा चुका है, ब्रिटिश अधिकारियों के प्रसंग में अनुशासन के प्रश्न का केवल दैक्षिक महत्व है। एक ब्रिटिश अधिकारी की जाँच के लिए कोर्ट मार्शल खरी करने का प्रश्न ही न था, क्योंकि जुने गये थोड़े से ऐसे ही लोग रह गये थे, जो भारत में सेवा करने के लिए सहमत हो गये थे। इसलिए ऐसी कोई जरूरत न पड़ी कि किसी ब्रिटिश अधिकारी को, भारतीय सेना में काम कर रहे ब्रिटिशजनों को कमान सम्भालने वाला, ब्रिटिश अधिकारी औपचारिक रूप में नियुक्त किया जाय। लेकिन खासकर सैन्य-प्रशासनों में यह चल्न है कि अनुशासन के बारे में जानबूझकर कोई त्रुटि न छोड़ दी जाय। फनस्वरूप, प्रशासन या अनुशासन के प्रयोजन में, भारतीय सेना में काम कर रहे ब्रिटिश अधिकारी और अन्य पदधारी, औपचारिक रूप से, सम्राट् की शन सेना में कमीशन प्राप्त वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारियों की कमान के अधीन रख दिये गये थे।

नौसेना के मामले में ब्रिटिश नौसेना के एक वाइस एडमिरल ही चीफ ऑफ नेवल



स्टाफ थे और उनको सम्राट्-सरकार ने एक कोर्ट मार्शल वारण्ट प्रदान कर दिया था, ताकि जल्दत पड़ने पर वह भारतीय नौसेना में काम कर रहे, रॉयल नेवी के अधिकारियों द्वारा किये गये अपराधों की जांच के लिए, कोर्ट मार्शल बनाने का आदेश दे सकें। इसी तरह वायुसेना के मामले में १ अप्रैल १९५४ तक एक रॉयल एयर फोर्स के अधिकारियों के हाथ में भारतीय वायुसेना की कमान थी और सम्राट्-सरकार ने उनको भी ऐसा ही कोर्ट-मार्शल-वारण्ट, भारतीय वायुसेना में काम कर रहे रॉयल एयर फोर्स के व्यक्तियों के बारे में कोर्ट मार्शल द्वारा जांच करने के लिए, प्रदान कर दिया था।

सौभाग्य से ऐसा कोई अवसर न आया कि ब्रिटिश सेना, रॉयल नेवी या रॉयल एयर फोर्स के किसी अधिकारी के सम्बन्ध में, भारत की सशस्त्र सेनाओं में काम करते समय, इस उपबन्ध को प्रयोग में लाया जाय।

### आर्डनेंस कारखाने

सशस्त्र सेनाओं के तीनों स्वर्यों के अपाधा आर्डनेंस कारखानों में भी विदेशी व्यक्ति काम कर रहे थे।

यहाँ भी तेजी से भारतीयकरण किया गया। उदाहरण के लिए इस संगठन में ज-भारतीयों की संख्या १५ अगस्त, १९४७ को ६६ की जगह पर १९५६ में ३० रह गयी। इन ३० अधिकारियों में भी अधिकांश स्थायी अफसर थे, जो सामान्यतः वाढंक्व आयु तक काम करते। बाकी सविदा पर थे, जो १९५८ को समाप्त हो रही थी।

### खण्ड २—भारतीय रियासती सेनाओं का भारतीय सेना के साथ एकीकरण

जब सशस्त्र सेनाओं का पुनर्गठन और राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था, तो एक तुरन्त ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण समस्या भूतपूर्व देशी रियासतों की सेनाओं का भारतीय सेना के साथ एकीकरण की भी समस्या थी।

ब्रिटिश काल में सभी बड़ी रियासतों के पास अपनी-अपनी सेनाएँ थी। ये १८६९ में भूलतः सम्राट् के अधीन सेवा के लिए सैनिक प्रदान करने के लिए गठित की गयी थी और इनको इम्पेरियल सर्विस ट्रूप्स कहा जाता था। ये सेनाएँ देशी रियासतों के नरेश अपने ही स्वयं पर सही और सन्धारित करने थे और भारत सरकार का, स्थायी रण से सैन्य सलाहकार और सहायक सैन्य सलाहकार के रूप में, भारतीय सेना के कुछ ब्रिटिश अधिकारियों का स्टाफ, देशी नरेशों को उनकी रियासतों की सेना गठित और प्रशिक्षित करने में मदद और सलाह देता था। इस स्टाफ का प्रमुख गिनिटरी एडवाइजर-इन-चीफ था। वह एक बरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारी, साधारणतः मेजर जनरल के ओहदे वान्त होता था। सैन्य-सलाहकार-स्टाफ राजनीतिक विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में था।

१९१४ में प्रथम विश्वयुद्ध होने से पहले उनतीस देशी रियासतों में इम्पेरियल सर्विस

द्रुप्त थी। युद्ध में प्राप्त अनुभव के फलस्वरूप, इन सेनाओं का पुनर्गठन जरूरी समझा गया, ताकि इनकी यूनिटों और भारतीय सेना की संवादी यूनिटों के बीच की असमानता यथासम्भव दूर की जा सके। नरेशों और रियासतों के प्रतिनिधियों की एक प्रवर समिति में सुधार-प्रस्तावों पर चर्चा की गयी और प्रवर समिति द्वारा की गयी सिफारिशों की मदद से १९२० की देशी रियासत सेना-योजना तैयार की गयी। पुनर्गठन के अनुसार देशी रियासतों की सेनाओं में तीन तरह के सैनिक रहे, अर्थात् .

**वर्ग-क** भारतीय सेना की पद्धति पर गठित सैनिक, जो नियमित भारतीय सेना की संवादी यूनिटों जैसे ही शस्त्रास्त्र से लैस किये गये।

**वर्ग-ख** जो सैनिक प्रशिक्षण और अनुशासन की दृष्टि से वर्ग-क के समकक्ष थे, पर भारतीय सेना की यूनिटों की तरह गठित और सज्जित न थे, और

**वर्ग-ग** . मुख्यतः भित्तिशिवा विरचना वाले सैनिक, जिनके वर्ग-ख की तुलना में प्रशिक्षण, अनुशासन और शस्त्र के मानक निचले थे।

इस पुनर्गठन के बाद इम्पोरियल सर्विस द्रुप्त का नाम देशी रियासत सेना (इंडियन स्टेट फोर्स) रख दिया गया और पहले बार रियासत के भीतर आन्तरिक सुरक्षा आवश्यक करने के लिए देशी रियासतों की सेनाओं का उपयोग उनका एक वैध, हालांकि अप्रधान कार्य माना गया।

इस योजना के अधीन कोई सैनिक-संख्या स्थिर न की गयी थी, क्योंकि वस्तुतः ऐसा उपबन्ध न रहने पर भी किसी भी वृद्धि की प्रत्याशा न की गयी थी। जब कभी कोई रियासत कोई नयी यूनिट खड़ी करने की इच्छा व्यक्त करती थी, तो मुख्यतः जिस बात पर ध्यान दिया जाता था, वह यह थी कि क्या इस राज्य के पास इस वृद्धि के पोषण के लिए पर्याप्त पैसा है। इसलिए हालांकि १९२० की योजना का एक उद्देश्य कार्यकुशलता बढ़ाना था, नतीजा यह हुआ कि कार्यकुशलता का महत्व संख्या की अपेक्षा कम हो गया। भारत सरकार को देवता भी असीमित थी, क्योंकि देशी रियासत के दो वर्गों के लिए शुरु में शस्त्र और उपकरण निःशुल्क प्रदान करने की उसकी जिम्मेवारी असीमित थी। इन कारकों से एक नयी योजना, देशी-रियासत-योजना, १९३६ में बनायी गयी। अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और युद्ध की आसन्नता के कारण दरबारी से पहले विमर्श सम्भव न था। यह योजना कमांडर-इन-चीफ के अधीन एक छोटी-सी समिति ने बनायी। इस तरह रियासतों पर अपना एक अन्तिम निर्णय थोपा दिया गया। पहले की तरह नयी योजना भी स्वल्पतः ऐच्छिक थी, पर उसमें एक यह महत्वपूर्ण उपबन्ध था। सम्राट के प्रतिनिधि को यह विवेकाधिकार था कि वह इस योजना में किसी रियासत का शामिल होना स्वीकार या अस्वीकार कर सकता था और किसी रियासत के योजना में प्रवेश की एक शर्त यह थी कि रियासत में कोई नयी यूनिट बनाने या किसी विद्यमान यूनिट की भंडार को नयी सख्या बढ़ाने-घटाने या भंडार सफाई में कुछ भी परिवर्तन करने के लिए सम्राट के प्रतिनिधि से पहले भंडारों से ली जाय। सम्राट के प्रतिनिधि को यह भी अधिकार था कि योजना में शामिल हो चुकी किसी रियासत से प्रवेश की किसी शर्त के

उल्लंघन पर योजना में अलग होने के लिए कह दें।

१९३६ की योजना के अधीन अपनी-अपनी भूमिका के अनुसार देशी रियासत मेना की यूनिटों का यह वर्गीकरण किया गया

(क) फोल्ड सेवा यूनिटें—जिन यूनिटों के बारे में अनुमान किया गया कि आपात के समय सेवा के लिए सम्राट् की भारतीय सेना के साथ सम्राट् के प्रतिनिधि को सौंप दी जायेंगी।

(ख) सामान्य सेवा यूनिटें—जिन यूनिटों के बारे में पहले पहल (क) के अनुसार सेवा करने की प्रत्याशा नहीं की गयी थी, पर उन्हें भी सम्राट् के प्रतिनिधि को सौंपा जा सकता था। प्रशिक्षण, संगठन तथा दूसरे मामलों में से यूनिट फोल्ड सेवा यूनिटों के प्रायः बराबर थी।

(ग) रियासत सेवा यूनिटें—जिन का प्रमुख काम रियासत की आन्तरिक सुरक्षा की देखभाल करना था।

योजना के आरम्भ होने के बाद सीधे ही एक चौथा वर्ग भी बन गया, चाकि ऊपर के वर्गों में न आ सकने वाली फुटकर यूनिटों को रखा जा सके, जैसे प्रशिक्षण यूनिटें, बेतार अनुभाग आदि। इन सब को 'अवर्गीकृत' नाम दिया गया।

रियासतों द्वारा रखी गयी अनियमित यूनिटों को भारत सरकार ने मान्यता न दी और वे पूर्णतः सम्बन्धित रियासत की ही जिम्मेदारी में रही। भोताल, रोवा, धौलपुर और धार को छोड़ कर शेष सभी रियासतों ने १९३६ की योजना स्वीकार कर ली।

फोल्ड सेवा यूनिटें, योजना में बताये गये शस्त्रों और सामग्रियों का आरम्भिक प्रदान और पुनः स्थापन, पा सकती थी, जैसे पिस्तौलें, रायफल्स, आर्टोमेटिक आदि। सामान्य सेवा यूनिटें भी यही शस्त्रास्त्र पा सकती थी, पर सागत मूल्य पर राज्य के खर्च पर। राज्य सेवा यूनिटें भी अपने कार्य के स्वरूप के अनुसार राज्य के खर्च पर सागत मूल्य में शस्त्रास्त्र पा सकती थी, पर सामान्यतः उनके लिए आर्टोमेटिकों की पूर्ति अधिकृत न थी। पर पिछले युद्ध में ये नियम काफी बदल गये थे। प्रथम विश्व युद्ध में इम्पीरियल स्टेट ट्रुप्स की संख्या १२००० हो गयी थी और उनमें से लगभग १८०० ने विदेशों में काम किया। देशी रियासत सेना की कुल संख्या दूसरे महायुद्ध के समय लगभग ८७००० थी, जो जनवरी, १९४४ में बढ़कर ९८००० तक पहुँच गयी थी और इन में से केवल ३६००० ही विदेश में या भारत में सम्राट् की सेवा में लगाये गये थे। पर इस भारी संख्या के बावजूद अपेक्षितवा नहीं कम यूनिटों का सक्रिय विरचनार्जो में इस्तेमाल किया गया।

दूसरे विश्व युद्ध के तुरन्त बाद देशी रियासत सेना के भविष्य के बारे में चर्चा हुई। हालांकि यह माना गया कि युद्ध छिड़ने पर रियासतों मेना भारतीय सेना का एक विस्तार मानी जायेंगी, पर यह तय किया गया कि देशी रियासत सेना का मुख्य काम रियासत की आन्तरिक सुरक्षा ही होना चाहिये। भोटे सौर पर यह निश्चित किया गया कि इस मेना में दो तरह की यूनिटें होनी चाहिये अर्थात् (क) सामान्य सेवा यूनिटें, जो भारतीय सेना की

## राष्ट्रीयकरण और एकीकरण

यूनिटों की ही तरह गठित और सन्वारित की जायें, और (ख) स्थानीय या रियासत सेवा यूनिटों, जो आन्तरिक सुरक्षा के लिए गठित और सन्वारित की जायें। लेकिन इस बारे में और कदम उठाये जायें, इसमें पहले ही साविधानिक हलचलें सामने आ गयीं।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, प्रमुख सैन्य सलाहकार (मिलिटरी एडवाइजर-इन-चीफ) का मुख्यालय राजनीतिक विभाग का अंग था और इसका मुख्य कार्य था, समन्वय, पर्यवेक्षण और सलाह देना। मुख्यालय के स्टाफ के अलावा स्थानीय सलाहकार अम्बाला, जयपुर, जालिमर, इन्दौर, राजकोट और हैदराबाद में स्थित थे और साथ ही तकनीकी सैन्य सलाहकार रडकी, भिमसा, कोरोजपुर आदि सुविधाजनक केन्द्रों में स्थित थे। सैन्य सलाहकार के अमले में पूरे तरह ब्रिटिश अधिकारी ही थे।

भारत सरकार के राज्य विभाग की स्थापना ५ जुलाई, १९४७ को की गयी। १५ अगस्त, १९४७ को प्रभुसत्ता के व्यपगत हो जाने पर देशी रियासतों की स्थिति की सम्मिलन-लिखतों और उनके द्वारा भारत के डोमिनियन के साथ किये गये यथास्थिति करार के प्रकाश में देखना होगा। इस तरह सम्राट के प्रतिनिधि का स्थान व्यवहारतः भारत सरकार के राज्य-मन्त्रालय ने ले लिया।

१५ अगस्त, १९४७ से राजनीतिक विभाग समाप्त हो गया। उसी तारीख से विभाग द्वारा पहले निकाले गये आदेश द्वारा, देशी रियासत सेना के प्रमुख सैन्य सलाहकार को, दोनों डोमिनियनों ने, संयुक्त रूप से अपनी सेवा में रख लिया। सरकियों के सैन्य सलाहकारों और उनके अपने के पद समाप्त कर दिये गये। इस तरह प्रमुख सैन्य सलाहकार का मुख्यालय दो अलग संगठनों में बँट गया, एक भारतीय डोमिनियन के लिए और दूसरा पाकिस्तानी डोमिनियन के लिए। प्रत्येक एक अलग उप-प्रमुख सैन्य-सलाहकार के अधीन था और ये दोनों प्रमुख-सैन्य-सलाहकार के अधीन थे। प्रमुख-सैन्य-सलाहकार सेना-मुख्यालय, भारत के प्रति उत्तरदायी थे और उसके जरिये भारत के रक्षा-मन्त्रालय के प्रति, उन रियासतों के बारे में जो भारत संघ में शामिल हो गयी थीं, और पाकिस्तान के रक्षा-विभाग के प्रति, उन रियासतों के बारे में जो पाकिस्तानी डोमिनियन में शामिल हो गयी थीं। पर वे समुक्त-रक्षा-परिपद के प्रति उत्तरदायी न थे और, दो तरह की हैसियत रखते हुए भी वे भारत और पाकिस्तान के प्रति समुक्त उत्तरदायित्व वाले पद पर न थे।

सैन्य-सलाहकार-संगठन (जो अब तक राजनीतिक विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में रहा था और जिसकी जगह अब राज्य-मन्त्रालय ने ले ली थी) इस तरह रक्षा-मन्त्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण में आ गया। वस्तुतः १५ अगस्त, १९४७ के कुछ प्रारम्भिक सप्ताहों में इस संगठन का कार्य चपल पुल की स्थिति में था। शीघ्र ही यह निर्णय लिया गया कि १५ अक्टूबर, १९४७ से प्रमुख-सैन्य-सलाहकार का पद समाप्त कर दिया जायेगा। वस्तुतः देशी रियासत सेना के सैन्य-सलाहकार १ नवम्बर, १९४७ से भारतीय सेना-मुख्यालय में आ गये और उन्हें देशी रियासतों की सशस्त्र सेनाओं के प्रशिक्षण और प्रशासन का काम सौंपा गया। वे ब्रिगेडियर के ओहदे के एक यूरोपीय अधिकारी थे और चीफ ऑफ दि जनरल स्टाफ के निदेशाधीन काम करते थे।

हालांकि शुरू में राज्य-मन्त्रालय ने यह मान लिया था सैन्य-सलाहकार-संगठन रक्षा-मन्त्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण में रहे, पर धीमे ही उन्होंने समझ लिया कि इस संगठन का कार्य अधिकांशतः राजनीतिक था और तब उन्होंने यह इच्छा प्रकट की कि यह संगठन उनके प्रशासनिक नियन्त्रण में कर दिया जाय। वस्तुतः १९४७ से भी पहले, तीन अलग-अलग अवसरों पर, इस प्रश्न पर विचार किया गया था कि प्रमुख-सैन्य-सलाहकार का नाता सामान्य मुख्यालय (अब सेना-मुख्यालय) के साथ होना चाहिये या राजनीतिक विभाग से, पर यह सोचा गया था कि उसे राजनीतिक विभाग के ही साथ रहने दिया जाय, क्योंकि देशी रियासत सेना सम्बन्धी मामले बहुत कुछ राजनीतिक प्रकार के होते हैं। पर रक्षा-मन्त्रालय का विचार था कि १५ अगस्त, १९४७ के बाद स्थिति में आबूझ परिवर्तन आ गया है, क्योंकि एक जापान जैसी स्थिति आ गयी है और रियासतों से राज्यों और उपकरणों को ऐसी मांग आ रही है, जिसकी पूर्ति उसी दिन की जानी चाहिये। साथ ही निष्पक्षमार्थी और धारणाधीन समस्याओं के निपटारे के लिए और सीमा-संधियों से संरक्षण के लिए भी रियासतों सैन्य-मदद की मांग कर रही है। यह काम बड़ी तेजी से किया जाना है, जिसके लिए सशस्त्र सेना-मुख्यालयों और देशी रियासतों के बीच निकट का सम्पर्क होना चाहिये। इस कारण कुछ समय तक सैन्य-सलाहकार-संगठन रक्षा-मन्त्रालय के अधीन बना रहा। स्थिति का पुनर्विलोकन करने के बाद जनवरी, १९४८ में यह निर्णय लिया गया कि सैन्य-सलाहकार देशी रियासत सेना का राज्य-मन्त्रालय के अधीन रहना ज्यादा उपयुक्त होगा। तदनुसार उक्त संगठन का प्रशासनिक नियन्त्रण १ मार्च, १९४८ से राज्य मन्त्रालय को सौंप दिया गया और तब तक वह उसी के अधीन बना रहा जब तक कि रियासती सेना के एकीकरण का अधिकांश पूरा न हो गया।

जब सैन्य-सलाहकार-संगठन रक्षा-मन्त्रालय के अधीन आया तो यह बाह्यनीय समझ गया कि सैन्य-सलाहकार, देशी रियासत सेना, के पद पर एक भारतीय होना चाहिये। ज्यादा अच्छा हो कि वह किसी देशी रियासत की ही प्रजा हो, ताकि रियासतों में विश्वास पैदा किया जा सके। इसलिए जनवरी, १९४८ के आरम्भ में इस पद पर मेजर जनरल हिम्मत्सिंह जी को नियुक्त किया गया। बाद में मुख्यालय के अमले के अलावा सैन्य-सलाहकारों के दो और पद (जिनका नाम अगस्त, १९४८ में रियासती सेना-सम्पर्क-अधिकारी कर दिया गया) लेफ्टीनेंट कर्नल के ओहदे के बनाये गये, एक दक्षिणी देशी रियासतों के लिए जिसका मुख्यालय बंगलूर में था, और दूसरा पश्चिमी देशी रियासतों के लिए जिसका मुख्यालय राजकोट में था। व्यक्ति-संगत रूप से मुख्यतः स्थित सैन्य सलाहकार का पदनाम १९४८ में फिर प्रमुख-सैन्य-सलाहकार, देशी रियासत सेना, कर दिया गया।

अब रक्षा एजेंड्रीय विषय था, इसलिए किसी भी सघटक इनाई के लिए एक अनग सेना रचना विलुप्त जल्दी न रह गया। भूतपूर्व देशी रियासतों को ब्रिटिश भारत के भूतपूर्व प्रान्तों से भिन्न नहीं माना जा सकता था। इसलिए देशी रियासतों द्वारा रखी गयी सेना को आगे बढ़कर उपयुक्त रूप में भारतीय सेना के साथ एकीकृत करता जरूरी हो गया। फिर भी, यह देशी रियासत विशेष के सांविधानिक और वित्तीय रूप में भारत में वर्गित हो जाने के बाद ही किया जा सकता था। ऐसे समय पर, जब भारतीय सेना के नामने अन्य अनेक सम्-

साथों भी थी, रियासतों का भारतीय सेना के साथ एकीकरण भी कोई आसान काम न था। साथ ही प्रविष्टान के मानक और सेवा की सामान्य शर्तें राज्य-राज्य में अलग-अलग थीं।

विभाजन के तुरन्त बाद, जबकि भारतीय सेना अभी पुनर्गठित हो रही थी, और भारत सरकार के सामने लाखों निस्थापित व्यक्तियों को लाने की समस्या भी थी, और साथ ही कानून-व्यवस्था का सामना करना और काश्मीर में युद्ध भी चलाना पड़ा था, उस समय कई नरेशों ने उदारतापूर्वक अपनी रियासती सेनायों सेवा के लिए सङ्घ सरकार को सौंप दो।

देशी रियासतों के भारत-सङ्घ में एकीकरण करने की प्रक्रिया में तीन अलग-अलग तरीके अपनाये गये। कुछ रियासतों का पड़ोस के प्रान्तों में विलय कर दिया गया (अर्थात् उन राज्यों के साथ जो सविधान की प्रथम अनुसूची के भाग 'अ' राज्यों में मूलतः शामिल थे), और कुछ को, मुख्य आयुक्त या उपराज्यपाल के प्रान्तों के रूप में, भारत सरकार के सीधे नियन्त्रण में रखा गया और इनको भाग 'सी' राज्य कहा गया। कुछ रियासतों को आपस में मिलाकर उनके सङ्घ बना दिये गये और उनका प्रशासन-टॉंचा प्रान्तों के रूप में ही रखा गया। ये सविधान के भाग 'ब' के राज्य बन गये। इस तरह बने और एकीकरण के समय विद्यमान संघ थे वे मध्य-भारत, पठियाणा और पूर्वी पंजाब रियासत सङ्घ, राजस्थान, सौराष्ट्र, तिरवाङ्गुर-कोचीन। फिर मैसूर, हैदराबाद और जम्मू-काश्मीर बच गये, जिनको अलग इकाई के रूप में रहने दिया गया। इनको भी भाग 'ब' राज्यों में शामिल कर लिया गया।

### विलीन राज्यों की सेनायें

भाग 'सी' राज्यों के प्रसंग में, कुछ मामलों में नियमित देशी राज्य-सेना की पूरी यूनिटें लेकर, भारतीय सेना के साथ एकीकृत कर दी गयीं, कुछ दूसरे मामलों में केवल वे व्यक्ति लिये गये, जिनको भारतीय सेना में आत्मसात् करने के लिए उपयुक्त पाया गया। (गैर-देशी रियासत सेना की यूनिटों का निपटारा करने की जिम्मेदारी पूरी तरह उत्तरवर्ती सरकार के ही ऊपर रखी गयी)। सभी मामलों में यूनिटों के सदस्यों की छानबीन भारतीय सेना के बुनाव-बोर्डों द्वारा की गयी और जिनको उपयुक्त समझा गया, उनको भारतीय सेना में लागू शर्तों-निबन्धनों के ही अनुसार, कमोनात दिये गये या नामावली पर दर्ज किया गया। जिस लोगो को भारतीय सेना में आत्मसात् करने के उपयुक्त नहीं पाया गया और जिनको उत्तरवर्ती सरकारें पुलिस या सैनिक नौकरियों में न रख सकीं, उनको भारत सरकार ने सेवान्त-हिततान प्रदान किये, अर्थात् रियासतें जैने-तैसे करके प्रदान करना, (जैसा कि इनको उस समय कहा गया) — अर्थात् रियासती सेना के नियमों में इनको जितना मिलता उससे ज्यादा उदार आचार पर पेशान या उपदान देना।

### भाग (व) राज्य

संविधान के अनुच्छेद २५६ (१) में, जैसा वह मूलतः अधिनियमित किया गया था, यह व्यवस्था थी कि प्रथम अनुसूची के भाग 'ब' में विनिर्दिष्ट, जिस किसी राज्य के पास यदि संविधान के आरम्भ के तुरन्त पूर्व कोई सशस्त्र सेनायें थी, तो वह इस आरम्भ के बाद, इन सेनाओं का सम्भारण, राष्ट्रपति द्वारा इस बारे में समय-समय पर जारी किये गये सामान्य या

विशेष आदेशों के अधीन, तब तक सन्धारण करता रहेगा, जब तक कि ससद् विधि द्वारा अन्यथा व्यवस्था न करे। खण्ड (२) में व्यवस्था की गयी कि यह सेना सङ्घ की सशस्त्र सेनाओं का अंग होगी। जब रियासती सेना का अलग अस्तित्व न रहा, वो सविमान (सातवां संशोधन) अधिनियम, १९५१ द्वारा यह अनुच्छेद निकाल दिया गया।

### तिरुवाकुर-कोचीन, मैसूर और हैदराबाद

मैसूर, हैदराबाद और तिरुवाकुर-कोचीन के राज्य-सङ्घ द्वारा सन्धारित सशस्त्र सेनायें पहले तो सम्बन्धित राज्य या राज्यसङ्घ की सरकार के प्रशासनिक नियन्त्रण में थी, लेकिन इन सेनाओं का सक्रियतागत नियन्त्रण जनरल अफसर कमांडिंग इन चीफ, दक्षिणी कमान के हाथ में था और भारतीय सेना के अधिकारी इन सेनाओं के कमांडेंट भी नियुक्त किये जाते थे। १ अप्रैल, १९५० से इन सेनाओं का सारा प्रशासनिक नियन्त्रण भारतीय सेना ने अपने हाथ में ले लिया, और अधिकारियों और अन्य पदधारियों के लिए पूरी व्यवस्था करने, और उनके लिए भण्डार और उपकरण प्राप्त करने की पूरी जिम्मेवारी भी, अपने हाथ में ले ली। भारत सरकार इन सेनाओं पर १ नवम्बर, १९४६ से ३१ मार्च, १९५० तक के समय के लिए उतना खर्च देने को भी राजी हो गयी, जो १९४६-४७ की तत्प्राप्त अवधि में उन पर हुए खर्च के अन्तर्गत था। फिर इस सेना को पुनर्गठित किया गया और तदनुसार उसकी संख्या कम की गयी और प्रशिक्षण और उपकरणों की दृष्टि से उसको भारतीय सेना के स्तर तक ले आया गया। इन रियासती सेनाओं के अधिकारियों की छानबीन भी भारतीय-सेवा-पुनाव बोर्डों द्वारा की गयी और अन्य पदधारियों का परीक्षण भी भारतीय सेना के मानकों के अनुसार किया गया। पुनर्गठन पूरा होने पर इन यूनिटों के सदस्यों पर भी भारतीय सेना की सेवा शर्तें-निबन्धन लागू कर दिये गये और ये सेनायें १ अप्रैल, १९५१ को भारतीय सेना के साथ पूरी तरह एकीकृत हो गयीं। इन सेनाओं के व्यक्तियों का भारत-सङ्घ के प्रति निष्ठा की जांच भी लेनी पड़ी।

राजस्थान, पेशू, मध्य-भारत और सौराष्ट्र पुरानी देसी रियासतों के सङ्घ थे। उनके बारे में विशेष व्यवस्था की गयी, जिसके अनुसार रियासती सेनायें राजप्रमुखों के नियन्त्रण में बनी रही, पर भारत सरकार द्वारा राजप्रमुख से परामर्श करके बुना गया भारतीय सेना का एक अधिकारी, सम्बन्धित राजप्रमुख द्वारा, उस सेवा का जनरल अफसर कमांडिंग नियुक्त कर दिया गया। फिर भी इन सेनाओं का सक्रियतागत नियन्त्रण भारतीय सेना के उस एरिया की कमान में जनरल अफसर कमांडिंग इन चीफ, दक्षिणी कमान में स्थित था, जिस एरिया में यह राज्य-सङ्घ स्थित था। सेना को खड़ा करने और उसका सन्धारण करने की शक्ति का प्रयोग राजप्रमुख भारत सरकार द्वारा भारतीय सेना के बारे में अपनाये गये नियमों के अनुसार, करते रहे। इन सेनाओं के व्यक्ति राजप्रमुख, और उनके जरिये भारत-सङ्घ के प्रति, निष्ठा की जांच लेते थे। इन सेनाओं का भी पुनर्गठन करके उनका प्रशिक्षण और उपकरण ३१ मार्च, १९५१ तक भारतीय सेना के स्तर तक ला दिये गये। इस अवधि में वे अपनी विद्यमान सेवा-शर्तों-निबन्धनों में अधीन बने रहे, पर १ अप्रैल १९५१ से उन पर भी भारतीय सेना की सेवा-शर्तों-निबन्धन

लागू कर दिये गये । इन रियासती मेनाओं के अधिकारियों की भी भारतीय सेना-चुनाव-बोर्डों ने छानबीन की और भारतीय सेना और रियासती मेनाओं के बीच अधिकारियों का आदान-प्रदान भी किया गया ।

सशोध-वित्तीय-एकीकरण की योजना के अनुसार भारत सरकार १ अप्रैल, १९५० ( पेन्सू के मामले में १३ अप्रैल, १९५०, जो इसके अगले वित्तीय वर्ष शुरू होने की तारीख थी ) से भारत सरकार देशी रियासत-सेना का सारा वित्तीय दायित्व सम्भालने की राजी हो गयी, जिसमे उस तारीख को या बाद में सेवानिवृत्त होने वाले रियासती मेना के व्यक्तियों के पेंशन का खर्च भी शामिल था । वह १ नवम्बर, १९४१ से ३१ मार्च, १९५० तक ( पेन्सू के मामले में १३ अप्रैल ) की अवधि के लिए रियासती सेना पर हुए खर्च और उस पर १९४६-४७ को सुनवाई अवधि में हुए खर्च का अन्तर देने को तैयार हो गयी ।

बिन्ध्य-प्रदेश की रियासतों की सेना को विपटित कर दिया गया, क्योंकि वह देश की समग्रीय रक्षा-आवश्यकताओं से ज्यादा थी । पर इन सेनाओं के उपयुक्त लोगों की भारतीय सेना या पुलिस जैसी दूसरी नौकरियों में लगा लिया गया ।

रियासती सेनाओं के जिन अधिकारियों ने भारतीय सेना-चुनाव-बोर्डों में स्वीकार्य पदक्रम प्राप्त कर लिया था, उनको भारतीय सेना में कमिशन दे दिये गये और उनकी बरिष्ठता भारतीय सेना के अधिकारियों के प्रसंग में एक विशेष बिन्दु पद्धति के आधार पर तय कर दी गयी ।

रियासती सेनाओं से सेनायुक्त किये गए लोगों के पुनर्वास के लिए, राज्य सरकारों से परामर्श करते हुए, योजना तैयार करके अमल में लायी गयी ।

भारत सरकार ने रियासती सेनाओं की सारी वित्तीय जिम्मेवारी संभाल ली थी, इसलिए रियासती मेना की सारी चल-अचल सम्पत्ति, जिसमे उनके कब्जे का आवास भी शामिल था, भारत सरकार की सम्पत्ति बन गयी और इस तरह भारतीय सेना के उपयोग के लिए उपलब्ध हो गयी ।

रियासती सेना का भारतीय सेना के साथ एकीकरण धीरे-धीरे ही हो सकता था । १९४८ और १९४९ की परिस्थिति की देखते हुए इसका तुरन्त एकीकरण व्यावहारिक नहीं था । साथ ही एकीकरण से पहले रियासती सेना के अधिकारियों और सैनिकों को भारतीय सेना के स्तर तक लाना भी जरूरी था ।

रियासती सेना का एकीकरण १ अप्रैल, १९५१ को पूरा हो गया, जिस तारीख से यह सेना अलग इकाई के रूप में न रही । पहली बार देश में एक पूर्णतः एकीकृत भारतीय सेना पूरे देश के लिए बनायी गयी ।

विलीन राज्यों की सेनायें विलीन राज्य विधियाँ अधिनियम १९४८ का ४३वाँ के अनुसार भारतीय सेना अधिनियम, १९११ के अधीन आ गयी । भारतीय सेना अधिनियम १९११ उपयुक्त सशोधनों के साथ भारत के राजपत्र में अधिगुणना प्रकाशित करके, हैदराबाद, तिरुवाकुर-कोचीन, मध्यभारत, पेप्सू, राजस्थान और सौराष्ट्र की सेनाओं पर भी १ अप्रैल,



१९४७ को लागू कर दिया गया। बाद में सेना अधिनियम, १९५० में रियासती सेनाओं पर लागू करने के लिए उपयुक्त उक्त व्यवस्था किये गये।

### रियासती सेना-सलाहकार के संगठन की समाप्ति

एकीकरण में प्रगति होने पर यह तय किया गया कि प्रमुख-मैज-सलाहकार, देशी रियासत-सेना, और उनके संगठन को फिर से १ अप्रैल, १९५० से रक्षा-मन्त्रालय के अधीन कर दिया जाय। उस तारीख से संगठन के भारगोष्ठ अधिकारी (एक कर्नल) का पदनाम, सलाहकार, रियासत-सेना कर दिया गया और संगठन-मुख्यालय, सलाहकार, रियासती-सेना, कहा जाने लगा। राज्य सेना का एकीकरण पूरा हो जाने पर यह संगठन १ अक्टूबर, १९५१ को खरम कर दिया गया। सैन्य कार्य केन्द्रित रूप से मन्त्रालय का एक अनुभाग सितम्बर, १९५३ तक चलाना रहा, और तब बाकी बचा काम विकेन्द्रित करके मन्त्रालय के सम्बन्धित प्रशासनिक अनुभागों को सौंप दिया गया।

जम्मू और काश्मीर राज्य-सेना १ नवम्बर, १९४७ को भारतीय सेना के प्रशासनिक नियन्त्रण में सौंप दी गयी थी और वह १ जनवरी, १९५७ को भारतीय सेना के साथ एकीकृत कर दी गयी।

इस तरह एक दशक से भी कम समय में भारत की सेना को पूरी तरह एकत्र करके एकीकृत सेना के रूप में गठित कर दिया गया। अब इस मभी में देश के नागरिक ही अधिकारी थे। भरती सभी भारतीयों के लिए खोल दी गयी थी, चाहे वे देश के किसी भी भाग के हों न हों और उनकी जाति या धर्म कुछ भी न हो। पर इसमें भी कहीं ज्यादा बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि भारत की सशस्त्र सेनाओं का सम्बन्ध अर्थों में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।

## अनुबन्ध

उन राज्यों की सूची, जहाँ एकीकरण से पूर्व देशी रियासत-मेनायें थी

१—नवानगर	}	सौराष्ट्र	२४—हैदराबाद	}	हिमाचल प्रदेश
२—भावनगर			२५—मैसूर		
३—धारावा			२६—जम्मू और काश्मीर		
४—पोरबन्दर			२७—बम्बा		
५—मेवाड़	}	राजस्थान	२८—मुक्त	}	हिमाचल प्रदेश
६—कोटा			२९—मडो		
७—जोधपुर			३०—धिरपुर		
८—जयपुर			३१—कच्छ		
९—बीकानेर			३२—भोपाल	}	विन्ध्य प्रदेश
१०—अलवर			३३—त्रिपुरा		
११—भरतपुर	}	मध्य भारत	३४—रोरवा		
१२—घोलपुर			३५—दतिया		
१३—खालियर			३६—पन्ना	}	बम्बई
१४—इन्दौर			३७—दजौदा		
१५—घार	}	पेन्स	३८—कोल्हापुर		
१६—मटियाला			३९—बारिया		
१७—कपूरथला			४०—ईदर	}	उत्तर प्रदेश
१८—माभा	}	निगवाकुर-कोबीन	४१—मुनावडा		
१९—जींद			४२—राजपीपला		
२०—फरीदकोट			४३—देहरी-बडवाल		
२१—मालेरकोटला	}	निगवाकुर-कोबीन	४४—रामपुर	}	उत्तर प्रदेश
२२—विशनाकुर			४५—बनारस		
२३—कोचीन			४६—कूब बिहार		

५० बंगाल

आठवाँ अध्याय

## भरती और प्रशिक्षण

### खण्ड १ भरती

स्वाधीनता के बाद सशस्त्र सेनाओं में भरती की रीति के बारे में महत्वपूर्ण और दूर-दामी परिवर्तन आये हैं। देश में हो आवश्यक प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करने में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। भरती को दो शीषों में वर्गीकृत किया जा सकता है (क) अधिकारियों की भरती और (ख) शेष की भरती, जिनको अन्ध पदचारी कहा जाता है। अन्धपदचारी सशस्त्र सेना का अधिकांश हिस्सा है। उनको भरती के बारे में किये गये परिवर्तनों को पहचान लिया जा सकता है।

### सेना में वर्गगत रचना

ब्रिटिश काल में सेना की भरती यूनिटों की वर्ग रचना पर आधारित थी और यह थोड़ा जानियों कहकर पुकारे जाने वाले कुछ वर्गों तक ही सीमित था। इस भेदभाव का औचित्य कमांडर-इन-चीफ ने वीसिल आफ स्टेट में सितम्बर, १९३८ में एक भाषण में यह कहकर देना चाहा था

सैन्य अधिकारियों ने अपने अनुभव से यह सिद्ध कर दिया है कि कुछ वर्गों में सर्वाधिक कुशल सैनिक पैदा होते हैं। कुल मिलाकर और आज की नीति का एरुमान औचित्य यही है कि यह गैरा वो प्रत्येक शाखा के लिए सर्वोत्कृष्ट व्यक्तियों के चुनाव की गारण्टी देता है।

इस नीति का अनुसरण करते हुए कुछ वर्ग भरती के प्रयोजन से त्रिनिटिड वर दिये गये थे। इस वर्गीकरण के आधार पर प्रत्येक रेजीमेंट की रचना प्रत्येक वर्ग के प्रतिशत के आधार पर निर्धारित की गयी थी और धार्मिकता में इस प्रतिशत का बढ़ो-सन्तो के साथ पालन किया जाता था। पर दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान सेना का काफी विस्तार करना पड़ा और थोड़ा जानियों में होने वाली भरती शीघ्र ही सन्तुष्टि-विन्दु तक पहुँच गयी। अतः और आगे भरती लक्ष्य जानियों से करती पड़ी जिनको पहचाने अथवा जानियाँ कहा गया था। युद्ध-

काल में योद्धा और अ-योद्धा जातियों का सिद्धान्त बिलकुल खत्म हो गया। वस्तुतः तभी यह समझा गया कि शान्तिकाल में सेना की रचना युद्धकाल में उसके विस्तार के स्वरूप पर ही होनी चाहिये। युद्ध के बाद शीघ्र ही यह पाठ मुला दिया गया और सेना अधिकारी एक बार सामान्य भरती के लिए फिर उसी पुराने जाति-रचना वाले ढर्रे पर आ गये। ३० मार्च, १९४६ को निकाले गये विशेष सेना आदेश में भरती के प्रयोजन से वर्गों का नामोत्तेजक र दिया गया।

### भरती का सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुलना

विशुद्ध राजनीतिक दृष्टिसाधकता पर आधारित वर्ग-रचना सम्बन्धी योजना स्पष्ट ही स्वतन्त्र भारत में अमान्य हो गयी। १५ अगस्त १९४७ के तुरन्त बाद ही भारत सरकार ने निर्णय लिया कि भारतीय सेना से समग्र साम्प्रदायिक और वर्णगत रचना समाप्त कर दी जानी चाहिये और सभी भारतीय नागरिकों को इसमें सेवा करने का समान अवसर मिलना चाहिये। जनवरी, १९४९ में आधिकारिक रूप से यह आदेश निकाले गये कि सभी मेनाओं/शाखाओं में वर्ग के आधार पर भरती को खत्म कर देना चाहिये। इस तरह भरती सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुली छोड़ दी गयी, वरन् कि वे विहित शैक्षिक और शारीरिक मानक के अनुरूप हों। फरवरी, १९४९ में सरकार की इस संघोषित नीति का अनुपालन किये जाने के बारे में प्रशासनिक अनुदेश निकाल दिये गये, जिनके अनुसार आर्टिलरी, इंजीनियरी और सिग्नल्स शाखाएँ बहुत कुछ एक मिश्रित आधार पर आ गयीं। रेजीमेंटों की भरती सम्बन्धी माँग इस तरह से तैयार की जाती थी कि कम से कम १० प्रतिशत रिक्त स्थान पहली सूची पर न आने वाले वर्गों को मिलें। जिन सेनाओं, शाखाओं में पहले से ही वर्णगत रचना काफी भिन्नत्व थी, उनमें भी अन्य वर्गों की भरती के लिए गुआइड बढ़ा दी गयी।

पुरानी वचनबद्धता और सेना की स्थिति की दृष्टि में इस निर्णय का तुरन्त पालन पैदल सेना और आर्मेड कोर के मामले में सम्भव न था। वर्ग विशेषों से बनी हुई रेजीमेंटों ने अनेक दशकों में कुछ समरसता प्राप्त कर ली थी और हालाँकि उनकी रचना को व्यापक आधार पर खाने के लिए कदम उठाये गये, यह भी आवश्यक समझा गया कि इस प्रकार की रचना के कारण उनमें भी लगाव पैदा हो गया है उसे सहसा ध्वस्त न कर दिया जाय। इसलिए परिवर्तन शमिक ही होना था। फिर लड़ाकू युनिटों की रचना में, कोई भी पूर्ण परिवर्तन करने से, कम से कम अस्थायी तौर पर, उनकी कार्यकुशलता पर असर पड़ेगा। इन स्थूल बाजों को ध्यान में रखते हुए पैदल सेना और आर्मेड कोर में भी मिश्रित वर्ग रचना का सूत्रपात करने के लिए अनेक कदम उठाये गये हैं। इस बारे में एक उल्लेखनीय दृष्टान्त बंगालियों का है, जिनको पैदल सेना में कोई स्थान प्राप्त न था। मार्च १९४९ में आदेश निकाले गये कि एक रेजीमेंट के अग्रस्वरूप बंगालियों की एक कम्पनी खड़ी की जाय। एक पैराशूट रेजीमेंट भी, मिश्रित वर्ग रचना के आधार पर खड़ी करने के लिए, आदेश निकाले गये।

जैसे ही रेजीमेंटों की रचना की व्यापक आधार पर लाने का प्रयत्न पूरा हो जायेगा, हममें कोई संदेह नहीं कि वैसे ही सारे देश के विभिन्न-वर्गों की जनता में ज्यादा अच्छा अवकाश पैदा हो जायेगा और यंगमेन, नौमेन और वायुमेन साथ-साथ देश की एकता का प्रतीक बन जायेंगी, भले ही भाषा, प्रथा और रीतिरिवाज में भेद रहे ।

ब्रिटिश काल में सेना की वर्ग-रचना वाली पद्धति नौमेन और वायुमेन में लागू न की गयी थी । इसलिए किसी वर्ग विशेष के लिए स्थान आरक्षित न थे और इन सेवाओं में भरती के लिए सभी भारतीय पात्र थे । इसलिए १५ अगस्त, १९४७ के बाद नौमेन और वायुमेन में भरती सम्बन्धी कोई सुधार करना आवश्यक न था ।

अब सशस्त्र सेनाओं में जाति, धर्म, समुदाय या देश के भागविशेष के भेदभाव के बिना, सभी भारतीय प्रवेश पा सकते हैं । किसी भी वर्ग के लिए न तो रिक्त स्थानों का आरक्षण ही किया जाता है और न आयु सीमा में ही छील दी जाती है । भरती केवल शारीरिक समर्थता और निहित योग्यताओं के आधार पर की जाती है । सशस्त्र सेनाओं के लिए शारीरिक समर्थता का बहुत ज्यादा महत्व है । हमें भरती अर्थात् नौकरियों की अपेक्षा कम आयु में ही की जाती है, क्योंकि उस समय उनको सैन्य दृष्टिकोण और अनुशासन के अनुरूप ज्यादा अच्छी तरह से मोटा जा सकता है । शारीरिक समर्थता की दृष्टि से प्रशिक्षण के लिए उपयुक्तता और विभिन्न ओहदों में आयु वर्गों का विशेष महत्व है । अतएव सशस्त्र सेना के विभिन्न ओहदों में भरती के लिए निहित आयुसीमा का कड़ाई से पालन किया जाता है । किसी भी वर्ग विशेष के लिए छील देना कार्य-कुशलता के प्रति साधक न होता । हाँकि आयुसीमा के मामले में भी जनवर्ग की छील नहीं दी जाती, पर सशस्त्र सेना के कमीशन वाले ओहदों में सशस्त्र लोक-सेवा-आयोग द्वारा की गयी भरती के लिए देश-व्यापक में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों और पाकिस्तान से विस्थापित स्थितियों को रियायत दी जाती है ।

रंगूटो के चुनाव के मामले में कुछ समय पूर्व एक गृहसंपूर्ण निर्णय लिया गया था । बान्नी चीजें समान रहने पर, अब देहात से आने वालों को वरीयता दी जाती है, क्योंकि यह समझा जाता है कि सैन्य जीवन की कठोरता वे ज्यादा अच्छी तरह से बरदाश्त कर सकते हैं । इसी तरह दोष चीजें समान रहते पर अनुसूचित जाति वालों को वरीयता दी जाती है ।

### भारतीय सैन्य-अकादेमी

युद्ध में पूर्व मोर्चे मंताओं में अधिकारियों का चयन फेडरल लोक-सेवा-आयोग द्वारा की गयी सर्ची परीक्षा ( और मौखिक परीक्षा ) के आधार पर किया जाता था ।

सेनाध्यक्षों को भारतीय सैन्य-अकादेमी, देहरादून में प्रशिक्षण दिया जाता था और हर छमाही में भारतीय सेना में तीस रिक्त-स्थान रहते थे । इनमें तो केवल पन्द्रह स्थान तुलसी स्वामी द्वारा भरे जाते थे, दोष पन्द्रह भारतीय सेना के क्षेत्र-छत्रों के लिए आरक्षित रहते थे, जो उन वायुसशस्त्र कमीशन प्राप्त अफसरों और अन्य पदधारियों में से चुने जाते थे, जो निच-तर कालेज, मोंग्राँव में दो साल का पाठ्यक्रम पूरा कर चुके होते थे । क्रिचर कालेज में भी हर

साल जुलाई और दिसम्बर में दो बार तीस-तीस उम्मीदवार लिये जाते थे ।

अकादेमी में दस स्थान हर छमाही में देशी रियासती सेनाओं के सम्भाव्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए रखे जाते थे ।

पन्द्रह खुले स्थानों के लिए सर्वोपरीक्षा सामान्यतः हर सात माँचें और अक्टूबर में फेडरल लोक-सेवा-आयोग द्वारा ली जाती थी । उम्मीदवार को अपने जनकों के निवास के जिनके जिलाधीश । उपायुक्त के जरिये अपना आवेदन भेजना होता था । आयुसीमा १८ और २० साल थी और परीक्षा शुल्क ५० रुपये तथा आवेदन पत्र का शुल्क साठे सात रुपये भरण । परीक्षा केवल दिल्ली में होती और इटरन्यू और अभिलेख के अलावा, जिसके लिए ५०० अंक होते थे, ६०० अंकों के चार अनिवार्य विषय होते थे, और तीन वैकल्पिक विषय, जिनका योग ८०० अंक तक का होना था । इटरन्यू और अभिलेख परीक्षा एक बोर्ड द्वारा ली जाती थी, जिसके अध्यक्ष फेडरल लोक-सेवा-आयोग के एक सदस्य होते थे । दो सदस्य कमांडर-इन-चीफ द्वारा नामित दो भारतीय सेना के अधिकारी होते थे और दो गैर सरकारी भद्रजन होते थे, जिनमें से एक का नामन भारत सरकार करती थी और दूसरे का कमांडर-इन-चीफ । भारतीय सैन्य-अकादेमी में नियुक्ति के लिए पात्र बनने के लिए एक उम्मीदवार को इटरन्यू और अभिलेख में कम से कम १७५ अंक प्राप्त करने होते थे और सब विषयों में मिलाकर ११००, अर्थात् लिखित और मौखिक सभी परीक्षाओं के कुल योग में से ५० प्रतिशत से कम कदापि नहीं ।

बर्ष में दो सत्र होते थे और अनुतिभण पाठ्यक्रम २३ वर्ष तक चलता था । भारतीय सैन्य-अकादेमी में भारतीय सेना के सेना-छात्रों के अलावा अन्य सेना-छात्रों द्वारा देय शुल्क पहले दो सत्रों में से प्रत्येक में ८०० रुपये होता था और फिर ७५० रुपये प्रति सत्र अथवा पूरे पाठ्यक्रम के लिए ३८५० रुपये । इस रकम में ट्यूशन, आवास, भोजन, अकादेमी के भृत्य, गुरु में बरदी का प्रदान, शिक्षा-भण्डार, खेलकूद, चिकित्सा आदि और प्रति मास २० रुपये का जेबलक्ष् ( दीर्घावकाश को छोड़ ) शामिल रहता था । अकादेमी में हर सत्र में दो किंग एम्बर सैन्य-छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती थी । इसमें किंग कमीशन प्राप्त अधिकारियों या वायसराय कमीशन प्राप्त अधिकारियों या अतिरिक्त राजपत्रित अधिकारियों के लड़के लिए जाते थे ।

भारतीय सैन्य-अकादेमी में प्रवेश प्राप्त करने वाले भारतीय सेना के सेना-छात्रों को ६० रुपये प्रतिमास का सम्प्रेषित वेतन, या वायसराय कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उस उच्चतर दर से वेतन मिलता था, जो उसे अपनी युनिट में ही धने रहने पर मिलता । अकादेमी में उनसे कोई फीस न ली जाती थी । अकादेमी उनके लिए बस्ती, बरदी और उपकरण के लिए भी व्यवस्था करती थी ।

इस तरह भारतीय सैन्य-अकादेमी के एक सेना-छात्र के पिता को लगभग ४००० रुपये प्रतिवर्ष व्यय करना पड़ता था । पर कुछ छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध थी, जो बम्बई, सयुक्त प्रान्त, मद्रास, मध्यप्रान्त और बिहार की सरकारें प्रदान करती थी ।

अकादेमी कमांडर-इन-चीफ के सीधे नियन्त्रण में थी । भारतीय सैन्य-अकादेमी का

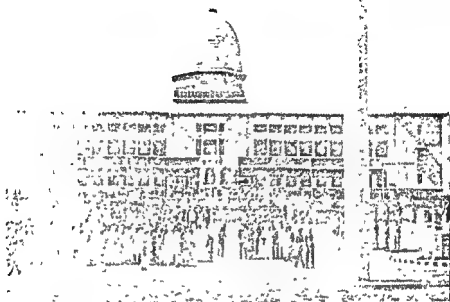
पाठ्यक्रम इस तरह बनाया गया था कि (क) मैना-छात्र में नेतृत्व, अनुशासन और शारीरिक समर्थता का विकास किया जा सके और उसमें कर्तव्य और सम्मान की उच्च भावना भरी जा सके और उसे राज्य के सेवक की जिम्मेदारियों का ज्ञान हो सके, (ख) यह आश्वस्त किया जा सके जब मैना-छात्र अपनी यूनिट में जाय तो वह प्लाटून कमांडर के अत्यावश्यक कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

### नौमेना के लिए दम्भीशन-प्राप्त अधिकारी

नौमेना की एग्जीक्यूटिव और इजीनियरी शाखाओं के उम्मीदवारों की भरती-परीक्षा दिल्ली में भारतीय सैन्य-अकादमी की परीक्षा के साथ-साथ होती थी। आयु सीमा १७½ और १६½ वर्ष थी। मैना के अधिकारियों के संवर्ष में एक विशिष्ट रिक्त स्थान भारतीयों के लिए आरक्षित थे। वार्षिक भरती स्वभावतः बहुत कम थी, क्योंकि समुद्रनामी छात्रा के लिए स्वीकृत अधिकार स्थापना की सव्या हो कम थी। उदाहरण के लिए १९८० में स्वीकृत, स्थापना, एग्जीक्यूटिव शाखा के लिए केवल ७७ और इजीनियरी शाखा के लिए केवल ३७ थी। कुल मिलाकर इस छोटी-सी स्थापना में स्थायी स्थान तो सेवानिवृत्ति आदि के बाद ही सामान्यतः पाली होते थे। फिर जिस किसी वर्ष में भारतीयों के लिए एक से ज्यादा रिक्त स्थान होना था, तो उनमें से कम से कम एक स्थान भारत सरकार के विवेकानुसार भारतीय वाणिज्य समुद्री-प्रशिक्षण-गोत, डकरिन, के कैडेटों के लिए आरक्षित रहता था। यदि दोनों शाखाओं में साथ-साथ मिलकर केवल एक ही स्थान रिक्त होना था, तो सरकार यह फैसला करती थी कि इसके लिए खुली स्पर्धा की जाय या वह डकरिन के कैडेटों तक ही सीमित रहे। नौमेना के परीक्षा-नियम भारतीय सैन्य-अकादमी जैसे ही थे, पर नौमेना के उम्मीदवारों द्वारा लिये जाने वाले अनिवार्य विषय कुछ भिन्न थे और विज्ञान-विषयों पर ज्यादा आग्रह रहता था। उम्मीदवार, परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही, योग्यतानुसार चुने जाते थे लेकिन कोई भी उम्मीदवार तब तक नहीं चुना जा सकता था जब तक वह साक्षात्कार और लिखित परीक्षा में अलग-अलग, कम से कम ३५ प्रतिशत अंक प्राप्त न कर ले और कुल योग के १० प्रतिशत।

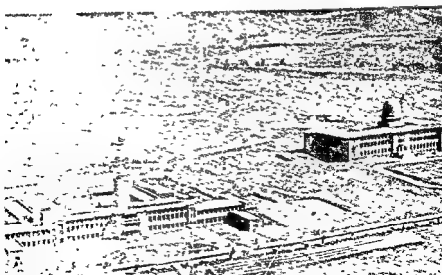
यूरोपीय उम्मीदवारों की भरती के लिए एक परीक्षा लन्दन में भी होती थी। यह परीक्षा तीनों मैनाओं के लिए संयुक्त थी। डकरिन के कैडेटों के लिए केडरल लोक-मेबा-आयोग एक विशेष परीक्षा लेता था।

सभी उम्मीदवार, चाहे भारत में चुने गये हों या इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम की ही नौमेना स्थापनाओं में प्रशिक्षित होने थे। यह शिक्षण उम्मीदवार के जनक या अभिभावक के लिए बड़ा खर्चीला बैठता था, जिसे यू० के० ने प्रशिक्षण के खर्च के लिए २६० पाँड (लगभग ३५००० रुपये) जमा करने होते थे। इन उम्मीदवारों का यू० के० में प्रशिक्षण भारत सरकार के लिए भी खर्चीला बैठता था, जिसे १२६८ पाँड ५ गिलिंग (जिसे एहमिरलदी प्रशिक्षण-ध्यय के ७६० पाँड शामिल थे) एक एग्जीक्यूटिव अधिकारी के लिए, और २२६१ पाँड ८ गिलिंग (एहमिरलदी प्रशिक्षण-ध्यय के १३८५ पाँड शामिल करके) एक इजीनियर अधिकारी के लिए देने पड़ते थे।

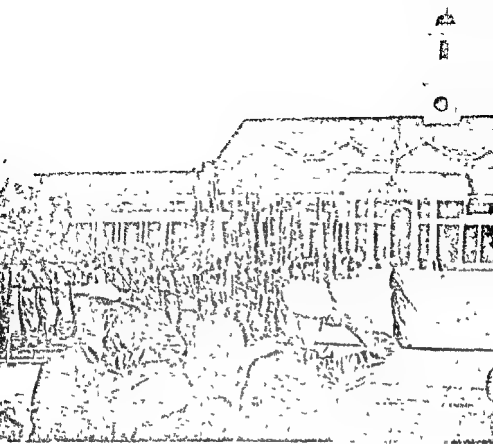


राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, सड़कवासला का प्रशासनिक ब्लॉक

अकादमी का विज्ञान ब्लॉक (बाग की ओर)  
दाहिने कोने में प्रशासनिक ब्लॉक है







भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून का प्रशासनिक ब्लॉक

अप्रैल, १९४७ में (जब अन्तरिम सरकार केन्द्र में पनारूढ थी), जनक के प्रशिक्षण व्यय का अंश घटाकर ११६ पाँड कर दिया गया। साथ ही जनक को यह रकम अब पेशगी न जमा करनी होती थी, जैसी कि पहले व्यवस्था थी, बल्कि वे सोवे भुगतान की व्यवस्था कर सकते थे। बाद में जुलाई, १९४७ में रॉयल इंडियन नैवी के कमीशन-प्राप्त अधिकारियों को भरती के लिए फेडरल लोक-सेवा-आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा की फीस भी ५० रुपये से घटाकर २० रुपये कर दी गयी। यह परीक्षा, आयोग द्वारा, जनवरी, १९४९ तक वर्ष में तीन बार ली जाती रही और आयुसीमा १७½ से १९½ रही। जून, १९४९ के बाद यह परीक्षा एक वर्ष के लिए रोक दी गयी।

### भारतीय वायुसेना में अधिकारियों की भरती

भारतीय सैन्य-अकादेमी की प्रवेश-परीक्षा, भारतीय वायुसेना में कमीशन दिये जाने से पहले, रायल एयर फ़ोर्स कालेज, क्रानवेल के लिए संयुक्त रूप से ली जाती थी। पर परीक्षा-योजना योगी-सी मिली थी। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उम्मीदवार को एक सवारी के रूप में सैन्य-विमान में एक व्यावहारिक उड़ान-परीक्षण देना होता था। फिर अन्तिम रूप से चुने गये उम्मीदवार ही आर० ए० एक० कालेज, क्रानवेल में उड़ान-प्रशिक्षण के लिए भरती किये जाते थे, जिसे सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उनको वायुसेना में कमीशन मिलता था। क्राउन-बाल में प्रशिक्षण-अवधि लगभग दो साल थी। पाठ्यक्रम के लिए कुल अनुमानित व्यय ५८० पाँड = शिलिंग था, जिसके लिए कैंडेट के जनक या अभिभावक को पेशगी ३६० पाँड = शिलिंग की रकम (लगभग ४८०० रुपये) भेजनी होती थी और वेप २२० पाँड का योगदान सरकार देती थी। भारतीय कैंडेटों की पहली टुकड़ी का प्रशिक्षण क्रानवेल में ४ सितम्बर, १९३० को गुरु हुमा और अन्तिम टुकड़ी का सितम्बर, १९३८ में।

### युद्धकाल में अधिकारियों का चुनाव

युद्ध छिड़ने के बाद सेना और वायुसेना में स्थायी कमीशनो का दिया जाना रोक दिया गया और आपात कमीशन देने की पद्धति शुरू की गयी। १९४१ में भारतीय सैन्य-अकादेमी एक अधिकारी प्रशिक्षण-स्कूल के रूप में बदल दी गयी और उसकी क्षमता बढ़ाकर, उसमें ११०० कैंडेटों का प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था कर दी गयी। पर भारतीय नौसेना के कमीशन वाले ओहदों के स्थायी संवर्ग में भरती के लिए स्पर्धा-परीक्षा युद्धकाल में सीमित पैमाने पर चलती रही। युद्धकाल में, रॉयल भारतीय नौसेना की बढ़ती हुई जरूरतों को देखते हुए, रॉयल भारतीय नौसेना रक्षिति में (जो समुद्रगामी अनुभव वालों के लिए थी) और रॉयल भारतीय नौसेना स्वयंसेवक रक्षिति (जो समुद्रगामी अनुभव न रखने वालों के लिए थी) में अस्थायी कमीशन प्रदान किये गये।

युद्धकाल में अफसरों के चयन के लिए, १९४२ के आरम्भ तक, प्रत्येक सेना का अपना-अपना साक्षात्कार-बोर्ड था, पर १९४२ में तीनों सेनाओं में अधिकारियों की भरती को एकीकृत किया गया और यह नाम सेना मुख्यालय की एड्युटेंट-जनरल की साखा द्वारा किया जाने

तथा । इस एकीकरण के बाद स्थूलरूप से आपान आयोग के लिए उम्मीदवारों का चुनाव दो प्रश्नों में किया जाता था . (क) प्रादेशिक चयन-बोर्ड द्वारा आरम्भिक चयन और (ख) केन्द्रीय साक्षात्कार-बोर्डों द्वारा अन्तिम चयन । इनकी संख्या तीन थी, एक उत्तर, एक दक्षिण और एक केन्द्रीय भारत के लिए । केन्द्रीय साक्षात्कार-बोर्डों में सामान्यतः एक वरिष्ठ अमेरिकी ज्य्योतिष होता था, एक वरिष्ठ मैथिल अधिकारी उपाध्यक्ष और दो सहयोगित स्थानीय अमेरिकी सदस्य होते थे । प्रादेशिक बोर्डों द्वारा अपनायी गयी चयन-रीति एकरूप न थी ।

यू० के० में भी चयन की रीति यही थी, पर इसकी बहुत आलोचना हुई थी । यह माना गया था कि एक सक्षिप्त-सा साक्षात्कार एक अधिकारी बनने के लिए, किसी व्यक्ति की उपयुक्तता का परीक्षण करने के लिए, सर्वथा अपर्याप्त है । एकच्छ मानक प्राप्त करना असम्भव है, क्योंकि साक्षात्कार की व्यक्तिगत समस्या का बड़ा हाथ रहता है । यह भी देखा गया कि वैयक्तिक साक्षात्कार में चुने गये उम्मीदवारों का बड़ा अंश अधिकारी प्रशिक्षण-स्कूल कमीशन के लिए सफल नहीं हो पाता । फलस्वरूप १९४१ के उत्तरार्द्ध में यूनाइटेड किंगडम में साक्षात्कार की एक नयी पद्धति विरचित की गयी, जो नेतृत्व, सहन-बुद्धि और शक्ति आदि विभिन्न गुणों का परीक्षण ज्यादा सन्तोषपूर्वक करने योग्य माना गया । नयी पद्धति वैज्ञानिक रीतियों पर आधारित थी, जिसका समर्थन मनोवैज्ञानिक तथा अन्य व्यक्ति बहुत समय से करते चले आ रहे थे ।

भारत में भी चुनाव की चालू पद्धति के बारे में बहुत चिन्तायें थी । १९४३ में काफी विमर्श के बाद यह तय किया गया कि यू० के० में अरनायी गयी नयी तकनीक प्रायोगिक रूप में लागू करने के लिए एक अलग चयन-बोर्ड बनाया जाय । नयी पद्धति में पारोरिक, बौद्धिक और मनोवैज्ञानिक परीक्षण लिये जाते थे । यह साधारणतः उपादा उपदेष्टा माना गया । तदनुसार इन्ने भारत के सभी नैटो के चयन के लिए उपयुक्त माना गया और केन्द्रीय साक्षात्कार-बोर्ड समाप्त कर दिये गये । पर भारत में इस नयी पद्धति को लागू करने से भारतीय उम्मीदवारों के चयन की समस्या का वैज्ञानिक बन्वेषण करना ज़रूरी हो गया । भारतीय स्थितियों के अनुरूप इस परीक्षण की मान्यता फिर से सिद्ध की जानी थी और तदनुसार पुनः मानक स्थापित किये जाने थे ।

जेंट-जेंट ज़रूरत बढ़ती गयी, नये प्रकार के चयन-बोर्डों की संख्या भी बढ़ती गयी, लेकिन चयन-प्रक्रिया मूलतः वैसी ही बनी रहती । जो भी परिवर्तन आया वह यही था कि १९४५ में प्रांतीय चयन-बोर्ड खत्म कर दिये गये और आरम्भिक चयन की एक नयी पद्धति गुरु की गयी । यही चयन-पद्धति भारत के आजाद होने के समय विद्यमान बनी आ रही थी । मुझ के बाद पहला शान्तिशालीन पाठ्यक्रम भारतीय सैन्य-अकादेमी में १९४५ में शुरू किया गया ।

### राष्ट्रीय रसा-अकादेमी की स्थापना

स्वाधीन भारत में सशस्त्र सेनाओं में, अधिकारियों की भरती और उनके आरम्भिक प्रशिक्षण के साथ, पूना के पास मद्रासमला में स्थित, राष्ट्रीय रसा-अकादेमी बहुत निवृत्त ग

सम्बद्ध है। अकादेमी की स्थापना, आभादी के बाद भारतीय सशस्त्र सेनाओं के इतिहास में, एक बहुत महत्व की घटना है।

दूसरे विश्वयुद्ध के बाद के चरणों में ही भारत सरकार ने एक उच्चतम भारतीय राष्ट्रीय-युद्ध-स्मारक बनाने की बात पर विचार किया था। २ मई, १९४५ को निकाली गयी एक प्रेस विज्ञप्ति में भारत सरकार ने घोषणा की कि वह रॉयल भारतीय नौसेना, भारतीय पवनसेना, और रॉयल भारतीय वायुसेना के सभी भारी अधिकारियों को शिक्षा और बुनियादी प्रशिक्षण देने के लिए, प्रस्तावित राष्ट्रीय-युद्ध-स्मारक के सर्वाधिक उपयुक्त रूप में, वेस्ट प्वाइंट स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका की सैन्य अकादेमी की तरह की (जहाँ नियमित सेना के अप्सर सेना-छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है), एक सैन्य-अकादेमी स्थापित करना चाहती है।

इस निर्णय के अनुसरण में, सरकार ने प्रस्तावित अकादेमी की योजना तैयार करने के लिए, जिसमें इस तरह के मामलों की ओर विशेष ध्यान दिया जाय कि अकादेमी का नाम क्या हो, कहाँ पर बनायी जाय, उसका आकार क्या हो, प्रवेश की आयु और रीति क्या हो, पाठ्यक्रम की अवधि और पाठ्य विवरण क्या हो और क्या अकादेमी को अनुपोषित करने के लिए कोई विशेष शिक्षा संस्थानें स्थापित की जायें, एक समिति बनाई।\*

इस समिति की एक उपसमिति सं० रा० अमेरिका, कनाडा और यू० के० को उन देशों की सेना-शिक्षण-संस्थाओं की कार्यप्रणाली देखने के लिए गयी। उपसमिति से कहा गया था कि वह सासुकर इन संस्थाओं के विनियम, पाठ्य-विवरण, प्रशिक्षण-रीतियों और स्थापना का अध्ययन करे।

समिति ने अपना प्रतिवेदन दिसम्बर, १९४६ के अन्त में प्रस्तुत किया। इसकी मुख्य सिफारिशें ये थीं—(क) हीनो सेनाओं में (चिकित्सा को छोड़ कर) कमोच्चन प्राप्त करने के हेतु शिक्षा और बुनियादी प्रशिक्षण की एक अकादेमी होनी चाहिये, जिसे राष्ट्रीय-युद्ध-अकादेमी कहा जाय, (ख) अकादेमी पूना के पास खड्कवासला में स्थापित की जाय और इसमें प्रवेश का आधार एकमात्र योग्यता हो, (ग) १६ से १९ साल तक के उम्मीदवार, जिनके पास मैट्रिक या समकक्ष शैक्षिक योग्यता हो, प्रवेश के पात्र माने जायें और चयन एक योग्यता-परीक्षण और उसके बाद एक चयन-बोर्ड द्वारा साम्राज्यकार के बाद, किया जाय (घ) इस अकादेमी में छात्र-सैनिकों के लिए दूधान, वस्त्र और भोजन निःशुल्क रहें पर उनको कोई अतिरिक्त मासिक वेतन न दिया जाय (ङ) अकादेमी में शिक्षण-माध्यम की अवधि चार साल हो, जिसके अन्त में

\* कमांडर-इन-चीफ इस समिति के सभापति थे और वे सदस्य थे। सामान्य स्टाफ-प्रमुख, फर्ग्य अक्सर कमांडिंग, रॉयल भारतीय नौसेना, एयर जफसर कमांडिंग, सशस्त्र-युद्ध-विभाग, भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार, सर मिर्जा मोहम्मद इस्माइल प्रधान मन्त्री अन्पुर राज्य, राजबहादुर राज रावा नरपत सिंह, जोधपुर, डा० अमरनाथ झा कुतराई, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, खान बहादुर मिर्जा अफजल हुसैन, भुवनेश्वर कुतुबुद्दीन पंजाब विश्वविद्यालय, बन्धु० एन० मैक्करोलहास, प्रिंसिपल इन्वीनियरी कालेज पूना, और ए० ई० फूट, हेडमास्टर, दून स्कूल, देहरादून।

अकादेमी एक डि-सोमा प्रदान करे, जिसे विश्वविद्यालयों से स्नातक उपाधि के समकक्ष मानने के लिए कहा जाय। आगामी सांविधानिक परिवर्तनों की दृष्टि में, सत्ता-हस्तान्तरण के समय तक, इस प्रतिवेदन पर विचार करने में कोई विशेष प्रगति न हुई।

१५ अगस्त के तुरन्त बाद भारत सरकार ने समिति की सिफारिशों पर विचार किया और सासकर यह देखा गया कि क्या बदलते परिस्थितियों में कोई परिवर्तन तो जरूरी नहीं है।

फरवरी, १९४८ में यह फैसला किया गया कि एक संयुक्त अकादेमी छद्मवासना में स्थापित की जाय, जहाँ दोनों ही सेनाओं के सेनाछात्र प्रशिक्षण प्राप्त करें। अन्त सेना-पाठ्य-क्रम की अवधि तीन साल रखी गयी। प्रवेश की आयु प्रायोगिक रूप में १५ से १७ साल रखी गयी, जिस पर अनुभव के अनुसार फिर विचार कर लिया जाय। नौसेना अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि सेनाछात्र ज्यादा से ज्यादा १८ साल की आयु में समुद्र पर ले जाये जायें और वायुसेना के अधिकारी चाहेंगे कि सेनाछात्र किसी स्वेडिश में पूरे-पूरे पाइलट लगभग २१ साल की आयु में बन जायें। इसलिए आयु-सीमा १५ और १७ साल रखी गयी (यह आयु सीमा बाद में १९५३ में १७½ साल तक बढ़ा दी गयी)। साथ ही नौसेना के सेना-छात्रों को १५ साल की आयु में ही प्रवेश पाने के लिए प्रोत्साहित किया जाय, ऐसा तय किया गया। तीन साल के संयुक्त पाठ्यक्रम के बाद नौसेना और वायुसेना के सेनाछात्र अपनी-अपनी सेना की स्थापनाओं में विशेषीकृत प्रशिक्षण पाने के लिए अकादेमी से चले जायेंगे, जबकि सेना के सेनाछात्र, उच्च प्रशिक्षण के लिए, एक साल और रहेंगे।

छद्मवासना में नये भवन बनने में देर लगती। इसलिए यह निश्चय किया गया कि भारतीय सैन्य-अकादेमी, देहरादून में, जनवरी, १९४९ से, प्रयोगात्मक आधार पर, एक अन्त सेना स्कन्ध खोला जाय। १ जनवरी १९४९ से इसके दो स्कन्ध रहे, नामतः सेना-स्कन्ध, जिसमें उस समय विद्यमान भारतीय सैन्य अकादेमी आती थी और दूसरा नवस्थापित अन्त सेना-स्कन्ध, जिसमें सभी सेनाओं के सेनाछात्र दो साल की अवधि तक संयुक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले थे। आरम्भिक संयुक्त प्रशिक्षण के बाद, सेना के सेनाछात्र दो साल और सेना-स्कन्ध में आगे प्रशिक्षण के लिए, बने रहने को थे, जब कि नौसेना और वायुसेना के सेनाछात्र अपनी-अपनी प्रशिक्षण संस्थाओं में और आगे प्रशिक्षण के लिए जाने वाले थे। पहले कुछ वर्षों में, जब तक भारत में प्रशिक्षण सुविधायें स्थापित की जाती, संयुक्त सेना-स्कन्ध का दो साल का पाठ्यक्रम पूरा करने, नौसेना-छात्र, ४ से ६ साल तक के और आगे के प्रशिक्षण के लिए, ५० के ० को भेजे गये। भारतीय-सैन्य-अकादेमी का नाम बदल कर संयुक्त सेना-अकादेमी कर दिया गया।

अन्त सेना-स्कन्ध में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को पहले मैट्रिक स्तर की एक परीक्षा देनी होती थी, जो फंडरल (अब संघीय) बोर्ड-मेन्स-आयोग द्वारा ली जाती थी। जो उम्मीदवार निश्चित परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते थे, उनको एक सेना-चपत-बोर्ड के सामने साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना पड़ता था, जो भारत सरकार में, अकादेमी में प्रवेश के लिए, उम्मीदवारों के अन्तिम चयन की सिफारिश करना था।

पहले, पाठ्यक्रम (जो जनवरी, १९४९ में शुरू होना था) की योग्यता की परीक्षा करने के लिए और जल्दी व्यवस्था के लिए कम समय उपलब्ध होने को दृष्टि में आरम्भिक चुनाव

रब-एरिया मुख्यालय में एक मासालकार में किया गया। सब एरिया मुख्यालय द्वारा सिफारिश किये गये उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए सेना-चयन-बोर्ड द्वारा बुलाये गये। दूसरे और अगले पाठ्यक्रमों के लिए विहित योग्यता-परीक्षा संघीय लोक-सेवा-आयोग द्वारा ली गयी।

जंसा पहले बताया जा चुका है, द्वितीय विश्व-युद्ध से पहले भारतीय सैन्य-अकादेमी में सेनाछात्रों को अपने प्रशिक्षण का सारा खर्च देना पड़ता था। १९२६ के अन्त की ओर जब युद्ध शुरू हुआ, सिविनियन सेनाछात्रों को अकादेमी में प्रवेश दिया गया। उनको ट्यूशन, वस्त्र और भोजन आदि के लिए कुछ न देना पड़ता था। साथ ही उनको लगभग १ रुपये प्रति दिन मिलने थे। जुलाई, १९४६ में सेनाछात्रों को दिया जाने वाला भत्ता बढ़ाकर २१० रुपये प्रति मास कर दिया गया। कुछ आवश्यक खर्च करने के बाद सेनाछात्रों के पास लगभग १५० रुपये बच जाते थे। बदली हुई परिस्थिति में सभी सेनाछात्रों के लिए दर १ अप्रैल, १९४८ से ७५ रुपये प्रतिमास कर दी गयी। इसी सादृश्य पर यह तय किया गया कि प्रायोगिक अन्त-सेना-स्कन्ध के सेनाछात्रों को भी नि शुल्क ट्यूशन, वस्त्र, भोजन आदि दिये जायें और कुछ अभिकृत भद्रों पर ध्यान करने के लिए ७१ रुपये मासिक भत्ता दिया जाय। १ जनवरी, १९५० से सारा प्रशिक्षण-खर्च सरकार द्वारा दिये जाने के कारण, यह भत्ता खत्म कर दिया गया। भत्ते के एवज में हर सेनाछात्र के हिसाब में २० रुपये मासिक की रकम कमाई के पाम रख दी जाती थी, ताकि निभियों के लिए चन्दा आदि, जैसे सेनाछात्रों के बाध्यकर खर्च, पूरे किये जा सकें। साथ ही खिदमतगार की अशकानिक सेवा भी उपलब्ध की जाती थी, पर सेनाछात्रों के लिए जल्दी जेबखर्च जनक या अभिभावक को पूरा करना होता था। सरकार ने बाद में ऐसे सेनाछात्रों के लिए ३० रुपये प्रति मास तक की वित्तीय सहायता देना शुरू कर दिया, जिनके जनक या अभिभावक की आय ३०० रुपये मासिक से कम होती थी। नौसेना के लिये चुने गये सेनाछात्रों के जनक या अभिभावक को एक घोषणा पर हस्ताक्षर करना होता था कि वह इस स्थिति में है कि अन्त-सेना-स्कन्ध में उम्मीदवार का प्रारम्भिक प्रशिक्षण पूरा होने के बाद, आगे ५० के० में प्रशिक्षण के लिए उसका वित्तीय दायित्व पूरा कर सकेंगे और ऐसा करने के लिए तैयार हैं। इस तरह जनवरी, १९४६ में सशस्त्र सेना-अकादेमी में, संयुक्त सेना-स्कन्ध के उद्घाटन के बाद, नौसेना के लिए अधिकारियों के चयन के वास्ते तीन मार्ग थे, अर्थात् संयुक्त सेना-स्कन्ध, फेडरल लोक-सेवा-आयोग द्वारा ली गयी परीक्षा द्वारा विशेष प्रवेश और भारतीय वाणिज्य-समुद्री-प्रशिक्षण-पीठ, इफरिन, के कैडेटों में से हर साल एक विशेष परीक्षा द्वारा चयन।

संघीय-लोक-सेवा-आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रारम्भिक परीक्षा में कुल मिला कर ५० प्रतिशत से ऊपर अंक पाने वाले छात्रों को ही एक चयन-बोर्ड के सम्मुख उपस्थित होने के लिए बुलाया जाता। दूसरे और तीसरे पाठ्यक्रमों के लिए अन्तिम चुनाव केवल सेना-चयन-बोर्ड की सिफारिश पर ही आधारित था। उसके बाद अन्तिम नतीजा तैयार करने में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया, जिसका उन्नेस इस अध्याय के अन्त में किया गया है।

प्रायोगिक अन्त-सेना-अकादेमी में दो साल का समान पाठ्यक्रम तैयार करने और सड़कवासला में प्रस्तावित अकादेमी का तीन साल का पाठ्यविवरण संशोधित करने के लिए

वनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के कुलपति डा० अमरनाथ झा के सम्भाषित्व में मई, १९४८ में एक समिति नियुक्त की गयी।

देहरादून में अन्त-सेना-स्कन्ध शुरू करने का तात्पर्य यह था कि जनवरी, १९४९ से फिर आगे और सीधे भरती न होगी, जबकि अन्त-सेना-स्कन्ध में अपना दो साल का प्रशिक्षण पूरा कर चुकने वाली सेनाछात्रों की पहली टुकड़ी उपलब्ध हो जायेगी। लेकिन इन सेनाछात्रों की संख्या अपर्याप्त रही और सेना-स्कन्ध में सीधे भरती जनवरी, १९४९ के बाद भी चालू रखनी पड़ी। कुञ्ज-समिति की सिफारिश पर (बाद में उल्लिखित) यह तय किया गया कि सीधे प्रवेश की यह रीति बालू रहनी चाहिये, ताकि सेना में उच्चतर वर्गों और अधिक वैज्ञानिक योग्यता वाले, और इस कारण भिन्न पृष्ठभूमि और अनुभव वाले, अधिकारी भी आने लगे।

१ जनवरी, १९४० में सशस्त्र सेना अकादेमी का नाम राष्ट्रीय-रक्षा-अकादेमी कर दिया गया और अन्त-सेना-स्कन्ध का नाम संयुक्त-सेना-स्कन्ध। सेना-स्कन्ध का नाम वही बना रहा।

इस बीच खडकवासला में राष्ट्रीय रक्षा-अकादेमी का अपना स्थायी भवन बनाने के लिए तेजी से काम उठाये गये। ६ अक्टूबर, १९४९ को प्रधान मंत्री ने आधार-शिला रखी और फिर निर्माण कार्य तेजी में आगे बढ़ा। इस प्रयोजन के लिए बम्बई सरकार ने उदारतापूर्वक ६,६७६ एकड़ जमीन प्रदान की। जमीन की कीमत के अलावा प्रयोजन के पृथीय का अनुमान ६५ करोड़ रुपये था। अकादेमी की योजना इस प्रकार बनी थी कि ५०० सेनाछात्र प्रतिवर्ष (२५० प्रति छात्राहो पर शुरू होने वाले प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए) लिये जा सकें और इस तरह एक समय में कुल १५०० सेनाछात्र रह सकें। प्रयोजना के उपर नियन्त्रण रखने के लिए दो समितियाँ बनायी गयीं एक पर्यवेक्षण-बोर्ड और दूसरी निर्माण-समिति।<sup>१</sup> पर्यवेक्षण-बोर्ड का काम अकादेमी सम्बन्धी प्रमुख नीति प्रश्नों से था, जबकि निर्माण समिति का सम्बन्ध अकादेमी के वस्तु निर्माण तथा उसमें सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं से था। निर्माण का खर्च रक्षा-मेनाओं के अनुमानों से पूरा किया जाता था, पर धन के लिए किये गये अनुरोध के फलस्वरूप विभिन्न राज्यों और नरेशों से ५९ लाख रुपये दान में प्राप्त हुए, जिसके फलस्वरूप अकादेमी के विभिन्न प्लाटों के नाम खानदाजों के नाम से रखने का निश्चय किया गया।

खडकवासला में अकादेमी का कार्यकलाप चलाने के लिए अत्यावश्यक इमारतें १९४४ तक पूरी हो गयीं। खडकवासला में शुरू होने वाला पहला पाठ्यक्रम, जो संयुक्त-सेना-स्कन्ध की देहरादून पाठ्यक्रम था, १० जनवरी, १९४५ को शुरू हुआ। नये भवनों का औपचारिक उद्घाटन १६ जनवरी, १९४५ को बम्बई के मुख्य मंत्री द्वारा किया गया। अकादेमी

- \* दोनों ही समितियों के अध्यक्ष रक्षा-सचिव थे, और वित्तीय-सहायकार, इंजीनियर-इन-चीफ और राष्ट्रीय-रक्षा-अकादेमी पाठोक्तों के इंजीनियर उसके सदस्य थे। इसके अलावा पर्यवेक्षण-बोर्ड में तीनों सेनाओं के प्रमुख और भारत सरकार के मुख्य वास्तुगार सदस्य थे। निर्माण समिति में केन्द्रीय सौकर-निर्माण-विभाग के अनिर्दिष्ट-मुख्य-इंजीनियर भी सदस्य थे।

पूना से प्रायः दस मील दूर मूठा नदी के बायें किनारे पर बनी हुई है। यह सड़कवासीना भील से नदी के किनारे-किनारे नीचे की ओर दो मील तक फैली हुई है और पूरा क्षेत्र लगभग दस वर्ग मील है। अकादेमी के कमांडेंट का ओहदा मेजर जनरल या समकक्ष अधिकारी का होता है और इस पर तीनो सेनाओं के अधिकारी क्रमवार रहते हैं। उनके स्टाफ के अधिकारी भी तीनो सेनाओं में आते हैं।

जैसा पहले बताया जा चुका है, सेनाछानों के सभी खर्च सरकार द्वारा दिये जाते हैं, केवल जेबखर्च को छोड़कर, जो पहले दो सालों में लगभग ३० रुपये मासिक और तीसरे साल में ४० रुपये मासिक आता है। जिन मामलों में जनक की आय ३०० रुपये मासिक से कम होती है, उन में सरकार यथास्थिति ३० या ४० रुपये प्रतिमास की वित्तीय सहायता दे देती है। जुलाई, १९६८ में आय सीमा एक बच्चे के लिए ३५० रुपये मासिक, और अगर किसी जनक या अभिभावक के एक से ज्यादा बच्चे सेनाछान प्रशिक्षण स्थापनाओं में हों, तो ४०० रुपये कर दी गयी।

देहरादून के संयुक्त-सेना स्कूल के दो साल के पाठ्यक्रम को भारत के अधिकांश विश्व-विद्यालयों ने आगे पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए इंटरमीडिएट स्तर के समकक्ष की मान्यता दे दी है, और संघीय लोक-सेवा-आयोग और युव-मन्त्रालय ने केन्द्रीय सरकार के अधीन सेवाओं के लिए। यह इसलिए किया गया कि यदि कोई सेनाछान पढाई के विषयों में कमजोरी के अलावा किसी अन्य कारण से हटाया जाय, तो हमें उसके जीवन-कार्य पर अकादेमी में प्रवेश लेने के कारण प्रभाव न पड़े। ऐसी ही मान्यता राष्ट्रीय रक्षा-अकादेमी द्वारा दो साल के पाठ्य-क्रम के बाद ली जाने वाली परीक्षा के लिए दे दी गयी।

राष्ट्रीय रक्षा अकादेमी का समान पाठ्यक्रम अब तीन साल का है। इस प्रशिक्षण को पूरा करने के बाद नौसेना और वायुसेना के सेनाछान, और आगे प्रशिक्षण के लिए, अपनी-अपनी सेना की स्थापनाओं में चले जाते हैं और सेनाछान अपने प्रशिक्षण के चौथे साल में देहरादून चले जाते हैं।

जनवरी १९५४ में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति डा० जी० एस्० महाजन की अध्यक्षता में एक तदर्थ समिति बनायी गयी, जिसमें तीसरे साल के दौरान, अध्ययन के पाठ्य विवरण पर प्रतिवेदन देने को कहा गया। जो पाठ्य-विवरण सरकार ने अनुमोदित किया, वह इसी समिति की सिफारिश पर आधारित था।

अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड की स्थायी समिति ने उन सेनाछानों के प्रश्न पर विचार किया, जिनको पहले या तीसरे वर्ष के अन्त में, अध्ययन की कमी या अनुशासन-हीनता के अलावा, किसी अन्य कारण से अकादेमी छोड़नी पड़ जाती थी और उससे यह सिफारिश की कि इन सेनाछानों को विश्वविद्यालयों में, उनकी शैक्षिक उपलब्धि के बारे में उपयुक्त परीक्षण करके, उसके आधार पर प्रवेश दिया जाय। अनेक विश्वविद्यालयों ने अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड के इस प्रस्ताव को मान लिया है।

तीनों सेनाओं के सेनाछानों के प्रशिक्षण के लिए संयुक्त व्यवस्था एक अपूर्व प्रयोग है। इसमें तीनों सेनाओं के सम्भाव्य अधिकारियों का परस्पर बहुत निकट का सम्बन्ध स्थापित हो



जाता है। यह अन्त-जना-अवबोध और सहकार में बहुत सहायक होता है। इस तरह पैदा हो जाने वाली सहयोग-भावना आधुनिक सक्रिया में बहुत काम की होती है, जब तीनों सेनाओं को बहुत महत्वपूर्ण योगदान देना पड़ता है।

जनवरी १९५५ के बाद भी देहली में सैन्य विंग ( जिसे बाद में सैन्य कालेज नाम दे दिया गया ) सेनाध्यक्षों को दो साल का प्रशिक्षण देता रहा, जो एक स्पर्धा-परीक्षा द्वारा चुने जाते हैं और उनके बाद सेना में सीधे कमीशन प्राप्त करने के लिए उनको एक चयन-बोर्ड का परीक्षण देना होता है। इन सेनाध्यक्षों के प्रशिक्षण के अलावा सैन्य कालेज ( अब भारतीय सैन्य अकादेमी ) में सेना में कमीशन देने से पहले एक साल का प्रशिक्षण तकनीकी स्नातको को दिया जाता है।

### चयन-रीति सम्बन्धी समिति

तीनों सेनाओं में अधिकारियों के चयन की पद्धति की अक्सर कुछ आलोचना की जाती रही थी। आरम्भिक चयन की पद्धति एकरूप न थी। सेना में ही, १९४८ में ही, सराफ़ सेना-अकादेमी के सैन्य-स्कन्ध में प्रवेश के लिए, सब-एरिया बोर्ड आरम्भिक चयन करते थे, जबकि विदेश स्नातक पाठ्यक्रम या तकनीकी शाखाओं में सक्षिप्त सेवा-कमीशन देने के लिए ऐसा कोई आरम्भिक चयन नहीं किया जाता था। इन कमीशनो के लिए उम्मीदवारों की सख्या कम होने के कारण उनको सीधे ही चयन-बोर्ड के सामने आने दिया जाता था। नौसेना में सक्षिप्त सेवा कमीशनो के लिए सीधे प्रवेश वाले अधिकारियों का प्रारम्भिक चुनाव नौसेना मुख्यालय करता था और वायुसेना में प्रारम्भिक चयन पूणत वायुसेना भरती-अधिकारी ही करते थे।

सामान्य भावना यह थी कि इस चयन-पद्धति के कारण ऐसे बहुत से लोग अस्वीकृत हो जाते हैं, जो बड़े अच्छे अधिकारी बन सकते थे। इसलिए सरकार ने तदन्तर, १९४८ में इस प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति स्थापित की।\* इस बीच अन्त-जना-स्कन्ध और सैन्य-स्कन्ध के उम्मीदवारों के प्रारम्भिक चुनाव के लिए एक योग्यता-परीक्षा लेने का निर्णय पहले ही किया जा चुका था।

समिति ने अपना प्रतिवेदन मार्च, १९४९ में प्रस्तुत किया। इनकी सिफारिशों में से सरकार द्वारा मानी गयी ज्यादा महत्व की सिफारिशें ये थी —

( एक ) सब एरिया या अन्य स्थानीय बोर्डों या भरती-अधिकारियों द्वारा चिये जाने वाले आरम्भिक चयन की जगह पर तीनों सेनाओं के लिए फेडरल सेल-मेरा-आयोग द्वारा

\* इस समिति में थे लोग थे वी० वी० घोष, सयुक्त-सचिव, रक्षा-मन्त्रालय, अध्यक्ष और सदस्य थे कैप्टन डबल्यू० आर्द० संमस्टन, नौसेना शिक्षा निदेशक, नौसेना-मुख्यालय, त्रिग्वियर सी० जे० एल० टर्नर, संगठन निदेशक सेना-मुख्यालय, ग्रुप कैप्टन के० एल० सोधी, वार्षिक निदेशक वायुसेना-मुख्यालय, डा० जी० एस० महाजनी, कुलपति राजभूषाना वि० वि० और डा० सोहन लाल निदेशक मनोविज्ञान-निदेशालय, सयुक्त प्रान्त और वी० एम० मिंडे अवरसचिव, रक्षा मन्त्रालय इसके सचिव थे।

परीक्षा ली जानी चाहिये, लेकिन इन्वीनियरी या तकनीकी शाखाओं के लिए अविकारियों का चयन करने समय ऐसा परीक्षा आवश्यक नहीं है, और इन मामलों में अपेक्षित योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को अन्तिम चयन-बोर्ड के सामने आ जाने देना चाहिए ।

( दो ) हातांकि चयन-बोर्डों द्वारा अनायी गयी पद्धति के अनेक पहलुओं में सुधार अपेक्षित है, पर इसमें सन्देह नहीं कि केवल एक संक्षिप्त साक्षात्कार द्वारा या इसके पहले एक लिखित परीक्षा लेकर चयन करने की पुरानी परम्परागत पद्धति की तुलना में कुल मिलाकर मनोवैज्ञानिक और मानस-परीक्षण पर आधारित चयन की नयी पद्धति निश्चय ही ध्येष्ठतर है । नयी पद्धति में अधिकारी प्रशिक्षण-स्कूलों और सैन्य अकादेमी में व्यर्थता को कम करने में मदद दी है । लेकिन इस प्रणाली की एक महत्वपूर्ण कमी यह है कि इसमें किसी उम्मीदवार को अपने ज्ञान या दौड़िक उपलब्धि के लिए कोई ध्येय नहीं मिल पाता, क्योंकि अन्तिम चयन बोर्डों की सिफारिशों पर ही किया जाता है । फलस्वरूप शैक्षिक और अध्ययन वाली पृष्ठभूमि के महत्व को नकार दिया जाता है और कुछ सीमा तक समानप्रियता और नेतृत्व जैसे गुणों के ऊपर अत्यधिक जोर दिया जाता है । इस बात को नहीं माना जाता कि ये गुण व्यक्ति विशेष में समुचित रूप से प्रशिक्षित और अनुशासित होने के बाद भी विकसित हो सकते हैं । सरासरी सेनाओं में ऐसे अधिकारी भी चाहिये जो चिन्तन, लेखन और आयोजना बनाने में भी समर्थ हों, अर्थात् जो अधिकारी उच्चतर आयोजना-निर्माण कार्य और स्टाफ के कर्तव्य निभा सकें । समिति ने सुझाव दिया कि लोक-सेवा-आयोग की प्रारम्भिक परीक्षा और चयन-बोर्डों के परीक्षणों को मिला दिया जाय यह ध्यान देना बड़ा रोचक है कि यू० के० में, सैंडहस्त के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों को, केवल दो ही ध्येयों में ग्रेड-बढ़ किया जाता है : उप-पयुक्त और अनुयुक्त । जो उपयुक्त होते हैं, उनको सैनिक-सेवा-शायकों द्वारा ली गयी लिखित परीक्षा के ही आधार पर योग्यताक्रम में रखा जाता है । रायल नौसेना के मामले में परीक्षा-फल समुक्त होता है—५०० अंक लिखित परीक्षा के लिए आवण्टित किये जाते हैं और ४०० चयन-बोर्डों के परीक्षणों के लिए । उम्मीदवारों को कुल प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता-क्रम में रखा जाता है । रायल वायुसेना में भी अन्तिम चुनाव चयन-बोर्ड के परीक्षणों और लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के समुक्त प्रतिक्रिया पर आधारित होता है ।

समिति ने सुझाव दिया कि भारत में फेडरल लोक-सेवा-आयोग की परीक्षा और चयन-बोर्ड के परीक्षणों को बराबरी का गुरुत्व दिया जाना चाहिये । इसलिए चयन-बोर्डों को, उम्मीदवारों का ग्रेड-निर्धारण न करके, उनको अंक प्रदान करने चाहिये । अन्त में ग्रेड-निर्धारण की जगह अंक देने की पद्धति नवम्बर, १९४६ से शुरू की गयी, जब अन्त-सेना-अनुसन्धान-धर्मन ने, और आगे पड़ताल करके, इसकी व्यावहारिकता सिद्ध कर दी थी । तब तक चयन-बोर्ड ग्रेड-निर्धारण करते रहे, जिसको फेडरल लोक-सेवा-आयोग के परिणामों और चयन-बोर्डों के परीक्षणों को मिलाने के प्रयोजन से अंकों में बदल दिया जाता था । सफल उम्मीदवारों को न्यूनतम अहंकारी अंक प्रत्येक परीक्षण में प्राप्त करने होते थे । चयन बोर्डों द्वारा निर्धारण की रीति भी और ज्यादा यथावश्यक कर दी गयी । बोर्डों द्वारा अंकों के लिए अनेक गुणों को दर्शाने वाला एक दर-निर्धारण मान नैपार किया गया और जनवरी, १९५१ में लागू कर दिया गया ।

(तीन) उपर उल्लिखित समिति ने एक अन्त-सेना-अनुसन्धान-मण्डल बनाये जाने की सिफारिश की। इसका मुख्य कारण यह था कि उस समय काम में आने वाले अधिकार परीक्षण यू० के० में लिये गये थे और बहुत समय में इस्तेमाल में आ रहे थे। इनमें से कुछ परीक्षण भारतीय सड़कों के लिए उपयुक्त न थे और उनमें संशोधन करना जरूरी हो गया था। यह भी जरूरी था कि इन परिणामों के ज़रिए जुड़े गये उम्मीदवारों के वृत्त्यकरण का अनुगामी-अनु-सन्धान किया जाय। परीक्षणों की मान्यता और परीक्षण सामग्री के गुणों का भी सांख्यिकीय अध्ययन करके देख-रेख रतना जरूरी था। तदनुसार, रक्षा-विज्ञान-संगठन के अगस्वरूप, १९४६ में एक मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान-मन्त्रालय बनाया गया, जिसका उल्लेख एक अन्य अध्याय में किया गया है।

राष्ट्रीय रक्षा-अकादमी (और मौमेना और वायुसेना की सहायी संस्थाओं) में प्रशिक्षण के लिए जुड़े गये सेनाद्वारा सेवामुक्त किये जा सकते थे, यदि वे परीक्षण-काल में अधिकारियों जैसे गुण प्रदर्शित न करें। इस आधार पर कुछ उम्मीदवार निकाल दिये गये। फिर भी यह आवश्यक करना जरूरी था कि प्रशिक्षण-काल के दौरान एक सेनाद्वारा की सम्भाव्यताओं के निर्धारण में कोई त्रुटि तो न रहे मधी थी। तदनुसार सरकार ने १४ नवम्बर, १९५३ को राज्य-सभा-सदस्य डा० हृदयनाथ कुंजरु के सभापतित्व में अधिकारी-मेनाद्वारा के अस्वीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रश्न का अध्ययन करने के लिए एक समिति नियुक्त की।\*

समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को ३० अप्रैल, १९५५ को सौंप दिया। समिति को सल्लोप था कि प्रशिक्षण-काल में सेनाद्वारा के निर्धारण की रीतियाँ तीनों सेनाओं में ठोस, व्यापक और युक्तियुक्त हैं और सेनाद्वारा को अपने भभाव दूर करने के लिए और उनके अन्तर्निहित गुणों को विकसित करने के लिए पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध हैं। समिति ने कहा कि सेनाद्वारा के अस्वीकृत किये जाने की दर सेना और मौमेना में बहुत कम है, पर वायुसेना में कुछ ज्यादा है। वायुसेना में सेनाद्वारा की व्ययंता को कम करने के लिए समिति ने सिफारिश की कि वायुसेना के उम्मीदवारों के अधिकारियों जैसे गुणों का परीक्षण सेना-चपन-शेडों द्वारा किये जाने से पहले, वायुसेना के उम्मीदवारों से पाइलट-इमान-परीक्षण को उत्तर्ण करने को अनेता को जानी चाहिये। समिति का विचार था कि चपन की यह पद्धति, जिसमें सही ढाँचा-आयोग द्वारा सी गयी परीक्षा और सेना-भयन शोध द्वारा लिये गये परीक्षणों की समान महत्त्व दिया जाता है, उम्मीदवारों की बौद्धिक-क्षमता और अधिकारियों जैसे गुणों के निर्धारण के लिए समुचित अवसर प्रदान करती है, अतः इसे चालू रखा

\* इस समिति के अन्य सदस्य थे . सरदार मुरजीत सिंह मजीठिया, उप-रक्षा-मन्त्री, डा० जी० एस० महामनी, कुलपति दिल्ली वि० वि०, मेजर जनरल टी० महारंज सिंह, डी० एस० बी०, एडजुटेंट जनरल, सेना-मुख्यालय, कैप्टन बी० ए० सेमसन, इंडियन नेवी, कर्माच प्रमुख, नौसेना-मुख्यालय, ग्रुप कैप्टन बी० पी० मेहरा, प्रशिक्षण निदेशक, वायु सेना-मुख्यालय, डा० सोहन लाल, मुख्य मनोवैज्ञानिक, रक्षा-मन्त्रालय, एच० सी० सरिन, आई० सी० एस० रजिस्ट्रार, रक्षा-मन्त्रालय (सदस्य-अतिथि)।

जाना चाहिये। समिति ने यह भी सिफारिश की कि उम्मीदवारों की शारीरिक क्षमता और हृदय के संव्यासक निर्धारण के लिए २०० अंक दिये जाने चाहिये और प्रत्येक उम्मीदवार को, लिखित परीक्षा और चयन-बोर्ड परीक्षणों की तरह, इसमें भी न्यूनतम अंकांश अंक प्राप्त करने चाहिये। समिति ने देखा कि सैन्य कालेज, देहरादून में १२ महीनों का राष्ट्रीय-सेना-छात्र दल का पाठ्यक्रम पूरा करने वाले सेनाछात्रों और दो साल तक वहाँ पर सीधे प्रवेश का पाठ्यक्रम पूरा करने वाले सेना-छात्रों के बीच अस्वीकृति-दरों में काफी असमानता है। इस असमानता को दूर करने के लिए समिति ने यह सिफारिश की कि राष्ट्रीय-सेनाछात्र-दल-पाठ्यक्रम प्रशिक्षण-काल १२ से बढ़ाकर १८ महीने कर दिया जाय।

जून, १९५६ से किये गये चयन में २०० अंकों का एक शारीरिक-सहन-सामर्थ्य-परीक्षण भी उन सभी उम्मीदवारों के लिए शुरू कर दिया गया, जो राष्ट्रीय रक्षा-अकादमी, सैन्य कालेज, वायुसेना कालेज आदि में प्रवेश चाहते थे। बाद में अगस्त, १९५६ में यह परीक्षण राष्ट्रीय सेनाछात्र-दल के पाठ्यक्रम और तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवारों पर भी लागू कर दिया गया। साथ ही, वायुसेना के सेनाछात्रों का पहले पाइलट-रुक्मान-परीक्षण लिया जाता है, जो किसी उम्मीदवार को केवल एक ही बार देना पड़ता है। इस परीक्षण में अनुत्तीर्ण होने वालों पर वायुसेना के लिए विचार नहीं किया जाता। अनुभव के आधार पर बाद में शारीरिक-सहन-सामर्थ्य-परीक्षण हटा दिया गया।

संक्षेप में राष्ट्रीय रक्षा-अकादमी के लिए सेनाछात्रों के चुनाव की वर्तमान स्थिति यह है कि जो उम्मीदवार सचोय सौक सेवा-आयोग की लिखित परीक्षा ( जिसमें कुल १०० अंक होते हैं ) में योग्य सिद्ध होते हैं, वे एक सेना-चयन-बोर्ड के सामने उपस्थित होते हैं, जहाँ पर बलमेना, नौसेना और वायुसेना के उम्मीदवारों के अधिकारों बचने की सम्भावनाओं में परीक्षण लिया जाता है और वायुसेना वालों का पाइलट-रुक्मान में भी निर्धारण किया जाता है। चयन-बोर्ड के परीक्षण में भी १०० अंक होते हैं। इन परीक्षणों में उम्मीदवारों को न्यूनतम अंकांश अंक प्राप्त करने होते हैं। वायुसेना वालों को इसके अलावा पाइलट-रुक्मान-परीक्षण में भी उत्तीर्ण होना पड़ता है। इन बातों के अधीन उत्तीर्ण छात्रों को योग्यता-क्रम में रखा दिया जाता है, जिस का आधार लिखित परीक्षा और सेना-चयन-बोर्ड के परीक्षणों में उनके द्वारा प्राप्त कुल अंक होते हैं। उनको दो अलग सूचियों में रखा जाता है, पहली में बलमेना और नौसेना के लिए तथा दूसरी में वायुसेना के लिए। अन्तिम चयन, प्रत्येक सेना में उपलब्ध रिक्त स्थानों के आश्रित रहते हुए, योग्यता-क्रम से ही किया जाता है।

चयन की यही योजना बलमेना, नौसेना और वायुसेना के लिए, कुछ ज्यादा आयु वर्ग में से, अधिकारियों की सीधी भरती पर भी लागू होती है। सैन्य अकादमी में प्रवेश के लिए आयु सीमायें प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम के आरम्भ के समय १८ और २१ है और प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्णता है। आयोग की लिखित अंकांश परीक्षा और चयन-बोर्ड के साक्षात्कार प्रत्येक में १००-१०० अंक रहते हैं। चुने गये सेनाछात्रों को मेना अधिनियम के अधीन भर्तन सेनाछात्र के रूप में नामाङ्कित किया जाता है और उनकी

सैन्य कालेज में लगभग दो साल का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसके बाद उनको स्थायी कमीशन मिल जाता है।

इन सोये प्रवेश वाले सेनाछात्रों के लिए दो साल के पाठ्यक्रम और राष्ट्रीय रक्षा-अकादमी से आने वाले पल-सेनाछात्रों के लिए एक साल से पाठ्यक्रम के अलावा भारतीय सैन्य कालेज में स्थायी कमीशन के लिए ये अतिरिक्त पाठ्यक्रम भी चलाये जाते हैं। (क) यशवेना छात्र-कालेज से उत्तीर्ण होकर आने वाले सेनाछात्रों के लिए (१९३ में २४ साल के बीच की आयु-सीमा वाले), १३ साल का पाठ्यक्रम, (ख) राष्ट्रीय सेनाछात्र-दल की अधिकारी प्रशिक्षण यूनिटों के सेनाछात्रों के लिए १३ साल का पाठ्यक्रम (इस प्रवेश के लिए आयु सीमा १६ और २२ साल के बीच), और (ग) तकनीकी स्नातक के लिए एक साल का पाठ्यक्रम, जिसमें विश्वविद्यालय-प्रवेश-योजना वालों को (२० और २७ सालों की आयु-सीमा के भीतर, यशवेना शिक्षा-कोर को छोड़ कर, जिसके लिए आयु-सीमा २१ और २७ साल है) इकीनियर-कोर, सिगनल्स-कोर, विजली और यान्त्रिक इकीनियरी-कोर, यशवेना-शिक्षा कोर और सैन्य-फार्म-सेवा में कमीशन देना शामिल है। इन तीनों मामलों में उम्मीदवारों को सैन्य लोकसेवा-आयोग को लिखित परीक्षा में नहीं बैठना पड़ता, बल्कि वे सीधे ही सेवा चयन-बोर्ड के समक्ष जाते हैं। अन्य पाठ्यक्रमों में विवाहित उम्मीदवार नहीं लिये जाते, पर स्नातक-पाठ्यक्रम में विवाहित उम्मीदवार भी प्रवेश के लिए पात्र माने जाते हैं। फिर भी अविवाहित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण-काल में विवाह करने की अनुमति नहीं दी जाती।

नौसेना के लिए, विशेष प्रवेश-सेनाछात्रों का चयन करने के लिए, आयु सीमायें १७½ और १९½ वर्ष हैं और प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडियेट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना है। लिखित अहंकारी परीक्षा और चयन बोर्ड के साक्षात्कार में ६००-६०० अंक होते हैं। चुने गये उम्मीदवार सेनाछात्र नियुक्त कर लिये जाते हैं और फिर उनको राष्ट्रीय रक्षा-अकादमी में एक साल का प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण पूरा कर लेने के बाद उनको नौसेना के पोतों / स्थापनाओं में अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जाता है। पूरा प्रशिक्षण-काल (अकादमी के एक साल को जोड़कर) १३ से ६३ साल तक का होता है, जो सेना-छात्र को आवण्टित शाखा पर निर्भर रहता है : राष्ट्रीय-सेनाछात्र-दल के बरिष्ठ डिवीजन के नौसेना-स्कन्ध के सेनाछात्र, जिनके पास 'सो'-प्रमाणपत्र होता है और जो १७½ और २० साल के बीच की आयु के होते हैं, नौसेना में विशेष प्रवेश वाले सेनाछात्र के रूप में लिये जाने के पात्र होते हैं। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडियेट या समकक्ष परीक्षा होती है। भारतीय वाणिज्य-समुद्री-प्रशिक्षण-गोठ, इकरिन के बैटेल भी नौसेना में विशेष प्रवेश वाले सेनाछात्रों को तरह लिये जाते हैं और उनके लिए आयु सीमा १७½ और १९½ साल होती है। ये विशेष प्रवेश वाले सेनाछात्र राष्ट्रीय रक्षा-अकादमी के पाठ्यक्रम के तीसरे साल में लिये जाते हैं और अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अकादमी के नौसेना छात्रों की भाँति इनको भी भारतीय नौसेना के पोतों और स्थापनाओं में आगे प्रशिक्षण दिया जाता है।

इसी तरह वायुसेना कालेज में सामान्य-नर्तन्य-(पाइलट) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए

## भरती और प्रशिक्षण

आयु सीमायें १७½ और २१ वर्ष हैं और प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मैट्रिक या सम-परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। लिखित अर्हकारी परीक्षा में ६०० अंक होते हैं और वायुसेना-चयन-बोर्ड के परीक्षण में भी ६०० अंक ही होते हैं, पिछले में पाइलट-कमान और अधिकारो-सम्भाव्यतायें आ जाती हैं। अन्तिम रूप से चुने गये उम्मीदवार लगभग १८ महीने वायुसेना कालेज में प्रशिक्षण पाते हैं। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा होने पर उनको स्थायी कमीशन दिया जाता है।

सामान्य-कर्तव्य-शाखा में रिक्त स्थानों का एक प्रतिशतक राष्ट्रीय सेनाछात्र-दल (वायु-स्कन्ध) के लिए आरक्षित रहता है।

स्नातको को अ-सकनीकी शाखाओं (या जिनको भूमि-कर्तव्य-शाखायें कहा जाता है) में भी सीधे कमीशन दिये जाते हैं, अर्थात् प्रशासनिक और विशेष कर्तव्य-शाखा, उपकरण-शाखा, लेखा-शाखा प्रत्येक मामले में आयु-सीमा २१ और २३ वर्ष होती है), शिक्षा-शाखा (आयु सीमा २१ और २५ वर्ष) और ऋतुविज्ञान-शाखा (१६ और २६ वर्ष)। इन शाखाओं के उम्मीदवारों की कोई लिखित परीक्षा नहीं होती। वे सीधे ही वायुसेना चयन-बोर्ड के सम्मुख उपस्थित होते हैं।

संघीय लोक-सेवा-आयोग द्वारा सचल सेनाओं के समुक्त ओहदों के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा का एक रोचक रूप यह था कि जो उम्मीदवार परीक्षा में कुल मिलाकर ३० प्रतिशत या ज्यादा अंक प्राप्त करते थे (पहले यह ३५ प्रतिशत था) उनको ३० रुपये की परीक्षा शुल्क (अनुसूचित जातिवालों के लिए ७.५० रुपये, क्योंकि अनुसूचित जाति वाले इतनी ही घटी हुई शुल्क पहली बार में देते थे) वापस दे दी जाती थी। वापस देने की यह योजना १९६५ में समाप्त कर दी गयी। कनिष्ठ कमीशन-प्राप्त अधिकारियों, गैरकमीशन-प्राप्त अधिकारियों और अन्य पदधारियों के बच्चे और भूतपूर्व सैनिकों के जो बच्चे के ० जी० स्कूलों (अब जिन्हें सैन्य स्कूल कहते हैं) में और सैनिक स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं उनका इन परीक्षाओं के लिए कोई शुल्क न देकर यह प्रमाणपत्र देना होता है कि उनके कुल मिलाकर ३० प्रतिशत अन्याय अंक प्राप्त करने की सम्भावना है।

जैसा पहले ही बताया जा चुका है, आवास, पुस्तकें, वर्दी, भोजन और चिकित्सा को शामिल करते हुए सारा खर्च सरकार द्वारा दिया जाता है। उम्मीदवारों से अपना जेबखर्च स्वयं पूरा करने की आशा की जाती है, जो ४० रुपये महीने आता है। यदि सेनाछात्र का जनक या अभिभावक इतना भी खर्च न दे सके और उसकी आय ३५० या ४०० रुपये राष्ट्रीय रक्षा-अकादेमी के प्रसंग में बतायी गयी परिस्थितियों के अनुसार हो, तो सरकार ४० रुपये प्रति मास तक वित्तीय मदद मंजूर कर देती है।

## खण्ड दो . आपात भरती

सबद्वार, १९६२ में आपात की घोषणा के बाद भारतीय सैन्य-अकादेमी के जरिये स्थायी कमीशन दिया जाना बन्द कर दिया गया, केवल (१) उन सेनाछात्रों को छोड़कर जो राष्ट्रीय-अकादेमी से उत्तीर्ण होकर आने थे, (२) जो सैनिक सेनाछात्र कालेज, नागांव (अब

पूना में) से प्रशिक्षण के लिए चुने जाते थे और (३) अधिकारी प्रशिक्षण यूनिटों में प्रशिक्षित होने वाले राष्ट्रीय सेनाध्वज-दल के छत्र में सेना के अधिकारों सवर्गों के सीधे विस्तार की पूर्ति के लिए नवम्बर, १९६२ में आयोजित कमीशन देना शुरू किया गया। अ-तत्कालीन सेनाओं में न्यूनतम प्रवेश-योग्यता इंटरमीडिएट परीक्षा विहित की गयी, लेकिन आयु सीमा स्थायी कमीशन के लिए रखी गयी योग्यता की तुलना में कम कर दी गयी। गुरु में तो आयु-सीमा १५ वर्ष तक रखी गयी थी, पर बाद में १ जुलाई, १९६३ से इसे ३० साल तक लाया गया और १ जनवरी, १९६४ से २७ साल कर दिया गया। न्यूनतम आयुसीमा १९ साल बनी रही। उम्मीदवारों की छानबीन पहले एक प्रारम्भिक साक्षात्कार सेना-स्वयन-बोर्ड करता था। विहित आयु-सीमा में आने वाले नौकरों करने वाले ऐसे व्यक्ति, जो मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण थे, और दो साल तक सेना में नौकरी कर चुके थे, आपात कमीशन के लिए आवेदन करने के पात्र बना दिये गये। जो लोग इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण थे, उनमें नौकरों की शर्त भी हटा दी गयी।

आपात कमीशन के लिए चुने गये उम्मीदवारों के प्रशिक्षण के लिए भारतीय सैन्य-अकादेमी का विस्तार किया गया और छोटे-छोटे प्रशिक्षण-क्षमता आपात के आरम्भ में १४८५ सेनाध्वजों से बढ़ाकर जुलाई, १९६३ में ३२०० सेनाध्वज कर दी गयी, और दो अधिकारी प्रशिक्षण विद्यालय मद्रास और पूना में जनवरी, १९६३ में शुरू किये गये, जिसकी आरम्भिक क्षमता २०० सेनाध्वज थी जो बढ़ाकर जुलाई, १९६३ तक १५०० भर्जन सेनाध्वज कर दी गयी। आपात कमीशन देने के पूर्व का २२ हफ्ते का प्रशिक्षण इन सम्पादकों में दिया जाता था, जिसके बाद युवा अधिकारी अपनी-अपनी शाखा और सेना में और आगे कमीशनोत्तर प्रशिक्षण के लिए भेज दिये जाते थे। अधिकारी-सत्रों में आपात मरणी कार्यक्रम सीधे ही पूरा भी हो गया। स्थायी कमीशन प्रदान करने के लिए नियमित पाठ्यक्रम अगस्त, १९६४ से भारतीय सैन्य-अकादेमी में फिर से शुरू किया गया और अन्तिम आपात कमीशन के सेनाध्वज ३१ अक्टूबर, १९६४ को उत्तीर्ण होकर चले गये। पूना स्कूल में आपात कमीशन का अन्तिम पाठ्यक्रम १ मई, १९६४ को पूरा हो गया। तब यह स्कूल बन्द कर दिया गया और यह जगह सेनाध्वज कालेज को दे दी गयी, जिसे नौगांव में यहाँ से आया गया था। अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल, मद्रास का अन्तिम आपात कमीशन पाठ्यक्रम १० अप्रैल, १९६५ को पूरा हो गया। अत्र अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल मद्रास में दो तरह के पाठ्यक्रम चले हैं अर्थात् (क) एक सज्जित सेवा कमीशन (नैर-तत्कालीन) प्रदान करने के लिए ४१ हफ्ते का पाठ्यक्रम, जिसके लिए उम्मीदवार १९ में २५ साल के होने चाहिये और उनके पास इंटरमीडियेट या समकक्ष योग्यता होनी चाहिये, और (ख) केन्द्र और राज्य सरकारों के प्रथम धेणी और द्वितीय धेणी के अमेरिकी इंजीनियरी अधिकारियों के ऊपर लागू अनिवार्य दायित्व योजना के अधीन १४ हफ्ते का पाठ्यक्रम सज्जित सेवा कमीशन के लिए (इस योजना का उल्लेख हम अध्याय में बन्द को ओर किया जायेगा)। पहली योजना के अधीन पहला पाठ्यक्रम जून, १९६५ में शुरू हुआ और अप्रैल, १९६६ में समाप्त हुआ। अनिवार्य दायित्व योजना के अधीन पहला पाठ्यक्रम ११ जुलाई, १९६५ को शुरू हुआ और २० नवम्बर, १९६५ को समाप्त हुआ।

तकनीकी शाखाओं और सेवाओं (अर्थात् इंजीनियरी, सिग्नल्स और ई० एम० ई० कोरों) में आपात कमीशन देने की योजना १ जुलाई, १९६३ तक चलनी रही, जब इसका स्थान पाँच वर्ष के सशस्त्र सेवा कमीशन ने ले लिया, जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता था। इस तकनीकी कमीशन के लिए उम्मीदवारों को स्नातक होना पड़ता था और उनको अपनी स्नातक उपाधि के लिए दो साल का पूर्व-साम मिल जाता था।

आपात में पहले भी सेना-चिकित्सा कोर में आपात कमीशन दिये जाते थे। चिकित्सा स्नातकों को सेना चिकित्सा कोर में भरती के लिए भी आपात कमीशन योजना लागू की गयी, जिसमें अधिकतम ६३ वर्ष का पूर्व-साम दे दिया जाता था।

इंजीनियरी और चिकित्सा-स्नातकों की भरती बढ़ाने के लिए कई योजनाएँ शुरू की गयीं। उदाहरण के लिए (क) असेैनिक नौकरी को अवधि के आधार पर वरिष्ठता का पूर्व-साम प्रदान करना, (ख) सरकारी कर्मचारियों के मामले में पुनर्ग्रहणाधिकार, वरिष्ठता, असेैनिक वेतन और उपवर्धियों और अन्य सेवा-अधिकारों का संरक्षण (ग) सरकार को इंजीनियरी और चिकित्सा-सेवाओं के प्रथम और द्वितीय श्रेणी के स्थायी रिक्त स्थानों के ५० प्रतिशत का आरक्षण, जो आपात में सशस्त्र सेनाओं में कमीशन-प्राप्त स्नातक इंजीनियरी और और डाक्टरों में से ही सीधे भरती करके भरे जाने से, और (घ) विश्वविद्यालय-प्रवेश-योजना। विश्वविद्यालय-प्रवेश-योजना के अधीन विशेष चयन-टुकड़ियाँ देश की भिन्न-भिन्न इंजीनियरी और चिकित्सा-संस्थाओं में जाती थी और इंजीनियरी पाठ्यक्रम के अन्तिम या अन्तिम से पूर्व वर्ष में पढ़ने वाले और आयु-विज्ञान पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष में पढ़ने वाले सम्भाव्य उम्मीदवारों का आरम्भिक चयन कर लेती थी। जो लोग आरम्भिक चयन-टुकड़ियों द्वारा उपयुक्त समझे जाते थे, उनका साक्षात्कार चल-सेना-चयन-बोर्ड करते थे और चुने गये उम्मीदवारों की परीक्षा पर, अस्थायी सशस्त्र सेवा कमीशन अन्तिम वर्ष के छात्रों के मामले में, अन्तिम चयन की तारीख से, और अन्तिम-पूर्व वर्ष के छात्रों के मामले में उनके अन्तिम वर्ष की कक्षा में प्रवेश लेने की तारीख से, सेकिंड लेफ्टोर्नेट के ओहदे में प्रदान कर दिया जाता था। उपाधि-परीक्षा में उत्तीर्ण होने और कमीशन-पूर्व का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर, इन उम्मीदवारों को पाँच साल का सशस्त्र सेवा कमीशन दे दिया जाता था।

विभिन्न प्रोत्साहनों के बावजूद इंजीनियरी अधिकारियों की कमी बनी रही और इस स्थिति का सामना करने के लिए एक अनिवार्य सेवा-दायित्व-योजना शुरू की गयी, जिसके अधीन इंजीनियरी सेवाओं में आने वाले लोग, पहले दस साल के सेवा-काल में, न्यूनतम चार वर्ष तक की अवधि के लिए रक्षा-सेनाओं में सेवा करने के दायी हैं। योजना के अधीन प्रथम या द्वितीय श्रेणी के पदों पर (स्थायी या अस्थायी) केन्द्र या राज्य सरकारों में (लोक उन्नयन समेत) काम करने वाले ऐसे इंजीनियर जिनकी आयु ३० साल से कम है, उनको सेना में चार साल का (प्रशिक्षण अवधि जोड़ कर) सशस्त्र सेवा कमीशन दिया जाता है। उनके लिए सेना चयन-बोर्डों के सामने उपस्थित होना जरूरी नहीं होता। मूलतः तृतीय श्रेणी के अधिकारियों को अलग रखा गया था, पर अब उनको भी इस योजना के अधीन कमीशन देने का पात्र बना दिया गया है, पर उनको सेना चयन-बोर्डों के सामने उपस्थित होना पड़ता है। चुने गये अधि-



कारियों के बिकसितकोष दृष्टि में योग्य होने पर, अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल में उनको लगभग चार महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है। सशस्त्र सेवा कमीशन पाने वाले अधिकारियों को, बिहित तकनीकी योग्यता रखने के लिए, दो साल का पूर्वलाभ दिया जाता है। सशस्त्र सेवा कमीशन का समय, असेनिक नौकरी के वेतन में वार्षिक वृद्धि, पदोन्नति, पेन्शन, उपदान के लिए जोड़ा जायेगा। जैसा बताया जा चुका है, इस अनिवार्य सेवा-दायित्व-योजना के अन्तर्गत पहला सशस्त्र सेवा कमीशन-पाठ्यक्रम अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल, मद्रास में ३१ जुलाई, १९६५ को शुरू हुआ था और २० नवम्बर, १९६५ को समाप्त हुआ।

नवम्बर, १९६२ के बाद जिन ६००० अधिकारियों को आपात कमीशन दिये गये हैं, उनकी छानबीन, कुल संख्या के एक तिहाई तक को सेना में स्थायी रूप से रख लेने के लिए, की जायेगी। सरकार ने, सेवामुक्त हुए आपात कमीशन वाले अधिकारियों के लिए, स्थायी रिक्त-स्थानों का एक प्रतिशतक आरक्षित करने का भी निर्णय किया है। भारतीय प्रशासन-सेवा और भारतीय विदेश-सेवा (आई० एफ० एस०) के लिए २० प्रतिशत, भारतीय पुलिस-सेवा के लिए ३० प्रतिशत, गैर-तकनीकी प्रथम श्रेणी सेवा पदों के लिए २५ प्रतिशत और गैर-तकनीकी वित्तीय श्रेणी सेवाओं-पदों के लिए ३० प्रतिशत।

आपात के समय से, २१ से २७ वर्ष के आयु समूह के भीतर, अन्य पदधारियों के लिए आरक्षित स्थायी कमीशनो के वार्षिक रिक्त-स्थानों का अनुपात १० प्रतिशत से बढ़ाकर २४ प्रतिशत कर दिया गया। बाद में स्थायी कमीशनो के वार्षिक रिक्त स्थानों में अन्य पदधारियों का अभ्यस्त और बढ़ाकर ४२ प्रतिशत कर दिया गया। १९५३ में चलनेवाले विरोधमूची-कमीशन शुरू किये गये, जो मुख्यतः उन कनिष्ठ कमीशन अधिकारियों और गैर-कमीशन अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग करने के लिए है, जो अपने-अपने व्यवसाय विरोध या कोटि में विशेषीकृत ज्ञान अर्जित कर चुके हैं। विरोध सूची में पदोन्नति के लिए उम्मीदवार ४२ साल से कम आयु के और कम से कम मैट्रिक पास होने चाहिये। १५ जनवरी, १९६४ को ८४१ विरोध सूची अधिकारी ऐसे थे, जो कनिष्ठ कमीशन अधिकारियों में से और गैर-कमीशन अधिकारियों में से पदोन्नति देकर लिये गये थे। पदोन्नति के लिए ज्यादा अवसर प्रदान करने के लिए विरोध सूची-सदस्यों की संख्या बढ़ाकर १५०० कर दी गयी।

अन्य पदधारियों के प्रशिक्षण की बढ़ी हुई जरूरतें पूरी करने के लिए, १५ नये प्रशिक्षण-केन्द्र स्थापित किये गये और निम्नलिखित प्रशिक्षण-केन्द्रों को स्थानांतरित किया गया। प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम को ज्यादा सघन बनाकर और प्रति सप्ताह प्रशिक्षण के घण्टियह बढ़ाकर, प्रशिक्षण की अवधि कम कर दी गयी। इस तरह प्रशिक्षण-धमता छोटे तौर पर बढ़ाकर पैदा संता के लिए १७०० में ४०,००० कर दी गयी, तोपखाने के लिए ५५०० में १८,०००, इन्जीनियर्स के लिए ३६०० में ३०,००० और सिगनल्स के लिए २३०० से १२,०००।

यथासमय ज्यादा संख्या में प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध हो जाने में विभिन्न तादात्म्य-कोरों के रणमण्डों के लिए आगत पान में पूर्व की पूरी प्रशिक्षण-अनुमूची क्रमशः फिर लागू कर दी गयी।

'बूली' (वस्तर-धुई सीमा) सैन्या में जनवरी-नवम्बर, १९६२ में हुई पराक्रम के बीच-प्रशिक्षण के प्रकाश में सैनिकों को दिने जाने वाले प्रशिक्षण को एक नयी दिशा दी गयी और पहाड़ी क्षेत्रों और उच्च घाटियों पर लड़ाई को और सात ध्यान दिया गया। उच्च घाटियों मुद्र-रिक्त-वन की, जो मार्च, १९६२ में स्थापित किया गया, समता काही बना दी गयी।

### खण्ड ३ . सेना के रूप का पुनर्गठन

पुनर्गठन सैनिक के अनुसार सेना में निरुक्ति पाकर अधिकारी काही बड़ी आहु तक आरम्भित (रिक्त) में रहते थे, जेहा कि नीचे बताया गया है :

आहवा	किम आहु तक आरम्भित में रहे जाते हैं	
	आर्म्ड-कोर, आर्म्ड-होन्डिपर्स विलम्ब और पैरल सेना।	जन्म सेवाएँ
मेजर और उनके नीचे	५३ साल	५५ साल
सेन्ट्रल कर्नल	५५ साल	५७ साल
कर्नल और सिग्नल	५७ साल	५९ साल
मेजर जनरल और ऊपर	सभी शाखाएँ	६० साल

सन्मन्त्र, जब आरम्भित जाने कुल लिने जाते थे, तो कडिन स्थितियों में कुछ करने के लिए कुछ भी प्रभावों जनसाधन न रहता था।

पहले एक अवधान का ऐल-मेंग (कनर सन्निध) के लिए नानाविध शाखा का व्यवहार के अनुसार ७ में १५ साल तक के लिए नानाकन किया जाता था और उसके अवधि जाने भी ५ से १० साल तक के लिए बढ़ानी या सकतो थी। व्यवहार में बुकि सेना को एक के बाद एक शाखा का सन्निध करना पड़ा, इसलिए नानाकन की अवधि सन्निध आरम्भित बानी अवधि तक बढ़ानी पड़ी, फलतः आगत में सेना का विस्तार करने के लिए कोई प्रभावों जन-साधन न रहता था। सेना में अनेक व्यक्ति काफी कुछ थे। अब सेना की काही कडिन स्थितियों पर, सातकर लंबे घाटियों पर, सन्निधाल होना पड़ता है। इसलिए इनमें नानाकन: कुल और आरम्भित दृष्टि में बहुत सौम्य व्यक्ति ही होने चाहिये। साथ ही आगत के सन्निध सेना के कुल विस्तार के लिए अनेकसा रन आहु के सन्निध में प्रशिक्षित जनसाधन का एक सन्निध व्यवस्था होना चाहिये। इन सन्निधों की कडिन के लिए, २५ जनवरी, १९६१ में, नये ऐल-मेंग के सन्निध होने की शर्तें बतायी गयीं। नयी दृष्टि के अनुसार एक पैर-वक्तोको सन्निध १० साल तक सन्निध में ऐल-मेंग और उसके बाद ५ साल तक का ३० साल की आहु तक, जो भी पड़े हो, वह आरम्भित में रहेगा और इन तरह सेना की कुल दारिजा १५ साल ही होते।

छवनीकी रंगमंच का रंग-मेवाकान १२ सात और आरंभित-दायिता ३ सात या ४३ साल को जानु तक होंगी, जो भी पढ़ते हो । (यहाँ पर भी कुछ दायिता १५ सात हो ह) । बहुत ज्यादा छवनीकी समूह में रंगमेवा १५ सात होंगी, जिसके बाद ३ सात की आरंभित-दायिता होंगी या ४३ सात की जानु तक, जो भी पढ़ते हो । इन तरह कुछ दायिता १८ साल होंगी । रंग-मेवा के अन्त में उसे कोई अवधि-विस्तार न मिलेगा, बल्कि उसका आरंभित में स्थानान्तरण कर दिया जायेगा और केवल आगत के समय ही उसे कुलावा या सकेगा । घुनह-वार (छवनीकी) के अथ पदधारियों की मेवाकानता की अवधि १८ सात या ८३ सात की जानु तक, जो भी पढ़ते हो, रखी गयी है । मारी ही अवधि रंग-मेवा होंगी और आरंभित की दायिता कुछ भी न होंगी । नदी रंग-मेवा और दायिता-अवधियाँ यह आरम्भ करेगी कि किसी भी समय मेवा में युद्ध करने वाला कोई भी व्यक्ति ८३ साल से ज्यादा आयु का न होगा ।

अन्य पदधारियों के नामाङ्कन की आयु-सीमाओं भी सुगोपित कर दी गयी है । सुगोपित आयु-सीमाएँ हैं १७ से २१, १७ से २४ और १७ से २७ साल, जो उस व्यवस्था पर निर्भर रहती हैं, जिसमें उस व्यक्ति को मारी किया जा रहा है ।

ऐसी ही योजना अधिकारियों के लिए भी बनायी गयी थी । आगत के शुरू होने से लगभग ६००० अधिकारियों को आगत-प्रवर्ग के लिए कमीशन दिये गये थे और उसके बाद छवनी अवधि के लिए, जिसकी अवधि ५००० से १६६५ में आगत कमीशन प्रदान करता बन्द कर देने का निर्णय किया गया और उसकी जगह पर गैर-छवनीकी नामाङ्कन में अधिक मेवा कमीशन दिये गये । इसलिए अधिकारियों की माँगी नरती म्यादी कमीशन (भारतीय मेवा-अकादमी, राष्ट्रीय रक्षा-अकादमी, मेवाकान कानून के अतिरिक्त राष्ट्रीय मेवाकान-वदन की अधिकारों प्रशिक्षण युक्तियों के मेवाकानों का और छवनीकी म्यादकों की, जिसमें विपरीत-प्रवर्ग-योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले अधिकार हैं) के अतिरिक्त अधिकारों प्रशिक्षण स्कूल, मद्रास के अतिरिक्त मेवा कमीशन (गैर-छवनीकी) देकर भी जायेगा । अधिक मेवा कमीशन (गैर-छवनीकी) वाले अधिकारों ५ सात की अवधि तक जान करेगा, जिसके अन्त में अन्त किया जायेगा और जो अधिकारों इच्छुक और उपयुक्त है, उनके एक हिस्से को रखी कमीशन दिये जायेंगे । गैर अधिकारियों का स्थानान्तरण आरंभित में कर दिया जायेगा, जहाँ वे १० साल की अवधि तक रहेंगे या ८० सात की जानु तक, जो भी पढ़ते हो । इन अधिकारों मेवा कमीशनों के सम्पादनकारों की छानबीन पढ़ते एक आरम्भित साजान्कार-बोर्ड द्वारा की जायेंगे और फिर चुने गये सम्पादनकारों का साजान्कार मेवा-वदन-बोर्ड करता है । इन सम्पादनकारों का पढ़ता प्रशिक्षण-साजान्कार अन्त, १६६६ में पूरा हुआ । १६७१ में जाने से अधिक मेवा कमीशन वाले अधिकारों, दिन का मेवाकान मेवा में ५ सात था (और जिसको म्यादी कमीशन नहीं दिया गया) मेवाकान (रितीत) कर दिये जायेंगे और ऊपर बताया गये अवधि तक आरंभित में रहेंगे । यह निर्णय किया गया है कि इन अधिकारियों के लिए अन्तिम मेवाकानों में रिक्त स्थानों का एक प्रतिशत हर सात आरंभित रखा जाय ।

यह भी हम बिना गवा कि स्वामी कमीशन वाले अधिकारियों को छवनी अवधि तक ही आरंभित में रखा जायेगा, जिसकी उनकी अधिकारों मेवा-वदन-बोर्ड की आयु उस बोर्ड में है,

जिससे वे सेवानिवृत्त हो रहे हैं, अगर वे उस ओहदे की पदावधि पूरा करने से पहले सेवानिवृत्त हो जायें, अन्यथा आरक्षित की कोई दायिता न होगी। इस तरह इन अधिकारियों की आरक्षित-दायिता प्रत्येक ओहदे के आगे नीचे दी गयी आयु तक ही है।

लेफ्टी० कर्नल और नीचे	४८ साल	मेजर जनरल	५४ साल
कर्नल	५० साल	लेफ्टी० जनरल	५६ साल
ब्रिगेडियर	५२ साल	जनरल	५८ साल

एक बार इस योजना के प्रभावों रूप में लागू हो जाने के बाद, देश के पास प्रशिक्षित और तरुण जनसाधन आरक्षण भी हो जायेंगे, जिनमें से सेना के किसी भी आपातकालीन विस्तार के लिए व्यक्ति लिए जा सकेंगे।

### खण्ड ४ - प्रशिक्षण

सरकार की नीति रही है कि यथासम्भव अधिकतम मात्रा तक प्रशिक्षण देश में ही दिया जाय। आजादी के बाद से भारत में स्थापित की गयी प्रशिक्षण-सुविधाओं का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है।—

सेना में प्रशिक्षण—सेना के प्रशिक्षण-संस्थानों में बंटेरा स्थित स्टाफ कालेज में अलावा अविभाजित भारतीय सेना की नीचे लिखी स्थापनायें भारत के पास न रही। सेना वायु-परिवहन-समयन स्कूल, चक्राला, पैरा-ट्रुप्स प्रशिक्षण स्कूल, चक्राला, विमानभेदी टोपखाना स्कूल, कराची, भार० आई० ए० एल० भी० स्कूल, काफ़ुन, आसूचना प्रशिक्षण स्कूल, कराची, भार० आई० ए० एल० सी० प्रशिक्षण केन्द्र (पूर्ति) साहौर, सामान्य भण्डार और वस्त्र प्रशिक्षण सैल, साहौर, वाहनचालन और सन्धारण विशेषतः प्रशिक्षण सैल, कराची। इस अभाव की पूर्ति करने के लिए सबादी प्रशिक्षण स्थापनायें भारत में बनायी गयी हैं। इनके अलावा बैंड मास्टर्स को प्रशिक्षण देने के लिए एक सैन्य संगीत स्कूल और घोड़े-खच्चरों और ऐसे दूसरे पशुओं को प्रशिक्षण देने के लिए एक सवारी-शु (रिमावेंट) क्लो भी स्थापित किये गये हैं।

पहले ऐसा कोई स्कूल न था, जहाँ बैंड मास्टर और बैंड के दूसरे आदमियों को प्रशिक्षण दिया जा सके। इन व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के अलावा नया सैन्य संगीत स्कूल, सेना के बैंडों में, निरन्तर पदोन्नति पुनो के स्थान पर भारतीय पुनो के समावेश का भी प्रयास करना आ रहा है।

साथ ही विमानन के समय भारत में कुछ विशेषज्ञ-पाठ्यक्रमों के लिए सुविधायें न थी, जैसे सिगनल, ट्रांसमिटर, अग्रिम आसूचना-प्रशिक्षण आदि। ऐसे प्रशिक्षण के लिए बुने हुए लोगों की यू० के० योजना पड़ती थी। जगस्त, १९४० से ये पाठ्यक्रम भारत में शुरू करने के लिए, और इस तरह विदेश भेजने की जरूरत खत्म करने के लिए प्रयास किया गया।

इस समय जो प्रशिक्षण स्थापनायें विद्यमान हैं और जो नये पाठ्यक्रम शुरू कर दिये गये हैं, उनके कारण भारत अब बहुत बड़ी सीमा तक सेना की प्रशिक्षण-सुविधाओं के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। लेकिन प्रशिक्षण के नवीनतम तरीकों और कूटचाल और तकनीकी

विकास में परिचित रखने के लिए हर साल सेना के कुछ व्यक्तियों को अन्य प्रगतिशील देशों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। कुछ चुने हुए अधिकारियों को स्टाफ कालेज-माध्यमों में सामान्य उच्चस्तरीय प्रशिक्षण देने के लिए विदेश भेजा जाता है, ताकि आधुनिक युद्धप्रणाली के सामान्य पहलुओं के बारे में विदेशों में जो सिखाया जाता है, उसका परिचय उनको कराया जा सके।

अविभाजित भारत में जो प्रशिक्षण स्थापनाएँ विद्यमान थी, उनमें रङ्की में १९४३ में शुरू किये गये सैन्य इंजीनियरी स्कूल का भी उल्लेख करना जरूरी है। अक्टूबर, १९४७ में यह स्कूल करंजी से जाया गया और १९४९ में इसका नाम बदल कर सैन्य इंजीनियरी कालेज, करंजी कर दिया गया। इस कॉलेज में इंजीनियर कोर, सिग्नल्स कोर और बिजली तथा यांत्रिक इंजीनियरी कोर के अधिकारियों के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाये जाते हैं, इसमें शिक्षकों (अधिकारी और अन्य पदधारियों) और विशेषज्ञों को इंजीनियर-कोर तथा सेना इंजीनियरी सेवाओं के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाता है। यह इंजीनियरी तरीकों और उपकरणों के सम्बन्ध में अध्ययन, अनुसन्धान और पढताल का काम भी करता है।

### मेनाछान (आर्मी कैंडेट) कालेज

अन्य होनहार पदधारियों की कमीशन वाले ओहदों में जाने के लिए प्रशिक्षण देने के लिए नौगांव, (म० प्र०) में सेनाछान कॉलेज, मई, १९६० में शुरू किया गया। (यह किचनर कॉलेज की छेती पर था, जो वहाँ बिगन निस्वयुद्ध के पहले और दौरान की अधिकांश अवधि तक काम करता रहा था)। मार्च, १९६४ में इस संस्था को पूना ले जाया गया। यह कॉलेज शिक्षित युवक सैनिकों को उच्चपदों पर जाने के लिए प्रेरित करता है, ताकि वे कमीशन सेवे का अवसर प्राप्त कर सकें। यह उन उम्मीदवारों की अतिरिक्त अवसर प्रदान करता है, जो सामान्य स्पर्धा या राष्ट्रीय सेनाछान-दल के जरिए राष्ट्रीय रक्षा-अकादमी और भारतीय सैन्य-अकादमी में प्रवेश नहीं ले पाते। ध्यान में आने के लिए वह अन्य पदधारी १९३ और २४ की आयु-सीमा में होना चाहिये, वह मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा या भारतीय सेना प्रथम बला प्रमाण-पत्र में उत्तीर्ण हो और वह सेना में दो साल काम कर चुका हो। सेना छान कॉलेज में पाठ्यक्रम की अवधि मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण लोगों के लिए १८ महीने है और भारतीय सेना प्रथम ध्येयी प्रमाणपत्र वालों के लिए २४ महीने। कॉलेज की समता शुरू में ६० सेनाछान थी, जो अब बढ़ाकर ४८० कर दी गयी है। कॉलेज में पाठ्यक्रम पूरा करने सेनाछान १३ साल के पूर्व-वर्गीय प्रशिक्षण के लिए भारतीय सैन्य अकादमी में प्रवेश लेते हैं।

सेना की प्रमुख प्रशिक्षण स्थापनाएँ ये हैं :

भारतीय सैन्य-अकादमी  
आर्मेड-फोर्स-वेन्ड और स्कूल  
सोरोसाना स्कूल  
सैन्य प्रशिक्षण केंद्र

देहपट्टन  
अहमदनगर  
देवगाली  
बरकी, पूना

सिगनल्स स्कूल	मडू
आसूचना-प्रशिक्षण स्कूल और डिपो	पूना
सेना स्वास्थ्य स्कूल	लखनऊ
सेना सेवा-कोर स्कूल	धरली
बिजली और यान्त्रिक इंजीनियरी-कोर स्कूल	सिकन्दराबाद
सैन्य पुलिस-कोर का केन्द्र और स्कूल	फैजाबाद
आरोही पशुचिकित्सा कोर स्कूल	मेरठ छावनी
आरोही पशु-प्रशिक्षण स्कूल और डिपो	सहारनपुर
अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल	मद्रास
पैदल सेना स्कूल	मडू
उच्च घरातल-युद्ध स्कूल	शुलमर्ग
सेनाशिक्षा कोर प्रशिक्षण कॉलेज और केन्द्र	पद्मढी
सेनाद्वारा कॉलेज	पूना
सैन्य यान्त्रिक-परिवहन स्कूल	फैजाबाद
सेना वायु-परिवहन-समर्पण स्कूल	आगरा
सेना धारोरिक प्रशिक्षण स्कूल	पूना

### नौसेना में प्रशिक्षण

अविभाजित भारत में मुख्य नौसेना प्रशिक्षण स्कूल कराची में थे। भारत में प्रमुख प्रशिक्षण केन्द्र ये थे : भारतीय नौसेना पोत शिवाजी (नौसेना के लिए इंजीनियरी अधिकारियों और आर्टिफिशर के प्रशिक्षण की यान्त्रिक प्रशिक्षण स्थापना), लोनावला, (बम्बई के पास), और भा० नौ० पो० बालमुरा, जामनगर में विद्युत स्कूल। विभाजन के बाद, पहले कुछ वर्षों में भारत में प्रशिक्षण सुविधाओं के अभाव के कारण, बहुत से अधिकारियों और सैनिकों को प्रशिक्षण के लिए यू० के० भेजना होता था। नियमित अधिकारियों के प्रसंग में इसके लिए आभार प्रदर्शन किया जाना चाहिये कि दिसम्बर, १९४७ में यू० के० एडमिरलटी ने अगले तीन साल तक के लिए हर साल ४६ भारतीय सेनाध्वजों की प्रशिक्षण के लिए लेना मंजूर कर लिया, जबकि पहले हर साल केवल १६ ही लिए जाते थे।

विभाजन के कारण स्कूल चले जाने से भारत को विवश होकर अपने नये स्कूल खोलने पड़े और ये विद्यालयपटनम् और कोचीन में खोले गये। नौवालन, पुर्त और सचिवालय, गनरी, सिगनल्स तथा टारपीडो और एंटी-सबमरीन (टास) स्कूल, कोचीन, (भा० नौ० पो० बेंदुरपी) में, अस्थायी भवनों में, १९४८ में काम करने लगे। नौवालन, गनरी और टास स्कूलों के स्थायी भवनों की आधारशिला रक्षा-मन्त्री ने फरवरी, १९५० में रखी और वे सभी पूरे बन चुके हैं। अब कोचीन, भारतीय नौसेना का, सबसे बड़ा प्रशिक्षण केन्द्र है और नौसेना के प्रमुख विशेषज्ञ स्कूल वहाँ पर हैं। इसी तरह १९४८ में व्यायस प्रशिक्षण-स्थापना (भा० नौ० पो० सरवार), विद्यालयपटनम् में शुरू की गयी। अविकसित नाविक भा० नौ० पो० सरकार में १९५३

और १६३ साल की आयु के बीच प्रवेश लेते हैं, जहाँ उनको नौसेना की सभी शाखाओं में ४४ हफ्ते का एक समान पाठ्यक्रम पूरा कराया जाता है और इस तरह नये बच्चे प्रशिक्षित नाविक बना दिये जाते हैं और उनको आरम्भिक नौबाहकता, नौ-सिगनल्स और मशीन का ज्ञान हो जाता है और कुछ सामान्य शिक्षा भी मिल जाती है। फिर उनको 'कार्मिक-चयन' परीक्षण में बैठाया जाता है, और इसके परिणाम, तथा बच्चों की बुनियादी शिक्षा के आधार पर, उनको विभिन्न शाखाओं में भेज दिया जाता है—नौबाहक, सञ्चार, विद्युत, इञ्जीनियरी, यान्त्रिक और नौ-उड्डयन। फिर उनको थ्योरेटिक प्रशिक्षण मिलता है। नौसेना के विजली इञ्जीनियर, आर्टि-फिशर और विजली-कम्बेनारियो को जामनगर में भा० नौ० पो० बालपुरा में प्रशिक्षण दिया जाता है। समुद्री इञ्जीनियरी पाठ्यक्रम सोनावला में भा० नौ० पो० शिवाजी में चलाये जाते हैं।

भारत में नौसेना प्रशिक्षण सुविधाओं में विस्तार की दिशा में एक बड़ा काम सौराष्ट्र के राजप्रमुख द्वारा २७ अप्रैल, १९५५ को जामनगर में नौसेना के नये विद्युत स्कूल भा० नौ० पो० बालपुरा का उद्घाटन था। इस नये स्कूल की आधारशिला नवम्बर, १९५२ में रखी गयी थी। वास्तव में विजली स्कूल का गन्म तो १९४२ में ही हो गया था। पिछले त्रिस्वयुद्ध के आरम्भ में भारत नौसेना ने ऐसे पोत अवाप्त किये थे, जिनमें आधुनिक जटिल विजली और टारपीडो उपकरण लगाये गए थे। इसलिए वह जरूरी समझा गया कि भारतीय व्यक्तियों को ये उपकरण चलाने के लिए भारत में ही प्रशिक्षित कर लिया जाय। पिछले त्रिस्वयुद्ध के अन्त की ओर नौसेना इन्वेस्टीगेशन और रकार में तेजी से हुई प्रगति के कारण अब इसमें और देर न की जा सकती थी। इसके साथ ही टारपीडो और एंटी-सबमरीन तथा गोना छायाएँ मिला दी गयीं। इसके तुरन्त बाद ही टारपीडो प्रशिक्षण का काम जामनगर से कोचीन भेज दिया गया। अब से नौसेना का भा० नौ० पो० बालपुरा एकमात्र विद्युत स्कूल रह गया है।

अब भा० नौ० पो० बालपुरा विजली में पूरा-पूरा प्रशिक्षण अधिकारियों और जवानों दोनों को देता है—उच्च, सिद्धान्तिक और प्रायोगिक। उसने प्रशिक्षण के इस क्षेत्र में भारतीय-नौसेना को पूर्णतः आत्मनिर्भर बनने में मदद दी है।

इन प्रमुख भा० नौप्रशिक्षण-स्थापनाओं ( भा० नौ० पो० सरकार, बेन्दुरुपी, शिवाजी और बालपुरा ) और भा० नौ० पो० हामला तथा पूर्ति और सचिवालय स्कूल के अलावा कुछ और छोटे-मोटे भा० नौस्कूल बम्बई में या उसके आस-पास हैं। गोरी अप्रेंटिस स्कूल नौसेना गोडो, बम्बई में है और नौसेना के गोडो के भरती अर्थनिक सिनियरों को प्रशिक्षण देता है।

नौसेना में प्रशिक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम कोचीन में नौसेना वायुस्थान का उद्घाटन था। पहला नौ-विमान गु० के० ने फरवरी, १९५३ के शुरू में प्राप्त किया गया था और कोचीन में नौ-उड़ान कार्य मार्च में शुरू हुआ। रक्षा-संगठन-मन्त्री ने भा० नौ० पो० गरड का औपचारिक अवतरण समारोह ११ मई, १९५३ को सम्पन्न कराया।

कोलाया, बम्बई, का सेन्य अस्थायी नौसेना ने १ मिनम्बर, १९५१ को अपने हाथ

में ले लिया और १८ सितम्बर को उसका नाम भा० नौ० अस्पताल पोत-वर्धनी रखा गया ।  
अस्पताल १ अप्रैल, १९२३ में नौसेना को स्थायी रूप से हस्तान्तरित कर दिया गया ।

नौसेना में १५ अगस्त, १९२७ के बाद स्थापित प्रशिक्षण-संस्थाओं के नाम और प्रत्येक में दिये जाने वाले प्रशिक्षण का स्वरूप नीचे बताया जा रहा है —

स्थापना का नाम	स्कूल का नाम	पढ़ाये जाने वाले विषय
भा० नौ० पो, वेदुक्षि (कोचीन)	गनरी स्कूल सिगनल्स स्कूल नौ-चालन और निदेशन स्कूल टारपीडो और एंटी सबमेरीन और गोता स्कूल बुनियादी और प्रभागीय स्कूल (बी० एंड डी०)	छोपखाना और रडार-निपटण (अस्त्र) दृश्य सिगनल्स-क्रिया और नेनार-तार-प्रेषण नौ- चालन और निदेशन (रडार से स्वतन्त्र) टारपीडो और एंटी सबमेरीन, सुरंग साफ करना और लगाना, गोता लगाना । बुनियादी, सेवा का सामान्य प्रशिक्षण, विज्ञान-विषय और सामान्य शिक्षा, नाविकता और नौका-कार्य ।
भा० नौ० पो० अग्रणी (कोयम्बटूर)	पेटो अफसर स्कूल	नौतुत्व और मनोबल प्रशिक्षण
भा० नौ० पो० गहड़ (कोचीन)	नौसेना हवाई स्टेसन	नौसेना-विमान चालन और नौसेना वायु तकनीकी प्रशिक्षण ।
भा० नौ० पो० सरकार (विशालपटनम्)	व्यायज का प्रशिक्षण	शिक्षाण प्रशिक्षण, नाविकता में प्रारम्भिक प्रशिक्षण, गनरी, भस्मचार, इंजीनियरी, विद्युत, रेडियो और रडार ।
भा० नौ० पो० हुंगलि (बम्बई)	विनियामक स्कूल	विनियामन और मुरसा सम्बन्धी प्रशिक्षण
भा० नौ० पो० आग्रे (बम्बई)	पोत चिन्वी स्कूल शारीरिक शिक्षा स्कूल	पोत चिन्वी प्रशिक्षण शारीरिक शिक्षा
गोदी अग्रेंटिस स्कूल (बम्बई)	गोदी अग्रेंटिस स्कूल	गोदी अग्रेंटिस प्रशिक्षण
भा० नौ० पो० हमला (बम्बई)	पूति और सचिवालय स्कूल	स्टोवार्ड, रसोइया, लिपिक और भण्डार- सहायकों का प्रशिक्षण
भा० नौ० पो० बालगुरा (जामनगर)	विद्युत स्कूल	विजली और रडार-प्रशिक्षण
भा० नौ० अस्पताल- पोत वर्धनी (बम्बई)	आयुर्विज्ञान प्रशिक्षण-केन्द्र	रुग्ण-शय्या-परिचरों के लिए आयुर्विज्ञान के विषय ।



इन समस्याओं का समाधान के बाद एग्जीक्यूटिव और प्रूति और सचिवालय शाखाओं के सेनाध्यक्षों का प्रशिक्षण भारत में अगस्त, १९५२ से शुरू हो गया। अगस्त, १९५२ के बाद तब तक इजीनियरी और विजली शाखाओं के सेनाध्यक्षों को प्रशिक्षण के लिए यू० के० भेजा जाता रहा, जब तक कि भारत में आवश्यक सुविधायें उपलब्ध न हो जायें। विजली प्रशिक्षण के लिए सेनाध्यक्षों की आखिरी टुकड़ी यू० के० को सितम्बर, १९५१ में भेजी गयी और इजीनियरी सेनाध्यक्षों की आखिरी टुकड़ी जनवरी, १९५५ में।

इतिहास में पहली बार भारतीय नौसेना ने धीलका की नौसेना के छ मीडियममैनो को जनवरी, १९५४ में आठ महीने के समुद्री प्रशिक्षण के लिए स्वीकार किया। यह भारत नौ-शिक्षण में हुई प्रगति का प्रतीक था। बाद में भारतीय नौसेना ने रॉयल ईथोपियन नौसेना, रॉयल मलेशियाई नौसेना, इंडोनेशिया और नाइजीरिया की नौसेना के नौसैनिक अधिकारियों और नाविकों को भी प्रशिक्षण दिया। इराकी सरकार के कुछ असेनिकों को भी भारतीय नौसेना ने प्रशिक्षित किया।

कुछ विशेषीकृत और उच्च स्तरों की छोड़कर अब नौसेना के लिए अपेक्षित प्राय सभी प्रकार का प्रशिक्षण भारत में ही देना सम्भव हो गया है।

### वायुसेना में प्रशिक्षण

१५ अगस्त, १९४७ को भारत स्थित वायुसेना प्रशिक्षण-स्थापनायें ये थी प्रारम्भिक उड़ान प्रशिक्षण स्कूल, जोधपुर और उच्च उड़ान प्रशिक्षण स्कूल, अम्बाला, आरम्भिक प्रशिक्षण-स्कन्ध, कोयम्बटूर, सख्या १ घरातल प्रशिक्षण केन्द्र जल्लाहन्ती, बंगलौर, और सख्या २ घरातल प्रशिक्षण स्कूल, ताम्बरम्। उड़ान प्रशिक्षण स्कूल अम्बाला में फरवरी, १९४८ में स्थापित किया गया।

उस समय चल रही पद्धति के अधोल पाइलटों को तीन विभिन्न सत्याओं में तीन प्रक्रमों में प्रशिक्षण दिया जाता था। इसी तरह घरातल-कर्तव्य वाले अधिकारियों का प्रशिक्षण भी बिछरा हुआ था। तकनीकी और गैर-तकनीकी अधिकारियों को आरम्भिक प्रशिक्षण कोयम्बटूर में दिया जाता था। तकनीकी अधिकारियों की व्यावसायिक प्रशिक्षण सख्या २, घरातल प्रशिक्षण स्कूल में चलता रहा।

एयरमैनो को आरम्भिक प्रशिक्षण वायुसेना रंगस्ट डिपो, जल्लाहन्ती में दिया जाता था, जहाँ केवल सामान्य-मेवा-प्रशिक्षण ही दिया जाता था। फिर तकनीकी ट्रेडों वाले एयरमैनो को २ घरा० प्र० स्कूल, ताम्बरम् को भेज दिया जाता था और गैर-तकनीकी ट्रेडों वाले को १ घरा० प्र० स्कूल, जल्लाहन्ती।

अधिकारियों को पूर्वोक्त त्रिवर्ती प्रशिक्षण-पद्धति का पुनर्गठन अगस्त, १९४९ में सर्व-गामी-प्रशिक्षण योजना के अनुसार किया गया। पाइलटों का प्रशिक्षण केन्द्रोहन कर दिया गया। अब वह प्रशिक्षण काल में अपने विषयों के साथ रह सकता था और उनकी प्रगति का निर्धारण कर सकता था। फलतः उच्च उड़ान प्रशिक्षण स्कूल, अम्बाला का नया नाम मंत्र्या १ वायुसेना-अकादेमी कर दिया गया। प्रशिक्षण स्कूल का नाम संख्या २ वायुसेना-अकादेमी

रखा गया। आरम्भिक प्रशिक्षण-कक्ष, कोयम्बटूर, का नाम संख्या ३ वायुसेना-अकादेमी रखा गया। बुनियादी प्रश्न और उच्च प्रश्न का प्रशिक्षण पाइलटों को संख्या १ वायुसेना-अकादेमी, भन्वावा, और संख्या २ वायुसेना-अकादेमी, जोधपुर, दोनों ही जगह दिया जाता था। कमीशनरों का और विंग का प्रश्न, प्रशिक्षण के उच्च प्रश्न को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद ही किया जाता था। घरातन-कतंत्र (बैर-तकनीकी) अधिकारियों को प्रशिक्षण (अर्थात् प्रशासनिक, उपकरण, लेखा और शिक्षा शाखाओं वालों का) संख्या ३ वायुसेना-अकादेमी, कोयम्बटूर, में दिया जाता था। तकनीकी अधिकारियों का प्रशिक्षण जवाहर्ली में जुलाई, १९४६ में शुरू किये गये नये तकनीकी प्रशिक्षण कानेज में स्वतन्त्रित कर दिया गया।

पहले भारतीय वायुसेना के अधिकारियों के तकनीकी प्रशिक्षण के लिए बने, में कोई समुक्त समस्या न थी। अस्थायी तौर पर अन्य पदधारियों में से कमीशन पाने वाले अधिकारियों को प्रशिक्षण संख्या २, घरातन-प्रशिक्षण स्कूल, ताम्बरम् में दिया जाता था; जबकि नये प्रवेश पाये हुए लोग तकनीकी प्रशिक्षण के लिए दू० के० को भेज दिये जाते थे। वायुसेना में तकनीकी अधिकारियों की भारी कमी थी। इसलिए भारत में एक तकनीकी प्रशिक्षण कानेज की स्थापना अविनम्बनीय रूप में जरूरी हो गयी थी।

भारत सरकार ने वायुसेना प्रशिक्षण लिमिटेड, ह्याम्बने में एक करार किया कि जवाहर्ली में एक तकनीकी प्रशिक्षण कानेज स्थापित और सञ्चालित करे, जो आरम्भ में ४ जुलाई, १९४६ में पाँच सालों के लिए बनाया जाय। इस कानेज में सीधे प्रवेश पाने वाले तकनीकी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था, और एयरोनॉटिकल, विद्युत, सिगनल और सक्काब शाखाओं में कमीशन पाने वाले अन्य पदधारियों को।

इस कानेज के ब्रिटिश शिक्षक कर्मचारियों के स्थान पर, बीरे-बीरे भारतीय अधिकारी लगाये गये। ४ जुलाई, १९४६ को एक भारतीय ने कानेज के कमिडेंट का पद संभाल लिया। कानेज को १०० अधिकारी मेनाज्जनों और १०० अटेंडिंजों को प्रशिक्षण देने के लिए बनाया गया है।

दोनों घरातन-प्रशिक्षण स्कूलों में सर्वोच्च प्रशिक्षण के आधार पर, एयरमैनो के घरातन-प्रशिक्षण को भी पुनर्गठित किया गया। इन योजना के अन्तर्गत रंगस्टों को सामान्य-सेवा-प्रशिक्षण और ट्रेड-प्रशिक्षण स्कोल में दिया जाता था। संख्या २ घरातल-प्रशिक्षण स्कूल, ताम्बरम्, एयरमैनो के एयरमैन, इडिन, सम्बद्ध इंजीनियरी और फोटो-ट्रेडों में ही प्रशिक्षण के लिए बिम्बेवार रहा। एयरमैनो के सिगनल, इडार, विद्युत-मन्त्र और सक्काब तथा वायुसेना-मुरभा म्दिया में प्रशिक्षण कार्य को संख्या २ घरातल-प्रशिक्षण स्कूल से नरस्या-पित संख्या ३ घरातल-प्रशिक्षण स्कूल, जवाहर्ली, में ३१ अक्टूबर, १९४६ से ले जाया गया। संख्या १ घरातल-प्रशिक्षण स्कूल, जवाहर्ली, ने नयी सञ्चालनी योजना जून, १९४६ में अपना ली और वह गैर-तकनीकी ट्रेडों के एयरमैनो को ही प्रशिक्षण देने लगा।

अविनामित भारत का पैराट्रूपरों का प्रशिक्षण स्कूल चक्काला (अब पाकिस्तान में) में स्थित था। भारत में आवाजे के बाद पैराट्रूपरों का प्रशिक्षण शुरू में आपरा में चारू किया गया, जहाँ १ फरवरी, १९२० ने पैराट्रूपर प्रशिक्षण स्कूल स्थापित किया गया। जामनगर में

सामान्य प्रशिक्षण शाखा अप्रैल, १९५१ में नमगार हवाईबाजों को नियमित सक्रियतागत प्रशिक्षण देने लिए शुरू किया गया। अगस्त, १९५१ में सख्या १ वायुसेना-अकादेमी और विपरिवर्तन-प्रशिक्षण पूरित अम्बाला से बेगमपेट ले जायी गयी। अम्बाला का उड़ान प्रशिक्षक स्कूल नवम्बर, १९५३ में ठाम्बरम् में ले जाया गया।

तीनों वायुसेना अकादेमियों के नाम १ अगस्त, १९५५ में वायुसेना कॉलेज कर दिये गये। जेट विमान सम्बन्धी प्रशिक्षण की बढ़ती हुई माँग को देखते हुए, सर्वगामी प्रशिक्षण योजना आगे न चल सकी। १९५७ में योजना में संशोधन किया गया, ताकि जेट-प्रशिक्षण काफी आरम्भिक प्रक्रम में शुरू किया जा सके। पाइलट और नेविगेटर के लिए अब बुनियादी और मध्यम वायुसेना उड़ान कॉलेज जोधपुर में, उच्च स्तरीय प्रक्रम में वायुसेना स्टेशन, हैदराबाद में, उच्च और अनुपयुक्त जेट प्रशिक्षण, जेट-प्रशिक्षण-शाखा, हाकिमपेट में, और परिवहन विमानों के पाइलटों और नेविगेटरों का उच्चस्तरीय प्रशिक्षण, परिवहन-प्रशिक्षण स्कूल, बेगमपेट में दिया जाने लगा। मई १९५७ में इस संशोधित उड़ान-प्रशिक्षण नीति के अनुसार कोयम्बटूर के वायुसेना कॉलेज का नाम वायुसेना-प्रशासनिक-कॉलेज कर दिया गया।

अप्रैल, १९६२ में एक सम्भारिकी-समर्पक-प्रशिक्षण कालेज, इलाहाबाद में हेनिकॉन्टरो में उच्चस्तरीय प्रशिक्षण देने के लिए खोला गया और वही पर एक पाइलट-प्रशिक्षण-स्थापना अगस्त, १९६२ में पाइलटों के प्रशिक्षण के बुनियादी और मध्यम प्रक्रमों के प्रशिक्षण के लिए बनायी गयी। ठाम्बरम् का उड़ान शिक्षक स्कूल, उड़ान शिक्षकों को प्रशिक्षण देता रहा।

१९६० में धरातल-प्रशिक्षण के क्रियाकलाप में और विस्तार किया गया। कानपुर में सख्या ४ धरातल-प्रशिक्षण स्कूल बनाया गया, ताकि नये बनने वाले यूनिटों के लिए एयरमैन को बड़ी हुई जरूरतें पूरी की जा सकें। जून, १९६२ में धरातल-प्रशिक्षण स्कूल ट्रेड के आधार पर पुनर्गठित किये गये। बिजली और यन्त्रों के ट्रेड वालों का जो प्रशिक्षण अब तक सख्या २ घ० प्र० स्कू० ठाम्बरम् में चल रहा था, उसे सख्या ५ घ० प्र० स्कू० जलाहन्ती में ले जाया गया, जिसकी स्थापना १ जुलाई, १९६२ को की गयी। इसी तरह रडार ट्रेड वालों का प्रशिक्षण, सख्या ३—घ० प्र० स्कूल, जलाहन्ती के जनवरी, १९६३ में बनने पर, वहाँ ले आया गया। मोटर परिवहन (एम टी) चालकों, भारतीय वायुसेना पुलिस और सशस्त्रबलों का प्रशिक्षण भी १९६३ में इस स्कूल को सौंप दिया गया, जब सख्या १ घ० प्र० स्कू० जलाहन्ती में साम्बरे (बेलगाम) में ले जाया गया।

नवम्बर, १९६२ के बाद वायु-जू का प्रशिक्षण, बढ़ती हुई माँग की पूर्ति के लिए, बढ़ा दिया गया। पाइलटों की अधिकतम संख्या में बढ़ाने के लिए किये गये पूरे-पूरे प्रयास के फलस्वरूप मद्रास, दिल्ली, कानपुर, नागपुर और पटियाला के उड़ान-क्लबों को पाइलटों के प्रशिक्षण का काम सौंप गया। आपात प्रशिक्षण आयोजना के अधीन, जो जनवरी १९६३ में शुरू की गयी, पाइलटों का सामान्य-सेवा-प्रशिक्षण कोयम्बटूर के वायुसेना प्रशासनिक कॉलेज में बनाये गये आरम्भिक प्रशिक्षण-स्कूल में केन्द्रित कर दिया गया। मोटर में एक अतिरिक्त जेट-प्रशिक्षण-स्कूल बनाया गया और येल्तहवा में परिवहन विमानों में उच्च प्रशिक्षण के लिए बनाये गये अतिरिक्त परिवहन-प्रशिक्षण-स्कूल को सौंप दिया।

आपात प्रशिक्षण योजना के अधीन उड़ान-प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम को अवधि घटाकर एक साल कर दो गयी और प्रवेश और बारबारिता बढ़ा दी गयी। प्रशिक्षण तीन को जगह पाँच प्रक्रमों में दिया जाने लगा, नामान आरम्भिक प्रशिक्षण, प्रारम्भिक उड़ान-प्रशिक्षण, बुनियादी, मध्यम और उच्च। अनुपयुक्त प्रक्रम वाला प्रशिक्षण बन्द कर दिया गया।

वायुसेना तकनीकी कॉलेज में प्रशिक्षण अधिकारियों के पाठ्यक्रम की अवधि कम कर दी गयी ताकि ज्यादा लोग प्रशिक्षित किये जा सकें। अप्रेंटिसों का प्रशिक्षण बन्द कर दिया गया, ताकि ज्यादा अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा सके। वायुसेना प्रशामनिक कॉलेज, कोयम्बटूर में गैर-तकनीकी छात्राओं में प्रशिक्षित होने वाले अधिकारियों को सख्या, प्रशिक्षण-अवधि एक साल से घटाकर छ महीने करते हुए, दूनी कर दी गयी।

अधिकांश एयरमैन ट्रेडों की प्रशिक्षण अवधि कम कर दी गयी, ताकि बराउल-प्रशिक्षण स्कूल में निकलने वालों की सख्या बढ जाय।

आगत प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राय २७ महीनो तक चलता रहा। जनवरी, १९६४ से आपात उड़ान-प्रशिक्षण में संशोधन किया गया और उसे एक साल से उढाकर ६८ हफ्ते कर दिया गया।

१९६७ के मध्य तक मंजूर सबर्गों के प्रत्यासित प्रशिक्षण की दृष्टि में, आपात प्रशिक्षण आयोजना में, फिर सुधार किया गया, ताकि सामान्य स्वर्ग व्यर्थताओं की ही प्रशिक्षण-जरूरतों के लिए व्यवस्था की जा सके। अब उड़ान-प्रशिक्षण के तीन प्रक्रम-छ छ महीनो के होंगे। बुनियादी, मध्यम और उच्च। कमीशन और बिग, उच्च प्रक्रम के प्रशिक्षण के बाद दिये जायेंगे। जेट-प्रशिक्षण-स्कन्ध के पाइलटों को कमीशनोत्तर प्रशिक्षण छ महीने और पूरा करना होगा। परिवहन पाइलट स्क्वेड्रनों में परिवहन विमान सम्बन्धी विहित अनुभव पूरा करने के बाद चार महीनो का कमान-विनिर्वातन-पाठ्यक्रम पूरा करेंगे।

एयरमैनो के लिए, कुछ अपवाधों को छोडकर, १९६५ में प्रशिक्षण आपात-पूर्व के संरूप में से आया गया। कुछ ट्रेडों के सम्बन्ध में वायुसेना की बडी हुई अधिकृत सख्या की प्रशिक्षण-जरूरतों की पूर्ति की जा चुकी है। अधिकांश गैर-तकनीकी ट्रेडों के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रम के १९६७ के अन्त तक पूरे हो जाने की आशा है और तकनीकी ट्रेडों के १९६८ के अन्त तक।

बडे हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्रमशः पूरे हो जाने से कुछ नयी नयी दूई सूरितें छोरे-छोरे समेट ली जायेंगी।

अब वायुसेना में प्रमुख प्रशिक्षण स्थापनायें ये हैं—

- (१) इलाहाबाद की पाइलट-प्रशिक्षण-स्थापना (जो अक्टूबर, १९६६ में बीदर ले जानी है)
- (२) वायुसेना उड़ान कॉलेज, जोधपुर (जो मार्च, १९६७ में बेगमपेट जाना है)।
- (३) जेट-प्रशिक्षण-स्कन्ध, हाकिमपेट, जेट विमानों के बारे में अनुपयुक्त और उच्च प्रशिक्षण देने के लिए।
- (४) चेन्नहंग का परिवहन प्रशिक्षण स्कन्ध, परिवहन विमानों में उच्च प्रशिक्षण देने के लिए।

(५) सम्भारिको-समर्थन-यूनिट, इलाहाबाद ।

(६) उद्धान शिक्षक स्कूल, ताम्बरम् ।

(७) वायुसेना तकनीकी कॉलेज, जलाहन्वी ।

(८) वायुसेना प्रशासनिक कॉलेज, कोयम्बरूर ।

(९) सख्या १ घरातल-प्रशिक्षण स्कूल, ताम्बरम् ।

सख्या २ घरातल-प्रशिक्षण स्कूल, ताम्बरम्

सख्या ३ घरातल-प्रशिक्षण स्कूल, जलाहन्वी

सख्या ४ घरातल-प्रशिक्षण स्कूल, वानपुर

सख्या ५ घरातल-प्रशिक्षण स्कूल, } जलाहन्वी

सख्या ६ घरातल-प्रशिक्षण स्कूल, }

(१०) जंगल और बर्त में मुरक्षित रहने सम्बन्धी स्कूल, श्रीनगर (जिसमें अधिकारियों और जवानों को जंगल और बर्त में मुरक्षित रहने की तकनीकें सिखायी जाती हैं)

प्रशिक्षण-योजना, १९६६ के मध्य में हैदराबाद में प्रस्तावित वायुसेना अकादेमी के काम शुरू कर देने पर, और भी पुनर्गठित हो जायेगी । आयोजना यह है कि यह अकादेमी एक बार में ३५० सेना छात्रों को प्रशिक्षण दे । उसकी लागत का अनुमान लगभग १२ करोड़ रुपये है । अकादेमी इनका प्रशिक्षण अपने हाथ में ले लेगी (क) पाइलट-प्रशिक्षण-स्थापना, इलाहाबाद में, और वायुसेना उद्धान कॉलेज जोधपुर में चलने वाला प्रशिक्षण (ख) नैविगेटरों और सिगनेलरों (वायु) का इस समय जोधपुर में चलने वाला प्रशिक्षण, और (ग) इस समय वायुसेना प्रशासनिक कॉलेज, कोयम्बरूर, में चलने वाला घरातल-नर्तन्य अधिकारियों का प्रशिक्षण ।

सुरक्षार यह आश्वासन करता चाहती थी कि वायुसेना में कोई भी निवार्य दुर्घटना न होने पाये । मन्त्रिमण्डल-सचिव के समानाधिकार में एक उच्चस्तरीय समिति मई, १९६४ में बनायी गयी जिसके सदस्य थे वे वायु स्टाफ उपप्रमुख और महानिदेशक, नागर-विमानन और मन्त्रिमण्डल-सचिवालय का एक अधिकारी सदस्य-सचिव था । समिति ने अपना प्रतिवेदन नवम्बर, १९६४ में दे दिया । समिति ने यह माना कि वायुसेना जैसी सेवा में उद्धान दुर्घटनाएँ पूरी तरह तो समाप्त नहीं की जा सकती । उसका निष्कर्ष था कि आघात काल से उद्धान-मध्यों में हुई वृद्धि के बावजूद बड़ी दुर्घटनाओं की दर स्थिर रही है और १९५४-६३ की अवधि के दौरान घातक दुर्घटनाओं और विमान को आर्थिक मरम्मत से परे दायि पहुँचे, ऐसी दुर्घटनाओं की दर कम हुई है । समिति का विचार था कि पाइलट की त्रुटि के क्षेत्र में अवतरण के समय दुर्घटनाएँ ज्यादा होती थी । तकनीकी तौर पर काम बन्द हो जाने या घत काम होने लगने के कारण लगभग २५ प्रतिशत दुर्घटनाएँ हुई हैं, जबकि विविध आकस्मिक कारणों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 'पथी-टकराहट' है । मौसम की सहायी के कारण १९६१ में दुर्घटनाएँ ५.१ प्रतिशत से बढ़कर १९६३ में १२.२ प्रतिशत हो गयी हैं । समिति ने अनुविमान सम्बन्धी आँकड़े इकट्ठे करने, भारत-सर्वेक्षण के नक्शों को संशोधित करने, वायु-क्षेत्रों में बिजली के प्रवाह की व्यवस्था करने और सभी वायु-क्षेत्रों में घरातल-निगरान-यद्दति अपना लेने आदि में गुपार

करने के लिए सिफारिशें की। इन सभी को अमल में लाने के लिए स्वीकार किया गया।

### खण्ड ५ स्टाफ कॉलेज और राष्ट्रीय रक्षा-कॉलेज

अविभाजित भारत में सेना के अधिकारियों को स्टाफ प्रशिक्षण देने वाला स्टाफ कॉलेज ब्रिटेन में स्थित था। विभाजन के बाद वैसी ही संस्था भारत में स्थापित की जानी थी। जब राष्ट्रीय रक्षा-अकादमी बन रही थी, यह समझा गया कि तीनों सेनाओं के अधिकारियों का एक समान प्रशिक्षण, दृष्टिकोण में एकरूपता और ज्यादा अच्छे अर्थात् सेना महयोग के विकास को प्रोत्साहित करेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, यह तय किया गया कि स्टाफ कॉलेज का रूप भी अन्त-सेना वाला होना चाहिये और उसमें तीनों सेनाओं के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये। तदनुसार रक्षा-सेवा-स्टाफ कॉलेज की स्थापना नॉल्मिडि पहाड़ियों में बेल्गिडन नगर में की गयी। नया कॉलेज ५ अप्रैल, १९४८ को शुरू किया गया, जब इसमें दलसेना, नौसेना और वायुसेना से आये हुए अधिकारियों ने प्रवेश लिया और उनको एक ही पाठ्यक्रम से प्रशिक्षित किया गया।

कॉलेज का उद्देश्य तीनों सेना के अधिकारियों को द्वितीय श्रेणी की स्टाफ-नियुक्तियों के लिए अपेक्षित स्तर का प्रशिक्षण देना है और, ऐसा करते हुए उनको और अधिक अनुभव प्राप्त करने के बाद, कमान और उच्चतर स्टाफ-नियुक्तियों के लिए उपयुक्त बनाना है। जब कॉलेज शुरू किया गया, तो स्वयं कमांडेंट और अधिकांश शिक्षक ब्रिटिश अधिकारी थे, जिन सब की जगह पर धीरे-धीरे भारतीय अधिकारी रखे गये। मई, १९५५ तक सभी शिक्षक भारतीय हो गये और एक भारतीय मेजर जनरल, पी० एस० ज्ञानी, ने कॉलेज के पहले कमांडेंट का पदभार संभाल लिया।

दलसेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारियों के साथ-साथ भारतीय प्रशासन-सेवा, भारतीय विदेश-सेवा, रक्षा-लेखा-सेवा और रक्षा-विज्ञान-सेवा के असेनिक अधिकारियों को भी स्टाफ कॉलेज में प्रशिक्षण दिया जाता है। अन्य देशों के प्रशिक्षार्थी भी आते हैं। ऐसे प्रशिक्षार्थी सामान्यतः पारस्परिकता के आधार पर लिये जाते हैं।

बेल्गिडन को कॉलेज के लिए अस्थायी स्थान के रूप में चुना गया था, क्योंकि वहाँ पर उपयुक्त आवास उपलब्ध था। दूसरे स्थानों की उपयुक्तता की जाँच करने के बाद, अन्त में मार्च १९४६ में यह तय किया गया कि स्टाफ कॉलेज स्थायी रूप से बेल्गिडन में ही बनाया जाय।

१ जून, १९६३ से प्रशिक्षित स्टाफ-अधिकारियों की बढ़ती हुई माँग को देखते हुए, एक साल में एक की जगह दो-दो पाठ्यक्रम चलाये गये और इस प्रयोजन से पाठ्यक्रम की अवधि ४५ हफ्ते से कम करके २७ हफ्ते कर दी गयी। १९६५ में यह अवधि बढ़ाकर ३० हफ्ते कर दी गयी।

बेल्गिडन का स्टाफ कॉलेज कैप्टन मेजर के ओहदे वाले या समकक्ष अधिकारियों के

लिए बनाया गया है। जल्द ही यह सम्पन्न होगी थी कि लन्दन के इम्पीरियल डिफेंस कॉलेज जैसी सस्था बनायी जाय, जहाँ मध्य स्तर के वरिष्ठ सैनिक और प्रमैनिंक अधिकारी, जिनके नीति-निर्माण वाले स्तर पर उच्चतर जिम्मेदारियों के सम्भालने की सम्भावना है, विभिन्न कोणों से, रक्षा के विभिन्न व्यापक पहलुओं पर, मिलकर विस्लेषण करने हुए, विमर्श करें। १९४७ में दो सेना अधिकारी (और १९५५ तक एक अमेरिकी अधिकारी भी) हर साल लन्दन में इम्पी० डि० कानेज के पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए भेजे जा रहे हैं। सीमित सस्था में ऐसे अधिकारियों के प्रशिक्षण का अपना उपयोग है, पर हमारी अपनी सस्था भी होनी चाहिये, जहाँ भारत की परिस्थितियों के अनुसार समस्याओं पर विचार किया जा सके। तदनुसार राष्ट्रीय रसा-कालेज की स्थापना दिल्ली में की गयी और पहला पाठ्यक्रम २७ अप्रैल, १९६० को शुरू किया गया। कॉलेज का अध्ययन लगभग १० महीने चलता है और उसका सम्बन्ध राष्ट्रीय रसा के स्वायत्तिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक और औद्योगिक पहलुओं से रहता है। एक पाठ्यक्रम की सामान्य सस्था लगभग पचासी अधिकारी रहती है, जो तीनों सशस्त्र सेनाओं से (कर्मल, ब्रिगेडियर या उनके समकक्ष), भारतीय प्रशासन-सेवा, भारतीय, विदेश-सेवा, भारतीय सीमान्त-प्रशासन-सेवा, रसा-विज्ञान-सेवा, रसा-लेखा-सेवा, रेलवे और भारतीय डाक-सेवा (और कभी-कभी केन्द्रीय सचिवालय-सेवा से भी) लिये जाते हैं। कमांडेंट, टेप्टी० जनरल या समकक्ष पद का होता है। वरिष्ठ निदेशक स्टाफ में तीन अधिकारी रहते हैं (जो मेजर जनरल या समकक्ष या भारत सरकार के संयुक्त-सचिव के ओहदे के होते हैं)। इनमें से दो सैन्य अधिकारी रहते हैं (जो कमांडेंट जिस सेवा का होता है, उसे छोड़ अन्य दोनों सेवाओं में से लिए जाते हैं) और तीसरा एक सिविलियन अधिकारी होता है।

आपात के आरम्भ में, वरिष्ठ अधिकारियों के ज्यादा बहुस्तरीय कामों में लग जाने से, तीसरा पाठ्यक्रम समाप्त होने पर अप्रैल, १९६३ में इस कॉलेज का काम बन्द कर दिया गया था। पर कॉलेज १४ जनवरी, १९६४ को फिर खोल दिया गया। १९६४ और १९६५ में निदेशक स्टाफ और छात्र-अधिकारी दो टुकड़ियों में विदेश-यात्रा पर भी गये।

दिसम्बर, १९६५ में राष्ट्रीय रसा-कालेज ने, विभिन्न समाचार-पत्रों और एजेंसियों से जुड़े गये पत्रकारों के लिए, एक हफ्ते का अनुस्थापन पाठ्यक्रम भी चलाया।

### राण्ड ६ शैक्षिक समस्याएँ

(क) सारेंस स्कूल—भारत में नौकरी करने वाले ब्रिटिश सैनिकों के बच्चों के लिए पहले दोन स्कूल थे, जिनको 'सारेंस स्मारक सैन्य-स्कूल' कहा जाता था, एक गिमरा पहाड़ियों में गनावर में था, दूसरा मोलविरि पहाड़ियों में सक्सेल में था और तीसरा माउंट आबू में। इन स्कूलों के लिए जनता ने चन्दा करके पैसा इकट्ठा किया गया था। आठारों के बाद अब ये स्कूल उच्च सीमित प्रयोजन से काम न कर पाते थे, जिसके लिए इनकी स्थापना की गयी थी।

१९४८ के आरम्भ में रक्षा-मन्त्रालय ने एक समिति की स्थापना की, जिसने उनके जारी रहने और भावी विकास के बारे में जांच करके, सिफारिश देने के लिए कहा गया। समिति की सिफारिश के अनुसार सरकार ने निर्णय किया कि सनावर और लवडेल स्थित स्कूलों को पब्लिक स्कूलों के रूप में विकसित किया जाय। तदनुसार ये स्कूल प्रबन्ध के लिए शिक्षा-मन्त्रालय को सौंप दिये गये। अब उनका प्रबन्ध सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अधीन बनो दो स्वायत्त सोसायटियाँ चलाती हैं। इन स्कूलों में चालीस प्रतिशत स्थान भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों के बच्चों के लिए आरक्षित रखे जाते हैं। मुफ्त छात्रों के लिए अनेक छात्रवृत्तियाँ भी शुरू की गयीं।

(स) किंग जार्ज स्कूल ( अब सैनिक स्कूल )—जालन्धर, अजमेर, बेलगांव और बंगलौर में चार किंग जार्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज थे। ये संस्थान भारतीय सैनिकों के बच्चों को इस तरह से शिक्षा देने के लिए बनायीं गयीं थी कि उनको किसी भी सैन्य जीवन-कार्य ( कैरीयर ) के लिए योग्य बनाया जा सके। इन कॉलेजों में प्रवेश कनिष्ठ कमीशन-प्राप्त अधिकारियों और अन्य पद-धारियों और नौसेना के वारंट अधिकारियों और नाविकों तथा वायुसेना के वारंट अधिकारियों और एयरमैनो के बच्चों को ही मिलना था, जो मेवा में थे या नियमित भारतीय सेना से निवृत्त हो चुके थे। इन स्कूलों की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने के लिए बनायीं गयीं समिति की सिफारिश पर, इन कॉलेजों को आवासीय पब्लिक स्कूलों के रूप में १ सितम्बर, १९५२ से पुनर्गठित किया गया और प्रवेश असैनिक और सैनिक अधिकारियों के बच्चों के लिए खोल दिया गया। तब इनको किंग जार्ज कॉलेज कहा जाने लगा। पहले ये स्कूल बच्चों को सीनियर मैट्रिक परीक्षा के लिए तैयार करते थे, पर हाल में ये उच्चतर माध्यमिक परीक्षा दिलाने लगे हैं। स्त्रियों से उत्तीर्ण होने के बाद बच्चों को अपना जीवनकार्य स्वयम् चुनने दिया जाता है और सशस्त्र सेनाओं में भरती के लिए उन्हें कोई दायित्व नहीं होता। १९५५ में यह फैसला किया गया कि हर स्कूल की अधिकतम ३०० की संख्या के १० प्रतिशत तक ही अधिकतम दिवस-छात्रों को प्रवेश दिया जाय। इन स्कूलों का प्रबन्ध मुफ्ताने के लिय सभी स्कूलों के लिए रक्षा-मन्त्री की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय शासी-नियंत्रण और प्रत्येक के लिए एक स्थानीय प्रशासन-बोर्ड १९६१ में बनाया गया। जालन्धर वाले स्कूल को १९५२ में नौगांव ( म० प्र० ) से आया गया और फिर १९६० में चेल ( तमिलनाडु ) में पौतपुर ( राजस्थान ) में १६ जुलाई १९६२ से एक नया स्कूल शुरू कर दिया गया। जनवरी, १९६३ से कनिष्ठ कमिशन अधिकारियों, अन्य पद-धारियों और उनके समकक्ष लोगों के बच्चों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या ३० प्रतिशत से बढ़ाकर ६० प्रतिशत कर दी गयी। १९६५ में इन स्कूलों का नाम मिलिटरी स्कूल ( सैनिक स्कूल ) कर दिया गया।

आज कुल ३५ सशस्त्र सेनाओं के व्यक्तियों के जिनकी आय ४०० रुपये मासिक से कम है, बच्चों का छत्रा खर्च ( जिसमें दूधदान, आवास, भोजन, पुस्तकें और वस्त्र शामिल हैं ) सरकार देती है। अधिकारियों के बच्चों के लिये जाने वाला शुल्क कमरा बजटी दर पर है, गान्तः सेपरेटों और कैम्पों के बच्चों के लिए १००० रुपये प्रति वर्ष, केजरो के लिए १२०० रुपये, सेपरेट बंगलों के लिए १५०० रुपये और कनवो या उनके ऊपर के लिए १६०० रुपये प्रति



वर्ष ( और सभी मामलों में अन्य दोनों सेनाओं के समकक्ष ओहदे वाले अधिकारी भी ) । अमेरिकी के बचो में प्रतिवर्ष १६०० रुपये लिये जाते हैं ।

इन स्कूलों में सीमित सख्या में बचो को छात्रवृत्ति भी मिलती है । इस योजना में उन बचो की फीम वापस कर ली जाती थी, जिनके जनको की आय ५०० रुपये प्रतिमास या कम होती थी और उनकी आधी फीस, जिनके जनको की आय ५०० से १००० रुपये प्रतिमास थी । जबद्वार, १९५६ में ये सीमार्यें बढ़ाकर क्रमशः ६०० और १२०० रुपये कर दी गयी, और इस तरह यह योजना शिक्षा मन्त्रालय द्वारा पब्लिक स्कूलों में चलायी गयी योग्यता छात्र-वृत्ति वाली योजना जैसी ही हो गयी ।

(ग) राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज—प्रिंस आफ वेल्स रॉयल इंडियन मिलिटरी कॉलेज, देहरादून की स्थापना १९२२ में भारतीय सैन्य-अकादेमी को छात्र देने वाली सस्था के रूप में की गयी थी । इसे दिसम्बर १९५५ में सैनिक स्कूल का नाम दिया गया और बाद में राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज का । फिर भी इस संस्था में दी जाने वाली शिक्षा के स्तर में कोई परिमर्तन नहीं आया और न राष्ट्रीय रक्षा-अकादेमी, सङ्गठनवाला को छात्र देने वाली सस्था के रूप में इसके उद्देश्य में ही । प्रवेश एक प्रवेश-परीक्षा के परिणाम के अनुसार दिया जाता है, जो ७० भा० आधार पर हर छ महीने में ली जाती है । पहले इस कॉलेज में जबहुँ विभिन्न प्रान्तों ( राज्यों ) के रैगण्टों की सख्या के अनुपात में बाँट दी जाती थी पर अब अनुरात, जिन राज्यों के उम्मीदवार प्रवेश परीक्षा में बैठते हैं, उनकी जनसख्या के अनुसार बाँट दिया जाता है । साक्षात्कार-बोर्ड में राज्य-सरकारों के भी प्रतिनिधि रहते हैं, जो प्रवेश-परीक्षा का ही एक अंग है । जो छात्र राष्ट्रीय रक्षा-अकादेमी में प्रवेश के लिए चुने जाने की स्थिति में भारतीय सशस्त्र सेनाओं में सेवा करने का वचन देते हैं, उनसे १५०० रुपये वार्षिक शुल्क लिया जाता है । १९५५ में यह तय किया गया कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों के बचो से रियायती दर पर ७५० रुपये वार्षिक ( १५०० रुपये वार्षिक की जगह ) शुल्क लिया जाना चाहिये । प्रायः सभी राज्य कॉलेज में छात्रवृत्तियाँ देते हैं ।

(घ) सैनिक स्कूल—अनुभव ने बताया है कि सशस्त्र सेनाओं के कमीशन वाले पदों पर आने वाले युवकों के गुण और सख्या में सुधार की जरूरत है । मिडिन और तैक्डरी के शिक्षा प्रक्रमों में ऐसी उपयुक्त शिक्षा देने के लिए, जिसमें जर्म सशस्त्र सेनाओं में जीवन कार्य ( नेरियर ) के रूप में नौकरी करने की अभिवृत्ति पैदा हो, एक नये प्रकार के स्कूल, जिनको सैनिक स्कूल कहा जाता है, १९६१ में शुरू किये गये, जो राष्ट्रीय रक्षा-अकादेमी के फोल्डमोडरु के रूप में हैं ।\*

\* पहले स्कूल ने सनारा ( महापट्ट ) में २३ जून, १९६१ में काम करना शुरू कर दिया । और सैनिक स्कूल बुजपुरा ( पंजाब ), बानाछेरी ( जयपुर, गुजरात ) और बनारस ( पंजाब ) में जुलाई, १९६१ में मुने, चितौड़गढ़ ( राजस्थान ) में अगस्त, १९६१ में, बीरकोटा ( आंध्रप्रदेश ), कङ्कटम् ( त्रिचेन्द्रम्, केरल ) और पुरलिया ( प० बंगाल )

ये स्कूल आवासीय पब्लिक स्कूल की तरह चलाये जाते हैं और उनका पाठ्यविवरण, चयन और परीक्षा अखिल भारतीय होती है। बच्चे इन स्कूलों में प्रान्तीयता, जातिवाद आदि से मुक्त वातावरण में बड़े हो, इस उद्देश्य से केवल ६७ प्रतिशत जगहें उस राज्य के लिए रक्षित रखी जाती हैं, जहां स्कूल स्थित हैं और शेष जगहें अन्य राज्यों के लड़कों के लिए रहती हैं। जगहें सैन्यजनो के बच्चों के लिए भी आरक्षित रहती हैं,—अधिकारियों के और अन्य पदधारियों के। स्कूलों की व्यवस्था एक पञ्जीबद्ध सोसायटी चलाती है और शासी-परिषद् के अध्यक्ष रक्षा-मन्त्री रहते हैं। उन राज्यों के मुख्य मन्त्री या शिक्षा-मन्त्री भी, जहां स्कूल स्थित हैं, शासी-परिषद् के सदस्य होते हैं। स्कूलों का वित्तपोषण छात्रों से प्राप्त शुल्क और राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार से प्राप्त छात्रवृत्तियों से किया जाता है।

सैनिक स्कूलों के उम्मीदवारों की पहली टुकड़ी राष्ट्रीय रक्षा-अकादेमी के लिए, प्रवेश-परीक्षा में, जुलाई, १९६३ में बैठी। उस समय से १९६ उम्मीदवार रा० र० अकादेमी में, प्रवेश के लिए, जनवरी, १९६६ तक चुने गये। सैनिक स्कूलों की पढ़ाई के पूरे प्रभाव का अनुभव करने में अभी कुछ समय और लगेगा।

---

में जनवरी, १९६२ में, भुवनेश्वर (उड़ीसा) में फरवरी, १९६२ में, अमरवतीनगर (मद्रास) और रोवा (म० प्र०) में जुलाई, १९६२ में और तिलैया (बिहार) और बीरापुर (मैसूर) में नवम्बर, १९६३ में, ग्वालघाटा (अछम) में नवम्बर, १९६४ में और पोरखान (नेनीताल—उ० प्र०) में मार्च, १९६६ में खोले गये।

## नया अध्याय

# नये संविधान से सम्बद्ध परिवर्तन

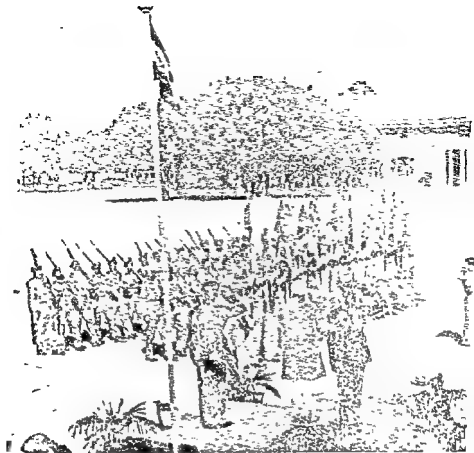
## खण्ड—१ नामो, ओहदो के बिल्लो और रज्जध्वज आदि मे परिवर्तन

२६ जनवरी, १९५० को भारत के नये संविधान के प्रारम्भ के साथ भारत एक सर्व-प्रभुत्व सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य हो गया और तब रक्षा सेवाओ में कुछ परिवर्तन जरूरी हो गये, खासकर सशस्त्र सेनाओ की यूनिटो और सेवाओ के नामो में और उनके ध्वजों और बिल्लो आदि में। सशस्त्र सेनाओ के लिए नये बीरता-पुरस्कार और पदक भी रखने पड़े। अनुच्छेद ५३ (२) के अधीन रक्षा-सेनाओ की सर्वोपरि कमान राष्ट्रपति में निहित है।

## सेना के व्यक्तियों द्वारा शपथ लिया जाना

१५ अगस्त, १९४७ के बाद भी भारत की सशस्त्र सेनाओ की बिछा महामहिम सम्राट के प्रति बनी रही। जिन अधिकारियों के पास किस कमीशन या भारतीय कमीशन थे तथा मौमेना के नाविको को इसके पहले महामहिम सम्राट के प्रति निष्ठा की शपथ न लेनी होती थी, पर यह शपथ चलतेना के अन्य पदधारियों और वायुसेना के समस्त पदधारियों को लेनी पड़नी थी। २६ जनवरी, १९५० को सशस्त्र सेनाओ के प्रत्येक सदस्य में नीचे लिखे रूप में शपथ लेने की अपेक्षा की गयी -

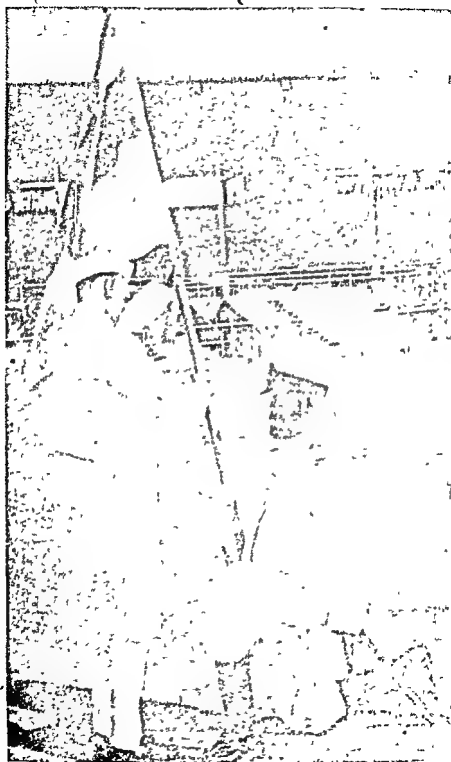
“मैं परमात्मा के नाम पर शपथ लेता हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची भक्ति और निष्ठा बनाये रखूंगा और मे वत्तंभ में बद्ध रूप में, ईमानदारी और सत्य भक्तिपूर्वक भारत सभ की नौयुना/नियमित चलतेना/वायुसेना में सेवा करूंगा और आदेश मिलने पर वही भी समुद्र, धरती और वायु में जाऊंगा और भारत-सभ के राष्ट्रपति के सभी कमानों का, और मेरे ऊपर रखे गये शिरो भी अधिकारी के कमान का, अपने प्राण भी सबट में डालकर पालन और आनापानन करूंगा।”



किय के एग बजो के साथ देहरादून में मार्च पास्ट रक्षाबंधन सलामी ले रहे हैं

भारतीय मैग्य अकादमी के बमार्डेंट किय का रागधन मुरखिन रखने के लिए प्रान्त करते हुए





डॉ० राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रपति का रणध्वज भारतीय नौसेना को प्रस्तुत करते हुए

भारत में सेवा कर रहे ब्रिटिश कमीशन प्राप्त या गैर-बमीशन प्राप्त जनों से उपपत्ते की अपेक्षा नहीं की गयी।

नये रूप का जारम्भ करने के लिए भारतीय सेना अधिनियम के नियमों और भारतीय वायुसेना अधिनियम के नियमों में उपयुक्त परिवर्तन कर दिये गये। इन्हीं नौसेना में प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा शुरू कर दिया गया और बाद में नौसेना अधिनियम, १९५७ में शामिल कर लिया गया। उस समय से यह शरय सशस्त्र सेनाओं में बमीशन पाने या भरती होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दिलायी जा रही है।

१४ अगस्त, १९४७ के बाद के प्रथम कार्यालय-दिन सभी अतिरिक्त अधिकारियों को भारत के प्रति, और ब्रिटिश द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति, निष्ठा की शपथ दिलायी गयी थी। इसलिए उनको संविधान के शुरू होने पर नयी शपथ दिलाना जरूरी नहीं समझा गया। पर नये प्रविष्ट होने वालों को विहित प्रपत्र में शपथ लेनी होती है।

### रॉयल नाम का हटाया जाना

ब्रिटिश युग में 'रॉयल' नाम ब्रिटिश सम्राट द्वारा किसी सेवा, यूनिट, या कोर के साथ लगाने के लिए उसकी सुविशिष्ट सेवा को मान्यता प्रदान करते हुए दिया जाता था और इसे बड़े सम्मान की वस्तु समझा जाता था। १८१२ में भारतीय मेरीन को यह नाम दिया गया और १९३४ तक इसका नाम रॉयल इंडियन मेरीन बना रहा। इस तिथि के बाद इसे रॉयल इंडियन नेवी कहा जाने लगा। भारतीय वायुसेना को भी १२ मार्च, १९४५ को द्वितीय विश्वयुद्ध में, उसकी सेवा को मान्यता देते हुए, रॉयल इंडियन एयरफोर्स नाम दिया गया। सेना की तरह वायुसेना या नौसेना में कोई पृथक कोर या सेवा नहीं होती। इसलिए रॉयल नाम पूरी सेना का ही रख दिया गया। फलसेना की कई सेवाओं और कोरों में रॉयल नाम, उसकी सुविशिष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए, जोड़ा गया। इस तरह भारतीय फनसेना में रॉयल इंडियन आर्मी सर्विस कोर, रॉयल इंडियन इंजीनियर्स, रॉयल इंडियन आर्टिलरी आदि हैं।

भारत के गणराज्य बनने के बाद 'रॉयल' नाम अनुपयुक्त हो गया। इसलिए उसे सभी सेवाओं, कोरों आदि से हटा दिया गया। इस तरह २६ जनवरी, १९५० से रॉयल इंडियन नेवी का नाम इंडियन नेवी (भारतीय वायुसेना) और रॉयल इंडियन एयरफोर्स का नाम इंडियन एयरफोर्स (भारतीय वायुसेना) हो गया। नौसेना के जो पोत पहले हिज मैजिस्ट्री इंडियन (एच. एम. आई) पोत कहलाते थे, अब भा० नौ० (भारतीय नौसेना) पोत कहे जाने लगे। फलसेना की कोरों और यूनिटों में भारतीय शब्द भी आवश्यक समझा गया। इस रॉयल इंडियन आर्मी सर्विस कोर का नाम आर्मी सर्विस कोर, इंडियन इन्वेस्टिगेशन एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स का इन्वेस्टिगेशन एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स और रॉयल इंडियन आर्टिलरी का नाम आर्टिलरी रेजीमेंट आदि रख दिये गये।

### कमीशन के प्रपत्रों में संशोधन

भारत की नयी प्रास्थिति ने सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों को दिये गये कमीशन के प्रपत्र में भी कुछ संशोधन जरूरी कर दिये ।

१९३४ तक भारतीय सेना के अधिकारियों को किंग कमीशन दिये गये थे और फिर १९३४ से आगे गवर्नर जनरल ने सम्राट् को ओर से कमीशन प्रदान किये । २५ जनवरी, १९५० को १२३ भारतीय अधिकारियों के पास किंग कमीशन था । ये अधिकारी भारतीय सेना अधिनियम के अधीन न आते थे, बल्कि ब्रिटिश सेना अधिनियम से शासित होते थे । भारत सरकार के अनुरोध पर यू० के० के राष्ट्रमण्डल सम्पर्क कार्यालय ने एक सर्वप्राप्ती अधिसूचना लन्दन गजट में प्रकाशित करके, इन अधिकारियों द्वारा किंग कमीशन के परित्याग का अनुमोदन, महामहिम सम्राट् ने २६ जनवरी, १९५० से कर दिया । उसी तारीख से राष्ट्रपति ने इस परित्याग से पूर्व वाले उनके ओहदे में, उसी बरिष्ठता और सेवाकाल के साथ, कमीशन प्रदान कर दिये ।

महामहिम सम्राट् द्वारा उनकी प्रतिनिहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए गवर्नर जनरल नौसेना और वायुसेना में कमीशन प्रदान करते थे । इसलिए इन दोनों सेनाओं में से ऐसा कोई किंग कमीशन धारण कर रहा अधिकारी न था, जिसका परित्याग जरूरी हो गया हो ।

सेवालों अधिकारियों को और मानद पद रखने वालों को दिये गये कमीशन महामहिम सम्राट् के नाम पर थे और भारत के गवर्नर जनरल की मुहर से तथा भारत सरकार के मुद्र (या रक्षा-विभाग के सचिव के हस्ताक्षर से ठाढ़ी किये जाते थे । वायुसेना कमीशनधारियों के लिए भी ऐसा ही प्रपत्र काम में आ रहा था । उनकी सेवा-विवृति होने पर सेकिंड लेफ्टीनेंट का मानद ओहदा प्रदान किया जाता था । ये सभी प्रपत्र २६ जनवरी, १९५० के बाद बदल दिये गये । कमीशन के प्रपत्र के अंग्रेजी में होने के साथ-साथ उनके बगल में हिन्दी रूपान्तर भी रहता है और कमीशन पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में रहते हैं । उन पर रक्षा-सचिव भी हस्ताक्षर करते हैं । स्थायी कमीशन और अल्पकाल कमीशन दोनों के लिए एक ही प्रपत्र काम में लाया जाता है ।

### ध्वज

१५ अगस्त, १९४७ से भारतीय नौसेना के पोनों में ध्वजदण्ड पर सामने की ओर भारतीय राष्ट्रध्वज फहरायी गयी और पताकादण्ड पर एक ध्वज पताका पीछे की ओर । सभी राष्ट्रमण्डलीय देशों द्वारा फहरायी जाने वाली ध्वज पताका एक बड़ी ध्वज पताका होती है, जिस पर रेडक्रास बना रहता है और दण्ड के पास ठाढ़ी जनुयौस पर यूनिफननेक रहता है । २६ जनवरी १९५० से रेडक्रास वाली सफेद पताका तो बनी रही पर यूनिफन जेज की जगह भारतीय राष्ट्रध्वज ने ले ली ।

### ओहदे के बिल्ले और बटन

नये सविधान के आरम्भ होने तक नौसेना, वायुसेना और सलसेना के बिन्ने विनड्ड

ब्रिटिश सशस्त्र सेनाओं जंगे ही थे। यत्नेना में मेजर से ऊपर के ओहदों वाले अफसरों के बिल्ले में ब्रिटिश ताज रहता था। २६ जनवरी, १९५० से ताज जहाँ कहीं भी ओहदे वाले के बिल्ले, रेजीमेंट के बिल्ले, बटनों, टोपियों के बिल्लो आदि में था, उसको जगह पर अशोक त्रिसिंह को लगा दिया गया। मेजर से नीचे के ओहदे के बिल्लो में 'आर्बंर ऑफ दि बाय' का सितारा रहता था। इसकी जगह भारत का पंचकोन सितारा लगा दिया गया। जमादारो (अब नाइब सूबेदारो) और सूबेदारो के ओहदे के बिल्लो में एक और चार नौको वाले दो सितारे रहते थे। इनकी जगह पर क्रमशः एक पंचकोन सितारा और दो पंचकोन सितारे लगा दिये गये। पहले प्रशासनिक कारणों से सूबेदार मेजरो और रिजालदार मेजरो (घुड़सेना में) के ओहदो के बिल्लो में मे ताज की जगह तीन पंचकोन सितारे लगा दिये गये थे। २६ जनवरी १९५० से इन तीन पंचकोन सितारों की जगह पर फिर अशोक त्रिसिंह का एक बिल्ला लगा दिया गया, जो अब सब बिल्लो में ताज की जगह पर आ गया था। नौसेना और वायुसेना में ओहदा पट्टियों से बताया जाता था, जो वस्तुतः अपने स्वरूप में अन्तर्राष्ट्रीय हैं और इसका राजपराने से कोई सास नादा नहीं है। इसलिए कोई भी परिवर्तन जरूरी नहीं समझा गया और नौसेना और वायुसेना में ओहदा अब भी पट्टियों से ही बताया जाता है। तीनों सेनाओं की बरती में और कोई परिवर्तन नहीं किये गये।

### रेजीमेंटो के बिल्ले

सत्ता-हस्तान्तरण से पहले बिल्लो के विद्यमान चिह्नो या भारतीय सेना की यूनिटो द्वारा नये बिल्ले अपनाये जाने के बारे में, सम्राट् से पहले अनुमोदन लेना होता था। यह अनुमोदन इंडिया आफिस के जरिये प्राप्त किया जाता था। १५ अगस्त, १९४७ के बाद यह अनुमद किया गया कि बिल्लो आदि के लिए अधिक आकर्षक भारतीय प्रारूप, जो अन्य राष्ट्र-मण्डलीय देशों से सम्बन्ध न हो, शुरू किये जाने चाहिये और किसी प्रकार के परिवर्तन का प्रस्ताव अन्तः भारत में निपटाया जाना चाहिये। बोमीनियनो और यू० के० में रेजीमेंट के लिए प्रस्तावित डिजाइनों की उपयुक्तता के बारे में कॉन्जे आफ हेरल्ड्स सलाह देता है। पहले यह प्रस्ताव किया गया कि एक विशेषज्ञ अन्तः सेवा-समिति भारत में भारतीय रेजीमेंटों और यूनिटों से आने वाले प्रस्तावों की छानबीन करने के लिए गठित की जानी चाहिये, ताकि वे सभी दृष्टि से उष्ण्युक्त रहे जा सकें। पर चूंकि केवल यन्सेना में ही रेजीमेंटों के बिल्लो की पट्टीय थी और सेना की यूनिटों आदि से ऐसा कोई प्रस्ताव आने की सम्भावना नहीं थी, जिसका नौसेना और वायुसेना के किसी चलन से सम्पर्क होता, इसलिए अन्तः सेवा-समिति गठित करना अनावश्यक समझा गया।

जिन रेजीमेंटों को रॉयल नाम मिल जाता था उनको महामहिम सम्राट् के अनुमोदन से अपने बिल्लों और बटनों में रॉयल यूथ या ताज इस्तेमाल करने की अनुमति प्रदान कर दी जाती थी। बिल्लो में अन्य ब्रिटिश चिह्न भी थे। कुछ रेजीमेंटों के बिल्लो में आदेशवाक्य अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन आदि में थे। अब रेजीमेंटों के बिल्लो में परिवर्तन करने की जरूरत थी। यह निर्णय लिया गया कि ताज की जगह अशोक त्रिसिंह रखे जायें और अन्य ब्रिटिश



चिह्न हटा दिये जायें या उनकी जगह कुछ और चीज रखी जाय। वहीं केवल ताज की जगह अशोक त्रिसिंह रखने का प्रश्न था, वह तो अपने आप कर दिया गया। पर कुछ मामलों में डिजायनें ऐसी थी कि ताज की जगह त्रिसिंह रखने से सौंदर्य में, राजकीय या अन्य कारणों से, कुछ और भी परिवर्तन करना जरूरी हो जाता था। आदर्शवाज्यों की जगह भी उपयुक्त हिन्दी आदर्शवाक्य रखने थे। पर यदि किसी बिल्दे की डिजायन बदलनी होती थी, तो यह जरूरी होता था कि प्रस्तावित परिवर्तन या अन्य चीजों को ध्यान से देखा जाय और तभी राष्ट्रपति का अनुमोदन मांगा जाय। अब यह सब काम पूरा हो चुका है।

जैसा कि बताया आ चुका है, रॉयल का सुविशिष्ट नाम पाने वाली यूनिटों या कोरों को सम्राट् के अनुमोदन से रायल यूज या ताज अपने बिल्लो और बटनो पर इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी जाती थी। नये सबिधान तन्त्र के अधीन वैसी ही सुविशिष्टता प्रदान करने के प्रश्न पर १९५० के आरम्भ में यह निर्णय किया गया कि जिन यूनिटों और कोरों ने राज्य की सुविशिष्ट और समाधारण सेवा की हो, उनको राष्ट्रपति के अनुमोदन से अपने बिल्लो और बटनो में राज्य चिह्न का इस्तेमाल करने की अनुमति देकर सम्मान दिया जाय। यह सुविशिष्टता देने से पहले स्वभावतः यूनिट के इतिहास, सप्तामो और युद्ध क्षेत्रों में उसकी उपलब्धियों, प्राप्त सम्मान और पुरस्कार और राष्ट्र-जीवन के क्षेत्रों में किये गये सामान्य कार्य आदि पर विचार करना होता था।

### सम्राट् के रणध्वज और रेजीमेंटो के रणध्वज

सत्ता हस्तान्तरण से पहले यूनिटों, रेजीमेंटों की विशेषतः सुविशिष्ट और सुयोग्य सेवाओं के लिए सम्राट् रणध्वज प्रदान किये जाते थे। सम्राट् के रणध्वज रेजीमेंट के लिए गर्व के चिह्न होते थे और परेडों में रेजीमेंट के रणध्वजों साथ ले जाये जाते थे। भारतीय पल-सेना की ३५ यूनिटों और नौसेना को सम्राट् के रणध्वज प्रदान किये गये थे। २६ जनवरी, १९५० से सम्राट् के रणध्वज परेड में ले जाने का चलन खत्म कर दिया गया। बाद में यह निर्णय लिया गया कि सम्राट् के रणध्वज राष्ट्रीय रक्षा-अकादेमी (इस समय देहरादून स्थित) में सुरक्षित रख दिये जायें। २३ नवम्बर, १९५० की देहरादून में एक समारोह-परेड हुई और परेड के बाद सम्राट् के रणध्वज अकादेमी (अब भारतीय सैन्य-अकादेमी) के चेटबुड हॉल में रख दिये गये।

मुद्ररन सेनाओं के पास सुविशिष्ट ध्वज होने का चलन काफी पुराना है और भारतीय पुराणेतिहास में इसके उल्लेख मिलते हैं। महाभारत में अग्ने-अग्ने सेनानियों के साथ लड़ने वाले सैनिकों द्वारा ले जाये जाने वाले ध्वजों का उल्लेख आया है। व्यक्तिगत सैनिकों के ध्वजों से सेना में रेजीमेंट के ध्वज विकसित हुए। यह ध्वज पहले युद्ध में सैनिकों को एक-दूसरे में जोड़ने के और सैनिक रेजीमेंट का ध्वज छानु के हाथ में न जा सके, हमारे लिए जम कर सड़ाने करने अपने जीवन की बलि भी चढ़ा देने थे। पर अब रेजीमेंटों के ध्वज युद्ध-क्षेत्र में ले जाने का रिवाज नहीं रहा है। अब रेजीमेंट अपने ध्वज केवल परेड में ले जाती है। सेना में प्रत्येक रेजीमेंट के विभेदक ध्वज को रेजीमेंट का रंग (रणध्वज) कहा जाता है। भारतीय सेना में

रंगध्वज के सामान्य आयाम होते हैं - ३' ६" X ३' ०", हालांकि कुछ रेजीमेंटों के रंगध्वज दूसरे आयाम के भी होते हैं।

सेना सेना-कोर, या सेना आर्जनेंस-कोर मान्य सेवाएँ हैं और उनके रेजीमेंट रंगध्वज पूरी कोर के ही होते हैं। ये कोर के चुने हुए केन्द्रों में रहते हैं। जब आठिलरी रेजीमेंटों के पास रेजीमेंट के रंगध्वज नहीं होते, पहले भी न थे। आर्मर्ड-कोर-रेजीमेंटों के पास २' ५३" X २' २' के आकार के मानध्वज (स्टैंडर्ड) होते हैं। दूसरों के पास दो नोकों वाली मार्ग-दर्शक पताका होती है, जिसे 'ग्विडन' कहते हैं। इन रेजीमेंटों के पास पहले की तरह पताका या मानध्वज बने रहे। लेकिन किसी रेजीमेंट की सुयोग्य सेवा के लिए मान्यता देते हुए राष्ट्र-पति के अनुमोदन से, उसकी पताका का दर्जा बढ़ाकर मानध्वज का कर दिया जाता था।

रेजीमेंटों के रंगध्वज सामान्यतः रेजीमेंटों की पूरी बरदी के किनारों के रंग के होते थे, इस तरह कुछ लाल और कुछ हरे होते थे। लेकिन जिन रेजीमेंटों को सम्राट् के रंगध्वज मिलते थे, उनकी पूरी बरदी के किनारों का रंग नीला होता था और यही रेजीमेंट के रंगध्वजों का भी होता था। रेजीमेंट के रंगध्वज पर रेजीमेंट का नाम और संक्रिया-स्थली का वह अनुमोदित नाम होता है, जहाँ उसने अपनी सुविशिष्टता दिखायी। पुढों को सन्क्रियाओं को वर्गीकृत करके रण (बैटल), संक्रिया (एक्शन) और रणनीतता (एग्रेजमेंट) नाम दिये जाते हैं। जिस रेजीमेंट ने किन्हीं रण (बैटलों) में भाग लिया हो, उन सभी का नाम वह अपने रंगध्वज पर लिखाने का अधिकार रखती थी, लेकिन यह सभी होता था, जब एक उच्च-अधिकार-समिति, इस अधिकार के लिए विहित योग्यताओं के अनुसार, उसकी छानबीन कर लेती थी। इस प्रकार लिखे गये नाम रण-सम्मान कहे जाते हैं और बीरता के द्योतक के रूप में प्रत्येक रेजीमेंट उनको बड़ा मूल्यवान समझती है।

रेजीमेंटों के रंगध्वजों में ब्रिटिश प्रतीक और उपरिरोध रहते थे, जैसे तारा, ब्रिटिश सिंह आदि। पर इन रेजीमेंट-रंगध्वजों का उपयोग तब तक बन्द नहीं किया जा सकता था, जब तक उनके स्थान पर दूसरे न दे दिये जायें। पुराने के स्थान पर नये रंगध्वज बदलने के लिए हर मामले में काफी जाँच अपेक्षित होती है। यूनिटों में, बड़े सम्बन्ध समय में विकसित रंगध्वजों के लिए कुछ भावार्थक मोह भी होता है। इसलिए नयी डिजायनों में यथासम्भव काफी सादृश्य पुरानी परम्पराओं के साथ रहना चाहिये, पर साथ ही बदली परिस्थितियों के साथ अनुगति भी रहनी चाहिये। इसलिए यह कैमला किया गया कि वे सभी रेजीमेंटों, जिनके पास रेजीमेंटों रंगध्वज, मानध्वज या पताका है, संशोधित डिजायन के नये ध्वज पाने के अधिकारी होंगे। जब नये रंगध्वज दिये जाते हैं, तो विद्यमान रंगध्वज उठाकर रख दिये जाते हैं।

नये रंगध्वज यथासम्भव हाथ से कटे और हाथ से बुने रेशम के होंगे। सशस्त्र के सभी सम्मान, जिनमें १५ अगस्त, १९४७ के पहले अर्जित किये गये सम्मान भी आते हैं, (केवल उनको छोड़ कर जो भारतीय भावना को ठेस पहुँचा सकते हैं,) नये रेजीमेंट रंगध्वजों पर अर्जित किये जायेंगे। पिछले विश्वयुद्ध में भाग लेने वाली भारतीय सेना की यूनिटों को रण-सम्मानों के लिए ५० के ० को रण-सम्मान समिति के पास आवेदन भेजना होता था, जो राष्ट्र-मण्डल के सभी देशों की सेना-यूनिटों के ऐसे दावों पर विचार करती थी। लेकिन केवल वही

सन्मान-सम्मान, जो राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित कर दिये जाते थे, नये रणध्वजों पर अंकित किये जा सकते थे।

आजादी के बाद की सन्धियाओं, जैसे काश्मीर के बारे में रण-सम्मान के लिए भारतीय यूनिटों के दावों पर विचार करने के लिए भारत में भी एक वैश्वी ही समिति बनायी गयी।

### सुयोग्य सेवा के लिए राष्ट्रपति की मान्यता

सम्राट् के रणध्वजों के स्थान पर कोई और रणध्वज रखने का प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि वे किसी भी गणराज्य में नहीं मिलते। फिर भी १९४७ के बाद की गयी सुयोग्य सेवा की मान्यता देते हुए, राष्ट्रपति एक विशेष प्रतीक प्रदान कर सकते हैं, जिसे नये रेजीमेंट रणध्वजों पर अंकित कराया जा सकेगा। यह प्रतीक एक बिन्दु के रूप में है, जिनमें राष्ट्रपति के मान-ध्वज पर चिन्हुरी पृष्ठभूमि में एक हाथी की प्रतिमूर्ति सुनहली कसीदाकारी से बनी रहती है और हाथी भी सुनहले कसीदे से बने दसकोनी चित्तारे से घिरा रहता है। यह बिन्दु रेजीमेंट के रणध्वज पर बायी ओर ऊपर के कोने में कसीदे से आरोपित किया जाता है।

नौसेना और वायुसेना की यूनिटों में, फलसेना के रेजीमेंट-रणध्वजों जैसी, कोई चीज नहीं होती। वे सेना-पताका फहराते हैं। इसलिए नौसेना या वायुसेना के मामले में पूरा सेना की ही सुविशिष्टता प्रदान करनी होती है। नौसेना राष्ट्रपति का रणध्वज २६ मई, १९५१ को दिया गया था। इसी तरह वायुसेना को भी राष्ट्रपति के रणध्वज का यही सम्मान उसकी २१वीं साल गिरह पर १ अप्रैल, १९५४ को दिया गया। प्रत्येक रणध्वज में, अभिप्राय के रूप में, सम्बन्धित सेना की पताका ही में राष्ट्रपति के मानध्वज के कुछ सङ्गण शामिल कर लिये गये हैं।

### सेनाओं में प्राथमिकता का क्रम

संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि-२ नौसेना, फलसेना और वायुसेना का उल्लेख करती है। यह संविधान का प्रारूप बनाने और उसे मजूर करने समय सेनाओं के बीच प्राथमिकता के क्रम पर आधारित था। नौसेना का यू० के० में हमेशा रक्षा में प्रमुख स्थान रहा है और उसे तीनों सेनाओं में सबसे वरिष्ठ स्थान दिया गया है। इस तरह यू० के० और उपनिवेशों में तीनों सेनाओं का उल्लेख इसी क्रम में किया जाता है नौसेना, फलसेना और वायुसेना। १९३४ में भारतीय नौसेना (अनुशासन) अधिनियम पास होने तक भारत में फलसेना सबसे वरिष्ठ सेना थी और प्राथमिकता के हिसाब से रॉयल इन्डियन मेरीन, फलसेना और वायुसेना के बाद आती थी। लेकिन जब रॉयल इन्डियन मेरीन का नाम रॉयल इन्डियन नेशी रखा गया, तो ब्रिटिश चलन का अनुसरण करते हुए, उसे भारत में भी सबसे वरिष्ठ स्थान दे दिया गया। हालाँकि आधुनिक युद्धकार्य में तीनों ही सेनाओं को, किसी भी सन्धिया को सफलतापूर्वक चलाने के लिए, बराबर का भागोदार बनना होता है, पर भारत में वस्तुतः फलसेना ही प्रमुख सङ्ग्रह सेना थी। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि फरवरी १९५० से सभी समारोहिक और औपचारिक प्रयोजनों से तीनों सेनाओं की आन्तरिक वरिष्ठता का क्रम

होना चाहिये : थलसेना, नौसेना और वायुसेना । इसलिए किसी भी सेना परेड में जब तीनों सेनायें भाग लेती हैं, तो पहले थलसेना को ठुकरा आती है, फिर नौसेना की ओर फिर वायु-सेना की ।

प्राथमिकता प्रश्न परिवर्तन का अर्थ यह बिल्कुल न था कि नौसेना और वायुसेना के महत्व में कुछ कमी आ गया है । सरकार तीनों सेनाओं को समान रूप से महत्वपूर्ण मानती है । वास्तव में दोनों तरफ सेनाओं की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और तीनों सेनाओं का समतुलित विकास आवश्यक करने के लिए उनमें से प्रत्येक को एक प्रमुख के अधीन रखा गया है । प्राथमिकता-क्रम में अंतर करने का अर्थ इस नीति से हटना नहीं है, इसलिए यह बिना दिक्का किये ही, किया गया ।

## खण्ड २ सशस्त्र सेनाओं के लिए नये पुरस्कार

### वीरता के लिए पुरस्कार

१५ अगस्त, १९४७ तक भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सदस्य वीरता के लिए ब्रिटिश अवसरण प्राप्त कर सका था । फिर कुछ ऐसे अवसरण भी थे जो सशस्त्र सेना के भारतीय सदस्यों के लिए खास तौर पर आरम्भ किये गये थे ।\*

\* सबसे बड़ा ब्रिटिश अवसरण विक्टोरिया क्रॉस था, जो तीनों सेनाओं के किसी भी ओहदे वाले व्यक्ति को मिल सकता था । तीनों सेनाओं के अधिकारियों और अन्य जनो को, वीरता कार्य के लए प्राप्तव्य विभिन्न अवसरण, इस तरह थे :

	अधिकारी	वायुसैन्य कर्मोच्चत प्राप्त अधिकारी या समकक्ष	भारतीय गैर-कमीशन प्राप्त अधिकारी और अन्य पदधारी
थलसेना	सुविशिष्ट सेवा क्रम (डी० एस० ओ०) (मिलिटरी क्रॉस (एम० सी०))	भारतीय योग्यता क्रम (आई० ओ० एम०) मिलिटरी क्रॉस	भारतीय योग्यता क्रम मिलिटरी क्रॉस
नौसेना	सुविशिष्ट सेवा क्रॉस (डी० एम० सी०)	सुस्पष्ट वीरतापदक (सी० जी० एम०)	सुविशिष्ट सेवा पदक (डी० एम० एम०) भारतीय सुविशिष्ट सेवा पदक (डी० एस० एम०)
वायुसेना	सुविशिष्ट उड़ान क्रॉस (डी० एफ० सी०) वायुसेना क्रॉस (ए० एफ० सी०)	सुविशिष्ट उड़ान पदक (डी० एफ० एम०) वायुसेना पदक (ए० एफ० एम०)	सुविशिष्ट उड़ान पदक वायुसेना पदक

१९८८ आरम्भ में राष्ट्रमण्डल-सम्पर्क कार्यालय से पृच्छा गया कि क्या ब्रिटिश वीरता-अलंकरण कश्मीर-संक्रिया में भाग लेने वाले भारतीय सशस्त्र सेना के व्यक्तियों को दिये जा सकते हैं। इस बीच दोनों सेनाओं और रक्षा-मन्त्रालय और वित्त-मन्त्रालय (रक्षा) के प्रतिनिधियों को एक समिति नये भारतीय वीरता पुरस्कारों को शुरू करने के प्रश्न को आँच करने के लिए बनायी जा चुकी थी। समिति के प्रतिवेदन पर, बाद में, भारत में सम्मान और पुरस्कार की पद्धति के आरम्भ करने सम्बन्धी प्रधान मन्त्री की समिति ने भी विचार किया। मई, १९४८ के आरम्भ में, प्रस्तावित नये पुरस्कारों की शर्तों और निबन्धों को अन्तिम रूप दिया गया और विभिन्न क्षेत्रों से सुझाव प्राप्त करने के बाद, जून, १९४८ में, इन पुरस्कारों के नाम अन्तिम रूप में इस प्रकार तय किये गये परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। इन अलंकरणों के प्रदान के लिए दोनों सेनाओं के प्रमुख अपनी सिफारिशें आरम्भ में रक्षा मन्त्रालय को भेजेंगे और रक्षा-मन्त्रालय प्रधान मन्त्री के पास, जो उनको अपनी सिफारिशों के साथ महाराज्यपाल या राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भिजवा देंगे।

ये नये पुरस्कार मन्त्रिमण्डल की सिफारिश पर महाराज्यपाल ही भारत में चालू कर सकते थे। उनको केवल भारत में ही प्राथमिकता मिलनी। पर यदि रॉयल वारंट मिल जाना, तो उनको पूरे राष्ट्रमण्डल में प्राथमिकता मिलनी। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के अनेक सदस्य ऐसे थे, जो सत्ता-हस्तान्तरण से पहले राष्ट्रमण्डल पुरस्कार पा चुके थे। इसलिए यह वास्तवीय समझ गया कि इन वीरता-पुरस्कारों का आरम्भ रॉयल वारंट के साथ किया जाय। नये पुरस्कारों की डिजाइन को अक्टूबर, १९४८ में अन्तिम रूप दिये जाने के बाद, इन नये अलंकरणों का आरम्भ करने वाले रॉयल वारंट का प्राकर, विहित प्रक्रिया के अनुसार, महाराज्यपाल के सचिव द्वारा महामहिम सम्राट् के निजी सचिव के पास सम्राट् का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए भेज दिया गया। हालाँकि यू० के० स्थित भारत के उच्चायुक्त ने इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय काम किया, तथापि १९४९ के मध्य में यह स्पष्ट हो गया कि कुछ सांविधानिक दिक्कतों के कारण सम्राट् का अनुमोदन न मिल सकेगा।

प्रस्तावित पदकों के डिजाइन की धारणा भारतीय थी। उनमें सम्राट् से किसी भी प्रकार का नाता न दिखाया गया था, जैसे कि रॉयल यूय रक्षा जानर। किसी अन्य डोमीनियनो ने भी, सम्राट् से स्वतन्त्र रहते हुए, अपने अलग पुरस्कार नहीं शुरू किये थे। फिर यह भी रुढ़ि चली आ रही थी कि व्यक्तियों को वीरता-अलंकरण के पुरस्कार सम्राट् के अनुमोदन से ही दिये जा सकते थे, पर अब प्रस्तावित कार्यविधि में इनको व्यवस्था न थी। इसलिए यह लगा कि महामहिम सम्राट् की स्थिति ठीक न रहेगी, यदि उनमें कोई भीधा सम्बन्ध न रखने वाले पुरस्कारों की मूर्ति उनके अनुमोदन से भी जाय। यदि वीरता-पुरस्कार का कुछ मनो-वैज्ञानिक प्रभाव है, तो यह वीर-कार्य के पश्चात् यथाशीघ्र ही दिया जाना चाहिये। कश्मीर-संक्रिया में, मुद्दबन्दों के १ जनवरी, १९४९ से शुरू हो जाने पर, पुरस्कार देने की सांविधानिक अड़चनें इनकी मूढम थी कि तैनिकों को नहीं समझाया जा सकती थी। पर चूँकि कुछ महीनों बाद ही नया संविधान प्रभावी होने जा रहा था, यह निर्णय लिया गया कि इन नये वीरता-पुरस्कारों के १५ अगस्त, १९४७ से आरम्भ की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा पहले गणराज्य दिवस

( २६ जनवरी, १९५० ) को की जायेगी । इसने भारत इन नये अलंकरणों को उच्चतम प्राथमिकता प्रदान कर रखेगा । प्राण्य शॉन वारंट में यह प्रस्ताव किया गया था कि परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र जयश-विक्टोरिया क्रॉस, सुविशिष्ट सेवा क्रम और मिनिट्री क्रॉस के सुरक्षित बाद आयेंगे । अब वे १५ अगस्त, १९४७ के पूर्व दिये गये किसी भी अलंकरण से पहले आते हैं । २६ जनवरी, १९५२ को, इन वीरता पुरस्कारों के प्रारम्भ की घोषणा के साथ-साथ ही, सगर्ज सेनाओं के उन सदस्यों के नामों को पहली किस्त में प्रकाशित कर दी गयी, जिनको कर्मावर-सक्रियता में वीरता के लिए ये अलंकरण प्रदान किये गये थे :

परमवीर चक्र शौर्य के सर्वाधिक सुस्पष्ट कार्य या शत्रु के सामने धरती, समुद्र या वायु में कुछ दुःसाहसपूर्ण या वीरता या आत्मवलिदान के पूर्णतः प्रकट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है । महावीर चक्र सुस्पष्ट वीरता के लिए और वीर चक्र भी वैसी ही स्थितियों में वीरता दिखाने के लिए दिया जाता है । सगर्ज सेनाओं के, आरक्षित सेनाओं के, प्रादेशिक सेना के अथवा किसी भी विशिष्ट गठित सगर्ज सेना के सभी सदस्य, नयन-वेदा के सदस्य और किसी भी लिंग के अतिरिक्त व्यक्ति जो किसी भी पूर्वोक्त सेना में काम कर रहे हों, इन अलंकरणों के पात्र हैं ।

इन अलंकरणों को प्राप्त करने वाले अपने नाम के साथ ये संक्षेप प्रयुक्त कर सकते हैं :

परमवीर चक्र के लिए	पी. बी. सी. ( प. बी. च. )
महावीर चक्र के लिए	एम. बी. सी. ( म. बी. च. )
वीर चक्र के लिए	वीआर सी. ( बी. च. )

सेक्रेट लेटरनेट या पब्लिक अफसर के ओहदे के नीचे के ( अर्थात् कमीशन वाले ओहदों से नीचे के ) जो व्यक्ति ये अलंकरण प्राप्त करेंगे, वे भारत सरकार द्वारा मंजूर किये गये नीचे लिखे मासिक भत्ते प्राप्त कर सकेंगे :—

परमवीर चक्र : २० ४० ( उन कनिष्ठ कमीशनधारी अधिकारियों को २० ७०, जिनको पहले वीरता के द्वितीय क्रम का पुरस्कार देने भारतीय योग्यता क्रम—आई. ओ. एम प्राप्त हो चुका है ) । परमवीर चक्र के प्रत्येक रोष के लिए २० २० का अतिरिक्त भत्ता ।

महावीर चक्र . २० ३० ( उन कनिष्ठ कमीशनधारी अधिकारियों को २० ५०, जिनको पहले वीरता के तृतीय क्रम का पुरस्कार जेम्स मिलिटी क्रॉस मिल चुका है ) । महावीर चक्र के प्रत्येक रोष के लिए २० १० का अतिरिक्त भत्ता ।

वीर चक्र : २० २० और वीर चक्र के प्रत्येक रोष के लिए २० ८ का अतिरिक्त भत्ता ।

यह स्पष्ट कर दिया जाय कि अब कोई व्यक्ति उसी अलंकरण के लिए दुबारा अधिकारी हो जाता है, तो उसे रोष प्रदान किया जाता है ( दुबारा परक नहीं ) । भन्ने उस कार्य की तारीख से मिलते हैं, जिसके लिए अलंकरण दिया जा रहा है और प्राप्तिकर्ता के जीवन काल में और उसको किये की मृत्युपूर्व या दूसरे विवाह पूर्व तक मिलते रहते हैं । इन भत्तों को पाने वाले कनिष्ठ कमीशनधारी अधिकारी बाद में कमीशन पाने पर भी इनको प्राप्त करते

रहेंगे। साथ ही राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्य के ये वीरता-अलकरण प्राप्त करने वालों को पुरस्कार देने की योजनाएँ भी चलायी हैं।

### सम्प्रेषणों में उल्लेख

सक्रिया-क्षेत्रों में सुविष्ट और सुयोग्य सेवा का बीर ऐसे वीरतापूर्ण कार्यों का, जो इतने ज्यादा उच्च प्रकार के नहीं हैं कि उनके लिए वीरता पुरस्कार दिये जा सकें, मायजा देने के लिए, १५ अगस्त, १९४७ से २१ नवम्बर, १९५० की अधिसूचना द्वारा, सम्प्रेषणों में उल्लेख की पद्धति शुरू की गयी। सम्प्रेषणों में उल्लेख सामान्य अर्थ में न तो अलकरण है, न पुरस्कार, बल्कि एक सैन्य-सक्रिया में अच्छे कार्यों की मान्यता देने के एक तरीके की तरह ही है। स्टाफ प्रमुख रक्षा-मन्त्री के पास ऐसे लोगों की एक सूची भेज देते हैं, जो किसी संक्रिया के दौरान ऐसी मान्यता के पात्र होने हैं। राष्ट्रपति का अनुमोदन लेकर ये नाम भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिये जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को रक्षा-मन्त्रालय के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र भी विहित प्रपत्र में दे दिया जाता है। सम्प्रेषण में उल्लेख का प्राक्तिकर्ता कास्य का मन्त्रालय प्रतीक उस युद्ध है, जिसमें यह उल्लेख किया गया, पदक के पीछे पर पहनने का अधिकारी होता है। (अने हो किसी व्यक्ति का नाम सम्प्रेषणों में एकाधिक बार आ गया हो, पीछे पर केवल एक ही प्रतीक पहना जायेगा।) छपाहरण के लिए कश्मीर-सक्रिया के दौरान जिन व्यक्तियों का उल्लेख सम्प्रेषणों में किया गया था, वे कश्मीर-सक्रिया सम्बन्धी युद्ध-पदक के पीछे पर प्रतीक को पहँेंगे। इस पदक का उल्लेख आगे किया जा रहा है।

### सामान्य सेवा पदक

यह एक मान्य बात है कि सारा सैन्यो में एक युद्ध-पदक होता है, जिसे सामान्य सेवा पदक कहते हैं, और जो सामान्य सक्रियताय सेवा को मान्यता देने के लिए होता है। यह उन सभी सैनिकों को प्रदान किया जाता है, जो सक्रिया-क्षेत्र में विहित अवधि तक सक्रिय रूप से सेवाशील रहे हों। चूँकि पदक सामान्य सक्रिय सेवा का चिह्न होता है, यह अपने आप उन युद्धों का सबेव नहीं दे सकता, जिनमें कि पहनने वाले ने भाग लिया। इसलिए यह पदक अकेले-अकेले नहीं पहना जा सकता। सक्रिया-विशेष को बताने के लिए एक फन्दा लगाने का चलन है, जो देश वाली छड़ के रूप में होता है। और यह युद्ध-पदक के पीछे के ऊपर पहना जाता है। जिस युद्ध-विशेष के लिए वह दिया गया है, उसका नाम उस पर उसीने रहता है।

१५ अगस्त, १९४७ से पहले युद्ध पदक या फन्दा—सभी आय वर्गों या पुस्तकालयों की तरह केवल सम्राट के अनुमोदन के बाद ही जानू किया जा सकता था। उक्त हस्तान्तरण के बाद यह निर्णय लिया गया कि एच 'सामान्य सेवा पदक, १९४७' १५ अगस्त, १९४७ के बाद की गयी सक्रिया-सेवा को मान्यता देने के लिए शुरू किया जाय और एक जम्मू और कश्मीर फंदा भी कश्मीर-सक्रिया में की गयी सेवा को मान्यता देने लिए। प्रस्तावित पदक की विवर्णन और उसे प्रदान करने की शर्तों और निषेधों की नवम्बर, १९४८ में अन्तिम रूप दिया गया और नये वीरता-पुरस्कारों के बारे में सम्राट के अनुमोदन के लिए

एक प्राच्य रॉयल वारंट जनवरी, १९४६ के शुरू में भेजा गया। नये बीरता-पुरस्कारों के विलमिने में बताये गये कारणों से ही सितम्बर, १९४६ में यह तय किया गया कि 'सामान्य सेवा पदक, १९४७' और जम्मू और कश्मीर फन्दा शुरू करने की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा २६ जनवरी, १९४० को की जानी चाहिये। बाद में यह वाञ्छनीय समझा गया कि पदक और फीजे की डिजाइन कुछ बदल दी जानी चाहिये। नयी डिजाइनों को अन्तिम रूप दिया गया और राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद १५ अगस्त, १९४७ से 'सामान्य सेवा पदक, १९४७' और जम्मू और कश्मीर फन्दा शुरू करने की अधिसूचना जून, १९४० में प्रकाशित की गयी। किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको पदक पहले ही मिल चुका हो, एक अन्य फन्दा दुबारा-तिबारा प्राप्त करने का अधिकार रहेगा। वह उसे या उन्हें पहले से अपने पास वाले पदक के फीजे पर पहनेगा।

सामान्य सेवा पदक और पहली बार में फन्दा और बाद में केवल फन्दा विहित शर्तें पूरे करने वाले लोगों को स्वतः मिल जायेगा। ऐसे सैनिकों की संख्या ज्यादा हो सकती है। इसलिए यह जरूरी नहीं समझा गया कि उनके नाम राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेजे जायें, न यही कि उनको राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

सामान्य सेवा पदक के अन्य फन्दे—सामान्य सेवा पदक के साथ पहने जाने वाले नीचे दिये अन्य फन्दे चालू किये गये —

(क) समुद्रपार-कोरिया १९४०-४३; जुलाई, १९४३ में उन सैन्य जनों द्वारा की गयी सक्रिय सेवा को मान्यता देने के लिए, जिन्होंने २२ नवम्बर, १९४० से ८ जुलाई, १९४३ की अवधि में पैरा फील्ड एम्बुलेंस यूनिट के साथ कोरिया में काम किया।

(ख) नागा पहाड़ी फन्दा—नागा पहाड़ियों में की गयी सैन्य-सक्रियता में की गयी सेवा को मान्यता देने के लिए २६ जनवरी, १९६० को शुरू किया गया।

(ग) गोआ फन्दा, १९६१—इसे उन सैन्य जनों की सेवा को मान्यता देने के लिए १९६२ में शुरू किया गया, जिन्होंने गोवा, दमन और ड्यू को आजाद कराने के लिए बलायी गयी सक्रियता में दिसम्बर, १९६१ में भाग लिया।

(घ) लद्दाख फन्दा, १९६२ और 'उपूसी' फन्दा १९६२—उत्तरी सीमान्त पर १९६२ में चीनी सैनिकों के विरुद्ध बतायी गयी सक्रियता में की गयी सेवा के लिए जून, १९६५ में शुरू किया गया।

### अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और ज्योति चक्र

परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र ऐसे बीरतापूर्ण कार्यों के लिए प्रदान नहीं किये जा सकते, जो शत्रु के मुकाबिले में न किये गये हों, जैसे आन्तरिक रक्षा कार्यों में या अन्यथा दिखायी गयी बीरता के लिये। इसलिए यह तय किया गया कि शत्रु के सामने युद्ध के अलावा अन्यत्र दिखायी बीरता के लिए तीन वर्गों में अशोक चक्र नामक एक नया अवर्तकरण चालू किया जाय। सशस्त्र सेनाओं के सदस्य और दोनों ही वर्गों के असेनिक नागरिक, चाहे वे



किसी भी जीवन-क्षेत्र में काम कर रहे हो, ( पुलिस दल और मान्य अग्नि-शमन-सेवा के सदस्यों को छोड़, जो अपनी वीरता के लिये राष्ट्रपति के पुलिस और अग्नि-सेना-पदक पा सकते हैं ), इस पुरस्कार के पात्र है । इस नये अर्जकण के चालू करने से, अन्य वीरता-अर्जकणों के साथ उनकी प्राथमिकता के बारे में भी निर्णय लेना जरूरी हो गया । अन्त में यह निर्णय लिया गया कि अशोक चक्र प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग क्रमशः परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र के बाद प्राथमिकता प्राप्त करेंगे । १५ अगस्त, १९४७ से तीन वर्गों में अशोक चक्र चालू करने वाली अधिसूचना ४ जनवरी, १९५२ को प्रकाशित की गयी ।

अन्य वीरता अर्जकणों की तरह अशोक चक्र के साथ कोई भत्ता नहीं मिलेगा । फिर भी यह तय किया गया कि अशोक चक्र पाने वालों के विशिष्ट मामलों, पर जो विपन्न स्थिति में हों, सरकार धन-सहायता देने के लिए विचार कर सकती है । हाल में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि एक शान्तिकर्ता ( या मरणोत्तर पुरस्कार की स्थिति में उसके उत्तराधिकारी ) को वार्षिक आय १००० रुपये से कम होने पर उसे असन्तोषप्रद वित्तीय स्थिति में माना जायेगा । ऐसी स्थिति में ६० ४० प्रति मास प्रथम वर्ग के लिए, ६० २५ प्रति मास द्वितीय वर्ग के लिए और ६० १५ तृतीय वर्ग के लिए भत्ते के रूप में दिया जावेगा । यह भत्ता शान्तिकर्ता ( अपना मरणोत्तर पुरस्कार की स्थिति में उत्तराधिकारी ) को आजीवन मिलेगा ।

अशोक चक्र प्रथम वर्ग पडे ही सुस्पष्ट शौर्य कार्य, कुछ साहित्यिक कार्य, सुप्रसिद्ध बहादुरी या आत्म-त्याग के लिए दिया जाता है, द्वितीय वर्ग सुस्पष्ट वीरता के लिए और तृतीय वर्ग वीरता के लिए जो घरेली, समुद्र या वायु में शत्रु के सामने दिखायी गये वीरता से भिन्न हो ।

२६ जनवरी, १९६७ को यह घोषणा की गयी कि अशोक चक्र प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्गों को आने से प्रमद अशोक चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र कहा जायेगा । पुरस्कार देने की शक्ति फिर भी पूर्ववत् बनी रह्यी ।

### प्रादेशिक सेना अलंकरण और प्रादेशिक सेना पदक

राष्ट्रपति ने १५ अगस्त, १९५१ से (अधिसूचना संख्या १६ प्रेस।५२, तारीख १ फरवरी, १९५२ द्वारा) प्रादेशिक सेना-अलंकरण और प्रादेशिक सेना पदक भी चालू किये हैं । जैसा उनके नामों से हो स्पष्ट है, ये केवल प्रादेशिक सेना के सदस्यों के लिए हैं । प्रादेशिक सेना-अलंकरण केवल प्रादेशिक सेना के कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, प्रमाणित क्षमता में, २० साल की मुख्य सेवा के लिए प्रदान किया जाता है । प्रादेशिक सेना-पदक प्रादेशिक सेना के कनिष्ठ कमीशन-प्राप्त अधिकारियों, गैर-कमीशन अधिकारियों और जवानों के लिए १२ साल की सशस्त्र सेवा और कम से कम बारह प्रतिशत प्राप्त करने वालों के लिए है, कि जिन के नाम की सिफारिश की गयी हो । इसके अलावा प्रादेशिक सेना के सदस्य ऐसे अलंकरण और पदक भी प्राप्त कर सकते हैं, जो सशस्त्र सेनाओं के नियमित सदस्यों को मिलते हैं ।

### दीर्घ सेवा और सदाचरण पदक और मुख्य सेवा-पदक

अगस्त, १९४७ से पहले बचनेवाला और नौसेना के जुने हुए गैर कमीशन-प्राप्त अधि-

कारियों को मुख्य सेवा-पदक और दीर्घ सेवा और सदाचरण पदक नाम के वीरता-इतर पदक (उपदान सहित या बिना) दिये जाने थे। पहला पदक हवलदारों को और नौसेना में समकक्ष पदधारियों को दिया जाता था, बशर्त कि उनका सेवा-काल १८ साल हो, जो सदाचरण और प्रवीणता-वेतन आदि के लिए जोड़ा जाय। इसके साथ १० २५ की वार्षिकी भी रहती थी। पुरस्कार का प्रमाण था, प्रत्येक ६०० व्यक्तियों के लिए एक। दीर्घ सेवा और सदाचरण-पदक उपदान के साथ नायकों और नौसे के बौद्धों वालों को या नौसेना के समकक्ष पदधारियों को १८ साल की सेवा के लिए उन्हें योग्यताओं के होने पर दिया जाता था, जिन पर मुख्य सेवा-पदक मिलता था। इस पुरस्कार के साथ २५ रुपये की वार्षिकी रहती थी और पुरस्कार का प्रमाण था, प्रत्येक ६०० व्यक्तियों के लिए दो। पिछला पदक उपदान के बिना उन लोगों को मिलता था, जो उपदान के सहित पदक पाने के पात्र थे, पर जिनको पुरस्कार दिये जा सकने से पहले ही वेतन वाली स्थापना में स्थानान्तरित कर दिया गया था। इस मामले में प्रमाण ६०० व्यक्तियों में से एक था। (ये पुरस्कार वायुसेना में चालू करने का कोई अवसर नहीं आया क्योंकि अपेक्षित सेवाकाल वाला अभी तक कोई भी व्यक्ति न था)। इस तरह इन दोनों सेनाओं में उपलब्ध इनमें से प्रत्येक पदक की कुल संख्या सीमित थी और केवल सेवानिवृत्ति या मृत्यु के पश्चात् ही स्थान रिक्त होते थे। सत्ता-हस्तान्तरण के बाद ये पदक बन्द कर दिये गये, क्योंकि ये संविधान द्वारा विजाओं आदि पर लगाये गये रोक के अधीन आ जाते थे। पर ये पदक सुविशिष्ट सेवा के लिए थे, सशस्त्र सेना के सदस्यों द्वारा बहुत ही बहुमूल्य माने जाते थे और उनके मनोबल पर इनका काफी प्रभाव पड़ता था। इसलिए सरकार ने यह तय किया कि पलसेना और नौसेना में इन दोनों पदकों को (घन-पुरस्कार सहित) फिर से चालू किया जाय और उनको वायुसेना में भी शुरू किया जाय। पिछले पदकों को विजायन में ताब और ब्रिटिश दिनों का संकेत देने वाले अन्य प्रतीक रहते थे। इसलिए उनको निश्चुन बदल दिया गया और नये पदक बनवाये गये। पुरस्कार की शर्तें मोटे तौर पर वही बनी रहो। पर मई, १९६४ में आदेश निकाल कर उपदान और वार्षिकी दोनों को ही बढ़ाकर १०० रुपये कर दिया गया।

### दूसरे नये पदक

उपर्युक्त पुरस्कार समय-समय पर देना होने वाली सभी प्रकार की अहर्तों पूरी करने के लिए काफी नहीं समझे गये। इसलिए २६ जनवरी, १९६० से नौसे तिवे नये पुरस्कार (अधिमूचना संख्या १४-प्रेसा २० द्वारा) जारी किये गये।

संग्रह सेवा-पदक—कठिन परिस्थितियों और उच्च जसवायु में सजिया-इतर सेवा को मान्यता देने के लिए। यह पदक सशस्त्र सेना के सदस्यों को ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी अवधि के लिए प्रदान किया जाता है, जो सरकार समय-समय पर तय करे। यह पदक जम्मू और कश्मीर, 'उज्जडी', हिमाचल, और अन्धमान तथा नौकोवर-द्वीपसमूह के क्षेत्रों में सेवा के लिए मान्य ठहराया गया है। इन चारों में से प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग-अलग पन्दा रखा गया है। इन पन्दों का प्रदान करने के लिए अहंकारी शर्तें और सेवा-अवधि सरकार द्वारा विहित की गयी है। जो लोग जम्मू और कश्मीर पन्दा सामान्य सेवा-पदक, १९४७ के साथ पहले प्राप्त

कर चुके हैं, उनकी पुनरावृत्ति से बचाने के लिए यह व्यवस्था की गयी है कि उस क्षेत्र में १ जनवरी १९४६ से पहले की उनकी सेवा को नहीं जोड़ा जायेगा। यथावश्यक सरकार समय-समय पर और फन्दे भी रख सकती है।

विशेष सेवा पदक भारत-संघ के बाहर सशस्त्र सेनाओं द्वारा की गयी सेवाओं को मान्यता देने के लिए। यह पदक एक फन्दे के साथ पहना जाना है, जिसमें सेवा का स्थान बताया गया है। काफ़ी, संयुक्त अरब गणराज्य, भूटान, नाइजीरिया, इथियोपिया, घाना, इण्डोचीन, लेबनान, नेपाल और कोरिया के फन्दे दिये गये। (पिछला फन्दा सशस्त्र सेना के उन व्यक्तियों को दिया गया था, जो २२ नवम्बर, १९५० से १७ मार्च, १९५४ तक तटस्थ-राष्ट्र-प्रत्यावर्तन-आयोग और भारत की अभिरक्षा सेना के कर्मचारियों के रूप में रहे थे)। अहंकारी सेवा की न्यूनतम अवधि और दूसरी शर्तें सरकार द्वारा विहित की गयी थी।

सेना-पदक, नौसेना-पदक और वायुसेना-पदक साहस और कर्तव्य के प्रति समन के ऐसे व्यक्तिगत कार्यों के लिए, जिनका सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए विशेष महत्व है। पदक के प्रत्येक परवर्ती प्रदान के लिए एक रोध दिया जाता है।

विशिष्ट-सेवा-पदक तीनो वर्गों में प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। प्रथम वर्ग का पदक बड़ी ही आपवादिक प्रकार की सुविशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, दूसरा आपवादिक प्रकार की विशिष्ट सेवा के लिए और तीसरा उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए। यह पदक राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के साथ, एक सनद देते हुए, प्रदान किया जाता है। उसी वर्ग के पदक के प्रत्येक परवर्ती प्रदान के समय प्राप्तिवर्ती को एक रोध दिया जाता है।

२६ जनवरी, १९६७ को की गयी घोषणा के अनुसार अब इन तीन वर्गों के पदकों के क्रमशः ये नाम होंगे परम-विशिष्ट-सेवा-पदक, अतिविशिष्ट सेवा-पदक और विशिष्ट-सेवा-पदक। प्रदान की शर्तें पूर्ववत् बनी रहेंगी।

समर-सेवा-समारक १९६५ और रक्षा-पदक, १९६५ . सशस्त्र सेना के व्यक्तियों और असेनिकों द्वारा सितम्बर, १९६५ में हुए भारत-पाक युद्ध के दौरान की गयी सेवा को मान्यता देने के लिए इन दो नये अमरारणों के प्रदान की घोषणा २६ जनवरी, १९६७ को की गयी। पंचकोना समर-सेवा-समारक सशस्त्र सेना के उन व्यक्तियों को दिया जायेगा, जिन्होंने बलुच मुठों में भाग लिया था जिनको सक्रियता के लिए युद्ध क्षेत्र में भेजा गया था। यह उन असेनिकों को भी मिलेगा जिन्होंने वास्तविक युद्धों में भाग लिया अथवा सक्रियता के दौरान छोटी मदद दी। सारक कुप्रो निजल का बनाया और पीता तीन रंगों में होता अर्थात् लाल, गहरा नीला और हल्का नीला, जो समर सेना, नौसेना और वायुसेना के तीन रंग हैं।

रक्षा-पदक, १९६५ सशस्त्र सेनाओं के उन सभी व्यक्तियों को दिया जायेगा, जो ५ अगस्त, १९६५ को १८० दिनों की सेवा कर चुके थे (यह वह तारीख थी, जब पाकिस्तान ने काश्मीर में दूसरा हमला और मुहुरेठ शुरू की थी)। रक्षा-पदक आकार में गोले होगा और कुप्रो-निजल का बनाया जायेगा और उसके साथ नारंगी रंग का पीता होगा जो लाल, गहरे

नीली और हल्की नीली तीन चदम धारियों द्वारा चार हिस्सों में बंट जायेगा ।

केन्द्रीय सम्मान और पुरस्कार-समिति वीरता अवकरण प्रदान करने की सभी सिफारिशें पहले प्रधान मन्त्री के अनुमोदन के लिए उनके पास भेजी जायेंगी और उसके बाद अग्नि अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति के पास । प्राप्त सिफारिशों की छानबीन करने के लिए और यह देखने के लिए कि एकल्य मानक स्वीकार किये जायें, एक केन्द्रीय सम्मान और पुरस्कार-समिति बनाना तय किया गया, जिसमें ये लोग रहें गये : रक्षा मन्त्री (अध्यक्ष), रक्षा-सचिव और तीनों सेनाओं के प्रमुख । अब असेनिकों को अशोक चक्र प्रदान करने की सिफारिश पर विचार होता है, तो गृहसचिव को भी इस समिति में सहयोजित कर लिया जाता है । वीरता-पुरस्कारों के अलावा अब यह समिति विशिष्ट सेवा पदक और सेना, नौसेना, वायुसेना पदकों के दिये जाने पर भी विचार करती है । समिति की सिफारिशें प्रधान मन्त्री और राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेज दी जाती हैं ।

परमवीर चक्र और अशोक चक्र, वर्ग-प्रथम पदक, राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली में गणराज्य दिवस पर समारोह-पर्यट के अवसर पर भेंट दिये जाते हैं । शेष वीरता अवकरण राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली में, इस काम के लिए हर साल होने वाले एक विशेष समारोह में, दिये जाते हैं, लेकिन १९६३ में यह तय किया गया था कि सेना, नौसेना और वायुसेना-पदक और विशिष्ट सेना-पदक तुनीय वर्ग प्राप्तिकर्त्ताओं को सम्बन्धित सेना प्रमुखों द्वारा ही भेंट दिये जायेंगे ।

विभिन्न पुरस्कारों का, असेनिक अवकरणों सहित, प्राप्ति-प्रणाली यह है :

भारत रत्न

परमवीर चक्र

अशोक चक्र

पद्मविभूषण

पद्मभूषण

परम विशिष्ट सेवा-पदक

महावीर चक्र

कीर्ति चक्र

पद्मश्री

अति विशिष्ट-सेवा-पदक

वीर चक्र

राज्य चक्र

वीरता के लिए राष्ट्रपति के पुलिस और अग्नि-शायन-सेवा-पदक

सेना, नौसेना, वायुसेना-पदक

विशिष्ट-सेवा-पदक

वीरता के लिए पुलिस-पदक

सामान्य सेवा-पदक, १९४७

सैन्य सेवा-पदक

विदेश सेवा-पदक

विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस और अग्नि-शमन-सेवा-पदक

सुयोग्यता सेवा-पदक

दीपसेवा और सदाचरण-पदक

शोभ्य सेवा के लिए पुलिस-पदक

प्रादेशिक सेवा-अलंकरण

भारतीय स्वाधीनता-पदक, १९४७

स्वाधीनता-पदक, १९५०

राष्ट्रमण्डल-पुरस्कार

अन्य पुरस्कार

(भारतीय स्वाधीनता पदक, १९४७, सशस्त्र सेनाओं के ऐसे प्रत्येक सत्येक सदस्य को दिया गया था जो १५ अगस्त, १९४७ को सेवा में था और स्वाधीनता-पदक, १९५०, पुलिस दल के उन सभी सदस्यों को, जो २६ जनवरी, १९५० को सेवा कर रहे थे। इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि भारतीय सशस्त्र सेना के व्यक्ति सत्ता-हस्तान्तरण से पहले उनको दिये गये वीरता अलङ्करण और अन्य पदक पहनें)। पूरी सम्बन्धिता वाले फ्रेतो सहित पदक समारोह के अवसरों पर धारण किये जाते हैं। सामान्यतः कम छोटे फ्रेतो (जो मानक आकार के होने हैं) धरती पर पहने जाते हैं।

### एण्ड ३ सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों द्वारा मताधिकार का प्रयोग

नये संविधान के साथ नागरिकों को प्रदान किया गया एक उन्नेतनीय अधिकार प्रोद् मताधिकार है। इस विशेषाधिकार ने अन्य नागरिकों की तरह सशस्त्र सेनाओं के व्यक्तियों के मन में भी यह भावना पैदा की कि वे देश के शासन में भाग ले रहे हैं। सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों को मतदान के लिए कुछ विशेष सुविधायें दी जाती हैं, जो उनको पहले प्राप्त न थी।

संविधान के स्वीकार किये जाने से पहले ही आरम्भिक मतदाना-सूचियाँ, प्रोद् मताधिकार के आधार पर, संघ और राज्य-विधान-मण्डलों में चुनावों के लिए तैयार करने का काम पूरे देश में शुरू हो चुका था, ताकि संविधान के लागू होने के बाद चुनाव व्यवस्थित रूप से चले सकें। सूचियाँ इस आधार पर बन रही थी कि अहंकारी तारीख को (१ जनवरी, १९४६ को, जिसे बदलकर बाद में १ मार्च १९५० कर दिया गया) २१ वर्ष की आयु वाला प्रत्येक नागरिक उस मतदान-क्षेत्र को मतदाता-सूची में अपना नाम दर्ज कराने का हकदार है, जिसमें वह अहंकारी समय में (अर्थात् ३१ मार्च, १९४८ को खत्म होने वाले वर्ष में—जिसे बाद में बढ़ाकर ३१ दिसम्बर, १९४६ कर दिया गया) १८० दिनों से अल्पमत वाला सामान्यतः रहा हो। इस निवासीय योग्यता ने सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों के मामले में बड़ी कठिनाई पैदा कर दी। सेना के किसी खास जगह स्थायी रूप से नहीं रहने, बल्कि उनका स्थान

क्रांतिक धारों ध्यान में रखकर तय किया जाता है। सशस्त्र सेनाओं के अधिकार सदस्य अपने घरों से दूर सेन्स-बैरको में रहते हैं और अपनी सेवा के स्वरूप और जरूरतों के कारण अतिरिक्त व्यक्तियों और अन्य नागरिकों की तुलना में उनका निवास-स्थान कहीं ज्यादा बदलता रहता है। उनमें से बहुत से निश्चय ही १५० दिन उत्तम अहंकारी अवधि में एक जगह पर नहीं रहेंगे और यदि उनके मामले में निवासीय योग्यता का आग्रह किया गया तो किसी भी मतदान-क्षेत्र की मतदाता-सूची में उनके नाम दर्ज न हो पायेंगे। यदि उनमें से कुछ लोग अहंकारी अवधि में छः महीने से ज्यादा एक जगह पर रहें भी और उनके नाम उस मतदान-क्षेत्र की सूची में आ भी जायें, तब भी सम्भव है कि चुनाव होते समय वे कहीं और काम कर रहे हों। इस तरह उनको अन्य नागरिकों की तरह स्वयं जाकर मतदान करने का अवसर न मिल सकेगा। इसलिए निवासीय-योग्यता का अर्थ होगा कि सशस्त्र सेनाओं के अधिकार सदस्यों को उनके मतदाधिकार से वञ्चित कर दिया जाय। किसी निर्वाचन-क्षेत्र की मतदाता-सूची के प्रकाशित होने पर, उसमें उस क्षेत्र में काम कर रहे सशस्त्र सेना के सदस्यों के भी नाम रहेंगे और इससे देश में मेना के विन्यास की बात प्रकट हो जायेगी, जो सुरक्षा की दृष्टि से स्पष्ट ही आपत्तिजनक होगा। इन धारों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया कि सशस्त्र सेनाओं के सदस्य सामान्यतः उस मतदान-क्षेत्र के निवासी मान लिये जायेंगे, जहाँ पर सशस्त्र सेनाओं में नौकरी न करने पर वे सामान्यतः निवास करते। यह उपबन्ध उनकी परिनियों पर भी लागू कर दिया गया। विहित प्रपत्र पर सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों द्वारा दिया गया वनउप्य (जिसमें मतदान-क्षेत्र-विशेष बताया जायेगा), जो उसके कमान अधिकारी द्वारा यथाविधि सत्यापित किया जायेगा, सामान्य निवास के लक्ष्यरूप में निश्चायक साक्ष्य माना जायेगा। यह भी ध्येयस्था की गयी कि सशस्त्र सेनाओं के जो सदस्य विस्थापित व्यक्ति हैं और जो भारत में अपने घर नहीं बसा पाये हैं, उस मतदान-क्षेत्र में अर्जित कर लिए जायेंगे, जहाँ वे स्थायी रूप से बसना चाहते हैं। इसके लिए उनकी वर्तमान-अधिकारी के सामने एक घोषणा-पत्र करनी होगी। ये प्रपत्र सशस्त्र सेनाओं के प्रत्येक सदस्य के पास व्यक्तिगत नहीं भेजे गये, बल्कि तीनों सेनाओं के विभिन्न अभिलेख-कार्यालयों द्वारा सम्बन्धित राज्य-सरकार के पास भेज दिये गये। इससे यह आश्वस्त हो गया कि सशस्त्र सेनाओं के २१ वर्ष की आयु वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम उसके घर या प्रतिष्ठित घर के मतदान-क्षेत्र में दर्ज कर लिया जायेगा। ये विशेष उपबन्ध शुरू में कार्यपालक आदेशों से कर लिए गये थे, पर फिर उनकी जन प्रतिनिधान अधिनियम, १९५० (१९५० का ४३ वाँ) की धारा २० और उसके अधीन बने जन प्रतिनिधान (मतदाता-सूची तैयार करना) नियम, १९५० में सांविधिक रूप दे दिया गया।

अगला कदम था मतदाधिकार का प्रयोग करने के लिए अपेक्षित सुविधाओं की व्यवस्था करना। यह प्रकट था कि सशस्त्र सेनाओं के निर्वाचक अपने मतदान-क्षेत्र में जाकर स्वयं मतदान न कर सकेंगे। इसलिए यह तय किया गया कि उन सभी को अपने मत डारु-शलाका द्वारा ही भेजने की अनुमति दी जायेगी, किसी अन्य रीति से नहीं, और साथ ही डाक द्वारा मतदान की प्रणाली सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों और उनकी पत्नियों के लिए सरल और एकरूप होने चाहिये। तदनुसार जन प्रतिनिधान अधिनियम, १९५१ (१९५१ का ४३ वाँ) की धारा ६०

में आवश्यक सावधिक व्यवस्था कर दी गयी ।

मतदान के लिए वास्तविक तन्त्र यह है कि निर्वाचन (रिटर्निङ्ग) अधिकारी से यह अपेक्षा की गयी है कि वह ससस्त्र सेनाओं के प्रत्येक सदस्य के पास, उस अभिलेख-कार्यालय के पते पर जिनमें उस व्यक्ति द्वारा चाहे गये मतदान-क्षेत्र में उसका नाम दर्ज करने के लिए उसकी घोषणा भेजी थी, डाक से मतदान-पत्र भेजेगा । मतदान-पत्र के साथ ये चीजें भी भेजी जाती हैं (१) साथ में एक पत्र जिसमें बताया जाता है कि अपनी इच्छा के उम्मीदवार के नाम के आगे मतदान-पत्र पर चिह्न लगाकर किस प्रकार मत अभिलिखित किया जाता है और साफ़कर इस जल्दोबात की ओर ध्यान दिलाया जाता है कि उसने किम तरह मत दिया है, यह कोई न देख पाये, (२) एक लिफाफा जिसमें आरम्भ में मतदान-पत्र रखकर उस पर मुहर लगायी जायेगी (३) एक घोषणा-पत्र, जिस पर मतदानपत्र लिफाफे में रखने के बाद, एक अधिकारी के सामने हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और (४) एक बड़ा लिफाफा जिसपर निर्वाचन अधिकारी का पता लिखा रहता है, जिसमें छोटा लिफाफा और घोषणापत्र रखे जाते हैं । इस तरह मतपत्र को परम गुप्त रखा जाता है । मतदान किये गये मतपत्र वाला लिफाफा अभिलेख-कार्यालय, रजिस्ट्री डाक से, निर्वाचन अधिकारी के पास भेज देता है । डाकखर्च भारत सरकार देती है । इस तरह जहाँ जनमाधारण-असेनिक अधिकारियों को धामिय करते हुए,—अपना मतदान करने के लिये मतदान केन्द्र पर जाने है,—और वे इस वर्तव्य से विमुक्त भी रह सकते हैं,—सशस्त्र सेनाओं का प्रत्येक सदस्य जहाँ बहो भी हो, वही से अपना मत डाल सकता है और उसे स्वयं मतदान-केन्द्र नहीं जाना पड़ता । जो लोग छुट्टी पर होते हैं या चुनाव के समय नौकरी छोड़ चुके होते हैं, उनके डाक-मतपत्र वाले लिफाफे अभिलेख-कार्यालय उनके घर के पत्तों पर भेज देता है । इसलिए सामान्यतः ऐसा कोई कारण नहीं कि ससस्त्र सेनाओं का कोई सदस्य अपना मत न डाल पाये ।

पूर्वोक्त कार्यविधि १९५१-५२ के साधारण चुनाव के समय अपनायी गयी थी । सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों की उम्मीदवारों के दली से परिचित कराने के लिए लोक-सभा और राज्य-विधान-सभाओं के डाक-मतपत्र को इस पत्र में संशोधित कर दिया गया था कि प्रत्येक उम्मीदवार के नाम के आगे उसे बटित किया गया प्रतीक भी रहे ।

निर्वाचन विधि में मतदाता-सूची के वार्षिक संशोधन की व्यवस्था है । यह समझा गया कि सशस्त्र सेनाओं के लोगों के बारे में हर साल यह घोषणा करना अनावश्यक होगा कि किस मतदान क्षेत्र में उनका नाम रखा जाय । इसलिए यह निर्णय लिया गया कि १९५२ में तैयार की गयी मतदाता-सूची को स्थायी माना जाय और उसके बाद जो लोग बाद में सेना में जाते हैं, और इस कारण जिनके नाम स्थायी सूची पर न होंगे, अथवा जो मान्य कारणों से अपना सामान्य निवास-स्थान बदलना चाहते हैं, उनके विहित प्रपत्र में घोषणा देने की कहा जाय । यह भी व्यवस्था कर दी गयी है कि पदोन्नति, अस्ती, मृत्यु आदि द्वारा मतदाता-सूची में जो भी जल्दी संशोधन हों, वे सशस्त्र सेनाओं सम्बन्धित अभिलेख-कार्यालयों द्वारा हर सात निर्वाचन-परीषद-अधिकारियों के पास भिजवा दिये जायें ।

इस तरह अपने मतधिकार का प्रयोग करने में सशस्त्र सेनाओं के लिए विशेष व्यवस्था

नये सविधान से सम्बद्ध परिवर्तन

की गयी है। १५ अगस्त, १९४७ में पहले उनके लिए डाक द्वारा मतदान करने की कोई व्यवस्था न थी और सीमित मताधिकार के और उस समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार जिन सशस्त्र सेनाओं के जिन लोगों के नाम मतदाता-सूची में आ भी जाते थे, तो भी उनमें से थोड़े से ही अपना वोट डाल पाते थे, (यदि वे चुनाव के समय सौभाग्य से विशेष मतदान-क्षेत्र में उपस्थित हो)। भारत सरकार अधिनियम, १९५५ में मतदाता-सूची तैयार करने के मामले में सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों का कुछ ध्यान रखा गया था, पर यह अतीत में सैन्य-सेवा कर चुके लोगों के बारे में था, काम कर रहे सैन्यजनों के बारे में नहीं। जो लोग सशस्त्र सेनाओं में काम कर चुके थे और सेवानिवृत्त हो गये थे या वहाँ से सेवामुक्त किये गये थे, वे सभी किसी मतदान-क्षेत्र विशेष में, मतदाता-सूची में, अपने नाम इकट्ठे हो लिखा सकते थे, लेकिन तभी जब वे उस निर्वाचन-क्षेत्र में विहित अवधि तक एक मकान में निवासवाली प्राथमिक योग्यता की पूर्ति करते हो। ये ही विशेषाधिकार और शर्तें उनको पत्तियों पर भी लागू थी, और पेन्शन पाने वाली विधवाओं और माताओं पर भी। सशस्त्र सेनाओं के कार्यरत सदस्यों के मामले में निवास सम्बन्धी नियम में कोई ढील न दी गयी थी, न उनको कोई विशेष सुविधायें ही अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए दी गयी थी। इस तरह चुनाव के बारे में, नये सविधान के लागू होने के बाद बने नये विनियमों के अधीन, सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों के लिए और उनको पत्तियों के लिए वोट डालने के बारे में एक विशेष व्यवस्था की गयी है और सशस्त्र सेनाओं के प्रत्येक सदस्य के निकट यह बात अब स्पष्ट कर दी गयी है कि वे भी किसी अन्य नागरिक की तरह तत्कालीन सरकार का चुनाव करने में योगदान दे सकते हैं।



**खण्ड १—वेनन-चहिला का संशोधन**

भारतीय कमीशन-श्राप्त अधिकारियों के लिए भिन्न वेतन-दरें विहित की गयी थीं, ये

\*उदाहरण के लिए जनरल अफमर क्वाड्रिग-इन-चोफ, कमान और सामान्य स्टार प्रमुख (लेफ्टी जनरल) का वेतन रु० ४४०० (समेतिन) था। एडजुटेंट जनरल, कमांडर मास्टर जनरल आफ आर्टिलेरी (लेफ्टी जनरल) का रु० ४००० था। एक डिस्ट्रिक्ट के कमानकारी मेजर जनरल का रु० ३१६१ (अनेने) और रु० ३२०० (विवाहित) था। मैज-मजिस्ट और इन्वोनियर-इन चोफ (मेजर जनरल) का रु० २७०५ (अनेने) और रु० २७८५ (विवाहित) था।

किंग कमीशन-धारी अधिकारियों को प्राप्त होने से बहुत कम थी। साथ ही विहित दरों पर कोर-वेतन और अनिश्चित आ भारसाधन वेतन देने-की भी पद्धति थी। ये १९३४ में तय की गयी थी और इनको तय करते समय १९३१ में अर्सेनिक कर्मचारियों के लिए जारी किये गये वेतनमानों, के० सो० आई० ओ० के वेतन-मानों और भारतीय स्थितियों के लिए उपयुक्त सामान्य वेतन-स्तर को ध्यान में रखा गया था। वायसराय कमीशन-प्राप्त अधिकारियों और भारतीय अन्य पदधारियों के वेतन-भत्तों की दरें सेना की शाखा विशेष के साथ भिन्न-भिन्न रहनी थीं। अनेक प्रकार के विशेष वेतन जैसे सदावरण-वेतन, प्रवीणता-वेतन, इजीनियर-वेतन, सिगनल-वेतन आदि भी उनको मिलते थे।

अन्य दोनों सेनाओं के अधिकारियों और अन्य पदधारियों के लिए भी ऐसी ही जटिल वेतन-भत्ता पद्धति चल रही थी। अन्तर केवल यही था कि नौसेना और वायुसेना में के० सी० आई० ओ० के संवादी अधिकारी न थे।

युद्ध काल में वेतन ढाँचा—इस तरह पिछले विश्वयुद्ध के पूर्व अधिकारियों की परिण-विधियों में वेतन की बुनियादी दरें होती थी और साथ ही विशिष्ट कर्तव्यों, दायित्वों के लिए विशेष वेतन और भत्तों की विराट व्यवस्था थी। युद्ध के कारण और भी अनेक नये भत्ते मजूर करना जरूरी हो गया, जिनमें से कुछ अप्रकट रूप में मँहवाई-भत्ते थे (सरकार के अधीन अर्सेनिक कर्मचारियों को मिलने वाले मँहवाई-भत्ते जैसे चीज सैन्यजनो की इसी रूप में न मिलती थी) और कुछ युद्ध-जोखिम के कारण दिये गये थे। १९४२ में भारतीय कमीशन-प्राप्त अधिकारियों की वेतन दरें ब्रिटेन के सैन्य-जनो की यू० के० में मिलने वाली दरों जितनी कर दी गयी और १९४४ में उनका स्तर बढ़ी कर दिया गया जो भारत की सशस्त्र सेनाओं में काम करने वाले ब्रिटिश सैन्यजनो का था। यह समानीकरण राजनीतिक आधार पर किया गया था और विमुदत्त एक युद्धकालीन कार्य था। पर किंग कमीशन अधिकारियों के साथ वेतन मानों की समानता मजूर करते समय भारतीय कमीशन अधिकारियों के निकट यह स्पष्ट कर दिया था कि ये वृद्धियाँ केवल युद्धकाल के लिए दी जा रही हैं और इनके अनन्तकाल तक चानू रहने का वे दावा न कर सकेंगे। उस समय निकाले गये आदेश के अनुसार युद्ध की समाप्ति पर ये अधिकारी अपने युद्ध पूर्व के वेतन-मानों में आ जायेंगे। फिर भी यह सोचा गया कि ऐसा करने से पूर्व तीनों सेवाओं में काफी समय से विचारणीय चले आ रहे वेतन-मानों का पुनर्संगठन ह्रास में लिया जाना चाहिये।

नया वेतन ढाँचा—१९४६ के आरम्भ में युद्ध-विभाग में युद्धोत्तर-वेतन समिति नामक एक विभागीय समिति बनायी गयी, जिसके अध्यक्ष विभाग के तत्कालीन अतिरिक्त सचिव थे और इसमें नौसेना-मुख्यालय, सामान्य-मुख्यालय (अब सेना-मुख्यालय) वायुसेना-मुख्यालय और सैन्य वित्त-विभाग (अब वित्त-मन्त्रालय रखा) के प्रतिनिधि थे। समिति के समस्त ये कार्य थे : (१) पूर्णतः भारतीय स्थिति के अनुकूल वेतन-मानों की सिफारिश करना, (२) वेतन-पद्धति को सरल बनाना, और (३) हर सेना में और छिन्नो सेनाओं के बीच भी यथासम्भव अधिकतम समरूपता लाना। इस बीच भारत सरकार ने सरकार के अधीन काम करने वाले

असैनिक-कर्मचारियों के वेतन-मानों के मुक्तिसमतीकरण के लिए एक केन्द्रीय वेतन-आयोग भी नियुक्त कर दिया था।

सशस्त्र सेनाओं के वेतन मानों को भारतीय स्थिति के अनुरूप बनाने के लिए मोटे तौर पर न्यूनतम और अधिकतम वेतन दरों के बारे में वेतन-आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय को मान लिया गया। युद्धोत्तर वेतन-समिति की सिफारिशें मई, १९४७ में प्राप्त हुईं और अन्तरिम सरकार ने उनको जून, १९४७ में मंजूर कर लिया। सशस्त्र सेनाओं के नये वेतन ढाँचे में अब विभिन्न ओहदों की वेतन-दरें और मंहवाई तथा प्रतिकर- (नगर) भत्ता आता है। पहले बस रहे अनेक विशेष भत्ते खत्म कर दिये गये। अधिकारियों को अब मंहवाई भत्ता और प्रतिकर भत्ता असैनिक अधिकारियों वाली दरों पर ही मिलता था, पर सरकारी खर्च पर आवास, भोजन और क्लब पाने वाले अन्य पदधारियों को मंहवाई और प्रतिकर भत्ते अभी दरों पर दिये गये।

सशस्त्र सेनाओं के वेतन-मान असैनिक सेवाओं से तुलनीय बनाने के लिए दोनो धेगियों की नियुक्तियों को मोटे तौर पर समकक्ष किया जाना था। इस प्रयोजन से पूर्ण-प्रशिक्षित पैदल सैनिक, जो तीन साल सेवा कर चुका था, मोटे तौर पर उन कर्मचारियों से तुलनीय माना गया, जिनको केन्द्रीय वेतन आयोग ने अर्द्ध कुशल माना था। सशस्त्र सेनाओं की सेवा को विशेष बातों को ध्यान में रखते हुए पूर्ण-प्रशिक्षित तीन साल सेवा वाले पैदल सैनिक का मूल वेतन ३० रुपये रखा गया। नौसेना और वायुसेना के तुलनीय ओहदों के लिए भी थोड़ी सी ही भिन्न-दरें रखी गयीं।

सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों के लिए मूल वेतन-मान रखे गये, जो सामान्यतः प्रथम ध्रेणी की असैनिक सेवा और भारतीय पुलिस-सेवा के लिए निश्चित वेतन मानों पर आधारित थे, पर उनमें कुछ ऐसे तत्वों का ध्यान रखा गया, जो इन तीनों सेवाओं की परस्पर विशिष्टता स्पष्ट कर देने थे। विवाह-भत्ता जैसी नयी चीज जो ५०० के० से ली गयी थी और केवल अधिकारियों को ही मिलती थी, खत्म कर दी गयी। इस निर्णय ने सशस्त्र सेनाओं की असैनिक चलन के अनुसार ही कर दिया और अधिकारियों के ओहदों के नीचे के उन लोगों के असन्तोष का एक सम्भव कारण खत्म कर दिया, जिनको यह भत्ता न मिलता था। तीनों सेनाओं की नयी वेतन-संहिता, अतिरिक्त कर्तव्य के लिए पारिस्थितिक के स्वरूप वाले सभी भत्ते हटाकर, अपेक्षाकृत सरल बना दी गयी। यह भी असैनिक प्रक्रिया पर आधारित था। पर यह माना गया है कि पैराचूट से उतरने या गोला मारने के जोखिम वाले कार्यों के लिए विशेष भत्ता उचित है और उसी तरह वायुसेना की सामान्य कर्तव्य दायरा के व्यक्तियों (अर्थात् वायु-सामानिक) को परागत कर्तव्य वाले लोगों की तुलना में ज्यादा पारिस्थितिक मिलना चाहिये। समरसना और सरलता की दृष्टि से अन्य विभिन्न परिवर्तन भी किये गये।

नयी संहिता का प्रभाव यह पड़ा कि बक्सरो ने ओहदों से नीचे वालों को युद्ध-पूर्व-वेतन की अपेक्षा ज्यादा मिला और अरिवाच मामलों में उनकी युद्धकालीन परिलब्धियों ने भी ज्यादा मिला। पर अनेक मामलों में १९४४ में मंजूर किये गये उनसे वेतन-भत्तों की तुलना में अधिकारियों के लिए काफी कटौती भी गयी।

ऐसे वायसराय कमीशन प्राप्त अधिकारियों और अन्य पदधारियों तथा नौसेना और वायुसेना के तत्संबन्धी पदधारियों के लिए जो १ जुलाई, १९४७ को मेवा में थे, नयी वेतन-संहिता भूत सन्धी प्रभाव से १ जनवरी, १९४७ से लागू की गयी, ताकि बड़े हुए वेतन का लाभ उनको पहुँचने की तारीख से मिल जाय। भारतीय कमीशनधारी अधिकारियों के मामले में (अर्थात् के० सी० आई० ओ० को छोड़कर जो अपनी पुरानी दरें लेते रहे) नयी दरें १ जुलाई, १९४७ से लागू की गयी। पर यह व्यवस्था की गई कि उनकी परिलब्धियों में सहसा कमी न हो जाय। हालाँकि नयी दरें उनकी युद्धकालीन परिलब्धियों से कहीं कम थी, पर वे सामान्यतः १९३४ में तय किये गये वेतन-मानों से अच्छे थे, फिर भी, युद्धकालीन परिलब्धियों से कटौती को कम सुलभ करने की दृष्टि से सरकार ने यह तय किया कि १ अप्रैल, १९४८ से पहले किसी ऐसे व्यक्ति के वेतन में कटौती न की जाय, जो १ जुलाई, १९४७ वाले मोहरे में बना रहे। इसके बाद नये वेतन की अपेक्षा पुराना वेतन जितना ज्यादा था, वह भी छमाही किस्ती में कम किया जाय। एक महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि अधिकारी-सर्वगों में तैयारी से दो गयी पश्चनतियों के कारण बहुत से अधिकारियों को पहले के वेतनों की अपेक्षा अपने नये मोहरों के लिए ज्यादा वेतन मिलने लगे थे।

नयी वेतन संहिता ने आयु के अनुसार सैनिक और असेनिक वेतन-दरों में समानोकरण करके सैन्य अधिकारियों को एक और लाभ प्रदान किया क्योंकि वरिष्ठ असेनिक सेवानों की प्रवेश-आयु की तुलना में ३-४ साल कम है। पर इस बीच सेवानवीन भारतीय कमीशन प्राप्त अधिकारियों की वेतन-संहिता के अनुसार, वेतन-कटौती की पहली किस्म सामने आ गयी थी और यह अनुभव किया गया कि युद्धकालीन स्थितियाँ पूर्णतः समाप्त नहीं हुई थी और इस कारण परिलब्धियों में कोई भारी कटौती करने से दिक्कत पैदा हो जाएगी, खासकर कनिष्ठ विभाहित अधिकारियों के लिए। इसलिए सरकार ने यह फैसला किया कि अधिकारियों के वेतन में जहाँ भी कटौती होनी है, किन्तु पूर्व-युद्धावधि छ की जगह नौ कर दी जायें। यह भी जरूरी समझा गया कि सप्ताह मेनाओं की कुछ विशेष स्थितियों को मान्यता देना जरूरी है, हालाँकि अनेक प्रसंगों वाली गड़बड़ फिर से अपना ना ठीक न होना, क्योंकि इतने सेना रखने में अतिशय पैदा हो गया था और अधिकारियों को तैनात या स्थानान्तरित करने में कुछ प्रशासनिक दिक्कतें भी सामने आ गयी थी और जिनको, इसी कारण, नयी वेतन-संहिता में नहीं रखा गया था। पुराने नियमों के अनुसार एक अधिकारी को सप्ताह-भर एक बार ही अपनी सेवा के गुरु में मिलना था और बाद में उसकी जगह चौबे उसे स्वयं खरोदनी होती थी। सैन्य अधिकारियों की वफा पर ही नहीं ज्यादा खर्च करना होता है, इसलिए यह तय किया गया कि कमीशन प्राप्त अधिकारियों को (जो नयी वेतन संहिता के अन्तर्गत आते हैं) सप्ताह-नवोतीकरण का नया भत्ता सेवाकाल के साथ-साथ वर्ष बाद दिया जाय। अधिकारियों के अनायास अन्य सैन्यजनों के वस्त्रों का खर्च सरकार देती है। अतः, १९६१ से आरम्भिक सप्ताह-भत्तों की दर ४०० रु० बढ़ा दी गयी।

कुछ विशेष प्रकार की नियुक्तियों वाले वरिष्ठ अधिकारियों की, सेवा की रिहाय और अपनी अधिकारि स्थिति के कारण, सप्ताह पर खर्च करना पड़ता है। इसलिए सरकार ने

निर्दिष्ट यूनिटों और विरचनाओं को कमान स्वतन्त्र रूप से धारण करने वाले और नयी वेतन-संहिता के अधीन आने वाले अधिकारियों के लिए सरकार-भत्ता मंजूर किया (अक्टूबर, १९५७ में यह भत्ता एक सरकार-अनुदान में बदल दिया गया, जिस पर आयकर नहीं लगता)। अधिकृत सैन्य-मैसों के लिए सरकार द्वारा दिए गये अनुदान की रकम में भी उदारतापूर्वक वृद्धि की गयी, क्योंकि कुछ ओहदों से नीचे के अधिकारियों के लिए इनमें सम्मिलित होना बाध्यकर है। सरकारी हैसियत से अधिकारियों के ऊपर बाध्यकर होने वाला अविवाहित सरकार-कार्यक्रम चूँकि इन मैसों में हो किया जाता है, इसलिए मैस-सन्धारण-अनुदान में की गयी वृद्धि ने बहुत से अधिकारियों को मदद पहुँचायी।

१९८८ में नयी वेतन-संहिता के अधीन आने वाले अधिकारियों के लिए स्थायी आधार पर नीचे लिखी और कुछ रियायतें भी दी गयी

(क) जहाँ पर अधिकारियों को फर्लोचर अधिकृत मान के अनुसार नहीं दिया जा सकता, अधिकारी अपने वेतन के ५ प्रतिशत तक का फरनीकर भाड़े पर ले सकते हैं और सरकार उनके वेतन के २५ प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति करेगी।

(ख) जहाँ अधिकारियों को उनके कर्तव्य-स्थान पर उपयुक्त विवाहित आवास नहीं प्रदान किया जा सकता, वे एकल आवास और सम्बद्ध सेवाएँ जैसे जल, बिजली आदि अपने लिए नि शुल्क प्राप्त कर सकते हैं।

(ग) सेप्टी० कर्नेल को शामिल करके इस ओहदे तक के अधिकारियों को (और दोनों अन्य सेनाओं में उनके समकक्ष को) कुछ विशेष योग्यताएँ रखने पर, योग्यताओं के उच्च या निम्न होने के अनुसार, ७५६० और ४०६० के योग्यता-वेतन प्राप्त किये गये। १९६२ में योग्यता अनुदान एकमुदत १८०० रुपये और १२०० १० देने के लिए व्यवस्था की गयी।

(घ) मेजर और नीचे के ओहदे वाले अधिकारियों (और उनके समकक्ष) को वायु-प्रेक्षण केन्द्र-भाद्रपट के रूप में नियुक्त होने पर ५००० मासिक का विशेष वेतन दिया गया।

(ङ) भारतीय वायुसेना की सामान्य कर्तव्य-शाखा के अधिकारियों और मेना और नोमेना में उद्घान-कर्तव्य संभालने वाले अधिकारियों को उद्घान-गरिबान (बाउटी) दी गयी जो ओहदे के अनुसार १२०० रुपये से १८०० रुपये तक वार्षिक थी। हाल में ये दरें बढ़ा दी गई हैं।

(च) सैनिकों का डाक-जीवन-जीमा पट्टे की विशेष दरों के स्थान पर सामान्य दरों के अनुसार किया जाने लगा और दोनों के बीच के अन्तर को पूर्ति रक्षा-मेना अनुमानों में की गयी।

ट्रिगेडियर तक के ओहदे के अधिकारियों (और उनके समकक्ष) को नीचे लिखी और रियायतें १९५० में दी गयी, लेकिन ये रियायतें अद्यावधि तौर पर ही मंजूर की गयी थीं और ये परिस्थितियों की माँग के अनुसार समीक्षा और पुनरीक्षण के अधीन थी —

(क) सरकारी आवास का किराया विवाहित अधिकारियों के लिए वेतन के १० प्रतिशत की जगह ५ प्रतिशत तक हो और अविवाहित अधिकारियों के लिए वेतन के ५ प्रतिशत की जगह २५ प्रतिशत तक ही सीमित रखा गया।

- (घ) अधिकारियों को वत और विजली के प्रसार को सैन्य इन्जीनियरों मेवा की दरों का आधा हो देना होता ।
- (ग) एक फिट सम्भारन-भत्ता और एक विद्युत-उपकरण-भत्ता प्रत्येक २०-३० रुपये मासिक का ।

इस प्रकार सम्पूर्ण सेनाओं के वेतन और सेवा-मजदुरी को नये वेतन-महिता ने काफी सरल बना दिया ।

अधिकारियों के नये वेतन-मान किए बनौंगनवाएँ भारतीय अधिकारियों पर लागू नहीं किये गये, बिनती मेस्टेडोरी अरु स्टेट को अन्य सेनाओं की तरह, जानी पड़ने की वेतन-दरों से उठने की अनुमति दे दी गयी । फिर भी ऐसे अधिकारियों को संख्या बहुत कम थी । १९६६ के अन्त तक भारतीय सेना में केवल एक ही ऐसा अधिकारी शेष रह जायेगा ।

दूसरे वेतन-आयोग (१९३७) को अधिकारियों के नये वनों पर लागू किये जाने पर विचार करने के लिए मजबूर, १९३८ में एक विनामीय समिति बनायी गयी, जिसमें सम्पन्न जन-रत्न-मन्त्री थे और रत्ता और वित्त (रत्ता) मन्त्रालयों और सेना-मुख्यालयों के बरिष्ठ प्रति-निधि उसके सम्म थे । समिति को अधिकारियों पर सरकार के निर्णयों को लागू करने के लिए आदेश विजम्बर, १९६० में (अधिकारियों के नौबे के सैन्य वनों के लिए) और जुलाई, १९६१ में (अधिकारियों के लिए) जारी किये गये और उनसे जनसः १ जुलाई १९३८ और १ अगस्त, १९६० में प्रभावी बनाया गया । अन्य पदधारियों के लिए संशोधित दरें, पढ़ने के नूतन वेतन में सब समय अर्धनिकांश पर लागू मेहगाई-भत्ते का दो-तिहाई जोड़ कर, निर्धारित की गयी । मेहगाई भत्ते की दरें भी अर्धनिकांश दरों के आधे से बढ़ाकर दो तिहाई कर दी गयी ।

बाद में, देश की सुरक्षा सेवा में अधिकारी के रूप में जीवन-कार्य के विभिन्न पहलुनों का परीक्षा करने के बाद, फरवरी १९६२ में गिनेबिंदर और दूसरी सेनाओं में समस्त एक के अंशों को शामिल करते हुए, सरकार ने अधिकारियों के वेतन में और सुधार करने का निर्णय लिया । नया आदेश १ अगस्त, १९६० में प्रभावी हुआ और सब के वेतन मान थे हैं : सेल्फ़ सेल्फ़ीनेट ४०० रुपये, सेल्फ़ीनेट ६० ४३०-३०-२४०, कैप्टन ७२०-६०-२२०, मेजर १०२०-२०/२-१३००, सेल्फ़ीनेट कर्नल (प्रवृत्ति) १३२०-२०/२-१३००, कर्नल १२२०-६०-१३३० और गिनेबिंदर ६० १७२०-१००-१८२० प्रति मास । उन अर्धनिकांश अधिकारियों के जो संयुक्त-निकांश और अतिरिक्त-निकांश के पद पर थे, वेतन बढ़ जाने के सम्बन्ध में, मेजर जनरल और सेल्फ़ीनेट जनरल ( और दोनों अन्य सेनाओं में उनके समस्त पदधारियों के म्याद प्रमुख की धोड़ कर ) के वेतन १ डिसेम्बर, १९६२ में बढ़ाकर समस्त जो कर दिये गये : २० २२००-१२२/२-२०३० और ६० ३००० । उच्च तारखे से २ प्रतिशत एक को फिटाना रिफ़ायर जो जनवरी, १९६३ में मेजर जनरल तक के अधिकारियों को दी गयी थी, वास्तव में ली गयी । भारतीय बनौंगन-वाट अधिकारी सेना कमांडर ( सेल्फ़ीनेट जनरल ) को २२० रुपये प्रतिमास का विशेष वेतन दिया गया है ।

## खण्ड २ सशस्त्र सेनाओं के लिए नयी पेन्शन-संहिता पेन्शन-समिति

मुद्रोत्तर वेतन-समिति, पेन्शन-संहिता के संशोधन का काम, साबकर इसलिए अपने हाथ में न ले सकी थी कि अमेरिकी कर्मचारियों के सेवा-निवृत्ति सम्बन्धी लाभ अभी भी सरकार के विचाराधीन थे और यह वास्तविक सम्भावना थी कि सशस्त्र सेना के सदस्यों की पेन्शन जिस सीमा तक संशोधित अमेरिकी पेन्शन से सम्बद्ध रहती जा सकती है। १९४७ में सशस्त्र सेना के मुलाजिमों के लिए नयी वेतन-संहिता आरम्भ होने पर यह भी जरूरी हो गया कि पेन्शन-लाभ की दृष्टि में संशोधन किया जाय। तदनुसार जुलाई, १९४९ में सरकार ने एक विभागीय समिति स्थापित की, जिसका नाम था सशस्त्र सेना पेन्शन-संशोधन-समिति और इसके अध्यक्ष न्यायिक-अनुभव वाले एक वरिष्ठ आई० सी० एस० अधिकारी थे और दोनो सेनाओं और वित्त-मन्त्रालय ( रक्षा ) के वरिष्ठ अधिकारी उसके सदस्य थे। समिति के सामने विकट काम था। उनकी दोनों सेनाओं पर लागू, बड़े ही भिन्न-भिन्न प्रकार की पेन्शन सम्बन्धी रियायतों को, मुक्तिमग्न और समन्वित करना था और सशस्त्र सेनाओं की मुविगिष्ट सेवा-दलानों को ध्यान में रखते हुए, एक सरल और एकरूप पेन्शन-संहिता बनानी थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त, १९५० में पेश की, लेकिन सिफारिशें एकमत न थीं। इसलिए सरकार की विभिन्न दूरगामी अन्तर्प्रसूत मामलों पर निर्णय लेने में कुछ समय लगा। नये पेन्शन-मान १ जून, १९५३ से प्रभावो विधे गये।

संशोधित पेन्शन-लाभों को निश्चित करने में अमेरिकी और संयुक्तों की सेवा-दलों के कुछ महत्वपूर्ण अन्तरो को ध्यान में रखना जरूरी था। अमेरिकी को सामान्यतः लगभग ३० साल की लगातार सेवा के बाद पेन्शन मिलती है और वे ५५ वर्ष तक ( अब ५६ ) या कुछ मामलों में ६० साल की आयु तक मौकरी कर सकते हैं।

सशस्त्र सेनाओं के मामले में स्थिति भिन्न है। उच्चतर ओहदों में स्थायी बने अधिकारी एक ओहदे में सामान्यतः चार साल नें ज्यादा मौकरी नहीं कर पाते, जब तक कि उनकी अगले उच्चतर ओहदे में पदोन्नति न दे दी जाय। अधिकारियों के ओहदों के मोटे के संयुक्तों में यह असमानता और भी सुस्पष्ट है। इनमें से अधिकांश सेव्यजन १५-वर्ष की सेवा पूरी हो जाने पर मेशनिक्न हो जाते हैं, और यह सेवा भी पूरी सक्रिय-मूकों में नहीं होती ( अर्थात् सामान्यतः ३ वर्ष रंग-मेका रहती है और ८ वर्ष आरक्षित में ) इस तरह जहाँ अमेरिकी सरकारी नौकर अपने जीवन के सन्ध्याकाल में अपनी पेन्शन सेना शुरू करता है, अधिकांश सेव्यजन अपनी मुखा होते ही अपनी पेन्शन पाने लग जाते हैं और इस तरह अभी उनमें अग्र-समता और नीचि रहने की दोषोत्तर आपाधा बनी रहती है। इसलिए अमेरिकी ध्यिक उठने ही वेतन वाले किसी सेव्यजन की अपेक्षा ज्यादा निवृत्ति-वेतन भी प्राप्त करे, तब भी वह अधिकांश मामलों में पीछे ही समय तक पेन्शन प्राप्त करेगा। साथ ही अधिकारी ओहदे के मोटे व सेव्यजन भंडन, कष्ट और आकाश सरकारी खर्च पर प्राप्त करते हैं और वेतन-मानें नष्ट पाते हैं। अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों के मामले में ऐसी व्यवस्था नहीं है।

## सेना-पेन्शन

इन सब बातों का ध्यान रखते हुए यह तय किया गया कि सहाय्य सेन्यजनों का सेवा-निवृत्ति-वेतन तदर्थ आधार पर निर्धारित करने की पद्धति चालू बनी रहनी चाहिये। तदर्थ दरो की यह पद्धति भारतीय सेना में शुरू से ही चली आ रही है और यू० के० जैसे दूसरे देशों में भी चलती है। यह लागू करने में आसान भी है। पर माय ही पुरानी तदर्थ दरो में कुछ प्रत्यक्ष ग्राह्यता भी है। पहले तो वे बहुत कम हैं और सेन्यजनों के लिए १९४७ में शुरू की गयी नयी वेतन-दरों के साथ उनका कोई गठजोड़ नहीं है। दूसरे तीन-तीन सालों के सेवा के समुच्चय के लिए दरें बड़ी हैं (३० साल से ज्यादा की अहंकारी सेवा वाले आमतौर पर कमीशन पारी अधिकारियों को छोड़कर), और तीसरे प्रत्येक ओहदे में समान सेवाकाल वालों के लिए कोई अन्तर नहीं है, हालांकि व्यक्ति विशेष के ट्रेड-समूहों के अनुसार उसकी वेतन-दरों में काफी अन्तर रहता है। इसलिए तदर्थ दरें निर्धारित करने के लिए एक नया सूत्र स्वीकार किया गया। इस सूत्र की प्रमुख बातें ये थी —

- (क) रंग सहित १५ साल की न्यूनतम अहंकारी सेवा के लिए प्रत्येक ओहदे और उची ओहदे में प्रत्येक वेतन-समूह के लिए तदर्थ पेन्शन दरें विहित की गयी।
- (ख) १५ साल से ज्यादा अहंकारी सेवा के प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए सेवा के वर्ष-समुच्चय के लिए पहले दी जाने वाली पेन्शन की स्थूल दरों को बगल पेन्शन दर में एक वार्षिक वृद्धि विहित की गयी। वार्षिक वृद्धि की दर में ओहदे के अनुसार अन्तर रहता था।
- (ग) दयासम्भव तीनों सेनाओं में तुलनीय वेतन-दरों के आधार पर पेन्शन-दरों में एकरूपता रखी गयी।

संघीयित दरों के अधीन एक सिपाही १५ ६० से ३२ ६० तक ही मासिक पेन्शन पा सकता था, नायक १७ ६० से ३६ ६०, हवलदार २३ ६० से ४८ ६०, जमादार (अब नायब सुबेदार) ३५ ६० से ७३ ६० तक, सुबेदार ५० ६० से १०५-५० ६० तक और सुबेदार मेजर १०१ ६० से १५३ ६० तक। ये दरें अप्रैल १९६१ से फिर संशोधित की गयी और अब इस तरह हो गयी सिपाही १७ ६० से ४० ६०, नायक २१ से ४५-५० ६०, हवलदार २४ ६० से ५३ ५० ६०, नायब सुबेदार ३८ ६० से ८०-५० ६०, सुबेदार ५२ ६० से १२१-५० ६० और सुबेदार मेजर १०१ ६० से १६८ ६०। १ जनवरी, १९६४ में लागू हुए नये आदेश के अनुसार उस तारीख को या उसके बाद सेवा-निवृत्त होने वालों को २५ ६० की न्यूनतम पेन्शन दी जाने लगी है।

## सेवा-निवृत्ति-पेन्शन

नयी पेन्शन-संहिता ने स्थायी कमीशनपारी अधिकारियों की सेवानिवृत्ति-पेन्शन जोड़ने के लिए मानक दर योजना वाली एक ब्रिजनुत नयी पद्धति चालू की। इसमें प्रत्येक ओहदे के लिए त्रिहिन सेवाकाल के बाद मानक दर से पेन्शन की व्यवस्था की गयी। सेवा-निवृत्ति-पेन्शन पाने के लिए एक अधिकारी को (दर में बरती होने वाली को छोड़ कर) २० साल की न्यूनतम



अहंकारी सेवा करती होती है। पेन्शन की अधिकतम मानिक दरें ये थी - कैप्टेन ३५० रु०, मेजर ४७५ रु०, लेफ्टी० कर्नल ६२५ रु०, कर्नल ६७५ रु०, ब्रिगेडियर ७२५ रु०, मेजर जनरल ८०० रु०, लेफ्टी० जनरल ९०० रु० और जनरल १००० रु०। नयी वेतन-संहिता में यह भी व्यवस्था की गयी कि जिन अधिकारियों को जीवन में देर से कमीशन मिला और जो २० साल से कम के सेवाकाल के बाद निवृत्त हो रहे हैं, पर उनका अहंकारी (कमीशन प्राप्त) सेवाकाल १५ साल या ज्यादा है, उनको आनुपातिक पेन्शन दी जायेगी। अन्य मामलों में कम से कम १० साल की अहंकारी सेवा होने पर अधिकारी सेवा-उपदान प्राप्त कर सकते हैं।

सेवा-निवृत्ति-पेन्शन की दरें १ अक्टूबर, १९६१ से बड़ा हो गयी। आजकल दरें ये हैं - लेफ्टि लेफ्टीनेंट और लेफ्टीनेंट ३०० रु०, कैप्टेन ४२५ रु०, मेजर ५५० रु०, लेफ्टीनेंट कर्नल ६७५ रु०, ब्रिगेडियर ८२५ रु०, मेजर जनरल ८७५ रु०। लेफ्टीनेंट जनरल और जनरल की दरें क्रमशः वही ९०० रु० और १००० रु० बनी रहो (ये सभी दरें अन्य दोनों मैनाओं के समान पदों पर भी लागू होती हैं)।

### नियोग्यता-पेन्शन

इस प्रकार की पेन्शन सदास्र मैना के एक सदस्य को इस शर्त पर मिल सकती है कि नियोग्यता सैन्य-सेवा के कारण है। उसका निर्धारण २० प्रतिशत या ज्यादा किया जाता है। इसमें दो तत्व रहते हैं - सेवा का तत्व और नियोग्यता का तत्व। जो कमीशनधारी अधिकारी २० साल की अहंकारी सेवा कर चुके हैं, उनके अपग होकर अलग किये जाने पर सेवा-तत्व सेवाकाल और ओहदे के लिए उपयुक्त सेवा-निवृत्ति-वेतन माना जाता है। इसी तरह कनिष्ठ कमीशनधारी अधिकारियों और अग्र पदधारियों के १५ साल की अहंकारी सेवा पूरी कर चुकने की स्थिति में सेवा-तत्व ओहदे की सेवा-पेन्शन के उपयुक्त रहता है।

### अन्य पेन्शनें

विशेष परिवार-पेन्शन, उपदान और सामान्य परिवार-पेन्शन की दरों में भी वृद्धि की गयी है।

### खण्ड ३ तीनों सेनाओं की अनुशासन-संहिता में मशौज

१५ अगस्त, १९४७ से पहले सभाट् को चलाने में किंग कमीशन-धारी सभी भारतीयों और ब्रिटिशजनों के ऊपर ब्रिटिश सेना-अधिनियम लागू होता था। भारतीय सेना के अन्य भारतीयजन (भारतीय कमीशन प्राप्त अधिकारियों समेत) १९६१ के भारतीय सेना-अधिनियम द्वारा शासित होते थे। यह अधिनियम पर्याप्त रूप से विस्तृत था। जहाँ वहाँ यह मोल था, तत्प्रादी ब्रिटिश-अधिनियम की व्यवस्था मान ली जाती थी। १५ अगस्त, १९४७ के ब्रिटिश सेना-अधिनियम लागू न रहा और किंग कमीशनधारी भारतीय अधिकारी २६ जनवरी १९४८ को जारी किये गये, पर १५ अगस्त, १९४७ से प्रभावी, एक अध्यादेश (१९४८ का अध्यादेश, सख्या दो)

द्वारा भारतीय सेना अधिनियम के अधीन कर दिये गये और इसने भारतीय सेना-अधिनियम में यह व्यवस्था करने के लिए संशोधन कर दिया कि भारतीय कमीशन-प्राप्त अधिकारी राज्य में भारतीय नागरिकता कावा और सम्राट् को मननेना में किंग कमीशनप्राप्त व्यक्ति भी शामिल माना जायेगा। यह संशोधन बाद में भारतीय सेना (संशोधन)-अधिनियम, १९६८, (१९६८ का अधिनियम, संख्या ४३) में शामिल कर लिया गया और इस तरह के० सी० आई० ओ० तब तक भारतीय सेना अधिनियम, १९११ के अधीन बने रहे जब तक कि इस अधिनियम को ही सेना के सभी कमीशन-प्राप्त अधिकारियों को समेटने के लिए संशोधित नहीं कर दिया गया।

संगठन और अनुशासन के मामले में नौसेना और वायुसेना जन्य. भारतीय नौसेना (अनुशासन) अधिनियम, १९३४ और भारतीय वायुसेना अधिनियम १९३२ और उनके अधीन बनाये गये विनियम-निर्देशनों में अनुशासित होंगी थीं। भारतीय वायुसेना-अधिनियम भारतीय सेना-अधिनियम के समूचे पर बनाया गया था, पर भारतीय नौसेना (अनुशासन)-अधिनियम केवल दू० के० नौसेना अनुशासन-अधिनियम को कुछ व्यवहार के साथ संशोधित इच्छित नेवी पर लागू कर देता था।

तीनों सेनाओं के इन अधिनियमों का पुनरीक्षण करने की जरूरत कुछ समय में अनुभव की जा रही थी। उनके कुछ उदाहरण पहले ही पुराने पड़ चुके थे और बर्तनी जरूरतों की पूर्ति के लिए आवश्यक निम्न हूँ थे। ११ अप्रैल, १९४७ के बाद प्रत्यक्ष कारणों से पुनरीक्षण की जरूरत और भी प्रबल हो गयी। इसलिए यह तब किया गया कि तीनों ही अधिनियमों को पुनरीक्षित किया जाए, (क) ताकि कुछ अन्य सम्बद्ध अधिनियमों के जरूरी उदाहरण शामिल करते हुए उनको स्वतंत्र संहिता बना दिया जाए, (ख) उनको नये सांविधानिक ढाँचे और आज की जरूरतों के अनुसार अनुकूलित किया जाए और (ग) एक ओर तो सेना-अधिनियमों और नागर-क्रान्तियों के बीच का अंतर अंतरालों के दमों के मानने में यथासम्भव कम किया जाए और दूसरी ओर सेना-अधिनियमों के बने ही उदाहरणों के बीच असमानता सन्तुष्ट की जाए। उद्देश्य यह था कि प्रत्येक सेना की विशेष जरूरत के अनुसार ही उसका रूप और व्यवस्था रखी जाए। पुनरीक्षण का कार्य करने के लिए जनवरी, १९४८ में मजिस्ट्रेट हाईकोर्ट का एक प्रसिद्ध बर्कोले एसा-अपवादन में निम्नलिखित किया गया। आरम्भ में तीनों सेनाओं की अनुशासन-संहिताओं को एक ही अधिनियम के रूप में सम्मिलित करने की सम्भावना पर विचार किया गया। पर परीक्षा करने में पता चला कि जरूरतों और परम्पराओं में, एक सेना में असादा अन्तर रहने के कारण, ऐसा करना सम्भव नहीं है। इसलिए यह फैसला किया गया कि अधिनियम अलग-अलग बनाने हों, पर उनके उद्देश्य, जरूरत अन्तर और अनुकूलनों के बावजूद, एक बने हो रहें।

पननेना और वायुसेना-अधिनियमों का पुनरीक्षण १९६८ में पूरा हो गया, पर भारतीय नौसेना (अनुशासन)-अधिनियम के बारे में यह पूछा होना सम्भव न था, क्योंकि यह तो, दू० के० नौसेना (अनुशासन)-अधिनियम को अनुकूल हेरफेर के बाद, भारतीय नौसेना पर लागू मान कर देता था। साथ ही इन बीच दू० के० में भी एक विशेष समिति गठित

नौसेना-अधिनियम के पुनरीक्षण के प्रश्न पर विचार करने के लिए नियुक्त की जा चुकी थी। यह समझा गया कि उक्त समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर सेना लाभकर होगा और उसके बाद ही भारतीय अधिनियम का पुनरीक्षण किया जाय। पर यह देखा गया कि पुनरीक्षित बलसेना और वायुसेना-विधेयकों का सूत्रपात करने के लिए, जिनका प्राकल्प बन चुका था, पुनरीक्षित नौसेना विधेयक के पूरे होने की प्रतीक्षा करना अनावश्यक था।

दोनों अधिनियमों के पुनरीक्षित संस्करण में दण्ड के उपबन्धों की सुक्ति-संगत बनाया गया। भारतीय सेना-अधिनियम, १९११ कुछ दण्डों के बारे में कठोर था और अपराधों की सव्यापिताने में अपर्याप्त था। पुनरीक्षित विधेयकों में, अधिकतम दण्ड में, भारतीय दण्ड-संहिताओं या देश की अन्य दण्डिक विधियों की तरह, प्रत्येक अपराध या अपराधों के समूह के अनुसार अन्तर रहता था और यह अपराध या अपराधों की गुरुता के अनुसार था। विभिन्न स्थितियों में अपराध की गुरुता के अनुसार दण्डों का श्रेणीकरण करने का भी प्रयास किया गया और अपराध जानबूझकर या सत्रिय सेवा के समय किये जाने पर दण्ड ज्यादा उच्च बना दिया गया। दोनों विधेयकों के बीच पूर्ण एकस्यता रखना न तो सम्भव ही समझा गया और न वांछनीय ही, पर यथासम्भव स्पष्ट असमानताएँ हटा दी गयीं। कोर्ट मार्शल में, अभ्याय के अवसर स्मृततम करने के लिए भी, व्यवस्था की गयी और साथ ही इन कोर्टों की प्राप्ति और उत्तरदायित्व भी बड़ा दिये गये। यह भी व्यवस्था की गयी कि नया सेना-अधिनियम उन देशों रियासतों की सेनाओं पर भी लागू होगा, जो भारत-संघ में सम्मिलित हो चुकी हैं। दोनों विधेयकों के बीच एकमात्र महत्वपूर्ण अन्तर यह था कि बलसेना के लिए सशस्त्र कोर्ट मार्शल की व्यवस्था थी, पर वायुसेना के लिए नहीं। यह बलसेना और वायुसेना के रंगस्टों के प्रकार में अन्तर के कारण था, सामान्य वायुसेना के रंगस्ट ज्यादा विरहित थे।

दोनों विधेयकों के तैयार होने तक सविधान-सभा ने नया सविधान स्वीकार कर लिया था। सविधान के अनुच्छेद ३१ में व्यवस्था है कि संसद सेनाओं के सदस्यों पर लागू होने के मामले में मूल अधिकार प्रतिबन्धित या निरास्त किये जा सकेंगे। इस बारे में उपर्युक्त उपबन्ध बलसेना और वायुसेना-विधेयकों में शामिल कर लिये गये। इस पक्ष को इस सन्दर्भ में आगे चलकर लिखा गया है।

बलसेना और वायुसेना-अधिनियम भारत की सविधान सभा (विधायी) में दिसम्बर, १९४६ में पेश किये गये और वे अग्रे, १९५० में पास हो गये। अधिनियम ने केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति दी कि वह अधिनियम के उपबन्धों की प्रभावशीलता के लिए नियम बना सकेगी। बलसेना-अधिनियम-नियम, १९५० और वायुसेना-अधिनियम-नियम, १९५० को २२ जुलाई, १९५० को प्रख्याति किया गया और अधिनियम उसी तारीख में प्रभावशील हो गये। सेना-अधिनियम-नियम, १९५० की जगह पर बाद में सेना-नियम, १९५४ बनये गये।

संगठित नौसेना विधेयक समूह में मई, १९५७ में पेश किये दिसम्बर, १९५७ में पास किया गया। विशेष बनाउ समय प्रथम उद्देश्य यह था कि नौसेना सम्बन्धी कानून स्वीकृत पूर्ण हो जाय। साथ ही यू०के० में ब्रिटिश नौसेना-संहिता के पुनरीक्षण के प्रश्न की जांच करना व लिए बनायी गयी समिति की रिपोर्ट पर भी विचार किया गया।

नौसेना-अधिनियम, १९५७ एक स्वतः पूर्ण संहिता है और इसमें साथ-साथ दो व्यवस्थाएँ भी हैं : (क) नौसेना के सदस्यों पर, मूल नियमों के लागू होने पर, प्रतिबन्ध लगाना, जैसा कि थलसेना-अधिनियम और वायुसेना-अधिनियम में किया गया था, (ख) मृत अधिकारियों और नाविकों की सम्पदाओं का समेटा जाना—जिसके बारे में थलसेना और वायुसेना पर लागू होने के लिए एक अलग अधिनियम है, और (ग) नौसेना के जज एडवोकेट जनरल द्वारा कोर्ट मार्शल की कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा का प्रावधान भी ।

पोत का कमान-अधिकारी सभी अपराधों की सक्षिप्त जाँच कर सकता है, पर यह ध्यान है कि वह ३ मास से ज्यादा का बन्दोकरण या निरोध का दण्ड नहीं दे सकता । सक्षिप्त कार्यविधि अधिनियम के अधीन बनाये गये साविधिक विनियमों में विहित की गयी है । कमान-अधिकारी को दण्ड की शक्ति पोत के अन्य अधिकारियों को प्रत्यापोषित करने की, शक्ति है और वह जिस सीमा तक प्रत्यापोषण कर सकता है, वह विनियमों में दे दी गयी है ।

यहाँ पर कोर्ट मार्शल-पद्धति का सक्षिप्त उल्लेख किया जा सकता है, (जिसका शब्दार्थ अर्प सैनिक न्यायालय है) जो सेनाओं के सदस्यों द्वारा किये गये अपराधों के लिए, सरासरी सेनाओं में ही, विसिष्टत चलती है । सशस्त्र सेनाओं की कार्यकुशलता के लिए अनुशासन का बड़ा ही महत्व है और अपराधों के लिए दण्ड, न्याय के सत्य का पूरा ध्यान रखते हुए, तेजी से और प्रभावी रूप में दिया जाना चाहिये । सरासरी सेना के व्यक्तियों को सेवाकाल में किये गये अपराधों का दण्ड देने के लिए या अनुशासन प्रदर्शित करने के लिए, कानून की सामान्य प्रक्रिया के अधीन रखना स्पष्ट ही असम्भव है । इसलिए पारी दुनिया को सशस्त्र सेनाओं में कोर्ट मार्शल पद्धति प्रचलित रही है । थलसेना और वायुसेना में साधारणतः कोर्ट मार्शलें तीन प्रकार की होती हैं, नामतः साधारण कोर्ट मार्शल, जिला कोर्ट मार्शल और सक्षिप्त साधारण कोर्ट मार्शल । कोर्ट मार्शल का संयोजन केंद्रीय सरकार या स्टाफ-प्रमुख या केंद्रीय सरकार या स्टाफ-प्रमुख द्वारा, इस प्रयोजन से सशक्त बनाये गये किसी अधिकारी द्वारा, किया जा सकता है । थलसेना में एक चौथे प्रकार की भी कोर्ट मार्शल होती है, जिसे सक्षिप्त कोर्ट मार्शल कहते हैं और जो गैर कमीशन-प्राप्त अधिकारियों और अन्य पदधारियों के लिए होती है और केवल सम्बन्धित कमान-अधिकारी ही इन कोर्टों का गठन करता है । लेकिन सक्षिप्त कोर्ट मार्शल की कार्यवाही में हमेशा दो अन्य अधिकारी, जिनका कमी० अधि० रहने है, जिनको इस रूप में शपथ/प्रतिज्ञान नहीं दिलाया जाता । सक्षिप्त कोर्ट मार्शल भारतीय थलसेना में ही होती है । इसे बंगाल सेना में १९५७ में मंदर के समय चालू किया गया था, ताकि सैन्य अरराधियों का निपटारा तुरन्त और प्रभावी रूप में करने के लिए रेजीमेंट-कमान-अधिकारियों के हाथ मजबूत किये जा सकें । यह पद्धति अनुशासन बनाये रखने में अपनी उपयोगिता सिद्ध कर चुकी है और अब वह एक ऐसी न्यायाधिकरण के रूप में है, जो अन्य पदधारियों की जाँच के लिए ज्यादातर प्रयोग में आती है ।

विधि प्रकार की कोर्ट मार्शल की रचना सम्बन्धित अधिनियम में दे दी गयी है । प्रायः साधारण कोर्ट मार्शल में, और कभी-कभी जिला कोर्ट मार्शल में भी, एक जज एडवोकेट रहता है, जिसका काम कार्यवाही के विधिक पहलुओं के बारे में कोर्ट की सलाह देना है ।

लेकिन अनियोजक और अभियुक्त दोनों को, आरोप या जांच से सम्बन्धित कानून के किसी प्रश्न के बारे में, अपना मत रखने का हक है। नौसेना में भी जब एडवोकेट कोर्ट मार्शल को मदद करने है। किसी कोर्ट मार्शल के निष्कर्ष और दण्ड की पुष्टि अधिनियम में विहित बरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा करनी जरूरी होती है। तभी वह प्रभावी हो सकता है। नौसेना में स्थिति भिन्न है, जहाँ कुछ परिस्थितियों में केवल मृत्यु-दण्ड की ही पुष्टि अपेक्षित होती है। फिर अधिनियम के अन्तर्गत आने वाला कोई व्यक्ति, जो अपने को किन्हीं कोर्ट मार्शल के किसी आदेश द्वारा पीड़ित मानता है, निष्कर्ष या दण्ड की पुष्टि करने के लिए सशक्त माने गये किसी अधिकारी या प्राधिकारी के पास, एक याचिका भेज सकता है और पुष्टिकर्ता प्राधिकारी पास किये गये आदेश के सही, वैध या उचित होने के बारे में, अपने समाधान के लिए, उपयुक्त नदम उठा सकता है। किसी निष्कर्ष या दण्ड की पुष्टि के बाद भी याचिका, विहित किये गये पुष्टिकर्ता प्राधिकारी से कमान में, बरिष्ठ अधिकारी के पास या स्टाफ प्रमुख या केन्द्रीय सरकार के पास, भेजी जा सकती है, और ये अधिकारी जो आदेश ठीक समझें, दे सकते हैं। वे किसी कोर्ट मार्शल की कार्यवाही को इस आधार पर निरस्त कर सकते हैं कि वह अवैध या अन्यायोचित है। मृत्यु-दण्ड के प्रत्येक मामले में (नौसेना में पूर्वोत्तिहित सीमा तक छोड़कर) केन्द्रीय सरकार को पुष्टि जरूरी होती है और फाँसी तक तक नहीं दी जा सकती, जब तक कि सिद्धोप व्यक्ति को राष्ट्रपति के पास याचिका भेजने का अवसर न दे दिया जाय। किसी कोर्ट मार्शल के निष्कर्ष या दण्ड के विरुद्ध किसी विधि-न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। सेनाओं में कोर्ट मार्शल की बड़ी जिम्मेदारी, प्राधिकार और प्रतिष्ठा होती है। साथ ही पूरी सुरक्षा इस दृष्टि में बरती गयी है कि न्याय का दुर्वहन न हो पाये। किसी कोर्ट मार्शल द्वारा दिया गया दण्ड बरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा बढ़ाया नहीं जा सकता और उसका हस्तक्षेप दण्ड कम करने के ही रूप में हो सकता है।

सैन्य कानून के अन्तर्गत आने वाला कोई व्यक्ति यदि ऐसा नागरिक अपराध करता है, जो एक सैन्य अपराध भी है, तो उस पर सामान्य फौजदारी न्यायालय या कोर्टमार्शल द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है। सम्बन्धित विरचना का बमान-अधिकारी यह फैसला करने के लिए सक्षम है कि कार्यवाही किस न्यायालय में चलाई जाय, पर फौजदारी न्यायालय ऐसे अपराधों को जांच के लिए नागर अतिरिक्ता में सौंपने की माँग कर सकती है। ऐसी स्थिति में सैन्य-प्राधिकारी या वे यह माँग स्वीकार कर सकता है या वह मामला केन्द्रीय सरकार के पास आदेशार्थ भेज सकता है। सैन्य-प्राधिकारियों के पास इस दावे के पूरे कारण हो सकते हैं कि अपराधी की जाँच सामान्य फौजदारी न्यायालय में न करके कोर्ट मार्शल द्वारा की जाय। कभी-कभी दण्ड शीघ्र दिया जाना जरूरी हो सकता है या सैन्य-अनुशासन की दृष्टि से उसमें ज्यादा बठोर दण्ड दिया जाना आवश्यक हो सकता है, बिना कि साधारणतः फौजदारी न्यायालय देते हैं। इसलिए सैन्य-प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार को लिख सकते हैं कि किसी अपराधी की जाँच कोर्ट मार्शल करे, सामान्य असेनिज न्यायालय नहीं।

## कुछ मूल अधिकारों पर प्रतिबन्ध

संविधान सभी नागरिकों को मूल अधिकार प्रत्याभूत करता है, लेकिन अनुच्छेद ३३ में व्यवस्था है कि सशस्त्र सेना के सदस्यों पर लागू होने के मामले में ये मूल अधिकार संसद द्वारा प्रतिबन्धित या निरास्त किये जा सकते हैं, ताकि उनके कर्तव्यों का सम्पत्क निर्वहन और उनमें अनुशासन बनाने रखना आसानी से किया जा सके। ऐसी बात नहीं है कि सशस्त्र सेना के सदस्यों के ऊपर कोई नया प्रतिबन्ध लगाया जा रहा हो। नया संविधान लागू होने से पहले भारतीय नागरिकों को कोई भी शरणाग्रित अधिकार मिले हुए न थे। ये सर्वप्रमुख सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक णगरण्य के लिए पूर्णतः एक नया वस्तु थे।

यह सहज ही स्वीकार किया जायेगा कि असेैनिक कर्मचारियों पर लागू सामान्य अनुशासन-नियम सशस्त्र सेनाओं के लिए काफी नहीं हैं। संविधान के आरम्भ से काफ़ी पहले सशस्त्र सेनाओं के जो विनियम विद्यमान थे, वे मजदूर-संघ बनाने, प्रेस से सम्पर्क रखने आदि के बारे में सेनाओं के सदस्यों के ऊपर कुछ प्रतिबन्ध लगाते थे। ऐसे प्रतिबन्ध नये संविधान के अनुकूल न रहते। साविधिक व्यवस्था करने से पूर्व, सशस्त्र सेना (प्रकीर्ण उपबन्ध) अध्यादेश, १९५० (१९५० का आठवाँ) २३ जनवरी, १९५० को लागू किया गया, जिसने सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों पर विनिर्दिष्ट प्रतिबन्ध लगाने के बारे में नियम बनाने की शक्ति सरकार को प्रदान की।

जैसा पहले बताया जा चुका है, सेना-अधिनियम, १९५० और वायुसेना-अधिनियम, १९५०, जिनमें इन प्रतिबन्धों की व्यवस्था है, २२ जुलाई, १९५० से प्रभावी किये गये, जबकि अध्यादेश समाप्त हो गया। नौसेना में ये प्रतिबन्ध नौसेना (प्रकीर्ण उपबन्ध) अध्यादेश, १९५० (१९५० का २१वाँ) द्वारा लागू किये गये और बाद में सीमा ही उसकी जगह पर नौसेना (प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, १९५० (१९५० का ५७) लागू कर दिया गया। बाद में नौसेना अधिनियम १९५७ में जलरी उपबन्ध शामिल कर लिये गये।

इन साविधिक उपबन्धों के अधीन नियमित सशस्त्र सेनाओं में स्थिर नियोजन या भर्ती नहीं हो सकती, ऐसी कोर, विभाग, शाखा या इन सेनाओं के किसी हिस्से के अंगभूत या उससे सतान किसी अन्य निकाय को छोड़कर, जैसा कि केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर दे, पर यह प्रतिबन्ध नियमित सशस्त्र सेनाओं या उसको किसी शाखा की किसी सहायक सेवा के सम्भारण और खड़े करने सम्बन्धी किसी विद्यमान व्यवस्था पर रोक नहीं लगाता, जिनमें स्थिरता नामांकित होने या नियोजन की पात्र है।

ये प्रतिबन्ध सेनाओं के नियमों, विनियमों में व्यतिरेक बताये गये हैं।

सशस्त्र सेनाओं का कोई सदस्य किसी ट्रेड यूनियन या मजदूर-संघ का सदस्य, या किसी रूप में अपने सम्बन्ध, नहीं हो सकता। साथ ही वह केन्द्रीय सरकार से स्पष्ट मंजूरी लिए बिना किसी ऐसी सभा, संस्था या सङ्गठन में भाग में नहीं ले सकता, जो सशस्त्र सेनाओं का एक भाग हुआ अंग नहीं है। फिर भी वह अपने वरिष्ठ अधिकारों से पूर्वानुमति लेकर मनोरंजन या धार्मिक स्वयं की किसी सभा आदि में शामिल हो सकता है।

सशस्त्र सेनाओं का कोई सदस्य किसी दल, या राजनीतिक प्रयोजन से आयोजित किसी बैठक, या प्रदर्शन में उपस्थित नहीं हो सकता, न भाषण दे सकता है और न किसी अन्य रूप में भाग ले सकता है। न वह किसी राजनीतिक सत्ता या आन्दोलन में हो शामिल हो सकता है और न उसके लिए चन्दा ही दे सकता है। यह प्रतिबन्ध असेनिक सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू है।

सशस्त्र सेनाओं का कोई सदस्य ससद् या राज्य-विधान-मण्डल या किसी स्थानीय प्राधिकार या किसी अन्य सामाजिक निकाय के चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं बन सकता। उसे किसी उम्मीदवार के चुनाव का काम सक्रिय रूप से चलाने या आगे बढ़ाने की भी अनुमति नहीं है।

किसी लोकतन्त्र सरकार में सैनिक और असेनिक दोनों ही सेवाओं को राजनीतिक कार्य-कलाप में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाती। सैन्य-क्षेत्रों में राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव आन्दोलन चलाने की भी अनुमति नहीं दी जाती।

दूसरा प्रतिबन्ध यह है कि सशस्त्र सेना का कोई भी सदस्य राजनीतिक प्रश्न से सम्बन्ध किसी मामले पर या सेना के किसी विषय पर या सेना सम्बन्धी कोई जानकारी देने वाली कोई भी वस्तु (पुस्तक, पत्र या लेख समेत) प्रकाशित नहीं कर सकता, न वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्रेस से कोई सम्पर्क रख सकता है, न भाषण या रेडियो भाषण ही दे सकता है।

#### खण्ड ४ मूल पदोन्नति, नियुक्ति पदावधि और अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु

जैसा कि राष्ट्रीयकरण वाले अध्याय में पहले ही बताया जा चुका है, नये पदोन्नति नियम बनने तक, १९४८ के आरम्भ में कार्यवाहक पदोन्नतियों के लिए स्वीकृत अर्हकारी सेवाकाल तय कर दिया गया था। ये सीमाएँ राष्ट्रीयकरण में सुविधा देने के लिये रखी गयी थी और ऐसा करने में विभिन्न ओहदों में अधिकारियों की उपलब्धता को ध्यान में रखा गया था।

तीनों सेनाओं के अधिकारियों के लिये, विभिन्न ओहदों में मूल पदोन्नति के लिये, अपेक्षित न्यूनतम सेवाकाल, अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु और उच्चतर ओहदों पर नियुक्ति की पदावधि निर्दिष्ट करने के प्रश्न पर, १९६६ के अन्त की ओर विचार किया गया। तीनों सेनाओं की भिन्न-भिन्न स्थितियों और जटिलताओं के कारण उनके नियमों में बिल्कुल एकरूपता नहीं लायी जा सकती थी। उदाहरण के लिए चलमेना में, नौ सेना और वायुसेना की तुलना में, वही ज्यादा गरिष्ठ अधिकार उपलब्ध थे। फिर भी यथासम्भव समानता प्रदान करने का प्रयास किया गया। (जब तक कि तीनों सेनाओं को सामान्य सार्वजनिक सेवाएँ निर्दिष्ट न हो जाय और पदोन्नतियों और सेवानिवृत्तियों के प्रवाह समरूप न बनने लगे, कार्यवाहक ओहदों की पद्धति को जटिल बनी हो रहेगी।) स्थायी नियमित कर्मचारीयों के अन्य अधिकारियों के (चिकित्सा और पशुचिकित्सा अधिकारियों को छोड़ कर) बारे में आदेश मार्च,

१९५० में जारी कर दिये गये । इन आदेशों में विहित मेवा-सीमा १९५० में विद्यमान परिस्थितियों के अनुकूल तय की गयी थी ।

यदि मूल पदोन्नतियों के लिए ज्यादा सेवा-सीमा रखी जाती, तो मंजूर किये गये संवर्ग को मूल पदोन्नतियों द्वारा भरना सम्भव न होता । १९५५ तक अधिकारी पाँच अतिरिक्त वर्षों तक मेवा कर चुके थे । फिर १९४१ में, और मुद्रक के वर्षों में कमोशन पाने वाले लोगों की संख्या के कारण, बहुत से अधिकारी ऐसे थे, जो सेप्टी० कर्नल के ओहदे में मूल पदोन्नति के पात्र बन चुके थे । इतनी बड़ी संख्या में लोगों के उपलब्ध होने और सीमित रिक्त-स्थानों की दृष्टि में यह जरूरी था कि चयन कठोरता से और योग्यता के आधार पर किया जाय । इस लिये पूरे दल पर पुनर्विचार किया गया और जनवरी, १९५० में नये आदेश निकाले गये ।

### यल-सेना

स्थायी कमोशनपारी सेना अधिकारियों (चिकित्सा, दन्तचिकित्सा, घुड़सवार, पशु-चिकित्सा, फार्म और विशेष सूची अधिकारियों को छोड़ कर) पर सामु, बुनियादी उपबन्ध इस प्रकार है

सेप्टी० कर्नल के मूल ओहदे या उच्चतर ओहदों की पदोन्नति चयन द्वारा की जाती है । यह निम्न ओहदों में काल-मान से होता है, नामतः सेप्टीनैट के ओहदे के लिये दो वर्ष, कैप्टन के ओहदे के लिए छ. वर्ष, और मेजर के ओहदे के लिये १३ साल, बशर्ते कि अधिकारी विहित व्यावसायिक परीक्षा पास कर लें और सब तरह से योग्य पाये जायें । जो चयन द्वारा सेप्टी० कर्नल के मूल ओहदे में पदोन्नति नहीं पा सकते, उनको उस पद पर, काल-मान द्वारा २४ वर्ष की मेवा पूरी करने पर, पदोन्नति दी जाती है । सेप्टीनैट कर्नल और आगे के वर्षों पर मूल संवर्ग में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये, चयन द्वारा पदोन्नति का पात्र होने के लिए, कमोशन ग्रांट ऐसा का न्यूनतम अपेक्षित काल सेप्टी० कर्नल के लिये १६ साल, कर्नल के लिये २० साल, रिजर्वियर के लिये २३ साल, मेजर जनरल के लिये २५ साल और सेप्टी० जनरल के लिये २८ साल है (जनरल के लिए कोई सेवा-सीमा विहित नहीं की गयी है ।)

उच्चतर पदों में नियुक्तियाँ पदावधि के आधार पर होती हैं । सेप्टी० कर्नल और आगे के मूल पदों में नियुक्ति की पदावधि ४ साल है और आगे की पदावधि, यदि कोई हो, तो चार साल से अधिक होती है । विभिन्न ओहदों के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति की भी आयु सीमाएँ हैं । इनको नीचे बताया जा रहा है :

ओहदा	पदावधियों की संख्या	अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु
जनरल	एक	५८ वर्ष
सेप्टीनैट जनरल	एक	५६ वर्ष
मेजर जनरल	दो	५४ वर्ष
रिजर्वियर	दो	५० वर्ष
कर्नल	दो	५० वर्ष
सेप्टीनैट कर्नल और नीचे	—	४८ वर्ष



चीफ आफ आर्मी स्टाफ की पदावधि तीन साल है।

विहित पदावधि पूरी करने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर, जो भी पहले हो, एक अधिकारी को सेवा निवृत्त होना पड़ता है। निम्नतर ओहदे के लिए, अधिकारियों को कमी की पूर्ति करने के उद्देश्य से, अनिवार्य सेवानिवृत्ति की ये आयुसीमाएँ, समय-समय पर, मेजर या नीचे के पदों के लिए, ५० साल तक की जाती रही हैं, ५२ साल इजीनियर अधिकारियों के लिए और लेफ्टीनेंट कर्नल के पद के अन्य लोगों के लिये ५० साल, कर्नल आदि पदों के इजीनियर के लिए ५२ साल।

मेजा-चिकित्सा कोर में लेफ्टीनंट कर्नल के ओहदे पर मूल पदोन्नति काल-मान द्वारा दी जाती है। कर्नल या आगे के ओहदे में मूल पदोन्नति चयन द्वारा दी जाती है। न्यूनतम अपेक्षित सेवाकाल कर्नल के लिये २० साल, त्रिगेडियर के लिए २२ साल, मेजर जनरल के लिए २४ साल होता है और लेफ्टी० जनरल के लिये कोई सीमा नहीं होती। अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिये आयु-सीमा लेफ्टी० कर्नल और नीचे के पदों के लिए ५५ वर्ष है, कर्नल और त्रिगेडियर के लिए ५७ वर्ष, मेजर जनरल के लिए ५९ वर्ष और लेफ्टी० जनरल के लिए ६० वर्ष। प्रत्येक ओहदे में सामान्य पदावधि ४ वर्ष या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु तक, जो भी पहले पड़े, होती है। ऐसे ही विनियम सेना-दम्तचिकित्सा-कोर के लिए हैं (अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु लेफ्टी० कर्नल और नीचे के लिए ५५ साल और त्रिगेडियर के लिये ५७ साल है।) घुड़-सवार और पशुचिकित्सा कोरों के लिए (अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयुसीमा लेफ्टी० कर्नल और नीचे के लिए ५५ साल और कर्नल और ऊपर के लिए ५७ साल है।) संन्य नर्सिंग-सेवा और विशेष सूची के अधिकारियों के लिये भी ऐसे ही विनियम हैं।

### नी सेना

लेफ्टी० कमांडर समेत तब की मूल पदोन्नतियाँ काल-मान के अनुसार चलती हैं, कमांडर और ऊपर के पदों के लिए मूल पदोन्नति चयन द्वारा की जाती है। (कमांडर के मूल पद पर पदोन्नति न पाने वाले अधिकारी, सेना के लेफ्टी० कर्नल पद के अधिकारियों की तरह, २४ वर्ष का सेवा-काल पूरा करने के बाद उस पद पर पदोन्नति पा सकते हैं।) एग्जीक्यूटिव, इजीनियरी, विज्ञानी और पूर्ति तथा सचिवालय-शाखाओं के अधिकारी, लेफ्टीनेंट के पद पर आठ साल की बरिष्ठता प्राप्त करने के बाद, लेफ्टीनेंट कमांडर के रूप में पदोन्नति पा सकते हैं। लेफ्टीनेंट कमांडर से कमांडर के रूप में पदोन्नति उन अधिकारियों में से चयन करके दी जाती है, जिनकी एग्जीक्यूटिव शाखा में लेफ्टीनेंट कमांडर के रूप में बरिष्ठता २ से ८ साल तक की होती है, इजीनियरी और विज्ञानी शाखा में २ से १० साल और पूर्ति तथा सचिवालय शाखा में ९ से १० साल। कमांडर से ब्रेटन की पदोन्नति उन अधिकारियों में से चयन करके होती है, जो कमांडर के पद पर ४ साल की बरिष्ठता प्राप्त कर चुके हैं, ब्रेटन से रोयर एडमिरल की पदोन्नति ब्रेटन पद के अधिकारियों में से चयन द्वारा दी जाती है (नौजमा में कमांडर ओहदे की अपेक्षा एक नियुक्ति मानी जाती है।)

ब्रेटन और नीचे के अधिकारियों के लिये निश्चित सेवा-अदावधि नहीं होती। रोयर

एडमिरल के मूल पद में सेवा-पदावधि तीन साल होती है, जिसे तीन साल में अनधिक दूसरी पदावधि तक बढ़ाया जा सकता है। चौक आफ नैवल स्टाफ की पदावधि तीन साल है।

सभी शाखाओं के अधिकारियों (शाखा-मूवों-अधिकारियों, शिक्षण-शाखा और चिकित्सा-शाखा के अधिकारियों को छोड़ कर) की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु इस तरह है - वाइस एडमिरल ६० साल। रीयर एडमिरल ५७ साल, कैप्टेन ५५ साल, कमांडर ५० साल, लेफ्टी-नैंट कमांडर और नीचे ४८ साल। इन उपबन्धों के बावजूद किसी भी शाखा के अधिकारी ४० साल की आयु के बाद, औचित्य के आधार पर सरकार द्वारा सेवानिवृत्त किमे जा सकते हैं। अधिकारियों को अपने ओहदे की अधिकतम पेंशन प्राप्त कर चुकने पर, सामान्यतः सेवानिवृत्त-मूवों पर रख दिया जाता है, मगर अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु में यह पहले हो जाय तत्प्रायः ४८ साल की आयु से पहले नहीं।

### वायु-सेना

वायुसेना में, बिग कमांडर के मूल ओहदे में पदोन्नति के लिए, एक अधिकारी को स्वेडेडन सीडर के रूप में न्यूनतम तीन साल की सेवा-वरिष्ठता प्राप्त करनी होती है, पुप कैप्टेन के लिए मूल पदधारी बिग कमांडर के रूप में ४ साल, एयर कमांडर के लिए मूल पदधारी पुप कैप्टेन के रूप में ३ साल, और एयर वाइस मार्शल के लिए मूल पदधारी एयर कमांडर के रूप में ३ साल।

एयर कमांडर और ऊपर नियुक्ति-पदावधि चार साल होगी। प्राप्य पदावधियाँ एयर कमांडर के लिए दो साल, एयर वाइस मार्शल के लिए एक और एयर मार्शल के लिए एक साल है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति आयु इस तरह है :

मूल ओहदा	सामान्य कर्तव्य	धरातल कर्तव्य
स्वेडेडन सीडर और नीचे	४८	५२
बिग कमांडर	४८	५२
पुप कैप्टेन	५०	५५
एयर कमांडर	५२	५५
एयर वाइस मार्शल	५५	५५

चौक आफ एयर स्टाफ ( एयर चौक मार्शल ) की पदावधि तीन साल है।

### खण्ड ५ : रक्षा-सेवाओं में असेैनिक जन

रक्षा सेवाओं के असेैनिक-जनों की सेवा शर्तें मुफारी और युक्तिसंगत की गयीं। ज्यादा महत्वपूर्ण कार्रवाईयों का संश्लिष्ट उल्लेख ही यहाँ पर किया जा रहा है।

### १९४७ में वेतन-मानों का पुनरीक्षण

१९४७ के पहले रक्षा-स्थापनाओं में काम करने वाले असेैनिक कर्मचारों साधारणतः

सरकार द्वारा विहित प्रणामी वेतन-मानों पर काम करते थे, या स्थानीय अधिकारियों द्वारा तय की गयी दैनिक दरों पर, जिनको 'नैरिक' दर कहा जाता था। आइनेंस कारखानों के कामकर दैनिक वेतन दरों पर थे, पर जिनो व्यवसाय के कामकरों के लिए भी ये दरें सभी कारखानों में एकदम न थी। फनस्वरूप कुल मिलाकर सभी कारखानों में ३०८ व्यवसाय थे और उनके लिए २४६ वेतन-मान थे। कामकरों की कुशलता की मात्रा के अनुसार कोई वर्गीकरण न था और न वेतन में एकरूपता थी।

रक्षा-सेवा अनुमान से वेतन पाने वाले असैनिक-जनो की सेवा-दशाओं की जाँच, भारत सरकार द्वारा १९४६ में नियुक्त किये गये केन्द्रीय वेतन-आयोग के विचारणीय विषयों में रखी गई और बाद में यथोचित संशोधन किया गया। अपने प्रतिवेदन में आयोग ने कहा कि कर्मचारियों की इन श्रेणियों की सेवा-शर्तों-निबन्धनों की जाँच, स्पष्ट कारणों से, उतनी व्यापक और पूर्ण नहीं हो सकती, जैसी अन्य असैनिक कर्मचारियों की। फिर भी आयोग ने रक्षा-स्थापनाओं के असैनिक कर्मचारियों के वेतन-मानों के बारे में कुछ स्थूल सिफारिशें की।

आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार के रक्षा-मन्त्रालय ने रक्षा-सेवाओं में असैनिक जन (वेतन पुनरोक्षण) नियम, १९४७ प्रख्यापित किये, जिसमें रक्षा-सेवाओं के असैनिक जनो के वेतन-मान विहित किये गये थे।

(फिर भी इन नियमों में आइनेंस कारखानों के कामकरों के कुछ अस्थायी वेतन-मान ही विहित किये गये थे, क्योंकि विभिन्न श्रेणियों के कामकरों को उनकी कुशलता के अनुसार उपयुक्त वेतन मान में रखने में दिक्कत थी। बाद में इन कामकरों के मामलों की प्योरेवार जाँच की गयी)।

इस पुनरोक्षण को एक महत्वपूर्ण ध्यान यह थी कि नियमित प्रकार के काम तक के लिए असैनिक-जनो को दैनिक वेतन-दरों पर खाने का चरन ग्रहण कर दिया गया। उनकी विहित वेतन-मानों में मासिक वेतन-दरों पर कर दिया गया।

### अतिरिक्त अस्थायी स्थापना की समाप्ति

दूसरा महत्वपूर्ण सुधार अतिरिक्त अस्थायी स्थापना को समाप्त करना था। रक्षा-सेवाओं के अस्थायी असैनिक कर्मचारियों की कई श्रेणियाँ थी, नामतः अतिरिक्त अस्थायी स्थापना (सेना आइनेंस-बोर्ड में), अस्थायी स्थापना (आइनेंस कारखानों में) अतिरिक्त अस्थायी कारीगर और आरुस्मिक स्थापना (सेना इन्वेनियरी सेवा में)। ये सभी तदर्थ सेना-दानों के अधीन आते थे और साधारणतः स्थानीय आधार पर रक्षा-संस्थापनों द्वारा, उनकी प्रदत्त शक्तियों के अधीन, दैनिक या मासिक वेतन दर पर रखे जाते थे। इन अतिरिक्त अस्थायी स्थापनाओं में मासिक वेतन दर पर रखे गये व्यक्तियों के लिए भी सेवा की एक दान यह थी 'काम नहीं तो वेतन नहीं'। कुछ स्थापनाओं में यह चलन था कि अस्थायी कर्मचारियों को एकदम ३१ मार्च को (वित्तीय साल के आखिरी दिन) सेवानिवृत्त कर दिया जाए और उनको हर साल १ अप्रैल को पुनः काम पर लगा लिया जाए। पदों की मासानुमान आधार तक पर मज़ूर किया जाता था। कर्मचारियों का स्थानान्तरण जहाँ भरती हुए थे वहाँ से वही अन्य

रक्षा-संस्थापन में नहीं किया जा सकता था। अन्तःऔद्योगिक धर्मियों तक में अतिरिक्त अस्थायी स्थापना में पद अधिक अनुदान से मजूर किये जाते थे। दूसरे अपों में उन्हें कोई सेवानुरता प्राप्त न थी और उनकी नौकरी केवल काम के भार और पैसा उपलब्ध रहने पर निर्भर थी। साथ ही, चूंकि स्थानीय अधिकारियों को किसी भी वेतन-दर पर पद खड़े करने की शक्ति थी—जो केवल विनिर्दिष्ट ज़रूरी सीमा के ही अंदर रहती थी—इसलिए विभिन्न रक्षा स्थापनाओं में वेतन-दरें तय करने का कोई एक मानक न था। साथ ही चूंकि बर्ग-बारी 'काम नहीं तो वेतन नहीं' आधार पर रखे जाते थे, इसलिए यह स्वाभाविक प्रवृत्ति थी कि मजूरी कुछ बड़ी-चड़ी रहे। फलतः ऐसे उदाहरण थे कि नियमित स्थापना के अस्थायी सदस्य, उत्कृष्ट बुद्धि जाति अर्जित करने के लिए अतिरिक्त अस्थायी स्थापना पर चले जाते थे और नियमित स्थापना में स्थायी नियुक्ति की सम्भावना का भी त्याग न रखते थे। ऐसे भी मामले थे कि अ० अ० स्था० के सदस्य अपने अस्थायी वित्तीय स्थानों को छोड़कर नियमित स्थापना में चले जाते थे। मने ही कम वेतन-दर हो, लेकिन आने चलकर अच्छे भविष्य की आशा में वे ऐसा करते थे।

इस तरह अ० अ० स्था० की सेवा-शर्तें स्थानीय हानतों के अनुसार भिन्न-भिन्न थीं। अधिकांश मामलों में सेवानिवृत्ति के लाभों की कोई व्यवस्था न थी। फिर भी अनुग्रह के रूप में उन्नयन या पेन्शन देने की पद्धति थी, पर इसके लिए जो शर्तें पूरी करनी होती थीं, वे इतनी कठोर थीं कि केवल लगभग संस्था में ही लोग इनमें लाभ उठा पाते थे। कारखानों में ३० से ४० साल तक की सेवा के लिए छ. महीने के वेतन से अधिक का उन्नयन साधारणतः दिया जाता था। कुछ संस्थानों में अंशदायी भविष्य निधि की योजना चली थी, जिसके अग्रे सरकार किसी कर्मचारी द्वारा दी गयी राशि का ७१ प्रतिशत सरकार देती थी और कर्मचारी अपने वेतन का ८९ प्रतिशत तक दे सकता था। वे कोई भी आकस्मिक छुट्टी या पूरे वेतन पर बिफ्रिस्त-छुट्टी न पा सकते थे।

अमेरिकी की दैनिक वेतन-दर पर लगाने का चयन समाप्त हो जाने पर अ० अ० स्था० आदि के कर्मचारियों की सेवा शर्तों को उदार बना दिया गया। १ अगस्त, १९४६ से इन सारे कर्मचारियों की औद्योगिक और अनीद्योगिक इन दो धर्मियों में बांटा गया। अनी-द्योगिक वर्ग में कर्च-स्थापना थी और इन्फ्रामैन, टेनोफोन आरेक्टर, स्टोरमोर, स्टोरमैन, वैज्ञानिक और प्रयोगशाला-सहायक, अस्त्राल स्थापना आदि आते थे। औद्योगिक धर्मियों को नियमित स्थापना पर रखा गया और वह से पेन्शन, भविष्य निधि, छुट्टी, बिफ्रिस्त-मुविषा आदि के मामले में रक्षा-सेवाओं के नियमित अमेरिकी कर्मचारियों पर लागू विनियमों के अन्तर्गत सभी सामान्य लाभ पा सकते हैं।

औद्योगिक स्थापना में कारीगर और कामकर तथा अनुदान अधिकारी भी आते हैं। औद्योगिक कर्मचारियों की भी १ अगस्त, १९४६ से अंशदायी भविष्य निधि का लाभ प्रदान किया गया। उस तारीख से पहले की सभी सेवा के लिए हर साल की सेवा के बदले आने वाले वे वेतन के हिसाब में उन्नयन की मजूर किया गया। यह उन्नयन आनु-वांशिक अंगुलि

या छुटनी के कारण सामान्य सेवामुक्ति के समय दिया जाता था। सेवाकाल में औद्योगिक कर्मचारी को मृत्यु की स्थिति में उपदान उसके आश्रितों को भी प्रदेय था।

समय-समय पर कुछ और रियायतें भी मजूर की गयीं, जैसे स्थानान्तरण पर यात्रा-भत्ता (पहले कामवर को अपने खर्च पर ही नयी जगह जाना होता था) और प्रत्यावर्तन भत्ता, जब पूरी स्थापना किसी अन्य जगह भेजी जाय।

अतिरिक्त अस्थायी स्थापना को समाप्त करने और इसके कर्मचारियों को नियमित स्थापना में मिला लेने का निर्णय लेते समय यह तय किया गया कि अ० अ० स्था० के व्यक्तियों द्वारा १ अगस्त, १९४६ से पहले की गयी सेवा, नियमित स्थापना में उनकी वरिष्ठता स्थिर करने के प्रयोजन से न जोड़ी जायेगी। फिर भी एक ही श्रेणी के कर्मचारियों के बीच बने आते हुए भेद को दूर करने और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अ० अ० स्था० की सेवा नियमित स्थापना की सेवा के समतुल्य नहीं मानी जा सकती, यह भी तय किया गया कि जनवरी, १९५५ में अ० अ० स्था० में समरूप बलकें ग्रेडों की आधी सेवा वरिष्ठता के लिए जोड़ी ली जाय। अ० अ० स्था० के कुछ बलकें १९२१ से भरती हुए चने आ रहे थे। लेकिन यह निर्णय न लेने पर वे सभी बलकों को नियमित स्थापना से कनिष्ठ हो जाते। १९४८ से मृतपूर्व अ० अ० स्था० की चौथाई सेवा, जो ज्यादा से ज्यादा चौब साल तक सीमित रखी गयी, पेंशन के लिए भी जोड़ी जाने लगी। १ नवम्बर, १९५६ से इसे १ अगस्त, १९४६ में पहले की गयी सेवा के आधे तक कर दिया गया और कोई ऊपरी अधिकतम सीमा नहीं रखी गयी।

१ अगस्त, १९४६ से पहले सेवा-समाप्ति की पूर्व सूचना का काल उस पद्धति पर निर्भर था, जिसके अनुसार अर्धैनिक कर्मचारी को वेतन मिलता था। यदि वे मासिक रूप से वेतन पाते थे, तो उनको एक मास की पूर्व सूचना दी जाती थी। यदि वे दैनिक वेतन पर थे, किन्तु वेतन पल्लवार या मासान्त में मिलता था, तो उनको दो हफ्ते की पूर्व सूचना दी जाती थी और यदि सप्ताहान्त में वेतन मिलता था तो एक सप्ताह की। इसके स्थान पर दस साल या ज्यादा के सेवाकाल वाले औद्योगिक कर्मचारी अब सेवा मुक्ति के लिए तीन मास की पूर्व सूचना या उसके बढ़ने तीन मास का वेतन पाने के अधिकारी हैं और १० साल से कम सेवाकाल वाले सेवामुक्ति के लिए १ महीने की पूर्व सूचना या बढ़ने में एक महीने का वेतन पाने के अधिकारी हैं।

अर्ध स्थायी और स्थायी औद्योगिक कर्मचारी अब तीन महीने की पूर्व सूचना या बढ़ने में तीन महीने का वेतन पाने के अधिकारी हैं, जबकि अस्थायी कर्मचारी एक महीने की पूर्व सूचना या बढ़ने में एक महीने का वेतन पाने के अधिकारी हैं। औद्योगिक और अर्ध-औद्योगिक दोनों ही प्रकार के कर्मचारियों के लिए चिन्तना-मुविधाओं में भी सुधार हुआ है।

### बल्दाणवाना-समिति की नियुक्ति

रक्षा-स्थापनाओं में रक्षा-सेवाओं में अर्धैनिक (वेतन पुनरीक्षण) नियम, १९४७ के अधीन विहित वेतन-मान सामान्यन सन्तोषजनक माने गये, पर आइर्नस और बम्ब-बारमानों की

विभिन्न स्थिति को देखते हुए यह जरूरी समझा गया कि उसके कामगरो के वेतन-मानों की कोर-वार जाँच की जाय। इन कामगरो पर मासिक वेतनमान की पद्धति लागू करने में देर न करने के लिए उनके हेतु १९४७ के वेतन नियमों में कुछ अनन्तिम वेतन मान तब तक के लिए मंजूर किये गये, जब तक अन्तिम वेतन-मान तय न कर दिये जायें। आर्डनेंस कारखाना-सेवा के एक अधिकारी को, आर्डनेंस-कारखानों के सभी वर्गों के कर्मचारियों के लिए, यथासंभव श्रमिकों के प्रतिनिधियों से परामर्श करते हुए, जाँच करके उपयुक्त वेतन मानों की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया। उनसे विभिन्न व्यवसायों के लिए अपेक्षित भिन्न मात्रा की कुशलता का भी ध्यान रखने को कहा गया। उनके प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद सरकार ने सितम्बर, १९४६ में आदेश निकाले और कारखानों के कामगरो के लिए अन्तिम प्रणामी वेतन-मान निर्धारित कर दिये।

रक्षा-स्थापना के कर्मचारियों का महासंघ वेतन-ढाँचे समेत अनुसूचित क्षेत्र-वातों के विभिन्न पहलुओं में सन्तुष्ट नहीं था, इसलिए सरकार ने सितम्बर, १९४० में उनकी 'शिकायतों' की जाँच करके, प्रतिवेदन देने के लिए एक समिति नियुक्त की।\*

समिति जरूरी आधार-सामग्री इकट्ठी कर चुकी थी कि दुर्भाग्य से दिसम्बर, १९४१ में अध्यक्ष की मृत्यु हो गयी। और समिति का काम अन्य दो सदस्य चलाते रहे। 'समिति' का प्रतिवेदन सितम्बर, १९४२ में सरकार को सौंपा गया, लेकिन दोनों सदस्यों की सिफारिशों में अनेक बातों पर मतभेद था।

समिति की सिफारिशों के आधार पर और भारत सरकार की सचिव-समिति की जाँच के बाद, सरकार इस निष्कर्ष पर पहुँची कि आर्डनेंस और वल-कारखानों के लिए विहित वेतन-मान केन्द्रीय वेतन-आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने के लिए एक सन्तोषजनक आधार है और कारखानों के विद्यमान वेतन ढाँचे को बदलने का कोई कारण नहीं है। पर रक्षा-स्थापना की कुछ श्रेणी के पदों के वेतन मानों में कुछ विसंगतियाँ थी। उनको ठीक करने के लिए आदेश जारी कर दिये गये।

सरकार ने ये रियायतें और मंजूर कीं :

(१) रक्षा असैनिक-जनों के लिए कुछ सस्थापनों में सस्ते परिवहन की व्यवस्था, जहाँ वे काम की अगह से काफी दूरी पर रहते हो।

(२) रक्षा-स्थापनाओं में काम कर रहे कर्मचारियों की मकिय निधि में सरकारी अदा-

\*समिति में ये लोग थे। एफ. एन. कल्याणवाला (अध्यक्ष) और बी. बी. घोष, संयुक्त-सचिव, रक्षा मन्त्रालय, और के. एन. सुब्रह्मण्यम, आई० सी० एस०, संयुक्त सचिव, घन-मन्त्रालय, सदस्य।

उस समय विद्यमान-रक्षा-कर्मचारियों के तीन महावर्गों अर्थात् अ० भा० आर्डनेंस कर्मचारी सघ, कलकत्ता, उत्तर और मध्य प्रदेश आर्डनेंस कर्मचारी सघ कानपुर, और अ० भा० रक्षा-सेवा असैनिक कर्मचारी सघ पूना को सलाहकार की हैसियत से समिति के साथ संलग्न किया गया।

दान १ अग्रेत, १९५३ में वेतन के ६२ प्रतिशत से बढ़ाकर ८२ प्रतिशत किया गया। यह भी निर्णय किया गया कि औद्योगिक कर्मचारियों द्वारा १ अगस्त, १९५२ से पहले अतिरिक्त अस्थायी स्थापना में (उसके नियमित संवर्ग में विद्यमान होने से पूर्व) की गयी सेवा के फल के लिए उनको औद्योगिक कर्मचारियों की ही तरह उपदान दिया जाय।

- (३) औद्योगिक कर्मचारियों के मामलों में समिति ने वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर, म्यार्थी पदों का एक केन्द्रित-समुष्पद (नानिक) बनाने की सिफारिश की थी। सरकार ने यह सिफारिश मानते हुए निर्णय किया कि १ सितम्बर, १९५३ को विद्यमान ८० में ५० प्रतिशत औद्योगिक कर्मचारियों को स्थायी बना दिया जाय। इससे पहले रक्षा-उपक्रमों के सभी औद्योगिक कर्मचारी आयादी आधार पर थे, हालाँकि वे बहुत सरल अनिश्चित काल के लिए सेवा में रहते, जब तक कि काम का बोझ ऐसा करना उचित ठहरे।

- (४) अनुष्ठान और अर्द्धगुण कामकर्तों को एक म्यूनरुम वेतन, अगस्त ३० ६० और ३५ ६० की, गारंटी दी गयी। (यह भी तय किया गया कि कामकर्तों के पुनरीक्षित मासिक वेतन मानों के आधार पर उच्चरी दरों में भी संशोधन किया जाय)।

- (५) रक्षा-स्थापनाओं के औद्योगिक कर्मचारियों की ३० दिन तक की छुट्टी अतिरिक्त करने की अनुमति दी गयी, प्रतिष्ठान अर्जन की दर उनके सेवाकाल की दीर्घता पर निर्भर थी। पहले एक साल में अतिरिक्त छुट्टी अगले साल में नहीं जोड़ी जा सकती थी और चाणू साल में न लेने पर स्थगित हो जाती थी। ऐसे कर्मचारियों की पूरे वेतन पर पत्रीय वर्ष में पाँच दिन का आकस्मिक अवकाश और चिरित्ता-प्रमाण-पत्र पर पूरे वेतन के साथ दस दिन का रोगावकाश, एक पत्रीय वर्ष में बाँधे वेतन के रोगावकाश समीप और टीका-अवकाश तथा अतिरिक्त छुट्टी (पूरे वेतन पर) के अवकाश दिया जा सकता था। अवकाशों और छुट्टियों के मामले में रक्षा-स्थापनाओं के कर्मचारियों की सेवा-शर्तें अनेक निम्न औद्योगिक स्थापनों की तुलना में ज्यादा अच्छी हैं।

अब औद्योगिक और औद्योगिक कर्मचारी समन्वय-समिति कारखाना-अधिनियम, १९४८ की ही दर पर पा सकते हैं और मात्र में उतनी ही छुट्टियाँ भी।

पूरे के निर्णयों ने रक्षा-सेवाओं के औद्योगिक कर्मचारियों की सेवा शर्तों में निम्नलिखित बदलाव किया।

अब रक्षा-संगठन के कामकर्तों को भी सेवा की बड़ी ज्यादा सुरक्षा प्राप्त है। पहले पानत कर्मचारी स्थानीय आधार पर ही सेवायुक्त होते जा सकते थे, पर अब एक जगह पानत हुए कर्मचारियों को दूसरी जगह की कमी के जाने सम्भवित कर दिया जाता है। इस तरह अब रक्षा-सेवाओं की समस्त आवश्यकताओं में पानत हुए कामकर्तों को अन्त में सेवायुक्त किया जा सकता है। सरकार इसके लिए भी हर कोशिश करती है कि सेवायुक्त करने के लिए

प्रस्तावित कर्मचारियों के लिए उपयुक्त वैकल्पिक रोजगार खोजा जाय। किसी भी मामले में कुशल कामकरो की रक्षा-सेवाओं से छूटनी नहीं की जाती।

दूसरे वेतन-आयोग की सिफारिशों के आधार पर रक्षा-सेवाओं के असैनिक-जनों के वेतन-मान पुनरीक्षित किये गये और रक्षा-सेवाओं में असैनिकजन (पुनरीक्षित वेतन) नियम, १९६० के रूप में १५ सितम्बर, १९६० को प्रकाशित करके प्रस्थापित किये गये।

सरकार के अधीन अस्थायी या स्वनापच सेवा, जिस के बाद उरी या किसी अन्य पद में स्थायीकरण हो जाय, अब पेन्शन के लिए पूरी-पूरी गिनी जाती है। २१ जुलाई, १९६० से अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू छुट्टी यात्रा-रियायतें अब औद्योगिक और कार्यभरित कर्मचारियों पर भी लागू कर दी गयी। ये इससे पहले इसके पात्र न थे।

१९६२ में पेन्शन सम्बन्धी लाभ औद्योगिक कर्मचारियों को भी उपलब्ध कर दिये गये, जो उनकी, अनौद्योगिक कर्मचारियों की भाँति, सेवा में स्थायी होने पर मिलने लगे। इन आदेशों के निकाले जाते समय जो पहले में ही स्थायी थे उनको यह विकल्प दिया गया कि वे पेन्शन वाली शर्तें अपना सकते हैं अथवा भविष्यनिधि में अंशदान देना जारी रख सकते हैं।

जनवरी, १९६४ में नयी परिवार-पेन्शन-योजन चालू की गयी—जिसके अधीन दो महीने का उपदान छोड़ देने पर सेवाकाल-में कर्मचारों के निधन की स्थिति में उसके परिवार को आजीवन पेन्शन मिलेगी—यह रक्षा-असैनिकजनों पर भी—औद्योगिक और अनौद्योगिक दोनों पर लागू कर दी गयी।

### रक्षा-सेवाओं में मजदूर-संघ

सक्रिय सेवा अध्यादेश, १९४१ के अनुसार सेवा-संस्थापनों में काम कर रहे असैनिक कर्मचारी युद्धकाल में सेना-अधिनिधम के अधीन ला दिये गये। सेना-अधिनिधम के अधीन रहने वाले व्यक्ति किसी भी मजदूर-संघ में शामिल नहीं हो सकते। इस लिए रक्षा-संस्थापनों में काम करने वाले असैनिक जनों के बीच, मजदूर-संघ कार्यकलाप, युद्धकाल में, व्यवहारतः बन्द कर दिये गये। अगस्त, १९४७ से पहले रक्षा-संस्थापनों में काम कर रहे इन असैनिक कर्मचारियों के छोटे से ही मजदूर-संघ और कर्मचारी संघ थे।

आजादी के बाद रक्षा-सेवाओं में मजदूर-संघ आन्दोलन में उत्तेजनीय प्रगति हुई है। १ जनवरी, १९६५ को रक्षा-संस्थापनों में १८९ पञ्जीकृत मजदूर-संघ काम कर रहे थे जिनमें से ९९ मान्यता-प्राप्त थे। (१ जनवरी, १९५५ को उत्तर्वादी जाँके क्रमशः ९६ और ६२ थे)। उक्त तारीख को ही रक्षा-संस्थापनों में काम कर रहे अनौद्योगिक कर्मचारियों के २२ मान्यता-प्राप्त कर्मचारी-संघ थे। औद्योगिक कर्मचारियों के मजदूर-संघों और वक्कों, पर्यवेक्षकों और कामकरो के मिले जुले संघों को मान्यता थम-मन्त्रालय द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार दी जाती है, जब कि अनौद्योगिक कर्मचारियों के संघों को गृह-मन्त्रालय के अनुदेशों के आधार पर मान्यता दी जाती है।

पहले रक्षा-संस्थापनों के कामकरो के अधिकांश संघ तीन महासङ्घों नामतः अ० भा०



आइर्नेस कर्मचारी-महासभ, कलकत्ता, अ० भा० रक्षा-सेवा अमेरिक कर्मचारी-सभ पूना और उत्तर और मध्यप्रदेश आइर्नेस कर्मचारी-सभ, कानपुर मे से किसी एक के साथ सम्बद्ध थे। १९५३ में ये तीनों सभ भी एक अ० भा० रक्षा कर्मचारी महासभ में विलीन हो गये, जिसका मुख्यालय लिडकी, पूना में रहा। हमने कामकरो के प्रतिनिधि और सरकार के बीच बातचीत में सुविधा हो गयी। इस महासभ को अधिनाश रक्षा-असैनिकजनों का प्रतिनिधि मान लिया गया। १९५६ में रक्षा-असैनिकजनों के अनेक मजदूर सभो ने मिल कर एक अलग भारतीय राष्ट्रीय-रक्षा-कर्मचारी-महासभ बना लिया। १९६१ में इसको सदस्यता की जाँच करके, सरकार से बातचीत चलाने को सुविधार्थ इस महासभ को भी प्रदान कर दी गयी।

### बातचीत का तन्त्र

रक्षा-संस्थापनों में लगे असैनिक-कर्मचारियों की शिकायतों को संगठित रूप से पहुँचाने और बातचीत चलाकर विवादों का समाधान करने के लिए, एक मञ्च स्थापित करने की दृष्टि से, दिसम्बर, १९५४ में बातचीत का एक तन्त्र बना दिया। यह तन्त्र स्वरूप में द्विपक्षीय था और कामकरो के साथ बातचीत तीन स्तरों पर चलायी जाती थी, नामतः (क) यूनिट या कारखाना, (ख) कमान-मुख्यालय, नौसेना मुख्यालय या वायुसेना मुख्यालय और (ग) सरकार (रक्षा-मन्त्रालय में)। यह तन्त्र सन्तोषजनक रूप से काम कर रहा था, पर यह १९६० में समाप्त हो गया, जबकि जुलाई, १९६० में हुई केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की आम हड़ताल में अ० भा० रक्षा-कर्मचारी-महासभ ने भी भाग लिया। फिर भी महासभ के सदस्यों पर प्रभाव डालने वाली समस्याओं पर चर्चा करने के लिए आये हुए इस महासभ प्रतिनिधियों के साथ मन्त्री और मन्त्रालय के सम्बन्धित अधिकारी मिलने लगे।

## रक्षा-भण्डार, वैज्ञानिक अनुसन्धान और रक्षा-उद्योग

### खण्ड १ रक्षा-भण्डार-प्राप्ति और उपबन्धन

भारत सरकार के सभी विभागों द्वारा अपेक्षित भण्डारों को प्राप्त करने की जिम्मेवारी पूर्ति और तकनीकी विकास-मन्त्रालय (पहले निर्माण, आवास और पूर्ति-मन्त्रालय) की है। इस मन्त्रालय के कुछ कार्य करने वाले संगठन देश भर में हैं (महानिदेशक, पूर्ति और निपटान), एक यू.के. में हैं (निदेशक, भारत पूर्ति मिशन, जिसे पहले महानिदेशक, भारत भण्डार विभाग, लन्दन कहा जाता था) और एक सं.रा. अमेरिका में (निदेशक, भारत पूर्ति मिशन, वाशिंगटन)।

स्थानीय भण्डार प्राप्त करने के लिए इंडेंट, सामान्यतः महानिदेशक, पूर्ति और निपटान को भेजे जाते हैं। आपात भण्डार के लिए इंडेंट, पूर्ति निपटान महानिदेशालय के केन्द्रीय इंडेंट अनुभाग के जरिए, विदेशस्थ क्रय-मिशनों के पास भेजे जाते हैं। फिर भी रक्षा के इंडेंट करने वाले को अधिकार दिया गया है कि कम मूल्य भण्डार को खरीद के लिए इंडेंट सीधे निदेशस्थ क्रय-मिशनों के पास भेज दें (अर्थात् विमानों के फलतू पुर्जों, कश्चिन सडाकू गाड़ियों और अग्निशमन यन्त्रों के बारे में एक साल रुपये से अधिक के इंडेंट और दूसरे इंडेंटों के बारे में सं. २५००० से अधिक के)। युद्धरोठ, टैंक, विमान, आदि जैसी सैन्य वस्तुएँ खुले रूप से खरीद के लिए उपनय्य नहीं हैं। केवल एक सरकार से दूसरी सरकार के आधार पर बातचीत चलाकर प्राप्त की जा सकती है। विदेश में भण्डार मँगाने के लिए सभी इंडेंट, तकनीकी अधिकारियों से उनके स्थानीय सूत्रों से प्राप्तव्य न हो सकने के बारे में प्रमाणपत्र पा लेने के बाद ही, विदेश भेजे जा सकते हैं।

आजादी के तुरन्त बाद ही विदेश से मँगाये जाने वाले भण्डार की समुचित छानबीन करने की जरूरत समझी गयी। इस प्रयोजन से जनवरी, १९४६ में एक आपात भण्डार छानबीन-समिति बनायी गयी, ताकि (क) रक्षा-भण्डार के मदों की लगातार जाँच के लिए एक तन्त्र हो, जिससे सरकार को समय-समय पर यह सत्ताह दी जा सके कि कौन-कौन चीजें स्थानीय उत्पादन द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं और कौन-सी विदेश होकर आयात करनी होंगी और (ख) इस समय बाहर से प्राप्त किये जाने वाले भण्डारों के क्यासम्भव देश में उत्पादन के लिए शीघ्र कदम उठाना। इस समिति में रक्षा-मन्त्रालय, तीनों सेना-मुख्यालयों, महानिदेशक,

आडमैंस कारखाना, वित्त-मन्त्रालय (रक्षा), निर्माण आवास और पूति-मन्त्रालय, महानिदेशक, पूति और निपटान और वाणिज्य और उद्योग-मन्त्रालय (विकास स्कन्ध) के प्रतिनिधि थे। इस समिति की मदद, विभिन्न प्रकार के रक्षा-भण्डारों की सूचियों की व्यौरेवार जाँच करने और आयात किये जाने वाले भण्डार और स्थानीय सूत्रों से प्राप्तव्य भण्डार की धेनियों में बाँटने के लिए, विभिन्न उपसमितियों द्वारा की गयी। उपसमितियों ने आयात और स्थानीय वाले भण्डारों की सूचियाँ बनायी और पहले बालों को तीन प्रकारों में बाँटा, नामतः वे जिनका निर्माण विद्यमान औद्योगिक समता के द्वारा सम्भव है, वे जिनका निर्माण निकट भविष्य में किया जा सकता है और वे जिनका निर्माण कुछ साल तक सम्भव नहीं है।

मुख्य समिति जैसी कि शुरू में बनायी गयी थी, काफी भारी भरकम समझी गयी, इसलिए उसे अप्रैल, १९५४ में पुनर्गठित किया गया और इसमें अब सेना-मुख्यालयों के निदेशक पदवाले बरिष्ठ अधिकारी रहे, पूति के उपमहानिदेशक रहे और रक्षा-मन्त्रालय और वित्त-मन्त्रालय (रक्षा) के प्रतिनिधि रहे। जनवरी, १९५६ में इसका नया नाम रखा गया, आयातित भण्डार और कच्चा माल छानबीन-समिति। यह केवल सामान्य नीति के प्रश्नों पर विचार करती थी आयातित भण्डार के लिए स्थानीय समता की खोजने का, वास्तविक व्योरे का और दैनन्दिन काम उपसमितियाँ करती थीं। जैसा कि नये नाम से पता चलता है, समिति ऐसे कच्चे माल की आयात करने की जरूरत पर भी विचार करती थी, जो स्थानीय रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता। समिति ने आयातित मान की एक वृहत् सूची बनायी, जिसमें वे भण्डार भी शामिल थे, जो स्थानीय रूप से प्राप्त नहीं हो सकते थे और जिन्हें निश्चय ही विदेश से आयात करना होता था। उनके नाम सभी सम्बन्धित सांघों के पास सूचना और मार्गदर्शन के लिए भेज दिये गये। आयातित भण्डार और कच्चा मान समिति और उसकी विभिन्न उपसमितियाँ आयातित भण्डार की सूची की मदद जाँच करती रहनी थी, ताकि उनमें शामिल मदों के स्थानीय उत्पादन की सम्भावनाओं पर विचार करना रहे। जैसा ही किसी मद का स्थानीय उत्पादन सन्तोषजनक रूप से होने लग जाता था, उसे सूची में अलग कर दिया जाता था और उस मद के लिए आगे में अवशिष्ट स्थानीय रूप से की जाती थी। समिति के कार्यान्वयन के बाद ऐसी अनेक मदों का स्थानीय उत्पादन होने लगा, जो पहले आयात की जाती थी। १९५७ में रक्षा-उत्पादन और पूति-समिति और रक्षा-अनुमन्याय और विकास समिति की स्थापना के बाद, आयातित भण्डार और कच्चा माल छानबीन समिति और उससे सलग उपसमितियाँ विघटित कर दी गयी।

पहले सेना मुख्यालय अपना इंटेंट, वित्त-मन्त्रालय (रक्षा) की सहमति प्राप्त करने के बाद, पूति निपटान महानिदेशालय के पास या विदेश में भेज सकते थे। १९५४ के आरम्भ में यह निश्चय किया गया कि ५ लाख रुपये से ज्यादा मूल्य के सभी इंटेंट, किसी एक देश की वस्तु के लिए, एक बार में अवशिष्ट-अधिकरणों के पास आदेश भेजने से पहले, रक्षा मन्त्रालय के पास भेजे जाने चाहिए। मई, १९५८ में ५ लाख रुपये की सीमा बढ़ाकर, पहले ने सेना में था रहे भण्डारों के लिए, ५० लाख रुपये कर दी गयी। नवम्बर, १९६२ में (आयात शुरू होने के बाद), पहले से सेना में आ रहे स्थानीय भण्डार की सीमा और अधिक बढ़ाकर दो करोड़

रूप में कर दी गयी। नयी मदों के मामले में, दिसम्बर, १९६२ में, सेना-मुख्यालयों को प्राधिकृत किया गया कि वित्तीय सहमति प्राप्त करने के बाद १० लाख रुपये तक की माँग भेज सकते हैं। इस तरह इस समय, पहले से ही सेवा में आ रहे भण्डारों के बारे में दो करोड़ रुपये से ज्यादा, और नयी मदों के मामले में १० लाख रुपये से ज्यादा के इडेंट, पूर्वानुमोदन के लिए रक्षा मन्त्रालय को भेजने होते हैं। इससे यह आश्चर्य हो जाता है कि बड़े-बड़े आदेश सरकार की सामान्य नीति के अनुसार पूरी-पूरी जाँच कर लेने के बाद ही भेजे जायें।

व्यवसाय-पद्धति (या अ-घातक भण्डारों) के मामले में पहले महानिदेशक, आर्डनेंस कारखाना से पूछा जाता है कि क्या वह अपेक्षित भण्डार का निर्माण कर सकने की स्थिति में है। यदि आर्डनेंस कारखानों में क्षमता होगी है, तो ७५ प्रतिशत माँग इन कारखानों के लिए रख ली जाती है और शेष व्यवसायियों के लिए छोड़ दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि व्यवसायियों के पास उत्पादन क्षमता कायम रखी जाय, ताकि आपात काल में, जब आर्डनेंस कारखाने घातक चीजों के उत्पादन में अत्यंत व्यस्त हो जायेंगे, तब उस मद की पूरी माँग व्यवसायियों के ही सूत्र में पूरी कर ली जाय। यदि आर्डनेंस कारखाना के महानिदेशक यह बता देते हैं कि किसी मद-विशेष की उत्पादन-क्षमता उनके पास नहीं है, तो सारे माँग, महानिदेशक, पूर्ति निपटान के जरिये, व्यवसायियों के ही ऊपर छोड़ दी जाती है। घातक भण्डारों के इडेंट सामान्यतः महानिदेशक, आर्डनेंस कारखाना को भेजी जाती है, पर यदि वे उनका निर्माण आर्डनेंस कारखानों में कर सकने की स्थिति में नहीं है और, मैनार्थ इसके उत्पादन के आर्डनेंस कारखानों में स्थापित हो जाने तक इन्तजार नहीं कर सकती, तो इन घातक मद्रों के विदेश से मँगाने के लिए कदम उठाये जाते हैं।

रक्षा-प्राधिकारियों को, विहित सीमा तक, स्थानीय खरीद, महानिदेशक पूर्ति-निपटान के समूह के जरिये इडेंट बिना भेजे हुए, सीधे खरीदने की शक्ति प्रतिनियोजित की गयी है। साथ ही जब कभी आपातक या सक्रियगत जरूरत के लिए भण्डार अपेक्षित हो, या जब कभी सम्बन्धित भण्डार के उपलब्ध होने से महत्वपूर्ण काम रुक जाने का भय हो, तो किसी भी मूल्य का सामान आपातक रूप से खरीदने का सहारा लेने का प्राधिकार भी रक्षा-अधिकारियों को दिया गया है। ऐसी आपातक खरीद का सहारा लेने से पहले रक्षा-मन्त्रालय और रक्षा-मन्त्रालय (वित्त) का अनुमोदन प्राप्त करना होता है।

### पूर्ति-निपटान महानिदेशालय में रक्षा सेना सम्पर्क-कोष्ठ

अक्टूबर, १९५१ में यह फैसला किया गया है कि महानिदेशक पूर्ति-निपटान के कार्यालय में एक रक्षा-सेना अवाप्ति सम्पर्क-कोष्ठ स्थापित किया जाय, ताकि तीनों सेनाओं के लिए समुचित रूप से इडेंट-व्यवस्था और भण्डार अवाप्ति करने में सुविधा हो सके। यह कोष्ठ रक्षा-मन्त्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण में है।

### आयात-भण्डार का संग्रहालय

स्थानीय उत्पादन और अवाप्ति को बढ़ाने के लिए एक नयी समिति बनायी गयी, जिसमें रक्षा-सेनाओं की तकनीकी विकास शाखाओं के, वाणिज्य-उद्योग-मन्त्रालय के विकास-

स्वयं के, तथा पूर्ति निपटान महानिदेशालय के प्रतिनिधि थे। समिति का काम विभिन्न सेना आर्डर्मेंस डिग्री में जाकर, ऐसे रक्षा-भण्डार की उपयुक्त मदों का ध्यान करना था, जिनका निमाण भारत में काफी आसानी से किया जा सकता है। ऐसे भण्डार के नमूने नयी दिल्ली, बसकता और बम्बई में स्थापित नमूना-कक्षों में रखे गए, जहाँ सम्भावनी निर्माता उनको देख सकते थे।

सामान्य उपयोग के सामानों का, गृहोद्योगों द्वारा उत्पादन प्रोत्साहित करने के लिए, विहित विनिर्दिष्टियों से थोड़ा विचलन भी अनुमत कर दिया गया। मुख्य में भी आयातित मदों के मूल्य पर १५ से २० प्रतिशत की बरीयता दी गयी।

भण्डार के नमूने फर्मों को उधार भी दे दिये जाते हैं, ताकि वे उनका स्थानीय उत्पादन विकसित कर सकें। स्थानीय रूप से निर्मित भण्डार, केवल इसी कारण, तब तक अस्वीकृत नहीं कर दिये जाते जब तक कि वे विहित विनिर्दिष्टियों का बख़्तरा से पालन नहीं करते, या जब तक कि स्थानीय माल की पहिया किसम उस मद की उपयोग्यता पर गम्भीर असर नहीं डालती। लेकिन इस ढील भी देश की वास्तविक औद्योगिक प्रगति का बाधक बनने की अनुमति नहीं दी जाती। जहाँ सम्भव हो, व्यवसाय द्वारा उत्पादन चीजों के निकट के ही मानक या विनिर्दिष्टियाँ विहित की जाती हैं और सुधार को प्रोत्साहित करने के लिए मानक सामान्य व्यवसाय की चीजों से थोड़े ऊँचे रखे जाते हैं। रक्षा-मेनाओं के प्राथमिकी सामान्यतः भारतीय मानक सस्था द्वारा विहित मानकों को स्वीकार कर लेते हैं, जब तक कि उनमें ऐसी बात न हो, जो रक्षा की जरूरतों से मेल न खाती हो।

### रक्षा-पूर्ति विभाग

सितम्बर, १९६५ में अनेक विदेशी सरकारों ने सैन्य सहायता के अनीत पूर्तियाँ भेजना विलुप्त बन्द कर दिया, जो वे अक्टूबर, १९६२ में चीनी आक्रमण के समय में भेजते आ रहे थे। उनमें से कई ने तो वाणिज्यिक सविदाओं के आगे भी सैन्य मुद्र-सामग्रियों के भेजे जाने पर रोक या प्रतिबन्ध लगा दिये। इससे स्पष्ट हो गया कि आपात काल में रक्षा सम्बन्धी जरूरतों की पूर्ति के लिए विदेशी स्रोतों पर निर्भर रहना सुरक्षापूर्ण न होगा। नवम्बर, १९६५ में बनाये गये रक्षापूर्ति विभाग ने, निजी और सरकारी दोनों उद्योग-क्षेत्रों की क्षमता का लाभ उठाकर, आयातित मदों के स्थानीय उत्पादन के लिए तेजी से और सपन प्रयास शुरू कर दिये हैं।

इस विभाग ने सामान्य भण्डार, नौ भण्डार, विजली और इलेक्ट्रानिकी भण्डार, इंजीनियरी भण्डार, मोटरगाड़ो भण्डार और विविधता भण्डार का निपटान करने के लिए अलग-अलग तकनीकी समितियाँ बना दी हैं। इन समितियों में निरीक्षण महानिदेशालय (रक्षा-उत्पादन विभाग के), अनुसन्धान और विकास संगठन, उपभोक्ता विभाग, वित्त-मन्त्रालय और तकनीकी विकास महानिदेशालय (पूर्ति विभाग के) के प्रतिनिधि हैं। नयी दिल्ली, बसकता और बम्बई में बनाये गये नमूना-कक्षों (और एक जो मद्रास में बन रहा है) में उद्योगानियों को पता चल जाता है कि किस प्रकार के भण्डार के लिए स्थानीय उत्पादन स्थापित किया जाना है और

कितनी मात्रा में जरूरत पड़ेगी।

### भण्डार का उपबन्धन

सशस्त्र सेनाओं द्वारा व्यपेक्षित सस्त्रास्त्र, गोलाबारूद और अन्य प्रकार के भण्डारों की जरूरत का निर्माण आरम्भिक उपकरण के लिए जरूरी संख्या के आधार पर (नयी शुरु की गयी किसी मद के लिए अबवा नयी मेना खड़ी करने के लिए), और फिर सामान्य प्रशिक्षण और युद्ध के आरम्भिक काल में अनुमानित खपत को ध्यान में रखते हुए, किया जाता है। युद्धकाल में ख़ात की दर हर मद के लिए बलग-बलग होती है। भण्डार की किसी मदविशेष को रक्षित बनाने की मात्रा, जिसे युद्ध बरबादी रक्षित कहते हैं, अवधि विशेष की, जो महीनों से सालों तक चलती है, बहु खपत होती है जो विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए तय की जाती है, नामतः स्थानीय उत्पादन की विद्यमानता और उसकी दर, या निर्माण-संसाधनों को बदलते हुए इस उत्पादन को स्थापित करने की कितनी सम्भावना है, और इस प्रकार के परिवर्तन में कितना समय लगेगा, उत्पादन या भण्डार केन्द्रों से अग्रवर्ती चौकियों तक भण्डार और उपकरण पहुँचने में कितना समय लगता है आदि। जो भण्डार सामान्यतः आयात किये जाते हैं, उनकी युद्ध-बरबादी रक्षित ज्यादा लम्बी अवधि के लिए बनानी होगी, क्योंकि युद्धकाल में उनकी पूर्ति बन्द हो जायेगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न धेनियों के उपकरणों के लिए, सेना द्वारा बनायी और रखी जाने वाली भण्डार रक्षितियों के स्तर की समीक्षा की गयी और १९६१ के अन्त में उनका निर्धारण किया गया। उपबन्धन के विहित स्तरों की समीक्षा समय-समय पर जरूरी होती है। रक्षित भण्डार बनाये रखने और उद्योग पर निर्भर रहने के बीच संतुलन की समस्या हर एक देश में है।

फिर, विज्ञान और शिल्पविज्ञान में तेजी से प्रगति के कारण, सस्त्रास्त्र और उपकरण कुछ वर्षों में ही पुराने पड़ जाते हैं। नये सस्त्रास्त्र के आकस्मिक विकास और निर्माण में पाँच-से दस साल तक लग सकते हैं। उन्मोक्ष (अर्थात् सशस्त्र सेनाओं) द्वारा सक्रियाकालीन जरूरतों के अनुसार बनाये गये सस्त्रास्त्र विज्ञान और शिल्पविज्ञान सम्बन्धी सम्भाव्यताओं को ध्यान में रखते हुए, आकल्पित किये जाते हैं। जब तक वह सस्त्र बनकर तैयार होता है, वह पुराना पड़ सकता है या उपभोक्ताओं की वर्तमान सक्रिया-कालीन आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं भी रह सकता। यदि आवश्यकताएँ सदैव बदलती रहें तो कोई भी प्रयोज्यता कभी साकार हो नहीं ग्रहण कर सकती। इसलिए इस बारे में एक समझौते का रास्ता निकालना ही पड़ता है और यह मानकीकरण द्वारा किया जाता है। वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक मानकीकरण-समिति बनायी गयी है, जिसमें तीनों सेवाओं के प्रतिनिधि और अन्य लोग हैं। इसने १९६३ में काम शुरू कर दिया और इस समिति को सिफारिशों के आधार पर यह निर्णय लिये गये हैं कि अगले साल से दस सालों तक सेना को किन मानक सस्त्रास्त्रों से सज्जित किया जायेगा। उत्पादन और उपबन्धन का समग्र कार्यक्रम इन मानकीकृत सस्त्रास्त्रों और उपकरणों पर आधारित होगा। उपकरण और भण्डार के दूसरे समूहों के बारे में समीक्षा चल रही है।

जब कोई सस्त्रास्त्र किसी विदेश से मँगाना होता है, तब प्रकारों की बहुलता कभी-कभी

अनिवार्य हो जाती है। सैन्य-युद्ध सामग्री का विक्रय उत्पादक देश की सरकार की अनुमति से ही किया जा सकता है, जो राजनीतिक आधार पर धासित रहता है। इसलिए जिस चीज की जरूरत है, वह केवल पैसे से ही नहीं प्राप्त की जा सकती। विमानों के मामले में, विभिन्न प्रकारों के विमान होने का यह मतलब जरूरी नहीं कि प्रकारों की बहुलता है। विभिन्न प्रकार के विमानों की जरूरत विभिन्न कामों के लिए होती है, क्योंकि किसी एक प्रकार का विमान सभी चीजों के काम नहीं आ सकता।

### अतिरिक्त रक्षा-भण्डार का निपटान

यहाँ पर पिछले युद्ध काल में इकट्ठे हुए अतिरिक्त भण्डार के निपटान का भी संक्षेप में उल्लेख किया जा सकता है। युद्धकाल में भारत के आर्डर्नेस डिपो बहुत से ऐसे पैकेज प्राप्त करते रहे थे, जो विदेश के, मुख्यतः, ब्रिटेन से आते थे। उस समय भारत के कारखानों और व्यवसायियों ने भी काफी मात्रा में प्राप्त की। यह पूरे युद्धकाल तक चलता रहा। जब युद्ध समाप्त हो गया, तो बन्द की गयी और समाप्त हुई धूलियाँ भी भण्डार, आर्डर्नेस डिपो को लौटाने लगी। फलस्वरूप रक्षा-मेगार्गों को सान्त्वित करने के लिए काफी मात्रा में अतिरिक्त भण्डार इकट्ठे हो गये। डिपो में इतना ज्यादा मात्रा प्राप्त हो रहा था कि इन चीजों की सत-प्रतिशत जाँच तक करना सम्भव न था। केवल प्रति-गनता जाँच करके, उनके बाउचरों और पैकेजों के ऊपर के अंकन के आधार पर ही, रजिस्ट्रारों में दर्ज कर लिया जाता था। जब ये पैकेज बाद में आवधिक निरीक्षण या स्टाक की जाँच या भेजने के लिए खोले गये तो पता चला कि पैकेजों के भीतर का माल हर मामले में ऊपर के अंकनों के अनुसार न था। अक्सर ये कमियाँ पकड़ी गयीं। कुछ मामलों में ज्यादा माल भी था। इन बीच मुख्यतः भण्डार रखने की अमूर्तताओं के कारण भण्डार की चीजें बिगड़ भी गयी थी।

१५ अगस्त, १९४७ के तुरन्त बाद रक्षा-मेगार्गों के सामने जरूरतों से अतिरिक्त हुए इस माल के निपटान की समस्या थी। छादिन जगह की कमी के कारण, मावी उपयोग की दृष्टि से भारी मात्रा में बाहर रने गये माल की जाँच करने पड़ने की जाती थी। यह बहुत बड़ा काम था, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में पैकेजों को खोलना था, पहचानना था और फिर बन्द करना था। पहचान का काम भी महत्वपूर्ण हो गया था, क्योंकि अनेक मामलों में ऊपर का वर्णन भीतर के वास्तविक माल से भिन्न न खाना था। अन्तर्गत काम के भारी आकार का मान इसी दान में हो सकता है कि विभिन्न केन्द्रीय आर्डर्नेस डिपो में ५२,५०,००० ऐसे पैकेजों को खोलना-बन्द करना पड़ा। जून, १९५० में पुनः एक बन्द करने की योजना बनायी गयी, ताकि पैकेजों के माल को ठीक से पहचान की जा सके और कभी-बेसी की वस्तु जाँच की जा सके। यह योजना अक्टूबर, १९५३ में पूरी हुई।

पिछले युद्ध में पहले, अतिरिक्त आर्डर्नेस भण्डार के निपटान की जिम्मेदारी, सेना-मुख्यालयों की आर्डर्नेस शाखा के मास्टर जनरल के अधीन मविश-निदेशक के ऊपर थी। युद्ध शुरू होने के बाद यह काम अन्तर्गत उपयोग और पूर्ण विमान के अधीन निपटान-निदेशक को सौंपा गया। एक श्रेणी के १०० टन तक की वस्तु के अतिरिक्त भण्डार के स्थानीय निपटान की

जिम्मेवारी रक्षा-सेनाओं की थी और इस मूल्य तक के भण्डार को सीधे ही निपटाने की जिम्मेवारी डिग्री को सौंप दी गयी। १०० रु० से ऊपर और ५००० रुपये से कम के सभी भण्डार प्रादेशिक निपटान-आयुक्त को बताने दिये जाने थे और ५००० रु० से ज्यादा कीमत के माल के बारे में निपटान महानिदेशक को सूचित किया जाता था। जनवरी, १९५० में यह फैसला किया गया कि किसी एक श्रेणी के भण्डार की १०० रु० की सीमा बढ़ाकर १००० रु० कर दी जाय। पर मूल्य में इतनी वृद्धि के बावजूद रक्षा-सेनाओं के पास के अतिरिक्त भण्डार का निपटान तेजी से नहीं हो पा रहा था। इसलिए नवम्बर, १९५० में रक्षा-सेनाओं को और उक्ति दी गयी कि एक श्रेणी के ५००० रुपये तक के पुस्तक-अकिन मूल्य के भण्डार का स्थानोप रूप से निपटान और मूल्य-सीमा के बिना उद्घाटन और रही घोषित कर सकें। ५००० रु० से ज्यादा मूल्य के अतिरिक्त भण्डार निपटान के लिए पूर्ति और निपटान महानिदेशक को सौंपे जाते थे।

भण्डार के निपटान से पहले अन्य सरकारी उपभोगशालाओं की, जिनको रक्षा और पूर्वता इंडेंटर कहा जाता है, जरूरतों का भी पता लगा लिया जाता है और केवल बाकी बचे भण्डारों का ही, राज्य को अधिकाधिक लाभ पहुँचाते हुए, निपटान कर दिया जाता है। अन्य केन्द्रीय सरकारी विभाग, राज्य सरकारों और सैनिक और वैज्ञानिक संस्थाओं, नदी-घाटी-परियोजनाओं और अन्य अर्द्ध सरकारी निकायों को पूर्वता इंडेंटर माना जाता है। पहले इस बात का, पूर्वता इंडेंटरों से पता चलाने में, बहुत समय लग जाता था कि निपटान के लिए प्रस्तावित भण्डार के बारे में उनकी कोई जरूरत तो नहीं है, क्योंकि वे परिवर्तन की विहित प्रवृत्ति में अपनी पुष्ट जरूरतों का अन्तिम निर्णय न कर पाते थे। अनुभव से यह भी पता चला कि उसलक्ष्य अतिरिक्त भण्डार के एक छोटे से अंश से ज्यादा का उपयोग इंडेंटर न कर पाते थे। अधिकांश भण्डार पतनस्वरूप रक्षा-डिग्री के पास निपटान के लिए बच जाते थे। समय की इस बदबारी को बचाने के लिए जून, १९५५ में यह फैसला किया गया कि पूर्वता इंडेंटरों के पास अतिरिक्त सामान की पूरी मात्रा के बारे में भ्रमना अनावश्यक है और यही वास्तव होगा कि किसी सामान के लगभग ५ प्रतिशत के बारे में ही चुने हुए पूर्वता इंडेंटरों के पास उनकी जरूरतें बनाने के लिए परिवर्तित कर दिये जायें और साथ-साथ ही दोष माल को निपटाने के लिए सामान्य रीति में कार्रवाई की जाय। इन पूर्वता इंडेंटरों को स्पष्ट बता दिया जाता था कि परिवर्तित भण्डार उसलक्ष्य भण्डार का एक छोटा अंश ही निरूपित कर रहे हैं और अगर किसी चीज की भारी मात्रा में जरूरत है, तो वह तत्काल निपटान-प्राधिकारियों को बता दी जाय। पूर्वता इंडेंटरों के लिए अच्छी अतिरिक्त भण्डार की रियायती दरों पर उनकी दिया जाता था, जो निर्धारित शोकभाव के ४० प्रतिशत पर तय किया जाता था या जहाँ पर शोकभाव तय नहीं किया जा सकता था, वहाँ पुस्तक-मूल्य के दस प्रतिशत की दर पर तय किया जाता था। बाद में रियायती दर हटा दी गयी।

पूर्ति और निपटान महानिदेशक के समूह में एक निपटान सम्पर्क-कोष्ठ मई, १९५४ में बनाया गया, ताकि अतिरिक्त भण्डार का तेजी से निपटान किया जा सके। यह कोष्ठ निरन्तर सभी प्रक्रमों में भण्डार के निपटान में होने वाली प्रगति का ध्यान रखता था और विभिन्न मात के डिग्री से बचावोद्यम हटा लिये जाने पर भी दृष्टि रखता था, ताकि वहाँ पर



भोड़-भाड़ न होने पाये। यह कोट निपटान की दर में सीधेता लाने के लिए आवश्यक समझे गये उपायों को भी रक्षा-मन्त्रालय के ध्यान में लाता था। जब १९५८ में अतिरिक्त भण्डार का निपटान मन्द पड़ गया, तो यह कोट समाप्त कर दिया गया।

जैसा बताया जा चुका है, रक्षा-सेनाओं को यह शक्ति थी कि प्रत्येक धेनो के ५००० रु० तक के मूल्य के अतिरिक्त भण्डार का निपटान कर सकें और किसी मूल्य-सीमा के बिना बित्तने भी सामान का उद्घाटन और उसे रद्दी घोषित कर सकें। लेकिन इस भण्डार के निपटान से पहले रक्षा-इंजेंटरी या आर्म्ड फोर्स कारखाना महानिदेशक की जर्जरताओं का पहले पता लगा लिया जाना था और भण्डार का वैकल्पिक प्रयोग से उपयोग करने की सम्भावनाओं का सम्यक् भी, तकनीकी विकास-प्रधिकारियों से परामर्श करने हुए किया जाना था। यदि किसी अन्य रक्षा-सेना-उपभोक्ता को उनकी जरूरत न होती थी या उनका कुछ भी वैकल्पिक उपयोग न होता था, तो उनको पूर्णतः इंजेंटरी के बीच परिवर्तित कर दिया जाता था। केवल परिणामी अतिरिक्त का ही रक्षा-सेना-प्रधिकारियों द्वारा निपटान किया जाता था। निपटान सरकार द्वारा नियुक्त अनुमोदित नीलामकर्ताओं के जरिये किया जाता था।

विद्युत् महाप्लुट से बचे हुए कई करोड़ रुपये की कोमल बाले और हजारों टन अतिरिक्त भण्डार का निपटान रक्षा-सेनाओं के लिए एक बड़ा भारी काम था, जबकि आबादी के बाद उनकी अनेक दूसरी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था।

१ अप्रैल, १९६८ से ३१ जनवरी, १९५५ के बीच में निपटान-पूर्ति महानिदेशालय ने ११३.२८ करोड़ रुपये के धुस्तक-मूल्य वाले भण्डार का निपटान किया, जिसका बित्तो-मूल्य ८०.४२ करोड़ रुपये रहा। इसमें न केवल मुद्रास्फीति अतिरिक्त भण्डार शामिल थे, बल्कि समय-समय पर अतिरिक्त घोषित किये गये थालू भण्डार भी थे। १ अप्रैल, १९५८ को अभी = २५ करोड़ रुपये के भण्डार का निपटान होना था।

जून, १९५८ में निपटान के लिए भण्डार के अतिरिक्त होने की घोषणा बन्द कर दी गयी, केवल नदर भण्डार और आर्थिक मरम्मत में परे हो गयी गाड़ियाँ को ही ऐसा घोषित किया जाना था। सभी अतिरिक्त भण्डार की (पूर्ति निपटान महानिदेशालय को अतिरिक्त घोषित किये गये की ही नहीं, बल्कि अतिरिक्त भण्डार को समीक्षाओं प्राप्तियों की भी) जाँच करने के लिए एक अलग-सेवा तकनीकी-टुकड़ी नियुक्त की गयी, ताकि किसी भी रूप में उससे सम्भावी पुनः उपयोग की जाँच की जा सके। समिति ने कुछ भण्डार के उपयोग की सिफारिश की और उसकी सिफारिशें कार्यान्वित की गयीं।

अतिरिक्त रक्षा-भण्डार के निपटान के प्रश्न की जाँच १९६३ के आरम्भ में की गयी। रक्षा-प्रारिणों के प्रतिनिधियों, निरीक्षण-महानिदेशक, वित्त-मन्त्रालय (रक्षा) और तकनीकी विकास महानिदेशालय (पूर्ति-विभाग) का एक समीक्षा बोर्ड उन मदों का पुनर्विचार करने के लिए बनाया गया, जिनकी जाँच पहले अन्तः-सेना तकनीकी-टुकड़ी कर चुकी थी। उद्देश्य यह देखना था कि आगत की दृष्टि में क्या किसी मद का उपयोग सेनाओं द्वारा या रक्षा-सेनाओं के लिए सामान के उत्पादन में किसी उपयोग द्वारा किया जा सकता था। तीन तकनीकी टुकड़ियाँ भी उस पुराने पड़ गये अतिरिक्त भण्डार को देखने और उसका निपटान

मुमाने के लिए बनायी गयी, जिनकी बाँच पहले अन्त-मेना तकनीकी-दुकड़ी द्वारा न की गयी थी। समीक्षा बोर्ड और तीनों तकनीकी समितियों ने १९७८-८१ लाख रुपये की कीमत के भण्डार के निपटान की सिफारिश की। अगस्त-सितम्बर १९६५ के हानान की दृष्टि में जहरतो का फिर से निर्धारण करते हुए यह फैसला किया गया कि निपटान के लिए सिफारिश किये जा सकें भण्डार में से लगभग १६१ करोड़ रुपये के भण्डार का दुबारा उपयोग किया जाय। एक ओर तकनीकी-दुकड़ी चालू और पुराने पड़ गये भण्डार की बाँच करने के लिए बनायी गयी। फलस्वरूप ऐसे भण्डार की कुछ चीजें आगे फिर काम में लायी जा रही हैं।

इस तरह लगातार यह प्रयास किया जा रहा है कि अनिश्चित भण्डार का अधिकतम सम्भव उपयोग किया जाय। साथ ही अनावश्यक भण्डार का निपटान भी शीघ्र ही होना चाहिये, ताकि भण्डार को जगह चालू उपयोग वाले सामान के लिए खाली हो सके। इस प्रयोजन से पूर्ति-निपटान महानिदेशानय में सम्पन्न अधिकारी का पद फिर से बना दिया गया।

उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो जायेगा कि गैर-जल्दी भण्डार की समस्या हमेशा रहेगी, क्योंकि कुछ भण्डार तो पुराने पड़ जाते हैं और कुछ उपन्यासीति आदि में परिवर्तन होते रहते हैं। दूसरे प्रकार के उदाहरण के रूप में १९६३ के अन्त में सरकार द्वारा दिये गये इस निर्णय का उदाहरण दिया जा सकता है कि सामान्य सेवा-गाड़ियाँ (३ टन, १ टन, जोप और मोटर साइकिलें) विहित वर्ष पूरे करने पर या विहित मील-संख्या तक चल चुकने पर, जो भी पहले हो, हटा दी जायें (और उनको जगह नयी रखी जायें)। यह निर्णय यह आश्वासन करने के लिए लिया गया कि सत्ता सेनाओं के पास केवल निर्भर-योग्य गाड़ियाँ ही रहे और उनको उनके सम्भारण और ओवरहाल के लिए अनुचित समय और पैसा न खर्च करना पड़े। साथ ही, अपेक्षित आर्थिक हानि में गाड़ियों के निकाल दिये जाने में, अस्तेनिक बाजार में भी काफी मर्यादा में गाड़ियाँ प्राप्त हो जायेंगी, जहाँ पर कि गाड़ियों की कमी है। आपन काल में रक्षा के प्रयोजन के लिए गाड़ियों का अधिग्रहण किया जा सकता है।

## खण्ड २—अनुसन्धान और विकास-संगठन

रक्षा को किसी भी योजना में वैज्ञानिक अनुसन्धान क्या योगदान दे सकता है, यह बात द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान उग्ररूप से प्रकट हो गयी थी। अब यह सर्वत्र माना जाने लगा है कि एक सुपरसस वैज्ञानिक अनुसन्धान-संगठन देश के रक्षा-ढाँचे में एक अनिवार्य तत्व है। सभी आधुनिक देश, ज्यादा से ज्यादा विष्वसात्मक शक्ति वाले शास्त्र के उत्पादन के लिए, विज्ञान का उपयोग कर रहे हैं। वैज्ञानिक अनुसन्धान न केवल आक्रमण में बल्कि रक्षा में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए पिछले विश्वयुद्ध में १९४० में ब्रिटेन युद्ध में हार गया होता, यदि वैज्ञानिकों ने रदार का उपयोग खोज कर जर्मनों द्वारा रात में टारोर्टों पर उनके ठीक-ठीक आक्रमण विपन्न न कर दिये होते। इसलिए यह कहा जा सकता है कि हालाँकि लड़ाई तो सैनिकों द्वारा युद्ध-क्षेत्र लड़ी जाती है, पर संचालन में वैज्ञानिकों की भूमिका का भी बहुत महत्व है।

फिर भी उच्च वैज्ञानिक अनुसन्धान अलग-अलग रक्षा-सेनाओं में ही नहीं चल सकता,

वल्कि वह देश की सामान्य वैज्ञानिक और औद्योगिक सम्भावनाओं का ही एक अंग होता है। इसलिए रक्षा-वैज्ञानिक-अनुसन्धान उद्योगों के बीच निकटतम परस्पर सहयोग जरूरी है।

### डॉ० वेन्सबोरो जोन्स का प्रतिवेदन

१९४७ से पहले रक्षा सम्बन्धी वैज्ञानिक अनुसन्धान भारत में व्यवहारतः अविदित वस्तु थी। भारत की रक्षा-मेनाओं के लिए एक वैज्ञानिक संगठन बनाने की जरूरत दूसरे विश्व-युद्ध के तुरन्त बाद समझी गयी। १९४६ के मध्य में ब्रिटेन में सेनापरिषद् के वैज्ञानिक सलाहकार डॉ० ओ० एच० वेन्सबोरो को, जिनको युद्धकाल में सन्निया अनुसन्धान का काफी अनुभव प्राप्त हो गया था, ऐसा एक संगठन भारत में बनाने के बारे में रक्षा-विभाग को सलाह देने के लिए बुलाया गया। उन्होंने नवम्बर, १९४६ में कमांडर-इन-चीफ को जो प्रतिवेदन दिया, वह एक बहुमूल्य दस्तावेज है, जिसमें रक्षा विज्ञान और ब्रिटेन की रक्षा-मेनाओं में वैज्ञानिकों के उपयोग का लगभग ३० साल का अनुभव सचित्र है। मुख्यतः, इस प्रतिवेदन के आधार पर, बाद में भारत में रक्षा मन्त्रालय के अधीन रक्षा-विज्ञान-संगठन स्थापित किया गया। डॉ० वेन्सबोरो ने इसे सामंजस्य समझा कि भारत में तीनो रक्षा-मेनाओं को प्रभावित करने वाला एक एकीकृत विभाग विद्यमान था। इसलिए आरम्भ से ही प्रस्तावित वैज्ञानिक सलाहकार रक्षा-विभाग और तीनो ही सेनाओं का काम कर सकता है।

### वैज्ञानिक सलाहकार की नियुक्ति

फरवरी, १९४७ में एक संगठन खड़े करने की दिशा में, पहले कदम के रूप में, एक वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त करने का काम हाथ में लिया गया। यह अनिवार्य था कि उसे उच्चतम प्रतिभा वाला वैज्ञानिक होना चाहिए और अक्षता हो कि उसका अनुभव रक्षा से सम्बन्धित हो, ताकि वह नये संगठन का समुचित रूप में सूचना करा सके और उसे मुहूर्त आधार पर स्थापित कर सके। उस समय भारत में जो थोड़े से प्रतिष्ठित भारतीय वैज्ञानिक थे, वे पहले से ही व्यस्त थे और हम नये पद के लिए उपलब्ध न थे। इसलिए यह जरूरी हो गया कि एक उपयुक्त वैज्ञानिक की मेढारें उस थोड़े से समय तक के लिए ब्रिटेन में प्राप्त की जायें, जब तक कि इस नियुक्ति के योग्य भारतीय न मिल जायें। ब्रिटेन के दो प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों से बात चलायी गयी, पर उनमें से एक भी, पहले से ही शैक्षिक या अन्य दृष्टियों में व्यस्त होने के कारण उपलब्ध न था। लेकिन इस बीच भारत की राजनीतिक स्थिति भी तेजी से बदल रही थी। अतएव यह निश्चय किया गया कि इस प्रश्न पर १५ अगस्त, १९४७ के बाद अलग-अलग होमोनियम सरकारें विचार करेंगी।

आजादी के बाद वैज्ञानिक सलाहकार की नियुक्ति के प्रस्ताव पर तेजी से काम दिया गया। प्रस्तावित रक्षा-विज्ञान संगठन का काम दुहरा था, नामतः राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रयास को रक्षा की जरूरतों के साथ तानमेज रखना और रक्षा-मेनाओं में भी वैज्ञानिक कार्य को बढ़ाना। इस पद का वेतन-मान २०००-१००-२५०० रुपये तय किया गया, जो देश की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के निदेशक का स्वीकृत वेतन-मान था। शासकानों ने पुनर्विचार के बाद मई,

१९४८ में यह निश्चय किया गया कि दिल्ली विश्वविद्यालय में विज्ञान-संकाय के अध्यक्ष डॉ० दोलतसिंह कोठारी ने रक्षा-मन्त्रालय में पहला वैज्ञानिक सलाहकार बनने के लिए अनुरोध किया जाय। दिल्ली विश्वविद्यालय डॉ० कोठारी की सेवाएँ भारत सरकार को अर्पित करने के लिए तैयार हो गयीं।

यहाँ पर रक्षा-विज्ञान-संगठन और तीनों सेनाओं की भूतपूर्व तकनीकी-विकास स्थापनाओं की भूमिका के अन्तर का उल्लेख कर देना भी उपयोगी होगा। तकनीकी-विकास मंडार और उपस्कर के मामले में रेनल्डिन विकास और उससे सम्बन्धित अनुसन्धान के लिए जिम्मेदार था। रक्षा-विज्ञान-संगठन का काम प्रथम विज्ञान के बुनियादी पक्ष और उसकी रक्षा की ज़रूरतों से सम्बद्ध था। मौलिक समस्याओं में सम्बन्धित व्यावसायिक वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन के बिना, सामान्यतः, कोई भी मौलिक विकास सम्भव नहीं है। एक ओर रक्षा-वैज्ञानिकों और तकनीकी-विकास-स्थापनाओं के बीच निकट सम्पर्क ज़रूरी है और दूसरी ओर रक्षा-वैज्ञानिकों और अर्सेनिक-वैज्ञानिक अनुसन्धान संस्थाओं, जैसे विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं आदि के बीच भी।

डॉ० कोठारी ने वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यभार १२ जुलाई, १९४८ से संभाला। वे १२ जुलाई, १९४२ को विश्वविद्यालय वापस चले गये, पर अवैतनिक रूप से वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में वे रक्षा विज्ञान-संगठन से सम्बद्ध बने रहे और १९६१ तक उस पद से सम्बद्ध सभी शक्तियाँ और विशेषाधिकार उनको मिले रहे, जब कि डॉ० एम० भगवन्तम्, निदेशक, भारतीय विज्ञान सल्लाहकार, बंगलूर को रक्षा मन्त्री का अवैतनिक-वैज्ञानिक-सलाहकार नियुक्त किया गया। अक्टूबर, १९६२ में डॉ० भगवन्तम् को रक्षा मन्त्री का पूर्णकालिक वैज्ञानिक सलाहकार और अनुसन्धान और विकास के महानिदेशक के रूप में ३५०० रुपये मासिक के निश्चित वेतन पर पाँच साल की सुविधा पर नियुक्त किया गया।

### रक्षा-विज्ञान-नीति-बोर्ड और रक्षा-विज्ञान-सलाहकार-समिति

वैज्ञानिक सलाहकार को नियुक्त करते समय यह भी तय किया गया कि उनकी परामर्श देने के लिए एक सलाहकार बोर्ड भी बनाया जाय, जिसमें डॉ० एच० जे० भाभा, एक० आर० एस०, डॉ० के० एम० कृष्णन, एक० आर० एस० और डॉ० एस० एस० मन्नागर, एक० आर० एस० रखे गये। प्रो० पी० एम० एम० ट्वेकेट भारत में तीन बार रक्षा-विज्ञान सम्बन्धी साधारण सलाह देने के लिए आये। बोर्ड की पहली बैठक वैज्ञानिक-सलाहकार-समिति के रूप में १६ जुलाई, १९४८ को हुई। १८ अगस्त, १९४८ को, उसकी दूसरी बैठक में, इसे वैज्ञानिक-सलाहकार-बोर्ड कहा गया और इसकी सदस्यता बढ़ा दी गयी तथा उसमें और लोगों के साथ-साथ तीनों सेना-प्रमुख और वित्तीय-सलाहकार (रक्षा) को भी रखा गया। यह बोर्ड ही प्रथमतः रक्षा-विज्ञान-नीति के लिए उत्तरदायी था। इसलिए बाद में सितम्बर, १९४८ में इसका नया उपयुक्त नाम रक्षा-विज्ञान-नीति-बोर्ड रखा गया। बोर्ड का सम्बन्ध रक्षा-विज्ञान और नीति के व्यापक पहलुओं और सैन्य और वैज्ञानिक विचारधारा के एकीकरण से था।

साथ ही उसका काम समग्र रूप से रक्षा-अनुसन्धान और विकास की आयोजना बनाना था, जिसके लिए देश के औद्योगिक स्थापनों को ध्यान में रखा जाता था। नवम्बर, १९४५ में, रक्षा-उत्पादन-बोर्ड के जन्म के बाद, रक्षा-सचिव के स्थान पर रक्षा-संगठन-मन्त्री रक्षा-विज्ञान-नीति-बोर्ड के अध्यक्ष बनाये गये और सचिव भी उसके सदस्य बने रहे। सरकार ने वैज्ञानिक-सलाहकार-बोर्ड के अलावा, १३ अगस्त, १९४८ से, एक रक्षा-विज्ञान-सलाहकार-समिति भी बनाने का निर्णय किया, जिसके अध्यक्ष वैज्ञानिक-सलाहकार थे और इसमें परामर्शदाताओं की एक नामिका थी, सेना के सहयोजित सदस्य थे और यथावश्यक अमेरिकी वैज्ञानिकों को भी सहयोजित कर लिया जाता था। इस समिति का कार्य था कि सैन्य आवश्यकताओं के तकनीकी और वैज्ञानिक पहलुओं पर विचार करे, सेनाओं की तकनीकी स्थापनाओं में अनुसन्धान और विकास के मामलों में निकट सम्पर्क रहे, सेवा की प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालयों और अनुसन्धान स्थापनाओं में रक्षा-विज्ञान के सिलसिले में बुनियादी अनुसन्धान का सूत्रपात कराये और, अन्ततः उनके साथ सहकार करते हुए, पूरे देश के समग्र वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के साथ निकट सम्पर्क रहे। विशेषीकृत विषयों के लिए रक्षा विज्ञान सलाहकार समिति के अधीन नामिकायें अन्य उपसमितियाँ भी थी, जैसे प्राक्षेपिकी, इलेक्ट्रानिक्की, विस्फोटक, आदि।

प्रो० ब्लैकेट सितम्बर, १९४८ में भारत प्यारे और उन्होंने भारतीय सशस्त्र सेनाओं की जरूरतों से सम्बन्धित, वैज्ञानिक-अनुसन्धान के योगदान के सम्बन्ध में, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रस्तावित रक्षा-विज्ञान-संगठन की भूमिका का रूपविन्यास उसी समय रक्षा-विज्ञान नीति-बोर्ड की एक बैठक में किया गया। यह माना गया कि देश में वैज्ञानिक अनुसन्धान के निम्नस्तर और अनुभवों वैज्ञानिक कार्यकर्ताओं के बहुत कम संख्या में उपलब्ध होने के कारण, रक्षा-सेनाओं के सामान्य ढाँचे में रक्षा-विज्ञान-संगठन का, आरम्भ में, केवल सलाहकार का ही रूप हो सकता है।

### संगठन की औपचारिक मजूरी

जून, १९४६ में रक्षा-मन्त्रालय के अधीन, रक्षा-विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में सम्बद्ध अध्ययन, पढ़ताल और अनुसन्धान करने के लिए और सेनाओं को उनकी तकनीकी और वैज्ञानिक समस्याओं के बारे में सलाह और मदद देने के लिए, एक रक्षा-विज्ञान-संगठन के निर्माण की औपचारिक मजूरी प्रदान कर दी गयी। वैज्ञानिक-सलाहकार के अलावा ४० वरिष्ठ वैज्ञानिकों और १०० कमिष्ठ वैज्ञानिकों के पद इस संगठन के लिए मंजूर किये गये और वैज्ञानिकों की भरती के लिए द्वािघ ही कार्यारम्भ किया गया। बाद में, दिसम्बर, १९८६ में, १० वरिष्ठ वैज्ञानिक-महायज्ञों के पदों की मजूरी दी गयी। इन सभी वैज्ञानिक नियुक्तियों पर लोभों को तभी रखा जाना था, जब उनकी वस्तुतः जम्मत हो। साथ ही रक्षा-विज्ञान संगठन की प्रयोगशाला कर्मचाला के लिए उपयुक्त कर्मचारियों की भी मजूरी दी गयी। १९४० के आरम्भ में राष्ट्रीय मोति की प्रयोगशाला, दिल्ली के भवन में रक्षा-विज्ञान प्रयोगशाला के लिए आवास दे दिया गया। एक कर्मचाला और एक अच्छा-खाा रुन्दर्भ और अनुसन्धान पुस्तकालय भी स्थापित किया

गथा और प्रयोगशाला के उपस्कर के लिए तीन साल की अवधि में १५ लाख रुपये का एक एकमुस्त अनुदान उपलब्ध कर दिया गया।

संगठन में १५ वैज्ञानिकों की पहली टुकड़ी अक्टूबर, १९४६ में नियुक्त की गयी। उसके बाद से संगठन में वैज्ञानिकों की संख्या में तेजी से वृद्धि होती रही है।

### रक्षा-विज्ञान-सेवा का गठन

यह जरूरी समझा गया कि विभिन्न स्थापनाओं में वैज्ञानिक कार्यों का नजदीकी एकीकरण किया जाय और उपलब्ध वैज्ञानिक कर्मठों का ज्यादा प्रभावी रूप से उपयोग किया जाय और इस संगठन में आने वालों के बीच सहयोग से काम करने की भावना पैदा की जाय। तदनुसार, रक्षा-मन्त्रालय और सेनाओं में काम कर रहे अवैज्ञानिक वैज्ञानिकों को एक रक्षा-विज्ञान-सेवा बनायी गयी। रक्षा-विज्ञान-सेवा के सूत्रन, संचारण और प्रशासन सम्बन्धी नियम अप्रैल, १९५३ में प्रकाशित कर दिये गये। यह सेवा निर्मित होने तक उप-मुख्य-वैज्ञानिक-अधिकारी के तीन पद (१३०० से १८०० रुपये के वेतनमान में) रक्षा-विज्ञान-संगठन में जून, १९५० में बनाये गये। इन तीन में से एक-एक को चल सेना, वायुसेना और नौसेना सम्बन्धी वैज्ञानिक और तकनीकी काम सौंप गया। चलसेना सम्बन्धी पद, सेना-मुत्पादक के आर्डर्नेस मास्टर जनरल के वैज्ञानिक सलाहकार के विद्यमान पद का रक्षा-विज्ञान-संगठन को स्थानान्तरण करके, और उसका नाम उपमुख्य-वैज्ञानिक-अधिकारी, चलसेना देकर, बना दिया गया। इस पद से सम्बद्ध कर्तव्यों में, उस समय तक आर्डर्नेस के मास्टर जनरल के वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा निर्वहन किये जाने वाले कर्तव्य भी, शामिल कर लिये गये।

नौसेना और वायुसेना सम्बन्धी अनुसन्धान कार्य शुरू करने के लिए, अप्रैल, १९५४ में, उप-मुख्य-वैज्ञानिक-अधिकारियों के रिक्त स्थानों पर दो प्रधान वैज्ञानिक-अधिकारियों (नौसेना और वायुसेना) की नियुक्ति की गयी।

### शस्त्रास्त्र-अध्ययन-संस्थान

आजादी के बाद भारत में प्रशिक्षण और अनुसन्धान के एक मिले-जुले केन्द्र को जरूरत समझी गयी, जिनमें शास्त्राल-सिद्धान्तों और शस्त्रों और वास्तरों के कृत्य-विष्पादन का विगुह वैज्ञानिक अध्ययन और शिक्षण की सुविधा हो। रक्षा-मन्त्रालय के ध्यामन्त्रण पर कर्नल एच० एम० पेंटरसन, जो एक समय यू० के० के मेना के विज्ञान कालेज के उप-कमांडेंट थे, जनवरी, १९५० में, विज्ञान और शिक्षा-विज्ञान में तीनों सेनाओं के अधिकारियों की शिक्षा के लिये एक स्थापना के निर्माण के बारे में सलाह देने के लिए भारत आये। उनके प्रतिवेदन के आधार पर सिड्की में, सैन्य इंजीनियरी कालेज के बहाड़े में, मई, १९५२ में, शास्त्राल-अध्ययन-संस्थान की स्थापना की गयी। संस्थान के प्रमुख संकाय-अध्यक्ष हैं और कर्मचारियों में सेनाओं के तकनीकी अधिकारी और अवैज्ञानिक वैज्ञानिक दोनों ही हैं। संस्थान शस्त्रों और उपस्करों के कृत्यनिष्पादन में अध्ययन और अनुसन्धान करता है और सेनाओं के अधिकारियों को तकनीकी स्टाफ की नियुक्तियों के लिए प्रशिक्षण भी देता है।

## रक्षा-विज्ञान-सम्मेलन

रक्षा-विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए यह अनिवार्य आवश्यक है कि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों और अन्य अमेरिकी-अनुसन्धान-संस्थाओं में रक्षा-विज्ञान और अनुसन्धान के लिए सक्रिय अभिरूचि जागृत और पल्लवित की जाय। विचारों के विमर्श और विनिमय के लिए अवसर पैदा करने के लिए, समय-समय पर रक्षा-विज्ञान-सम्मेलन आयोजित किये जाते रहे हैं। इनमें भारत के विश्वविद्यालयों और विज्ञान-संस्थानों के, आइंस्टीन कारखानों के, तकनीकी-विकास-स्थापनाओं के और घन, वायु और नौसेनाओं के प्रतिनिधि भाग लेते रहे हैं।

### नौसेना-अनुसन्धान

पू० के० की रायन नौसेना-वैज्ञानिक-सेवा के डॉ० कीस्टन को सितम्बर, १९४६ में नौसेना वैज्ञानिक अनुसन्धान के बारे में भारतीय नौसेना की जम्हरी के सम्बन्ध में सलाह देने के लिए भारत बुलाया गया। उनके प्रतिवेदन के अनुसरण में बम्बई में एक नौसेना-भौती-प्रयोगशाला (जिसका नाम अब नौसेना रासायनिक और धातुकामिक प्रयोगशाला है) और कोचीन में एक नौसेना भौतिकी प्रयोगशाला १९५३ में स्थापित की गयी।

### अग्नि-सलाहकार

रक्षा-संस्थापनों में भारी संख्या में ज्वननशील और रिमोट कन्ट्रोल का काम किया जाता है। पहले इन संस्थापनों में अग्नि-संरक्षण की जिम्मेदारी स्थानीय निवासियों की थी, जो इस काम के बिना अंतर्कालिक अधिकारी नियुक्त किया करते थे। तीनों सेना-मुख्यालय अपनी-अपनी विरचनाओं की अनन्य-अलग अनुदेश दिया करते थे और उनके बीच कोई समुचित सामंजस्य न था।

मुद्रकाल में सेना-मुख्यालय में एक अग्नि-समन-सेवा निदेशालय स्थापित किया गया और पू० के० से लाये गये अग्नि-समन-अधिकारी, ज्यादा महत्त्वपूर्ण आइंस्टीन कारखानों में पूर्वाकालिक आधार पर नियुक्त किये गये। मुद्रकाल में नियुक्त केवल एक अग्नि-समन-अधिकारी भारतीय था। मुद्रकाल के बाद अग्नि-समन-अधिकारियों की संख्या घटा दी गयी। १९६७ के आरम्भ में सभी ब्रिटिश अधिकारी बायस किये गये। उस समय योग्यता-प्राप्त एकमात्र भारतीय अधिकारी बंगाल के आइंस्टीन कारखानों के समूह में काम कर रहा था। यह नियुक्ति भी ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त कर दी गयी। दिसम्बर, १९६७ में यही अक्षर अमेरिकी अग्नि-समन-अधिकारों के लिये पद पर नियुक्त किया गया। वह सभी आइंस्टीन कारखानों में अग्नि-समन-व्यवस्था के उत्तरदायी था। वह सामान्य स्टाफ शाखा (सेना-मुख्यालय) के आइंस्टीन कारखाने के निदेशालय में काम करना था। सितम्बर, १९६८ में उसे आइंस्टीन डिपो में भी वेसी ही व्यवस्था के लिए जिम्मेदार बना दिया गया। उस समय वह आइंस्टीन कारखाने को रक्षा-मन्त्रालय के मीडिय प्रशासनिक नियंत्रण में आ गये थे, जबकि आइंस्टीन डिपो सेना-मुख्यालय की क्वार्टर मास्टर जनरल की शाखा द्वारा नियंत्रित किये जाते थे (आइंस्टीन के मास्टर जनरल की शाखा जनवरी, १९६६ में ही पुनर्गठित की गयी थी)। नियंत्रण की डिवा की

दूर करने के लिए अग्निदायन अधिकारी का पद सीधे रक्षा-मन्त्रालय के अधीन कर दिया गया और ११ सितम्बर, १९४८ से पद का नाम अग्नि-सलाहकार, रक्षा-मन्त्रालय, रख दिया गया। हालाँकि यह नियुक्ति प्रथमतः आर्डनेंस कारखानों और आर्डनेंस डिपो के लिए थी, जहाँ आग का खतरा बहुत अधिक था, तथापि वह निर्णय किया गया कि अग्नि-सलाहकार, नौसेना और वायुसेना के संस्थापनों में अग्निशमन के पूर्वोपग्रह और व्यवस्था के बारे में, नौसेना और वायुसेना की भी मदद करेंगे। इस तरह अग्नि-सलाहकार के उत्तरदायित्व का क्षेत्र सभी रक्षा-संस्थापनों तक व्याप्त हो गया। अग्नि-सलाहकार समय-समय पर रक्षा-संस्थापनों का निरीक्षण करते रहते हैं, जिसका उद्देश्य उनकी अग्नि-निरोध और अग्निशमन व्यवस्थाओं का पता चलाना और उनमें सुधार करना होता है। वे रक्षा-संस्थापनों में अग्नि के कारणों की पड़ताल से भी सम्बद्ध रहते हैं और उपचारात्मक उपाय सुझाते रहते हैं।

रक्षा-सेनाओं के अग्निशमन-अधिकारियों के सिवे, पर्याप्त प्रशिक्षण-सुविधा की व्यवस्था करने के लिये, दिल्ली में, अग्नि सलाहकार के पर्यवेक्षण और नियन्त्रण के अधीन, सितम्बर, १९५० में, एक अग्निशमन-प्रशिक्षण-केन्द्र चालू किया गया। यह केन्द्र व्यावहारिक अग्निशमन के सभी पक्षों, उपकरणों के उपयोग और सन्चारण तथा अग्नि-निरोध के बारे में शिक्षण देता है और दो महोदयों की अध्यक्षता के पाठ्यक्रम चलाता है।

अग्नि-सलाहकार का कार्यालय, जो रक्षा-मन्त्रालय के अधीन एक अन्तः-सेना-संगठन था, रक्षा-अनुसंधान और विकास-संगठन का एक हिस्सा बन गया।

### मनोविज्ञान अनुसंधान-स्कन्ध

तीनों सेनाओं में अधिकारी सेनाध्यात्रों की चयन-योजना की जाँच करने के लिये, नवम्बर १९४८ में बनायी गयी समिति की सिफारिश के अनुसार, एक मुख्य मनोवैज्ञानिक के अधीन, एक मनोवैज्ञानिक-अनुसंधान-स्कन्ध, अगस्त, १९४९ में, रक्षा-विज्ञान-संगठन में खोला गया। इस स्कन्ध में कई मनोवैज्ञानिक, मनोरोग-विज्ञानी, सांख्यिकी-विद्वद् और सेनाओं के अधिकारी काम करने हैं, जिनको चयन-रीतियों में प्रशिक्षण दिया जाता है। यह स्कन्ध चयन के लिये नये परीक्षणों का निर्माण करता है, इन परीक्षणों के आधार पर व्यक्तियों को चयन-रीतियों का प्रशिक्षण देता है, जुने शये उम्मीदवारों का अनुगामी अध्ययन करता है और चयन-रीतियों में अनुसंधान भी करता है।

स्कन्ध, आसूचना, अभियोग्यता और व्यक्तित्व के ऐसे परीक्षणों का निर्माण करता है, जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल हों। इसने सेवा-चयन बोर्डों को कार्यकरण-रीतियों का भी सर्वेक्षण करके, उनकी कई सुधारे हुई प्रविधियाँ सुझायी हैं, ताकि चयन-बोर्डों के सदस्य उम्मीदवारों के व्यक्तित्व का सही-सही निर्धारण कर सकें।

सेनाध्यात्रों के प्रशिक्षण-काल के दौरान और कमीशन-प्राप्त सेवा के पहले पाँच सालों में चनाये गये अनुगामी अध्ययनों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मनोवैज्ञानिक-अनुसंधान-स्कन्ध द्वारा निर्मित और सशस्त्र सेनाओं द्वारा अपनायी गयी चयन-रीतियाँ ठीक से काम रही हैं।



लगातार चलने वाली अनुगामी जाँच से काम में साधी गयी रीतियों की कार्यक्षमता को निरन्तर जाँच करते रहने में भी मदद मिलती है।

मनोवैज्ञानिक-अनुसन्धान-स्वस्थ तीनों सेनाओं के अन्य पदधारियों के चयन और व्यवसाय आवण्टन की भी देखभाल करता है। वह व्यक्तियों के चयन के सम्बन्ध में भारत सरकार के विभागों, जैसे आयोजना आयोग, शिक्षा मन्त्रालय और सशस्त्र सैनिक सेवा आयोग का भी सहायक सिद्ध हुआ है।

### अनुसन्धान-विकास सङ्गठन की रचना

रक्षा-वैज्ञानिक-अनुसन्धान और विकास का स्तर और कार्यक्षेत्र बढ़ाने की दृष्टि से, सरकार ने जनवरी, १९५८ में वैज्ञानिक-सलाहकार के अधीन एक अलग अनुसन्धान और विकास सङ्गठन बनाने का निश्चय किया। वैज्ञानिक सलाहकार अब रक्षा-अनुसन्धान और विकास के महानिदेशक हो गये। नया सङ्गठन, आरम्भ में, रक्षा-विज्ञान-सङ्गठन, तकनीकी-विकास-स्थानाओं (जो उस समय रक्षा-उत्पादन महानिदेशक के महानिदेशक के अधीन थीं) और तकनीकी विकास और उत्पादन-निदेशालय (बायु) को मिलाकर बनाया गया। अग्नि-सलाहकार और मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान स्कन्ध भी अनुसन्धान विकास-सङ्गठन के अंग हो गये।

वैज्ञानिक-सलाहकार की सहायता अनुसन्धान और विकास के मुख्य निदेशक (मेजर जनरल के ओहदे का बरिष्ठ सेनानिकारी) द्वारा की जाती है। यह अक्रमर सशस्त्र सेनाओं के साथ अनुसन्धान और विकास के सम्बन्ध के काम के लिए और उपस्कर प्रवण-स्थानाओं के कार्यक्षम रूप से कार्य करते रहने के लिए उत्तरदायी होता है। सहायता के लिये एक मुख्य वैज्ञानिक भी होता है, जो अनुसन्धान और विकास की प्रयोगशालाओं में, वैज्ञानिक अनुसन्धान का सम्बन्ध रखने के लिए, और विद्वत्विद्यालयों से तथा राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अनुसन्धान-स्थाओं से सम्पर्क रखने के लिए, उत्तरदायी होता है। रक्षा-अनुसन्धान और विकास सङ्गठन के प्रमुख कृत्य ये हैं : (क) सेना-मुख्यालयों की वैज्ञानिक सलाह देना, (ख) सेनाओं की समस्याओं के समाधान के लिए अनुसन्धान अनुसन्धान-कार्य चलाना, (ग) सेनाओं द्वारा परिभाषित सन्नियाग ज़रूरतों के अन्तर्गत परीक्षण और उपस्करों का अभिव्यक्ति और विकास करना, (घ) नये अथवा देश में बने सन्धियों और उपस्करों का शून्य और उनका तकनीकी परीक्षण करना और (ङ) नये उपस्करों के विकास के लिए अमेरिकी व्यवसाय को तकनीकी मार्गदर्शन देना।

सरकार ने इस बार नये सङ्गठन से सम्बन्धित नीति के प्रश्नों पर विचार करने के लिए रक्षा-मन्त्री की (अनुसन्धान और विकास) समिति की भी स्थापना की। समिति में वैज्ञानिक-सलाहकार के अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख और वित्तीय सलाहकार भी हैं। वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक अनुसन्धान विकास सलाहकार समिति भी बनायी गयी, जिसमें प्रतिष्ठित अमेरिकी वैज्ञानिक बरिष्ठ सेना अधिकारी और रक्षा वैज्ञानिक सदस्य थे। इन समितियों ने पूर्वोन्मिश्रित रक्षा विज्ञान-नीति बोर्ड और रक्षा-विज्ञान-सलाहकार समिति की जगह ले ली।

यह माना गया कि सरकार के एक मन्त्रालय का सामान्य सन्ध रक्षा अनुसन्धान और विकास के प्रकाशन के लिए पूरी तरह उपयुक्त न था। तदनुसार अगस्त, १९६२ में एक रक्षा-

अनुसन्धान-विकास परिपद् बनायी गयी, जिसके अध्यक्ष रक्षा मन्त्री थे। परिपद् के सदस्य ये हैं - रक्षा-उत्पादन मन्त्री, रक्षा सचिव, रक्षा-उत्पादन सचिव, वैज्ञानिक सलाहकार, तोनी सेना प्रमुख, वित्तीय सलाहकार (रक्षा), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिपद् के महानिदेशक, सशस्त्र सेना-चर्चित्ता-सेवाओं के महानिदेशक, अनुसन्धान और विकास के मुख्य नियन्त्रक, और निरीक्षण महानिदेशक। परिपद् के उद्देश्य ये हैं (क) अनुसन्धान और विकास, व्यक्तियों के प्रशिक्षण और मिलते-जुलते मामलों के बारे में कार्यक्रम तैयार करना (ख) प्रत्येक वित्तीय साल में अनुसन्धान और विकास के बजट प्रस्तावों पर विचार करना, ग) वैज्ञानिक सलाहकार के संगठन के अनुसन्धान विश्वास स्वयं में किये गये काम की समीक्षा करना और (घ) वैज्ञानिक-अनुसन्धान और विकास का काम करने वाले संगठनों के साथ सम्पर्क रखना। उपरोक्ता सेवाओं, निरीक्षण और उत्पादन प्राधिकारियों और देश के रक्षेत्र अनुसन्धान-संगठनों के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों से निरुद्ध सम्पर्क रखने के लिए, विभिन्न तकनीकी विषयों को सलाहकार समितियाँ और अनुसन्धान-विकास-नमिकाएँ भी बनायी गयी। अनुसन्धान विकास-परिपद् की एक कार्यपालक समिति है, जिसके अध्यक्ष वैज्ञानिक-सलाहकार हैं। यह समिति परिपद् की ओर से अनुसन्धान-विकास-संगठन के कार्यपालक निदेशन के लिए उत्तरदायी है।

इस समय अनुसन्धान और विकास-संगठन में लगभग ३० स्थापनाएँ, प्रयोगशालाएँ, क्षेत्रीय स्टेशन और प्रशिक्षण-संस्थान हैं, जो पूरे देश में फैले हुए हैं। ये निम्नलिखित हैं।

शास्त्राध्य-अनुसन्धान और विकास-स्थापना, सिडकी (पूना)—यह तीनों सेनाओं के सभी प्रकार के शास्त्राध्य, गोलाबारूद, और सम्बन्धित भण्डारों के बारे में अनुसन्धान, अभिकल्पन और विकास काम से सम्बन्धित है।

रक्षा-धातुकर्म-अनुसन्धान-प्रयोगशाला, हैदराबाद—रक्षा-उपकरणों में उपयोग के लिए धातुओं और मिश्रधातुओं के बारे में अनुसन्धान और विकास के लिए उत्तरदायी है।

विस्फोटक-अनुसन्धान और विकास-प्रयोगशाला सिडकी, पूना—सभी प्रकार के नौदलों और विस्फोटकों के अनुसन्धान और विकास के लिए।

यन्त्र-अनुसन्धान और विकास-स्थापना, देहरादून—सभी प्रकार के प्रकाशिकीय (ऑप्टिकल), अग्नि-नियन्त्रक, सर्वेक्षण, आरेखण और फोटोग्राफी यन्त्रों के अनुसन्धान, अभिकल्पन और विकास के लिए।

प्रसारण और प्रायोगिक-स्थापना, बालासोर (उड़ीसा)—हर प्रकार की नौसेना और दलसेना की बन्दूकों और गोलाबारूद के बारे में प्रमाणन सम्बन्धी परीक्षण करने के लिए।

रक्षा-अनुसन्धान-विकास-प्रयोगशाला, हैदराबाद—रॉकेटों और विशेष दलों के स्थानीय उत्पादन के प्रयोजन से अनुसन्धान, अभिकल्पन और विकास का काम हाथ में लेना।

छोर-प्रापेदिकी-अनुसन्धान-प्रयोगशाला, चण्डीगढ़—विस्फोटकों के उत्पादन और छोर प्रापेदिकी की समस्याओं का अध्ययन और निपटान करने के लिए।

इलेक्ट्रॉनिकी और रडार-विकास-स्थापना, बंगलौर—सशस्त्र सेनाओं की जहूरतों को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी उपकरण का अभिकल्पन और विकास करना।

धन-अवस्था-भौतिकी-प्रयोगशाला, दिल्ली—धन अवस्था गोचर सम्बन्धी बुनियादी अध्ययन करती है और धन-अवस्था भुविनयो के सम्बन्ध में विकासकार्य और सामग्री और प्रविधि की पड़ताल करती है।

रक्षा-इलेक्ट्रॉनिकी-अनुसन्धान-प्रयोगशाला, हैदराबाद—इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में अनुसन्धान पल्लवित करना ताकि उसके परिणाम रक्षा-उपकरणों के अभिकल्पन और भावी-परास के विकास में अनुप्रयुक्त किया जाय।

अनुसन्धान और विकास-स्थापना (इंजीनियर्स), बीघो-पूना—सशस्त्र सेनाओं के लिए विदेशी महत्त्व की अनेक इंजीनियरी अनुसन्धान और विकास समस्याओं में सम्बन्ध रखती है।

वैमानिकी-विकास स्थापना बंगलौर—विमानों के विभिन्न पक्षों, जैसे वायुगतिकी, विमान ऊँचा, उड़क्यनिर्वाही, नियन्त्रण-पद्धति, यन्त्रों आदि में सम्बन्ध रखती है।

गैस-ट्रस्टाइन-अनुसन्धान-स्थापना, बंगलौर—विमान मोदन-पद्धति के अभिकल्पन और विकास में सम्बन्ध रखती है।

वैमानिकी-परीक्षण प्रयोगशाला, बानपुर—वायु-सेना और विमान निर्माण डिग्री के लिए परीक्षण सुविधायें उपलब्ध करती है।

वैज्ञानिक-भूतत्त्व-समूह, दिल्ली—सत्ताओं और उनमें सम्बद्ध उपकरणों के भूतत्त्व और अध्ययन से सम्बन्ध रखता है।

रक्षा-अनुसन्धान-प्रयोगशाला (सामग्री) बानपुर—इंधन, तेल, स्नेहक, सतह परत चढ़ान, औषध और भेषज द्रव्य, अकार्बनिक और कार्बनिक रसायन, प्रकृत और सन्निष्ट रेने जैसे सभी अमप्राप्तिक भण्डारों और अन्य सामान्य भण्डारों के सम्बन्ध में अनुसन्धान और विकास में सलग्न है।

रक्षा-विज्ञान-प्रयोगशाला, दिल्ली—भौतिकी, रसायन, गणित, सन्निया-अनुसन्धान, सांख्यिकी और सम्बद्ध विज्ञानों में बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसन्धान में सलग्न है।

रक्षा-प्रयोगशाला, जोधपुर—रक्षा के सम्बन्ध में शुष्क क्षेत्र की समस्याओं के अनुसन्धान और सत्ताओं और उपकरणों के क्षेत्रीय परीक्षण के लिए।

रक्षा-परास-अनुसन्धान-प्रयोगशाला, मँसूर—सैनिकों की सेनाओं वाले क्षेत्रों में मिलने वाली हालतों की विनिष्ट स्थाय समस्याओं पर अनुसन्धान और विकास कार्य में सम्बन्धित है।

सामरिक-आधुनिकीकरण और सम्बद्ध-विज्ञान-संस्थान, दिल्ली—रक्षा के लिए विदेशी अभिकल्पित जाने क्षेत्रों में रेडियोममस्थानिक और विविध प्रविधियों का अध्ययन, सागहर रेडियोममस्थानिकों और अयनीकरण-विकिरणों का उपयोग विज्ञान और चिकित्सा के प्रयोजनों में करने के लिए।

रक्षा-परीक्षण-विज्ञान और सम्बद्ध-विज्ञान संस्थान, मद्रास—रक्षा की जम्हरी के सम्बन्ध में परीक्षण-विज्ञान और जीव रसायन में बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसन्धान कार्य करता है और क्षेत्र अनुसन्धान-केन्द्रों और अन्य रक्षा अनुसन्धान प्रयोगशालाओं द्वारा किये गये परीक्षण-विज्ञान अनुसन्धान का निदेशन और समन्वय करता है।

भारतीय नौसेना-भौतिकी-प्रयोगशाला, कोचीन—पनडुब्बी-रोधी युद्ध के सम्बन्ध में समुद्र-विज्ञान, ध्वनिकी, इलेक्ट्रानिकी आदि के क्षेत्र में अनुसन्धान और विज्ञान का काम करती है।

नौसेना रासायनिक और धातुकामिक-प्रयोगशाला, बम्बई—नौसेना के पोतों और उपस्करों को कार्यक्षम और समुद्र गमनयोग्य रूप में सन्धारण करने के लिए वैज्ञानिक मदद देती है।

शास्त्रास्त्र-शिल्पविज्ञान-संस्थान, पूना—सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों और रक्षा-असैनिक-वैज्ञानिकों को शास्त्रास्त्र के विज्ञान और शिल्पविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित करने के लिए।

कार्य-अध्ययन-संस्थान, लुहरी, मसूरी—रक्षा मन्त्रालय के अधीन अन्तर्सेना-संगठनों और रक्षा-सेनाओं के सभी स्तरों के व्यक्तियों को कार्य-अध्ययन की रीतियाँ और सम्बद्ध विषयों में प्रशिक्षण देने के पाठ्यक्रम चलाता है।

अग्नि-सेवा-अनुसन्धान, विकास और प्रशिक्षण-स्थापना, दिल्ली छावनी—रक्षा के व्यक्तियों को अग्नि निरोध और अग्नि-क्षमण रीतियों में प्रशिक्षित करने के लिए।

मनोविज्ञान-अनुसन्धान-निदेशालय, नयी दिल्ली—व्यक्ति-चयन रीतियों, प्रशिक्षण-रीतियों के मूल्यन और प्रशिक्षण-सहायक वस्तुओं के विकास कार्य में अनुसन्धान करता है।

मोटर गाड़ो-अनुसन्धान और विकास-स्थापना, अहमदनगर—(इसके इत्य नाम से ही स्पष्ट है)।

क्षेत्र-अनुसन्धान-प्रयोगशालाएँ और कार्म—विभिन्न अवयवों की स्थितियों में उपस्करों का परीक्षण करने के लिए।

अनुसन्धान विकास संगठन में असेनिक और तीनों सेनाओं के जुड़े हुए सैन्य-अधिकारों होते हैं। निश्चय, अधिकारियों की सहायता का लगभग २० प्रतिशत होते हैं। इस संगठन को असेनिक वैज्ञानिकों सम्बन्धी अहर्निश पूरा करने के लिए और उनको समुचित रूप में रक्षा प्रवण बनाने के लिए एक अप्रेंटिसी योजना चल रही है, जिसके अधीन विज्ञान और इंजीनियरी में माध्य योग्यता रखने वाले तत्काल विज्ञानविदों और शिल्पविज्ञान विदों को रक्षा अभिनति के साथ बुनियादी और अनुप्रयुक्त विज्ञानों में अविधि विशेष के लिए शिक्षा (अप्रेंटिस) रखा जाता है, जिसके बाद उनकी रक्षा-विज्ञान-सेवा में लिया जाता है।

## तकनीकी विकास और उत्पादन (वायु)-निदेशालय

किसी वायुसेना की प्रभावी लड़ाकू सामर्थ्य उपलब्ध विमानों की मध्या पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि सन्धारण और मरम्मत की सुविधाओं तथा विमानों और उपस्करों के चालू उत्पादन पर भी निर्भर है। इसलिए यह अत्यावश्यक है कि देश में यथासम्भव शीघ्र विमानों, वायु-वास्त्रास्त्र और गोला-बारूद और अन्य सैन्य-मण्डारों का स्थानीय रूप से निर्माण प्रशस्त किया जाय। इस दिशा में, पढ़ने अत्यावश्यक कदम के रूप में, रक्षा मन्त्रालय के सीधे अधीन एक तकनीकी विकास और उत्पादन-निदेशालय (वायु) १ अप्रैल, १९५४ से खोला गया।

निदेशालय का काम वैमानिकी के क्षेत्र में अनुसन्धान और विकास-कार्यकलाप का आयोजन, समन्वयन और कार्यनि्विन् करना था और साथ ही विमान और सम्बद्ध उपकरणों के स्थानीय निर्माण के उपर तकनीकी नियन्त्रण रखना भी था ।

वायुसेना-मुख्यालय के तकनीकी-सेवा-निदेशक ने इस नये संगठन के पहले निदेशक का कार्यभार संभाला । तकनीकी-सेवा-निदेशालय के कुछ पद नये तकनीकी विकास और उत्पादन (वायु)-निदेशालय में भी शामिल कर लिये गये थे ।

निदेशालय में वायुसेना के तकनीकी-अधिकारी और अर्धनिक वैज्ञानिक दोनों ही हैं । पिछले, रक्षा-विज्ञान सेवा से सम्बद्ध हैं ।

एक ही केन्द्रीय संरचना में सभी विकास और अनुसन्धान-कार्य को एकीकृत करने की नीति के अनुसार, यह निदेशालय १ जनवरी, १९५७ में रक्षा-उत्पादन-महानियन्त्रक के अधीन स्थानान्तरित कर दिया गया । जनवरी, १९५८ में यह अनुसन्धान और विकास-संरचना का भाग बन गया, पर दिसम्बर, १९६५ में इसे फिर वहाँ से अलग करके रक्षा-उत्पादन-मन्त्रालय के सीधे अधीन कर दिया गया ।

### खण्ड ३ रक्षा-उद्योग

(क) आर्डेन्स कारखाने—विज्ञान और सिन्धविज्ञान के क्षेत्र में इतनी ज्यादा प्रगति हो चुकी है कि आजकल किसी सैनिक की कार्य दक्षता उसके अस्त्रों की अग्नि-शक्ति पर ज्यादा निर्भर रहती है । इसलिए एक कार्यक्षम सेना को न केवल कवायद कराना और भोजन-वस्त्र देना जरूरी है, बल्कि उसे अद्यतन शास्त्रास्त्र से लैस करना होना है और उनमें प्रशिक्षण भी देना होता है । इसलिए किसी देश की रक्षा-योजना में जरूरी अस्त्र-गोलाबारूद का देश ही में उत्पादन बड़े ही महत्त्व की वस्तु है । ऐसा तब और भी जरूरी हो जाता है, जब कोई देश स्वतन्त्र विदेश-नीति अपनाता है और आत्म-निर्भर बनना चाहता है । ३० अप्रैल, १९५० के औद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव में शास्त्रास्त्र, गोलाबारूद और रक्षा-उपकरणों की सम्बन्धित मशीं और विमानों को उन उद्योगों में रखा गया है, जिनका भावी विकास एकमात्र राज्य की जिम्मेवारी होगी ।

### दूसरे विश्वयुद्ध में पहले आर्डेन्स कारखाने

दूसरे विश्वयुद्ध से पहले भारत में छः ऐसे आर्डेन्स कारखाने थे, जो शास्त्रास्त्र, गोला-बारूद और सम्बन्धित मशीनों का उत्पादन करने थे और दो धातुपरिष्कारखाने (नामक हारनेस-सैडिलरी कारखाना और वस्त्र कारखाना) थे । आज के रूप में चारू होने वाले आर्डेन्स कारखानों में पहला १८७२ में शुरू हुआ गोलाबारूद का कारखाना था । अगला कारखाना १८८० में शुरू होने वाला हारनेस-सैडिलरी कारखाना था (उन दिनों अस्त्र-सेना एक महत्वपूर्ण सेना बनी थी) । धातु रण्पाट कारखाने ने १९०० में काम शुरू किया । १९०४ में राइफ़ल कारखाना, बार्डस्ट कारखाना और तोपगाड़ी कारखाना चारू हुए और अगले साल बन्दूक और गोला कारखाने ने काम शुरू किया । वस्त्र कारखाना इनमें आखिरी था जो १९३० में शुरू ।

फिर भी ये कारखाने सैन्य-उपकरणों के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नहीं खड़े किये गये थे। वे ब्रिटेन के रॉयल आर्डनेंस कारखानों के सहायकों के रूप में काम करते थे। फिर भी भारत में उत्पादन छोटे शस्त्रास्त्र और गोले बनाने तक ही सीमित था।

ये कारखाने मेना-मुसालय की आर्डनेंस के मास्टर जनरल की शाखा के आर्डनेंस-कारखाना-निदेशक के प्रशासनिक नियन्त्रण में थे। आ० का० निदेशक थोड़े तौर पर घातक शस्त्रास्त्र, भण्डार और वस्त्रों के निर्माण के लिए उत्तरदायी थे। उनको भारत के स्थानीय निर्माताओं से भी सम्पर्क रखना होता था, जिससे स्थानीय उत्पादन का पूरा उपयोग किया जा सके।

युद्ध में थोड़े ही पहले लाइव चैटफोल्ड भारत आये और उन्होंने विद्यमान आर्डनेंस कारखानों का विस्तार करने और आधुनिक शस्त्रास्त्र और गोलाबारूद के निर्माण के लिए नये प्रकार की जल्दी मशीन-ओजारों को स्थापित करने की सिफारिशें कीं। चैटफोल्ड-योजना के फलस्वरूप विभिन्न आर्डनेंस कारखानों के कार्य-कलाप में विस्तार हुआ।

### युद्धकाल में कारखानों का नियन्त्रण

१९१६ में विश्वयुद्ध गुरु होने से थोड़े ही पहले, भारत सरकार में एक पूर्ति-विभाग युद्ध चलाने के लिए सब प्रकार का जल्दी समान प्राप्त करने के लिए बनाया गया था। आर्डनेंस कारखाने १९४० में, एक युद्धकालीन उपाय के रूप में, उत्पादन के उत्तर निकट का समन्वय और नियन्त्रण रखने की दृष्टि से, पूर्ति-विभाग की स्थानान्तरित कर दिये गये। उस वर्ष जुलाई में ये कारखाने शस्त्रास्त्र-उत्पादन के उप-महानिदेशक के सीधे नियन्त्रण के अधीन रख दिये गये, जो पूर्ति-विभाग में इंजीनियरी-उत्पादन-निदेशक के अधीन थे और जिनका पदनाम शीघ्र ही बदलकर शस्त्रसामग्री (म्यूनिसन) उत्पादन-महानिदेशक कर दिया गया। यह दफ्तर कलकत्ता ले जाया गया, ताकि असैनिक उद्योगों के निकट सम्पर्क में रह सके। आर्डनेंस के मास्टर जनरल, गवर्नर जनरल की परिषद् के पूर्ति-सदस्य के सैन्य सलाहकार बन गये। फिर भी युद्धकाल में वस्त्र कारखाना और हारनेस-सैडिलरी कारखाना पूर्ति-विभाग के वस्त्र-निदेशालय द्वारा नियंत्रित रहे। आर्डनेंस कारखानों के सेन-सेना रक्षा-सेनाओं के हिसाब में आते रहे और सैन्य-वित्त के वित्तीय सलाहकार को वित्तीय-सलाहकार (युद्ध और पूर्ति) बना दिया गया।

१९४० के शरद में ब्रिटेन के पूर्ति-मन्त्रालय ने एक तकनीकी मिशन भारत भेजा (जिने उसके अध्यक्ष सर ओग्नेयर रोजर के नाम पर 'रोजर-मिशन' कहा गया)। इस मिशन का काम भारत में सशस्त्र सेनाओं के लिए शस्त्रसामग्री और दूसरे भण्डार के उत्पादन का विस्तार करने के लिए उठाये जा सकने योग्य सर्वोत्तम प्रभावों कदमों के बारे में प्रतिवेदन देना था। इस की सिफारिशों के अनुसार कई विस्तार-प्रायोजनाएँ, जिनको पूर्वोक्त-प्रायोजना कहा गया, विद्यमान आर्डनेंस कारखानों में आयोजित की गयी या अमल में लायी गयी। साथ ही बाठ नये कारखाने कटनी, बम्बरनाथ, देहरादून, अमृतसर, सिकन्दरगढ़, दोहद, सखनऊ और समरिया में स्थापित किये गये। जापान के युद्ध में शामिल हो जाने के बाद बंगाल में कोई नया कारखाना न स्थापित करने का निश्चय किया और यह भी कि बंगाल के कारखानों में

संस्थापन के लिए आयोजित पूर्वी-समूह प्रायोगना, यदि कोई हो तो, अन्यत्र संस्थापित की जाय। इनको पुनः संस्थापित प्रायोगना कहा गया और इसमें तीन और नये कारखाने बनाये गये (नामत आर्डनेंस कारखाना और छोटे-अस्त्र कारखाना कानपुर और आर्डनेंस कारखाना, मुराद नगर)। युद्ध के बाद दो कारखाने (एक सख्तनऊ का और एक दोहद का) फिर रेलवे को सौंप दिये गये, एक अमृतसर में पनाब सरकार को, और कलकत्ते का गणित-यन्त्र कारखाना उद्योग और पूर्ति-मन्त्रालय को। कुछ कारखानों को देखभाल और सन्धारण-आधार पर चलाया गया। इस बात पर फिर जोर देना जरूरी है कि युद्धकाल में कारखानों का विस्तार भारत की अकूरतो पर आधारित न होकर साम्राज्य के समग्र युद्ध-प्रयास के पुरजे के रूप में हो पा। युद्धकाल में आर्डनेंस कारखाने तीन पारी के आधार पर और प्रायः लगातार काम करते रहे। फलस्वरूप संयन्त्र और यन्त्र काफी घिस-पिट गये और फलतः उनका शीघ्र ही बदलाव जरूरी हो गया।

१ अप्रैल, १९४७ से आर्डनेंस कारखानों का नियन्त्रण फिर रक्षा-विभाग को सौंप दिया गया, पर चूंकि उस तारीख से आर्डनेंस के मास्टर जनरल की शाखा बन्द कर दी गयी थी, उनको सेना-मुख्यालय की सामान्य स्टाफ शाखा के अधीन कर दिया गया। युद्धकाल में पूर्ति-विभाग के वस्त्र-निदेशालय के अधीन चलने वाले वस्त्र कारखाना, हारनेस-सैंडिलरी कारखाना और पैराचूट कारखाना भी आर्डनेंस कारखाना-निदेशक के अधीन आ गये।

### कारखाने और विभाजन

सत्ता-हस्तान्तरण के समय भारत में आर्डनेंस कारखाना-निदेशक के अधीन १९ आर्डनेंस और वस्त्र कारखाने थे और कलकत्ते का गणित-यन्त्र कारखाना भी। कारखानों में ब्रिटिश और भारतीय असेनिक-जन कर्मचारी थे। मजदूर पूर्णतः भारत के ही थे और ज्यादातर स्थानीय रूप से भरती किये जाते थे।

आर्डनेंस कारखानों में उत्पादित सभी सामान का निरीक्षण तकनीकी विकास-निदेशालय के कर्मचारी कर सकते थे, जो कारखानों के सङ्गठन से अलग स्वतन्त्र रूप से काम करते थे। ये कर्मचारी अशत सैनिक और अशत असेनिक थे।

सारे ही आर्डनेंस कारखाने भारत डोमीनियन में स्थित थे। विभाजन सम्बन्धी अभ्यास में पहले ही बताया जा चुका है कि पाकिस्तान को आर्डनेंस कारखानों समेत, सभी (अभाज्य) विशिष्ट संस्थाओं के सम्बन्ध में, ५ करोड़ रुपये दिये थे।

जैसाकि पहले ही बताया जा चुका है, तत्कालीन विद्यमान कारखाने भी राक्षस और उपराक्षसों के बारे में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आयोजित नहीं किये गये थे। भारत में सैन्य-बहुरतों के सम्बन्ध में कोई भी अनुमन्यन-कार्य नहीं चल रहा था। यह काम प्रभवद्ध रूप में ब्रिटेन में ही चलता था और भारत के कारखानों को तो आबन्ध और ड्राईंग मिल जाती थी, जिनके अनुसार उनको अपने निर्माण को आयोजित करना होता था। इसलिए सत्ता-हस्तान्तरण के समय भारत में ऐसा कोई सङ्गठन न था, जो प्रभवद्ध अनुमन्यन का बड़ा ही जटिल कार्य हाथ में लेने के लिए सक्षम हो।

## रक्षा-मन्त्रालय के अधीन कारखाने

पहले आर्डनेंस कारखाने केवल सेना की ही जरूरतों को पूरा करते थे। इसलिए यह उचित ही था कि आर्डनेंस कारखाने सेना-मुख्यालय के प्रशासनिक नियन्त्रण में काम करें। १५ अगस्त, १९४७ के बाद आर्डनेंस कारखानों को तीनों ही सेनाओं को बढ़ती हुई जरूरतें पूरी करनी पड़ी। इसलिए जगह अब यह उपयुक्त न रहा कि इन कारखानों की तीनों में से किसी एक सेना-मुख्यालय के अधीन रखा जाय। इसलिए आर्डनेंस-कारखाना-निदेशालय को सेना-मुख्यालय की सामान्य स्टाफशाखा से अलग करके १ अप्रैल, १९४८ से रक्षा-मन्त्रालय के सीधे नियन्त्रण में कर दिया गया। उसी तारीख से आर्डनेंस कारखानों के निदेशक के पद की जगह आर्डनेंस के कारखानों के महानिदेशक का पद बनाया गया। रक्षा-मन्त्रालय के निदेशान में, आर्डनेंस कारखानों के महा निदेशक को, आर्डनेंस और बम्ब कारखानों के उनमें नियोजित व्यक्तियों समेत, सगठन और प्रशासन के लिए और तीनों सेनाओं द्वारा मांगे गये सामान के उत्पादन के लिए और अधिकारियों और कामकरों के प्रशिक्षण के लिए, जिम्मेदार बना दिया गया।

अगस्त, १९४७ के बाद कुछ कारखानों का उत्पादन-कार्यकलाप बिलकुल बदल गया था। उदाहरण के लिए, सेना के यन्त्रोत्तरण के कारण हारनेस-सैडिनरी की चीजों की मांग बहुत कम हो गयी थी, इसलिए हारनेस-सैडिनरी कारखाना सेना के लिए तरह-तरह की चीजें बनाने लगा और डाक-सार विमान, पुलिस, रेलवे आदि की जरूरतें पूरा करने के लिए व्यापक मात्रा में औद्योगिक व्यवसाय-कार्य में लग गया। दूसरे कारखानों में भी अनेक नयी मशीनें का निर्माण स्थापित कर दिया गया, जिनमें औद्योगिक व्यवसाय की मशीनें और पहले विदेश से आयात होने वाली चीजें शामिल थीं। पुरानी, बरबाद हो चुकी मशीनें नई मशीनें बनाने की प्रविधि भी बदल दी गयी। इस परिवर्तन-कार्य में आरम्भ में अनुभवी ब्रिटिश अधिकारियों के चले जाने और अनुभवी मुसलमान कामकरों के पाकिस्तान चले जाने से कुछ कठिनाइयाँ भी हुईं।

आर्डनेंस कारखाना महानिदेशक का कार्यालय कलकत्ते में है। उनकी सहायता के लिए अतिरिक्त, उप और सहायक महानिदेशक हैं। हर कारखाना एक अधीक्षक के सीधे अधीन है, जिनको अब महाप्रबन्धक कहा जाता है।

## राष्ट्रीयकरण

सत्ता-हस्तान्तरण से पहले आर्डनेंस कारखानों सम्बन्धी काम बड़ा गोपनीय माना जाता था और प्रशासनिक और पर्यवेक्षक स्टाफ में प्रायः यूरोपीय ही थे। १९३९ में राजपत्रित पदों पर ४४ यूरोपीयों के अतिरिक्त केवल एक ही भारतीय अधिकारी था। १९४७ तक ३४ भारतीय अधिकारी और ८४ यूरोपीय अधिकारी हो गये, लेकिन विभाजन के बाद ३ भारतीय अधिकारी और ५ यूरोपीय पाकिस्तान का चुनाव करके चले गये। मुख्य भारतीय पर्यवेक्षक और तकनीकी स्टाफ की भारी कमी के कारण, इन कारखानों को कार्यदक्ष रूप से चलाने की जरूरत को देखते हुए, ब्रिटिश अधिकारियों को मजबूर होकर रोकना पड़ा। लेकिन भारतीयों को ब्रिटिश-अधिकारियों के साथ अध्येता के रूप में लगा दिया गया और उनमें से कई प्रति-



क्षण के लिए विदेश भी भेजे गये । १९४८-४९ में १९५३-५४ के वर्षों में कारखानों के ७५ भारतीय अधिकारी प्रशिक्षण के लिए ब्रिटेन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, फ्रान्स, जर्मनी, बेल्जियम और इटली भेजे गये । यूरोपीय अधिकारियों की संख्या १९४८ में ७४ में घटाकर १९५६ में ३० कर दी गयी । जो रह गये थे, वे स्वामी थे, जिनमें आखिरी सामान्य क्रम में, १९७४ में सेवानिवृत्त होगा ।

आजादी के बाद साम्राज्य-उत्पादन में कई बातें आत्मनिर्भरता के आड़े आ गयी । पहले तो ब्रिटेन से जो निर्माण-विशिष्टियाँ प्राप्त होती रहती थी, अब नये उपकरणों के निर्माण के लिए मिलाया बन्द हो गयी । ब्रिटेन भारत को पूरे निर्माण-विशिष्टियाँ और थ्योरेटिक ड्राइंग और प्रक्रम-अनुसूचियाँ, ऐसे साम्राज्य-गोलाबारूद के निर्माण के लिए भेजता था, जिनका निर्माण भारतस्थित आर्टिफैक्ट कारखानों में करना होता था । हालाँकि तकनीकी-विकास निदेशालय का, जो १९४६ में ही आर्टिफैक्ट के मास्टर जनरल की शाखा में हो बनाया गया था, एक काम यह भी था कि नये उपकरणों के आकलन भी बनाये, लेकिन उस निदेशालय में कोई भी मौलिक काम नहीं किया जाता था । थोड़े से ही अपवादों को छोड़कर, जो अधिकांशतः बम और सामान्य भण्डार की चीजों के सम्बन्ध में थे, भारत में साम्राज्य भण्डार के अनुसन्धान-विकास का कोई भी काम न किया गया था । वस्तुतः इस क्षेत्र में किसी सस्था को प्रोत्साहन भी न दिया जाता था, क्योंकि पूरा विषय ही बड़ा गोपनीय माना जाता था । अत्यन्त प्रवीण कामकरो, ड्राइंग अधिकारियों, आकलन कर्मचारियों और दर-निर्धारक और अनुमानकर्ता कर्मचारियों की कमी के कारण भी दिक्कतें सामने आयी । इसलिए कारखानों को काफी विकास और उत्पादन-पूर्व का काम करना पड़ा, ताकि प्राथमिक सिद्धान्तों से ही निर्माणकार्य का भोगयोग किया जाय । अत्यन्त प्रवीण व्यक्तियों के अभाव की दिक्कत दूर करने के लिए प्रशिक्षण योजनाएँ भी तेज की गयी ।

कोई भी देश, जो साम्राज्य, गोलाबारूद और अन्य महत्वपूर्ण भण्डारों की पूर्ति के लिए विदेशी स्रोतों पर निर्भर है, रक्षा के लिए सुपर्याप्त रूप से तैयार नहीं कहा जा सकता । लेकिन आत्मनिर्भरता प्राप्त देश के औद्योगीकरण की हानत पर हो पूर्णतः निर्भरता रहती है ।

एक कठिनाई और भी है । शान्तिकाल में सशस्त्र सेवाओं की जरूरतें तुलना में बहुत कम होती हैं । इसलिए सारा समय आर्टिफैक्ट कारखाने पूरा उत्पादन कार्य नहीं बना सकते । आर्टिफैक्ट कारखानों के अस्तित्व का प्रमुख आधार लड़ाकू सेना के लिए साम्राज्य का निर्माण करना है, लेकिन सेनाओं की जरूरतें अनेक कारणों से समय-समय पर बदलती रहती हैं । ये उपकरण भी प्रमाण कम कर देने से कम हो जाती हैं, लेकिन आपात की पूर्वांशा में अगर रक्षिति बढ़ाना अच्छी हो जाय, तो ये काफ़ी बढ़ जायेंगे । युद्धकाल में कारखानों की उत्पादन-क्षमता काफी बढ़ा दी गयी थी, लेकिन युद्ध समाप्त होने पर कारखानों में भी जाने वाली माँग सहसा कम हो गयी । यदि सरकार लड़ाकू सेनाओं की चालू जरूरतों का ही ध्यान रखती तो कुछ कारखाने बन्द हो गये होते । ऐसा करने में निषेधित मजदूरों की छूटनी भारी पैमाने पर करना जरूरी हो जाता । इसके अलावा बड़े ही जटिल प्रकार के उपकरणों की उत्पादन-प्रक्रिया जोड़ित न रह पाती और अनेक वर्षों में प्रशिक्षित, अत्यन्त प्रवीण व्यक्ति, कारखानों की फिर

न मिन पावे और जल्दतर पडते ही उनको वापस लाना सम्भव न हो पाता । किसी अन्य अत्यन्त विशेषीकृत कार्य की तरह रासायन-भोलाबाह्य के उत्पादन की कार्यक्षमता भी लगातार उत्पादन के प्रक्रम द्वारा ही बनायी रखी जा सकती है । इस कारण रक्षा के बृहतर हित में यह जरूरी है कि ये कारखाने चलते रहें और यथासम्भव मजदूरों को बनाये रखा जाय और वर्षों में अज्ञित प्रविधि और अनुभव व्यर्थ न जाय । इसलिए कारखाने काफी सख्या में असेैनिक आदेश स्वीकार करते रहे ।

आजादी के बाद के कुछ आरम्भिक वर्षों में आर्डनेंस कारखानों ने भण्डार की कई ऐसी चीजों का बनाना शुरू कर दिया, जिनका पहले आयात किया जाता था । अतएव कारखानों में काम का इस बोझ पूरा-पूरा मार आ गया । धीरे-धीरे परिमाण में सेनाओं की माँग सीमित होती गयी और केवल उन चीजों के लिए ही जिनका विकास करने और निर्माण स्थापित करने में काफी समय लगता था । इसलिए कारखानों के पास काफी अतिरिक्त क्षमता हो गयी, जिसका उपयोग रक्षा-सेनाओं के अलावा अन्य माँग को पूर्ति में किया जा सकता था । आर्डनेंस कारखानों के अधिकांश संयन्त्र तो विशेषीकृत और एक ही उद्देश्य के लिये होते हैं और उनको शान्तिकाल में, जरूरी रासायन-भोलाबाह्य के अलावा, मुविवापूर्वक, उभोवना सामान के उत्पादन के लिए अनुकूलित नहीं किया जा सकता । इन सीमाओं के अधीन, आर्डनेंस कारखानों की सारी क्षमता को, असेैनिक जरूरतें पूरी करने के लिए बदल दिया गया । फिर भी सरकारी कारखाने पूर्ण स्थापित स्थानीय उद्योगों के साथ न तो स्पर्धा कर सकते थे और न उनकी जगह ही ले सकते थे । इसलिए उत्पादन ऐसी मदों में ही सीमित करना पड़ा जिनके निर्माण के लिए अन्यत्र सुविधायें उपलब्ध न थी और जिनको आयात करना पड़ता था । सरकार ने जुलाई, १९५१ में आदेश निकाल दिये कि सभी विभागों को अपनी जरूरत की ऐसी चीजें आर्डनेंस कारखानों से ही लेनी चाहिये, जो वे लगभग सामान्य बाजार भाव पर दे सकते हैं । कारखानों द्वारा उत्पादित उपभोग्य-द्रव्यों का क्षेत्र बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास किये गये । १९४६-५० में आर्डनेंस कारखानों में किये गये असेैनिक व्यवसाय-कार्य लगभग १५१.३ लाख रुपये के थे, जबकि १९५६ में यह मात्रा बढ़कर ४ करोड़ रुपये हो गयी थी । आर्डनेंस कारखानों द्वारा असेैनिक उपयोग के लिए उत्पादिन कुल ज्यादा महत्व की चीजें ये थी . ( एक ) इस्पात की बलाई की चीजें, इस्पात की भारी गद्दी चीजें, कमनियाँ और मिश्र इस्पात के छर्रे आदि (दो) अलौह चादरें, काट और टनाई की चीजें, (तीन) पसीमार बन्दूकें और पिस्तार की रायफलें (चार) चमड़े और काड़े की चीजें, (पाँच) वैज्ञानिक और प्रकाशिकी (ऑप्टिकल) यन्त्र (छ.) गणित और सर्वेक्षण के यन्त्र और (सात) रसायन । ऐसे पदार्थों का अधिकाधिक निर्माण स्थापित करके, जिनका कि आयात किया जाता था, यह सम्भव हो गया कि उपयुक्त वैकल्पिक काम बहुत से ऐसे कामकारों के लिए पैदा कर दिया जाय, जिनकी अन्यथा छँटनी करनी पड़ जाती ।

रक्षा-उत्पादन के लिए बड़ी ही उच्च प्रकार का गुणवत्ता बौद्धिक आधार अत्यावश्यक होता है । सशस्त्र सेनाओं के लिए विस्फोटक को पूर्ति करने के लिए बड़े प्रगतपूर्ण रसायन-उद्योग का विद्यमान होना बहुत ही सहायक होगा । बढ़िया-सा वाणिज्य-बेदा और सुगठित जहाज-

निर्माण उद्योग नौसेना का मेरुदण्ड होता है। सुविकसित विमान-उद्योग के बाद ही कोई देश एक अच्छे कार्यक्षम वायुसेना रख सकता है और बाहरी निर्भरता के बिना किसी भी आघात का सामना कर सकता है। दूसरे शब्दों में रक्षा के लिए जरूरी उपकरणों का उत्पादन चलाना और चालू रखना देश में सुविकसित इंडीनिबरो और औद्योगिक सम्भाव्यता की पृष्ठभूमि पर ही निर्भर है। इसलिए न केवल जनता का जीवन-स्तर सुधारने के लिए बल्कि देश की रक्षा के लिए भी भारत का औद्योगिक विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है।

### मशीन-औजार आधरूप कारखाना

सेना के नये भण्डार के विकास की सुविधाएँ स्थापित करने का दिशा में, पहले कदम के रूप में, सरकार ने मेमर्स ओपिकन मशीन औजार वर्क्स, स्विटजरलैंड के सहयोग से अम्बरनाथ में मशीन औजार आधरूप कारखाना आरंभ किया, जिसका नाम आधरूप शस्त्रास्त्र का आकल्पन, विकास और निर्माण, और उनका परीक्षण और जाँच करना था, आधरूपों की पूरी इजाजत वर्कशॉप के लिए बनाना था, जिसमें आर्डनेंस कारखाने अनुमोदित आधरूपों का उत्पादन शुरू कर सकें, तथा आर्डनेंस कारखानों के लिए विशेष मशीन-औजारों और आर्डनेंस कारखानों की मानक मशीनों के आकल्प बनाना और उनका निर्माण करना था। इस कारखाने के स्वतन्त्र इकाई के रूप में १ जनवरी, १९५१ को काम शुरू कर दिया। कारखाने की योजना बनाते समय यह माना गया कि सुप्रवीण यथातथ्य कामगारों की कमी भावी विस्तार में बहुत बड़ी बाधा है। इसलिए कारखाने के साथ-साथ, फर्म के साथ ठेका करके, सुप्रवीण कामगारों के और आधरूप कारखाने तथा आर्डनेंस कारखानों के काम के लिए उच्च धेनो वाले जरूरी प्रवीण और तकनीकी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए एक कारीगर-प्रशिक्षण-विद्यालय भी खोला गया। विद्यालय ने अबदूबर, १९५० में काम शुरू कर दिया। संविदा में यह भी व्यवस्था थी कि आधरूप कारखाना और विद्यालय चलाने के लिए अपेक्षित भारतीय कामगारों और अधिकारियों को काफी सख्या में स्विटजरलैंड में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जायेगी। औद्योगिक और निवास के भवनों समेत इस योजना की कुल लागत ५ करोड़ रुपये अनुमानित की गयी थी।

यह उल्लेख कर देना उचित होगा कि अम्बरनाथ के कारीगर विद्यालय के अलावा, प्रवीण कामगारों के प्रशिक्षण की दूसरी योजनाएँ, जैसे विभिन्न आर्डनेंस कारखानों में घास-कारीगर-प्रशिक्षण-योजना और प्रत्येक आर्डनेंस कारखाने में कामगारों के लिए प्रवीण और अर्धप्रवीण प्रशिक्षण-योजनाएँ भी चालू की गयी, जिससे प्रवीण व्यक्तियों की कमी के कारण आर्डनेंस कारखानों के कार्यक्षम रूप से चलाने में पैदा हुई दिक्कतें दूर हो जा सकें।

### गोलाबारूद का कारखाना

मशीन-औजार-आधरूप-कारखाने के अलावा, गोलाबारूद के निर्माण में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के कार्यक्रम के अंगस्वरूप, एक गोलाबारूद प्रायोगिक चलाने के लिए भी कदम उठाये गये। युद्ध के बाद जो कारखाने देव माल और सन्यारण की स्थिति में ला दिये गये थे, उनको भी उत्पादन के लिए फिर से खोल दिया गया।



वैद्यपत्त टैक

रक्षा-मण्डार, वैज्ञानिक अनुसंधान और रक्षा-उद्योग

## आइर्नेस कारखानों के पुनर्गठन के लिए समिति की नियुक्ति

मूलतः आइर्नेस कारखाने तदर्थ ज़रूरती की पूर्ति के लिए बनाये गये थे और उनमें विस्तार किया गया था। यह जरूरी था कि इन कारखानों की संगठनकार्य-विधि और उत्पादन-रीति की जांच, रक्षा-सेनाओं को सम्भावित माँग का ध्यान रखते हुए, की जाय। तदनुसार सरकार ने २३ जनवरी १९५८ को सरदार बलदेव सिंह, ससई-सदस्य (भूतपूर्व रक्षा-मन्त्री) की अध्यक्षता में एक समिति बनायी।\*

समिति का काम आइर्नेस कारखानों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवेदन देना था, खास-कर असेनिक उपयोग के पदार्थ बनाने के लिए इन कारखानों की बेकार पड़ी क्षमता का उपयोग करने की सम्भावना के बारे में। समिति ने अपना प्रतिवेदन दिसम्बर, १९५४ में दिया। समिति का एक निष्कर्ष यह था कि कारखानों के प्रशासन के वर्तमान ढाँचे में खोद्य निर्णय करने की गुंजाइश नहीं है और इसमें इन निर्माण-स्थापनाओं के प्राधिकारियों को सुपर्याप्त शक्ति प्रदान करने की भी व्यवस्था नहीं की गयी है।

## उत्पादन-बोर्ड

समिति की सिफारिश पर सरकार ने एक रक्षा-उत्पादन-बोर्ड स्थापित किया, जिसके अध्यक्ष रक्षा-संगठन-मन्त्री थे।<sup>†</sup> बोर्ड के कार्य थे : (एक) आइर्नेस कारखानों में उत्पादन से सम्बन्धित नीति के तथा अन्य सभी महत्वपूर्ण मामले, जिसका अभिप्राय यह था कि उस समय आइर्नेस कारखानों के महानिदेशक की शक्तियों में न आने वाले बहुत से मामलों पर तुरन्त निर्णय लिया जा सके और उनको सरकार को न भेजना पड़े, (दो) तीनों सेनाओं और आइर्नेस कारखानों में अनुसंधान-विकास, आकल्पन और उत्पादन के कार्यक्षेत्र का समन्वय करना (इन बहुत महत्वपूर्ण काम के लिए पहले कोई व्यवस्था न थी। उपस्करों का उपयोग करने वाली सहाय्य सेनायें ही बहुत कुछ उसके आकल्पन और विकास के लिए जिम्मेदार थी और सत्यवात निर्माण आइर्नेस कारखानों में किया जाता था। अनुभव ने बताया है कि नये उपस्करों के आकल्पन में निर्माता की काफी आरम्भ की स्थिति से ही साथ रखना चाहिये, ताकि वास्तविक

- \* इसके सदस्य थे : पी० सी० मुकुर्जी (महाप्रबन्धक चित्तरंजन लोको वर्कस), एस० पी० क्लॉस्कर (उद्योगपति) और एस० वैद्य (चाटर्ड लेखाशास्त्र) और इसके सचिव थे एस० जे० घाहने (सहायक महानिदेशक, आइर्नेस कारखाना)।

- † रक्षा-सचिव अपाध्यक्ष थे और सदस्य थे : रक्षा-उत्पादन-महानियन्त्रक (एक नवनिर्मित पद), आइर्नेस के मास्टर जनरल, सेना-मुख्यालय, सामग्रो-प्रमुख, नौना-मुख्यालय, भारसाधक वायु-अधिकारी, तकनीकी और उपस्कर सेवार्थ, वायुसेना-मुख्यालय, वित्त-मन्त्रालय (रक्षा) के एक वरिष्ठ प्रतिनिधि, आइर्नेस कारखाना-महानिदेशक, रक्षा-मन्त्रालय के वैज्ञानिक-मसाहकार और एक उप-वैज्ञानिक सहाय-कार। एक उप-महानियन्त्रक बोर्ड का सचिव था।

निर्माण-समस्याओं की ओर मुपर्वत ध्यान दिया जा सके। नये उपकरणों का आन्वयन वैज्ञानिक-अनुसन्धान के साथ निकटत सम्बद्ध होना चाहिये। इस तरह वैज्ञानिक, उपभोक्ता और निर्माता के बीच और देश के वैज्ञानिक-अनुसन्धान के साथ वाष्पीकृत का सम्पर्क होना चाहिये। उत्पादन-बोर्ड को रक्षा-विज्ञान-संगठन, तीनों सेनाओं की तकनीकी शाखाओं और आर्मेन्स कारखानों के बीच जरूरी समन्वय का काम भी करना था। और (तीन) देश के रक्षा-उत्पादन-प्रयत्न का समन्वय करना, जिसमें अमैत्रिक औद्योगिक क्षमता का निर्माण भी शामिल है, ताकि, त्रितनी ओ विफलयुक्त और धोत्रना के साथ सम्भव हो, रक्षा-भण्डार के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली जाय।

नोटि के तथा अन्य महत्वपूर्ण मामलों के निपटान को उत्पादन-बोर्ड और महानियन्त्रक को करना था, पर कारखानों का दैनन्दिन प्रशासन आर्मेन्स कारखाना-महानिदेशक और उसके अधीन मशीनरों (अथ महाप्रबन्धकों) को सौंपा गया। जो शक्तियाँ उत्पादन-बोर्ड और रक्षा-उत्पादन के महानियन्त्रक को प्रत्ययोचित नहीं की गयी थीं, उनको ही आदेशार्थ सरदार के पास भेजना होता था।

रक्षा-मन्त्रालय में अब तक आर्मेन्स कारखानों से सम्बन्धित काम के मारसायक संयुक्त-सचिव ने, १ नवम्बर, १९५५ से, अपने अन्य विद्यमान कर्तव्यों से अतिरिक्त रूप में, रक्षा-उत्पादन-महानियन्त्रक का कार्यभार भी संभाल लिया। विभिन्न ध्यौरों को अन्तिम रूप देने में पहले ही उत्पादन-बोर्ड भी बन गया और उसी पक्षी बैठक में १ नवम्बर, १९५५ को हुई। रक्षा-उत्पादन के महानियन्त्रक के मुख्यालय-संगठन ने भी १ मार्च, १९५६ से काम शुरू कर दिया।

समन्वय आदेशस्त करने की दिशा में, अगले बंदस के रूप में, सेना-मुख्यालय की आर्मेन्स के मास्टर जनरल की छाया के अधीन बना आने वाला तकनीकी विकास निदेशालय और उसकी अधीनस्थ तकनीकी-विकास स्थानार्थ, निरीक्षणालय, प्रयोगशालाएँ आदि १ जनवरी, १९५६ से रक्षा-उत्पादन-महानियन्त्रक के अधीन कर दिये गये। आगे चलकर १ जनवरी, १९५७ में तकनीकी-विकास और उत्पादन (वायु)-निदेशालय (जो अब तक मन्त्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण में था) और भण्डार-उत्पादन-निदेशालय (जिसे पहले पड़ती अवधूवर, १९५५ में सामग्री-प्रमुख, प्रीमेरा-मुख्यालय के अधीन बनाया गया था) भी रक्षा-उत्पादन-महानियन्त्रक के नियन्त्रण में स्थानान्तरित कर दिये गये।

उसके द्वारा-अभ्यादन में रक्षा-उत्पादन-बोर्ड की सहायता तीन समितियाँ करती थीं, त्रिनको स्थापना जनवरी, १९५७ में की गयी थी। रक्षा-उत्पादन-सहायकार समिति का काम अमैत्रिक उद्योगों के साथ प्रभावों सम्पर्क रखना था और इसमें विभिन्न मन्त्रालयों और निरी उद्योगों के प्रतिनिधि थे। रक्षा-उत्पादन के महानियन्त्रक की अध्यक्षता में, रक्षा-उत्पादन और पूर्ति-समिति का काम विदेश से आयात होने वाले रक्षा-भण्डारों का स्थानीय उत्पादन स्थापित करने, कच्चे माल के स्टॉक रखने, भण्डार-उत्पादन में पूर्वेता तय करने और उत्पादन की वापस हटाने के बार में सिफारिशें करना था। तीसरी समिति रक्षा-अनुसन्धान और विकास-समिति थी, जिसके अध्यक्ष वैज्ञानिक-सहायकार थे और उनका काम था अनुसन्धान और

विकास-प्रायोजनाओं की जाँच करना और उनमें प्रगति करना, सेनाओं के अनुसन्धान-कार्यक्रम का राष्ट्रीय अनुसन्धान-कार्यक्रम के साथ तालमेल रखना और प्रायोजनाओं की पूर्वंता वृत्त करना ।

नये रास्त्रास्त्र और नये उपस्कर उत्पादन और पूर्ति-समिति ( जो रक्षा-मन्त्री की समिति की एक सहायक के रूप में १९४७ से चली आ रही थी ) को जगह पर पहले ही रक्षा-अनु-मन्वान और विकास-सलाहकार-समिति बनायी जा चुकी थी । १९५७ के आरम्भ में रक्षा-उत्पादन और पूर्ति-समिति और रक्षा-अनुसन्धान और विकास-समिति की स्थापना के फल-स्वरूप, नीचे लिखी समितियाँ और उपसमितियाँ, नामिकार्यें भंग कर दी गयीं—

- (क) रक्षा-अनुसन्धान और विकास-सलाहकार-समिति तथा संलग्न-उपसमिति ।
- (ख) आयात-मण्डार और कच्चा माल-छानबीन की समिति और संलग्न उपसमिति ।
- (ग) रक्षा-विज्ञान-सलाहकार-समिति और संलग्न उपसमिति ।
- (घ) रक्षा-स्त्रास्त्र-सलाहकार-समिति ।

### आर्डनेंस कारखानों के उत्पादन का निरीक्षण

१९३२ से पहले आर्डनेंस कारखानों के उत्पादनो का निरीक्षण आर्डनेंस-निदेशक ( अब पदनाम आर्डनेंस-कारखाना-महानिदेशक ), और रास्त्रास्त्र-निदेशक, सेना-मुख्यालय, जिनको बाद में तकनीकी-विकास-निदेशक कहा गया, करते थे, पहले अफसर तो प्रक्रम से प्रक्रम तक का मध्यवर्ती निरीक्षण करते थे, जैसा कि वह ठीक समझते थे, और दूसरे केवल अन्तिम निरीक्षण ही करते थे, ( उन मामलों को छोड़कर, जहाँ ऐसे पुरखों का प्रारम्भिक निरीक्षण जरूरी था, जिनका निरीक्षण अन्तिम उत्पादन के समायोजित कर दिये जाने के बाद सम्भव न था । ) १९३२ में यह निर्णय किया गया कि रास्त्रास्त्र-निदेशक को मध्यवर्ती निरीक्षण की भी जिम्मे-वारी सँभालनी चाहिये । फिर भी, अब भी विभिन्न कारखानों में निरीक्षण की कोई एक रूप की पद्धति न थी । कुछ कारखानों में, मध्यवर्ती निरीक्षण, कारखाने के प्रबन्धकों द्वारा किया जाता था, जब कि कुछ में मध्यवर्ती और अन्तिम दोनों ही निरीक्षण सेनाओं द्वारा किये जाते थे । तकनीकी-विकास-निदेशालय के साथ-साथ निरीक्षण की जिम्मेवारी रक्षा-उत्पादन-महा-नियन्त्रक के ऊपर आ गयी ।

### भारतीय आर्डनेंस-कारखाना-सेवा

आर्डनेंस कारखानों के उच्च सेवाधिकारी भारतीय-आर्डनेंस-सेवा ( अब भारतीय आर्डनेंस कारखाना सेवा ) के होते हैं, जिसका गठन १९५५ में किया गया था । सहायक-निर्माण-प्रबन्धक के कुछ पदों को छोड़कर, जो नीचे के अराजकचित कर्मचारियों में से पदोन्नति देकर भरे जाते हैं, अधिकारी, साधारणतः, ब्रिटेन में भारतीय उच्चस्तर और संघीय-स्तोक-सेवा-आयोग के जरिये भरती किये जाते थे । भारतीय-आर्डनेंस-सेवा ( कारखाना ), प्रथम धोषी, की जिसका नया नाम अगस्त, १९५५ से भारतीय-आर्डनेंस-कारखाना-सेवा रखा गया, भरती को विनियमित करने वाले नये नियम ५ जून, १९५४ को प्रकाशित किये गये ।

१९५७-५८ में किये गये पुनरावसोक्तन के फलस्वरूप, रक्षा-उत्पादन-बोर्ड की रचना और कृत्यों में कुछ परिवर्तन किये गये। मार्च, १९५६ में बोर्ड का नया नाम रक्षा-मन्त्री की उत्पादन-समिति रख दिया गया। अब समिति में रक्षा-मन्त्री अध्यक्ष हैं और ये सदस्य हैं - रक्षा-संगठन-मन्त्री, तीनों मेना-प्रमुख, रक्षा-सचिव, रक्षा-उत्पादन-विभाग के सचिव, रक्षा-भूति-विभाग के सचिव, वैज्ञानिक-सलाहकार, वित्तीय-सलाहकार, आर्मेन्स-कारखाना-महानिदेशक और अनुसन्धान और विकास के मुख्य-नियन्त्रक। इस समिति का काम है देश के रक्षा-उत्पादन प्रयासों को विनियमित करना तथा आर्मेन्स कारखानों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रायोजनाओं की परीक्षा और अनुमोदन करना।

मई १९६४ में एक नया रक्षा-उत्पादन-बोर्ड बनाया गया, जिसके अध्यक्ष रक्षा-उत्पादन-विभाग के सचिव थे।\* इसका काम है (क) रक्षा-उत्पादन की भारी आयोजनाओं (ख) सशस्त्र सेनाओं और आर्मेन्स कारखानों जैसे कार्यान्वित संगठनों की उपबन्धन कार्यविधि, जहाँ तक वह उत्पादन पर प्रभाव डालती है, (ग) कच्चे माल खासकर स्त्राविक माल का ह्रास रखने की नीति (घ) रक्षा-सेनाओं के लिए अपेक्षित नयी मशीनों के उत्पादन को स्थापित करना और (ङ) आयातित रक्षा-भण्डार के म्यानीय निर्माण के सम्बन्ध में होने लगे प्रस्तावों के बारे में जाँच करना और सरकार के पास सिफारिश करना।

### आर्मेन्स कारखानों में नया उत्पादन

जुलाई, १९५६ में, एक आर्मेन्स कारखाने में, जर्मनी के मेसर्स धान के सहकार से ३ टन के एक टुक 'सक्तिमान' का निर्माण स्थापित हो गया। कोमासू ट्रेक्टरों का उत्पादन भा आर्मेन्स कारखानों में स्थापित किया गया। फरवरी, १९६० में जापान की निशान मोटर कम्पनी के सहकार से १-टन के 'निशान' टुक के निर्माण की व्यवस्था को अन्तिम रूप दिया गया। १९६१ में मध्याकार टैंकों के निर्माण के लिए आवडी में एक भारी-माड़ी-कारखाने को स्थापित करने की मन्जूरी दी गयी। पहला 'मैजयल' टैंक इस कारखाने से दिसम्बर, १९६५ में बन कर बाहर निकला। दिसम्बर, १९६१ में आर्मेन्स कारखानों में निशान-गस्त-माड़ी ( ३ हूड-वेट ) के प्रथम निर्माण [॥] लिए लाइसेंस-कटार निष्पादित किया गया।

अक्टूबर, १९६२ के आपात के बाद, उत्पादन के आधार को विस्तृत करने की आवश्यकता को देखते हुए, धातु उत्पादन के दायित्वों को आगे की अरुतों की आयोजना सम्बन्धी दायित्वों में मलग किया गया। रक्षा-उत्पादन के महानियन्त्रक का पदनाम निरीक्षण और आयोजना-महानियन्त्रक रखा गया और उनको रक्षा-उत्पादन-आधार के विस्तार-कार्यक्रम की आयोजना

\* वैज्ञानिक-सलाहकार, वित्तीय सलाहकार, आर्मेन्स-कारखाना-महानिदेशक, हिन्दु-स्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड के प्रबन्धनिदेशक, भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड के प्रबन्धनिदेशक, आर्मेन्स के मास्टर जनरल (मेना-मुख्यालय) और निरीक्षण-महानिदेशक इसके सदस्य हैं। आयोजना और समन्वय के निदेशक इसके सचिव हैं।



का काम सौंपा गया। पर निरीक्षण-स्थापनाओं पर उनका नियन्त्रण बना रहा। अब नवम्बर, १९६२ में आर्डेनस-कारखाना-महानिदेशक रक्षा-मन्त्रालय में स्थापित रक्षा-उत्पादन के नये विभाग के साथ सीधे काम करते थे। अगस्त, १९६३ में फिर पुनर्गठन किया गया, जब आयोजना और निरीक्षण के काम विभिन्न अधिकारियों को, नामतः निरीक्षण-महानिदेशक और आयोजना-निदेशक को सौंपे गये।

१९६३ में ७.६२ मिलीमीटर वाली अट्रेंस्वचलित राइफल का, जिसे ईसापुर राइफल कहते थे, निर्माण सफनडापूर्वक स्थापित किया गया। यह वस्तुतः एक महत्वपूर्ण सफलता थी। हल्की मशीनगनों और बोट-प्रिया राइफलों का रूपभेद भी हाथ में लिया गया, ताकि वे कोर-हीन ७.६२ मिलीमीटर की गोलीयों चला सकें। अन्य महत्वपूर्ण विकास थे नये भारी मॉर्टर और गोलाबारूद का उत्पादन, जिसका परास लम्बा था, नये प्रकार के टैंक गोलाबारूद, नया टैंकमार गोलाबारूद और विमानभेदी तोपें और गोलाबारूद के उत्पादन की स्थापना।

आवडी में एक नया बल्ल-कारखाना बनाया गया। सिले बल्ल बनाने के अलावा, इसने अक्टूबर, १९६३ में, पैरासूट का उत्पादन शुरू कर दिया। चण्डीगढ़ में नये आर्डेनस-केबुल-कारखाने ने भी सितम्बर, १९६३ में उत्पादन शुरू कर दिया।

छोटे अल्ल और गोलाबारूद का उत्पादन बढ़ाने के लिए छ नये आर्डेनस कारखानों की स्थापना आयोजित की गयी। इसमें ये शामिल थे। छोटे अल्ल गोलाबारूद का कारखाना, बनगाँव ( महाराष्ट्र ) में जिसके लिए अतिरिक्त अमेरिकी मंजूर उपलब्ध कर दिये गये, गोला बनाने के लिए अम्बाभड़ी में एक कारखाना, तिश्चिरापल्ली में एक छोटे अल्ल का कारखाना, विस्फोटकों के निर्माण के लिए बुर्ला में एक कारखाना, प्रणोदी ( प्रोपेलैंट ) बनाने के लिए पानवेल में और चन्द्रपुर में एक-एक फिलिंग कारखाना। नये कारखाने बनाते समय विद्यमान कारखानों में पुराने और फिसे उपकरणों के बदलने के लिए भी कार्रवाई की गयी। बनगाँव वाला कारखाना १५ अक्टूबर, १९६४ को चालू हुआ। अग्नारा में विस्फोटक के उत्पादन के लिए एक कारखाने को, जिसको आयोजना पहले बन चुकी थी, दिसम्बर, १९६४ में चालू कर दिया गया, अम्बाभड़ी और चन्द्रपुरी के कारखानों पर काम चल रहा है।

पश्चिमी जर्मनी के सहकार से जवलपुर में एक नया मोटरगाड़ी का कारखाना स्थापित किया जा रहा है।

बुर्ला में तीव्र विस्फोटक और पानवेल में प्रणोदियों ( प्रोपेलैंट ) के निर्माण वाली आयोजनाओं की लागत, २० करोड़ रुपये के विदेशी विनिमय को शामिल करते हुए, ६२ करोड़ रुपये अन्दाजी गयी थी, पर उनको फिनहाल रक्षा-आयोजना से निकाल दिया गया है और उनकी जगह, तीव्र विस्फोटकों और प्रणोदियों की जरूरत, स्टॉक इकट्ठा करके पूरी की जायेगी, जो कम खर्चीला होगा।

आपात के आरम्भ के बाद आर्डेनस कारखानों में अतैय्य चीजों का उत्पादन कम हो गया। वस्तुतः, साम्राज के घटकों के निर्माण और सामान्य इन्जिनियरी भण्डार की चीजों को अतैय्य उपयोगों से बनवाने का प्रयास बढ़ाने के लिए, नवम्बर, १९६१ में, रक्षा-मन्त्रालय में हो रक्षा-यूक्ति-विभाग की स्थापना की गयी।

सचिवालय के अलावा, रक्षा-उत्पादन-विभाग में, नीचे लिखे पदाधिकारी आदि सलग्न हैं, जो अपेक्षित तकनीकी सलाह देते हैं और सरकार के निर्णयों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार हैं।

- (१) आर्जेंट-कारखाना-महानिदेशक।
- (२) निरीक्षण-महानिदेशक।
- (३) अनुसन्धान और विकास-संगठन।
- (४) आयोजना और समन्वय-निदेशालय।
- (५) मानकीकरण-निदेशालय।
- (६) तकनीकी विकास और उत्पादन (वायु)-निदेशालय।

### ख—सरकारी उद्योग-क्षेत्र के उपक्रम

#### हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स, लैम्बर्ट

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड की स्थापना २३ दिसम्बर, १९४० को बंगलूर में एक निजी लिमिटेड कम्पनी के रूप में ४ करोड़ रुपये की अधिकृत पूँजी और ४० लाख रुपये की प्रदत्त पूँजी के साथ स्थापित की गयी, जिसका आधा, योजना के मूल-अस्थापक बालबन्ध हीराचन्द ने दिया था और आधा, मैसूर सरकार ने। मार्च, १९४१ में भारत सरकार का उद्योग और पूर्ति-विभाग भी एक साझेदार बन गया और प्रदत्त पूँजी बढ़ाकर ७५ लाख रुपये कर दी गयी। प्रत्येक साझेदार का हिस्सा २५-२५ लाख रुपये था।

कारखाने ने आयात किये गये पुर्तकों का समायोजन करके विमान बनाया शुरू किया और पहला विमान १९४१ में बना। मार्च, १९४२ में हिन्दु० एय० लिमिटेड को भारत सरकार ने अपने सीधे नियन्त्रण में, एक मुद्र-कारखाने के रूप में चलाने के लिए, अपने हाथ में ले लिया। जून, १९४२ में भारत सरकार ने बालबन्ध हीराचन्द समूह के सारे हिस्से खरीद लिये, जिससे कम्पनी भारत सरकार और मैसूर सरकार की समुक्त कम्पनी रह गयी। मुद्रकाल में कम्पनी की दोसर पूँजी ७५ लाख रुपये रही। संचालन के लिये वसापेक्षित पैसा भारत सरकार पेशगियों की तरह व्यवस्था करती रही।

कम्पनी का उद्देश्य आरम्भ में भारत में सरकार के लिए विमानों का निर्माण करना था। जुलाई, १९४२ में यह नीति बदल दी गयी और यह निर्णय किया गया कि सामरिक विमानों, इजिनों और सम्बन्धित सहायक-यन्त्रों के ओवरहाल और मरम्मत की सुविधाओं का उपयोग किया जाय। भारत-द्वितीय समुक्त राज्य-अमेरिकी सेन्स-आयुध-योजना को निदेशक मण्डल के अध्यक्ष का सलाहकार बनाया गया। उनको ओवरहाल के कार्यक्रम के लिए जरूरी उपकरणों और अतिरिक्त व्यक्तियों और पूर्ति की भी व्यवस्था करनी थी। मितम्बर, १९४३ में चीन, बर्मा, भारत वायुसेना-कमान के कमांडिंग जनरल की मुद्रकाल के लिए कम्पनी का प्रबन्ध-अभिकर्ता नियुक्त किया गया। १९४३-४५ की अवधि में हिन्दु० एय० लिमिटेड ने विभिन्न प्रकार के १२०० विमानों और ३५०० इजिनों का ओवरहाल/मरम्मत की, और कई हजार

दन्त्रों और सहायक-सामान की। संयुक्त-राज्य-अमेरिकी, सैन्य-वायुसेना के साथ प्रबन्ध-अभिकर्ता सम्बन्धी करार दिसम्बर, १९४५ में समाप्त कर दिया गया।

युद्ध समाप्त होने पर, कम्पनी ने १ अप्रैल, १९४६ से, अपना काम एक वाणिज्यिक फर्म के रूप में करना शुरू कर दिया। मुख्य काम युद्धकाल के अतिरिक्त, डगलस मो-४७ विमानों के ओवरहाल और परिवर्तन का था। काम का भार कम हो जाने से मजदूरों की संख्या, सिल्वर काल के १४००० के स्थान पर, जनवरी, १९४६ में, लगभग ४००० रह गयी और लगभग १००० अमेरिकनो में से केवल दर्जन भर ही रह गये।

ब्रिटेन से एक तकनीकी मिशन १९४६ में भारत सरकार को भारत में विमान-उद्योग की स्थापना के बारे में सलाह देने के लिए आया। मिशन ने सिफारिश की कि हिन्दु० एय० लि० इस उद्योग के विकास के लिए सर्वथा उपयुक्त केन्द्र था। मिशन ने यह भी सिफारिश की कि हिन्दु० एय० लि० को विशेषोक्त प्रकार के रेल-सवारों के डिब्बे और सबक-परिवहन की बॉदियाँ, सहायक उद्योग के रूप में, बनानी चाहिये।

तकनीकी मिशन की सिफारिशों के अनुसार हिन्दु० एय० लि० को एक लाइसेंस-करार के अधीन भारतीय वायुसेना के लिए 'परसीबल' प्रेंटिस-प्रशिक्षक-विमान के समायोजन और निर्माण का काम सौंपा गया। हिन्दुस्तान एय० द्वारा बनाये गये पहले प्रेंटिस विमान ने अप्रैल, १९४८ में उड़ान भरी।

मार्च, १९४८ में कम्पनी की टोयल पूंजी १ करोड़ रुपये बढ़ा दी गयी और फिर और अतिरिक्त रकम मँगाकर यह १८०.२४६ लाख रुपये कर दी गयी। हिन्दु० एय० लि० में किया जाने वाला अधिकांश काम वायुसेना के लिए था। वायुसेना का विकास और हिन्दु० एय० लि० का विस्तार साथ-साथ जुड़ा हुआ माना गया। इसलिए सरकार ने जनवरी, १९५१ में यह निर्णय किया कि इसका प्रशासनिक-नियन्त्रण उद्योग और पूर्ति-मन्त्रालय से रक्षा-मन्त्रालय को स्थानान्तरित कर दिया जाय। १९५२-५३ में हिन्दु० एय० लि० की टोयल पूंजी २ करोड़ रुपये और बढ़ा दी गयी, ताकि कम्पनी अपनी विभिन्न विकास-आयोजनाओं में पैसा लगा सके। यह पूरी रकम भारत सरकार ने दी थी।

यद्यपि इस कम्पनी के कार्य एक निदेशक मण्डल के सर्वोपरि नियन्त्रण में आ गये थे, जिसमें भारत सरकार के पाँच प्रतिनिधि शामिल थे, नामतः रक्षा-सचिव (अध्यक्ष), चीफ ऑफ एयर स्टाफ, वित्तिय-सलाहकार (रक्षा), डे० आर० डी० टाटा और एक प्रबन्ध निदेशक और मैसूर सरकार का एक प्रतिनिधि। १९५० में विमानों में ओवरहाल और मरम्मत के अलावा हिन्दु० एय० लि० ने विमान-निर्माण का भी कार्यक्रम हाथ में ले लिया। जून, १९५० में एक लाइसेंस-करार के अधीन भारतीय वायुसेना के लिए लडाकू 'वैम्पायर जेट' का उत्पादन हाथ में लिया गया।

१९४८ में हिन्दु० एय० लि० में भारतीय मुख्य आकल्पकर्त्ता के अधीन एक आकल्प और विकास-अनुभाग खोला गया। इस अनुभाग ने बुनियादी प्रशिक्षक विमान, एच० टी० २, का आकल्प और विकास किया, जिसके पहने आदर्श ने १३ अगस्त, १९५१ को पूरा करने पर, परीक्षण की उड़ान भरी थी। इस विमान ने १९५२ में संचार-मन्त्रालय से वायुवहन योग्यता

का प्रकार-प्रमाण-यत्र प्राप्त किया और उसके बाद विमान का भारी मात्रा में निर्माण शुरू हुआ।

१९४७ में हिन्दु० एय० लि० ने एक सुघर प्रकार के पूर्णधातुक तीसरे दर्जे के ब्रॉड नेज के सवारी डिब्बे का निर्माण भारतीय रेलवे के लिए स्थापित किया, जो देश में बहुत लोकप्रिय रहा। साथ ही कम्पनी ने विभिन्न राज्यों और परिवहन-अधिकारियों के लिए पूर्णधातुक इकमजिली और दुमजिली बसें भी बॉडियो के साधान का भी निर्माण शुरू किया। १९४६ के उत्तरार्द्ध में जर्मनी फर्म मान के साथ हिन्दु० एय० लि० में इकमेल रेन सवारी डिब्बों के निर्माण के लिए एक करार किया गया। इसमें प्रकार के सवारी डिब्बों के निर्माण के साथ-साथ परम्परागत प्रकार के सवारी डिब्बों का निर्माण कुछ समय तक चलता रहा, जो १९६० में बन्द कर दिया गया।

अप्रैल, १९५१ में कम्पनी का एक शाखा-कारखाना बैरकपुर में विमानों के ओवरहॉल और मरम्मत के लिए खोला गया।

१९५६ में सरकार ने ब्रिटेन के मेसर्स फौवैड एयरक्राफ्ट लिमिटेड के साथ हिन्दु० एय० लि० में नैट सहायक विमानों के निर्माण के लिए करार किया और दूसरा करार मेसर्स ब्रिस्टल एयरो इजिन लिमिटेड के साथ और आरकियस जेट विमान-इजिनो के निर्माण के लिए जो शक्ति के लिये 'नैट' विमानों में लगाया जाता है। डा० टैक के नेतृत्व में जर्मनी से विमान-निर्माण-विशेषज्ञों की एक टीम भारत में आधुनिक विमान के आगमन और विकास के लिए लगायी गयी। कई भारतीय इन्जीनियर भी इस इस टीम के साथ नियुक्त किये गये।

हिन्दु० एय० लि० द्वारा विकसित एक बहुत हल्के विमान, 'पुष्पाक', ने २४ मितम्बर, १९५८ को सकलगावर्क उड़ान भरी और उसका भारी सफा में उत्पादन शुरू हो गया। बुनियादी जेट-प्रशिक्षण विमान का विकास १९६० में शुरू किया गया। उसी साल आरकियस विमान-इजिनो का निर्माण भी शुरू हो गया।

हिन्दु० एय० लि० द्वारा माजिलित और विकसित अनिन्दन जेट विमान एच० एफ० २४, एम० के० १ के आधारेण ने पहली सफल उड़ान १७ जून, १९६१ को भरी। उसी साल आयातित कच्चेमाल से नैट विमान का निर्माण भी शुरू हुआ और एच० टी० २ का उत्पादन बन्द कर दिया गया। हिन्दु० एय० लि० ने चार सौटों वाले हल्के विमान 'पुष्पाक' का सकल आकल्पन और विकास किया। कम्पनी ने शार्ट आर डा० ७ इजिनो का निर्माण भी ब्रिटेन की फर्म से साइसेंस-कार करके शुरू किया। यह इजिन एरो-७८८ विमानों में लगाया जाता है, जिसका निर्माण विमान-निर्माण-इजिनो, बालपुर में शुरू किया गया।

१९६३ में सरकार ने नौवें निम्नी प्रायोक्ताओं का निष्पादन हिन्दुस्थान एयरक्राफ्ट लिमिटेड को सौंपा (ए०) एनोएट हैनोकीप्टरो का निर्माण मूड एवियेशन क सहकार से और आरटीडम्ट इजिनो का निर्माण टरबोमेका के सहकार से—दोनों फर्मो मान्य की थी। (दो) भारती मिट्टी हटाने और खनन के उपकरण स० रा० अमेरिका की ती टोनिपू बेन्टिंग हाटस कम्पनी के सहकार से और (तीन) ब्रिटेन के हार्ड इयूटी एलीयन लिमिटेड के सहकार से हल्की निष्पाद और गहरी नीचों का निर्माण। मिट्टी हटाने की भारी मशीनों के

आरम्भिक प्रक्रम का काम, एक अलग लोक-उपक्रम बनने तक, रेल-सवारी-टिकट-प्रभाग को सौंपा गया (अब अलग उपक्रम बन गया है, जो भैरूर के कोयार जिले में 'भारत अर्थ मुवर्स लिमिटेड' नाम से बना है) ।

पहले दो एच० एफ० २४ विमान (जिनका नाम 'भक्त' रखा गया) हिन्दु० एप० लि० द्वारा निर्मित होकर मई, १९६४ में भारतीय वायुसेना को सौंप दिए गये । बुनियादी जेट प्रशिक्षक ने, जो पहले से विकसित हो रहा था, दिसम्बर १९६४ में आरम्भिक उड़ान भरी और इसका नाम 'किरण' रखा गया ।

इस बीच सरकार ने सोवियत सरकार से लाइसेंस करार करके एक इजिन वाले एम मिग-२१ लड़ाकू विमान के निर्माण के लिए तीन कारखाने स्थापित करने का निर्णय किया था, एक विमान-ढाँचे के लिए नासिक में, दूसरा इंजिन के लिए कोरापुट (उड़ीसा) में और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक और सम्बद्ध उपकरणों के लिए हैदराबाद में । अगस्त, १९६३ में एयरोनौटिक्स इंडिया लिमिटेड नाम की एक नयी लोक मर्यादित कम्पनी बनायी गयी, जिसकी जिम्मेदारी इन तीनों कारखानों की स्थापना और प्रबन्ध की थी और उसके लिए २५ करोड़ रुपये की अधि-दत्त पूंजी सगायी गयी ।

जनसाधन और प्रबन्ध के सीमित संसाधनों के अधिकतम उपयोग को आवश्यक करने की दृष्टि से मार्च, १९६४ में यह निर्णय किया गया कि विमान और सम्बद्ध उपकरणों का उत्पादन करने के लिए लोक-उद्योग-क्षेत्र का एक ही संगठन होना चाहिये । तदनुसार हिन्दु-स्तान एयरक्राफ्ट्स लिमिटेड और एयरोनौटिक्स इंडिया लिमिटेड का विलय करके 'हिन्दुस्तान एयरोनौटिक्स लिमिटेड' नामक एक नयी कम्पनी १ अक्टूबर, १९६४ से बनायी गयी । ब्रिटेन के हाकर सिडले एवियेशन के साथ लाइसेंस-करार करके, विचले परिवहन विमान (एब्रो ७४८) का निर्माण करने के लिये जुलाई, १९५९ में बताया गया विमान-निर्माण-शिप, कानपुर भी हिन्दुस्तान एयरोनौटिक्स लिमिटेड के साथ मिला दिया गया । हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट्स लिमिटेड का रेलकोच प्रभाग १ जनवरी, १९६५ से ववगठित भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड के प्रबन्धाधीन स्थानान्तरित कर दिया गया । १९६४ में कानपुर में बने दो एब्रो-७४८ विमान भारतीय वायु-सेना के स्क्वेड्रन में शामिल किये गये । कानपुर में एक सीट और दो सीट वाले ग्वाइडर भी बनते हैं । हिन्दुस्तान एयरोनौटिक्स की अधिकृत पूंजी अब ५० करोड़ रुपये है । सारे दोषर भारत सरकार के स्वामित्व में हैं । अब इसका एक पूर्णकालिक अध्यक्ष है । बोर्ड के अन्य सदस्य जो नाम से (पद से नहीं) नामित किये जाते हैं, वे इन पदों के धारी हैं : रक्षा-उत्पादन-विभाग के सचिव, रक्षा-मन्त्री के वैज्ञानिक-सलाहकार, वित्तीय-सलाहकार (रक्षा), चीफ ऑफ दि एयर स्टार, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलूर के निदेशक और प्रबन्ध-निदेशक ।

### भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलूर

पहले सशस्त्र सेनाओं द्वारा अपेक्षित अधिकांश विशेषीकृत उपकरण आयात किये जाते थे । इस उपकरण को एक श्रेणी सिविल सम्बन्धी सामान था । इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के निर्माण के लिए एक कारखाना खड़ा करने का निर्णय किया । एक

फासीसी फर्म (कम्पनी जनरल टेलोग्राफी सा फिन) के साथ ११ दिसम्बर, १९५२ को रेडियो, रडार और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर ( ब्राडकास्ट और टेलीविजन रिसीवर सैंटो को छोड़ ) का, मुख्यतः रक्षा सेनाओं और फिर केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों और राज्य सरकारों के लिए, उत्पादन करने हेतु एक कारखाना खड़ा करने के लिए हस्ताक्षर किये गये । इस प्रकार के उपस्करों की माँग बहुत ज्यादा है । भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का पञ्जीयन २१ अप्रैल, १९५४ को केन्द्रीय सरकार द्वारा ही पूर्णतः प्रदेय १० करोड़ रुपये की पूँजी के साथ किया गया । कारखाना वाणिज्यिक आधार पर एक निदेशक-मण्डल के साथ चलाया जाता है, जिसमें सरकार और तीन गैर सरकारी सदस्य हैं । कम्पनी ने उत्पादन-कार्य दिसम्बर, १९५५ में शुरू किया और धुल्ल-धुल्ल में उसने सामान्य-प्रयोजन संचार-रिसीवर और ४०० वाट संप्रेषित के लिए जहरी 'टूल' और 'जिग' बनाने का काम हाथ में लिया । १९६६ छात्रों की वांछित भरती के साथ एक प्रशिक्षण-विद्यालय भी चलाया गया । कम्पनी में ६०० कर्मचारी हैं । यह सन्ध्या क्रमशः बढ़ती गयी ।

विभिन्न विभागों की तरह-तरह की जरूरतें पूरी करने के लिए समय-समय पर अनेक विदेशी फर्मों के साथ तकनीकी सहकार-करार किये गये, नामतः जनवरी १९५६ में पाई टेली-कम्युनिकेशन्स लिमिटेड, इंग्लैण्ड से रक्षा-सेनाओं के लिए जहरी विशेष उपस्कर के निर्माण के लिए, अर्द्ध, १९५६ में हालैंड के फिलिप्स कं० के साथ बाल्व बनाने के लिए, अगस्त, १९५६ में मुख्यतः रेलवे द्वारा अपेक्षित अत्युच्च चारचारिता वाले बहुप्रणालीय उपस्कर के निर्माण के लिए, अक्टूबर, १९६० में जापान की निप्पन इलेक्ट्रिक कम्पनी के साथ मीडियम तरंग वाले प्रसारण-संप्रेषितों के निर्माण के लिए और १९६२ में टेपरिकार्डर और टेप-उफो के निर्माण के लिए, रडार उपस्करों के निर्माण के लिए स्विट्जरलैंड के कौट्रेक्स कं० के साथ, सितम्बर, १९६२ में हालैंड के फिलिप्स कं० के साथ ट्रांजिस्टरो के निर्माण के लिए और महत्वपूर्ण रक्षा-संचार उपस्करों के निर्माण के लिए जर्मनी के सार्दिनेन्स रेडियो और अमेरिका के रेडियो कारपोरेशन के साथ ।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने स्वयं भी इलेक्ट्रॉनिक उपस्करों की कई चीजें, उपयुक्त और सहायक यन्त्र और उपकरण आकल्पित और विकसित किये हैं, जिनका उत्पादन शुरू हो चुका है और जो रक्षा-सेनाओं, असेनिक विभागों और जनसाधारण को दिये गये हैं । ७० से ऊपर विभिन्न प्रकार के उपस्कर जो छाटे से आकार वाली से लेकर उच्च शक्ति वाले ट्रान्सीटरो तक हैं, और मुन्दर-मुन्दर रडार और वाक्व, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर और रिस्टल जैसे अनेक घटक पुर्जे बनाये गये हैं ।

जुलाई, १९६३ में रक्षा-भूतों के वैज्ञानिक मलाहाजार को निदेशक-मण्डल का अध्यक्ष नामित किया गया । इनमें अन्य लोगों के साथ-साथ वित्तिय सलाहकार (रक्षा), रक्षा-उत्पादन-विभाग का एक मयुक्त सचिव, सेना-मुख्यालय के सिगनल्स निदेशक, निरीक्षण महानिदेशक, लघु-उद्योग-निगम के अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा स्थापना के तकनीकी-मौलिकी-प्रभाग के प्रमुख, भारत सरकार के बेतार-सलाहकार और प्रबन्ध-निदेशक भी हैं ।

१९६५-६६ में उत्पादन का कुल मूल्य १० करोड़ रुपये से अधिक रहा ।

## ममगांव डॉक लिमिटेड, बम्बई

ममगांव डॉक लिमिटेड, बम्बई को, १९३४ के कम्पनी अधिनियम के अधीन, ब्रिटिश इंडिया स्टीम नैविगेशन कम्पनी और यू के को औरियटल स्टीम नैविगेशन कम्पनी को प्रमुख शेयरधारी के रूप में रखते हुए, निर्गमित किया गया। कम्पनी का मुख्य काम पोत-निर्माण और पोतों की मरम्मत था। १९६० में बम्बई की नौसेना गोदी-प्रागण के विस्तार के कारण नौ-सेना-वेडे के संधारण के लिए और भुविधार्य बढ़ाना जरूरी हो गया। काम की कमी से जो कम्पनी घाटे पर चल रही थी, अपने को बेचने लिए तैयार थी और उसे भारत सरकार के रक्षा-मन्त्रालय ने १९ अगस्त, १९६० के एक करार के अधीन अपने हाथ में ले लिया।

कम्पनी को अधिकृत शेयर पूंजी २०० लाख रुपये है। हाथ में लेते समय अशदान में हो गयी पूंजी ६३ लाख रुपये थी। अब यह बढ़ाकर १६० लाख रुपये कर दी गयी है। कम्पनी द्वारा निर्मित सबसे बड़ा पोत 'मेरेवा' है, जो १५०० टन का सबारी व मालवाही पोत है और इसका निर्माण अब्दमान नौकीबर होयसमूह के लिये १९६४ में पूरा किया गया।

गोवा में एक छोटा सा मरम्मत-गार्ड है, जो १९६३ में क्रिये के आधार पर इस कम्पनी को सौंप दिया गया।

ममगांव डॉक में विद्यमान सुविधाओं के विस्तार के लिए एक कार्यक्रम १.५ करोड़ रुपये की कुल लागत पर अनुमोदित किया गया है। इस कार्यक्रम के पूरे होने के फलस्वरूप पोत-निर्माण और मरम्मत क्षमता में काफी विस्तार हो जायेगा। नवम्बर, १९६४ में ब्रिटिश सरकार भारत सरकार को एक विनियम रक्षा-उद्योग में ४७ लाख डॉलर देने की तैयार हो गयी, ताकि तीन 'लीनडर' वर्ग के फ्रिगेट तैयार करने की बाहरी लागत पूरी की जा सके। ब्रिटेन के विकर्स आर्मस्ट्रॉंग और यैरो के साथ फ्रिगेट-निर्माण के लिए एक करार २२ दिसम्बर, १९६४ को निष्पादित किया गया और यह काम ममगांव डॉक को सौंप दिया गया। पहले फ्रिगेट के १९७१ में पूरे हो जाने की उम्मीद है। रक्षा-उत्पादन-विभाग के सचिव निदेशक-मण्डल के अध्यक्ष हैं और प्रबन्ध-निदेशक के अलावा अन्य सदस्यों में वित्त-मन्त्रालय (रक्षा) के एक अतिरिक्त वित्तीय सलाहकार, रक्षा-मन्त्रालय के एक संयुक्त-सचिव, नौसेना-गोदी-विस्तार-योजना के निदेशक, नौसेना-उप-प्रमुख, मैकिन्ज़न मैकेंबी एण्ड कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्ध-निदेशक, भारत के पंत-नियम के प्रबन्ध-निदेशक, हिन्दुस्तान डिस्पाईं लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक, निरीक्षण महानिदेशक और गार्डेन रीच वर्कशाप लिमिटेड के प्रबन्ध-निदेशक हैं।

## गार्डेन रीच वर्कशाप लिमिटेड, कलकत्ता

गार्डेन रीच वर्कशाप लिमिटेड, कलकत्ता १९३४ में, भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत, ब्रिटेन की ब्रिटिश इंडिया स्टीम नैविगेशन कम्पनी और रिबर स्टीम नैविगेशन कम्पनी को प्रमुख शेयरधारी के रूप में रखते हुए, निर्गमित किया गया। इसका काम अपने पोतों और जलयानों की मरम्मत और सफाई करना था। कम्पनी भारत सरकार के रक्षा-मन्त्रालय

ने १९ अग्रेन, १९६० के एक करार द्वारा अपने हाथ में ले ली। कम्पनी की सम्पत्ति ६४ एकड़ के क्षेत्र में फैली हुई है और नदी का सामना भी लगभग आधे मील का है। अधिग्रहण के समय अधिकृत पूँजी ३ करोड़ रुपये और डेपर अभिदत्त पूँजी ७० लाख रुपये थी। पिछले बढ़कर अब १०० लाख रुपये हो गयी है।

कम्पनी ने ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, हॉलैंड और जापान के सुप्रसिद्ध पोत-निर्माताओं के साथ सहकार-करार रते हैं और इसने अपने को टग, हलके नौसेना जहाज, नदी स्टीमर, जल नौका, वाज नौका, पीनटून नौका को धामिन करते हुए उयले आकषं बाने जनयानी के आकल्पन और निर्माण में बिरोपीकृत बनाया है।

कम्पनी ने जापान की होकेत्सू कम्पनी लिमिटेड के साथ मुबाइस वायु कम्प्रेसरों के निर्माण के लिए सहकार करार किया है। इसने परकिन्सन बीडल इजिन के साथ काम करके ८-१० टन क्षमता का रोडरोलर का भी आकल्पन और उत्पादन किया है। मेरीन बीडल इजिनों के निर्माण के लिए पश्चिमी जर्मनी की भान फ० के साथ एक सहकार-करार करने का काम इस कम्पनी को मीपा गया है।

वक्तता बन्दरगाह के कमिश्नरों के अध्यक्ष कम्पनी के निदेशक-मण्डल के अध्यक्ष हैं। प्रबन्ध-निदेशक के अलावा अन्य सदस्य रक्षा-उत्पादन-विभाग के एक संयुक्त सचिव, वित्त-मन्त्रालय (रक्षा) के अतिरिक्त वित्तीय-सहायकार, अन्तो सिपिंग कम्पनी लिमिटेड के तकनीकी-निदेशक, रक्षा-मन्त्रालय के एक संयुक्त-सचिव, नौसेना-मुख्यालय के सामग्री-प्रमुख, आर्मेन्स कारखानों के महानिदेशक, भारत के पोत-निष्पन्न के प्रबन्ध-निदेशक और हिन्दुस्तान रिपपाई लिमिटेड के प्रबन्ध-निदेशक हैं।

### प्रागा टूलस लिमिटेड, हैदराबाद

प्रागा टूलस १९४३ में लोक सीमित कम्पनी के रूप में छोटे औजार, नाप के यन्त्र आदि के निर्माण के लिए स्थापित किया गया था। कम्पनी का प्रशासन उद्योग-मन्त्रालय (भारी इजीनियरी विभाग) में, दिसम्बर, १९६३ में, रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) की उप-लब्ध क्षमता का उपयोग रक्षा-उत्पादन को करने में समर्थ बनाने के लिए कर दिया गया। कम्पनी मुख्यतः छोटे औजार और यथातथ्य यन्त्रों के निर्माण की विशेषज्ञ है। कम्पनी ने औजारों और काटने वाले ग्राहकों के निर्माण के लिए इगलैंड के जोस एण्ड डिपमेन और बरमा चको के निर्माण के लिए इगलैंड के जिअरने और ट्रेकर के साथ सहकार-करार किये हैं।

कम्पनी की अधिकृत पूँजी १.५ करोड़ रुपये है, जो पूरी-पूरी अभिदत्त है। लगभग १६ प्रतिशत डेपर केन्द्रीय सरकार के हैं, जबकि ३२ प्रतिशत और १२ प्रतिशत, प्रमत्त, आन्ध्र प्रदेश सरकार और जनसाधारण के हैं। निदेशक-मण्डल में अध्यक्ष के अलावा, रक्षा-उत्पादन-विभाग के एक संयुक्त-सचिव, वित्त-मन्त्रालय (रक्षा) के एक अतिरिक्त वित्तीय सहायकार, आन्ध्र प्रदेश सरकार के दो अधिकारी और प्रबन्ध-निदेशक हैं।

### भारत धर्म-मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर

रक्षा की जरूरतों के लिए और बड़ी-बड़ी सिवाई और बिजली आयोजनाओं के लिए



मिट्टी हटाने वाले तरह-तरह के भारी उपकरणों की माँग को दृष्टि में रखते हुए, एक नया कारखाना स्थापित करने का फैसला किया गया और इस प्रयोजन से अमेरिका के ले टोरनियू वेस्टिंग हाउस के साथ अवदूर, १९६२ में एक तकनीकी-सहकार करार किया गया। इस बीच यह प्रयोजना हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, बंगलूर के रेलकोच-प्रभाग द्वारा चलाई जा रही थी। अगस्त, १९६३ में यह तय किया गया कि मिट्टी हटाने के भारी उपकरण बनाने वाला यह नया कारखाना कोलार के सोना-क्षेत्र में स्थित किया जाय। भारत अर्थ-भूवर्ग को बंगलूर में ११ मई, १९६४ को ७.५ करोड़ रुपये की अधिकृत पूँजी के साथ पञ्जीबद्ध किया गया। हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड का रेलकोच-प्रभाग १ जनवरी, १९६५ से इस नयी कम्पनी के साथ मिला दिया गया। आइर्नस कारखानों में जो कोमालू काउलर बनाया जा रहा है, उसे भी भारत अर्थ भूवर्ग को स्थानान्तरित कर दिया जावेगा।

निदेशक-मण्डल में एक अध्यक्ष है और प्रबन्ध-विदेशक के अलावा वित्तीय-सलाहकार (रक्षा), केंद्रीय जल-विद्युत-आयोग का एक सदस्य, सोमा-मार्ग के महानिदेशक, रक्षा-उत्पादन-विभाग के एक सयुक्त-सचिव, मैमूर सरकार के एक मुख्य सचिव और रेलवे-बोर्ड के अतिरिक्त सदस्य (यान्त्रिक) इसके सदस्य हैं।

## अन्तःसेना-संगठन

उन संगठनों का उल्लेख किया जा चुका है जो रक्षा मन्त्रालय के सीधे प्रशासनिक नियन्त्रण में हैं क्योंकि वे तीनों सेनाओं को समान आवश्यकताओं को पूरा करने हैं। इनको अन्तःसेना-संगठन कहा जाता है। सैन्य-भूमि और छावनी-निदेशालय, सैन्य-विनियमों और प्रश्नों का निदेशालय और भारतीय सैनिक-बोर्ड (अब भारतीय सैनिक, नाविक और वायु सैनिक-बोर्ड), जो पहले भूतपूर्व रक्षा-विभाग के अधीन थे, अब सीधे रक्षा-मन्त्रालय के अधीन हैं। १५ अगस्त, १९४७ के बाद आइर्नस कारखाने और जन-सम्पर्क-निदेशालय सीधे मन्त्रालय के अधीन ला दिये गये।

रक्षा-उद्योग, रक्षा-विज्ञान-संगठन (अब अनुसन्धान और विकास-संगठन) और राष्ट्रीय सेनाछात्र-दल को अन्य अध्यायों में लिया गया है। तोय अन्तःसेना-संगठनों की बर्दा मोटे तौर पर इस अध्याय में की जा रही है।

### खण्ड—१ सैन्य-भूमि और छावनी-संगठन

सैन्य-भूमि और छावनी-संगठन सैन्य-भूमि और छावनी-निदेशक के अग्रीन काम करता है और छावनीयों के प्रशासन, रक्षा-भूमियों के अधिग्रहण, अभिरक्षा और परिष्कार, रक्षा-सेनाओं और अन्य रक्षा-प्रयोजनों के उपयोग के लिए जमीन और भवन किराये पर लेना या अधिग्रहण करना और रक्षा-सेना की जरूरतों से अतिरिक्त होने वाले रक्षा-मन्त्रालय की परिसम्पत्तियों के निपटान के लिए उत्तरदायी है।

छावनी शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी परिचालन (मैन्यूवर) आदि में भाग लेने सम्य सैनिकों के अस्थायी निवास-गृह। १५० साल से यह शब्द भारत के उन स्थायी सैन्य-केंद्रों के लिए प्रयुक्त हो रहा है, जहाँ सैनिकों को नियमित रूप से रखा जाता है। कचहारा स्वयं शोध में भी अब यह अर्थ आ गया है कि भारत में छावनी (कटोनमेंट) शब्द का अर्थ 'स्थायी सैन्य-केंद्र' है।

छावनीयों का प्रशासन छावनी अधिनियम, १९२४ (२९२४ का संख्या २) के अग्रीन चलाया जाता है। इस अधिनियम के अधीन, कमानीय के जनरल अफसर कमांडिंग इन फोर्, छावनी-बोर्ड के जरिये, अपने क्षेत्र की छावनीयों के सैन्य-प्रशासन के नियन्त्रण के लिए जिम्मेदार है।

### छावनीयों का प्रशासनिक ढाँचा

हर छावनी का एक छावनी-बोर्ड होता है, जिसमें प्रदेन, नामित और चुने हुए सदस्य

होते हैं। स्टेशन का अक्सर कमांडिंग पदेनत बोर्ड का प्रधान होता है और उपप्रधान चुने हुए सदस्यो द्वारा अपने में से चुना जाता है। अमेनिक जनसंख्या के आधार पर छावणियों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम वर्ग की छावणी के बोर्ड में १५ सदस्य होते हैं, द्वितीय वर्ग की छावणी में ६, ११ या १३ (अमेनिक जनसंख्या के अनुसार) और तृतीय वर्ग की छावणी में ३ सदस्य। सभी मामलों में पदेन प्रधान को छोड़कर अधिकांश और चुने गये सदस्यो की संख्या बराबर रहती है। हालांकि चुने गये सदस्यो की तुलना में अधिनियम के अनुसार नामित सदस्यों से एक का बहुमत होता है, पर छावणी-प्रशासन में लोकतन्त्र लाने की दिशा में एक कदम के रूप में १९५७ से अनुदेश निकाले गये थे कि एक नामित सदस्य को जहाँ खासो रखी जाय, ताकि चुने गये और नामित सदस्यों की संख्या बराबर रहे। छावणी अधिनियम का संशोधन करके इसे सविहित बना देने का भी विचार है। सदस्यो की पदावधि तीन साल है, पदेन सदस्यों को छोड़कर जो उस पद के धारी रहने तक, जिसके कारण सदस्य है, बोर्ड के सदस्य बने रहते हैं। जिन बोर्डों में एक से अधिक चुने हुए सदस्य होते हैं उनमें एक उपप्रधान भी होता है, जो चुने गये सदस्यो द्वारा केवल अपने में से चुना जाता है। बोर्ड के दैनन्दिन कार्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा चलाये जाते हैं।

बोर्ड के चुनाव में मत देने के लिए योग्य व्यक्तियों के नाम बताने वाली मतदाता-सूची तैयार करके प्रकाशित कर दी जाती है। छावणी-बोर्डों के लिए होने वाले चुनावों में वयस्क मताधिकार लागू कर दिया गया है। प्रत्येक प्रथम या द्वितीय वर्ग की छावणी में बोर्ड द्वारा बोर्ड के चुने सदस्यो, स्वास्थ अधिकारी और कार्यपालक अधिकारी की एक समिति छावणी के ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के लिए बना दी जाती है, जिनको अमेनिक क्षेत्र अधिसूचित किया जाता है और जिनको पहले बाजार-क्षेत्र कहा जाता था। बोर्ड का उपप्रधान इस समिति का अध्यक्ष होता है। हर छावणी-बोर्ड एक नगरपालिका समिति मान लिया जाता है और बोर्ड, केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से, छावणी में ऐसे कर लगा सकता है, जो उस राज्य की किसी नगरपालिका द्वारा लगाये जा सकते हैं, जिसमें कि राज्य स्थित है। छावणी अधिनियम, १९२४ का सामान्य ढांचा अधिकांश नगरपालिका कानूनों जैसा ही है। इसलिए, हालांकि छावणी-बोर्ड में एक सरकारी प्रधान होता है और कुछ नामित सदस्य, फिर भी चुने गये सदस्यो का, छावणी के प्रमुखतः अमेनिक क्षेत्रों के प्रशासन में, काफी प्रभाव रहता है।

### सैन्य-सम्पदा-अधिकारी

छावणी की भूमियो का प्रबन्ध, (१) छावणी-बोर्डों के प्रबन्ध में सौंपे गये या उनमें निहित की गयी की और (२) जो रक्षा-सेनाओं के सक्रिय उपयोग में नहीं आ रही उनको छोड़कर, सैन्य-सम्पदा-अधिकारियों के उत्तरदायित्व में आता है। उनको रक्षा-सेनाओं के लिए भूमि-भवन अभिग्रहण करने, किराये पर लेने और अवाप्त करने का, और उनकी ज़रूरतों में अतिरिक्त हो गयी परिस्थितियों के परिणाम और निपटान का, उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है। जहाँ वाम के बोम्ब के कारण ज़रूरी होता है, वहाँ सहायक-सैन्य-सम्पदा-अधिकारी के उपकार्यालय

भी सैन्य-सम्पदा-अधिकारियों के अधीन बना दिये जाते हैं। जिन क्षेत्रों में किराये पर लेने और अधिग्रहण करने का काम ज्यादा होता है, वहाँ पर इस काम का समन्वय, नियन्त्रण और पर्यवेक्षण एक सहायक-निदेशक द्वारा किया जाता है।

### कमानों का ढाँचा

कमान-मुख्यालय में एक उपनिदेशक, सैन्य-भूमि और छावनी होता है, जो छावनी बोर्डों के नगर-प्रशासन के लिए जनरल अफ़्फ़र कमांडिंग इन चोफ़ का सलाहकार होता है। सैन्य-सम्पदा-अधिकारी कमानों के उपनिदेशकों के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

मुख्यालय में निदेशक, सैन्य-भूमि और छावनी, छावनी-बोर्ड द्वारा नगर-कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी सभी मामलों में और भूमि के प्रशासन और रक्षा सेनाओं के लिए सम्पत्तियों के प्राप्ति करने के बारे में, रक्षा-मन्त्रालय का सलाहकार होना है।

### युद्ध से पूर्व और विभाजन के बाद छावनियों की स्थिति

सेना की सहाय और स्थान के अनुसार छावनी क्षेत्र छोड़ दिये जाते हैं और व्यववर्धक नये स्थापित कर लिये जाते हैं। फलस्वरूप दूसरे महायुद्ध से पहले पूरे भारत में फैसी हुई ७७ छावनियाँ थी। इनमें से २८ उत्तरी कमान के अंगीत, २६ पूर्वी कमान के, १७ दक्षिणी कमान के और ६ पश्चिमी जिन्ना के अधीन थी। पिछले में मिथ और विलोचिस्तान आता था, जो प्रबन्धन, १९३८ में पश्चिमी कमान की जगह पर बनाया गया था। युद्ध काल में ४ नयी छावनियाँ बनायी गयी।

सत्ता-हस्तान्तरण के बाद भारतीय डोमोनियन में ५६ छावनियाँ थी, जिनमें से १४ पश्चिमी कमान में थी, २७ पूर्वी कमान में और १५ दक्षिणी कमान में।

मुरार छावनी ( खगलियर ) का प्रशासन नवम्बर, १९५१ में ले लिया गया और जम्मू और काश्मीर भाग की छावनियों का अप्रैल, १९५४ में। बरीना, देहू रोड और अजमेर में नयी छावनियाँ भी बनायी गयी थी अब भारत में ६२ छावनियाँ हैं।

### छावनियों सम्बन्धी केन्द्रीय समिति की नियुक्ति

छावनियों का जन्म विभिन्न सैन्य विधियों की तरह हुआ और उनमें बेरक़, अन्कार, शस्त्रागार, हवाई अड्डे, परेड मैदान, सैन्य-अभियन्त्रक मैदान, चाँदमारी, फार्म, भट्टे, अस्पताल, सैनिक उद्यान आदि, और असेनिकों के बच्चे वाले क्षेत्र होते हैं, जिनकी 'आवास-क्षेत्र' कहा जाता है। हाल के वर्षों में अमेनिक जनसंख्या भी काफी बढ़ गयी है। अम्बाला, पूना और मेरठ जैसी कुछ छावनियों में अमेनिक जनसंख्या ५०,००० से ज्यादा है, जब कि दूसरों में अमेनिक जनसंख्या बहुत कम है और छावनियों का सैन्य निर्धार वाता पुराना रूप बना हुआ है। छावनियों में अमेनिक आवादी के बढ़ने से नगर प्रशासन की अतिरिक्त समस्याएँ भी सामने आयी।

भारत सरकार के स्वास्थ्य-मन्त्रालय द्वारा स्थानीय स्वशासन मन्त्रियों का जो सम्मेलन

४ अगस्त, १९४८ को बुलाया गया था, उसने छावनी-प्रशासन पर भी चर्चा हुई। सैनिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के हितों के कारण सम्मेलन ने माना कि जहाँ सैनिक निवास करते हैं, वे क्षेत्र सेना-अधिकारियों के सामान्य नियन्त्रण में रहने चाहिये, पर सम्मेलन ने यह सिफारिश भी की कि केन्द्रीय सरकार छावनी-क्षेत्रों का परिसीमन करने के लिए, और छावनी अधिनियम में संशोधन करने की वाञ्छनीयता के प्रश्न की जाँच करने के लिए, एक समिति की स्थापना करे।

सरकार ने निर्णय किया कि छावनियों की सीमाओं की फिर जाँच होनी चाहिये, ताकि छावनियों को उन असेनिक क्षेत्रों से पृथक् किया जा सके, जिनका सशस्त्र सेनाओं की स्थापनाओं और सैनिकों के साथ कोई संघर्ष माना नहीं है या मामूली माना है और सीमा में ऐसे समझौते किये जा सकें, जो प्रशासनिक, सुरक्षा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उपयुक्त हों। १७ जनवरी, १९४९ को छावनी सम्बन्धी केन्द्रीय समिति, सचिवान-सभा-सदस्य श्री एस० के० पाटिल की अध्यक्षता में, छावनी-क्षेत्रों के परिसीमन और छावनी अधिनियम में संशोधन की वाञ्छनीयता के प्रश्नों की जाँच करने के लिए गठित की गयी।\*

### केन्द्रीय समिति का प्रतिवेदन

केन्द्रीय समिति ने अपना प्रतिवेदन नवम्बर, १९४९ में प्रस्तुत किया। समिति का विचार था कि छावनियाँ प्रमुखतः सैन्य-केन्द्र हैं, न कि नागरिकों के नगर। असेनिक भाग, जो अनेक मामलों में बहुत छोटे-छोटे थे, वे भी सेना के 'आ जाने के कारण', विशेषकर सेना की जरूरतों के आनुषंगिक बनकर ही, खड़े हो गये थे, समिति के विचार ने यह वाञ्छनीय था—

“कि छावनियों को, वस्तुतः, निकट भविष्य में, सैन्य-केन्द्र की तरह का, अपना मूल रूप बनाये रखना चाहिये और इसके लिए देश को राजनीतिक, आर्थिक और जन-स्वास्थ्य पक्षों सम्बन्धी वर्तमान वस्तुस्थिति का भी ध्यान रखना चाहिये। सैनिकों में सुरक्षा, अनुशासन और स्वास्थ्य की सन्तोषजनक स्थिति बनाये रखना, जो कार्य दक्षता के लिए जरूरी है, में कोई ख़तरा नहीं उठाया जा सकता और हमारा विचार है कि छावनी-क्षेत्रों के प्रशासन का, असेनिक बहुसंख्यकों की स्थानान्तरण, ऐसे प्रतिफलों वाला होगा जो सेना की कार्यक्षमता, उसके स्वास्थ्य और मनोबल के लिए घातक होंगे।”

समिति ने यह भी कहा कि छावनियों में असेनिक जनसंख्या के काफी घाट, प्रायः

\* समिति के अन्य सदस्य थे : आर० के० रामध्यानी, सचिव, रक्षा-मन्त्रालय (उपाध्यक्ष), आर० के० सिधवा (सचिवान-सभा-सदस्य), बम्बई, युस्त प्रान्त और पंजाब सरकारों के एक-एक प्रतिनिधि, क्वार्टर मास्टर जनरल (सेना-मुख्यालय), सशस्त्र सेना-बिजिलिया-सेना-महानिदेशक। सैन्य-भूमि और छावनी-निदेशक उसके सचिव थे।

बहुसंख्यक, ऐसे हैं जो स्थानान्तरण के प्रतिफलितों के प्रति आशङ्कित हैं और स्थिति में कोई परिवर्तन करने के घोर विरोधी हैं।

समिति इस नतीजे पर पहुँची कि बहुत सी छावनियों में अमेरिकी क्षेत्रों को काट कर अलग करना या तो भौगोलिक कारणों से सम्भव न था या वह क्षेत्र इतना छोटा था कि, नगर-प्रशासन के उपयुक्त मानकों की ज़रूरत का ध्यान रखते हुए, उनके लिए स्वयं एक अलग स्थानीय निकाय बनाना सम्भव न था। कुछ छावनियाँ विद्यमान नगरपालिकाओं के निकट थी और कुछ मामलों में इनके अमेरिकी क्षेत्र मिले जुले थे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए समिति ने छावनियों की तीन श्रेणियों में बाँटा, नामतः प्रथम श्रेणी, जिनमें सेना की ज़रूरतों से ज्यादा बहुत से क्षेत्र थे, जो काटकर अलग स्थानीय निकाय बनाये जा सकते थे, दूसरी श्रेणी में वे अमेरिकी क्षेत्र थे, जो इतने बड़े तो न थे कि अलग स्थानीय निकाय बन सकें, पर जिनका पड़ोस के निकाय में विलय किया जा सकता था, और तीसरी श्रेणी में अन्य दोष छावनियाँ। समिति ने सिफारिश की कि तीसरी श्रेणी की छावनियाँ और प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी की दोष छावनियाँ १९२४ के छावनी अधिनियम के अधीन प्रशासित बनी रहनी चाहिये।

इस वर्गीकरण को प्रभावित करने के लिए भारत सरकार ने प्रथम और द्वितीय श्रेणी की सभी छावनियों के लिए काट समितियाँ बना दी, जिनमें सेना कमान के सैन्य-भूमि और छावनी-उपनिदेशक और राज्य-सरकार, सेना-मुख्यालय, छावनी बोर्ड और छावनी के पड़ोस की नगर-पालिका के प्रतिनिधि रहे गये। काट-समितियों ने इस प्रश्न की ध्येयरेखा ज़ाँब की और अपनी सिफारिशों पेश कर दी। राज्य-सरकारों के साथ परामर्श करके और स्थानीय जनता के विचार जानकर, यह निर्णय लिया गया कि कानपुर, अहमदाबाद, बेलगाम, देवलासी, लहौर, नैनीताल, फीरोजपुर, लिङ्गूकी, मेरठ, पूना, सागर और अम्बाला के मामले में छावनी से कोई क्षेत्र न काटा जाना चाहिये। यह ध्यान देने की बात है कि छावनियों की अधिकांश अमेरिकी जनता किसी अमेरिकी क्षेत्र के काट दिये जाने के पक्ष में नहीं है। हालाँकि काट-समिति ने यह सिफारिश की थी कि दिल्ली छावनी से कोई इलाका न काटा जाय, तथापि भारत सरकार ने इस छावनी क्षेत्र से १६४० एकड़ का और ८१६५ की आबादी वाला इलाका अलग कर दिया। यह क्षेत्र पिछले विद्रोह में छावनी में शामिल किया गया था। काट की अन्तिम रूप देकर अधिसूचना अक्टूबर, १९५४ में प्रकाशित कर दी गयी। वास्तविक काट १९५६ में पूरी हुई। तबसे रक्षा की ज़रूरतों से ज्यादा पाए गए कुछ क्षेत्र आगरा, वाराणसी, भाँसी, इलाहाबाद और अहमदनगर की छावनियों से भी काट दिये गये हैं।

### छावनो-प्रशासन का और अधिक लोकतन्त्रीकरण

छावनियों के प्रशासन का और अधिक लोकतन्त्रीकरण करने के लिए भी कदम उठाये गये। छावनी अधिनियम, १९२४ की धारा २७ छावनी विधियाँ (विस्तार और मनोपन) अधिनियम, १९५० द्वारा संशोधित करके व्यवस्था मजबूत की गयी और, तबसे तथा राज्य-विधान मण्डलों की निर्वाचन-व्यवस्था के समान, निवास की योग्यता को बारह महीने के घटाकर छ महीने कर दिया गया। मई, १९५८ में यह निर्णय लिया गया कि छावनी-इलों की दलित, अमेरिकी क्षेत्रों के मामलों में (जिन को पहले बाजार-क्षेत्र कहते थे), भयन-

आयोजना और व्यवसाय-नाइसेसों के बारे में असेनिक क्षेत्र-समितियों को प्रत्याशान्वित कर दी जाय। अब असेनिक क्षेत्र-समितियाँ इन शक्तियों का प्रयोग काफी सीमा तक छावनी-बोर्डों से स्वतन्त्र रूप में कर सकने हैं। साथ ही असेनिक क्षेत्रों से इकट्ठा किया गया पैसा यथासम्भव इन क्षेत्रों के निवासियों के लाभ के लिए ही खर्च किया जाना चाहिये। छावनी-बोर्डों को सलाह दी गयी है कि कर-निर्धारण-समितियों में अधिकांश सदस्य गैर सरकारी होने चाहिये और बोर्डों का उपप्रधान ही समिति का अध्यक्ष होना चाहिये। यह आवश्यक करता है कि मनदाताओं के प्रतिनिधियों को निर्धारण-सूचियों के प्रमाणीकरण के साथ रखा जाता है, जिसमें प्रदेश कर-राशि बताया जाती है। अगर उपप्रधान किसी समिति का सदस्य होता है, तो वह स्वतः उस समिति का अध्यक्ष हो जाता है। स्टेशन के कमांडिंग अफसर को ३० दिनों तक की अस्थायी अनुत्पत्ति में वह छावनी बोर्डों की बैठकों की भी अध्यक्षता करता है।

अब छावनियों को बोर्डों में बाँट दिया गया है और आवश्यक होने पर, छावनी बोर्डों में, उनकी जनसंख्या के अनुसार, अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए भी जगह आरक्षित रहती जाती है। छावनी बोर्डों में चुनाव की रीति को भी बहुत कुछ राज्य-विधान-मण्डल/लोकसभा के चुनावों के ही समान कर दिया गया है। अगस्त, १९५७ से सभी प्रथम और द्वितीय घेणों की छावनियों में छावनी-बोर्डों में नामित और निर्वाचित सदस्यों के बीच समानता कर दी गयी है।

बासठ छावनियों में से ब्यालोस आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं है और फलस्वरूप भारत सरकार को उनको बनाये रखने के लिए काफी अनुदान देना पड़ता है। यह पहले ही निश्चय किया जा चुका है कि वित्तीय सहायता के बारे में कोई अन्तिम सीमा तय नहीं की जायेगी और सरकार को पञ्चवर्षीय-आयोजना-कार्यक्रम में छावनी-बोर्डों से वास्तविक और अनिवार्य कामों के लिए ली गयी पैमे की प्रार्थना पर विचार करना चाहिये। वित्तीय सहायता (क) छावनी-बोर्डों के वित्तीय समन्वय को बनाये रखने के लिए सामान्य अनुदानों और (ख) छावनी की कल्याण-योजनाओं के वित्तपोषण के लिए विशेष अनुदानों के रूप में विभिन्न छावनी-बोर्डों की तीसरी पञ्चवर्षीय-आयोजना के दौरान दी गयी थी।

१९६४-६५ के दौरान सरकार ने पूर्वोक्त प्रयोजनों से ६५ लाख रुपये का अनुदान दिया गया। १९६५-६६ में यह रकम ७० लाख रुपये के समान हो जाने की सम्भावना है। सरकार द्वारा छावनियों की असेनिक रक्षा सम्बन्धी ज़रूरतें पूरी करने के लिए सरकार ने एक विशेष अनुदान भी मंजूर किया है।

पहले छावनियों के हिस्सा की लेखा-परीक्षा उस राज्य के महालेखापाल द्वारा की जाती थी, जिसके राज्य-क्षेत्र में छावनी-विशेष स्थित होती थी। १ अक्टूबर, १९५१ से यह जिम्मेवारी भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा-विभाग से स्थानान्तरित करके सैन्य- (अथवा रक्षा) लेखा-विभाग को सौंप दी गयी और अब छावनियों की निधि की लेखापरीक्षा सम्बन्धित रक्षा-लेखा-नियन्त्रक/संयुक्त-नियन्त्रक करने हैं।

केन्द्रीय समिति की सिफारिशों के अनुसार १९२४ का छावनी अधिनियम छावनी (संगोपन) अधिनियम, १९५३ (१९५३ का अध्याय २) द्वारा संशोधित कर दिया गया। अब

केन्द्रीय सरकार के लिए यह बाध्यकर हो गया है कि किसी छावनी के पास स्थित किसी स्थानीय क्षेत्र को छावनी के भीतर शामिल करने के या किसी छावनी के भीतर आने वाले स्थानीय क्षेत्र को छावनी से बहिष्कृत करने के अपने इरादे की घोषणा करने से पहले, सम्बन्धित राज्य-सरकार से परामर्श कर ले। वस्तुतः ऐसी कार्रवाई के पहले राज्य सरकारों के साथ पहले भी हमेशा परामर्श किया जाता था, लेकिन तब केन्द्रीय सरकार के लिए ऐसा करना बाध्य-कर न था।

किसी अन्य स्थानीय प्राधिकार का सदस्य अब छावनी-बोर्ड के सदस्य के रूप में चुने जाने या नामित होने के लिए अर्ह नहीं रह गया है। 'बाजार-क्षेत्र' के स्थान पर 'अर्सेनल क्षेत्र' शब्द रद्द दिये गये हैं, क्योंकि 'बाजार-क्षेत्र' जनता की भावनाओं की दृष्टि से हीन समझा गया था।

### अर्सेनल क्षेत्रों का विस्तार

पिछले कुछ समय से केन्द्रीय सरकार छावनियों के अर्सेनल क्षेत्रों के विस्तार की बात सोच रही थी, ताकि उन क्षेत्रों के निवासियों को सुविधाएँ प्रदान की जा सकें। तदनुसार ऐसी सभी छावनियों में तदर्थ समितियाँ बना दी गयीं, जिनमें अधिसूचित अर्सेनल क्षेत्र थे, जिन से इन क्षेत्रों के विस्तार के बारे में सिफारिशें करने के लिए कहा गया। ६२ छावनियों में से २६ में अधिसूचित अर्सेनल क्षेत्र नहीं थे। क्षेत्र ३६ छावनियों में से छ में तदर्थ समितियों ने अर्सेनल क्षेत्रों के विस्तार की कोई सिफारिश नहीं की। इन तरह २७ छावनियों में अर्सेनल क्षेत्रों के विकास की सिफारिश की गयी (जिन में से तीन हाल में बनायी गयी छावनियाँ थी)। इनमें ॥ अधिकांश के बारे में कार्रवाई की अन्तिम रूप दिया जा चुका है।

### छावनियों में भूमि-नीति

छावनियों में निजी लोगों के बन्दों में जमीन तरह-तरह के भूमि-अधिकारों के अधीन होती है। कुछ "पुराने अनुदान" वाले क्षेत्र हैं। ये बंगाल, मद्रास और बम्बई की प्रेसीडेंसियों की सरकारों द्वारा १७८६ से १८६६ तक के वर्षों में समय-समय पर जारी किये गये नियमों, ब्रिटिशों और आदेशों के अधीन दिए गए हैं। फिर १८६६ और १९१२ की छावनी-संहिताओं के अधीन और छावनी-भूमि-प्रशासन-नियम, १९२५ और १९३७ के अनुसार दिये गये पढ़े हैं। देश की बदली हुई परिस्थिति का ध्यान रखते हुए छावनियों की भूमि-नीति का सरकार पुनर्विलोकन कर रही है।

### भूमि, किराया और निपटान-सेवा का बनाया जाना

#### भूमि, किराया और निपटान

युद्ध से पूर्व सशस्त्र सेनाओं के लिए ज़रूरी भूमि-मवन की किराये पर लेने का प्राथमिक उत्तरदायित्व सैन्य इंजीनियरी सेवा का था, जबकि अवार्ति का काम छावनी-विभाग (अब से-य-भूमि और छावनी-सेवा) द्वारा लिया जाता था। युद्धकाल में १९४४ तक से० ई० सेवा



भूमि-भवन किराये पर लेती रही। भारत-रक्षा-अधिनिष्पन्न, १९३६ के अधीन सम्पत्तियों का अधिग्रहण या अवांति सैन्य-भूमि और छावनी-सेवा द्वारा किया जाता था। युद्ध के प्रगति करने पर विभिन्न रक्षा-यूनिटों को जमाने के लिए भूमि की माँग बहुत बढ़ती गयी। फलतः दिसम्बर, १९४४ में सेना-मुख्यालय के क्वार्टर मास्टर जनरल की शाखा के अधीन एक भूमि और किराया-सेवा बनाना बहुत जरूरी हो गया। ( १९४५ में युद्ध समाप्त होने पर इन भूमि, किराया और निपटान-सेवा कहा गया था )। यह भू० कि० नि० सेवा भारत के सीमा-क्षेत्र के भीतर रक्षा-सेवाओं द्वारा अपेक्षित (अथवा उसकी जरूरतों से ज्यादा हुई) भूमि और भवनों को किराये पर लेने, अधिग्रहण करने ( और प्रत्यर्पण या अधिग्रहण-रहित करने ) तथा उनसे पैदा होने वाले सब प्रकार के दावों के मुग्तान के लिए जिम्मेवार थी। भूमि, किराया और निपटान-सेवा स्थानीय असेनिक अधिकारियों से सीधे बात करती थी और यथावश्यक सैन्य इंजीनियरी-सेवा और सैन्य-भूमि और छावनी-सेवा से सलाह और सहायता ले लेती थी।

हालांकि बार्डन में यह सेवा बहुत थोड़े से अफसरों से बनी थी, पर फिर यह भूमि किराया और निपटान-सेवा काफी विस्तृत हो गयी और जनवरी, १९४५ में इसका विस्तार चरम सीमा तक पहुँच गया। मुख्यालय में एक महानिदेशक और दो निदेशक थे और प्रत्येक सेना-कमान में एक उपनिदेशक था, हर एरियर में एक सहायक-निदेशक, हर सब-एरिया में एक उप-सहायक-निदेशक और हर जिले या महत्वपूर्ण स्टेशन पर एक एरिया-भूमि-किराया और निपटान-अधिकारी नियुक्त किया गया। चरम अवधि में किराये पर लिये गये या अधिग्रहण किये गये भवनों और भूमियों की संख्या १७,००० तक पहुँच गयी और वार्षिक किराया-वापिस लगभग ६४५ लाख रुपये हो गया। युद्ध के बाद अधिकांश सम्पत्तियाँ जहरतों से एक-दम अतिरिक्त होती गयी और उनको यथासम्भव सीधता से उनके मालिकों को लौटा दिया गया। मुख्यालय में महानिदेशक और एक निदेशक का पद समाप्त कर दिया गया और निदेशालय एक निदेशक के प्रभार में आ गया।

१५ अगस्त, १९४७ की भूमि भवन-निपटान-सेवा मुख्यालय कमांडर के अधीन एक संयुक्त-रक्षा-स्थापना बन गयी और १५ नवम्बर, १९४७ तक इसी तरह बनी रही। पिछली सदी की भूमि-भवन और निपटान-निदेशालय, जो अब तक क्वार्टर मास्टर जनरल की शाखा का अंग था, रक्षा-मंत्रालय को स्थानान्तरित कर दिया गया और सैन्य-भूमि और छावनी-निदेशक साथ-साथ भूमि, किराया और निपटान के भी निदेशक हो गये। अतिरिक्त सम्पत्ति का प्रत्यर्पण करने के लिए और सरकार का वित्तीय दायित्व कम करने के लिए तेजी से कदम उठाये गये। १० सितम्बर, १९४७ तक जो किराये पर लिये गये भवन न छोड़े जा सके, उनका काम सैन्य-इंजीनियरी-सेवा को स्थानान्तरित कर दिया गया। लेकिन ३० सितम्बर, १९४७ तक छोड़े गये किराये के भवनों के बारे में अन्तिम क्षतिपूर्ति ( अर्थात् अधिग्रहण-काल समाप्त होने पर किराये के अन्तर्गत दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि ) के मुग्तान का निपटारा तब तक भूमि-किराया और निपटान-सेवा द्वारा किया गया, जब तक कि सभी मामलों का अन्तिम निपटारा न हो गया। १९४८ के मध्य में सैन्य-इंजीनियरी-सेवा को भूमि और भवनों को नये धोर पर किराये पर लेने के लिए भी उत्तरदायी बना दिया गया। इसी तरह नये अधिग्रहण

और अवांति सैन्य भूमि और छावनी-सेवा को जिम्मेवारी हो गया। दिसम्बर, १९४६ में भूमि-किराया और निपटान-निदेशक का पृथक पदनाम सैन्य-भूमि और छावनी-निदेशक के पद के साथ विलय कर दिया गया। नमानो का भूमि-किराया और निपटान-सेवा का काम सैन्य-भूमि और छावनी के उपनिदेशकों द्वारा, अपने कर्तव्यों के अलावा, अपने हाथ में ले लिया गया और विभिन्न एरिया और सब-एरिया में सैन्य-सम्पदा अधिकारियों द्वारा।

अतिरिक्त भूमि और भवनो को शीघ्र खोद देने पर, इन सम्पत्तियों को कब्जे में रखने के लिए, क्षतिपूर्ति के असस्य मामले उठ खड़े हुए और उनका शीघ्र निपटारा करने के लिए विशेष बचम उठाने पड़े। सक्रिया के पूर्वी रणक्षेत्र के निकट होने के कारण परिचमो बंगाल में यह सख्या बहुत ज्यादा थी। उस राज्य में ऐसे भवनो के अन्तिम क्षतिपूर्ति दावो का आपसी बातचीत द्वारा निपटारा करने के लिए तदर्थ समितियाँ बना दी गयी, जहाँ क्षतिपूर्ति के लिए कुछ प्रस्ताव किये गये थे, पर दावेदारो ने माने न थे और जहाँ वे लोग मध्यस्थ-निर्णायक के पास के मामलो को आपस से लेने के लिए राजी हो चुके थे। दूसरे राज्यों में विभिन्न सरकारो से अनुरोध किया गया कि तेजी से भुगतान की व्यवस्था कर दें और जिन मामलो में मालिक, कनवन्टर के निर्णय को न मानें, मध्यस्थ-निर्णायक नियुक्त कर दिये जायें। पश्चिमी बंगाल में नियुक्त की गयी तदर्थ समिति की जगह पर १६ मई, १९५५ को एक स्थायी समिति बना दी गयी, जिसमें रक्षा और वित्त-(रक्षा) मन्त्रालयो और भूमि-किराया और निपटान निदेशालय के प्रतिनिधि रखे गये। उनका काम क्षतिपूर्ति के शेष दावो का तेजी से निपटारा करना था। बाद में समिति को बिहार, उड़ीसा और आसाम राज्यों के दावो के निपटारे का भी काम सौंपा गया। यह स्थायी समिति भी ३१ मई, १९५६ को समाप्त कर दी गयी, जब इसे सौंपे गये काम का अधिकांश पूरा हो चुका था। क्षतिपूर्ति के दावो का जो छोड़ा-सा शेष काम रह गया था, उसके लिए तदर्थ समिति फिर बना दी गयी। अधिवृहीत, किराये पर ली गयी या अवाप्त की गयी भूमि के बारे में मध्यस्थ-निर्णायक एक अलीपुर में और एक बर्दवान में नियुक्त कर दिये गये।

### भूमि-किराया और निपटान-सेवा का समेटा जाना

अधिकांश काम पूरा हो जाने पर अप्रैल, १९५७ में यह तय किया गया कि भूमि-किराया और निपटान-संगठन को समाप्त कर दिया जाय और शेष काम को सैन्य-भूमि और छावनी-सेवा, क्वार्टर मास्टर जनरल की शाखा और इंजीनियर-इन-चार्ज की शाखा के बीच बाँट दिया जाय। फिर अप्रैल, १९६२ में जो शेष काम क्वार्टर मास्टर जनरल की शाखा और इंजीनियर-इन-चार्ज की शाखा को स्वयंभारित किया गया था, फिर सैन्य-भूमि और छावनी-सेवा-को सौंप दिया गया। इस समय लगभग ३५० जमीनें और भवन, जो पिछले विद्व युद्ध के दौरान किराये पर या अधिग्रहण करके लिये गये थे, अब भी रक्षा-सेनाओं के प्रचार पर आप्त हैं।

अक्टूबर, १९६२ में आपात की घोषणा के बाद से, सैन्य-भूमि और छावनी-संगठन के विशेषीकृत अनुभव की ध्यान में रखते हुए, उगे रक्षा-सेनाओं के उपयोग के लिए जरूरी अपन

सम्पत्तियों को किराये पर या अधिग्रहण करके लेने सम्बन्धी कार्यपालक काम के लिए उत्तरदायी बनाया गया। मार्च, १९६६ में बुद्धोत्तर काल में किराये पर ली गयी २८६ भूमियाँ भी, जो उस समय तक सैन्य-इंजीनियरी-सेवा के प्रभार में थी, सैन्य-भूमि और छावनी-संगठन को स्थानान्तरित कर दी गयी।

किराये पर या अधिग्रहण करके ली गयी सम्पत्तियों को, वक़ाअत मास्टर जनरल की वन्त योजना-समिति द्वारा, निरन्तर समीक्षा चलती रहती है, जो सम्पत्तियों को छोड़ देने या आगे रखे रहने के बारे में सरकार के पास अपनी सिफारिशें भेजती है।

इसके अलावा रक्षा-स्वामित्व वाली, किराये पर ली गयी, और अविपृहीत सम्पत्तियों के सम्बन्ध में आकड़े इकट्ठे और सञ्चालित करने के लिए एक विशेष टीम भी बनायी गयी है, जिसका अन्तिम लक्ष्य यह है कि सरकार यह निर्णय करने में समर्थ हो सके कि इनमें से कौन सी सम्पत्तियों को स्थायी रूप से रखा जाना चाहिये और कौन सी छोड़ दी जानी चाहिये।

### सैन्य-भूमि और छावनी-सेवा

१९३७ तक एक छावनी-विभाग चला आ रहा था, जिसका पुनर्गठन १ अप्रैल से एक भूमिशाखा और छावनी-कार्यपालक-अधिकारी-सेवा में किया गया। भूमि-शाखा में काम करने वाले अधिकारी, सैनिक अधिकारी थे, पर असैनिक सेवा में माने जाते थे। वे एक केन्द्रीय सेवा बनाते थे। छावनी-कार्यपालक-अधिकारी-सेवा में भरती संचयी लोक-सेवा-आयोग के जरिये की जाती थी। पूर्वोक्त पुनर्गठन के बाद भूमि-शाखा में कोई भरती न की गयी और बाकी सभी रिक्त स्थान छावनी-कार्यपालक-अधिकारी-सेवा के अधिकारियों में से चयन करके भरे गये।

१९४७ के आरम्भ में भूमि शाखा में १३ ब्रिटिश और १३ भारतीय अधिकारी थे। सारे वरिष्ठ पदों पर ब्रिटिश अधिकारी थे। पर छावनी-कार्यपालक-अधिकारी-सेवा में ६७ में से ६५ निपुणियों पर भारतीय अधिकारी थे।

यह मामला १९४७ में सशस्त्र-सेना-राष्ट्रीयकरण-समिति के साफने आया और फलस्वरूप दोनों सेवाओं को मिलाकर एकीकृत सेवा बना दी गयी। मिली-जुली सेवा का नाम सैन्य-भूमि और छावनी-सेवा रख दिया गया। समिति की सिफारिश पर १९४७ में यह भी निर्णय किया गया कि सैन्य-भूमि और छावनी-सेवा का तत्काल राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय और भविष्य में इस सेवा में केवल असैनिकों को ही प्रवेश दिया जाय।

नयी सेवा के नियम, ब्रिटीश सैन्य-भूमि और छावनी-सेवा (प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी) नियम, १९५१ कहा गया, १७ फरवरी, १९५१ से प्रभावी हुए। इन नियमों के अनुसार इस सेवा में सीधी भरती अन्य केन्द्रीय सेवाओं की तरह सचोप-लोक-सेवा-आयोग द्वारा ली गयी एक संयुक्त-केन्द्रीय-सेवा-परीक्षा के परिणाम पर की जाती है।

### खण्ड २—सशस्त्र-सेना-चिकित्सा-सेवाएँ

तबनीकी प्रशिक्षण के साथ सशस्त्र सेनाओं की कार्यक्षमता में स्वास्थ्य भी एक महत्त्वपूर्ण तत्व है। फिर भी इन सेनाओं की स्वास्थ्य की समस्याएँ और अपेक्षित स्वास्थ्य का मानक

असैनिक-जीवन वाले लोगों से भिन्न है। इसीलिए सभी देशों की सशस्त्र सेनाओं में सैन्य-चिकित्सा-सेवा अलग से गठन की जाती है।

तदनुसार भारत की सेना की भी अपनी अलग चिकित्सा सेवा रही है, जिसका नाम “भारतीय चिकित्सा-सेवा” था और जो १७६३ में शुरू हुई थी। सेना के विस्तार के साथ, जिसमें भारतीय मिराहियों की टुकड़ी का विस्तार भी शामिल था, चिकित्सा-सेवा का भी विस्तार करना पड़ा। भारतीयों को भारतीय-चिकित्सा-सेवा में पहली बार १८६० में लिया गया और १९२९ में एक भारतीय और दो यूरोपीय का अनुपात तय किया गया। एक सहायक सेवा, जिसका नाम था भारतीय-चिकित्सा-विभाग, भी बनायी गयी, जिसमें एक ब्रिटिश सर्जन था और एक भारतीय। पहली ब्रिटिश अधिकारियों और अन्य पदधारियों वाले अस्पतालों में सेवा के लिए थी और दूसरी भारतीय सैनिकों वाले अस्पतालों में। भारतीय सैनिकों के परिवार चिकित्सा-उपचार के पात्र न थे।

भारतीय-चिकित्सा-सेवा के अधिकारियों के अलावा रॉयल आर्मी मेडिकल-कोर के अधिकारी भी भारत की सेना के साथ, पदावधि के आचार पर, काम कर रहे थे। वे ब्रिटिश सैनिकों और उनके परिवारों की चिकित्सा सम्बन्धी जरूरतों की देखभाल करते थे। रॉयल आर्मी डेंटल-कोर और क्वीन अलेक्जेंड्रा की इम्पीरियल नर्सिंग सर्विस के भी अधिकारी थे और रॉयल आर्मी मेडिकल-कोर और रॉयल आर्मी डेंटल कोर के अन्य पदधारियों भी थे जो ब्रिटिश अधिकारियों, अन्य पदधारियों और उनके परिवारों की विभिन्न अस्पतालों में देखभाल करते थे।

ब्रिटिश और भारतीय सैन्य-अस्पताल अलग-अलग थे और अधिकतर स्टेशनों में पहुंचने के भवन आदि पिछने वालों के से ज्यादा अच्छे थे। भारतीय-चिकित्सा-सेवा अमेरिक और सैनिक जरूरतों के लिए एक मिली-जुली सेवा थी। अधिकारियों को पहुंचने सैन्य-स्कन्ध में कमीशन दिया जाता था और उम्र हान्ध में स्थायी हो जाने के बाद उनकी अमेरिक-स्कन्ध में जाने का विकल्प मिल जाता था। अमेरिक-स्कन्ध में नौकरी पर भी बुतावे जाने पर वे सेनाओं में काम करने के दायित्व से बंधे रहते थे।

दूसरे विश्वयुद्ध से पहुंचने रॉयल इन्डियन नैवी या भारतीय वायुसेना के लिए अलग चिकित्सा-सेवाएं न थी। भारतीय-चिकित्सा-सेवा के कुछ अधिकारी और भारतीय चिकित्सा-विभाग के कुछ अधिकारी ब्रिटिश-नौय दल्लों के लिए नौसेना के साथ सनान कर दिये जाने थे और वे तैनातों भारत की चिकित्सा-सेवाओं के निदेशक करते थे। भारतीय वायुसेना में भारतीय-चिकित्सा सेवा का कोई अधिकारी सलमन न था और उसका चिकित्सकीय कार्य रॉयल एयरफोर्स के चिकित्सा-अधिकारियों ( ब्रिटिश सेवा ) द्वारा देखा जाता था। मुद शुरू हो जाने और वायुसेना का विस्तार होने पर, आवश्यकतानुसार भारतीय-चिकित्सा-सेवा के अधिकार समर्पित करने वायुसेना में भेजे जाने लगे।

१९४१ में जब चिकित्सा अधिकारियों की मांग भारतीय-चिकित्सा-सेवा में उलम्य जनशक्ति के कहीं ज्यादा बढ़ गयी, तो ८० साल से कम आयु के अमेरिक डाक्टर और आई० एम० डी० के ब्रिटिश सर्जनों के अधिकारियों को भारतीय-चिकित्सा-सेवा में आगत कमीशन के

## अन्त-सेना संगठन

लिए पात्र मान लिया गया। फिर भी सेना के लिए चिकित्सा-अधिकारियों की माँग पूरी नहीं हो सकी और १९४३ में भारतीय-सेना-चिकित्सा-कोर नानक एक नयी कोर बनाने पड़ी। भारतीय-चिकित्सा-सेवा के सभी अधिकारियों को भारतीय-सेना-चिकित्सा-कोर में अध्यारोपित कमीशन दिये गये और भारतीय-आगत-कमीशन-प्राप्त अधिकारी भारतीय-सेना-चिकित्सा-कोर के लिए समर्पित किये गये। भारतीय-सेना-चिकित्सा-कोर में आगत-कमीशन असेनिक डाक्टरों को उन्नत कर दिये गये। इस तरह १९४३ के बाद सभी चिकित्सा-अधिकारियों को भारतीय-सेना-चिकित्सा-कोर में कमीशन दिये गये और उनको दयावश्यक नौसेना और वायुसेना में कमीशन-प्राप्त सेवा के लिये समर्पित किया गया। इस तरह एक प्रकार की एकीकृत चिकित्सा-सेवा का जन्म हुआ, हाँकि तीनों सेनाओं अपनी-अपनी चिकित्सा सम्बन्धी जहरतों की देख-भाल स्वतन्त्र रूप से करती थी। युद्ध के अन्त में रॉयल इंडियन नैवी के पर्येण अफसर कमांडिंग को सलाह देने के लिए एक प्रमुख चिकित्सा-अधिकारी आर० आई० एन० था और रॉयल इंडियन एयर फोर्स के एयर मार्शल कमांडिंग को सलाह देने के लिए प्रमुख चिकित्सा-अधिकारी (वायु मुख्यालय) था। चिकित्सा-सेवा-निदेशक दन-सेना की जहरतों की देखभाल करते रहे।

दूसरे विश्वयुद्ध के बाद अतिरिक्त माने गए अधिकारी सेवामुक्त कर दिये गये और आगत-कमीशन-प्राप्त चुने हुए अधिकारियों को भारतीय-सेना-चिकित्सा-कोर में स्थायी-कमीशन प्रदान किये गये।

१५ अगस्त, १९४७ को भारतीय-चिकित्सा-सेवा समाप्त कर दी गयी। सशस्त्र सेनाओं में काम करने वाले इस सेवा के अधिकारी भारतीय-सेना-चिकित्सा-कोर में स्थानान्तरित कर दिये गये और असेनिक पदों पर काम करने वालों को या तो सैन्य-सेवा में वापस आकर, भारतीय-सेना-चिकित्सा-कोर में स्थानान्तरित हो जाने का या केन्द्रीय राज्य-सरकारों के विवेकानुसार असेनिक पदों पर ही स्थायी रूप से रह जाने का विकल्प दे दिया गया। भारतीय-चिकित्सा-सेवा के जो अधिकारी सैनिक काम में सगे थे, उनकी भारतीय-सेना-चिकित्सा-कोर के नियमित अधिकारी मान लिया गया। भारतीय-सेना-चिकित्सा-सेवा का पूरा तरह भारतीय-करण कर दिया गया और सभी ब्रिटिश अधिकारी और अन्य पदधारी पेंशन या उपदान पा कर बने गये।

## राय-समिति

युद्ध के बाद जब स्थिति स्थिति में सेना के पुनर्गठन पर विचार चल रहा था तो यह मुद्दा पड़ा कि सशस्त्र सेनाओं की चिकित्सा-सेवाओं को एकीकृत कर दिया जाय। फरवरी, १९४७ में सरकार ने सशस्त्र-सेना-चिकित्सा-सेवाओं और अनुसन्धान-एकीकरण-समिति नियुक्त की जिसके अध्यक्ष डा० बी० सी० राय थे।\* समिति का काम भारत की सशस्त्र

\* समिति में तीन गैरसरकारी सदस्य थे, नामतः डा० ए० ए० ए० ए० ए०, कर्नल रामनाथ चौधरी और कैप्टन पी० बी० मुकुर्मी, और छः सरकारी सदस्य थे, नामतः भारत की चिकित्सा-सेवाओं के निदेशक (सेना); महानिदेशक, भारतीय-

सेनाओं के लिए एक एकीकृत-चिकित्सा-सेवा स्थापित करने और तीनों सेनाओं में चिकित्सा-अनुसन्धान को एकीकृत करने की वाञ्छनीयता और सम्भावना पर विचार करना और प्रतिवेदन देना था और यह भी प्रतिवेदन देना था कि सशस्त्र सेनाओं की एकीकृत-चिकित्सा-सेवा का सामान्य रूप क्या हो। समिति ने अपना अन्तिम प्रतिवेदन अगस्त, १९४७ के आरम्भ में दिया।

समिति ने चलसेना, नौसेना और वायुसेना की चिकित्सा-सेवाओं के एकीकरण और समूची सशस्त्र सेनाओं के लिए एक एकीकृत-चिकित्सा सेवा की स्थापना की सिफारिश की। इसका विचार था कि सशस्त्र सेनाओं के लिए चिकित्सा-अनुसन्धान का भी एकीकरण करके वह एक केन्द्रित जगह पर चलाया जाय, जहाँ पर सम्बद्ध विज्ञानों में अनुसन्धान का वातावरण हो। वस्तुतः उस समय तक भारत में कोई भी उल्लेखनीय तन्त्र सशस्त्र सेनाओं की चिकित्सा-समस्याओं पर अनुसन्धान-कार्य चलाने के लिए था ही नहीं।

समिति ने यह भी सिफारिश की कि सशस्त्र-सेना-चिकित्सा-सेवा की तीन शाखाएँ होनी चाहिये, नामतः चलसेना, नौसेना और वायुसेना। सेवा में भरती के तुरन्त बाद चिकित्सा-अधिकारी का प्रशिक्षण एक केंद्रीयकृत सत्या में थोड़े समय के लिए दिया जाय, ताकि वह तीनों सेवाओं के लिए समान बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त कर ले। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद छमे तीनों में से एक सेना में लगाया जाय, जिसके लिए सेना-विशेष की जरूरतों और व्यक्ति की इच्छा का ध्यान रखा जाय। वहाँ पर वह कई साल तक काम करे। सेवाकाल में उसे दो सेनाओं में भी थोड़े-थोड़े समय के लिए सुविधानुसार अन्तर के बाद जाना होना था, ताकि जब तक वह पढ़ाया वरिष्ठ हो, छमे तीनों सेनाओं के कार्य और चिकित्सकीय प.तों का अनुभव हो जाय। कुछ सेवाकाल के बाद एक चिकित्सा-अधिकारी की सेना की व्यवसाय-गत या अनुसन्धान-शाखाओं में से एक को चुन सेना होता था या विमुक्त प्रशासनिक शाखा को। जो चिकित्सा-अधिकारी व्यवसाय में ही रह जाना चाहते थे, वे बड़े समुक्त-अस्पतालों में परामर्श-दाता और विशेषज्ञ के रूप में काम करते थे, जहाँ चलसेना, नौसेना और वायुसेना के विभिन्न प्रकार के रोगों से पीड़ित रोगी उपचार के लिए भरती किये जाते थे। यह भी वाञ्छनीय समझा गया कि तीनों सेनाओं के विशेषज्ञ भी उसी क्षेत्र में काम करें, ताकि वे भी प्रायः पर्यावरण परस्पर परामर्श और विचार-विनिमय कर सकें।

समिति का यह भी विचार था कि भारत की सशस्त्र-सेना-चिकित्सा-सेवाओं का एक महानिदेशक होना चाहिये, जो आवश्यकतानुसार रक्षा-मन्त्री या, सशस्त्र सेनाओं का नियन्त्रण करने वाले सर्वोच्च कमांडर की, सशस्त्र-सेनाओं की चिकित्सा सम्बन्धी जरूरतों के बारे में

चिकित्सा-सेवा, रॉयल इंडियन नेवो के प्रधान चिकित्सा-अधिकारी, वायु-मुख्यालय (भारत) के प्रधान चिकित्सा-अधिकारी, भारतीय-सेना-चिकित्सा-सेवा के उप-निदेशक (जो भारतीय-चिकित्सा-सेवा में एक वरिष्ठ अधिकारी थे)। लेफ्टी० कर्नल एस० पी० भाटिया, भारतीय चिकित्सा-सेवा भारतीय-सेना चिकित्सा-सेवा इस समिति के सचिव थे।

सलाह दे। वह भारत की सशस्त्र-सेना-चिकित्सा-सेवाओं का प्रशासन-प्रमुख होगा। सशस्त्र-सेना-चिकित्सा-सेवा (प्रशासनिक और व्यवसायिक दोनों) की तीनों शाखाओं के प्रमुखों की एक सलाहकार-समिति भी महानिदेशक को मदद और सलाह देने के लिए बनायी जानी चाहिये।

जैसी कि समिति ने सिफारिश की थी, एकोकृत-चिकित्सा-सेवा के संगठन और प्रशासन के व्योरे तैयार करने के लिए, सेवा के सदस्यों, नामतः चिकित्सा-सेवा-निदेशक, पलसेना, प्रधान चिकित्सा-अधिकारी, रॉयल इंडियन नैवी और प्रधान चिकित्सा-अधिकारी वायु-मुह्यालय (भारत), की एक उपसमिति बना दी गयी।

१९४८ के आरम्भ में सरकार ने प्रतिवेदन पर विचार किया और सामान्यतः इसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। अगस्त, १९४८ में महानिदेशक, सशस्त्र-सेना-चिकित्सा-सेवाओं का पद लेफ्टी० जनरल के ओहदे में स्वीकृत किया गया। निदेशालय के लिये केन्द्रीय स्टाफ भी स्वीकृत किया गया। प्रधान चिकित्सा-अधिकारी, रॉयल इंडियन नैवी और प्रधान चिकित्सा-अधिकारी, वायु-मुह्यालय (भारत) में पदनाम बदलकर, कमश, निदेशक, चिकित्सा-सेवा आर० आई० एन० और निदेशक, चिकित्सा-सेवा, आर० आई० ए० एक० कर दिये गये। महानिदेशक सशस्त्र-सेना-चिकित्सा-सेवा के प्रमुख थे और उनका काम सरकार को, सशस्त्र सेनाओं की समस्त चिकित्सा नीति के बारे में, सलाह देना था। पलसेना, नौसेना और वायुसेना की चिकित्सा-सेवा के निदेशक, अपनी-अपनी सेना की चिकित्सा-समस्याओं के सम्बन्ध में, अपने-अपने कमांडरों (अथवा स्टाफ-प्रमुखों) को सलाह देने थे। महत्वपूर्ण मामलों से वे महानिदेशक को परिचित रखते थे। नीति और आयोजना के मामलों में भी महानिदेशक निदेशकों के साथ परामर्श करते थे। चिकित्सा-सेवा-सलाहकार-समिति नामक एक समिति भी बनायी गयी, जिसके महानिदेशक अध्यक्ष थे और सभी निदेशक सदस्य। सलाहकार-समिति विचारों के आदान-प्रदान और चिकित्सा संगठन तथा सेमिकों के चिकित्सा-उपचार और स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण मामलों के बारे में चर्चा करने का मंच है।

महानिदेशक एकोकृत-चिकित्सा-सेवा में अधिकारियों की भरती और उनके सेवामोचन या सेवानिवृत्ति के लिए तथा तीनों सेनाओं के लिए चिकित्सा-भण्डार की व्यवस्था करने के लिए भी उत्तरदायी है। वह एक प्रयत्न तकनीकी पुस्तकालय भी रखते हैं और तीनों सेनाओं के लिए चिकित्सा-अधिकारियों और सामयिकी आदि की भी व्यवस्था कराते हैं। साथ ही, चिकित्सा-सेवाओं के तीनों निदेशकों से परामर्श करते हुए, अन्त-सेना-नीतियों के लिए अधिकारियों का नामन करते हैं और तीनों सेनाओं के लिए निवारक औषधों सघन सेना-चिकित्सा के सभी पक्षों पर अनुसंधान के विकास-आयोजना और निदेशन का समन्वय भी करते हैं।

यद्यपि राय-समिति ने एक अलग और एकोकृत-सशस्त्र-सेना-चिकित्सा-सेवा के गठन की सिफारिश की थी, लेकिन विधिक और तकनीकी कठिनाइयों के कारण यह सिफारिश कार्यान्वित नहीं की जा सकी। इसके बजाय चिकित्सा-अधिकारियों की सेना-चिकित्सा-क्षेत्र में कमीशन दिये जाते रहे और वे दोष दोनों सेनाओं में समायोजित किये जाते रहे। नौसेना और वायुसेना के लिए अनुसंधान अधिकारियों को इस मेवाकाल के लिए अस्थायी-अध्यापक-कमीशन प्रदान कर दिये जाते हैं, वे नौसेना और वायुसेना के समकक्ष आह्वानों पर रहते हैं और सम्बन्धित सेवा की

वर्दी पहारते हैं। फिर भी सेवानिवृत्ति से थोड़े पहले उनको सेना-चिकित्सा-कोर में समरक्ष-सैनिक ओहदे में वापस भेज दिया जाता है।

एकोरुण के फलस्वरूप सेना-चिकित्सा-प्रशिक्षण-केन्द्र (पूना) और चिकित्सा-भण्डार-द्विपो के नाम बदलकर क्रमशः सरास-सेना-चिकित्सा-कॉन्वेज और सरास-सेना-चिकित्सा-भण्डार-द्विपो कर दिये गये।

एकोरु-चिकित्सा-सेवा के कार्यक्रम की समीक्षा प्राप्त अनुभव के प्रकाश में की गयी और महानिदेशक, सरास-सेना-चिकित्सा-सेवा के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का सजोचित अधिलेख (चाटर्) १९५४ में जारी किया गया। सजोचित अधिलेख में यह व्यवस्था है कि महानिदेशक सीनो चिकित्सा-सेवाओं के निदेशकों के साथ अधिकाधिक परामर्श करता रहे, ताकि अन्त-सेवा सम्बन्ध रखने वाले सभी मामलों पर चिकित्सा-सेवा-सलाहकार-समिति में चर्चा होती रहे, जिसका कार्यवृत्त, अब प्रस्ताव विचारार्थ रसा-मन्त्रालय भेजने से पहले, स्टाफ-प्रमुखों के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाता है।

सेना-चिकित्सा-कोर में स्थायी कमीशन प्रदान करने की चयन-पद्धति में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। युद्धकाल से कोर में भरती अल्पकालीन कमीशन के और स्थायी कमीशन के रूप में रहो है और उम्मीदवार चयन-बोर्ड के सामने सीधे उपस्थित हो सकते हैं। १९५६ से सचीव-लोकसेवा-आयोग द्वारा ली गयी स्पर्धा-परीक्षा के आधार पर, सेना-चिकित्सा-कोर के चयन-बोर्ड द्वारा साक्षात्कार लिया जाता है और सब से कुछ सहाय्य में स्थायी कमीशन प्रदान करने की पद्धति शुरू की गयी है। इस प्रकार भरती किये गये २५ उम्मीदवारों की पहली टुकड़ी जुलाई, १९५६ में बनावे गयी।

जैसा पहले ही बताया जा चुका है, १५ अगस्त, १९४७ से पहले सरकार ने ब्रिटिश सैनिकों के परिवारों के लिए चिकित्सा-उपचार को व्यवस्था कर रखा था, लेकिन भारतीय सैनिकों के लिए नहीं। स्वाधीनता के बाद कनिष्ठ कमीशन धारियों और अन्य पेशावरियों और नौसेना और वायुसेना में उनके समकक्ष के परिवारों को चिकित्सा-सुविधाओं का पात्र बना दिया गया।

युद्धकाल में एक इन्जिन-अङ्ग केन्द्र-सरास-सेना के उन व्यक्तियों के लिए इन्जिन-अङ्ग प्रदान करने के लिए खोला गया था, जिन्होंने युद्ध में घात पाये हो या आहत हुए हों। १९५१ में यह सुविधा भुगतान करने पर अमेरिका को भी उपलब्ध कर दी गयी और यह केन्द्र-चिकित्सा-सेवा (फल सेना) के निदेशक से सरास-सेना-चिकित्सा-सेवा के महानिदेशक द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया। इन्जिन-अङ्गों के निर्माण और सम्मत् की सुविधायें प्रदान करने के अलावा इस केन्द्र में एक बड़ा-सा उल्था-स्थल है, जिसमें आम्बुलैन्स-रोगियों के उपचार को व्यवस्था है। यह केन्द्र हड्डी की नियोम्यता और विरुणाङ्गता का भी उपचार करता है।

सरास-सेना-आयुर्विज्ञान-कॉन्वेज, पूना, सरास-सेना-चिकित्सा-सेवा के महानिदेशक के प्रशासनिक नियन्त्रण में है और इसकी स्थापना १ मई, १९४८ को तीनों सेनाओं के चिकित्सा-अधिकारियों को स्नातकोत्तर प्रशिक्षण देने और परा-चिकित्सकीय व्यक्तियों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने और अनुसन्धान-कार्य चलाने के लिए की गयी थी। जुलाई, १९६२ में एक



स्नातक-सम्बन्ध भी, छात्रों को पूना विश्वविद्यालय की एम० बी० बी० एस० उपाधि के लिए तैयार करने के लिए, चलाया गया। १९६४ में बी० एस० सी० ( नर्सिंग ) पाठ्यक्रम के लिए एक नर्सिंग कॉलेज भी चालू किया गया। सशस्त्र-सेना-आयुर्विज्ञान कॉलेज अनेक स्नातकोत्तर या डिप्लोमा परीक्षाओं के लिए पूना विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध है। अब यह एक विस्तृत भवन में स्थित है।

पहले भारतीय सैनिक दाँतों की चिकित्सा के पात्र न थे। युद्ध के आरम्भ में दन्तोपचार की जरूरत समझी गयी और भारतीय सेना दन्त चिकित्सा-कोर का एक केन्द्रक बनाया गया। सेना-चिकित्सा-कोर की ही तरह भारतीय सेना-दन्त चिकित्सा-कोर में भी आपात कमीशन दिये जाते थे। सशस्त्र-सेना-आयुर्विज्ञान-कॉलेज में एक दन्त-प्रशिक्षण-केन्द्र भी है, जो विभिन्न पाठ्यक्रम चलाता है और सेना-दन्त-चिकित्सा-कोर के व्यक्तियों को दन्त-स्वास्थ्य-रक्षाविज्ञ के रूप में प्रशिक्षित करता है। कनिष्ठ कमीशनधारियों और अन्य पदधारियों और नौसेना और वायुसेना में उनके समकक्ष के परिवारों को भी सशस्त्र-सेना दन्त-चिकित्सा-केन्द्रों में निःशुल्क दन्तोपचार (नये दाँत प्रदान करना छोड़कर) का पात्र बना दिया गया।

मवनूर, १९६२ में आपात की घोषणा होने पर सेना-चिकित्सा-कोर में, पूर्वतिथि के साथ उदात्तापूर्वक देने वाली शर्तों के साथ, आपात कमीशन आरम्भ किये गये। राज्य-सरकार के डाक्टरों की कोर में सेवाएं समर्पित करने की योजना भी शुरू की गयी। चिकित्सा अधिकारियों की बड़ी हुई माँग पूरी करने के लिए, अन्तिम वर्ष के एम० बी० बी० एस० छात्रों का चयन करके, उनको विश्वविद्यालय-प्रवेश-योजना के अधीन अल्प सेवा कमीशन (परिवीक्षा पर) प्रदान किये गये। उनको सेकिड लेफ्टिनेंट का ओहदा, ४०० रुपये महीने के समेकित वेतन के साथ, उनके अध्ययन के आखिरी बारह महीनों में इस शर्त पर दिया गया कि एम० बी० बी० एस० की अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे ५ साल तक अल्प सेवा कमीशन अधिकारी के रूप में नौकरी करेंगे।

सेवा में ज्यादा रंगरूटों की आकर्षित करने और उच्चतर पदों में उनकी उन्नति की बाधाएँ दूर करने के लिए सरकार ने १ जनवरी, १९६६ से सेवा-चिकित्सा-कोर के अधिकारियों की सेवा निबन्धन-शर्तों में कुछ सुधार मजूर किये। वे ये थे - (क) सेवा के पहले सात वर्षों में बुनियादी वेतन का २५ प्रतिशत अ-ग्रेडिड भत्ता प्रदान करना, दस से १५वें वर्ष तक ३३ प्रतिशत और १५वें वर्ष के बाद ४० प्रतिशत का भत्ता सभी मामलों में, ६०० रुपये मासिक के अधिकतम के अधीन रहते हुए, प्रदान करना। (ख) त्रिप्रेडियर के ओहदे तक अधिकारियों का प्राप्य विशेष वेतन में वृद्धि करना। (ग) लेफ्टी० कर्नल के ओहदे तक समयमान पदोन्नति में त्वरण। अ-ग्रेडिड भत्ता मजूर कर देने के बाद अब जनवरी, १९६६ से सेना-चिकित्सा-कोर के अधिकारी निजी ग्रेडिड नहो कर सकते। वस्तुतः, अग्रिम क्षेत्रों में ऐसी ग्रेडिड की कुछ गुंजाइश भी नहीं है। सरकार ने कुछ नियुक्तियों का दरजा भी बढ़ा दिया है, उदाहरण के लिए चिकित्सा-सेवा-(पलतेना), निदेशक का मेजर जनरल से लेफ्टीनेंट जनरल; चिकित्सा-सेवा (वायु) के निदेशक का एयर कमांडोर से एयर वाइस मर्चेंट, सशस्त्र-सेना-चिकित्सा-सेवा के

उप-महानिदेशक परामर्शक (सैन्य चिकित्सा), परामर्शक (चिकित्सा) और चिकित्सा-अनुसन्धान-निदेशक का त्रिग्रेडिपर से भेजकर अनरल ।

### खण्ड ३ सैन्य विनियम और फार्म-निदेशालय

प्रथम विश्वयुद्ध के तुरन्त बाद सेना विभाग में सेना के नियम, विनियम और प्रपत्रों में संशोधन करने के लिए, जो पुराने पड़ गये थे, एक छोटा-सा अनुभाग खोला गया । यह अनुभाग बाद में १९३१ में केन्द्रीय-संशोधन-अनुभाग कहा जाने लगा । इस अनुभाग के प्रमुख का पदनाम सैन्य विनियम और फार्म-निदेशक रखा गया । उस समय यह अधिकारी सेना विभाग के स्थापना अधिकारी का अनिवार्य काम भी देखता था ।

१९३६ में वित्तीय प्रकार के बुनियादी विनियमों के संशोधन और सन्धारण की जिम्मे-दारी वित्त-विभाग को स्थानान्तरित कर दी गयी, जबकि प्रशासनिक विनियमों से सम्बन्धित काम और सैन्य फार्मों के मुद्रण और वितरण का काम केन्द्रीय-संशोधन-अनुभाग में बना रहा, जिसका नाम १९४३ में प्रकाशन, फार्म और लेखनसामग्री-अनुभाग कर दिया गया । निदेशालय में दो अन्य अनुभाग ये नामतः पदक-अनुभाग और सेना-सूची-अनुभाग । ये तीनों अनुभाग साथ-साथ १९४६ तक रक्षा-अनुभाग में अलग-अलग रूप से काम करते रहे, जिसके बाद सारे कर्मचारियों को विभाग के एक ही रौस्टर पर लाकर रखा दिया गया ।

प्रकाशन, फार्म और लेखनसामग्री-अनुभाग-रक्षा-सेनाओं के नियमों और विनियमों के मुद्रण, यथावश्यक विदेशों से प्रकाशनों की प्राप्ति, रक्षा-सेनाओं की सभी इकाइयों के लिए लेखनसामग्री की सभी मदों की पूर्ति, यलमेना, नौसेना और वायुसेना के काम आदि का मुद्रण और व्यवस्था के लिए जिम्मेवार है । १९४१ में इस निदेशालय को फिर से सेना, नौसेना और वायुसेना के अनुदेश, अलग-अलग प्रत्येक सेना के लिए निकालने के लिए, जिम्मेवार बना दिया गया (अवर्गीकृत प्रकार के और विस्तृत परिचालन की अपेक्षा रखने वाले सरकारी आदेश प्रति सप्ताह इन अनुदेशों के रूप में जारी किये जाते हैं) । यह काम मूलतः सेना-सूची-अनुभाग कर रहा था । १९४२ में जब सैन्य विनियम और फार्म-निदेशालय को मिलवा ले जाया गया तो दिल्ली में मुद्रित होने वाले इन अनुदेशों के जारी होने में विलम्ब न होने देने के लिए यह काम दिल्ली में ही एक अनुभाग को सौंप दिया गया ।

पदक-अनुभाग समस्त सेनाओं के पात्र सदस्यों की पदक और अलंकरण जारी करने के लिए और भविष्य में जारी करने के लिए पदकों, अलंकरणों और पोंतों का भण्डार रखने के लिए जिम्मेवार है । विश्व महायुद्ध के बाद पदक-अनुभाग के सामने बहुत बड़ा काम था, क्योंकि ६० लाख के लगभग पदकों का वितरण करना था । वितरण में सोधना लाने के लिए यह दफ्तर १९४६ में कर्तव्यता से जाया गया, ताकि कतकता स्थित भारत सरकार के टक-साल के निरुद्ध रह सके, जो इन पदकों का विनिर्माण कर रही थी । वितरण का काम पूरा होने के बाद पदक-अनुभाग फिर दिल्ली वापस ले आया गया ।

सेना-सूची-अनुभाग सेना-सूची के संरक्षण के लिए जिम्मेवार है, जो सेना में काम कर रहे अधिकारियों के बारे में सूचना प्रदान करता है । मूलतः यह अनुभाग सेना-सुब्बानय की

सैन्य-सचिव-दाला के अधीन था और १९२०-२१ में इंडिया आफिस के सुमाव पर इसे सेना-विभाग में स्थानान्तरित कर दिया गया। (पर, नौसेना-सूची और वायुसेना-सूची के संकलन की जिम्मेवारी क्रमशः नौसेना और वायुसेना-मुख्यालयों की ही बनी हुई है)।

विभाजन के पश्चात् सेना-सूची का व्यवहारतः पुनर्संरचना करना जरूरी हो गया, क्योंकि बहुत भारी सस्या में अधिकारी स्थानान्तरित या सेवानिवृत्त हो गये थे।

दूसरे विश्वयुद्ध के बाद और खासकर सत्ता-हस्तान्तरण के बाद सेना, नौसेना और वायुसेना के विनियम पूर्णतः बनसतन हो गये और उनका पूरी तरह से फिर लिखना जरूरी हो गया। मुद्रण, फार्म और लेखन-मामूनी-अनुभाग, जो जारी किये गये सशोधित आदेशों के आगार पर बुनियादी विनियमों में संशोधन जारी करने के लिए जिम्मेवार था, इस प्रकार का काम निभाने में असमर्थ था। तदनुसार १९६१ में रक्षा-मन्त्रालय में एक उपसचिव (विनियम) सभी बुनियादी विनियमों में संशोधन करने के लिए नियुक्त किया गया (बाद में उसे दूसरे काम भी सौंपे गये)। बहुत बड़ी सस्या में विनियमों में संशोधन करना जरूरी था और इस जटिल काम में काफी समय लगना था। उपसचिव (विनियम) का विनियमों के संशोधित रूप को अंतिम रूप से तैयार करने में मदद देने के लिए सेना, नौसेना और वायुसेना मुख्यालयों में एक-एक अलग विनियम-कोष्ठ खोला गया। सैन्य विनियम और फार्म-निदेशालय, तैयार हो जाने पर, संशोधित विनियमों के मुद्रण और वितरण के लिए जिम्मेवार है। इस समय तक बुनियादी विनियमों का संशोधन पूरा हो चुका है।

अप्रैल, १९४७ तक सैन्य विनियम और फार्म-निदेशक के पद पर सेना-प्रधिकारी रहते थे और उसके बाद रक्षा-विभाग का एक असेनिक अधिकारी। यह कार्यालय १९६६ में शिमला भेज दिया गया था, पर १९५१ में उसे फिर दिल्ली लाया गया। दिसम्बर, १९५२ में इस कार्यालय को मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (रक्षा-मन्त्रालय में पदेन उपसचिव) के प्रशासनिक नियन्त्रण में रखा गया। नवम्बर, १९५६ में यह निश्चित किया गया कि इन कार्यालय को वास्तव सचिवालय में ले आया जाय।

### खण्ड ४—सैनिक, नाविक और वायुसैनिक बोर्ड

इस संगठन का प्रथम कृत्य भूतपूर्व सैनिकों और सशस्त्र सेनाओं के मेजाकालीन और मृत सदस्यों के परिवारों के कल्याण-कार्य की देखभाल करना है।

फरवरी, १९१६ में प्रथम विश्वयुद्ध के बाद सरकार ने केन्द्रीय-भारती-बोर्ड को जगह भारतीय मेनिफ-बोर्ड को स्थापना, सेवामीन, सेवा-मुक्त और मृत भारतीय सैनिकों और मृत सहायक जनों के हितों सम्बन्धी सभी मामलों में सलाह देने के लिए और सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को यथामुम्भव सभी सहायता प्रदान करने के लिए, की। यह बोर्ड सेना-विभाग के साथ संबद्ध कर दिया गया। केन्द्रीय सरकार के सुमाव पर प्रांतीय सरकारों और प्रशासनों ने भी सैनिकों के बोर्ड बना दिये, क्योंकि यह बहुत कुछ उन पर ही निर्भर था कि सैन्यविशेषित सैनिकों और भूत सैनिकों के परिवारों के कल्याण-कार्य के लिए कार्रवाई करें। दिसम्बर, १९२२ में इंग्लोरियल इंडियन रिस्लीफकड से प्राप्त १० लाख रुपये की रकम से एक



(वेटरन) सप का सदस्य बन गया, जो ३१ देशों के १३५ भूतपूर्व सैनिक-सघों से बना एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है और जिसका उद्देश्य सभी देशों के युद्ध-अभ्यस्तों और युद्ध के शिकार हुए लोगों के हितों का संवर्धन करना है ।

भूतपूर्व सैनिकों और सशस्त्रसेनाओं के सेवालीन जनो के लिए कुछ कल्याण निधियाँ हैं । सशस्त्र-सेना-हितकारी-निधि का प्रथम उद्देश्य भारतीय सशस्त्र सेनाओं के वर्तमान और भूतपूर्व सदस्यों और उनके आश्रितों को आर्थिक तंगी को दूर करना है । सशस्त्र-सेना-पुनर्गठन-निधि का उपयोग सशस्त्र सेनाओं के सेवाकालीन सदस्यों को सुविधायें प्रदान करने के लिए किया जाता है । नियोग्यता की सामूहिक देखभाल और भूतपूर्व सैनिकों को पुनर्वास-योजनाओं के लिए भी इस निधि में से अनुदान किये जाते हैं । हर मास ऋतु बेचकर और दान इकट्ठा करके ध्वज-दिवस (६ दिसम्बर) निधि इकट्ठी की जाती है, जो भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की तकलीफें कम करने के लिए और सेवाकालीन व्यक्तियों के वास्ते सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए इकट्ठी की जाती है । सेंट-डन्स्टन (भारत)-निधि का उपयोग अन्धे हो गये सैन्यजनो के व्यावसायिक प्रशिक्षण और आगे चलकर उनके पुनर्व्यवस्थापन और पुनर्वास के लिए किया जाता है । इन सारी निधियों को कुछ समितियाँ प्रशासित करती हैं, जिनके अध्यक्ष रक्षा-मन्त्री हैं ।

भारतीय भूतपूर्व गोरखा-सैनिक-कल्याण-केन्द्र को एक समिति प्रशासित करती है, जिसके अध्यक्ष रक्षा-सचिव हैं ।

भारतीय सैनिक, नौमैनिक और वायुमैनिक-बोर्ड के सचिव इन सभी निधियों के सचिव का काम करते हैं ।

## खण्ड ५—पुनर्व्यवस्थापन-महानिदेशालय

पिछले त्रिंश्वयुद्ध के दौरान भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्व्यवस्थापन और कल्याण की समस्या बड़े महत्त्व की समस्या बन गयी और इसके लिए एक बड़ा संगठन बनाना पड़ा । उस समय भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए भ्रम-मन्त्रालय का पुनर्व्यवस्थापन और नियोजन-महानिदेशालय और उनके कल्याण के लिए सेना-मुख्यालय की सामान्य-कल्याण-शाखा जिम्मेवार थी । स्वाधीनता के बाद रक्षा-मन्त्रालय में विभाजन के फलस्वरूप पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से उलट्ट कर आये रक्षा-सेनाजनो और भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए रक्षा-मन्त्रालय में एक संगठन बनाया गया । यह संगठन पुनर्वास-मन्त्रालय के निश्चित सम्पर्क में काम करता रहा ।

१९५१ में पुनर्वास-मन्त्रालय समाप्त कर दिया गया और रक्षा-जनो सम्बन्धी दोष काम रक्षा-मन्त्रालय में उस समय बनाये गये पुनर्व्यवस्थापन-अनुभाग को सौंप दिया गया । पुनर्व्यवस्थापन-अनुभाग, केन्द्रीय मन्त्रालयो, राज्य सरकारों और अन्य सरकारी और गैरसरकारी संगठनों के सहयोग से, भावजनिक और निजी उद्योग-क्षेत्र उद्योगों, भू-वस्त्रियों, व्यावसायिक तकनीकी कार्यों में, परिवहन सेवाओं, लघुउद्योगों आदि में भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास की योजनाएँ बनाने के लिए भी जिम्मेवार था ।

पुनर्व्यवस्थापन-अनुभाग ने पत्राच में महाबलीपुर, करनाल और बानूर में, उत्तर प्रदेश में मनुगर और अफजलपुर में, आन्ध्रप्रदेश में अम्मगुडा और पटहनगर में, मद्रास में जम्बूवानीदे में, मेसूर में रत्नपुर में, केरल में रानी और वेत्तिलारा में और मध्य प्रदेश में बयोनाभीर और बमबाद-बहागांव में १३ भू-वस्तियों का काम शुरू किया और उनको स्थापित किया। इन वस्तियों में कुल मिलाकर ३००० भूतपूर्व सैनिक बसाये गये।

इन भू-वस्तियों के अलावा भूतपूर्व सैनिकों की अनेक सहाकारी (भू) संस्थाएँ भी राज्य-मुद्रोत्तर-पुनर्निर्माण-निधि से वित्तीय सहायता लेकर स्थापित की गयीं।

एक पुनर्व्यवस्थापन-अनुभाग भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्व्यवस्थापन और कल्याण की समस्याओं से निराकरण के लिए अग्रगण्य सिद्ध हुआ। फलतः १९५६ में इस अनुभाग को एक महा-निदेशक के अधीन एक निदेशालय में बदल दिया गया।

सेवानीन और भूतपूर्व सैनिकों की भवान की सुविधा देने की भारी ज़रूरत की दृष्टि से एक सैनिक सहाकारी गृहनिर्माण समा बना दी गयी, जिसका विश्व कार्यालय दिल्ली में था और जिसका लक्ष्य पूरे देश में ६० जगह डिफेंस कोलोनियाँ बनाना था। यह समा अब दिल्ली और पश्चिम के क्षेत्र जैसे गाजियाबाद आदि में डिफेंस कोलोनियों के निर्माण का काम देखती है। देश की दूसरी जगहों में ऐसी वस्तियाँ बनाने का काम स्थानीय स्टेशन बमार्डर समन्वित करते हैं।

केन्द्रीय सरकार के रिक्त स्थानों के लिये अपने माम भेजने के मानने में रोजगार-दस्तरो द्वारा भूतपूर्व सैनिकों की लुब्ध-सुखता प्रदान की जाती है। सशस्त्र सेनाओं में अपने प्रशिक्षण और अनुभव के आधार पर भूतपूर्व सैनिकों को पुतिष्ठ, हॉमगार्ड, रेलवे के रक्षा और प्रतिपालन, परिवहन सेवाओं, मजदूर कामस्टेजियों आदि में बरीयता मिलती है। केन्द्रीय सरकार की सेवामें में भरती के लिए भूतपूर्व सैनिकों को विहित ऊपरी आयु-सीमा में सशस्त्र सेनाओं वाली उनकी सेवा और अतिरिक्त तीन छान की ढील दी जाती है। केन्द्रीय सरकार के कुछ पदों में न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भी उनके लिए कम कर दी गयी है।

औद्योगिक उपक्रमों में सामग्रद रोजगार प्राप्त करने या अपने-आप अपना स्वतन्त्र कार-बार स्थापित करने में भूतपूर्व सैनिकों को मदद देने के लिए देश के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण-संस्थानों में पाँच जगहें भूतपूर्व सैनिकों को इजीनियरो और गैर-इंजीनियरो कामों में प्रशिक्षण देने के लिए आरक्षित कर दी गयी है। इस संस्थानों में प्रशिक्षण पाने जाने हर भूतपूर्व सैनिक को केन्द्रीय सरकार ३५ रुपये सहाने की सिलावृत्ति देती है।

१९५६ में एक रक्षा-सेवा-सम्पर्क-संगठन सशस्त्र सेनाओं के सेवानिवृत्त या सेवामुक्त अधिकारियों को केन्द्रीय और राज्य-सरकारों तथा सरकारी और निजी क्षेत्र के उपक्रमों में अपेक्षित रोजगार देने के लिए बना दिया गया है। १९६५ में पुनर्व्यवस्थापन-महानिदेशक का नया पदनाम रक्षा-सेवा-सम्पर्क-अधिकारी, आयोजना-आयोग, कर दिया गया। रक्षा-सेवा-सम्पर्क-संगठन अनेक भूतपूर्व अधिकारियों को सरकारी और निजी उपक्रमों में जगह दिलाने में धन्य रहा है। सेना-अधिकारियों के लिए कारवार-प्रक्रम-याठक्रम भी बनाने गये हैं, ताकि

वे सेवानिवृत्त होने के बाद सरकारी और निजी उपक्रमों के प्रबन्धक पदों के लिए उन्मुख हो सकें।

नियोष्य-जनों के अर्थनिक जीवन में पुनर्वास के लिए एक विशेष पुनर्व्यवस्थापन-कक्ष खोला गया। पुनर्वास की व्यवस्था या तो नियोष्य व्यक्ति की शेष क्षमता के अनुकूल सीधे रोजगार देकर या पर्यावश्यक उनको सामग्रिक रोजगार के लिए उपयुक्त बनाने वाला प्रशिक्षण देकर की जाती है। इस प्रशिक्षण का खर्च केन्द्रीय या राज्य-सरकार देती है।

भूतपूर्व सैनिकों और सेवानिवृत्त सैनिकों के परिवारों के पुनर्वास और कल्याण की ओर ज्यादा अच्छी तरह ध्यान देने के लिए, चारों में से प्रत्येक सेना-कमान-मुख्यालय में, एक कमान-सम्पर्क-प्रधिकारी नियुक्त किया गया है।

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास राष्ट्रीय महत्व प्राप्त कर चुका है। इसे क्रमबद्ध आधार पर निपटाने के लिए सरकार ने आरम्भ में राष्ट्रीय रक्षानिधि से ५ करोड़ रुपये का अंशदान देकर और १९६५-६६ से शुरू करके तीन लाख तक रखा बजट में से एक करोड़ रुपये का वार्षिक अंशदान देकर, एक विशेष सेनानिधि स्थापित की है। कुल राशि में से ८० प्रतिशत, रंगछटों की संख्या के आधार पर, राज्यों और संघ-राज्य-क्षेत्रों के बीच बाँट दिया जाता है। रक्षा-बजट में से अंशदान, राज्य सरकारों और संघीय-राज्य-क्षेत्र द्वारा उतना ही अंशदान देने की शर्त पर, दिया जाता है। निधि का उपयोग भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण और पुनर्व्यवस्थापन के लिए किया जायेगा।

### खण्ड ६—सौक-सम्पर्क-निदेशालय

सत्ता-हस्तान्तरण से पहले सशस्त्र सेना-मुख्यालय में एक सौक-सम्पर्क-निदेशालय भीधे कमांडर-इन-चीफ के अधीन था। इसका काम दुहरा था, अपरिचित सेनाओं के सदस्यों तक पत्रिका द्वारा, विशेषतः सशस्त्र सेना के सदस्यों में परिचालन के लिए निजालकर, प्रचार पहुँचाना और दूसरे सेनाओं के बारे में जनमाधारण तक समाचार-पत्रों के जरिये प्रचार पहुँचाना—ये समाचार-पत्र सेनाओं के बारे में सचित्र समाचार सहित भेजे जाते थे—और सचित्र पुस्तकें-मुस्तिफायेँ निजालना, जिनमें भारत के सैनिकों द्वारा प्राप्त की गयी सफलताओं के व्योरे दिये जाते थे।

सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों के बीच परिचालन के लिए खासतौर पर तैयार की गयी पत्रिका का, जिसमें सैन्य अभिरुचि के समाचार और विचार रखा करते थे, नाम सप्ताहिक 'धौनी प्रश्रवार' था। यह पहले-सह २ जनवरी १९०६ को उर्दू में निकला। यह इलाहाबाद में प्रकाशित होता था, हालाँकि सम्पादन-कार्यालय सिमला में था। उर्दू के अलावा फौजी बख्शवार के समय-समय पर पाँच और संस्करण निकाले गये हिन्दी (५ जून, १९०६ से), गुजराती (२ अक्टूबर, १९०६), अंग्रेजी (३ फरवरी, १९२३), रोमन उर्दू (अप्रैल, १९२६) और तमिल (२७ मार्च, १९४५ से)। दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान पत्रिका में पृष्ठसंख्या बढ़ गयी और उसमें अनेक चित्र भी दिये जाने लगे और कुछ लोकप्रिय फीचर भी बढाये गये, जैसे सशस्त्र सेना-सदस्यों की उल्लेख रियायतों और जीर्ण पुस्तकारों आदि के बारे में जानकारी। पत्रिका का कार्यालय भी दिल्ली से आया गया।

द्वितीय विश्वयुद्ध शुरू होने के तुरन्त बाद एक दो पृष्ठ का अर्द्धसाप्ताहिक पूरक निकाला गया, जिसमें युद्ध समाचार दिये जाते थे और यह फौजी बख्शार के पाठकों को निशुल्क उपलब्ध कर दिया गया। अक्टूबर, १९४० में इस पूरक को अगह 'जंग की खबरें' नामक चार-पृष्ठ का अलग पत्र निकाला गया, जो अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, रोमन उर्दू, गुरुमुखी, तमिल, वेल्लु, मराठी, और बाद में गोरखाली में भी निकाला गया। सितम्बर १९४५ में इस पत्र का नाम 'जवान' कर दिया गया।

### सशस्त्र-सेना-सूचना-कार्यालय मन्त्रालय के अधीन

१५ अगस्त, १९४७ के बाद तीनों सेनाओं के प्रमुखों की पृथक नियुक्तियाँ होने पर लोक-सम्पर्क-कार्यालय को उपयुक्त रूप में रक्षा-मन्त्रालय के अधीन कर दिया गया। सितम्बर, १९४७ में यह निर्णय किया गया कि सूचना और प्रसारण मन्त्रालय को, जो सभी सरकारी प्रचार के लिए जिम्मेवार था (और बना हुआ है), रक्षा-सेनाओं सम्बन्धी प्रचार के लिए भी जिम्मेवार बना दिया जाय। तदनुसार सूचना-प्रसारण-मन्त्रालय-द्वारा, संयुक्त-प्रमुख-सूचना-अधिकारी की हैसियत से, सशस्त्र सेना सूचना-अधिकारी के एक पद का मूजन किया गया। यह अधिकारी इस तरह के प्रशासनिक नियन्त्रक के अधीन नियुक्त तो किया गया, पर वह दैनंदिन कार्यकलाप के लिए रक्षा-मन्त्रालय के अधीन था और सशस्त्र सेना-मुख्यालय के निकट सम्पर्क से काम करता था। तीनों सेनाओं में से प्रत्येक के लिए अलग-अलग लोक-सम्पर्क-अधिकारी हैं, जो सेना-मुख्यालय से नियम सम्पर्क रखते हैं। ये अधिकारी सशस्त्र-सेना-सूचना कार्यालय के संगठन के अंग हैं। पहले सशस्त्र-सेना-सूचना-अधिकारी ने अपना कार्यभार १५ नवम्बर, १९४७ को संभाला। जून, १९६५ में सशस्त्र-सेना-सूचना-कार्यालय का नाम लोक-सम्पर्क-निदेशालय कर दिया गया।

इस संगठन को प्रेस के प्रसंग में प्रेस-सूचना-कार्यालय (रक्षा-स्कन्ध) कहा जाता है, हालाँकि सशस्त्र-सेना-सूचना-अधिकारी (अब लोक-सम्पर्क-निदेशक) और एक सूचना-अधिकारी को छोड़कर, सभी अधिकारी रक्षा-मन्त्रालय द्वारा नियुक्त और नियन्त्रित किये जाते हैं। इस तरह इस संगठन का ढाँचा भारत सरकार के अन्य मन्त्रालयों वाले ढाँचों से कुछ भिन्न है।

### कमानों में और जम्मू और कश्मीर में लोक-सम्पर्क-अधिकारी

तीनों सेना-मुख्यालयों के तीनों लोक-सम्पर्क-अधिकारी पहले थप सेना में मेजर, नीलेना में लेफ्टी० कमांडर और वायुसेना में स्क्वैड्रन लीडर के ओहदे वाले थे। इनके अलावा १ दिसम्बर, १९४७ को तीनों में से प्रत्येक सेना-कमान में भी एक-एक लोक-सम्पर्क-अधिकारी नियुक्त किया गया था। पर दिसम्बर, १९५६ में प्रचार-कार्य दिल्ली में केन्द्रित कर दिया गया और कमानों में लोक-सम्पर्क-अधिकारी न रहे। बाद में अनुभव ने पता चला कि बम्बई और कलकत्ता में प्रादेशिक कार्यालय होना ज्यादा वाछनीय होगा। ये १ मार्च, १९५१ से मंजूर किये गये। एक तीसरा प्रादेशिक कार्यालय भी १ अक्टूबर, १९५५ से बालघर में स्थापित किया गया। इसे बाद में अम्बाला से जाया गया और अब यह पंजीगढ़ में है। सेना की केन्द्रीय कमान



की स्थापना के बाद, सखनऊ में इस कमान की एक लोक-सम्पर्क-यूनिट बना दी गयी। ये चारो लोक-सम्पर्क-अधिकारी मेरा की चारों कमानों और अन्य दोनो सेनाओं की उत्सवादी विरचनाओं का काम देखते हैं। वे प्रचार के सभी मामलों में लोकसम्पर्क-निदेशक के अधीन काम करते हैं।

१९४७ में कस्नोर-मरिया के गुरु होने पर उस क्षेत्र में सशस्त्र सेनाओं के कार्यकलाप का प्रचार-कार्य करने के लिए श्रीनगर और जम्मू में विशेष लोक-सम्पर्क-कर्मचारी नियुक्त किये गये। इस समय श्रीनगर में एक लोक-सम्पर्क-अधिकारी है और जम्मू में एक सहायक-लोक-सम्पर्क-अधिकारी। दिसम्बर, १९६० में पूर्वी खण्ड और नागालैण्ड सम्बन्धी प्रचार-कार्य संभालने के लिए एक लोक-सम्पर्क-अधिकारी वहाँ पर भी रख दिया गया।

देश के विभाजन से पैदा हुई कठिनाइयों के कारण, और सभी मुसलमान कर्मचारियों और मुद्रकों के प्रद्वजन के कारण, फौजी अखबार और जवान का प्रकाशन अस्थायी तौर पर बन्द कर देना पड़ा। ये पत्र सशस्त्र-सेना-सूचना-अधिकारी के कार्यालय से सितम्बर, १९४८ में फिर निकाले गये।

### जवान का बन्द किया जाना और फौजी अखबार में सुधार

बदली परिस्थितियों में सैनिकों के लिए समाचार-पत्र के रूप में 'जवान' का उपयोग न रहा। सामान्य सान्त्विकालीन स्थिति फिर आ जाने से अन्य नागरिकों की तरह सैनिक भी दैनिक समाचार-पत्र प्राप्त करने लगे। वैसे भी 'जवान' के समाचार सैनिकों तक पहुँचने-पहुँचते पुराने पत्र जाते थे। इसलिए २२ मार्च, १९५० से जवान का प्रकाशन बन्द कर दिया गया। साथ ही फौजी अखबार को पुच्छ संख्या बढ़ाकर अंग्रेजी संस्करण की २८ से ३६ और अन्य संस्करणों की २८ से ३२ कर देने का भी निर्णय किया गया। उस समय यह नौ भाषाओं में प्रकाशित होता था जवां प्रग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, रोमन हिन्दुस्तानी, पंजाबी, मराठी, गोरखाली, तमिल और तेलगू। ४ अप्रैल, १९५४ को 'फौजी अखबार' नाम भी बदल कर 'सैनिक समाचार' कर दिया गया। १९६३ में रोमन हिन्दुस्तानी संस्करण भी बन्द कर दिया गया और जनवरी, १९६४ में मतशायम संस्करण और निकाला गया।

यह पत्रिका एक समुल्लेख प्रकाशन है। अब इसमें बहुत सारे चित्र रहते हैं और हाल के वर्षों में इसकी विषय-वस्तु और साजसज्जा दोनों में ही गुणात्मक दृष्टि से बहुत सुधार हुए हैं।

'सैनिक समाचार' बड़े उपयोग का है, क्योंकि यह सेनाओं के कार्यकलाप के बारे में जानकारी देता है, जो सामान्य समाचार-पत्रों में नहीं मिल सकती। यह खेलकूद और सैनिकों के अन्य कार्यकलाप को महत्व देता है, जिनके ज्यादा ब्योरे किसी भी सामान्य समाचार-पत्रों में नहीं मिलते। एक बड़ा महत्त्वपूर्ण फीचर सशस्त्र सेना के सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर जाता है। गोरखाली संस्करण खासकर गोरखा सैनिकों के बड़े उपयोग का है, क्योंकि गोरखाली में अन्य कोई समाचार-पत्र उपलब्ध नहीं है।

लोक-सम्पर्क-निदेशालय आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से मिल्य एक विशेष सैनिक कार्यक्रम भी चलाता है। जनता के लाभ के लिए अनेक जानकारी-पूर्ण पुस्तिकाएँ भी तीनों सेनाओं के बारे में निकाली गयी हैं।

१९६२ में भारत-चीन-सन्धिया के दौरान दो नयी लोक-सम्पर्क-यूनिटें, लेपटी० कर्नल के ओहदा वाले एक-एक मुख्य-नोड-सम्पर्क-अधिकारी की अध्यक्षता में, 'उपूमी' और लद्दाख के लिए कम्मा सेजपुर और थोनागर में आरम्भ की गयी। तब से उन सेनिकों के लिए प्रचारकार्य की दृष्टि हुई जल्द ही पूरी करने के लिए, जो सीमान्त क्षेत्र में है, और उन क्षेत्रों में प्रेस के दलों को ले जाने के लिए भी, छ छोटो-छोटी स्थानीय लोक सम्पर्क यूनिटें भी बनायी गयी हैं।

निदेशालय का प्रचार-कार्य उस समय भारत की सीमा से बाहर तक फैल जाता है, जब भारतीय सैनिक विदेश भेजे जाते हैं। इस तरह कोरिया, भाजा और कांगो में भारतीय सैनिकों के साथ लोक-सम्पर्क-कार्य की व्यवस्था की गयी थी।

जून, १९६५ में सशस्त्र सेना कर्णालिय का दरवा औपचारिक रूप से एक निदेशालय तक बढ़ा दिया गया और उसको एक निदेशक के अधीन रख दिया गया। निदेशक केन्द्रीय सूचना सेवा का बरिष्ठ अधिकारी होता है, पर अगर वह सैनिक अधिकारी बनना पसन्द करे, तो उसको त्रिगैडियर का ओहदा दिया जाता है। १९६३ में संयुक्त सूचना-अधिकारी, सशस्त्रसेना का, एक पद और उप सूचना अधिकारी, सशस्त्रसेना, के दो पद (अर्ध उप-निदेशक, लोक-सम्पर्क) बनाये गये, जिनमें से एक पर सेना के कर्नल ओहदे का एक अधिकारी रहता है और दूसरे पर थुप कैप्टन ओहदे वाला एक वायुसेना का अधिकारी। इसके अलावा मुख्यालय में सहायक निदेशक, लोक सम्पर्क, के दो पद बनाये गये, जिनका ओहदा लेपटी० कर्नल का है।

### खण्ड ६ मुख्य प्रशासन-अधिकारी का कार्यालय

सामान्य मुख्यालय (जिसे अब सेना-मुख्यालय कहते हैं), नौसेना मुख्यालय और वायु-सेना-मुख्यालय का पिछले विश्वयुद्ध में बहुत काफी विस्तार हुआ। आवास, अमेरिकी व्यक्ति आदि के मामले में उनकी बढ़ती हुई मांग को देखते हुए, १९४२ में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय बनाया गया।

अब मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निम्नांकित के लिए उत्तरदायी है (क) सशस्त्र सेना-मुख्यालयों और अन्त-सेना-संगठनों के रासपत्रित और अरासपत्रित अमेरिकी व्यक्तियों सम्बन्धी सभी मामलों और (ख) रक्षा-मुख्यालयों के लिए कार्यालय-आवास और सशस्त्र सेना मुख्यालयों और अन्त-सेना संगठनों में नियोजित सेवा अधिकारियों के लिए निवासार्थ आवास-व्यवस्था।

### खण्ड ७ इतिहास-अनुभाग

दूसरे विश्वयुद्ध की समाप्ति के तुरन्त बाद, युद्ध का विवृत इतिहास संकलित करने के लिए, शासक-रत्न सचिवालयों के सन्दर्भ में जिनमें भारत की अस्थिरित सेनाओं ने प्रमुख भाग लिया, एक इतिहास अनुभाग खोला गया। विभाजन के बाद यह सपटन भारत और पाकिस्तान का एक संयुक्त संगठन बना रहा और उसका नाम संयुक्त-अन्त-सेना इतिहास-अनुभाग (भारत और पाकिस्तान) रखा गया।

इस योजना में २४ जिन्दों की भांति के लिए व्यवस्था थी, जिनमें से सात युद्ध के चिकित्सकों के पक्ष पर लिखी जानी थी। १९४७ से १९६३ के वर्षों के दौरान २३ जिन्दें

प्रकाशित की गयी और इस माला की अन्तिम जिल्द १९६२ में प्रकाशित की गयी। संयुक्त इतिहास-अनुभाग १९६३ में बन्द कर दिया गया।

इतिहास-अनुभाग ( भारत ) नामक एक अन्य अनुभाग १९५३ में भारतीय सशस्त्र सेनाओं की विभाजन-उत्तर सैन्य-सक्रियताओं का इतिहास संकलित करने के लिए खोला गया। यह अनुभाग सैन्य-इतिहास और सम्बद्ध विषयों के बारे में भी मन्त्रालय और तीनों सेनाओं को जानकारी प्रदान करता है और सेनाओं के ध्वजों, सिखरों, चिह्नों आदि के लिए आकल्प और आदर्शवाक्य के चयन में भी उनको सलाह देता है।

हैदराबाद-युनिवर्सिटी-कारंवाई (१९४८) और गोवा-युक्ति (१९६१) के इतिहास का भी काम शुरू कर दिया गया है। एक पुस्तक के, भारतीय सेनाओं द्वारा कोरिया, इंडोचीन, लेबनान, गाजा और कांगो में निष्पादित अन्तर्राष्ट्रीय कार्य के बारे में भी लिखे जाने का विचार है।

### खण्ड ८ संयुक्त बीजलेख-कार्यालय

यह अन्य महत्वपूर्ण संगठन है, जिसे स्वाधीनता के बाद नई दिशा दी गयी।

"रक्षा सेनाओं की विरचनाओं के बीच सभी गुप्त प्रकार के संकेत- (सिग्नल) संचार और भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों और विदेश के बीच सभी संचार कूटों में ही भेजने होते हैं, जिनको 'बीजलेख' कहते हैं। सरकार के लिए विश्वसनीय बीजलेख-पद्धति पर महत्व देना जरूरी होता है, युद्ध काल में तो यह अनिवार्य रूप से आवश्यक है। विभाजन के बाद तुरन्त भारत सरकार का एक अविलम्बनीय कार्य एक विशुद्धतः भारतीय-संगठन बीजलेख बनाने के लिए खड़ा करना था।

युद्ध से पहले भारत सरकार के प्रायः सभी बीजलेख जाने प्रलेख, सैनिक और असैनिक दोनों ही विभागों के, ब्रिटेन सरकार द्वारा ही दिये गये थे। युद्ध कार्यालय द्वारा प्रदान किये गये दस्तावेज सामान्य मुख्यालय, भारत के जरिये बाँटे जाते थे और भारत कार्यालय समेत ब्रिटेन के असैनिक विभागों द्वारा दिये गये दस्तावेज भारत सरकार के विदेश और राजनीतिक विभागों के जरिये बाँटे जाते थे। इन दस्तावेजों के बाँटने और इनका हिसाब रखने के अलावा भारत में बीजलेखों के निर्माण और मुद्रण का प्रायः कोई भी काम नहीं किया जाता था। सेना मुख्यालय के सैन्य-आसूचना-निदेशालय के एक अनुभाग में ब्रिटेन से इकट्ठे ही दस्तावेज प्राप्त हो जाते थे और वे इस अनुभाग द्वारा भारत की सशस्त्रसेनाओं में बाँट दिये जाते थे।

पिछता विषययुद्ध छिड़ जाने और इसके पूर्वी एशिया में फैल जाने के बाद यह निर्णय रिया गया कि युद्ध के पूर्वी रण-क्षेत्र के लिए बीजलेख समायोजी भारत होकर केन्द्रित रूप में बाँटी जाय, सीधे-सीधे ब्रिटेन से नहीं। जब धीरे-धीरे पोतवहन की क्षमता क्रमशः कम होने लगी, तो १९४२ के उत्तरार्ध में यह जरूरी हो गया कि दस्तावेजों की ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारत में मुद्रित किया जाय, लेकिन बुनियादी सामग्री अब भी ब्रिटेन से ही जाती रही।

रॉयल इंडियन नौसेना और रॉयल नौसेना के जो अंग पूर्वी रणक्षेत्र में सक्रिय रहते थे, उनके

लिए सभी जरूरी बीजलेख दस्तावेज एडमिरल्टी द्वारा और भारत स्थित वायुसेना के लिए ये दस्तावेज वायु-मन्त्रालय द्वारा प्रदान किये जाते थे।

युद्ध के वास्तविक अनुभव से यह स्पष्ट हो गया कि भारत के लिए यह बात बुद्धिमानी पूर्ण न होगी कि असली बीजलेख सम्बन्धी जरूरतों के लिए बाह्य के स्रोतों पर निर्भर रहे। युद्ध के अन्त की ओर भारत की रक्षा-सेनाओं ने विचारित की कि भारत के लिए जरूरी सभी बीजलेख-दस्तावेजों के निर्माण, वितरण और हिप्साव रखने के लिए एक संगठन बनाया जाय। इसके फलस्वरूप नवम्बर, १९४५ में संयुक्त बीजलेख-कार्यालय की रचना की गयी, जिसका केन्द्राधार सैन्य-आमूचना निदेशालय का विद्यमान सैन्य-उत्पादन केन्द्र की ही बनाया गया। कार्यालय की ब्रिटेन के बीजलेख-नीति-बोर्ड के साथ सम्पर्क रखने का काम सौंपा गया।

नया संगठन पूरी तरह के काम मुरु कर पाया, इसी बीच दूरगामी राजनीतिक परिवर्तन सामने आ गये। हमारे फलस्वरूप इस अन्त-सेना-संगठन का विस्तार एक अन्त-सेना और अन्तर्विभागीय संगठन के रूप में करना पड़ा, ताकि यह अर्सेनिक विभागों की जरूरतों की भी पूरा कर सके। इस नये उपक्रम की अमूर्तनिष्ठ कठिनाइयों का बोझ इसी से हो सकता है कि उस समय तक एक भी भारतीय को इस संगठन में सम्बद्ध न किया था। नये राजनीतिक विकासों के बाद यह निर्णय किया गया कि इसमें भारतीयों को भरती किया जाय और पहली बार तीन सेना-अधिकारियों को इस संगठन में अग्रेल-मई १९४७ में नियुक्त किया गया और १७ आदमियों को जुलाई-दिसम्बर, १९४७ में।

देश के विभाजन के बाद संयुक्त बीजलेख-कार्यालय के व्यक्तियों का भी विभाजन कर दिया गया। भारत में केवल एक ही यूरोपीय सैन्य-अधिकारी रह गया, जिसने मार्च, १९६८ तक भारसाधक अधिकारी के रूप में बना रहना मंजूर कर लिया था। एक सैन्य के ठेक पर एक अर्सेनिक यूरोपीय अधिकारी रह गया और तीन भारतीय अधिकारी, जो, कुछ महीने पहले ही आये थे। एक भारतीय अधिकारी उसके कुछ समय बाद ही सेवानिवृत्त होकर चला गया।

१५ अगस्त, १९४७ को संयुक्त बीजलेख-कार्यालय (भारत) और म० बी० का० (पाकिस्तान) दोनों सुप्रीम कमांडर के मुख्यालय के अधीन आ गये और इस मुख्यालय के समस्त हो जाने तक इसी प्रकार बने रहे। सुप्रीम कमांडर ने भारत और पाकिस्तान के दो कार्यालयों के बीच परिसम्पत्तियों और व्यक्तियों के आवंटन का पर्यवेक्षण किया।

नवजात भारतीय कार्यालय के ऊपर, सह्याय कश्मीर में सक्रिया केन्द्र जाने से, जो भारी जिम्मेवारी आ पड़ी, उसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। दुर्भाग्य से भारत को कुछ समय तक उन्हीं दस्तावेजों का प्रयोग जारी रखना पड़ा, जो पाकिस्तान के और उसके एक जेने ही थे, जबकि पाकिस्तान कुछ आरक्षित दस्तावेज हस्तगत कर सकता था, जो उसके आवष्टित किये गये थे और केवल उसके ही पास थे। निर्निवृत्त प्रयास किया गया पर तब भी पहला परिवर्तन ११ नवम्बर, १९४७ को लाया गया, जब कि कश्मीर-सक्रिया आना सबसे महत्व का परण प्रायः एक पक्षधारे तक पार कर चुकी थी। तब भी सभी अवावश्यक

दस्तावेजों के मामले में ऐसा नहीं हो सका और वे कुछ ज्यादा समय तक पाकिस्तान के साथ एकलप चपटे रहे, ज्यादातर इसलिए कि आरक्षित दस्तावेजों की कमी थी।

फरवरी, १९४८ के आरम्भ में भारसाधक यूरोपीय अधिकारी के स्थान पर एक भारतीय अधिकारी को रखा गया, क्योंकि वह मार्च, १९४८ में जाने को था। इन अधिकारी को बीजलेखों का काफी अनुभव था, लेकिन दूसरों की तरह इसे भी निर्माण का अनुभव न था। इस समय तक संघीय-लोक-सेवा आयोग के जरिये कुछ और स्थानों को भरा जा चुका था और काफी बीजलेख अनुभव वाले कुछ सैनिक अधिकारी आयोग ने असैनिक स्तर में नियुक्ति के लिए चुने थे। इस समय भारत के सामने बीजलेख निर्माण की इतनी भारी समस्या था खड़ी हुई थी, जो उसके जनसाधन, अनुभव और सीमित मुद्रण क्षमता के परे थी। इन बड़े ही कठिन काल द्वारा अपेक्षित काम पूरा करने के लिए तदर्थ व्यवस्था कर दी गयी और पूरे १९४८ और १९४९ के कुछ काल तक बीजलेख दस्तावेजों के निर्माण और पूर्ति के मामले में प्रायः 'रोज खोदना-रोज पीना' जैसी स्थिति बनी रही। लेकिन निःसंकोच सहयोग, मिल-जुलकर काम करने की भावना और समुचित मार्गदर्शन से इस विघास कार्य में सफलता सम्भव हो गयी।

बीजलेख-निर्माण एक बड़ा ही विशेषीकृत कार्य है और इसके लिए भारी तकनीकी प्रवीणता जरूरी होती है। निर्माण की रीतियों की निरन्तर समीक्षा करते रहना पड़ता है, ताकि ज्यादा सुरक्षा रखी जा सके और उनके उपयोग में तेजी और सुविधा भी बनी रहे। बीजलेखों का निर्माण और उपयोग करने वालों के, और उनका भेद खोल पाने के इच्छुक शत्रु लोगों के बीच निरन्तर संपर्क-सा चलता रहता है। इसलिए संरक्षणकर्ताओं को अपने बीजलेखों में सुधार करने के लिए निरन्तर साधनोपकरण सोचने रहने पड़ते हैं और सुगठित बीजलेख भेदी हमलों के आगे अपनी दुर्बलता को जाँच करते रहना पड़ता है। कार्यालय ने यथासम्भव सर्वोत्तम काम किया। कार्य की विपुलता और उसके उत्तरदायित्व ने आरम्भिक वर्षों में प्रायः उसकी कमर ही तोड़ दी थी।

१९४९ में समुक्त बीजलेख-कार्यालय के वर्द्धमान उत्तरदायित्वों और वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए उसका पुनर्गठन किया गया। उसके समुचित कार्यकरण के लिए अत्यावश्यक अनेक नये अनुभाग बनाये गये। मुद्रण-क्षमता बढ़ायी गयी और ज्यादा कर्मचारी भरती किये गये। १९४९ के अन्त तक स्थिति में कुछ सुधार हो गया था। कभी-कभी निगति के बावजूद, जेने-जेने समय बीता गया, स्थिति अधिकाधिक सन्तोषजनक होती गयी। दस्तावेजों के निर्माण और रक्षितियों के मामले में अब यह कार्यालय बहो ज्यादा दृढ़तर स्थिति में है।

जिसी भी देश की सुरक्षा उसके संचार की सुरक्षा पर निर्भर है और इस कारण प्रयुक्त बीजलेखों की सुरक्षा पर निरन्तर कड़ी-ने-कड़ी सतर्कता रखनी पड़ती है। इसलिए अधिकतम प्रयास और कार्यक्षमता इस संगठन का आदर्श है।

अक्टूबर, १९४४ में समुक्त बीजलेख-कार्यालय के भारसाधक अधिकारी का नया पद-नाम निदेशक, समुक्त-बीजलेख-कार्यालय कर दिया गया। इस संगठन के अन्य पदों के नामों में भी परिवर्तन कर दिये गये।

## खण्ड ९. विदेशी-भाषा-विद्यालय

विदेशी-भाषा-विद्यालय स्वाधीनता के बाद स्थापित किया गया ब्रितकुल नया संगठन है, जो प्रथमतः सेनाओं के व्यक्तियों को विदेशी भाषाओं के अध्ययन की सुविधायें प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। सभी देशों में यह सामान्य चलन है कि अपने विदेशस्थ मित्रों में सैन्य-सहचारी रखे जायें। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारी सैन्य, नौसेना और वायुसेना सहचारी के रूप में (राष्ट्रमण्डल के देशों में उनको सैन्य, नौसेना और वायुसेना सलाहकार कहा जाता है) कुछ उन महत्वपूर्ण विदेशस्थ मित्रों में संनान किये जाने हैं, जिन देशों में उनकी उपस्थिति ज्यादा उपयोगी समझी जाती है। इन अधिकारियों के लिए यह बहुत जरूरी है कि अपने कर्तव्यों का समतापूर्वक निर्वाह करने के लिये कुछ विदेशी भाषाओं का पूर्ण ज्ञान रखें। देश में १९४८ से पहले विदेशी भाषाओं के अध्ययन के लिये पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध न थीं। इसलिए रक्षा-मन्त्रालय के अधीन एक विदेशी-भाषा-विद्यालय स्थापित करने का निर्णय किया गया और २० अक्टूबर, १९४८ को एक सुप्रसिद्ध भाषाविद् को इस विद्यालय का निदेशक नियुक्त किया गया। बाद में अन्य कर्मचारी नियुक्त किये गये और विद्यालय ने १ फरवरी, १९४९ से काम करना और फ्रेंच, फारसी, चीनी, अरबी, रूसी और जर्मन भाषाओं का प्रारम्भिक शिक्षण देना शुरू कर दिया और पहले सत्र में २१४ छात्रों ने प्रवेश लिया। फ्रेंच, जर्मन और रूसी में अगस्त, १९५० में, चीनी में अगस्त, १९५२ में और फारसी में अगस्त, १९५३ में उच्च पाठ्यक्रम आरम्भ किये गये। अगस्त, १९५४ से जापानी, बर्मी और तिब्बती में भी उच्च प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी और १९५१ से स्पेनिश में भी। भलय और बहाला दबोनेलिया शुरू करने के लिये भी कदम उठाये जा रहे हैं।

हालांकि इसका आरम्भ प्रमुखतः सगन्ध सेनाओं की जरूरतें पूरी करने के लिये किया गया था, इस विद्यालय में विभिन्न मन्त्रालयों में काम करने वाले राजपत्रित अधिकारियों को और आगे चलकर अराजपत्रित कर्मचारियों को भी प्रवेश दे दिया गया।

विद्यालय के छात्र या तो प्रायोजित होने हैं या अ-प्रायोजित। विद्यालय तीन तरह के पाठ्यक्रम चलाता है, नामतः प्रारम्भिक, उच्च और दुभाषियावाला। पहले दो अराजकालिक पाठ्यक्रम हैं, जिनमें अमैनिक और सैनिक अधिकारी प्रायोजित और अ-प्रायोजित, आ सकते हैं, जबकि दुभाषिया पाठ्यक्रम पूर्णकालिक है और इसमें बड़ी प्रायोजित अधिकारी भाग ले सकते हैं, जो दुभाषिये के रूप में प्रशिक्षण के लिए विशेष रूप में प्रशिक्षित किये जाते हैं। प्रारम्भिक पाठ्यक्रम की अवधि एक साल है। उच्च पाठ्यक्रम १८ महीने का है और दुभाषिया का पाठ्यक्रम भाषा के अनुसार १८ से २७ महीने तक का है।

प्रायोजित छात्रों के लिये मन्त्रालय का सम्बन्धित विभाग प्रति भाषा के हिसाब से ४० रुपये प्रतिमास की दरमान मुक्त देता है। अ-प्रायोजित सम्मोदशरी के मुक्त की दर में उनकी आय के अनुसार अन्तर रहता है।\* बाहर वालों के लिये बिहित मुक्त दर १५ रुपये मासिक

\* ५०० रुपये मासिक से कम पाने वालों में १० रुपये मासिक लिया जाता है, ५०० रुपये से २००० रुपये के बीच में पाने वालों में १५ रुपये मासिक लिया जाता है और

है। पर सरकारी कर्मचारियों के आश्रित सम्बन्धियों के लिये ट्यूशन शुल्क उतना ही है, जितना सरकारी कर्मचारों के द्वारा स्वयं अपने लिये देय है।

विद्यालय में विदेशी भाषाओं को पढ़ने वाले छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए हर साल प्रारम्भिक और उच्च दोनों पाठ्यक्रमों के सुपात्र अराजपत्रित अप्रायोचित छात्रों को दो नि.शुल्क और चार अर्द्ध नि.शुल्क वृत्तियाँ प्रदान की जाती है। विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली सभी भाषाओं की प्रारम्भिक और उच्च परीक्षाओं में विशेष योग्यता के साथ सर्वप्रथम आने वाले छात्रों को नीचे लिखे आधार पर छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं (क) प्रारम्भिक पाठ्यक्रम-अप्रायोचित फीस देने वाले छात्र २०० रुपये, प्रायोचित छात्र और नि.शुल्क वृत्तिवाले १०० रुपये, (ख) उच्च पाठ्यक्रम-अप्रायोचित शुल्क देने वाले छात्र ३०० रुपये, प्रायोचित छात्र और नि.शुल्क वृत्ति पाने वाले १५० रुपये। जिस भाषा के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है, कम से कम ५० प्रतिशत पुरस्कार उस भाषा की पुस्तकों के रूप में दिया जाता है।

१९५० में एक परीक्षक बोर्ड विद्यालय के निदेशक की अध्यक्षता में भारतीय भाषाओं की (सेना के अधिकारियों के लिये) और विदेशी भाषाओं की परीक्षाएँ चयन के लिए बनाया गया। विदेशी भाषाओं की परीक्षाएँ विदेशी भाषा विद्यालय के छात्रों, राष्ट्रीय रक्षा-अकादेमी के सेना-छात्रों, सेना-अधिकारियों और अन्य पदधारियों, भारतीय विदेश-सेवा के सदस्यों और भारतीय सूचना-सेवा के अधिकारियों, राज्यों के आसूचना-संगठनों के कर्मचारियों, भारतीय धान और अनुग्रमुक्त भूविज्ञान, धनबाद के छात्रों और राज्य सरकारों द्वारा प्रायोचित उम्मीदवारों के लिए ली जाती है।

विद्यालय के आरम्भ से लेकर धीरे १९६५ तक विदेशी भाषाओं में विभिन्न परीक्षाओं में उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की सराया निम्न प्रकार है—

भाषा	प्रारम्भिक	उच्च
अरबी	३८	१२
बर्मी	२०	४
चीनी	२१७	५५
कोच	५८२	६६
जर्मन	३४६	४३
जापानी	६६	५
फारसी	७३	२४
रूसी	४६४	१५६
स्पेनिश	५२	१६
तिब्बती	३६	५
	<hr/> १८६७	<hr/> ४२२

२००० रुपये मासिक से ज्यादा पाने वाले में २५ रुपये मासिक लिपा जाता जाता है।

उत्तीर्ण छात्रों को प्रारम्भिक परीक्षा के लिए प्रमाण-पत्र और सञ्च और दुभाषिया परीक्षा के लिए डिप्लोमा प्रदान किये जाते हैं।

अगस्त, १९५४ में विदेशी-भाषा-विद्यालय को स्थायी आधार प्रदान कर दिया गया। विद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या १९४८-४९ में २१४ से बढ़कर १९६५-६६ में ५१७ तक पहुँच गयी थी।

भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों और विभागों के लाभ के लिये फरवरी, १९५४ में विदेशी भाषाओं के दस्तावेजों का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए एक छोटा अनुवादक-बोर्ड बनाया गया था। योग्यताप्राप्त भाषाविदों, सरकारी और गैरसरकारी, को एक नामिका विद्यालय में रखा जाता है और काम इस नामिका के ही अनुवादकों में बाँट दिया जाता है। इन अनुवादकों को किये गये काम का पैसा दिया जाता है।

### खण्ड १० सशस्त्र सेना फिल्म और फोटो-प्रभाग

यह प्रभाग १५ जुलाई १९५४ को रसा-मन्त्रालय के सीधे अधीन एक अन्त-सेना-संगठन के रूप में तीनों सेनाओं का विशेषतः प्रशिक्षण और अभिलेख सम्बन्धी ज़रूरतें पूरी करने के लिए बनाया गया था।

विद्युत् महायुद्ध के दौरान तीनों सेनाओं के लिए प्रशिक्षण अनुदेश और भरती सम्बन्धी फिल्मों और फ़िल्म पट्टियों के निर्माण, प्राप्ति और वितरण के लिए सेना काइनेमेटोग्राफी-निदेशालय की स्थापना की गयी थी। वह मनोरंजक फिल्मों की, विभिन्न भारतीय यूनिटों में जहाँ भी वे स्थित हों, प्रदर्शित करने के लिए भी जिम्मेदार थी। यह निदेशालय ३१ मार्च, १९४७ को बन्द कर दिया गया और सेना-मुख्यालय के सैन्य प्रशिक्षण-निदेशक के अधीन फिल्म और फोटो अनुभाग नामका एक छोटा-सा संगठन-प्रशिक्षण और अभिलेख के प्रयोजन से सेना की फिल्म और फोटो सम्बन्धी ज़रूरतें पूरी करने के लिए बनाया गया। उस समय नीमेना और वायुसेना में इस तरह के अपने-अपने संगठन थे और फिल्मों और फिल्म पट्टियों की प्राप्ति और वितरण सम्बन्धी काम उनके अपने-अपने उपस्कर और प्रशिक्षण निदेशालय देखते थे।

तीनों सेनाओं में प्रशिक्षण के काम के लिए दृश्य साधनों के बढ़ते हुए महत्व के साथ-साथ, सेना मुख्यालयों में दुहरा काम न होने देने के प्रयोजन से, एक केन्द्रीय फिल्म संगठन की ज़रूरत समझी गयी। दूसरे नीमेना और वायुसेना की ज़रूरतें इतनी बड़ी न थी कि उनके लिए उनके अपने अलग-अलग संगठन बचत और कार्यक्षमता की भी दृष्टि से धर्मोचित ठहराये जा सकते। मन्त्रालय की सीधे अधीनता में एक अन्त-सेना-संगठन समुचित संगठन और उत्तम नियन्त्रण के साथ बनाया जा सकता था। निदान्ततः ऐसा संगठन बनाने का निर्णय अगस्त, १९४२ में कर लिया गया, जब इतिहास-अनुभाग के फिल्म और फोटो-अनुभाग के, जिनके पास युद्धकाल की फिल्मों का काफी ढेर हो गया था, अभिव्य-निर्णय की समस्या सामने आयी।



विभिन्न प्रशासनिक व्योरो को अन्तिम रूप देने के बाद जुलाई १९५४ में सशस्त्र फिल्म और फोटो-प्रभाग स्थापित करने के लिए आदेश निकाले गये, जिसमें इनका वितरण कर दिया गया :

(क) सैन्य-प्रशिक्षण-निदेशालय का फिल्म और फोटो अनुभाग (ख) इतिहास-अनुभाग का फिल्म और फोटो अनुभाग और (ग) आर्डनेंस डिपो, बम्बई का एक अंश, जो यूनिटों को फिल्में वितरित करता था और उनका भण्डार रखता था। इन तीनों कार्यालयों के मिलाने से कुछ बचत भी हुई। दिसम्बर, १९५६ में सशस्त्र सेना फिल्म और फोटो-प्रभाग को स्थायी संगठन बना दिया गया।

यह प्रभाग एक फिल्म अधिकारी के अधीन है और तीनों सेनाओं के लिए सभी प्रकार की प्रशिक्षण-फिल्मों, फिल्म-शट्टियों के निर्माण, शक्ति और भण्डार में रखने और वितरण के लिए समुचित जिम्मेवार है। और सेना की यूनिटों के लिए प्रोजेक्शन मशीनों की भी व्यवस्था करता है। इसका सम्बन्ध सूचना, प्रचार या भरती के प्रयोजन वाली फिल्मों से नहीं है, जो सौक सम्पर्क अधिकारी के क्षेत्र में आती हैं, और न वायु-फोटोग्राफी से, जो वायु मुख्यालय की जिम्मेवारी है।

सशस्त्र सेना फिल्म और फोटो-प्रभाग अवर-कमीशन प्राप्त अधिकारियों और गैर कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए, सैन्य-प्रशिक्षण-निदेशालय के जरिये, फोटोग्राफी के पाठ्यक्रम भी चलाता है। चल-सिनेमा-यूनिट जो पहले सौक सम्पर्क अधिकारी के अधीन थी, १ मार्च, १९५६ को फिल्म और फोटो-प्रभाग द्वारा अपने हाथ में ले ली गयी। सिनेमा-यूनिट, दृष्ट-चित्रों और समाचार-चित्रों के प्रदर्शन का प्रबन्ध, दिल्ली की विभिन्न सैन्य-स्थापनाओं और स्थानीय शिक्षा-संस्थाओं में भी करती है।

प्रशिक्षण के काम के लिए फिल्मों का निर्माण सूचना और प्रसारण-मन्त्रालय के फिल्म-डिपार्ट्मेंट द्वारा सशस्त्र सेना फिल्म और फोटो-प्रभाग के तकनीकी पर्यवेक्षण में किया जाता है।

### खण्ड ११—सेना-खेलकूद-नियन्त्रण-बोर्ड

एक अन्त-सेना संगठन के रूप में सेना-खेलकूद-नियन्त्रण-बोर्ड १५ जुलाई, १९५४ को बनाया गया था। बोर्ड तीनों सेनाओं के व्यक्तियों के खेलकूद कार्यक्रमों का संगठन और समन्वय करता है।

प्रत्येक सेना का अपना खेलकूद-नियन्त्रण-बोर्ड है। अन्त-सेना-बोर्ड में एक प्रधान होता होता है, जो एक प्रधान स्टाफ अधिकारी होता है। तीनों सेनाओं में एक एक सदस्य रहता है, एक सचिव रहता है और एक सहायक सचिव। सचिव और सहायक सचिव बोर्ड के पूर्ण कार्यात्मक अधिकारी हैं, जबकि प्रधान और सदस्यों के सेना-मुख्यालयों में अपने-अपने पद अलग होते हैं। प्रधान, सचिव और सहायक सचिव हर चार साल के लिए प्रत्येक सेना में से प्रमाण-मुद्रा चुने जाते हैं।

बोर्ड का मुख्य कर्तव्य मेला की चैम्पियनशिपों का संगठन और संचालन करना, असेनिक टूर्नामेंटों में मेला की टीमों में भाग लेने को विनियमित करना, खासकर राष्ट्रीय खेल कूद चैम्पियनशिप और अन्य अखिल भारतीय खेलकूद टूर्नामेंटों में, विदेशी सेनाओं की टीमों की भारत-यात्रा के लिए यातचीन चलाना और संगठित करना आदि। जब विदेशी असेनिक टीमों भारत आती हैं, तो उनकी सेना-टीमों से प्रतियोगिता भी यह बोर्ड ही संगठित करता है। बोर्ड भारतीय ओलिम्पिक-संघ से और राष्ट्रीय खेलकूद-महासंघ के साथ भी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में मेला के व्यक्तियों और सैन्य-टीमों के भाग लेने सम्बन्धी सभी मामलों के बारे में सम्पर्क रखता है।

## तेरहवाँ अध्याय

# नागरिकता का प्रशिक्षण

## खंड १—प्रादेशिक सेना

आजादी से पहले भी देश में यह आवाज माँग की जा रही थी कि भारतीय नागरिक जनता को सैन्य-प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उपयुक्त सुविधायें प्रदान की जाएँ। अगस्त, १९४७ के बाद यह माँग और उच्च हो गयी। ऐसी बात न थी कि राष्ट्र सैन्य प्रवृत्ति वाला बन गया हो और देश के सैन्यीकरण की बात चाहता हो। वनाम्हियों के विदेशी शासन ने राष्ट्रीय मनोबल के साथ बड़ा अनर्थ किया था और इसके साथ सार्वजनिक कार्यों के प्रति लोगों में अश्वि और वैयक्तिक प्रतिष्ठा का अभाव हो गया था। राष्ट्रीय चेतना के उद्भव के साथ यह अनुभव किया गया कि सैन्य-अनुशासन जैसी ही कुछ चीज लोगों की जड़ता दूर करके उनकी प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित कर सकेगी और एक प्रगतिशील राष्ट्र के योग्य नागरिक बना सकेगी। सैन्य-प्रशिक्षण की माँग को युक्ति यही थी। सरकार ने यह भाग प्रादेशिक सेना और राष्ट्रीय सेना-छात्र-दल गठित करके पूरी की।

## प्रादेशिक बल

१९४७ में पहले भारतीय प्रादेशिक बल अधिनियम १९२० ( १९२० का ४८ वाँ ) के द्वारा एक प्रादेशिक बल गठित किया गया था। यह बल प्रकटतः इस दृष्टि से खड़ा किया गया था कि भारतीय जनों को सैन्य-सेवा के लिए ज्यादा अवसर दिये जा सकें। पहले आठ प्रादेशिक बटालियनों थीं और यह संख्या क्रमशः बढ़ाकर बीस कर दी गयी। पिछले युद्धकाल में ये बटालियनें नियमित सेना का अंग बनाकर और फिर कुछ समय बाद उसमें विलीन कर दी गयीं। उस समय भारतीय प्रादेशिक बल प्रांतीय यूनिटों से, बिस्मिल्ला-खासा, सहरी यूनिटों और त्रिभुवनियातल-प्रशिक्षण कोर यूनिटों से बना था।

पर उस समय गठित प्रादेशिक बल का क्षेत्र बड़ा सीमित था। लोक-कल्याण के समायान के लिए कुछ अधिक करने की जरूरत थी। फिर भी १५ अगस्त, १९४७ के तुरंत बाद प्रशिक्षित अधिकारियों की भारी कमी पड़ गयी। साथ ही पूरे देश के सैन्य-प्रशिक्षण के लिए एक विद्यालय योजना बनाने का अर्थ भारी खर्च करना होता, भले ही यह मान लिया जाता कि इस काम के लिए अपेक्षित सैन्य-सामग्री और व्यक्ति दोनों ही उपलब्ध हो जायेंगे।

## प्रादेशिक सेना का गठन

पठानाईमें के बाबजूद सरकार ने वृहत्तर दृष्टिकोण से प्रादेशिक सेना गठित करने का निर्णय किया। १९४८ के आरम्भ में त्रिगुटिपर के ओहदे के एक अधिकारी को सेना-मुख्यालय की सामान्य स्टाफ-खासा में प्रादेशिक सेना का निदेशक नियुक्त किया गया। उक्त योजना के

व्योरे तैयार किये और प्रादेशिक सेना गठित करने वाला विधेयक संविधान सभा ( विधायिनी ) में २३ अगस्त, १९४८ को पेश किया गया, जो १ सितम्बर, १९४८ को पास हो गया । १० सितम्बर, १९४८ को प्रादेशिक सेना अधिनियम प्रभावी हो गया और भारतीय प्रादेशिक वन अधिनियम, १९२० का निरसन कर दिया गया ।

यथागठित प्रादेशिक सेना एक नागरिक बल है, जो लोगों को, नियमित सेना में भरती हुए बिना, सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है । राष्ट्रीय आपातकाल में प्रादेशिक सेना नियमित सेना की द्वितीय रक्षा-पंक्ति के रूप में काम करती है । इसका काम यथोपेक्षित आन्तरिक रक्षा के कर्तव्यों को संभालना होता है और इस तरह वह इस जिम्मेवारी से नियमित सेना को मुक्त कर देती है । वह विमान-रोधी रक्षा-कार्य के लिए भी उत्तरदायी है और यथोपेक्षित नियमित सेना के लिए यूनितें भी प्रदान करती है । लेकिन प्रादेशिक सेना के क्रिमी सदस्य में भारत में बाहर सैन्य-कार्य संभालने की अपेक्षा नहीं की जाती । केवल केन्द्रीय सरकार के विशेष या सामान्य आदेश से ही ऐसा हो सकता है । ( १९६२ में आपात की दृष्टि से यह दायित्व इस रूप में बढ़ा दिया गया था ) । जब प्रादेशिक सेना की यूनिटों को सेना का अंग बनाया जाता है, तब इन यूनिटों के व्यक्तियों से नियमित सेना की तरह कर्तव्य सौंपे जाते हैं । आवश्यकतानुसार समय-समय पर इसकी यूनिटों का सेना में अथोभवन किया जाता है या अग्रेषण किया जाता है ।

जल्दी व्यवस्था पूरी करने के बाद प्रादेशिक सेना की पहली यूनिटें अगस्त, १९४९ में खड़ी की गयी । जब अक्तूबर, १९४९ में अधिराज राठोड़ी की राजधानियों में उद्घाटन समारोह किये गये, तो हमने लोगों में बड़ा उत्साह पैदा हुआ । भारतीय प्रादेशिक बल की जो चार बटालियनें १० मिनम्बर, १९४८ को भी विद्यमान चली आ रही थी, उनको प्रादेशिक सेना की पैदा बटालियनों के रूप में गठित कर दिया गया । भूतपूर्व प्रादेशिक वन के जिन व्यक्तियों ने प्रादेशिक सेना में सेवा करने की इच्छा व्यक्त की, उनको भी शामिल कर लिया गया ।

प्रादेशिक सेना में नामाङ्कन के लिए एक व्यक्ति को १८ और २५ की आयु-सीमा में होना चाहिये, पर आयुसीमा में भूतपूर्व सैनिकों और तकनीकी योग्यता वाले अतिरिक्तों के मामले में छील दी जा सकती है । इस अधिनियम के अर्जित क्रिया भी प्रादेशिक सेना में प्रवेश से मनाही है, लेकिन आरम्भ में केवल डाक-तार विभाग को महिला कर्मचारियों को डाक तार सिगनल-यूनिटों में भरती दिया जा रहा है । प्रादेशिक सेना में भरती की अवधि ७ साल है और प्रादेशिक सेना रक्षितियों ८ साल । प्रशिक्षण के अनिवार्य होने में प्रादेशिक सेना में भरती होने वाला कोई व्यक्ति अपना सामान्य अवैधिक काम चालू रख सकता है ।

प्रादेशिक सेना में नियमित सेना की तरह सभी सेनाओं और सैन्य-शाखाओं की सहरी और प्रान्तीय यूनिटें होती हैं । इस तरह प्रादेशिक सेना की आठवरी कोर की यूनिटें हैं, जिनमें विमान-रोधी यूनिटें शामिल हैं, इञ्जीनियरी कोर की यूनिटें हैं, जिनमें अतटदीय जल-परिसहन, बन्दरगाह और गोदी और रेलवे यूनिटें भी आती हैं, साथ ही पैदल सेना, सेना-चिकित्सा-कोर और विजरी और पारित्रिक इञ्जीनियरी की कोरों की यूनिटें भी होती हैं ।

प्रान्तीय यूनिटों में भरती देशजों इनको में की जाती है, जबकि सहरी यूनिटें बड़े

शहरो में बनायी जाती है। प्रान्तीय यूनिटों को दो महीनो तक का लगातार प्रशिक्षण, फसल काटने का मौसम न होने पर, दिया जाता है। माघ ही भरती के पहले साल में एक महीने का रंगरूट-प्रशिक्षण अलग से दिया जाता है। शहरी यूनिटें पूरे साल, काम के सामान्य घण्टों के अलावा, तथा रविवार और छुट्टी के दिन को छोड़ प्रशिक्षण पाती रहती है। चार घण्टे के प्रशिक्षण को एक दिन का प्रशिक्षण माना जाता है। भरती के पहले साल शहरी यूनिटों के प्रत्येक सदस्य को १२८ घण्टों का प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है, जिसमें से चार से चौदह दिन तक एक शिविर में बिताये होते हैं। १२० घण्टे या ३० दिनों का न्यूनतम प्रशिक्षण और २४० घण्टे या ६० दिनों का अधिकतम प्रशिक्षण आने के वर्षों के लिए विहित किया गया है, जिसमें शिविर में बिताये जाने वाले चार से चौदह तक दिन भी गिने जाते हैं। हर एक को शिविर में कम से कम चार दिनों को अवधि तक रहना होता है। प्रशिक्षार्थी की इच्छा पर यह अवधि चौदह दिनों तक बढ़ायी जा सकती है, लेकिन ऐसा नौकरी देने वाले मासिक की रिलिफ स्कीम से ही किया जा सकता है।

वर्ग या समुदाय की ओर ध्यान दिये बिना, भारतीय अधिकांश के सभी भारतीय राष्ट्रियों को भरती किया जा सकता है। भरती के प्रयोजन से देश को महाखण्डों में बाँट दिया गया है। प्रत्येक महाखण्ड में कुछ राज्य आते हैं।

इन समय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी केवल भारतीय यूनिटों में ही प्रवेश पा सकते हैं, जहाँ वे अपने सामान्य अमेरिक कर्तव्यों में बाधा दिये बिना अपना प्रशिक्षण पा सकते हैं, क्योंकि इन यूनिटों में प्रशिक्षण, चार से चौदह दिनों तक के वार्षिक शिविर के समय को छोड़कर, अचकालिक ही होता है। लेकिन यह व्यवस्था रेलवे और डाक-घर-यूनिटों के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त नहीं है। इसलिए यह फैसला किया गया कि रेलवे और डाक-घर-विभाग के व्यक्ति को, जो इन यूनिटों में प्रवेश पाने के एकमात्र पात्र होते हैं, वर्ष में एक मास तक लगातार शिविर में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।

प्रादेशिक सेना के सदस्य सेना अधिनियम, १९५० से और उसके अधीन बनाये गये नियम से शासित होते हैं। पहले उन पर भारतीय सेना अधिनियम १९११ लागू होता था। शुरू में इन यूनिटों को खड़ा करने और प्रशिक्षण देने के लिए नियमित सैन्य अधिकारियों का तैनात करना जरूरी था, लेकिन बाद में थोड़े-थोड़े प्रादेशिक सेना के अधिकारियों और अन्य पदधारियों ने ही प्रशासनिक और औपचारिक कर्तव्य संभाल लिये।

प्रशिक्षण पाने समय प्रान्तीय यूनिटों के सदस्य अपने ओहदे के अनुसार वेतन-भत्तों को दरे पाने के अधिकारी होते हैं। शहरी यूनिटों के मामले में अचकालिक प्रशिक्षण पाते समय सरकारी कर्मचारी अपने वेतन-भत्तों की अर्धविक दरें प्राप्त करते रहते हैं और इसके अलावा प्रादेशिक सेना में अपने ओहदे के अनुरूप सैन्य वेतन-भत्ते भी प्राप्त करते हैं। जब प्रादेशिक सेना की यूनिटों का सेवा के लिए अंगीकरण होता है, तो उसके सदस्य नियमित सेना के संवादों ओहदों वाले वेतन-भत्ते आदि पाने के अधिकारी हो जाते हैं। पर जब ये परिस्थितियाँ पहले के अर्धविक नियोजन से कम होती हैं, तब सामान्यतः दोनों का अन्तर सरकारों या निजी नियोजकों द्वारा पूरा कर दिया जाता है।

प्रादेशिक सेना के व्यक्तियों को प्रोत्साहन देने के लिए मिलिटरी कॉलेज का राष्ट्रीय रक्षा-अकादेमी के सैन्य-रक्षक में उपलब्ध वास्तविक रिक्त स्थानों का २३ प्रतिशत उनके लिए आरक्षित कर दिया जाता है और अपना पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर उनकी नियमित कमीशन दे दिया जाता है ।

### सलाहकार समिति

प्रादेशिक सेना के गठन और विकास सम्बन्धी मामलों में भारत सरकार को सलाह देने के लिए मार्च, १९५३ में रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय सलाहकार-समिति बनायी गयी । इस समिति में ससद सदस्य, सुपसिद्ध सार्वजनिक व्यक्ति, मानिकी और मजदूरों के प्रतिनिधि, रक्षा-सचिव, सेना-स्टाफ-प्रमुख, वित्तीय-सलाहकार (रक्षा), सचिव (सञ्चार-विभाग) और अध्यक्ष, रेलवे-बोर्ड थे । प्रादेशिक सेना में भरती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राज्यों में भी सलाहकार समितियाँ नियुक्त की गयी ।

१९४८ के प्रादेशिक सेना अधिनियम में उन लोगों के अवैधिक रोजगार को सरक्षण देने की कोई व्यवस्था न थी, जो प्रादेशिक सेना में आ गये थे और फलस्वरूप उनकी मालिकी ने उनको प्रादेशिक सेना की नियुक्ति-काष्ठ में पुनर्पङ्क्याधिकार नहीं रखने दिया था । १९५१-५२ में प्राप्त अनुभव के आधार पर ससद द्वारा प्रादेशिक सेना (सञ्चयन) अधिनियम, १९५२ पास किया गया, जिसने मालिकों को इस दायित्व से बाँध दिया कि उनकी इन कर्मचारियों को पुनः उन शर्तों से अन्तून अनुबूल शर्तों पर वापस नौकरी में रखना होगा, जो प्रादेशिक सेना में शामिल होने के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति में बाधा न पड़ने पर उनकी प्राप्त हुई होती । यह विहित कर दिया गया कि ऐसे किसी कर्मचारी को फिर नौकरी देने से इनकार करने पर या ऐसा करने में अपने दायित्व से मुक्त जाने पर या ऐसे कारण बनाने पर कि पुनः रखना अनुमत्त है, यह मामला मानिक या नौकर द्वारा मध्यस्थ निर्णय के लिए सौंपा जा सकता था । जहाँ मालिक रहता है, उस जिले के जिला और सच-न्यायाधीश इस अधिनियम के अधीन इस प्रकार के विवाद के निर्णय के लिए मध्यस्थ-निर्णायक-प्राधिकारी के रूप में विहित किये गये हैं । इस अधिनियम के प्रयोजन से सैन्य-सेवा में प्रशिक्षण-अवधि भी शामिल की जाती है । इसलिए अब यह मालिक के लिए वैध रूप से बाध्यकर हो गया है, कि प्रशिक्षण के बाद प्रादेशिक सेना के व्यक्ति को उनकी पुरानी नौकरी पर बहाल करे ।

शुरू में मालिक अपने कर्मचारियों की प्रादेशिक सेना में भरती में आनाकारी करते थे, जिसका कि कारण उनकी यह आशंका थी कि आपात काल में प्रादेशिक सेना में भरती हुए कर्मचारियों की सेवा के लिए बुला लिया जायेगा और इस तरह वे मालिक को ऐसे समय पर उपलब्ध न रहेंगे, जबकि उनकी आन्धी ज़रूरतें हो पहले से बहुत ज्यादा हो जायेंगी । लेकिन योश ही प्रादेशिक सेना में दिये जा रहे प्रशिक्षण की उपयोगिता सभी की समझ में आ गयी और प्रादेशिक सेना ने इस प्रगति की ।

यथासमय अनिवार्य-प्रशिक्षण के अनाश प्रादेशिक सेना के व्यक्तियों की नियमित सेना की प्रुनिटा के साथ सहोच्छा से प्रशिक्षण देने के लिए बुलाया गया और सेना के प्रशिक्षण-

विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में भी शामिल होने के लिए भी बुलाया गया, ताकि उनका व्यावसायिक ज्ञान अद्यतन हो जाय।

हालांकि प्रादेशिक सेना की प्रांतीय यूनिटों में भरती का काम काफी सन्तोषजनक रहा, लेकिन शहरी यूनिटों में खासकर, तकनीकी व्यवसायों में, आरम्भ में यह बहुत सन्तोषजनक न रहा और तकनीकी यूनिटों की अविबुध संख्या में काफी कमी रही। केन्द्रीय सलाहकार-समिति ने ८ मार्च, १९५३ को हुई अखिली बैठक में मिफारिज की कि कुछ घेणियों के कर्मचारियों की २० से ४० साल की आयुसीमा में प्रादेशिक सेना में अनिवार्य नामांकन का दायित्व होना चाहिये। इस अनिवार्य दायित्व के लिए चुनी गयी सभी घेणियाँ सरकारी कर्मचारियों की और विनिर्दिष्ट लोक-उपयोगिता-उपक्रमों के कर्मचारियों की घेणियाँ थी। केन्द्रीय सरकार प्रस्तावित विधान के अधीन लाये जाने वाले लोक-उपयोगिता-उपक्रमों के कर्मचारियों के बारे में राज्य-सरकारों से परामर्श कर रही थी, ताकि उनका अनिवार्यता नामांकन किया जा सके। तदनुसार प्रादेशिक सेना अधिनियम (संगोपन) विधेयक ससद में २१ मार्च, १९५४ को पेश किया गया ताकि १० से ४० के आयु-वर्ग के सभी सरकारी कर्मचारियों और लोक-उपयोगिता-उपक्रमों के कर्मचारियों की प्रादेशिक सेना में अनिवार्य सेवा की व्यवस्था की जा सके, लेकिन यह विधेयक १९५६ के ससद तक चर्चायें नहीं लिया जा सका।

इस बीच हालांकि प्रादेशिक सेना में भरती की स्थिति में काफी सुधार हो गया था, फिर भी यह जरूरी समझा गया कि प्रादेशिक सेना में भरती की प्रभाव में लाने के लिए सरकार के पास कुछ घावियाँ होनी चाहिये, ताकि विद्यमान रिक्त स्थान भरे जा सकें और आपात में उसका विस्तार किया जा सके। सेना संगोपन अधिनियम, १९५६ ससद द्वारा १९५६ में पास किया गया था। फिर भी ऐसा इरादा नहीं है कि सभी सरकारी कर्मचारियों और लोक-उपयोगिता-उपक्रमों के सभी कर्मचारियों को प्रादेशिक सेना में भरती होने के लिए विवश किया जाय। लोक-उपयोगिता-उपक्रमों की अनिवार्य-नामांकन-योजना के अधीन लाने का कारण यही है कि अनिवार्य सेवार्थे आपात काल में काम करती रहें। लोक-उपयोगिता-उपक्रम वे हैं, जो जनता की बिजली, प्रकाश, गैस या पानी की पूर्ति करने हैं और लोक-परिवहन, लोक-सफाई का स्वच्छता कार्य भी, जो राज्यन में अधिमूचना द्वारा इस रूप में पोषित कर दिये जायें। ऐसी कोई अधिमूचना जारी करने से पहले केन्द्रीय सरकार को अपना यह समानान करना होता है कि ऐसे लोक-उपयोगिता-उपक्रमों में काम कर रहे व्यक्तियों का लोकहित में प्रादेशिक सेना में सेवा करने के लिए दायित्वाधीन बनाया जाना जरूरी है। स्त्रियाँ, अ-भारतीय नागरिक और केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति अधिनियम के अधीन अनिवार्य सेवा के दायित्वाधीन नहीं है।

## खण्ड २ . राष्ट्रीय सेना-दाय-दल

यह पहले बताया जा चुका है कि भारतीय प्रादेशिक बल के अंग-स्वरूप एक विश्व-विद्यालय-अभिधान-भर (यू० टी० सी०) गठित की गयी थी। विश्वविद्यालय-प्रतिपक्ष-पाठ्यक्रम में प्रतिपक्ष का उद्देश्य यह बताया गया था कि "सैन्य-मेरा के सिद्धान्त और आचरण में उनकी

दीक्षित किया जाय, व्यक्तियों का नेतृत्व करने का प्रशिक्षण दिया जाय, देशभक्ति और अनुशासन की भावना जगायी जाय, स्वास्थ्य सुधार जाय और भारतीय प्रादेशिक बल के अधिकारियों, गैर-कमीशन-प्राप्त अधिकारियों और सैन्य जनो के हेतु चयन की पृष्ठभूमि तैयार की जाय।” विश्व-विद्यालय से सम्बद्ध न रहने पर कौर के सदस्य को मुक्त कर दिया जाता था। विश्व-विद्यालय-प्रशिक्षण-कौर की बटानियमों पर सैन्य-सेवा करने का बन्धन न था।

विश्वविद्यालय-प्रशिक्षण-कौर में प्रशिक्षण पद्धति निम्नानुसार बहूत सन्तोषजनक न थी। सेना छात्र कमान के अधीन रहते थे, पर उनको कमान सँभालने का कभी अवसर न मिलता था और निश्चय ही उनका प्रशिक्षण व्यवहारिक रूप से नहीं होता था। १९४१ में कमांडर-इन-चीफ ने विश्वविद्यालय-प्रशिक्षण-कौर की प्रशिक्षण और प्रशिक्षण का स्तर ऊँचा करने की जरूरत पर जोर दिया, ताकि वह अधिकारियों को जन्म देने की स्थिति में हो जाय। तदनुसार कौर का नाम ही बदल कर अधिकारी-प्रशिक्षण-कौर कर दिया गया। लेकिन कार्यक्षमता का स्तर न सुधर सका और नया नाम भ्रामक सिद्ध हुआ।

पिछले विश्वयुद्ध के दौरान सशस्त्र सेनाओं में अधिकारी ओहदों के लिए पर्याप्त संख्या में उपयुक्त रूप से योग्यता प्राप्त युवकों को प्राप्त करने में कठिनाई का अनुभव किया गया। १५ जुलाई, १९४६ को सरकार ने एक समिति बना दी, जिसका काम एक ऐसे राष्ट्र व्यापी सेना-छात्र-दल-संगठन की, जिसमें विद्यालय और विश्वविद्यालय सभी आ जायें, स्थापना करने के प्रश्न पर विचार करना और सिफारिशें देना था। पोपंगा में कहा गया कि “हालांकि कमीशन प्राप्त करने के लिए बहुत संख्या में आवेदक ( युद्धकाल में ) सामने आते हैं, लेकिन अधिकांश लोगो में सूत्रपात, आत्मविश्वास और उत्तरदायित्व की भावना के गुण नहीं होते हैं। नेतृत्व के ये अनिवार्य गुण, जिनका होना एक अधिकारी में चारीरिक साहस और देश के स्वस्थ होने जितना ही जरूरी है, स्वभावतः अपने आप विकसित नहीं होते और एक व्यक्ति के चरित्र का निर्माण हो जाने के बाद फिर उनको विकसित करना भी हमेशा आसान नहीं होता। व्यक्ति के जीवन के प्रभाव ग्रहण करने वाले वर्षों में ही प्रशिक्षण लेकर सामान्यतः उनका निर्माण किया जा सकता है। इसलिए इतने सारे उम्मीदवारों में इनकी कमी यह बताती है कि शिक्षा की वर्तमान पद्धति में ही कोई त्रुटि है। यह विश्वास किया जाता है कि पूरे देश में राष्ट्रीय सेना-छात्र-दल के गठित हो जाने से इसमें सुधार हो सकेगा।” शुरू में समिति रक्षा-विभाग के एक समुक्त सचिव की अध्यक्षता में गठित की गयी और उसमें चार सरकारी सदस्य रॉयल इन्डियन नैवी, भारतीय सेना, रॉयल इन्डियन एयर फोर्स और भारत सरकार के शिक्षा-विभाग में लिये गये थे और उसमें चार गैर-सरकारी सदस्य और दो रियासतों से दो सदस्य रहे गये थे।

अन्तरिम सरकार के कार्यभार सँभाल लेने के बाद २६ सितम्बर, १९४६ को समिति के गठन में भारी परिवर्तन कर दिये गये।\*

\* सरकारी नौसल ऑफ स्टेट के सदस्य पंडित हृदयनाथ कुँवर को समिति का अध्यक्ष बनाया गया। रक्षा-विभाग के समुक्त सचिव सेफ्टी० नरेंद्र शम्भर मिश्रा



इस समिति को उपसमितियों ने भारत के विभिन्न प्रान्तों का पर्यटन किया। एक उप-समिति फरवरी-मार्च, १९४७ में इंग्लैण्ड भी नीमेना, मेना और वायुमेना के सेना छात्र संगठनों का और सासकर युवा-आन्दोलन का मामान्य अध्ययन करने के लिए गयी। समिति ने अपना प्रतिवेदन मार्च, १९४७ में सरकार को प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने बताया कि विश्व-विद्यालय-अधिकारी-कोरो के सेना छात्रों में आत्मविश्वास की कमी है और उनमें अनुशासन की भी कमी है और इसलिए पूरे कोर का ओवरहाल जरूरी है। प्रतिवेदन पाने के तुरन्त बाद ही महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन आसन्न आ गये और राष्ट्रीय सेना-छात्र-दल स्थापित करने की योजना पर उस समय सक्रिय अनुकार्य न हो सका।

आजादी के बाद अन्य अनेक कामों में व्यस्तता के बावजूद सरकार ने समिति के प्रति-वेदन पर काम शुरू किया। प्रान्तीय सरकारों को दिसम्बर, १९४७ में लिखा गया, क्योंकि शिक्षा-संस्थाओं के प्रशासन की जिम्मेवारी उनकी थी और योजना की सफलता बहुत सीमा तक उनकी सक्रिय अभिरूचि पर निर्भर थी। उनके उत्तर आने पर कोर बनाने सम्बन्धी एक विधेयक संविधान सभा ( विधायिनी ) ने २६ मार्च, १९४८ को पेश किया गया, जो ३ अप्रैल, १९४८ को पास हो गया। यह १६ अप्रैल, १९४८ से प्रभावी हो गया।

रक्षा-मन्त्रालय में एक राष्ट्रीय सेना-छात्र-दल-निदेशालय अप्रैल, १९४८ में बनाया गया और कर्नल के ओहदे के एक सेना-अधिकारी उसके निदेशक नियुक्त किये गये ( १९४४ में कोर का विस्तार होने पर यह ओहदा बड़ाकर ग्रेनेडियर का बना दिया गया )। राष्ट्रीय सेना-छात्र-दल के उद्देश्य संक्षेप में ये हैं : देश के युवकों में चरित्र, छापी-भावना, सेवा का जादरा और नेतृत्व की क्षमता विकसित करना, युवकों को सेनाओं का प्रशिक्षण देकर उनमें देश की रक्षा के प्रति अभिरूचि जागृत करना और जनसाधन को एक रसिति बनाना, ताकि सशस्त्र सेनाओं में राष्ट्रीय आपात में सेना में विस्तार किया जा सके। हालांकि राष्ट्रीय सेना-छात्र-दल शुरू में विद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्रों के लिए बनाया गया था, पर राष्ट्रीय सेना-छात्र-दल की पारा ७ में व्यवस्था है कि अतिरिक्त 'छुली' यूनिटें भी बनायी जा सकती हैं, जिनमें अपनी आजीविका कमाने वाले बालकों और युवकों को भरती किया जा सकता है।

राष्ट्रीय सेना-छात्र-दल में तीन डिबिजन हैं - स्कुलों के बच्चों के लिए कनिष्ठ डिबि-

उपशम्यंश थे। सरकारी सभ्य मे लोग थे : रॉयल इंडियन नैवी से कमांडर एच० एम० एस० चौधरी, भारतीय मेना के सेपटी० कर्नल अन्नाफ कादिर, रॉयल इंडियन एयर में फोर्न के ड्रप वैप्टिन ए० एम० इब्रीनियर, कर्नल जी० डब्ल्यू०एम० बटन, निदेशक सैन्य प्रशिक्षण और सेपटी० कर्नल बी० के० बाय-रम, शिक्षा-विभाग। और सरकारी सभ्य ये थे . डॉ० ए० सत्यनारायणो मुद-निपार, डॉ० अमर नाथ भा, पत्राईट सेपटी० क्पचन्द, मेजर जनरल ई० एल० एडम्स, सेपटी० कर्नल एम० हैदर, डॉ० मंजीव राव, डॉ० जी० एस० महाशनी। सेपटी० कर्नल एल० पी० सेन समिति के सचिव थे।

जन, विश्वविद्यालयों, इंटरमीडियेट और डिग्री कालेजों तथा तकनीकी संस्थाओं के लिए वरिष्ठ डिब्रीजिंग और वारिफा डिब्रीजिंग जिसमें पहले कालेजों और विश्वविद्यालयों की छात्राओं को ही लिया जाता था, पर १९४५ में वारिफा डिब्रीजिंग का एक कनिष्ठ स्कन्ध भी बना दिया गया है, जिसमें हाई स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियाँ ली जाती हैं ।

कनिष्ठ डिब्रीजिंग में प्रवेश के लिए बाल-वारिफाओं की आयु १३ और १८ के बीच होनी चाहिये, वरिष्ठ डिब्रीजिंग और वारिफा डिब्रीजिंग के वरिष्ठ स्कन्ध में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के छात्रों की आयु २६ वर्ष से कम होनी चाहिये । कनिष्ठ डिब्रीजिंग का सेवा-काल दो साल है और वरिष्ठ डिब्रीजिंग का तीन साल ।

वरिष्ठ डिब्रीजिंग और वारिफा डिब्रीजिंग ( वरिष्ठ स्कन्ध ) के प्रत्येक अधिकारी और सेना-छात्र की राष्ट्रीय सेना-छात्र-दल में अगले कार्यकाल में कम-से-कम एक समान सेवा और स्वयं सिविल में शामिल होना पड़ता है ।

गोर में कॉलेजों और स्कूलों के स्टाफ के चुने हुए सरसभ अधिकारी बनाये जाते हैं । पदों के समय अधिकारी विहित आयु-सीमा में होने चाहिये और ४५ साल की आयु तक वे राष्ट्रीय सेना-छात्र-दल में बर्गीकरण प्राप्त रहते हैं, जिसे ५० साल तक बढ़ाया जा सकता है ।

प्रशिक्षण का अंग है—हर साल ९० से ८० पीरियड तक सेवाओं के विषयों का प्रशिक्षण, कनिष्ठ डिब्रीजिंगों के लिए दस दिनों का और वरिष्ठ डिब्रीजिंगों के लिए १४ दिनों का, नियमित सैन्य-अधिकारियों के पर्यवेक्षण में, सिविल में बिताया जाना । प्रशिक्षण-वर्ष स्कूलों-कॉलेजों के वार्षिक वर्ष के अनुसार रहता है ।

प्रशिक्षण इस तरह व्यवस्थित किया जाता है कि वार्षिक अध्ययन के आगे न आये । कनिष्ठ डिब्रीजिंग के पहले साल के सेना-छात्र ए-१ प्रमाणपत्र तक प्रशिक्षित किये जाते हैं और दूसरे साल में प्रशिक्षण ए-२ प्रमाणपत्र तक के स्तर का होता है । वरिष्ठ डिब्रीजिंग में सेना-छात्रों को पहले साल में बी-प्रमाणपत्र और दूसरे तीसरे सालों में सी-प्रमाणपत्र तक का प्रशिक्षण दिया जाता है । वारिफाओं को दिये जाने वाले प्रशिक्षण में प्राथमिक उपचार, आरम्भिक नर्सिंग, बेथार और टेलीफोन संचार और अतिरिक्त रक्षा पर उपाय और दिया जाता है । दस प्रमाणपत्रों में गणन होने वाले सेना-छात्र प्रमाणपत्र के अनुसार सफेद, लाल, हरा या नीला प्रतीकता द्वारा सजा सकते हैं ।

राष्ट्रीय सेना-छात्र-दल में बर्गीकरण-प्राप्त और वरिष्ठ डिब्रीजिंग की किसी यूनिट में सेवा में अधिकारी, अधिक प्रशिक्षण डिब्रीजिंगों में सम्मिलित किये गये समय के लिए और सेना-स्कूलों और सेना यूनिटों में अभिप्रेत प्रशिक्षण प्राप्त करने समय के लिए, अपने ओहदे के मुख्य-दो समान सेनाओं के ओहदे के अनुसार वेतन पाने के हक्दार होते हैं । कनिष्ठ डिब्रीजिंगों के अधिकारी भी सैनिक स्कुलों में और सेना की यूनिटों के साथ विभिन्न पाठ्यक्रमों में वास्तविक उपस्थिति के समय के लिए, विहित वेतनदरों से मानदेय भी पा सकते हैं, बशर्ते कि उन्होंने उस समय के वार्षिक प्रशिक्षण-सिविल में भाग लिया हो ।

सेना छात्र किसी वेतन के पाने के हक्दार नहीं है । पर फिर भी उनकी प्रशिक्षण-

सिविल में वास्तविक उपस्थिति के प्रत्येक दिन के लिए कुछ भत्ता दिया जाता है, अगर वे सिविल में हो रहें, खाना खाएँ और सोएँ। अधिकारी और सेना-छात्र दोनों ही स्त्रियों या कॉन्वेन्सो में वापस प्रशिक्षण सिविल के स्थान तक निःशुल्क यात्रा के हक्कदार होने हैं और उस सेना-भूतल या यूनिट तक जाने-आने के लिए भी, जहाँ पाठ्यक्रम प्रशिक्षण या आगे का सैन्य-प्रशिक्षण दिया जाता है।

वरिष्ठ डिब्रीजिंग के अधिकारियों को पहले मेकिंग सेपरीनेंट का ओहदा या नौबेना और वायुसेना में समकक्ष ओहदा दिया जाता है और उसके बाद वे लेफ्टिनेंट, कैप्टन और मेजर के या समकक्ष ओहदे, विहित वर्षों तक कमीशन-मेवा पूरी करने के बाद, प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह जूनियर डिब्रीजिंग में पहले तृतीय अधिकारी के ओहदे में कमीशन पाने वाले अधिकारी फिर द्वितीय अधिकारी, प्रथम अधिकारी और मुख्य अधिकारी के ओहदे, विहित वर्षों तक कमीशन-मेवा पूरी करने के बाद, प्राप्त कर सकते हैं।

वरिष्ठ डिब्रीजिंग के अधिकारी नियमित सेना-अधिकारियों के ओहदों वाले ही बिन्ने लगाते हैं पर कन्वे पर जाने अक्षरों में रा० से० ६० की पट्टी रहती है। वरिष्ठ डिब्रीजिंग के अधिकारी कन्वे पर पीने अक्षरों में रा० से० ६० की पट्टी के साम नीचे लिये बिन्ने पहनते हैं। तृतीय अधिकारी-एक तारा, द्वितीय अधिकारी दो तारे, प्रथम अधिकारी-तीन तारे और मुख्य अधिकारी-अशोक त्रिभिह। अधिकारियों और सेना-छात्रों की परेड के समय, प्रशिक्षण के दौरान या किसी अधिभूत समारोह के अवसर पर ही वर्दी पहनने दी जाती है। वरिष्ठ और वरिष्ठ दोनों ही डिब्रीजिंग के अधिकारियों को नियुक्ति की अधिमूचना भारत के राजपत्र में तिकापी जाती है।

राष्ट्रीय सेना-छात्र-दल नियमों के प्रकाशन के बाद कोर शुरू करने के लिए कदम उठाये गये। ११ और १२ जून, १९४८ की दो अधिमूचनाओं द्वारा शिनिज प्राप्तों में १५ जुलाई १९४८ में वरिष्ठ और वरिष्ठ डिब्रीजिंग की मूनिटें बनायी गयीं। विरविद्यालय-अधिकारी प्रशिक्षण-कोर की मूनिटें १२ जून, १९४८ को भारतीय प्रादेशिक बल अधिनियम के अधीन एक अधिमूचना निकालकर समाप्त कर दी गयी।

पहले तो वरिष्ठ और वरिष्ठ डिब्रीजिंग की मूनिटों में सेना-स्कन्ध ही शुरू किया गया। पहले साल में पैदल सेना की मूनिटें खड़ी करने पर जोर दिया गया। १९४९ में आर्शिलरी, इजीनियर, सिगनल, बिबली और यांत्रिक इजीनियरी और बिबिस्ता-यूनिटों जैसी छानीकी मूनिटें खड़ी की गयीं।

जुलाई, १९४९ में दाहिना डिब्रीजिंग की तीन मूनिटें बचकता, नागपुर और मुयियाना में बनायी गयीं। भारत में पहली बार ही सड़ियों की सैन्य-व्यवस्था के अधीन प्रशिक्षण देने का उद्देश्य दिया गया था।

१९५० में वरिष्ठ डिब्रीजिंग में वायु-स्कन्ध की दो मूनिटें बम्बई और बनारस में और फिर तीसरी १९५१ में मद्रास में खड़ी की गयी। १९५२ में नौबेना-स्कन्ध का उद्घाटन, वरिष्ठ डिब्रीजिंग की दो नौबेना मूनिटें बम्बई और कोचीन में खड़ी करके, दिया गया। वरिष्ठ डिब्रीजिंग (वायु-स्कन्ध) की एक मूनिट दिन्नी, बानपुर और पटना में भी बनायी गयी। १९५३

में वरिष्ठ डिवीजन (नौसेना स्कन्ध) की यूनिट कलकत्ते में और वरिष्ठ डिवीजन (वायु-स्कन्ध) की एक यूनिट नागपुर में और एक जालन्धर में बनायी गयी। १९५३ में वरिष्ठ डिवीजन (वायु स्कन्ध) के सेना छात्रों के लिए स्टाइडिंग शुरू किया गया।

फनिष्ठ डिवीजन में भी सेना, नौसेना और वायुसेना-स्कन्ध खड़े किये गये, जो वरिष्ठ डिवीजन की वैसी ही यूनिटों के सवादी थे।

राष्ट्रीय-सेना-छात्रदल के अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार कोर के गठन और प्रशासन सम्बन्धी नीति के सभी मामलों पर केन्द्रीय सरकार को सलाह देने के लिए एक केन्द्रीय सलाहकार-समिति बनायी गयी। पहली बैठक ५ फरवरी, १९४९ को हुई। समिति के अध्यक्ष रक्षा-मन्त्री हैं और सदस्य रक्षा-सचिव, शिक्षा-सचिव, वित्तीय-सलाहकार (रक्षा), तीन सेना प्रमुख, ससद्द द्वारा चुने गये दो सदस्य और सरकार द्वारा नामित पाँच सदस्य।

प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय-सेना-छात्र-दल की, अपने-अपने राज्य में स्थित यूनिटों के प्रशासन और उनमें सुधार के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सलाह देने के लिए, सलाहकार-समितियाँ बनायी गयी।

राष्ट्रीय-सेना-छात्र-दल-निदेशालय में तीनों सेनाओं में आये हुए कर्मचारी होते हैं। संगठन के प्रमुख को निदेशक, राष्ट्रीय-सेना-छात्र-दल कहते हैं और १९६१ में उसके ओहदे को बड़ाकर मेजर जनरल का बना दिया गया। १९६२ में इस पद का नाम महानिदेशक, राष्ट्रीय-सेना-छात्र-दल रखा गया। विभिन्न राज्यों में प्रिंसिपल कर्नल या समकक्ष ओहदे के अफसर राष्ट्रीय-सेना-छात्र दल के निदेशक हैं।

राष्ट्रीय-सेना-छात्र-दल का खर्च केन्द्रीय सरकार और राज्य-सरकार के बीच मोटे तौर पर २:१ के अनुपात में आपस में बाँटा जाता है। केन्द्रीय सरकार का रक्षा-मन्त्रालय स्थायी प्रशिक्षण-कर्मचारियों (सहाय्य छात्रों के) का वेतन-भत्ता वा, यूनिट उपस्करों का, यांत्रिक परिवहन और उसके सन्धारण का, सेना-छात्रों के लिए वरदी का, वार्षिक प्रेरित छ गोलाबारूद, का सारा खर्च और सिविल खर्च का ५० प्रतिशत वहन करता है। राज्य-सरकारें राष्ट्रीय-सेना छात्र दल की यूनिटों के असैनिक कर्मचारियों के वेतन भत्तों का और दफ्तर का, आउटफिट भत्ते का, राष्ट्रीय-सेना-छात्र-दल के अधिकारियों के मानदेय का, सेना-छात्रों के भत्ते का पूरा खर्च उठाती हैं और सिविल-व्यय का ५० प्रतिशत खर्च।

समान सेनाओं के बर्गीकरण वाले ओहदों में भरती के इच्छुक सेना छात्रों को विशेष प्रोत्साहन देने के लिए १९५१ में एक विशेष योजना तैयार की गयी। वरिष्ठ डिवीजन (सेना-स्कन्ध) के सेना-छात्र, जो तीन साल की सेवा राष्ट्रीय-सेना-छात्र-दल में कर चुके थे और जिनके पास विश्वविद्यालय की उपाधि थी और जो राष्ट्रीय-सेना-छात्र-दल का 'ग' प्रमाण-पत्र पर चुके थे, उनको सपीय-लोक-सेवा-आयोग को लिखित परीक्षा दिये बिना सेना में नियमित कर्मीकरण का पात्र बना दिया गया। योग्यता वाले सेना-छात्रों को केवल सेना-चयन-बोर्ड के समक्ष उचित होना पड़ता था और उनको चुने जाने पर वरत एक साल का प्रशिक्षण ( जो अक्षय बाद में बढ़ा दी गयी ) भारतीय सैन्य-अकादेमी में प्राप्त करना होता था, जबकि संघीय-लोक-सेवा-आयोग के अखिरे प्रवेश वाले सेना-छात्रों ने निए अक्षय दो साल की थी। पहले कर्मीकरण

वाले ओहरे में १० प्रतिष्ठित जगहे राष्ट्रीय-सेना-छात्र-दल के सेना-छात्रों के लिए आरंभित रखी जाती थी। यह आरंभित बाद में बढ़ाकर १५ प्रतिष्ठित कर दी गयी, लेकिन जुलाई, १९६३ में समाप्त कर दी गयी, जबकि अधिकारी-प्रशिक्षण-यूनिटें (राष्ट्रीय-सेना-छात्र-दल) शुरू कर दी गयी।

अधिकारी-प्रशिक्षण-यूनिटें अगस्त १९५६ में शुरू की गयी, जो विशेष रूप से चुने गये ऐसे सेना-छात्रों के प्रशिक्षण के लिए बनी थी, जो सशस्त्र सेनाओं में भरती होना चाहते थे। इस योजना के अधीन अधिकारी-प्रशिक्षण-यूनिट में वार्षिक रूप से २५० छात्र लिए जाते हैं। यूनिटों को कुल सेना-छात्र-संख्या ७५० है। शुरू में योजना में यह कल्पना थी कि गैर तकनीकी और तकनीकी (इंजीनियरी और चिकित्सा) दोनों प्रकार के छात्रों को लिया जाय, लेकिन तकनीकी छात्रों का प्रवेश १९६३ में बन्द कर दिया गया।

चुने हुये सेना छात्र अधिकारी-प्रशिक्षण-यूनिटों में भेजे जाते हैं और उनका छ हफ्ते की अवधि के वार्षिक सिलेबो में तीन सालों तक के शीघ्रतावकास में प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रकार इन सेना-छात्रों को वरिष्ठ डिप्लोमा, राष्ट्रीय-सेना-छात्र-दल के सेना छात्रों की अपेक्षा ज्यादा गहन प्रशिक्षण दिया जाता है। अधिकारी प्रशिक्षण यूनिटों के सेना-छात्रों को 'घ' प्रमाण पत्र के लिये परीक्षा देनी होती है। जिन लोगों के पास यह प्रमाणपत्र और शैक्षिक डिग्री होती है, वही भारतीय सैन्य-अकादेमी में प्रवेश पा सकते हैं। अधिकारी-प्रशिक्षण-यूनिट के सेना-छात्रों की पहली टुकड़ी भारतीय-सैन्य अकादेमी के जुलाई, १९६२ में शुरू होने वाले पाठ्यक्रम में प्रवेश का शान बनी थी।

आपातकाल में पहले भारतीय-सैन्य-अकादेमी की १५ प्रतिष्ठित जगहे अधिकारी-प्रशिक्षण-यूनिटों के सेना-छात्रों के लिए सुरक्षित रहती थी। बाद में हर-साप्ता ८० जगहे अधिकारी प्रशिक्षण-यूनिटों के सेना-छात्रों को स्थायी कनिष्ठ प्रदान करने के लिए आरंभित कर दी गयी। अगस्त, १९६६ में यह संख्या घटाकर ३० कर दी गयी है।

राष्ट्रीय सेना-छात्र-दल-योजना मुख्यतः शैक्षिक और राष्ट्रनिर्माण के प्रकार की है। अधिकारियों और सेना-छात्रों का सक्रिय सैन्य-सेवा का कोई वादित्व नहीं है। इन तरह राष्ट्रीय सेना-छात्र-दल प्रादेशिक सेना में भिन्न है, जो सेना-मुख्यालय के अधीन है, जबकि राष्ट्रीय सेना-छात्र-दल सीधे रक्षा-मन्त्रालय के ही अधीन है।

राष्ट्रीय सेना-छात्र-दल-योजना का एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि सेना-छात्रों को उच्चतम प्रशिक्षण-काल का कुछ अंग समाज-सेवा-कार्य के लिए उपलब्ध कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य यह है कि (एक) सेना-छात्रों को धर्म की प्रतिष्ठा को दिया दो जाय (दो) उनमें रचनात्मक कार्य के प्रति रुचि जगायी जाय, जो समुदाय के काम आयेगी (तीन) नि स्वार्थ कार्य का उदाहरण प्रस्तुत किया जाय (चार) सहकार्य की भावना पैदा की जाय और (पांच) संगठित कार्य में नेतृत्व प्रदान किया जाय, ताकि लोगों के फालतू समय, शक्ति और अन्य साधनों का उपयोग किया जा सके और उनकी सामाजिक और आर्थिक कार्य-कलाप के विभिन्न क्षेत्रों में निर्देशित किया जा सके। देश के विभिन्न भागों में आयोजित होने वाले वार्षिक

शिविरो में रक्षणात्मक कार्य भी किया जाता है, जैसे कच्ची सड़कें, गाँव के रास्ते, छोटे पुल, पुलियाँ, सिंचाई की नहरें और वर्षा और बाढ़ के पानी के निकास की नहरें बनाना, सिंचाई और पीने के पानी के तालाबों और कुओं का सुधार करना, विद्यालय-भवन बनाना, प्रौढ-शिक्षा-आन्दोलन चलायाना और दूर के गाँवों में चिकित्सा की सुविधा पहुँचाना।

काफी बड़े पैमाने पर छात्रों के लिए सैन्य-प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए १९५६ में यह निर्णय किया गया कि राष्ट्रीय सेना-छात्र-दल की राइफल यूनिटें पैदल राइफल-रेजीमेंटों की तरह बनायी जायें। इन यूनिटों में कॉलेजों के (सड़के लड़कियाँ दोनों) १६ साल और ऊपर के छात्र प्रवेश ले सकते थे। अगले साल राष्ट्रीय सेना-छात्र-दल की राइफल-यूनिटों में प्रवेश शुरू किया गया। बाद में यह योजना १९६३ में शुरू की गयी अनिवार्य राष्ट्रीय सेना-छात्र-दल-योजना में शामिल कर दी गयी।

जैसा बताया जा चुका है, राष्ट्रीय सेना-छात्र-दल में प्रवेश बिलकुल स्वैच्छिक था। योजना का विस्तार प्रत्येक राज्य द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन उपलब्ध किये गये सहायनों से जुड़ा था। जुलाई-अगस्त, १९६३ से शुरू होने वाले शिक्षा-सत्र से कॉलेजों के सभी समर्पण पुराने छात्रों के लिए राष्ट्रीय सेना-छात्र-दल का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया। यह शिक्षा-अधिकारियों के समर्थन से किया गया था, जिन्होंने इस प्रयोजन से आर्मीनैस निकाल दिये थे। स्नातकोत्तर छात्र और कुछ अन्य धर्मियाँ इस अनिवार्य प्रशिक्षण से मुक्त हैं। इस योजना के अधीन प्रत्येक सेना छात्र को सप्ताह में दो दिन चार घण्टों की कुल अवधि तक प्रशिक्षण लेना पड़ता है।

### खण्ड ३ सहायक सेना-छात्र-दल और लोक-महायक-सेना

बिस्तीय कठिनाइयों के कारण शिक्षा-संस्थाओं में की जाने वाली राष्ट्रीय सेना-छात्र-दल के भारी विस्तार की बढ़ती हुई माँग को पूरा करना संभव न था। राष्ट्रीय सेना छात्र-दल के एक मध्यहीन पूरक के रूप में १९५४ में स्कूलों में सहायक-सेना-छात्र-दल की योजना 'देश-सेवा' के आदर्श आशय के साथ शुरू की गयी, जिसका उद्देश्य यह था युवकों का मानसिक, शारीरिक और नैतिक निर्माण किया जाय और उनके चरित्र और नेतृत्व की क्षमता का विकास करके उनको अच्छा और अनुशासनबद्ध नागरिक बनाया जाय, छात्रों में देशभक्ति की भावना जगायी जाय, सहयोग की भावना, संगठित जीवन और आत्मविश्वास की भावना विकसित की जाय और उनकी समाज सेवा के लिए प्रशिक्षित किया जाय और उनकी श्रम की प्रतिष्ठा का गठ पड़ाया जाय।

भाष्यमिक कक्षाओं के सभी छात्र, लड़के-लड़की, जिनकी आयु-सीमा १३ और १६ के बीच है, सहायक-सेना-छात्र-दल में प्रवेश ले सकते हैं।

द्विचारा प्रशिक्षण में शारीरिक प्रशिक्षण, दुर्बलियों के खेल, प्रारम्भिक प्रयोगचार, स्वस्थता और स्वास्थ्य रक्षा, समाज-सेवा, शेनोय-गिन्य और शारीरिक श्रम शामिल होता है। प्रशिक्षण स्कूल के सामान्य घण्टों में दिया जाता है, जिसके लिए अनिवार्य की छोड़ सभी कार्य-दिनों का ४० मिनट का एक पीरियड बनव रखा जाता है। हौसी, बला, सिला, और

सांस्कृतिक कार्य-शाला को प्रोत्साहित करने वाला सामान्य प्रशिक्षण स्कूल के सामान्य पोलिसियों के बाहर सप्ताहान्त में और दीर्घावकाश में उत्तम स्वानीय मुविचाओं के अनुसार दिया जाता है। सहायक-सेना छात्र-दल के लिए सादो यूनीफार्म रखी गयी थी। धर्म और समाजसेवा-सिविर-समुदाय-विकास-क्षेत्रों में और राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्लबों में सेना-छात्रों में धर्म की गतिष्ठा के भाव जाग्रत किये जाते थे।

सहायक-सेना-छात्र-दल के अन्तर्गत स्कूलों में शिक्षा-मन्त्रालय द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय अनुसामन-योजना भी चल रही थी और क्लब स्काउट और गर्ल गाइड की योजनाएँ भी थी। शिक्षा-मन्त्रालय ने स्कूलों के लिए उपयुक्त एक एकीकृत योजना की सिफारिश करने के लिए एक समिति बनायी। फरवरी एक नयी योजना राष्ट्रीय स्वस्वसेवा-दल नाम से शिक्षा-मन्त्रालय ने स्कूलों में शुरू करायी। १९६५-६६ में सहायक-सेना-छात्र-दल उन स्कूलों में समाप्त कर दिया गया, जहाँ इसकी जगह नयी योजना चलाई जा सकती थी। इस तरह सहायक-सेना-छात्र-दल को अलग योजना के रूप में खत्म किया जा रहा है।

### सोफ्ट-सहायक-सेना

प्रादेशिक सेना, राष्ट्रीय-सेना-छात्र-दल और सहायक-सेना-छात्र-दल-योजनाओं के बाहर भी गांवों की बहुत सारी प्रौढ़ जनसंख्या रोप रह जाती थी। प्रादेशिक-सेना-प्रशिक्षण-योजना में ज्यादा विस्तार करने में वित्तीय दिक्कतें थी।

१९५३ में जनता में सपासंभव अधिकाधिक अनुशासन और आत्मविश्वास की भावना भरने के लिये सहायक-प्रादेशिक-सेना, जिसे फरवरी, १९५४ में सहायक-प्रादेशिक-दल नाम दिया गया, शुरू की गयी। प्रशिक्षण में बन्दूक चलाना, २२ राइफल चलाना, आरम्भिक क्षेत्र-इंजीनियरी, कक्षापद, पारोरिक प्रशिक्षण, प्रथमोपचार और स्वास्थ्य-रक्षा शामिल थे। १६ से ४० वर्ष तक के सभी समर्पण पुरुष नागरिक, (भूतपूर्व सैनिकों और राष्ट्रीय सेना-छात्र-दल के सेना-छात्रों को छोड़), इस धन में भरते ही सकते थे। अनिवार्य सैन्य-सेवा पर कोई बंधन न था। मई १९५४ में सहायक-प्रादेशिक-दल-विशेषक ससद् में पेश किया गया, ताकि योजना को वेध आधार मिल जाय और प्रशिक्षणियों पर अनुसामन-नियन्त्रण रखा जाय।

१९५३-५४ में गुविपारनक स्थानों में देहाती और शहरी सिविर बनाये गये। देहाती सिविरों में साठ दिनों का सप्ताहिक प्रशिक्षण चलता था, जो बाद में बड़ाकर दस दिन कर दिया गया, जबकि शहरी सिविरों में १४ कार्य-दिनों में हर रोज एक घण्टे का प्रशिक्षण दिया जाता था। देहाती सिविरों के प्रशिक्षणियों को मुक्त राशन मिलता था। सम्पूर्ण में आवास और खरचो दी जाती थी। प्रशिक्षण के अन्त में उनको कुछ भत्ता भी दिया जाता था। शहरी सिविरों में प्रशिक्षणियों को सिविरों में नहीं रहना पड़ता था।

जब सिविर चलाये गये, तो स्पष्ट हो गया कि लोग प्रशिक्षण पाने के लिए उत्सुक थे और प्रशिक्षण प्रभावों बनाने के लिए इसकी अवधि बढ़ाना जरूरी था। नवम्बर, १९५४ में प्रादेशिक सेना की केन्द्रीय सप्ताहिक-समिति ने इस योजना का पुनर्विचार किया और सिफारिश की कि सिविर कम-से-कम एक महीने के होने चाहिये और बहुत ज्यादा लोगों को इस

योजना के अन्तर्गत लेना चाहिये। तदनुसार यह निर्णय किया गया कि अगले पाँच साल तक लगभग एक लाख व्यक्तियों को हर साल राष्ट्रीय स्वैच्छिक-बल नामक एक नयी योजना के अधीन प्रशिक्षित किया जायेगा। इस बल का उद्घाटन १ मई, १९५५ को किया गया। योजना का लक्ष्य जनता के सदस्यों को सैन्य-प्रशिक्षण देना था, ताकि उनमें अनुशासन, सुरक्षा, आत्म-निर्भरता की भावना आये और राष्ट्र-मेवा की रूचि पैदा हो। प्रशिक्षण-अवधि बढ़ाकर ३० दिन कर दी गयी। सभी समयांग व्यक्ति जो भारत के नागरिक थे (और भूतपूर्व सैनिक और भूतपूर्व राष्ट्रीय सेना-छात्र-दल के सेना-छात्र न थे) और १८ से ४० की आयु सीमा में थे, इस योजना में प्रवेश लेने के पात्र थे।

प्रादेशिक सेना के लिए जो केन्द्रीय सलाहकार समिति १९५३ में बनायी गयी थी, उसका अगस्त, १९५५ में प्रादेशिक सेना और राष्ट्रीय स्वयंसेवी-दल की एक संयुक्त समिति के रूप में पुनर्गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष रक्षा-मन्त्री थे। संयुक्त समिति में सामुदायिक प्रायोजनाओं के प्रचारक भी शामिल थे और बाद में जब सितम्बर, १९५६ में समुदाय-विकास-मन्त्रालय बनाया गया, तो उसके एक प्रतिनिधि को भी रखा गया। इसने समुदाय-प्रायोजनाओं और इस प्रशिक्षण-योजना के बीच सहकार पर जोर दिया। २६ सितम्बर, १९५५ को हुई पहली बैठक में संयुक्त केन्द्रीय सलाहकार-समिति ने राष्ट्रीय स्वयंसेवी-दल का नामकरण लोक-सहायक-सेना करने का निर्णय किया।

लोक-सहायक-सेना योजना के अधीन पूरे देश में विभिन्न जगहों में हर साल लगभग २०० शिविर आयोजित किये जाते थे, जो प्रत्येक क्षेत्र के मौसम के अनुसार और फसल-कटाई आदि की दृष्टि से स्थानीय प्रयोगों की सुविधा की दृष्टि में रखकर रखे जाते थे। चुने गये प्रायोजना-स्थल साधारणतः समुदाय-प्रायोजना-क्षेत्र और राष्ट्रीय-विस्तार-सेवा-मलाको के बहुत निकट रहते थे, ताकि सैन्य-प्रशिक्षण के साथ-साथ प्रशिक्षार्थी रचनात्मक राष्ट्र-कार्य का प्रायोगिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। हर शिविर में एक समय में अधिकतम सख्या ५०० प्रशिक्षार्थी रहती थी और हर शिविर की अवधि ३० दिन की रहती थी। लोक-सहायक-सेना में स्वैच्छा से शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को लगातार तीस दिन का प्रशिक्षण लेना होता था। प्रशिक्षण पाठे समय उस पर सेना-अधिनियम नहीं लागू होता था, न प्रशिक्षण पूरा होने पर उस पर किसी प्रकार की सैन्य-सेवा के लिए बुलाये जाने की दायिता ही होती थी। शिविरो में रहने पर प्रशिक्षार्थियों को मुफ्त राशन मिलना था और मुफ्त चिकित्सा-उपचार। कपड़े और दूसरे वस्तुओं सामान भी (जो शिविर के अन्त में वापस करने होते थे) उनको दिये जाते थे। प्रशिक्षण के अन्त में हर एक प्रशिक्षार्थी को जेबखर्च-भत्ता भी दिया जाता था।

प्रत्येक शिविर के सर्वोत्तम प्रशिक्षार्थी को योग्यता-प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता था। और प्रोत्साहन देने के लिए पिछले साल में हुए सभी शिविरो के योग्यता-प्रमाण-पत्र पाने वाले को दिवसी में गणराज्य दिवस परेड और समारोहों में शामिल होने के लिए बुलाया जाता था। पहली दुबई ने १९५६ की परेड में भाग लिया।

हालांकि लोक-सहायक-सेना सैन्य-सेवा का कोई बन्धन नहीं सादती थी, फिर भी



प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को एक प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा जाता था कि भूकम्प, बाढ़ आदि जैसे आपात में वह राष्ट्र-सेवा करेगा।

मूल योजना की संकल्पना कुछ-कुछ बदल जाने से संसद में मई, १९५८ में पेश किया गया सहायक-प्रादेशिक-बन-विधेयक वापस ले लिया गया। संसद ने संशोधित लोक-सहायक-सेना-विधेयक सितम्बर, १९५९ में पास कर दिया।

लोक-सहायक-सेना-योजना १ जनवरी, १९६१ से पुनर्गठित की गयी, जिसके अनुसार सोमा-क्षेत्रों में प्रशिक्षण शिविरों को अधिक साठ दिन तक बड़ा दो गयी। अन्य क्षेत्रों में यह अधिक १० दिन की बनी रहो।

अक्टूबर, १९६२ में आपात की घोषणा के बाद लोक-सहायक-सेना की योजना स्पष्ट कर दी गयी, ताकि इसके उत्स्कर और अन्य साधन निवर्तित सेना के लिए उपलब्ध हो जायें। बाद में सीमा-स्थिति को ध्यान में रखते हुए लोक-सहायक-सेना को २६ टीमों में से १७ को फिर से सजा किया गया और उनको सीमावर्ती राज्यों में वार्षिक जनता को १५ दिनों के शिविरों में राष्ट्रक-प्रशिक्षण देने के लिए लगाया गया। पर देखा गया कि बदली परिस्थिति में लोक-सहायक-सेना के लिए सामान्य जोर ठा पड़ता जा रहा था और फलत कुछ राज्यों में स्वयंसेवियों की संख्या पर्याप्त न थी। इसलिए १७ टीमों में से ११ वापस बुला ली गयी।

साथ ही आपात के आरम्भ होने पर राज्यों में होम-गार्ड-संगठन का विस्तार किया गया और उसे पुनर्गठित किया गया। ग्राम-रक्षा-दन जैसे अन्य संगठन बाँव की जनता को आत्म-रक्षा का प्रशिक्षण देने के लिए बनाये गये। लोक-सहायक-सेना-योजना के मूल उद्देश्य की अव सगठनों द्वारा गुणवत्ता रूप में पूर्ति हो रही थी। इस तरह लोक-सहायक-सेना व्यर्थ मानी गयी और उसकी दोष टीमें भी १९६४ में विघटित कर दी गयी। फिर भी लोक-सहायक-सेना-अभिनिर्णय, १९५९, संविधि-पुस्तिका में बल रहा है, ताकि जब कभी जरूरी समझा जाय, तो इस योजना को पुनर्जीवित किया जा सके।

## घोड़हवा अध्याय

### रक्षा-व्यय और रक्षा-आयोजना

किसी देश के आय-व्यय का अनुमान अब केवल उस देश के विधान-मण्डल के सदस्यों और वहाँ की जनता की स्थानीय रूचि का ही विषय नहीं रह गया है, बल्कि दूसरे देशों के लिये भी सामान्य रुचि का विषय हो गया है। अगर इन अनुमानों का ध्यान से कुछ वर्षों की अवधि के अनुसार विवरण दिया जाए तो उससे हम देश की आर्थिक शक्ति और युद्ध शक्त का संकेत मिल सकता है।

भारत में, युद्ध से पूर्व, सविदा आय-व्यय की प्रणाली रक्षा-सेवाओं के लिए प्रयुक्त होती थी, जिसके अनुसार रक्षा-व्यय प्रति वर्ष ५५ करोड़ रुपये की रकम से बँध जाता था। इसका मतलब यह था कि बहुत आवश्यकताओं का स्वरूप कुछ भी हो, शांति-काल में सामान्यतः इस रकम से अतिरिक्त और कोई रकम न मिल पाती थी। उन दिनों में ५५ करोड़ रुपये से ज्यादा रकम की व्यवस्था को न्यायोचित ठहराना वास्तव में बहुत मुश्किल था, क्योंकि यह रकम भी केन्द्रीय सरकार के कुल राजस्व के आधे से ज्यादा थी और उस समय रक्षा-सेनाओं का नाम पश्चिमोत्तर सीमान्त की सुरक्षा को आसवस्त रखने और आन्तरिक अव्यवस्था रोकने तक ही सीमित था। इस अधिकतम सीमा को निर्दिष्ट कर देने का अर्थ स्वभावतः यह था कि इस सीमा के भीतर अगर कोई बचन हो तो वह आब की तरह व्यय नहीं होकर अगले सालों में ले जायी जा सकती थी। इस प्रकार से १९२८-२९ वर्ष में 'रक्षा-आरक्षित-निधि' की स्थापना एक ऐसी निधि बनाने के उद्देश्य में की गयी थी, जिसमें से सशस्त्र सेनाओं को पुनः सज्जित करने के अविलम्बनीय उपायों के हेतु पैसा खर्च किया जा सके और सरकार न यह अपेक्षा न की जाये कि वह ५५ करोड़ रुपये की 'सविदा' रकम से ज्यादा पैसा हर साल देने के लिए व्यवस्था करे। इससे रक्षा-सेवाओं के आय-व्यय का अनुमानों को स्थिर कर रखने में मदद मिली। सशस्त्र सेनाओं वर्षानुवर्ष जो बचत अपने स्थायी खर्चों को कम करने के बचत-आन्दोलन चलाकर कर लेती थी, वह रकम इस निधि में स्थानान्तरित कर दी जाती थी। युद्ध से पहले खर्च किसी पूर्वी-शीर्ष के नाम नहीं डाला जाता था और रक्षा-आरक्षित-निधि का उपयोग मुख्यतः पुनः सज्जा के कामों के लिए पैसा देने में किया जाता था। वर्ष १९३६-३७ के अन्त में रक्षा-आरक्षित निधि में ३-४६ करोड़ रुपये जमा थे।

१ अप्रैल १९३९ से ३१ मार्च, १९४७ तक रक्षा-सेवाओं सम्बन्धी व्यवसाय भारत सरकार और इंग्लैण्ड में मन्त्रालय सरकार के बीच, दोनों सरकारों द्वारा, युद्ध शुरू होने के तुरन्त बाद किये गये द्वितीय करार के अनुसार, बाँट दिया जाता था। इस करार के चारू रहते समय यह अनुमति नहीं थी कि रक्षा-आरक्षित-निधि में कोई रकम ली जाए या उसमें जमा की जाए। यह करार ३१ मार्च, १९४७ को समाप्त हो गया। ४ अगस्त, १९४७ को रक्षा-आरक्षित-निधि में

रोकड़ बाकी १०५ करोड़ रुपये थे, जिसे अविभाजित भारत सरकार के हिस्से में जमा कर दिया गया।

अप्रैल, १९४७ में भारत की अन्तरिम सरकार ने यह फैसला किया कि ५ वर्षों की अवधि के लिये रक्षा-मेधाओं के हेतु 'मविदा' आय-व्ययक की मुद्र-पूर्व वाली प्रणाली फिर से लागू की जाये। १९४६-४७ के वित्तीय वर्ष से १०२५ करोड़ रुपये की रकम भारतीय संसद सेनाओं के नाम अर्जित कर दी गयी। उस समय १९४७-४८ का व्यय-अनुमान १८६ करोड़ रुपये लगाया गया था और यह आशा की गयी थी कि यह रकम अगले दो सालों में ८६५ करोड़ रुपये कम हो जा सकती थी, लेकिन उसके बाद परिस्थितियाँ बदल गयीं। आज की आय-व्ययक समस्याएँ इतनी जटिल हैं कि किसी आरंभित-निधि को खर्च करने की बात नहीं सीधी जा सकती, भले ही यह वास्तविक वचन द्वारा खड़ी की जाये।

### स्वाधीनता के बाद वित्तीय-वचनबद्धता

सत्ता-हस्तान्तरण के बाद राज्य की रक्षा का दायित्व पूरी तरह भारत के ऊपर आ गया और अब सारा व्यय उसके अपने ससाधनों द्वारा ही पूरा करना था। विभाजन के फल-स्वरूप भारत की स्थल सीमाएँ काफी लम्बी हो गयीं, जिसका मतलब यह हुआ कि रक्षा-व्यय की वचनबद्धता बड़ गयी। सेना की यूनिटों को आधुनिक स्तर तक लाने के लिए यन्त्रीकृत करना पड़ा। जी-मेनो और वायुसेना को, न्यूनतम आवश्यकताएँ पूरी करने के लिये ही, प्रायः आदि से पुनर्निर्मित करना था। इसका मतलब था कि जहाजों, विमानों और यन्त्र-सामग्री की खरीद की जाये, जिसके लिए पूरा-पूरा पैसा जुटाना होता था।

विभाजन ने पहले भारत की रक्षा-मेधाओं के आवास अधिवास ऐने क्षेत्रों में स्थित थे जो अब पाकिस्तान के अंग हैं। सशस्त्र सेनाओं के विभाजन के बाद हालाँकि भारत का हिस्सा मेधाओं का दो-तिहाई था, तथापि उसके क्षेत्र में उपलब्ध आवास की मुविधा केवल एक-तिहाई ही थी। रक्षा-मेधाओं को जगह देने के लिए न्यूनतम अत्यावश्यक आवास स्थान की भी व्याख्या करने के लिए व्यय करना पड़ा। कुछ सैन्य-प्रतिष्ठान संस्थान पहले पाकिस्तान के क्षेत्र में स्थित थे। उनको भारत में फिर से बनाना पड़ा। दूसरे प्रतिष्ठान-संस्थान, जो पहले अस्तित्व में नहीं थे, उनकी भी स्थापना करनी पड़ी, ताकि भारत यथासम्भव रक्षा-मेधाओं के प्रतिष्ठान के मामले में आत्मनिर्भर हो जाये।

मुद्र के बाद रहन-सहन के खर्च में भी काफी वृद्धि हो गयी है। इसलिए राशन, कपड़ा और रक्षा मेधाओं के लिए जरूरी अन्य चीजों की पूर्ति करने के लिये भी अब पहले से ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ा। रक्षा-नामिकों के वेतन और भत्ते, सरकार के अर्जित कामियों के वेतन-भत्ते के समान रहने की दृष्टि से, बढ़ाने पड़े। प्रादेशिक-सेना, राष्ट्रीय-सेना-प्राय-दल, रक्षा-अनुसंधान-मण्डल आदि जैसे अनेक नये संगठन भी बनाने पड़े। आयोजित भण्डार और सामग्री के दाम भी मुद्र-पूर्व के मूल्य-स्तर की तुलना में काफी बढ़ चुके थे। आजादी के बाद देश में जो महत्त्वपूर्ण रक्षा-उद्योग स्थापित किये गये उनमें भी काफी पूँजी व्यय करनी पड़ी और उनसे

कारण आवर्तों खर्च भी बढ़ गया। सत्ता-हस्तान्तरण के बाद इन सब कारणों ने मिलकर भारत में न्यूनतम रक्षा-सेवाओं को बनाये रखने का खर्च काफी बढ़ा दिया।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, रक्षा-सेनाओं के लिए कुछ प्रशिक्षण-संस्थान स्थापित करने और यूनिटों तथा विरचनाओं के लिये न्यूनतम आवश्यक आवास की व्यवस्था करने और नये जहाजों, विमानों आदि को खरीदने में, जिनको कि प्रत्यक्ष परिसम्पत्ति माना जा सकता है, काफी व्यय करना पड़ा। ऐसा-व्यय पूँजी-शीर्ष में डाला जा सकता था, जैसा कि युद्ध के वर्षों में सरकार के सामान्य चलन के अनुसार किया जाता था, लेकिन जब १९४७-४८ का आय-व्ययक अन्तरिम सरकार ने प्रस्तुत किया तो यह चलन खत्म कर दिया गया और ऐसे सारे खर्च राजस्व-अनुमान पर भारित किये गये। इस स्थिति का पुनर्विचिन्तन अगले साल किया गया, जब यह फैसला किया गया कि रिकर और प्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ बनाने वाला सारा व्यय पूँजी-व्यय माना जाना चाहिए और ऐसे सारे खर्च को डालने के लिए १९४८-४९ में एक अलग शीर्ष 'रक्षा-पूँजी-व्यय' खोला गया।

१९४९-५० के वर्ष में अनुमान और सेवाओं के रूप में एक नया महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया गया और एक सेवा द्वारा दूसरी सेवा को दिये गये भण्डार और सामग्री की सागत के अन्त-सेवा-सम्बन्धों की व्यवस्था की गयी। इस प्रकार राशन, पैट्रोल, विमान-पैट्रोल, सामान्य उपयोग की गाड़ियाँ और उपकरण की सागत, जब ये चीजें सेवा द्वारा नौसेना या वायुसेना को दी जाती थी, तो इसका खर्च नौसेना या वायुसेना के खाते में डाला जाता था और उमे सेना के सगत खाते में जमा कर दिया जाता था। ऐसा ही सम्बन्ध नौसेना या वायुसेना द्वारा अन्य दो सेनाओं में से किसी को दिये गये भण्डार की सागत के लिए भी किया गया। अनुमानों में दिये गये हिसाब सम्बन्धी इस परिवर्तन ने सींगे सेनाओं को बहुत सीमा तक आत्म-निर्भर बना दिया और सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अपनी अपनी सेनाओं के व्यय के ऊपर ज्यादा सक्षम और निष्कट का नियन्त्रण रखना सम्भव कर दिया।

१९४८-४९ में शुरू की गयी व्यवस्था के अनुसार विमानों की खरीद सम्बन्धी व्यय पूँजी-व्यय माना जाने लगा। लेकिन, विमानों के बारे में खतरे की गुंजायश ज्यादा होती है और उनके सम्बन्ध में यह आशा नहीं की जा सकती कि वे अपने जीवन की ओरत अनुमानित अवधि तक-परिसम्पत्ति बने रहेंगे। इसलिए यह अनुभव किया गया कि विमानों की खरीद पर होने वाले खर्च के बारे में यह ज्यादा उपयुक्त होगा कि उमे राजस्व पर भारित किया जाये। यह परिवर्तन १९५१-५२ के अनुमानों से पानू किया गया। १ अप्रैल, १९५१ से केवल बड़ी निर्माण परियोजनाएँ, जमीन अर्जित करना, कारखानों आदि के लिए सयन्त्र और मशीनें खरीदना, नौसेना के लिए पूँजीगत जहाज खरीदना और कारखानों के लिए अत्यावश्यक माल के भण्डार पूँजी-व्यय के अन्तर्गत माने जा रहे हैं। बाद में, ऐसे लोक-क्षेत्र के उपकरणों की अदा-पूँजी पर किया गया निवेश भी पूँजी आय-व्ययक में रखा गया, जो रक्षा मन्त्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण में है।

इन सभी बड़ी-छोटी बचनबद्धताओं के बावजूद, जो काफी वित्तीय खर्च की माँग करती थी, रक्षा-व्यय आजादी के बाद लगभग १५ वर्ष तक लगभग ३०० करोड़ रुपये वार्षिक से

ज्यादा न हो पाया। इसका कारण यह था कि इस अवधि में देश की रक्षा सेनाओं को बढ़ाकर संगठित करने के ऊपर बहुत कम जोर दिया गया। विदेशी भत्ता से आगामी प्राप्त करने के बाद के वर्षों में पूरा-पूरा ध्यान लोगों के आर्थिक मुद्धार को ओर ही केन्द्रित किया गया। १९५१ में भारत में तीन पञ्चवर्षीय आयोजनार्ये बनी, जो वस्तुतः विकास आयोजनार्ये थे। इनका उद्देश्य यह था कि लोगों का जीवन-स्तर तेजी से उठाया जाए और इसके लिए देश के साधनों का सशम विवेहन किया जाए, उत्पादन बढ़ाया जाए और समुदाय को सेवा में सभी के लिए रोज-गार के अवसर पैदा कर दिये जाएँ। इस बात को ओर ध्यान देना होगा कि इनमें से किसी आयोजना में रक्षा सम्बन्धी खण्ड नहीं था। भारत ने तटस्थता की नीति अपनायी और सच्चाई से सभी राष्ट्रों के साथ शान्ति और सह-अस्तित्व बनाये रखने की नीति की घोषणा की और उसने सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने के लिए सक्रिय कार्य किया। जब भारत की नीति के ऐसे सुन्दर उद्देश्य थे तो भारत को यह आशा थी कि दूसरे राष्ट्र भी उसे अपने आर्थिक विकास का कार्यक्रम आगे बढ़ाने के लिए मत्स्य छोड़ देंगे। तदनुसार देश के साधनों को पूरी तरह से विकास-आयोजनाओं को कार्यान्वित करने में हो लगाया गया।

१ जनवरी, १९४६ को मुडबन्दी के बाद भी पाकिस्तान ने कश्मीर में मुडबन्दी रेखा के साथ-साथ सत्ता बनाये रखा। पूर्वो सीमायें भी सपाटार उपद्रव-ग्रस्त रही। पाकिस्तान सैन्य-सन्धियों में शामिल हो गया और १९५४ से भारी सैन्य-सहायता प्राप्त करने लगा। पाकिस्तान के द्वारा सैनिक नैपारियाँ करने और अधिकाधिक आग्रामक रख अपनाने पर भी भारत हथियारों की स्पर्श में शामिल न हुआ। वस्तुतः सैन्य व्यय कम करने की वास्तविक इच्छा के साथ एकाधिक बार सशस्त्र सेनाओं की संख्या भी कम की गयी। देश शान्ति और आर्थिक विकास का इतना इच्छुक था कि यह मान लिया गया था कि पाकिस्तान भारत के ऊपर सैन्य-नु माहस न करेगा। फिर भी किसी समय सशस्त्र सेनाओं की कुल संख्या प्रकट न की गयी। मेला की समस्या में की गयी कुछ घटा बड़ी यदि जनता को बता दी जाती, जो उसके पूरे आत्मपरी को नहीं समझती, तो जनता बढ़ा-बढ़ा कर अर्थ निकालती, जो राष्ट्र के वृहत्तर हितों के खिलाफ हो जाते। भारत जैसे देश में, जहाँ केवल रक्षित शास्त्र ही है, सशस्त्र मेलाओं की शक्ति मुड-शमता का सोचा संकेत दे देती। समुजन देशों के पास तो नये-नये और बिना मनुष्य के चलाए चलने वाले अस्त्र होते हैं, जिनमें वे सदा सुपार करते रहते हैं, इसलिए अगर उनसे सशस्त्र स्थितियों की कुल संख्या के ध्यारे प्रकाशित भी कर दिये जायें, तो उससे सैन्य-शमता का असली रूप विदित न हो सकेगा।

वस्तुतः शान्ति और आर्थिक विकास की उय इच्छा के साथ-साथ देश के कुछ लोगों में यह प्रवृत्ति भी आ गयी कि वे रक्षा-व्यय को अनुप्रादी समझने लगे और ऐसे तरीकों की माँग करने लगे, जिससे अनिवार्य सीमा तक न्यूनतम कर दी गयी सेना का भी उपयोग सम्पूर्ण-निर्माण के शानों में किया जा सके। जब १९६० में यह स्पष्ट हो गया कि चीन का अनिवार्य भारत के साथ शान्ति-पूर्ण सह-अस्तित्व बनाये रखने का नहीं है, तब भी यह समझ जाता था कि सीमा-समस्या का कुछ शान्तिपूर्ण हल निकल सकेगा।

अगस्त, १९६२ में चीन द्वारा आग्राम दिये गये हमने से स्पष्ट हो गया कि देश की

प्रादेशिक अखण्डता को यथावत् मान लिया जाय, ऐसा नहीं है, और शान्ति केवल एक तरफ से स्थापित नहीं हो सकती। राष्ट्र में एक नयी रक्षा-चेतना ने जन्म लिया और किसी बाह्य-आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए पर्याप्त सशस्त्र मेनार्थें सन्धारित करने की जरूरत का अनुभव किया गया।

पर सशस्त्र सैन्य सेना आसमान से नहीं टपक पड़ती। सेनाओं की कार्यक्षमता पर्याप्त साधनों की व्यवस्था और निरन्तर प्रशिक्षण से ही प्राप्त की जा सकती है। सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों के लिए भी तकनीकी ज्ञान और अनुभव जरूरी है, जैसाकि इंजीनियरों और वायु-विज्ञान जैने किसी अन्य तकनीकी व्यवसाय के लिए जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि जब युद्ध नहीं चलता, तब सैनिक अपना समय आलस्य में गंवा देते हैं। वस्तुतः एक अधिकारी या एक सैनिक अपने कार्यकाल में किसी भी नयी घटना का सामना करने का प्रशिक्षण सतत प्राप्त करता रहता है। शिक्षण-पाठ्यक्रम के अलावा, सेनाओं की युद्ध-सज्जता की जाँच करने के लिए समय समय पर विभिन्न अभ्यास चलते रहते हैं।

रक्षा-क्षमता हुकों और महीनों में नहीं खड़ी की जा सकती है। साथ ही वास्तविक रक्षा-सामर्थ्य अन्तर्गत देश में विद्यमान औद्योगिक और आर्थिक आधार पर निर्भर होती है।

जब राष्ट्र आरम्भिक धक्के से उभरा और दीर्घकालीन खतरे का रूप ज्यादा स्पष्ट हो गया, तब सरकार रक्षा-सज्जता ज्यादा प्रमत्त रूप से सगठित करने के लिए अप्रसर हुई, जो पहले घटनाचक्र के दबाव के कारण किये गये तदर्थ निर्णयों से परे की बात थी।

हमारी सशस्त्र सेनाओं को पुनः सज्जित तथा आधुनिकीकृत करने का काम बहुत बड़ा है। देश के सामने आये खतरे के प्रकाश में अपनी रक्षा-सामर्थ्य के क्रमवद्ध विकास के लिए १९६४ में एक पञ्चवर्षीय योजना बनायी गयी, जिसमें देश में उपलब्ध सत्ताधनों का स्थान रखा गया और मित्र-देशों से प्राप्तव्य सहायता का भी। शीघ्र तौर से इन आयोजना पर ५० अरब रुपये खर्च होंगे और इसमें यह किया जायेगा—

- (क) ८,२५,००० सैनिकों वाली एक सुसज्जित सेना को खड़ा करना और उसका सन्धारण करना ;
- (ख) ४५ स्क्वेड्रनों वाली वायुसेना का सन्धारण, जिसमें पुराने विमानों जैसे बैंगालर, ग्लोब, और मिस्टियर के स्थान पर ज्यादा आधुनिक विमान मंगाये जायें और उनको पुनः सज्जित करने का वायु-रक्षा-रदार और संचार-सुविधाओं के गुप्तार के कार्यक्रम भी शामिल रहें ,
- (ग) नौसेना के पुराने पड़ गये पोतों को बदलने का चरण बद्ध कार्यक्रम ,
- (घ) सीमा-क्षेत्रों में सड़क-संचार-व्यवस्था में गुप्तार ,
- (ङ) रक्षा-उत्पादन-आधार को सुदृढ़ करना ताकि वह आगे चलकर हमारी सशस्त्र सेनाओं की हथियार-सामानाजिक सम्पत्ती जम्में पूरी कर सके ; और

(च) उपबन्धन और प्राप्ति करना, भांडारण, प्रशिक्षण आदि के क्षेत्रों में संगठन-व्यवस्था में सुधार करना और रक्षा के लिए आवश्यक निधियों का जमादा से जमादा वृत्तपूर्ण उपयोग ।

भारती जहरतों की आयोजना बना सेना निश्चय ही पहला कदम है, पर सबसे बड़ा काम इनमें सोचे गये हथियारों, उपस्करों, पोतों, विमानों आदि का उत्पादन या प्राप्त कर सेना है । इनमें से कुछ चीजें देश में विनियुक्त या काफी सख्या में पैदा नहीं होती, उनको मित्र-देशों से प्राप्त करना ही होगा । यहाँ पर भी, पिछले अध्यायों में बताये गये अनुसार, सैन्य-सामग्री खुद बाजार में पैसा देकर नहीं खरीदी जा सकती । इस मामले में सरकारें राजनीतिक बातों का ध्यान रखती हैं और सैन्य-सामग्री सरकार-से-सरकार आकार पर ही प्राप्त हो सकती है । रक्षा-आयोजना को कार्यान्वित करने के लिए ही रक्षा-मन्त्री ने १९६४ में सं० रा० सं० अमेरिका, सोवियत रूस और ब्रिटेन की यात्रा की ।

सेना में उच्च-गुणवत्ता वाले पहाड़ी क्षेत्रों में सक्रियता की अपेक्षा की जायेगी, इसलिए अनेक द्वितीय पहाड़ी द्वितीय होने और उनके पास पहाड़ी क्षेत्रों में सक्रियता के अनुकूल उपस्कार और गाड़ियाँ होंगी । विभिन्न प्रकार के घन्नों, गाड़ियों और अन्य उपस्करों की जहरतों की योजना बना ली गयी है । ये देश के कारखानों के उत्पादन के साथ जोड़ दो जाय, ऐसा प्रस्ताव है । आर्मेन्स कारखाने पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं और नये कारखाने स्थापित किये जा रहे हैं ।

विद्युत दशकों में प्राप्त किये गये विमानों में से कुछ को जगह पर एच० एफ० २४ विमान (जिसे अब 'महत्' कहते हैं) रणे जायेंगे, जो राज्य-स्वामित्व वाले हिन्दुस्तान एयर-क्राफ्ट (अब हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स) लिमिटेड द्वारा मैच-१ सामर्थ्य के साथ पूर्णतः विकसित किये जा चुके हैं । तामी जहरतें पूरी करने के लिए रूस से मिग-२१ के कुछ स्वदेशीय प्राप्त किये गये हैं । सोवियत रूस की सहायता से देश में इस विमान का उत्पादन भी सुस्थापित किया जा रहा है ।

इस देश में अभी मुद्रागत नहीं बनते हैं । विदेशों से खरीद करके ही पैदा बढ़ाया जा सकता है । इस क्षेत्र में भी उपनयता की मात्रा सीमित है । इस क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार राज्य स्वामित्व वाली मम्भाई गोदी, बम्बई, में सीनहर-बर्ग के खोन क्रिगेट बनाने के लिए आर्थिक संपादों की व्यवस्था के लिए राखी हो गयी है । बड़े को बढ़ाने के लिए और कदम भी उठाये जा रहे हैं । इस समय रक्षा-आयोजना का एक महत्वपूर्ण पक्ष है । केवल सैनिक भरती कर सेना, कारखानों में हथियारों का उत्पादन कर सेना और उनकी दिनों तक पहुँचा देना ही पर्याप्त नहीं है । इतना ही महत्वपूर्ण यह आवश्यक करना भी है कि राज्य, पोतावाक्य और अन्य पूर्णता मैनिशों के पास ठीक समय पर और ठीक जगह पर पहुँच जायें । भारत की उत्तरी सीमा जलवायु की दृष्टि से बड़ी ही विचल-अयोग्य है । जगह काफी ऊँची है और खबार-व्यवस्था नगण्य है । फिर भी १.९० में सीमा-सङ्घ-विभाग-बोर्ड की स्थापना हो जाने पर सीमान्त सङ्घ सङ्घ बनाने के लिए वेको में कदम उठाये जा रहे हैं, ताकि सैनिकों को अच्छी तरह जामरी प्राप्त होती रहे । इनमें से अधिकांश सामानान विमानों में भेजा जा रहा है,

लेकिन इस परिवर्तन-रीति की कुछ सीमायें हैं। अनुमान लगाया गया है कि १ टन सामान को विमान से गिराने के लिए लगभग ५००० रुपये के तो पैराशूट उपकरण की ही जरूरत पड़ती है। अग्रवर्ती स्थानों पर एक सैनिक रखने पर, आने वाले खर्च का अन्दाजा लगाया जा सकता है। इसलिए हमारे सीमा-प्रदेश में सड़कों का बनाया जाना बहुत जरूरी है, और इसके लिए एक चरण-बद्ध कार्यक्रम चल रहा है। विमान से माल गिराना सड़क संचार सुलने की धीरे-धीरे कम होता जा रहा है।

## रक्षा और विकास

१९६३-६४ से कुल रक्षा व्यय हर साल ८०० करोड़ रुपये से ज्यादा होता है। लेकिन वह स्पष्ट कर दिया गया है कि रक्षा सम्बन्धी निर्माण कार्य राष्ट्र के आर्थिक निर्माण की गति की दृष्टि पहुँचाकर नहीं किया जाये। आर्थिक विकास के क्षेत्र में देश के सर्वोच्च आयोजना-निर्वाह राष्ट्रीय-विकास-परिषद् ने ५ नवम्बर, १९६२ को हुई अपनी बैठक में घोषणा की कि देश की विकास-आयोजनायें राष्ट्रीय रक्षा का ही अंग हैं और चीनो आक्रमण के बाद, इन आयोजनाओं की और तेजी से कार्यान्वित करना बहुत आवश्यक हो गया है। आपात काल में सुरक्षा इन्हीं आयोजनाओं की सफलता पर निर्भर है।

यह पूरी तरह समझ लिया गया है कि रक्षा और आर्थिक विकास साथ-साथ चलना चाहिये। बिना आर्थिक आधार के बिना रक्षा-समर्थता अपूर्ण रहेगी।

रक्षा-व्यय के स्तर का निर्णय करने समय यह भी ध्यान में रखना होगा कि भारत एक सशस्त्र राज्य है और रक्षा केन्द्रीय सरकार की ही जिम्मेवारी है। वस्तुनिष्ठ रहने के लिए हमें राष्ट्रीय आय के प्रतिशतक के रूप में निर्धारित करना होगा। इस आधार पर १९६३-६४ में भारत का प्रतिशतक ४.७ आता है, जो सं. रा. अमेरिका में १०.६, ब्रिटेन में ८.३, फ्रांस में ६.१, कनाडा में ४.७, पाकिस्तान में ४.५ (प्राप्त हुई भारी सैन्य सहायता को छोड़कर), आस्ट्रेलिया में ४.२, सं. अ. गणराज्य में ८.२, यूगोस्लाविया में ७.५ और स्वीडन में ५.३ है। इनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत अपने आर्थिक विकास की दृष्टि पहुँचाकर अनुपात में ज्यादा ससाधन रक्षा पर नहीं खर्च कर रहा है।

पाकिस्तान ने कच्छ के रत पर अग्रेज, १९६५ में हमला किया और सितम्बर, १९६५ में जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में। इससे निरन्तर तैयार रहने की जरूरत स्पष्ट हो गयी। सितम्बर, १९६५ के कुछ दिनों में भी स्पष्ट हो गया कि वास्तविक अग्राज में विदेशों से प्रत्यासित महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त न हो सकेगी। नवम्बर, १९६५ में रक्षा-वृत्ति-विभाग की स्थापना की गयी, ताकि रक्षा की सामग्री के मामले में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से कदम उठाये जा सकें।

नवम्बर, १९६५ के दौरान पाकिस्तान से लड़ाई के समय चीन ने जो अन्तिमेटम दिया था, उसमें भी रक्षा के लिए आने वाली सहायकों को पूरी तरह से काम में लाने की भारी जरूरत और आर्थिक-विकास-आयोजना से पूरा-पूरा पौषण प्राप्त करने की भारी जरूरत और भी स्पष्ट हो गयी। सितम्बर, १९६५ में हुई अपनी बैठक में राष्ट्रीय-विकास-परिषद् ने रक्षा-



आयोजना की समीक्षा करना अधिकृत कर दिया, ताकि आपाती परिस्थिति का सामना करने के लिए उसमें समन्वय कर लिये जायें। रक्षा-मन्त्रालय में नवम्बर, १९६५ में एक आयोजना कक्ष विकास-आयोजन के सभी बृहत्तर पक्षों का निपटान करने के लिए बनाया गया, क्योंकि ये चीजें रक्षा के प्रयास के ऊपर बहुत प्रभाव डालती हैं। इस तरह आयोजना-आयोग और अन्य मन्त्रालयों के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाये रखने की व्यवस्था कर दी गयी है, ताकि यह आवश्यक किया जा सके कि विकास आयोजना के रक्षा-प्रयास पर प्रभाव डालने वाले घटकों को समुचित पूर्वाज्ञा दी जा सके।

### रक्षा एक राष्ट्रीय उत्तरदायित्व

सशस्त्र सेनाओं को कार्यक्षम रूप में प्रशिक्षित करने के लिए और उनको यथासम्भव सर्वोत्तम षड्बाह्य में सज्जित करने के लिए यद्यपि सभी कुछ किया जा रहा है, पर यह चीज अब ज्यादा अच्छी तरह से समझी जाने लगी है कि युद्ध केवल युद्धक्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका असर हर शहर, गाँव और घर पर पड़ता है। इसलिए किसी देश की आबादी की रक्षा के लिए पूरे राष्ट्र को संगठित होना पड़ता है। असेनिक जनता में सुव्यवस्था, अनुशासन और मनोबल बनाये रखना भी युद्धरत सशस्त्र सेनाओं की कार्यक्षमता के लिए बड़े ही महत्व की बात है। इस तरह रक्षा केवल सशस्त्र सेनाओं की ही चीज नहीं है। देश की रक्षा के लिए हर पुरुष, स्त्री और बच्चा भी एक सैनिक होता है। किसी एकलव्य राष्ट्र की अरम्य आकांक्षा को कोई पराजित नहीं कर सकता।

## परिशिष्ट एक

### रक्षा-उत्पादन और रक्षा-पूर्ति-विभागों समेत रक्षा-मन्त्रालय के अन्तर्गत आने वाले विषय

#### रक्षा-मन्त्रालय

- १—रक्षा-मन्त्रालय और उसका प्रत्येक अंग, जिसमें रक्षा-सकृद्वता और ऐसे सभी कार्य शामिल हैं, जो युद्ध के समय उभे चलाने और उसकी समाप्ति पर प्रभावी सैन्य-वित्तपोषण के लिए लाभकर होंगे।
- २—संव की सहाय्य सेनाएँ, नामतः पलसेना, नौसेना और वायुसेना।
- ३—पलसेना, नौसेना और वायुसेना की रक्षितियाँ।
- ४—प्रादेशिक सेना और सहायक वायुसेना।
- ५—राष्ट्रीय सेना-छात्र-दल।
- ६—पलसेना, नौसेना, वायुसेना और आर्डनेंस कारखानों के बारे में निर्माण-कार्य।
- ७—अस्त्र, पशुचिकित्सा और फार्म-संगठन।
- ८—कैंटीन मण्डार-विभाग (भारत)।
- ९—रक्षा-अनुमानों से प्रदत्त असेनिक सेवाएँ।
- १०—जलवर्षना-मर्वक्षण और नौबहन-जहाजों को तैयार करना।
- ११—छावणियों का निर्माण, छावनी-क्षेत्रों का परिसीमन / अलग करना, ऐसे क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन, ऐसे क्षेत्रों में छावनी-बोर्ड और अन्य प्राधिकारियों का गठन और उनकी शक्तियाँ और इन क्षेत्रों में रहने के आशय का विनियमन (किराये के नियन्त्रण समेत)।
- १२—रक्षा-प्रायोजनों से अमीन और सम्पत्ति की अवाप्ति, अधिग्रहण, अभिरक्षा और त्याग। अनधिकृत धारकों की रक्षा-अमीन और सम्पत्ति से निष्कासन।
- १३—नूतनपूर्व सैनिकों (पेंशनधारियों समेत) सम्बन्धी मामले।

#### रक्षा-उत्पादन-विभाग

- १—आर्डनेंस कारखानों के महानिदेशालय।
- २—निरोधन-महानिदेशालय।
- ३—प्रायोजना और समन्वय-निदेशालय।
- ४—रक्षा-अनुसन्धान और विकास-संगठन।
- ५—हिन्दुस्तान एयरोनौटिक्स लिमिटेड।
- ६—भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड।

- ७—मम्गांव डौक लिमिटेड, बम्बई ।  
 ८—गाडन रोच वर्कशॉप लिमिटेड, कलकत्ता ।  
 ९—प्रागाहू स लिमिटेड, सिकन्दराबाद ।  
 १०—भारत अयर्मूवर्स लिमिटेड, बगदोर ।

### रक्षा-पूति-विभाग

- १—रक्षा-प्रयोजनों के लिए आयात की ज़रूरतों के स्थान पर निर्माण की आयोजना, खासकर इलेक्ट्रॉनिकी यन्त्र, गाड़ियाँ और पौनर्निर्माण के क्षेत्रों में और इन विषयों पर, ध्यौरेवार योजनाएँ तैयार करना ।  
 २—अनुसन्धान और विकास के कार्य के लिए तथा विनिर्माण के लिए देश की औद्योगिक क्षमता के उपयोग के जरिए इन योजनाओं की कार्यान्विति ।  
 ३—देश के भीतर होने वाले विज्ञान और शिप-विज्ञान के अनुसन्धान और विकास के कार्य का रक्षा-अनुसन्धान और विकास-मण्डल के साथ समन्वय ।  
 ४—इलेक्ट्रॉनिकी का विकास और इसके विभिन्न उपयोगों के बीच समन्वय ।

## परिशिष्ट-दो

### रक्षा-मन्त्रालय के बारे में चालू केन्द्रीय अधिनियमों की सूची

१. विदेशी भारतीय अधिनियम, १८७४ (१८७४ का चार), इसमें विदेशी राज्यों में सेवा करने के लिए भारत में भरती पर नियन्त्रण की व्यवस्था है।
२. नगरपालिका कराधान अधिनियम, १८८१ (१८८१ का ११), इसमें सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों पर नगरपालिका कर लगाने से विमुक्ति की व्यवस्था है।
३. भारतीय रक्षितबल अधिनियम १८८८ (१८८८ का ४), इसमें भारतीय रक्षितबलों के शासन, अनुशासन और विनियमन की व्यवस्था है।
४. भारतीय पय-कर (सेना और वायुसेना) अधिनियम १९०१ (१९०१ का २), इसमें पयमेन्ता और वायुसेना के व्यक्तियों और सम्पत्तियों पर पय-कर से विमुक्ति की व्यवस्था है।
५. भारतीय रक्षा निर्माण कार्य अधिनियम १९०३ (१९०३ का ७), इसमें रक्षा के निर्माण-कार्यों के पास की जमीन के प्रयोग और उपयोग पर बन्धन लगाने की व्यवस्था है, ताकि वह जमीन मकान और दूसरी बाधाएँ खड़ी करने से मुक्त रखी जा सके और इस प्रकार बन्धन लगाने के कारण देय प्रतिफल की राशि तय करने की व्यवस्था है।
६. छावनी (निवासीय आवास) अधिनियम १९२३ (१९२३ का ९), इसमें छावनियों में सैन्य-अधिकारियों के निवासी आवास के उपबन्ध के लिए व्यवस्था है।
७. छावनी अधिनियम १९२४ (१९२४ का २)।
८. भारतीय सैनिक (मुकदमा चलावना) अधिनियम १९२५ (१९२५ का ४), इसमें विशेष स्थितियों में काम कर रहे भारतीय सैनिकों पर चलाये गये दोशानी और माल मुकदमों के बारे में विशेष संरक्षण की व्यवस्था है।
९. परिपालन क्षेत्र पावर और आदित्तरी बन्धन अधिनियम १९३८ (१९३८ का ५), इसमें सैन्य परिपालन, पोन्ड पावर और आदित्तरी बन्धनों को चलाने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था है।
१०. आपराधिक विधि संग्रोहन अधिनियम १९३८ (१९३८ का २०), इसमें सशस्त्र सेनाओं में अपराधों की भरती और उनके अनुशासन के लिए बाधक कुछ कार्यों के लिए दण्ड की व्यवस्था करके आपराधिक विधि की अनुपूर्ति की गयी है।
११. सशस्त्र सेनाएँ (विशेष शक्तियाँ) अध्यादेश, १९४२ (१९४२ का ४१), यह सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों को सम्पत्ति के स्वयं रक्षण के लिए कुछ विशेष शक्तियाँ प्रदान करता है।

१२. सेन्य नसिंग सेवायें अध्यादेश १९४३ ( १९४३ का ३० ), सेन्य नसिंग सेवाओं के सही करने और अनुशासन के लिए ।
१३. बेंटीन भण्डार ( स्थानीय करो से विमुक्ति ) अध्यादेश १९४६ ( १९४६ का ५ ) ।
१४. सशस्त्र सेनायें ( आपात कर्तव्य ) अधिनियम, १९४७ ( १९४७ का १५ ), यह आपात-काल में महत्त्वपूर्ण सेवाओं के बारे में सशस्त्र सेनाओं पर कुछ कर्तव्य आरोपित करने में समय बनाता है ।
१५. राष्ट्रीय सेना ध्वज दत्त अधिनियम, १९४८ ( १९४८ का ३ ) ।
१६. प्रादेशिक सेना अधिनियम, १९४८ ( १९४८ का ५६ ) ।
१७. समुद्रमुख आटिलरी अभ्यास अधिनियम, १९४६ ( १९४६ का ३ ), समुद्रमुख आटिलरी अभ्यास चलाने के लिए सुविधायें प्रदान करता है ।
१८. सेना और वायुसेना ( निजी सम्पत्ति निपटान ) अधिनियम, १९५० ( १९५० का ४० ), इसमें सेना अधिनियम, १९५० या वायुसेना अधिनियम, १९५० के अधीन आने वाले ऐसे व्यक्तियों की निजी सम्पत्ति के निपटान की व्यवस्था है, जो मर जाते हैं, भगोड़े बन जाते हैं और यह सुनिश्चित हो जाता है कि उनका दिमाग सही नहीं है, या सैन्य सेवा करते हुए जिन्हें सरकारी तौर पर छोड़ा हुआ बताया जाता है ।
१९. वायुसेना अधिनियम, १९५० ( १९५० का ४५ ) ।
२०. सेना अधिनियम, १९५० ( १९५० का ४६ ) ।
२१. रक्षित और सहायक वायुसेना अधिनियम, १९५२ ( १९५२ का ६२ ) ।
२२. कमांडर्स-इन-चीफ ( पदनाम में परिवर्तन ) अधिनियम, १९५५ ( १९५५ का १६ ) ।
२३. सौक सहायक सेना अधिनियम, १९५६ ( १९५६ का ५३ ), इसमें भारत के नागरिकों को सैन्य-प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है ।
२४. छावनियाँ ( किराया-नियन्त्रण-विधियों का विस्तार ) अधिनियम, १९५७ ( १९५७ का ४६ ), इसमें मकान-आवास के किराया-नियन्त्रण और विनियमन सम्बन्धी विधियों के छावनियों तक विस्तार की व्यवस्था की गयी है ।
२५. नौसेना अधिनियम, १९५७ ( १९५७ का ६२ ) ।
२६. रेलवे ( सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों का नियोजन ) अधिनियम, १९६५ ( १९६५ का ४० ), इसमें सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों के रेलवे कार्यकरण और प्रबन्ध में नियोजित किये जाने के सम्बन्ध में कुछ उपबन्ध किये गये हैं ।

## परिसिस्ट-सीन

### तीनों सेनाओं के सापेक्ष ओहदे

यल सेना	नौसेना अधिकारी	वायुसेना
फोल्ड मार्शल	एडमिरल आफ दि फ्लोट	मार्शल आफ दि एयर फोर्स
जनरल	एडमिरल	एयर चीफ मार्शल
लेफ्टी० जनरल	वाइस एडमिरल	एयर मार्शल
मेजर जनरल	रोयर एडमिरल	एयर वाइस मार्शल
ब्रिगेडियर	कप्तान	एयर कप्तान
कर्नल	कैप्टन	ग्रुप कैप्टन
लेफ्टी० कर्नल	कमांडर	ब्रिग कमांडर
मेजर	लेफ्टी० कमांडर	स्ववेइज़ लीडर
कैप्टन	लेफ्टीनेंट	फ्लाइट लेफ्टीनेंट
लेफ्टीनेंट	सब-लेफ्टीनेंट	फ्लाईंग अफसर
सेक्रेट लेफ्टीनेंट	एक्टिंग सब लेफ्टीनेंट	पाइलट अफसर
(समकक्ष पद नहीं)	मिडशिपमैन	(समकक्ष पद नहीं)

### कनिष्ठ कमिशन-प्राप्त अधिकारी

रिजालदार मेजर सूबेदार मेजर रिजालदार रिजालदार, सी० आई० आई० अइब-मगु-बिरित्सा-नोर सूबेदार नाइब सूबेदार नाइब रिजालदार	समकक्ष पद नहीं	मास्टर वारंट अफसर मास्टर सिगनेयर मास्टर इंजीनियर
चारट अधिकारी		

चारट अफसर ए० पी० एस० सी० आई० आई० चारट अफसर, ए० पी० एस० सी० आई० डबल आई०	समकक्ष पद नहीं चीफ पेटी अफसर	चारट अफसर फ्लाइट साजेंट
---	---------------------------------	----------------------------

## गैर कमिशन-प्राप्त अधिकारो

<p>हवलदार/दफादार</p> <p>(क) रेजीमेंट दफादार मेजर</p> <p>रेजीमेंट हवलदार मेजर</p> <p>रेजीमेंट मास्टर दफादार</p> <p>रेजीमेंट क्वार्टर मास्टर हवलदार</p> <p>बटालियन हवलदार मेजर</p> <p>बटालियन क्वार्टर मास्टर हवलदार</p>	<p>}</p> <p>पेटी अपसर</p>	
<p>(ख) स्ववेड्डन दफादार मेजर</p> <p>स्ववेड्डन क्वार्टर मास्टर दफादार</p> <p>बैटरी हवलदार मेजर</p> <p>बैटरी क्वार्टर मास्टर हवलदार</p> <p>कम्पनी हवलदार मेजर</p> <p>कम्पनी क्वार्टर मास्टर हवलदार</p>	<p>}</p>	
<p>(ग) दफादार</p> <p>फारिपर दफादार मेजर</p> <p>फारिपर दफादार</p> <p>हवलदार</p> <p>ट्रम्पेट मेजर</p> <p>ड्रम मेजर</p> <p>बिगुल मेजर</p> <p>पाइप मेजर</p> <p>दफादार ड्रेसर</p>	<p>}</p>	<p>साजेंट</p>
<p>सेंसदफादार/नायक</p> <p>सेंस हवलदार</p> <p>सेंस दफादार</p> <p>नायक</p> <p>फारिपर सेंस दफादार</p>	<p>}</p> <p>सीडिंग सीमेन और समकक्ष ओहदे (पर सेना ओहदों से वनिष्ठ)</p>	<p>बारडोन</p>

## परिशिष्ट-खोन

जवान

एक्टिंग लास दफादार

लास नायक

राइडर

गनर

सैपर

सिगनलमैन

सिपाही या राइफलमैन

ट्रम्पेटर

बिगुलर

पाइपर

ड्रमर

बैड्समैन

ट्रैसर/राइडर, अस्व पशुविक्रित्ता

कोर

क्रापट्समैन

एकुल सीमेन,

आर्डिनरी

सीमेन

और समकक्ष

ओहदे

लीडिंग एयर

क्रापट्समैन

एयर क्रापट्समैन-

प्रथम वर्ग

एयर क्रापट्समैन-

द्वितीय वर्ग



## परिशिष्ट-चार

### तीनो सेनाओं में प्रयुक्त शब्दावली

#### सेना शब्दावली

##### प्लाटून और कम्पनी

एक प्लाटून में एक मुख्यालय और तीन सेवक होने हैं और इसमें लगभग ३५ सैनिक होते हैं। इसकी कमान एक कनिष्ठ कमीशन-प्राप्त अधिकारी के हाथ में होती है। कम्पनी की कमान एक मेजर के हाथ में होती है।

##### बटालियन

पैदल सेना की एक बटालियन में लगभग ६०० सैनिक, कनिष्ठ कमीशन-प्राप्त अधिकारी और कमीशन-प्राप्त अधिकारी होते हैं। यह एक स्वतंत्र पूर्ण इकाई है और इसकी कमान एक लेफ्टिनेंट कर्नल के हाथ में होती है।

##### पैदल रेजीमेंट

एक पैदल रेजीमेंट में कई पैदल बटालियनें होती हैं, जिनको क्षेत्र-विशेष में भरती किया जाता है और बटालियनों की संख्या पाँच से पन्द्रह तक होती है, जिनको एक साथ समूहित करना जरूरी नहीं है। एक रेजीमेंट का एक रेजीमेंट-केन्द्र होता है, जिसकी कमान एक कर्नल के हाथ में होती है और जहाँ पर रैगस्टों की थोड़ा के रूप में तैनाती से पहले प्रशिक्षित किया जाता है।

##### ब्रिगेड

एक पैदल ब्रिगेड-समूह में एक मुख्यालय, तीन पैदल बटालियनें और कुछ पोषक और प्रशासनिक तत्व या छोटे सलमन या सम्बद्ध होते हैं। एक ब्रिगेड में लगभग ३००० जवान होते हैं और इसकी कमान एक ब्रिगेडियर के हाथ में होती है।

##### पैदल डिवीजन

एक पैदल डिवीजन युद्ध में लड़ने के लिए एक बुनियादी विरचना होती है। यह सैन्य-स्रोतों में वह सबसे निचली विरचना है, जिसमें एक ही कमांडर के अधीन सभी शाखाओं का बन एक समग्र इकाई के रूप में युद्ध के लिए एकीकृत, संचालित, प्रशिक्षित और समूहित किया जाता है। इसमें तीन पैदल ब्रिगेडें और सभी शाखाओं और सेवाओं के सन्तुलित तत्व रहते हैं। यह आनम्य होता है और इसमें विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का सामना करने के लिए अतिरिक्त विरचनाएँ और यूनिटें हो सकती हैं।

## कोर और आर्मी

दो या ज्यादा डिवीजनो से एक कोर बनती है और दो या ज्यादा कोरो से एक आर्मी कोर और आर्मी दोनों की हो कमान लेफ्टी० जनरलो के हाथ में होती है ।

## आर्मंड रेजीमेंट

आर्मंड रेजीमेंट ४५ कर्वाचित गाड़ियो (टैंकों) से सज्जित होती है । ये रेजीमेंटें तीन तरह की होती है, नामन आर्मंड रेजीमेंट, टोड रेजीमेंट और डिवीजन रेजीमेंट । आर्मंड रेजीमेंट का लक्षण उसकी चत्तनशीलता और फायर शक्ति है ।

## आर्टिलरी

आर्टिलरी का काम युद्ध क्षेत्र में फायर की अधिकप्रभुता इस तरह स्थापित करना और सभी शाखाओ को पृष्ट करना है, कि शत्रु न तो हमारी सन्निया में बाधा डाल सके और न अपनी ही सन्निया को प्रभावी रूप में बिखरित कर सके । आर्टिलरी यूनिटों का वर्गीकरण स्पूल रूप में क्षेत्र शाखा, वायुरक्षा और ठटोय आर्टिलरी में किया जाता है ।

## क्षेत्र शाखा आर्टिलरी

क्षेत्र रेजीमेंटो (पहाडो रेजीमेंटो समेत) का काम अन्य शाखाओ को निवृत्त से आर्टिलरी समर्थन प्रदान करना होता है । वह सामान्यतः सरेन्द्रित रूप से किया जाता है और अप्रत्यक्ष रूप से फायर प्रदान करता है । मध्याकार और इहदाकार रेजीमेंटो को विनाश और शत्रु की गहराई तक पीजित रखने में अनुपूति के लिए नियोजित किया जाता है, क्योंकि उनके गोले भारी और सुदूर पराम वाले होते हैं ।

## वायु रक्षा रेजीमेंट

वायुरक्षा रेजीमेंटो का उद्देश्य वायुसेना के साथ सहयोग देते हुए शत्रुतापूर्ण विमानों द्वारा हमारी अपनी तैयारी के साथ की गयी बाधा का निवारण करना और मर्म-क्षेत्रों की भारी रक्षा करने में मदद देना होता है । ये रेजीमेंटें दो तरह की होती हैं—हल्की, नीचे डडते हुए शत्रु-विमानों के लिए और भारी मध्यम सुदूरवा शस्त्रों के लिए ।

ये रक्षार सज्जित होती है और दिन-रात कभी भी काम में ली जा सकती है ।

## पशु परिवहन कम्पनियाँ

पहाड़ी क्षेत्रों में सभी प्रकार का बोझ लादने के लिए पशुओ (खच्चर और पाऊ) का उपयोग किया जाता है, जहाँ पर सड़कें नहीं होओ और यांत्रिक परिवहन काम में नहीं आ सकता ।

## ठिकाना निहपक रेजीमेंट

इस रेजीमेंट का इन्फेन्ट्री शत्रु की तोहो के स्थान का पता लगाने के लिए किया जाता

है, ताकि उनको नष्ट करने में सुविधा हो सके। यह क्षेत्र आर्टिलरी के उपयोग के लिए सर्वेक्षण-दत्त सामग्री भी तैयार करती है।

### वायुप्रेक्षण चौकी उड़ान

वायुप्रेक्षण चौकी उड़ान का इस्तेमाल आर्टिलरी के फायर का वायु से प्रेक्षण करने और उसका नियन्त्रण करने के लिए किया जाता है। यह सेना और वायुसेना की मिलीजुली यूनिट होती है।

### तटीय आर्टिलरी

तटीय बैटरियों का काम समुद्र के जलपानों से तटीय जलक्षेत्रों की रक्षा करना होता है और अपने बन्दरगाह में उनको प्रवेश न करने देना होता है।

### सेना-सेवा-दल-बटालियन

एक सेना-सेवादल-बटालियन में एक मुख्यालय, दो यान्त्रिक परिवहन कम्पनियाँ और एक पूर्ति कम्पनी होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में काम करने वाली बटालियनों से दो पशु-परिवहन कम्पनियाँ सलग्न कर दी जाती हैं।

### होबितजर

होबितजर एक अल्प प्रवेग वाला अस्त्र है, अपने पूर्णाकार के अनुसार यह एक भाँपे गोले का फायर ऊँचे बल प्रक्षेप-मय के साथ करता है।

### मॉर्टर

मॉर्टर एक ऊँचा प्रक्षेप-मय वाला अस्त्र है, जिसकी फायर-दूर बढ़ी ऊँची होती है। यह ऊपर से फायर-समर्थन इलवाँ मोट के पीछे से दे सकता है और ऐसे टारगेटों को योजित रख सकता है, जो स्वतः संगत प्रक्षेप-मय वाले अस्त्रों से ओटवाली स्थिति में होते हैं।

### हलकी मशीनगन

हलकी मशीनगनों द्वारा थोड़े से ही जवानों को लगाकर परिशुद्ध रूप से मात्रा-निश्चय में फायर किया जा सकता है, सामान्यतः एक आदमी फायर करने के लिए और एक आदमी गोलाबारूद की पूर्ति के लिए लगाया जाता है। इनमें एक ही गोला भी फायर किया जा सकता है और स्वचलित रूप से भी।

### स्टेन मशीन कार्बाइन

यह एक बहुत हलका स्वचलित अस्त्र है, जो नजदीक के परास में काम करने के लिए प्रयुक्त होता है। यह एक गोला भी फायर कर सकता है और स्वचलित रूप से भी।

### गुरगो

चार्य गुरगो मुख्यतः दो तरह की होती है, टैंकमार और व्यक्ति-मार। टैंकमार गुरगो भारी छे भाँपे टैंकों को असमर्थ बना सकती है और इस तरह आगमक टैंकों का आगे बढ़ना

रोकती है। व्यक्ति-वार सुरंगों का उपयोग शत्रु की सेना की घुसपैठ और टैंकमार सुरंगों का हटाया जाना रोकने के लिए किया जाता है।

## प्रेनेड

प्रेनेडों के मुख्य दो प्रकार हैं, एक तो हथगोला जिसका जन्म वस्तुतः विस्फोटकों की खोज के साथ-साथ ही हथ और राइफल-चरित गोलों, जो राइफल में भगे अनुकूलकों के द्वारा छोड़े जाते हैं। घुमा हथगोले धूम्रावरण बना देने के लिए और रंगीन घुमा हथगोले सिगनल-कार्य के लिए छोड़े जाते हैं।

## चिकित्सकीय

द्विवीजन के चिकित्सकीय ढाँचे में एक चिकित्सा-घटातिपन और एक चल-क्षेत्र-अस्पताल होता है। पहली द्विवीजन को एक स्ट्रेचर-बाहक-कम्पनी रखने के लिए भी प्राधिकृत कर दिया जाता है। चिकित्सकीय यूनिटें रण और पापलों को जाती हैं, निष्क्रामित करती हैं और उनकी चिकित्सा करती हैं।

## हताहत-शोधन-केन्द्र

यह कौर की चिकित्सा-यूनिट है और अग्रवर्ती क्षेत्रों से निष्क्रामण-यंक्ति में यह पहली चिकित्सा-यूनिट है, जहाँ आहतों के परीक्षण, उपचार, नर्सिंग और भोजन देने की सुविधायें होती हैं।

## बिजली, यान्त्रिकी, इलेक्ट्रॉनिकी (वि० या० ६०) मरम्मत-पद्धति

एक द्विवीजन में वि० या० ६० घटातिपन का काम बिजली, यान्त्रिक, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उपकरणों की सहायता के लिए ठीक रखना होता है। इस काम के लिए मरम्मत पद्धति की तीन धेरियाँ होती हैं, नामतः (एक) हलकी मरम्मत—इसमें यूनिटों के व्यवसाय-विशेष वाले लोग होते हैं या इसमें वि० या० ६० के व्यक्ति भी लगा दिये जाते हैं।

(दो) क्षेत्र मरम्मत—क्षेत्र कारखाना कम्पनियों द्वारा की जाती है। वे गाड़ियों, रास्त्राओं, पन्नों, छोटे अन्तों और दूर-संचार उपकरणों को मरम्मत करते रहने के लिए जिम्मेवार हैं, इसमें पूरी समवेत मशीन को बदल देना भी शामिल है।

(तीन) आधार मरम्मत—यह आधार पर स्थित कारखानों द्वारा की जाती है, जो स्थिर होते हैं। वे उपकरणों और गाड़ियों का पूरा-पूरा ओवरहाल करती हैं और बड़े-बड़े समवेत-यन्त्रसमूह को भी बदल देती हैं।

## सामासिक पोदली राशन

इस राशन में सुपरग्रांथ विभिन्नता और पोषण-मूल्यों वाला भोजन होता है और इसको पकाना नहीं पड़ता तथा इसे पाँच-जनों के लिये एक पोदली में बाँधा जाता है। इस राशन का सभी उपभोग किया जाता है, जब सामान्य राशन की सुविधा नहीं हो पाती।

### सामान्य वर्गचारी रक्षिति

पूति डिग्री में पूति के मण्डार आगत के लिए रक्षिति के रूप में सन्धारित किये जाने हे ।

### क्वार्टर गारद

हर सेना इकाई में एक क्वार्टर गारद होनी है, जिसकी कमान एक हवलदार दफादार या कमी-कमी एक नायक के हाथ में होनी है । सस्था में यूनिट के आकार और गारद के कर्तव्यों के अनुसार अन्तर रहता है । क्वार्टर गारद एक यूनिट का समारोह-नेत्र होता है और उसमें एक गारद होता है, जो यूनिट के भीतर गारद-कर्तव्य के लिए जिम्मेदार है और सकट-मनेत के समय तत्काल कार्रवाई के लिए जिम्मेदार है । यूनिट का भ्रष्टा क्वार्टर-गारद के पास केन्द्र में रहता है । क्वार्टर-गारद किसी यूनिट के 'व्यक्तित्व' और कार्यक्षमता का प्रतिबिम्ब होता है और यूनिट इस बात का गर्व करती है कि कर्तव्यस्य जवान आपदादिक रूप में प्रसर हो और मुसलद रहे ।

### नौसेना की शब्दावली

#### पलोटिल्ला

छोटे युद्धपोतों का एक समूह, सामान्यतः आठ का, जैसे डेट्रोयट में पलोटिल्ला, सुरग-स्वच्छर पलोटिल्ला, एम० एल० पलोटिल्ला आदि ।

#### स्ववेडून

ज्यादा बड़े युद्धपोतों का एक समूह, सामान्यतः चार का, जैसे विमानवाहक स्ववेडून, बूजर स्ववेडून आदि ।

#### मिली-जुली सत्रियायें

अब इसे उभयचर युद्ध कहते हैं, जो वायु-उत्तर पर अवतारण-सक्रियता का सकेत देता है, जिसमें नौसेना पल-मेना बल की पूर्वनिर्धारित टिकाने पर ले आती है और उसे अवतारण-मौत या नौका से नौसेना और वायु द्वारा समर्थन देकर उतार देती है ।

#### ध्वजपोत

उस जगह का युद्धपोत जहाँ पर बेड़े के ध्वज ओहदे वाले ( अर्थात् रीयर एडमिरल अपर ) के एक वरिष्ठ अधिकारी का सक्रियमाण और प्रशासनिक मुख्यालय होता है ।

#### समुद्रतट स्थापना

यह मात्र समुद्रतट पर स्थित नौसेना-स्थापना का सकेत देता है । ये प्रशिक्षण-विद्यालय, बेड़े और नौसेना के बेस होते हैं । समुद्र-तटीय स्थापनाओं को पोतों की ही तरह वर्गीकृत दिया जाता और नाम दिया जाता है, जिसमें "भारतीय नौसेना पोत" ( यानौरी ) पूर्वसर्ग लगाया जाता है ।

नाविक ( पहले रेटिंग कहलाते थे )

नौसेना के सूचीबद्ध जवान या 'अन्य पदधारी' ।

पोत की कर्णधारी

एक पोत या तटीय स्थापना के सभी नाविक-कर्मचारी, जिसमें अधिकारी और जवान दोनों आते हैं ।

कर्णधार

जो नाव का कर्णधार होता है, एक वरिष्ठ नाविक जो एक नाव और नाविकों का प्रभारी होता है ।

वॉसन

एक अधिकारी ( चोकर पेटी अकमर । पेटी अकसर ) जो पोतों, नावों, रिग मंडों आदि की देखभाल करता है । उनका सहायक वॉसन सीमेंटों को सीटी बनाकर काम पर बुलाता है ।

नौट

बाल के प्रसंग में आता है और प्रति घंटे समुद्र-मोल को बताता है । एक समुद्रमोल लगभग १ 1/2 यलमोल के बराबर होता है ।

ताम्र ( गंगवे )

पोत के भीतर कोई मान्य घेरा या रास्ता, मार्ग या चढ़ने-फिरने का मार्ग । यह किसी अधिकारी को मार्ग देने के एक आदेश के रूप में भी इस्तेमाल होता है ।

घिन्न

एक सफ़रा उठा हुआ मंच, जहाँ से कमान अधिकारी पाव को निर्देशित करता है ।

पिछनाड

पोत का पिछना या पीछे का हिस्सा ।

किलिन-डैक

पोत के ऊपरी डैक का वह हिस्सा जो पोत के पिछनाडे की ओर ज्यादा होता है ।

विमान-बाहक

विमान-बाहको के आकार १०००० से ५००० टन तक के होते हैं और उनका ऊपरी डैक सपाट होता है, जो विमानों के उड़ान भरने और उतरने के काम आता है । प्रणोदन परम्परागत तरीकों से अथवा परमाणु-शक्ति द्वारा किया जाता है । इन पोतों की रस्तेदार अधिकतम २०-३० नौट होती है और वे स्वातंत्रिक बममार, योधा मार करने वाले विमानों आदि को छोड़ने में समर्थ होते हैं और वायु-आक्रमण के विरुद्ध निरुद्ध-पराध से रक्षा करने के लिए विमान वेधी अस्त्र प्रभेष्पास्त्र भी उनमें होते हैं ।

### क्रूर

ये सामान्य प्रयोजन के लड़ाकू पोत होते हैं और इनकी कार्रवाई की परास काफी बड़ी होती है। इनमें प्रहार-शक्ति, रफ्तार और परिचालन-क्षमता मिले-जुड़े रूप में होती है। उनकी रफ्तार ३०-३५ नॉट तक होती है और वे मध्याह्न की तोंपें (६" से ८") रखते हैं, जो अनेक प्रकार से प्रभावों का मा में आ सकती हैं। इन पोतों पर क्षेप्यास्त्र भी धराये जा सकते हैं।

### फ्लोट

समुद्री काफिले को निकट में अनुरक्षा करने के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले सभी जलयोय फ्लोट कहे जाते हैं। इनमें से अधिकांश २०००-३००० टनों के होते हैं। ये पोत विमान भेदी और पनडुब्बी-विरोधी संरक्षण प्रदान करते हैं और काफी सहन-क्षमता वाले होते हैं।

### डैस्ट्रॉयर

धूम में डैस्ट्रॉयर आकार में छोटे होते हैं और तारपीडो-नाबो को नष्ट करने के काम में आते हैं। आधुनिक डैस्ट्रॉयरो की विस्थापन-क्षमता ५५०० टन होती है और वे प्रथमतः विमान-ध्वंस के काम आते हैं और विमानवेधी निर्देशित अस्त्रों के लिए प्लवमान आधार के रूप में बनाये जा रहे हैं। इन पोतों में पनडुब्बी-भेदी प्राक्षेपिकी-अस्त्र और पोल-विरोधी क्षमता भी होती है।

### पनडुब्बी

पनडुब्बियों का उपयोग मुख्यतः पोतों के विरुद्ध आक्रामक कार्रवाई के लिए किया जाता है और वे सामान्यतः अन्य पोतों से असम्बद्ध रहकर अपना काम करती हैं। उनकी पनडुब्बी-रोधी काम में भी लाया जाता है। इस जनमान की आधुनिक सफलता असंमित सहन-क्षमता वाली और परमाणु-शक्ति चालित पनडुब्बी है। परमाणु-चालित पनडुब्बियों में निर्देशित-अस्त्र-पद्धति रहती है जैमे पोलरिस क्षेप्यास्त्र। इन्होंने नौ-युद्ध में नये आयाम उपस्थित कर दिये हैं। परम्परागत पनडुब्बियाँ २५०० टन तक की हो सकती हैं, जिनकी जल के भीतर की अधिकतम रफ्तार १७ नॉट होती है और तारपीडो उनका प्रमुख अस्त्र होता है।

टिप्पण—यह ध्यान रखा जाय कि एक युद्धपोत का टनभार सामान्यतः उसका जल-विस्थापन होता है अर्थात् पोल द्वारा विस्थापित जलीव भार, जो पोत और उसके भीतर की सभी चीजों के भार के बराबर होता है। विस्थापन टनों में विस्थापित जल के आयतन (पन फीटों में) में छारे पानी में ३५ का और मीठे पानी में ३६ का भाग देकर निकाला जाता है।

### वायुसेना की शब्दावली

#### सामरिक वायुसेना

सामरिक वायुसेना का गठन क्षेत्र में सन्तुलन मेला विरचना (सामान्यतः कोर) के साथ सक्रिया करने के लिए किया जाता है।

## विरचना

एक विरचना में एक मुख्यालय यूनिट के अधीन समूहित एक या अधिक यूनिटें होती हैं। जैसे विंग एक विरचना है, जिसमें एक विंग मुख्यालय और एक या अधिक स्क्वेड्रन होते हैं और उसमें यथावश्यक अन्य यूनिटें भी हो सकती हैं।

## विंग-मुख्यालय

एक या अधिक स्क्वेड्रनों को लचीले आधार पर एक साथ इकट्ठा करके उनको कृत्यकारी और प्रशासनिक रूप में नियन्त्रित करने वाली एक विरचना।

## स्टेशन

विंग की तरह स्टेशन भी एक विरचना है, जो आने निपटणवाली यूनिटों को मुख्यतः प्रशासनिक सेवाएँ प्रदान करती है।

## स्क्वेड्रन

स्क्वेड्रन एक उड़ान-यूनिट है, जिसमें उसकी भूमिका के अनुसार प्रकार-विशेष के विमान विशेष संख्या में होते हैं। स्क्वेड्रन की भूमिका लड़कू बममार या दोनों हो सकती है, या टोह, मेना-प्रेक्षण, परिवहन, सञ्चार, प्रशिक्षण आदि हो सकती है।

## फ्लाइट

फ्लाइट स्क्वेड्रन की वह सबसे बड़ी मान्य सघटना है, जो असम्बद्ध रूप से काम कर सकती है। इसमें दो या अधिक अनुभागी में चार या अधिक विमान हो सकते हैं।

## हारया-फलक-आधार

किसी यूनिट की तब सम्बन्ध-फलक-आधार पर रखा हुआ मान लिया जाता है, जब जनसाधन, विमान आदि की कमी के कारण अस्थायी तौर पर किसी यूनिट का कार्य निलम्बित कर देना जरूरी हो जाए और उसके व्यक्तियों, उपकरण आदि को दूसरी यूनिटों में भेजना पड़े, जिनका चलते रहना ज्यादा महत्वपूर्ण है।

## विमान

सूक्तनी—(फॉव औरगांव) एक जेट-शोदिन लड़ाकू विमान है, जो जमीन आक्रमण वाले काम में आता है।

बैनबेरा एक दो जेटों वाला बममार, जिसे उच्च तुल्य वाले बममार या अर्द्धनियंत्रित विमान विमान की तरह काम में लाया जा सकता है।

नंट : जेट-शोदिन लड़ाकू बममार, जिसे अन्तर्बाधक या जमीन-आक्रमण विमान के रूप में काम में लाया जा सकता है।

मिस्टिफर : एक इजिन वाला जेट लड़ाकू विमान, जो मुख्यतः जमीन आक्रमण वाले काम में आता है, इसे अन्तर्बाधक के रूप में भी काम में लाया जा सकता है।



- हटर** एक इंजन वाला लड़ाकू विमान, जो जमीन-आक्रमण और वायु-रक्षा दोनों ही कामों में लाया जा सकता है ।
- मिग-२१** एक इंजन वाला अतिस्वचालु अन्तर्बाधक विमान, जो वायु रक्षा में आता है ।
- परिवहन विमान** सैनिकों और साजसामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और हवाई-निष्क्रामण आदि के काम में ही मुख्यतः जाने वाला विमान (जैसे पैकेट, कैरिबो, ए एन-१२, डकोटा) ।
- हैलीकोप्टर** (सव्वायर नावों, हवाई-निष्क्रामण, सम्भारिकी-समर्थन आदि के लिए) ।
- एलोएट** फ्रांसीसी हैलीकोप्टर, मुख्यतः उच्च गति पर काम आता है ।